

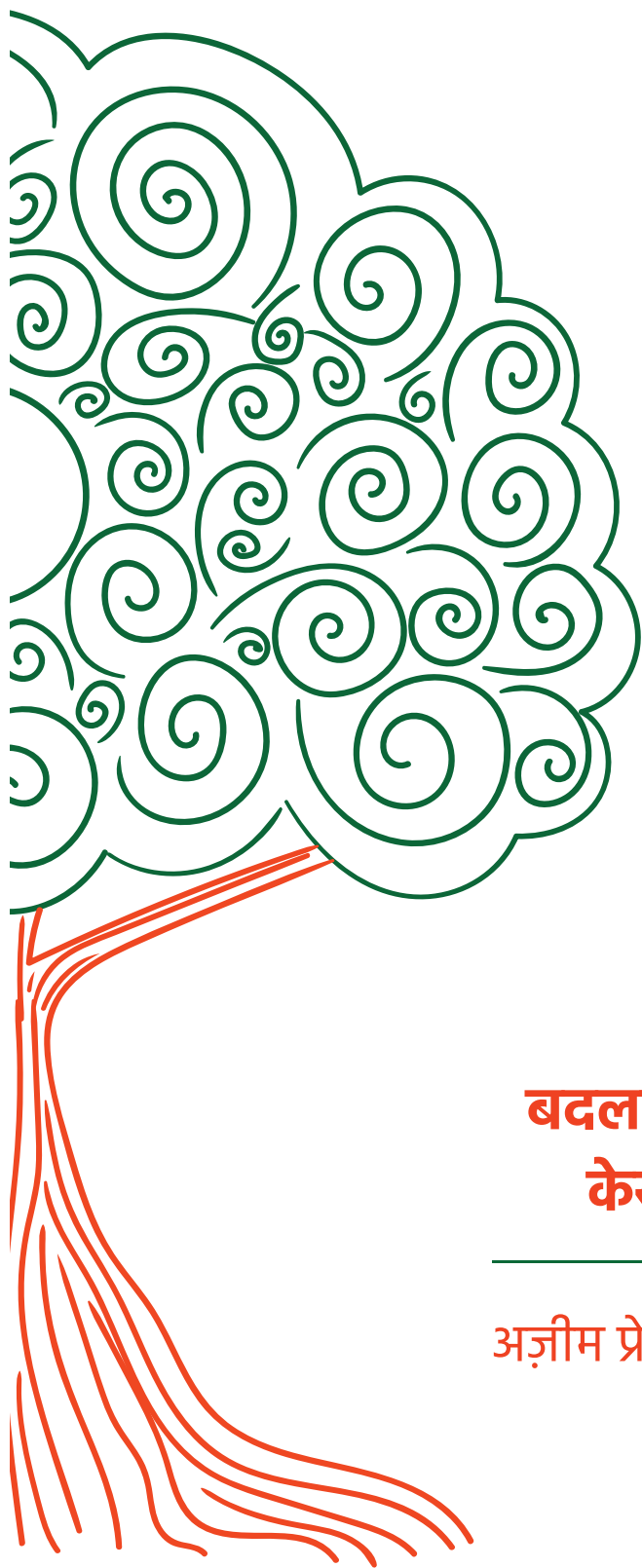


बदलाव की कहानियाँ

— 2019-2020 —

विकास कार्य और
प्रभाव पर केस स्टडीज़

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का प्रकाशन



बदलाव की कहानियाँ केस स्टडीज़ चुनौती



अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

विषय सूची

1. सामुदायिक सक्रियता के प्रयासों की केस स्टडीज़.....	7
1.1 रान रेडे—जंगल का रेडियो: डांग, गुजरात में सामुदायिक रेडियो के अनुभव.....	10
1.2 जब परिवर्तन का नेतृत्व युवा करते हैं : मुंबई के एक होनहार युवा संगठन की यात्रा को समझना.....	41
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताओं की केस स्टडीज़.....	69
2.1 चिकित्सा शिक्षा और नैदानिक अभ्यास में लैंगिकता को एकीकृत करना : प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में परिवर्तन.....	72
2.2 मध्य प्रदेश के धार ज़िले में समुदाय-आधारित सुरक्षित पेय जल आपूर्ति के माध्यम से फ्लोरोसिस शमन.....	112
3. लैंगिक चिन्ताओं पर केस स्टडीज़.....	147
3.1 सीसी हब: एक आईटी पार्क में एक चाइल्ड केयर हब.....	150
3.2 खुद के खेतों पर मज़दूर से भूस्वामी बनना : गुजरात में महिला किसानों की आजीविका को बढ़ावा देना.....	170
4. शैक्षिक हस्तक्षेपों की केस स्टडीज़.....	195
4.1 शिक्षा, संरक्षण, और आजीविका के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की केस स्टडी.....	198
4.2 कदम स्टेप-अप प्रोग्राम.....	231
5. आजीविकाओं में हस्तक्षेप सम्बन्धित केस स्टडीज़.....	261
5.1 सहयोगात्मक अधिगम : स्थाई और परिवर्तनकारी विकास को उजागर करना.....	264
5.2 बन्नी, गुजरात में पशुपालकों के बीच एकता और सामूहिक कार्यवाही.....	293

बदलाव की कहानियाँ: केस स्टडीज़ चुनौती

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

आधुनिक भारत का एक जीवन्त और सक्रिय सामाजिक क्षेत्र का एक इतिहास है। कई स्थानीय विकास संगठन, सामुदायिक संगठन, सामाजिक आन्दोलन और गैर-सरकारी संगठन सामाजिक कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आ रहे हैं। ऐसे संगठन एक अलग भविष्य की कल्पना करते हुए विभिन्न स्तरों पर सामाजिक हस्तक्षेपों की योजना बनाते एवं क्रियान्वित करते हैं। इनमें से कई हस्तक्षेपों का समाज और लोगों के जीवन पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ा है। हालाँकि, उनके प्रयास, और विशेषकर, इन पहलों से मिले सबकों से न केवल सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि 'विकास व्यवहार' और 'विकास शिक्षा' के लोग भी व्यापक रूप से अनभिज्ञ हैं। यह कमी हस्तक्षेपों, संगठनों और समय के स्तर पर सीखने और विकास की प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती है।

जबकि अधिकांश सामाजिक क्षेत्र के संगठन दस्तावेज़ीकरण और ज्ञान सृजन में इस कमी को स्वीकार करते हैं, पर ऐसे प्रयासों की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी समय और प्रेरणा जुटा पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। गहन चिन्तन और स्व-विश्लेषण से प्रेरित लेखन महज़ दस्तावेज़ीकरण से कहीं अधिक सीखने के लिए एक आधार का सृजन करता है जिसके लिए समय और स्थान की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप, उनका लेखन प्रायः अनुदान प्रस्तावों या परियोजना अद्यतन (update) या 'अच्छी कार्यप्रणालियों' जैसे दस्तावेज़ीकरण तक ही सीमित रह जाता है। यही वजह है कि उनका लेखन कार्यों की बारीक़ियों, सीमाओं तथा कमियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता है।

इस आवश्यकता को समझते हुए, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने सामाजिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा ज़मीनी ज्ञान आधार के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'बदलाव की कहानियाँ : केस स्टडीज़ चुनौती' आरम्भ की है। हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस चुनौती के पहले वर्ष (2018-19) में हमें 95 केस प्राप्त हुए जो शिक्षा, सततता, आजीविका, संस्कृति के संरक्षण और सामुदायिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेपों से सम्बन्धित थे। लक्षित समूहों में अन्य के साथ आदिवासी, छोटे किसान, बच्चे, महिलाएँ, युवा और अन्यथा सक्षम (differently abled persons) व्यक्ति आदि शामिल थे। 2018-19 बदलाव की कहानियाँ चुनौती के लिए, विश्वविद्यालय ने द्विस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से 3 विजेता और 3 विशेष उल्लेख चयनित किए। इसके अलावा, हमने 4 अतिरिक्त प्रविष्टियों का चयन किया है जो उल्लेखित विजेताओं के साथ संयुक्त रूप से प्रकाशित इस सार-संग्रह में प्रस्तुत की गई हैं।

हमें विश्वास है कि शिक्षक और पेशेवर समान रूप से अपने विभिन्न कार्यों—नीति को प्रभावित करने, पेशेवरों के क्षमतावर्धन, भावी शिक्षार्थियों के लिए अच्छी कार्यप्रणालियों का दस्तावेज़ीकरण करने, शिक्षण में पेशेवरों को स्थान उपलब्ध कराने, सहयोगपूर्ण अनुसन्धान करने और यहाँ तक कि सामाजिक बदलाव के लिए नए विचार गढ़ने—में इन कहानियों को महत्वपूर्ण पाएँगे।

सन्दर्भ तैयार करना

1. सामुदायिक सक्रियता के प्रयासों की केस स्टडीज़

सरकारों द्वारा सामुदायिक सक्रियता का प्रचार किया गया है, ज़मीनी स्तर के संगठनों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों को विकास के परिणामों में सुधार के मुख्य साधनों में गिना जाता है। इसका एक कारण यह है कि अपने स्वभाववश सामुदायिक सक्रियता प्राप्तकर्ताओं के बीच कुछ स्तर तक सहभागिता प्रेरित करती है जो बदले में समुदाय को सशक्तिकरण की दिशा में ले जाती है। उन समाजों के सन्दर्भ में यह स्वीकार किया जाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो जाति, लिंग, धर्म और वर्ग आधारित असमानताओं के शिकार हैं।

हालाँकि, ऐसा लगता है कि हाल के दशकों में सामुदायिक सक्रियता और विकास के लिए सहभागी दृष्टिकोणों के महत्व के बारे में फिर से सोच विचार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अविश्वास का कुछ अंश इस तथ्य से उभरा है कि हमने विकास के क्षेत्र में बदलाव की एक शृंखला देखी है जिसे प्रायः सामूहिक रूप से 'एनजीओकरण' (NGOisation) के रूप में जाना जाता है। सामुदायिक सक्रियता के विशिष्ट सन्दर्भ में, यह तर्क दिया जाता है कि कई गैर-सरकारी संगठनों (Non-Government Organisations—NGOs) ने समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सहभागिता 'प्रेरित' करने के प्रयास किए हैं। आलोचकों ने तर्क दिया है कि इस तरह के एक कृत्रिम दृष्टिकोण ने, जिसने सामुदायिक सहभागिता की 'सहजता' और 'बुनियादी' प्रकृति की राह में गतिरोध पैदा किया है, ज़मीनी स्तर पर किसी भी तरह के वास्तविक सशक्तिकरण की राह में रुकावट पैदा की है क्योंकि इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों का स्वामित्व और निर्देशन दान दाता संगठनों के हाथों में रहता है। इसी सन्दर्भ में दो केस स्टडीज़ का अवलोकन करना दिलचस्प हो जाता है जो इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि एक मामले में सामुदायिक सक्रियता ने किस तरह क़ानूनी सहायता सुलभ बनाने में और दूसरे मामले में युवाओं का सशक्तिकरण सुगम बनाने में भूमिका निभाई है।

पहले हस्तक्षेप, जिसका नाम 'रान रेडे' (शाब्दिक अर्थ "जंगल का रेडियो") है, में आदिवासी समुदाय को क़ानूनी सहायता तक पहुँच और उनकी अपनी संस्कृति के कार्याकल्प के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए गुजरात के डांग ज़िले में एक सामुदायिक रेडियो की स्थापना करना शामिल था। हस्तक्षेप की रूपरेखा सामाजिक न्याय केन्द्र (Centre for Social Justice—CSJ) द्वारा तैयार की गई थी। हस्तक्षेप की रूपरेखा कार्यवाही का सम्पूर्ण चक्र शामिल करने

के लिए तैयार की गई थी, जिसमें जन-जागरूकता पैदा करने से लेकर, समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों की पहचान करना, क़ानूनी सलाह केन्द्र के माध्यम से उनके लिए अधिकारों के लिए हस्तक्षेप की एक प्रक्रिया का पालन करना तक शामिल था। जैसा कि मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है, इस हस्तक्षेप ने सामुदायिक रेडियो की अन्तर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए भारत में स्वतंत्र राजनीतिक / लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति आन्दोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हस्तक्षेप ने रेडियो प्रसारण के बाद आगे की एक चर्चा में सदस्यों की सक्रिय सहभागिता की सुविधा दी, जिसका नेतृत्व रान रेडे टीम के स्वयंसेवकों और मध्यस्थों (volunteers and moderators) ने किया। ऐसा प्रतीत होता है कि हस्तक्षेप में डांगी संस्कृति का समावेश करने का एक साभिप्राय प्रयास किया गया है ताकि लोग ख़ुद को उससे पृथक् महसूस न करें। हस्तक्षेप में स्वयंसेवक डांगी समुदाय से ही भर्ती किए गए, जिससे लोग क़ानूनी सलाह केन्द्र के साथ एक अन्तराफलक (interface) की सुविधा के ज़रिए अपनी समस्याओं की ज़िम्मेदारी संभाल सकें।

हाल के वर्षों में युवाओं की सक्रियता समुदाय की सक्रियता के एक महत्वपूर्ण तत्त्व के रूप में उभरी है और इसके प्रभावों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवाओं से निर्मित होता है। इस सन्दर्भ में, यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (Youth for Unity and Voluntary Action—YUVA) की केस स्टडी उत्तर-पश्चिमी मुंबई के एक उपनगर मालवणी में एक अभिनव हस्तक्षेप की खोज करती है। YUVA के मामले में दिलचस्प बात यह है कि स्कूलों और कॉलेजों के नेटवर्क का दोहन करके शिक्षित युवाओं के साथ मुख्य रूप से साझेदारी करने वाले विकास निकायों के विपरीत, वे युवाओं के सबसे सीमान्त वर्गों के साथ काम कर रहे हैं जो या तो निरक्षर हैं या अर्ध-साक्षर हैं और समाज के सबसे वंचित वर्गों से सम्बन्धित हैं। 'रान रेडे' के मामले की तरह, यहाँ भी, हस्तक्षेप का ज़ोर राजनीतिक चेतना पैदा करते हुए, एक समालोचनात्मक सोच के लिए स्थान निर्मित करते हुए और लोकतांत्रिक मूल्य, लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देते हुए एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने में निहित है। कार्यक्रम के संचालन का तरीका संगठन के दृढ़ विश्वास से उपजा है कि "जिन लोगों को सबसे पहले समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे लोग पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायक ज्ञान के साथ ख़ुद इससे निपटने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं"। इस प्रकार अपनी समस्याओं की पहचान तथा हल करने और आन्दोलन की ज़िम्मेदारी संभालने तथा अन्ततः इसे स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए युवाओं को सक्षम बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

इसलिए दोनों ही मामलों में, एक अधिकार-आधारित संवाद को बढ़ावा देने पर आसानी से ज़ोर दिया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी संगठन सामाजिक समस्याओं का सामना करने और उनके समाधान के लिए राजनीतिक मार्ग अपनाने से कतरा नहीं रहा है,

हालाँकि सामाजिक न्याय केन्द्र के मामले में यह अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोनों संगठन इस दृढ़ विश्वास से प्रेरित प्रतीत होते हैं कि विकास तभी स्थाई हो सकता है जब समुदाय को जागरूक किया जाए और अपनी भलाई की ज़िम्मेदारी सँभालने के लिए उसका सशक्तिकरण किया जाए। दोनों ही मामलों में, संगठन ने विश्वास किया और समुदाय में आत्मविश्वास पैदा करते हुए उसके लिए यह सम्भव बनाया कि वह हस्तक्षेप की ज़िम्मेदारी सँभाले और इसे अपना बना ले। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों संगठनों ने हस्तक्षेप में लाभार्थियों की स्थानिक और सांस्कृतिक कल्पना का समावेश करने में निरन्तरता प्रदर्शित की। विशिष्ट सन्दर्भ का पूरा संज्ञान लेते हुए सामुदायिक सक्रियता परियोजनाओं में 'बुनियादी सहभागिता' के इस पहलू के कारण ही यह दोनों मामले ग़रीबों के जीवन में एक वास्तविक अन्तर लाते हैं।

1.1 रान रेडे - जंगल का रेडियो

डांग, गुजरात में सामुदायिक रेडियो के अनुभव

सामाजिक न्याय केन्द्र, डांग, गुजरात

सारांश

अन्य जनसम्पर्क माध्यमों के साथ, रेडियो मीडिया स्पेस की शुरुआत भी उस समय हुई जब भारत में स्वतंत्र राजनीतिक और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति आन्दोलन के दायरे और तीव्रता में विस्तार हो रहा था। यह संवाद, हालाँकि, काफ़ी हद तक शहरी विवेकाधीन क्षेत्रों तक ही सीमित था, और यह केवल सामुदायिक रेडियो का विकास ही है, जिससे ग्रामीण समुदायों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के बीच वास्तविक स्वतंत्र अभिव्यक्ति आन्दोलन उदित हुए हैं। रान रेडे खुद को इस वातावरण में एक सामाजिक-क़ानूनी हस्तक्षेप के रूप में देखता है। डांग में स्थित, इसने न केवल क़ानूनी जागरूकता के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया विकसित की—अपने-आप में सामुदायिक रेडियो का क्षेत्र और मिशन—बल्कि स्थानीय क़ानून केन्द्र, क़ानूनी सलाह केन्द्र को शामिल करते हुए एक मज़बूत प्रतिक्रिया रणनीति के साथ इसका पालन किया। रान रेडे के परिवर्तन के सिद्धान्त (Theory of Change) ने सूचना के प्रसार को शामिल किया, और इस तरह के प्रसार के माध्यम से अधिकारों के उल्लंघनों की पहचान की गई, जिसका निवारण किया जा सकता है। साम्प्रदायिक रूप से स्वामित्व और एक सर्व-आदिवासी दल द्वारा संचालित होने के नाते, रान रेडे ने इस तरह एक अनोखी क़ानूनी हस्तक्षेप की रणनीति अपनाई जो प्रतीकात्मक रूप से क़ानूनी कार्यवाही-अनुसन्धान को सांस्कृतिक कायाकल्प और सशक्तिकरण के लिए मज़बूत और लक्षित हस्तक्षेपों के साथ जोड़ती है। इसकी समाप्ति के बाद भी कार्यक्रम के प्रभावों को लम्बे समय तक महसूस किया जाता रहा है, और आज तक यह सामुदायिक मीडिया के प्रभावी उपयोग पर केन्द्रित एक सांस्कृतिक-क़ानूनी हस्तक्षेप विकसित करने के लिए एक रणनीतिक पद्धति उपलब्ध कराता है।

रान रेडे - जंगल का रेडियो : डांग, गुजरात में सामुदायिक रेडियो के

अनुभव - परिचय

पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि सामान्य रूप से भारतीय मीडिया का उदारीकरण, सच्चे सहभागी लोकतंत्र के धीमे किन्तु क्रमिक आगमन में एक ऐतिहासिक क्षण था। चौथे क्षेत्र (स्टाम्प) के रूप में, इसने दोनों काम किए—अभूतपूर्व सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का साक्षी बनना एवं उनका सूत्रपात करना, जिनमें राजनीतिक संस्थानों की जवाबदेही तय करने और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए बढ़ती माँगें शामिल हैं। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव स्वतंत्र सम्भाषण और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन रहा है, जो एक संवैधानिक गारंटी और एक मूलभूत मानव अधिकार है, जिसके लिए सामान्य रूप से मीडिया सिर्फ ज़िम्मेदार ही नहीं है, बल्कि जिस पर वह निर्भर भी है। जबकि आज का सार्वजनिक मीडिया—सबसे विशेष रूप से, टेलीविज़न समाचार—विशाल बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा शासित किया जाता है, और उनकी मज़ी तथा सनक के अधीन है, एक स्वतंत्र मीडिया की जड़ें और उसकी अन्तर्निहित उद्धारक शक्ति सामुदायिक-नेतृत्व और सामुदायिक-नियंत्रण वाले मीडिया की पहलों में मज़बूती से स्थित हैं।

राज्य-नियंत्रित मीडिया से दूर इस व्यापक बदलाव में, स्वतंत्र सम्भाषण और अभिव्यक्ति के सामुदायिक दावों के लिए रेडियो का माध्यम एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। देश के बड़े इलाकों की पूँजीवादी विकास के महानगरीय केन्द्रों, व्यापक अशिक्षा, रेडियो तरंगों की विस्तृत पहुँच से दूरी, और लागत-कुशलता का अर्थ है कि भारतभर में सामुदायिक-स्वामित्व वाली मीडिया के लिए रेडियो एक अत्यधिक प्रासंगिक, प्रभावी, और उपयुक्त विकल्प है। इस प्रकार, सामुदायिक रेडियो के लिए मंच तैयार किया गया। इस विषय पर पहली नीति 2002 में लागू की गई थी, लेकिन रेडियो की उपलब्धता का विस्तार केवल शैक्षणिक संस्थानों तक ही किया गया था। मोटेतौर पर, इसका मतलब था उपयोग में कमी। जबकि प्रसारण और संचार के सन्दर्भ में रेडियो लागत-कुशल है, इसके लिए निश्चित रूप से उल्लेखनीय पूँजीगत लागतों की पूर्ति की आवश्यकता होती है, जो इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक बाधा है। शैक्षणिक संस्थान अक्सर इस खर्च को वहन करने में असमर्थ थे, जिससे भारी अभाव की स्थिति पैदा हो गई। 2002 के बाद के चार वर्षों में, भारत में, 2006 में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए नए नीतिगत दिशा-निर्देशों को अपनाने तक, नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organisations—CSOs) ने माध्यम के वास्तविक लोकतंत्रीकरण के लिए व्यापक पैरवी के प्रयास करना और माँगें रखना शुरू किया। उनकी पैरवी सफल सिद्ध हुई। 2006 के नीतिगत दिशा-निर्देश इन प्रयासों के परिणाम दर्शाते हैं।

2006 में सामुदायिक रेडियो की शुरुआत के साथ, देशभर में जड़ें जमाने के तीन प्रमुख प्रयास शुरू हुए (कच्छ, कर्नाटक, और फिर डांग में)। यह काफ़ी हद तक जागरूकता निर्माण और सूचना के प्रसार पर केन्द्रित थे। कुछ हद तक, यह कार्य प्रणाली रेडियो से जुड़ी अन्तर्निहित सीमाओं से प्रेरित थी : जो कि उसका एकल दिशा में कार्य करने वाला एक संचार माध्यम होना था। जबकि इस गतिशीलता के दौरान सामाजिक परिवर्तन तेज़ी से जारी रहा, मानव अधिकारों के उल्लंघन को सम्बोधित करने की आवश्यकता के बारे में सवालियों को उसमें समायोजित नहीं किया जा सका। इसी तरह, यह समझा गया था कि स्वतंत्र सम्भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के वास्तविक इस्तेमाल के लिए भी विशेष रूप से अन्याय के खिलाफ़ कार्य करने की क्षमता आवश्यक है। इस प्रकार, सामुदायिक रेडियो को एक निरन्तर चलने वाली प्रभावी प्रक्रिया के साथ जोड़ने की एक आवश्यकता थी जो कि अधिकारों के उल्लंघन को सम्बोधित करे। इस माहौल में सामाजिक न्याय केन्द्र (Centre for Social Justice—CSJ)¹ ने रान रेडे हस्तक्षेप विकसित किया।

रान रेडे, जिसे सचमुच “जंगल का रेडियो” समझा जा सकता है, सामुदायिक रेडियो और ठोस सामाजिक-क़ानूनी हस्तक्षेप के बीच एक सहजीवी सम्बन्ध बनाने का एक प्रयास था। यह गुजरात के डांग ज़िले में पहले 2006/07 में और फिर 2011 में पुनः शुरू हुआ। सामुदायिक रेडियो की यह अनोखी पहल आहवा, डांग में सामाजिक न्याय केन्द्र के क़ानूनी केन्द्र (क़ानूनी सलाह केन्द्र) द्वारा संचालित और सहायता-प्राप्त थी। इस प्रकार, हस्तक्षेप में समुदाय के भीतर उभरने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता निर्माण से लेकर उनके समाधान तक के लिए, अधिकारों के हनन के निवारण हेतु एक अनुवर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की विस्तृत श्रेणी शामिल की गई।

यह केस स्टडी सम्पूर्ण रान रेडे हस्तक्षेप का एक आशुचित्र (snapshot) है। मोटेतौर पर यह एक कालानुक्रमिक तरीके से संयोजित की गई है, जिसकी शुरुआत एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और भौगोलिक क्षेत्र के रूप में डांग की पृष्ठभूमि, और संचार के एक माध्यम के रूप में सामुदायिक रेडियो की भूमिका से होती है। फिर यह हस्तक्षेप के पैमाने और वैचारिक बुनियादों का वर्णन करता है, विशेष रूप से इसके परिवर्तन के सिद्धान्त का वर्णन करता है। यह रान रेडे के प्रभाव और उसके सामने आने वाली चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह भविष्य की सम्भावनाओं के आकलन के साथ सम्पन्न होता है और हस्तक्षेप के अपने खुद के अनुभव के आधार पर भविष्य के लिए एक वैचारिक रास्ता प्रदान करता है।

¹ सामाजिक न्याय केन्द्र का आधिकारिक नाम IDEAL, सामाजिक न्याय केन्द्र है। IDEAL का अर्थ इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग (Institute for Development Education and Learning) है।

सामुदायिक रेडियो : एक पृष्ठभूमि

रेडियो प्रसारण के लिए सामुदायिक रेडियो एक “तीसरे तरीके” वाला दृष्टिकोण है। यह सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से निजी या व्यावसायिक हितों से दूर रखा गया है, और स्थानीय समुदाय एवं उसके हितों पर अत्यधिक विशिष्ट रूप से ध्यान केन्द्रित करने के माध्यम से सार्वजनिक प्रसारण से दूर रखा गया है। इस प्रकार सामुदायिक रेडियो एक ऐसा रेडियो प्रसारण या ऐसी प्रसारण सेवा मात्र है जिसकी सामग्री स्थानीय समुदायों के अनुसार स्थानीय, सन्दर्भगत, और प्रासंगिक रखी जाती है, और जिसका स्वामित्व, संचालन, और नियंत्रण ऐसे समुदायों में निहित होता है।

इस प्रकार सामुदायिक रेडियो एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों, समूहों, और समुदायों को अपनी खुद की कहानियाँ बताने, अपने स्वयं के सामूहिक अनुभव साझा करने में समर्थ बनाती है, और न सिर्फ स्वतंत्र मीडिया, बल्कि लोकतांत्रिक स्वतंत्र सम्भाषण और अभिव्यक्ति की एक व्यापक संस्कृति के निर्माता बनने, और उसमें योगदान करने वाले बनने में भी समर्थ बनाती है।

द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ़ कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स (The World Association of Community Radio Broadcasters-WACRB) ने उन मानदण्डों की एक सूची निर्मित की है जो सामुदायिक रेडियो-आधारित पहलों को परिभाषित एवं निर्धारित करती है, और उनका औचित्य सिद्ध करने के साथ उनकी पहचान करती है। यह मानदण्ड हैं :

- सामुदायिक रेडियो प्रसारण के अधिकार को बढ़ावा देते हैं, सम्भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुविधा देते हैं, रचनात्मकता और विविधता को प्रोत्साहित करते हैं, और एक बहुलतावादी समाज के भीतर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान करते हैं।
- सामुदायिक रेडियो शैक्षिक और उत्पादन-सम्बन्धित सम्भावनाएँ प्रदान करते हैं। वे स्थानीय रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं, स्थानीय परम्पराएँ विकसित करते हैं, और अपने श्रोताओं के लिए एक मनोरंजक, शिक्षाप्रद, और विकास को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।
- रेडियो या रेडियो कार्यक्रमों के स्वामित्व को सामुदायिक रेडियो इस तरह से सुरक्षित करते हैं जो यह सुनिश्चित करे कि एक दृश्य समुदाय के स्थानीय प्रतिनिधि, या एक हित रखने वाला समुदाय उसका स्वामी हो।
- सम्पादकीय रूप से सामुदायिक रेडियो अपने रेडियो कार्यक्रमों के संकलन में सरकारों, व्यापारिक निकायों, धार्मिक संस्थानों, और राजनीतिक दलों से स्वतंत्र हैं।

- सामुदायिक रेडियो यह सुनिश्चित करते हैं कि सीमान्त समूहों और अल्पसंख्यकों की रेडियो तक पहुँच हो, और सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता का संरक्षण करने के साथ-साथ उसे बढ़ावा दें।
- सामुदायिक रेडियो सुनिश्चित करते हैं कि श्रोताओं को कई स्रोतों से जानकारी मिले, वे अनेक दृष्टिकोणों को सुनें, और प्रत्येक व्यक्ति या समूह की ओर से आने वाले विरोधी दृष्टिकोणों के लिए भी स्थान हो।
- सामुदायिक रेडियो ऐसे संगठन हैं जो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ग़ैर-लाभकारी आधार पर काम करते हैं और बड़ी संख्या में दान दाताओं द्वारा वित्तपोषित होते हैं।
- सामुदायिक रेडियो स्वैच्छिक कार्य को मान्यता देते और उसका सम्मान करते हैं तथा संगठनात्मक मामलों और काम के ढाँचों के ऐसे विस्तार के लिए सवैतनिक कार्य के अधिकार को स्वीकार करते हैं जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए फ़ायदेमन्द हो।
- सामुदायिक रेडियो ऐसे प्रबन्धन के स्वरूप, कार्यक्रम संरचनाएँ, और काम की परिस्थितियाँ प्रदान करते और अपनाते हैं जो किसी भी तरह के भेदभाव को ख़ारिज करते हैं और इसमें शामिल सभी लोगों, कर्मचारियों, और स्वैच्छिक सहायकों के लिए समान रूप सुलभ होते हैं।
- सामुदायिक रेडियो शान्ति, सहिष्णुता, लोकतंत्र, और विकास के मामलों में समझ को बढ़ावा देने और उसमें वृद्धि करने के लिए अन्य सामुदायिक रेडियो के साथ संवाद बनाए रखते हैं।

यह दिशा-निर्देश सामुदायिक रेडियो की एक पहचान स्थापित करते हैं जो ख़ुद की कल्पना मौलिक रूप से लोकतांत्रिक तथा वास्तविक स्वतंत्र सम्भाषण और अभिव्यक्ति के लिए एक स्थान के रूप में करता है। इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना है, और एक सामाजिक-क्रान्ती सामुदायिक रेडियो के सन्दर्भ में, यह क्रान्ती जागरूकता पैदा करने और अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करने पर केन्द्रित है। इसी प्रकार, यह समुदाय के अन्दर एकजुटता को मज़बूत करने और साझा आदर्श एवं मानक ढाँचे विकसित करने का एक साधन है। लेकिन शायद सबसे उल्लेखनीय रूप से—और निश्चित रूप से यहाँ इसकी प्रासंगिकता है—एक लोकतांत्रिक पद्धति के रूप में सामुदायिक रेडियो की अवधारणा है। सामुदायिक रेडियो की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि यह उन मुद्दों पर स्थानीय लोकतांत्रिक जुड़ाव को और स्थानीय समुदायों की तरफ़ से सहभागिता को बढ़ावा दे जो उनके हितों से जुड़े हों, और यह संचालन के एक ऐसे लोकतांत्रिक तरीक़े को विकसित करता और अपनाता है जो इस तरह

के मानदण्ड सम्बन्धी आदर्शों को मज़बूती प्रदान करे। पूर्ण साम्प्रदायिक स्वामित्व, समुदाय-जनित और समुदाय-नियंत्रित सामग्री, और गैर-भेदभाव, कृषि विज्ञान, विविधता, तथा सांस्कृतिक विरासत के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान की भावना के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो आन्तरिक रूप से वास्तविक लोकतांत्रिक सहभागिता के लिए एक स्थान विकसित करता है जो अपने लोकतांत्रिक सन्देश में खुद को बाहरी रूप से व्यक्त करता है। इस प्रकार, यह अरक्षित समुदायों के लिए सामाजिक-राजनीतिक संगठन और एकजुटता के लिए एक आधार तैयार करता है जो अन्यथा हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं।

सामुदायिक रेडियो का “तीसरे तरीके” वाला दृष्टिकोण तीन कारणों से इन अरक्षित समुदायों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।

सबसे पहले, अरक्षितता किसी को मुख्य धारा से दूर करते हुए हाशिए पर धकेलने का एक कृत्य है। अरक्षितता के सामुदायिक अनुभवों को अदृश्य कर दिया जाता है, महानगर-केन्द्रित विकास के एक संवाद का प्रभुत्व होता है जो किसी मनमाने राष्ट्रीय हित की ठोस अवधारणाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के बहाने मानव अधिकारों के मुद्दों को गौण स्थिति में पीछे धकेल देता है। इन कहानियों और वर्णनों को सामने लाकर, सामुदायिक रेडियो उत्पीड़ित समुदायों के संवाद को इन समुदायों के भीतर व्यापक रूप से परिचालन करने वाले अप्रासंगिक समूहों के भीतर वापस लाता है।

दूसरा, सामाजिक सम्बन्धों को वस्तु समझने के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक अधिकारों की उपेक्षा भी होती है, जो मानवाधिकार ढाँचे का एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। एक सर्व-विजयी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के हमले के खिलाफ़, अरक्षित समुदायों को पहचान खो देने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। सांस्कृतिक प्रथाओं, विरासत, पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों, और शासन प्रक्रियाओं को एक ओर समग्रता के सामने शीघ्रता से अप्रचलित घोषित कर दिया जाता है जो एक तरफ़ पहचान कर रहा है, और दूसरी तरफ़ विनाश कर रहा है। स्थानीय सांस्कृतिक प्रणालियों में दृढ़ता से निहित होने के साथ, और सांस्कृतिक एवं पारम्परिक प्रथाओं तथा ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो आंशिक रूप से ध्वस्त पहचानों, साझा पूर्ववृत्त (history) और साम्प्रदायिक सांस्कृतिक अनुभवों के पुनर्निर्माण के द्वारा इस ज्वार का मुक़ाबला करने का प्रयास करता है।

तीसरा, राज्य द्वारा लागू क़ानून अकसर अरक्षित समुदायों को इस तरीके से प्रभावित करते हैं जो इन क़ानूनों द्वारा अन्य गैर-अरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करने के तरीके से बहुत भिन्न होता है। अरक्षितता को सम्बोधित करने वाले क़ानून या तो अस्तित्व में नहीं हैं, या लागू नहीं हैं, या आगे भी अरक्षितता की स्थिति को और मज़बूत बनाने का कार्य करते हैं। इन समुदायों के लिए, इस तरह के क़ानून में उद्धार करने की वह क्षमता मौजूद नहीं है जिसका यह वादा

करता है। वास्तव में, यह उत्पीड़न का एक उपकरण है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अधिकारों की रूपरेखा जैसी क़ानूनी अवधारणाओं की मानकीय क्षमता इन समुदायों के लिए अप्रासंगिक है। वास्तव में, यह काफ़ी विपरीत है। क़ानूनी प्रक्रिया और न्याय-वितरण प्रणालियों से उनके बहिष्करण के कारण यह स्थिति है कि ऐसी क्षमता का बोध और दोहन नहीं हो पाता है। मानवाधिकारों के मुद्दों के इर्द-गिर्द क़ानूनी जागरूकता के निर्माण और इस क़ानूनी जागरूकता को एक सम्पूर्ण क़ानूनी हस्तक्षेप के आधार के रूप में विकसित करने के लिए एक साधन के रूप में सामुदायिक रेडियो का उपयोग एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ़ रान रेडे ध्यान देता है और इसे क्रियान्वित करता है, क्योंकि वह इसे क़ानूनी प्रक्रिया की तरफ़ अरक्षित समुदायों की वापसी के लिए प्राथमिक प्रक्रिया के रूप में देखता है।



सामुदायिक रेडियो हमारे लिए क़ानूनी जागरूकता निर्मित करने के रचनात्मक साधनों का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा क़ानूनी कार्यक्रम को मज़बूती प्रदान करने का एक साधन है।

- रोशन सरोलिया, रेडियो निर्माता, रान रेडे



डांग : एक सामाजिक और भौगोलिक सन्दर्भ

डांग (या "The Dangs" जैसा कि यह नौकरशाहों द्वारा पुकारा जाता है) पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य का एक आदिवासी ज़िला है। यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जनजातीय समुदायों से है। भील, कुकना (कुन्ची), वरली, और गामिट इस क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी समूह हैं। भील सदियों से डांग में रह रहे हैं जबकि अन्य जनजातियाँ आजीविका की तलाश में डांग आई थीं। दक्षिण-पश्चिम भारत में महाराष्ट्र के एक तटीय क्षेत्र कोंकण से कुकना इस क्षेत्र में आकर बस गए। कुकना और उनकी बोली का नाम उनके उद्गम स्थल से व्युत्पन्न हुआ है।

ऐतिहासिक रूप से, उल्लेखनीय सामाजिक स्तरीकरण हमेशा डांग की विशेषता रहा है, जो पूर्व-औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले, भील राजाओं (चार प्रमुख और दस नायक) ने डांग पर शासन किया। 1872 की पहली जनगणना में 7,426 भील, 6,517 कुकना, 2,491 वरली, और 302 गामिट पाए गए। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, कुकनाओं की स्थिति में सुधार हुआ, जबकि भीलों की स्थिति और खराब हो गई। शिक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की दृष्टि से कुकना एक बेहतर स्थिति में थे; वन्य श्रमिक सहकारी समितियों (Forest Labour Cooperatives—FLCs) पर

उनका प्रभुत्व था और उन्होंने राजनीतिक आरक्षण का उपयोग भी किया। इस तरह, कुकनाओं और भीलों के बीच सत्ता के विभाजन में बदलाव आ गया। सत्ता की यह व्यवस्था डांगी जीवन के सभी पहलुओं में प्रासंगिक बनी हुई है।

डांग के लोगों की आजीविका प्राकृतिक संसाधनों और जंगलों, आर्थिक बंदोबस्तों, और संस्थागत व्यवस्थाओं पर बहुत अधिक निर्भर है। पहाड़ी इलाकों के कारण, लोगों के पास आजीविका के सीमित विकल्प हैं; कृषि सीमित है, औद्योगिक गतिविधि अस्तित्वहीन है, और मानव विकास की स्थिति खराब है। डांग की आदिवासी आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत वन-आधारित गतिविधियाँ और कृषि है।

डांग का क्षेत्रफल लगभग 1,788 वर्ग किमी है। भौगोलिक रूप से, यह दूरस्थ इलाका है। डांग ज़िले से अलग, डांग क्षेत्र उत्तर में नर्मदा ज़िले से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के क्षेत्रों और पश्चिम में वलसाड एवं नवसारी के क्षेत्रों तक फैले व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक समरूपता के एक बड़े क्षेत्र को समाहित करता है। डांग क्षेत्र में रहने वाले समुदाय एक ऐसी भूमि में रहते हैं जो बीहड़ है, घने जंगलों से आच्छादित है और एक उभरती हुई स्थलाकृति है। बुनियादी ढाँचा सीमित है। परिवहन के साधन कठिन हैं, और सड़क मार्ग सीमित हैं। पहुँच की इस कमी का एक ऐतिहासिक आयाम है। औपनिवेशिक शासनकाल में, डांग के समृद्ध जंगलों को उनकी इमारती लकड़ी के लिए लूटा गया था। इस क्षेत्र में अब भी इस गतिविधि के सबूत मौजूद हैं; एक रेल लाइन नवसारी शहर (मुंबई व्यापार मार्ग पर) से वाघई (डांग और बाक़ी गुजरात की सीमा पर एक शहर) तक फैली हुई है। जैसा कि रमेश धूम ने बताया है, जो रान रेडे के एक रेडियो निर्माता हैं, इस रेल लाइन का निर्माण डांग से नवसारी तक इमारती लकड़ी पहुँचाने और वहाँ से आगे ब्रिटिश भारत के अन्य क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए किया गया था। प्राकृतिक संसाधन के शोषण के इस पूर्ववृत्त का अर्थ था कि आने वाली सरकारों ने डांग के भीतर बुनियादी ढाँचे के विकास में बहुत कम निवेश किया। इस तरह की उपेक्षा न केवल सड़कों और पुलों तक, बल्कि स्कूलों, आँगनवाड़ी केन्द्रों, और स्वास्थ्य केन्द्रों जैसी अन्य राज्य सेवाओं तक भी पहुँची। जब रान रेडे का हस्तक्षेप शुरू हुआ, डांग की साक्षरता दर केवल 38 प्रतिशत थी।

क्षेत्र की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति, और सामाजिक-राजनीतिक जनसांख्यिकी को देखते हुए, मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता निर्माण के लिए रेडियो का इस्तेमाल करना सर्वाधिक प्रभावी प्रक्रिया साबित हुई। यह सुलभ, किफ़ायती थी, और इसकी व्यापक पहुँच थी जिसके कारण सूचना प्रसार के अन्य रूपों जैसे अभियानों (campaigns) और प्रिंट मीडिया की तुलना में यह काफ़ी अधिक प्रभावी था।

मापदण्ड	रेडियो	प्रिंट मीडिया	अभियान
फैलाव	व्यापक फैलाव	निरक्षरता एक बाधा है	सीमित फैलाव
लक्षित श्रोताओं का जुड़ाव	समुदाय का प्रत्यक्ष जुड़ाव	समुदाय से कोई सम्पर्क नहीं	समुदाय का बहुत सीमित जुड़ाव
मनोरंजन का स्तर	मनोरंजक	मनोरंजन की कमी	प्रचारकों पर निर्भर करता है
पहुँच	आसान पहुँच	सुगम्यता के लिए प्रयास आवश्यक	क्षेत्र का भू-भाग और स्थलाकृति सुगम्यता को मुश्किल बनाते हैं
लागत प्रभाविता	किफ़ायती	महँगा	महँगा
प्रभाव	बड़ा प्रभाव	सीमित प्रभाव	सीमित प्रभाव
गुंजाइश	व्यापक गुंजाइश	शिक्षा की कमी के कारण सीमित	स्थानीय क्षेत्र के लिए विशिष्ट
प्रतिक्रिया	त्वरित प्रतिक्रिया	धीमी प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया की गति परिवर्तनशील

उल्लेखनीय ढंग से, किसी व्यापक कवरेज से जुड़ी बढ़ती हुई मानव संसाधन लागत का मतलब है कि कोई हस्तक्षेप शीघ्र ही आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाएगा। जैसा कि रोशन सरोलिया, रान रेडे के एक रेडियो निर्माता, कहते हैं, “औसत क़ानून सहायक (paralegal) एक दिन में दो गाँवों तक पहुँच सकता है, जबकि रेडियो द्वारा हम एक ही समय में 400 गाँवों तक पहुँच सकते हैं। इस प्रकार, रेडियो की लागत-कुशलता उसके मज़बूत बिन्दुओं में से एक थी।” ऊपर दी गई तालिका प्रभावी सामाजिक-क़ानूनी जागरूकता निर्माण के लिए सामुदायिक रेडियो के तुलनात्मक लाभों पर प्रकाश डालती है।

इस पृष्ठभूमि में रान रेडे हस्तक्षेप की स्थापना और उसका संचालन किया गया था। निम्नलिखित खण्ड में, हम सम्पूर्ण कार्यक्रम के कार्यक्रम सम्बन्धी और वैचारिक आधारों की गहराई से पड़ताल करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, डांग का सन्दर्भ, बल्कि समान रूप से संचार के एक माध्यम के रूप में सामुदायिक रेडियो का सन्दर्भ भी, गहराई से बताते हैं कि किस तरह रान रेडे संकल्पित, स्थापित, और संचालित किया गया था।

रान रेडे : वैचारिक आधार, परिवर्तन का सिद्धान्त, और संचालन

डांग क़ानून केन्द्र, क़ानूनी सलाह केन्द्र (Kanooni Salah Kendra—KSK) में टीम पहले से ही श्रवण माध्यम के प्रभाव से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी क्योंकि इसका उपयोग क़ानूनी जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए किया जा रहा था। इसने पहले 'क़ायदा ना दस्तूर' जैसे ऑडियो कैसेट विकसित किए थे जिन्हें सामुदायिक सदस्यों की एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। उसके साथ-साथ, टीम पूरी तरह स्थानीय निवासियों और आदिवासी समुदाय के सदस्यों से मिलकर बनी थी। अपने-आप में, यह सामुदायिक रेडियो और इसकी अनुूठी सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति से जुड़ी जटिलताओं से निपटने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। क़ानूनी सलाह केन्द्र टीम द्वारा प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव को सामाजिक न्याय केन्द्र का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। तत्पश्चात, सामुदायिक मीडिया से जुड़े एक संगठन दृष्टि (Drishti) और कच्छ महिला विकास संगठन (Kutch Mahila Vikas Sangathan—KMVS), एक संगठन जो पहले एक सामुदायिक रेडियो संचालित कर चुका था, के साथ विचार विमर्श और नीति निर्धारण किया गया। दृष्टि और कच्छ महिला विकास संगठन बृहत् रान रेडे परिवार और उनके निविष्टों (inputs) का हिस्सा बन गए, विशेष रूप से प्रशिक्षण के दौरान और तकनीकी सहायता के सन्दर्भ में, जो कि महत्वपूर्ण था। किसी रेडियो स्टेशन के संचालन से जुड़ी उच्च पूँजीगत निवेश लागतों के कारण, रान रेडे ने बदले में सूरत में ऑल इंडिया रेडियो (All India Radio—AIR) स्टेशन से अपने कार्यक्रम बन्द करने का विकल्प चुना।



रान रेडे – स्टूडियो

एक अनुवर्ती प्रक्रिया प्रदान के लिए क़ानूनी सलाह केन्द्र की क्षमता का दोहन करना रान रेडे की रणनीति के केन्द्र में था। रान रेडे की संकल्पना कभी भी किसी एकल जागरूकता कार्यक्रम के रूप में नहीं की गई थी। प्रसारण के बाद आहवा, डांग के क़ानूनी सलाह केन्द्र में ठोस कार्यवाही की गई, और रान रेडे के माध्यम से (या उसके प्रभाव के माध्यम से) पहचाने गए अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को वकीलों और क़ानून सहायकों द्वारा सँभाला गया। इस प्रकार, क़ानूनी सलाह केन्द्र न सिर्फ़ रान रेडे के विकास और संचालन में मददगार रहा, बल्कि उसे अवैधताओं पर ध्यान देने की क्षमता प्रदान कर रान रेडे को अनूठा बनाने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इस प्रकार डांग में क़ानूनी केन्द्र और उसकी विशिष्ट स्थिति का संक्षिप्त परीक्षण किया जाना प्रासंगिक होगा।

क़ानूनी केन्द्र

सामुदायिक ज़रूरतों और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किए गए एक विशिष्ट स्टाफ़ बल के साथ, सामाजिक न्याय केन्द्र के क़ानूनी केन्द्र एक अनोखे तरीके से काम करते हैं। क़ानूनी केन्द्र समुदाय और सामाजिक न्याय केन्द्र के बीच अन्तराफलक (interface) बिन्दु है। अपने-आप में, समुदाय सामाजिक न्याय केन्द्र के साथ नहीं, बल्कि क़ानूनी केन्द्र के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। उसके साथ-साथ, सामुदायिक नेतृत्व विकसित करने के सामाजिक न्याय केन्द्र के संस्थागत सिद्धान्त को ध्यान में रखा गया।

केन्द्रों का निर्माण ऐसे एक या एक से अधिक व्यक्तियों के इर्द-गिर्द किया जाता है जिन्होंने सामाजिक न्याय केन्द्र के साथ काम किया हो और जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व की सम्भावना प्रदर्शित की हो, यानी नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ अग्रणी वकील (leader-lawyers)। क़ानूनी केन्द्र अग्रणी वकील से परामर्श से बनाया जाता है, और इसकी रूपरेखा अक्सर अग्रणी-वकील की ज़रूरतें और आकांक्षाएँ ध्यान में रखते हुए निर्मित की जाती है। क़ानूनी केन्द्र एक ही समय में एक अद्भुत श्रेणी में गिने जाने योग्य पहल है, जो सामाजिक न्याय केन्द्र द्वारा निरूपित वैचारिक, सैद्धान्तिक, और क्रिया-अनुसन्धान सिद्धान्तों (action-research principles) को एकीकृत करती है, और समुदाय के साथ सम्पर्क बिन्दु होने के नाते, एक स्थानीय और स्वायत्त पहचान के साथ, तथा सामाजिक न्याय केन्द्रों और क़ानूनी केन्द्रों के ज़मीनी स्तर के पैरवी के एजेंडा को आगे ले जाने वाली एक मेसा श्रेणी (mesa category) है।

आहवा में क़ानूनी सलाह केन्द्र इसी तरह के एक ढाँचे में स्थापित किया गया था और क़ानूनी जागरूकता निर्माण के मुद्दों पर केन्द्रित था। सभी सामाजिक न्याय केन्द्रों की तरह क़ानूनी सलाह केन्द्र—डांग भी ऐसे स्वयंसेवकों, क़ानून सहायकों, और वकीलों की एक शक्तिशाली टीम के इर्द-गिर्द निर्मित गया था जो सभी डांग के थे और आदिवासी समुदाय से सरोकार रखते थे। अपने सभी हस्तक्षेपों के दौरान, क़ानूनी सलाह केन्द्र—डांग ने वरिष्ठ स्थानीय स्टाफ़ सदस्यों

को नेतृत्व का ज़िम्मा सौंपा। उदाहरण के लिए, वरिष्ठ स्वयंसेवकों को कनिष्ठ स्वयंसेवकों को सलाह और प्रशिक्षण देने का काम सौंपा गया था। यह सामाजिक और क़ानूनी परिवर्तन की प्रक्रियाओं के साम्प्रदायिक स्वामित्व के लिए सामाजिक न्याय केन्द्र की गहरी प्रतिबद्धता का एक स्वाभाविक परिणाम था। रान रेडे ने अपने निर्माण और प्रसारण में इस मूल सिद्धान्त को लागू किया, जिसमें पूरी टीम डांग के स्थानीय निवासियों और आदिवासी समुदाय के सदस्यों से मिलकर बनी थी। क्षेत्र में काम करने के क़ानूनी सलाह केन्द्र—डांग के अनुभव ने रान रेडे द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए ठोस आधार निर्मित किया, उदाहरण के लिए, जागरूकता निर्माण कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में मनोरंजन का उपयोग। टीम जानती थी कि तमाशा, यानी पारम्परिक लोक नाटक, व्यापक रूप से लोकप्रिय था और इसलिए यह क़ानूनी जागरूकता निर्मित करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम सिद्ध होगा। हालाँकि, लागत और संगठनात्मक कठिनाइयों का अर्थ था कि तमाशा संचार का एक अव्यवहारिक माध्यम था।

इसके बजाय, रान रेडे के मामले में यह सिद्धान्त स्वीकार कर लागू किया गया, जहाँ मनोरंजन और “मज़ा” कार्यक्रम का एक उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे जितने महत्वपूर्ण क़ानूनी ज्ञान और जानकारी थी। ‘तिव्रपदा ना तमाशा’ (इस पर हम बाद में लौटेंगे) जैसे शो, तिव्रपदा नामक एक काल्पनिक गाँव के बारे में एक काल्पनिक कहानी, बेहद लोकप्रिय हो गए, और समुदाय के सदस्यों को रान रेडे की तरफ़ आकर्षित करने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी।



कार्यक्रम के संचालन के दौरान ‘तिव्रपदा ना तमाशा’ इतना लोकप्रिय हो गया कि समुदाय के सदस्य अक्सर हमसे गाँव और उसकी घटनाओं के बारे में ऐसे पूछते, जैसे वह गाँव सचमुच अस्तित्व में हो।

- रोशन सरोलिया, रेडियो निर्माता, रान रेडे

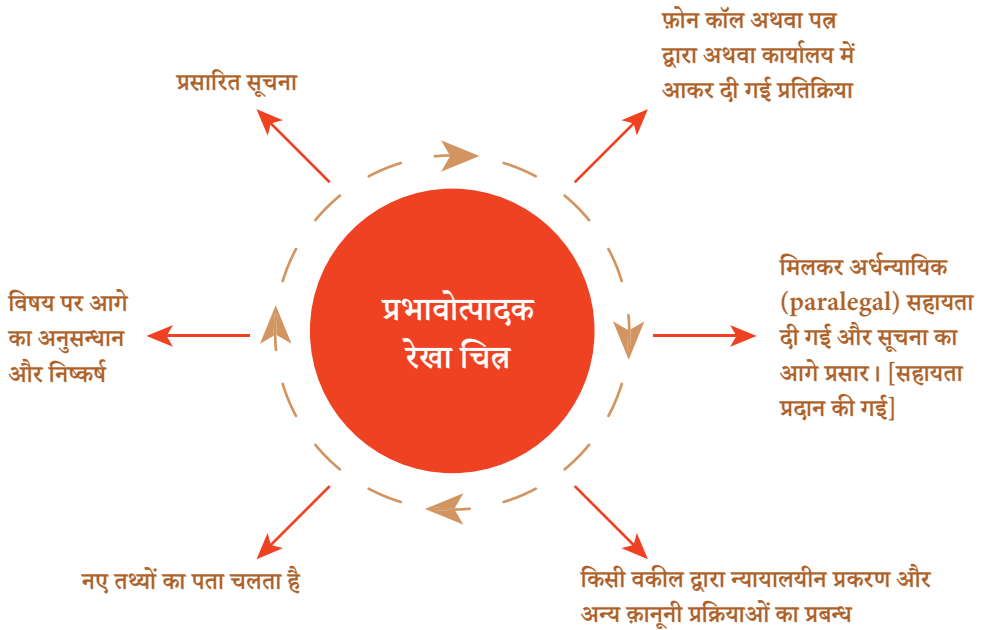


परिवर्तन का सिद्धान्त

जबकि ‘तिव्रपदा ना तमाशा’ शो किसी प्रसारण या एपिसोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, रुपरेखा के विकास में परिवर्तन का एक सिद्धान्त अन्तर्निहित था जिसने हस्तक्षेप की चक्राकार (या बल्कि, ऊपर की ओर सर्पिल) प्रकृति पर ज़ोर दिया। जैसा कि नीचे दिए गए रेखाचित्र से पता चलता है, रान रेडे एक निरन्तर प्रतिवर्ती क्रिया-अनुसन्धान प्रक्रिया (reflexive action-research process) में लगा हुआ था, जहाँ प्रत्येक प्रसारण ने स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यवाही रणनीति के लिए आधार तैयार किया, जो, परिणामस्वरूप, सूचना के

और अधिक प्रसार तथा जागरूकता बढ़ाने सम्बन्धी पहलों के लिए इनपुट का स्रोत बना और उनमें मददगार रहा। एक चक्राकार या सर्पिल ढाँचे को दो कारणों से चुना गया था। सबसे पहले, इसने प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं और कार्यवाही अनुसन्धान के लिए सामाजिक न्याय केन्द्रों की खुद की संगठनात्मक प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित किया (सामाजिक न्याय केन्द्रों का स्वयं का परिवर्तन का सिद्धान्त भी ऊपर की ओर एक सर्पिल आकार बनाता है)। दूसरा, एक चक्राकार रूपरेखा का अर्थ था कि हस्तक्षेप आत्मनिर्भर था। आवधिक बाहरी इनपुट या निवेश की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि, प्रसारण के प्रयोग और अन्याय पर प्रतिक्रिया के माध्यम से, नए मुद्दे उठे और बाद में सम्बोधित किए गए। सम्पूर्ण ढाँचा दो प्रमुख मुद्दों पर केन्द्रित था : सार्वजनिक प्रकटीकरण और खोजी पत्रकारिता में निवेश, और इन पर निरन्तर ध्यान केन्द्रित करते हुए क़ानूनी एवं सांस्कृतिक जागरूकता का विकास और प्रशासनिक प्रणालियों के परिवर्तन। नीचे दिए गए रेखाचित्र में परिवर्तन के इस सिद्धान्त को दर्शाया गया है।

प्रभावोत्पादक रेखा चित्र :



आधार-रेखा सर्वेक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा

यदि सामुदायिक रेडियो उस समुदाय की आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं है जिससे यह उभरकर आता है तो यह एक निरर्थक और अप्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। इसे स्वीकार करते हुए, रान रेडे के संचालन की दिशा में पहले क़दम में नवसारी ज़िले के डांग और

वंसदा ब्लॉक में 90 गाँवों और 1,780 परिवारों का एक व्यापक आधार-रेखा सर्वेक्षण (baseline survey) शामिल था। सर्वेक्षण का उद्देश्य ऐसी लोककथाओं, लोक संगीत, कहानियों, अनुभवों, और विचारों की पहचान करना था जिन्हें एक रेडियो कार्यक्रम के रूप में विकसित किया जा सके। पहचान की इस प्रक्रिया के बाद समेकन और उसके बाद समुदाय के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन किया गया, जिसके बाद ही कार्यक्रम की सामग्री को अन्तिम रूप दिया गया।

क्रानूनी सलाह केन्द्र-डांग टीम ने 40 स्वयंसेवकों के साथ इन गाँवों के सांस्कृतिक इतिहास का दस्तावेज़ीकरण करने के लिए आधार-रेखा सर्वेक्षण किया। पाँच उप-इकाइयाँ बनाई गईं, और प्रत्येक इकाई ने निम्नलिखित पहलुओं पर गौर किया :

- तमाशा दल
- लोक संगीत और स्थानीय वाद्य यंत्र
- स्थानीय लोक कलाकार
- टकराव के समाधान की पारम्परिक प्रक्रियाएँ
- श्रोताओं की सम्भावित विविधताएँ
- रेडियो के माध्यम से उपभोग किए जाने वाले मीडिया के प्रकार, जैसे-समाचार, संगीत
- भाषाई प्राथमिकताएँ
- समुदाय के सदस्य क्या सुनना चाहते हैं इस आधार पर आवश्यकता का आकलन
- रेडियो श्रोताओं की लिंग-आधारित गतिकी, जैसे-महिलाओं की रेडियो तक पहुँच कब और कहाँ थी
- तकनीकी विवरण, जैसे-रेडियो रिसेप्शन और सिग्नल तीव्रता।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने वह सबसे महत्वपूर्ण भाग तैयार किया जिसके आसपास रान रेडे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत से पता चला कि पूरी तरह से क्रानूनी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना उन्हें प्रासंगिक या मददगार नहीं लगता। हालाँकि, चूँकि रान रेडे बुनियादी रूप से सामाजिक-क्रानूनी परिवर्तन की दिशा में उन्मुख था, इसने अपने बृहत् मिशन के दायरे में समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया। इसलिए, रान रेडे कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित क्रानूनी बिन्दुओं की पहचान की गई :

6. बुनियादी मानवाधिकार और मौलिक अधिकार
7. पुलिस, पुलिस की शक्तियों, पुलिस द्वारा शोषण के खिलाफ अधिकारों और अपराधिक प्रक्रियाओं की जानकारी की भूमिका
8. संदिग्ध व्यक्तियों की खोज

9. वन विभाग की पुलिस और / या अधिकारियों / पहरदारों द्वारा किए गए अत्याचार
10. घरेलू हिंसा, बलात्कार, लैंगिक हिंसा, पैतृक और / या वैवाहिक सम्पत्ति के अधिकारों, और बच्चों की अभिरक्षा के अधिकार सहित महिलाओं के अधिकार जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फ़ॉर्मस् ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वीमेन (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women—CEDAW) के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए
11. न्यायालय और राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रक्रियाएँ और संरचनाएँ
12. वन निवासियों के अधिकार और उनके विषय में वन प्रशासन और सरकारी विभाग
13. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1993 का क्रियान्वयन, और ग्राम सभाओं का पुनः सक्रियण
14. राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (National Food for Work Programme—NFWP) के खराब क्रियान्वयन से उत्पन्न आपदा से निपटने की तैयारी और प्रबन्धन

जबकि यह प्रमुख क़ानूनी मुद्दों के उद्भव पर प्रकाश डालते हैं, रान रेडे केवल इन्हीं पर निर्भर नहीं रहा। अनेक सामाजिक प्रथाओं जैसे—जुआ, शराब की लत, महिलाओं के अधिकारों का हनन, और कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता / अधिकारों में धोखा देने को भी एक अधिकार-आधारित परिप्रेक्ष्य के माध्यम से सम्बोधित किया गया। ऐसा ही एक उदाहरण मटका जुआ की जानकारी देना था। यहाँ दो परस्पर-सम्बद्ध क्षेत्रों—सांस्कृतिक प्रथा और क़ानूनी मुद्दों के बारे में जानकारी की पहचान करने पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करना था। इसलिए, रान रेडे ने अपने कार्यक्रमों के लिए एक रूपरेखा विकसित की जिसने समुदाय के हितों और सांस्कृतिक एकजुटता को निर्बाध रूप से क़ानूनी जागरूकता और पहुँच के साथ मिला दिया।

आधार-रेखा सर्वेक्षण के निष्कर्षों का मूल्यांकन रान रेडे के मुख्य केन्द्र बिन्दु को ध्यान में रखते हुए किया गया था, यानी, सांस्कृतिक और क़ानूनी हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रासंगिकता सुनिश्चित करना, और उसके बाद पाँच खण्डों वाले रेडियो कार्यक्रम के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई थी। यह रूपरेखा, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है, समुदाय के सदस्यों के आदानों (inputs) के आधार पर परिशोधन और संशोधन की एक प्रक्रिया से गुज़री। अन्ततः, प्रत्येक खण्ड के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित करते हुए पाँचों खण्डों को समायोजित किया गया। यह खण्ड थे :

1. **ऐ कर** (सूचनात्मक) : कार्यक्रम का यह पहला खण्ड सूचना का प्रसार करने के लिए तैयार किया गया था। नए क़ानून (या मौजूदा क़ानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन) और

सरकारी कल्याणकारी पात्रताओं के बारे में जानकारी पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से साक्षात्कार के माध्यम से संचालित, इस खण्ड ने कार्यक्रम के दौरान क़ानूनी जागरूकता निर्माण के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य किया।

2. **धाराई ग्यास** (खोजी पत्रकारिता) : धाराई ग्यास (शाब्दिक रूप से “ग्रहण किया गया” के रूप में अनुवादित) रान रेडे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसने सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध कार्यों या चूक के कृत्यों पर ध्यान केन्द्रित किया, जिसके फलस्वरूप यह किसी भी सामुदायिक रेडियो का एक केन्द्रीय सिद्धान्त बन गया—प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता कायम करना और इनकी माँग करना। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार, कल्याणकारी पात्रताओं और सरकारी सेवाओं को प्रदान करने से इंकार करने के मामलों, और भ्रष्टाचार एवं कुशासन के उदाहरणों को उजागर किया गया और एक अधिकार-आधारित ढाँचे के भीतर से उन पर ज़ोर दिया गया। इसने निवारण के लिए एक प्रक्रिया उपलब्ध कराई, जिसे क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा के माध्यम से माँगा जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप, ज़िला प्रशासन की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए दबाव बढ़ गया।
3. **बारिक आश** (मामले की कहानी) : पिछले खण्ड में सरकारी फ़िज़ूलखर्चों और शक्ति के दुरुपयोग के प्रसारण के चौंकाने वाले विवरणों के बाद यह कहानियाँ प्रस्तुत की गईं कि कैसे समुदाय के सदस्यों ने उनके खिलाफ़ किए गए ग़लत कामों और अन्याय के निवारण के लिए काम किया था। इस खण्ड की कहानियों में विस्तारपूर्वक सारे पहलुओं को शामिल किया गया, जिनमें दैनिक वेतन भोगी लोगों द्वारा नियमित वेतन की माँग से लेकर स्थानीय महिलाओं के समूहों द्वारा अपने गाँव तक एक बस मार्ग का विस्तार करने के लिए परिवहन एजेंसियों को याचिका देने की कार्यवाही तक शामिल है। इस खण्ड ने उदासीनता एवं नकारात्मकता के वातावरण को दूर करने और राज्य द्वारा लगातार व बेरहम उत्पीड़न के कारण महसूस की जाने वाली बेबसी की भावना का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उन प्रक्रियाओं, रणनीतियों, और दृष्टिकोणों को साझा किया और उन पर प्रकाश डाला, जिनका दायित्व सामाजिक परिवर्तन के लिए समुदाय के सदस्यों द्वारा स्वयं लिया गया था और लिया जा सकता है।
4. **तिव्रपदा ना तमाशा** (काल्पनिक मनोरंजन) : रान रेडे की रूपरेखा सूचना प्रसार के प्रासंगिक रूपों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी जिसमें काल्पनिक थिएटर और कहानियों (तमाशा) के माध्यम से मनोरंजन ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई थी। इसे पहचानते हुए, एक खण्ड शामिल किया गया, जिसने त्रिपदा के काल्पनिक गाँव की कहानी बताई। गाँव एक भ्रष्ट सरपंच द्वारा संचालित किया जाता था, और कहानियाँ पात्रों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती थीं, जिनमें शामिल थे एक शिक्षित शहरी युवक, एक युवा अशिक्षित ग्रामीण लड़का, एक युवा लड़की जिसमें “क्रान्तिकारी” उत्साह था, एक रेडियो रिपोर्टर, और वर्णनकर्ता के रूप में एक कौवा। कार्यक्रम ने न केवल एक मनोरंजक कहानी प्रस्तुत की, बल्कि इसकी सामग्री ने एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी सन्देश भी लोगों तक पहुँचाया। उदाहरण के लिए, यह गाँव का लड़का था जो हमेशा अभिनव समाधानों और उत्तरों के साथ आता था, कुछ ऐसा जो पारम्परिक रूप से शिक्षित शहरी वर्गों के लिए सुरक्षित रखा गया माना जाता है। इसी तरह, युवा लड़की ने लिंग-आधारित रुढ़ियों को तोड़ने की कोशिश की और कठोर लैंगिक भूमिकाओं पर सवाल उठाए। सरकारी कल्याणकारी पात्रताओं, मौलिक अधिकारों, और क़ानूनी अधिकारों को अक्सर त्रिपदा में होने वाली घटनाओं का मूल आधार बनाया गया।

5. **निरोप** (पहुँच और पत्र) : सामुदायिक स्वामित्व रान रेडे का एक केन्द्रीय सिद्धान्त था, जो इसकी रूपरेखा और सामग्री दोनों में प्रतिबिम्बित होता था। इस अन्तिम खण्ड ने एक त्वरित पूछताछ-प्रतिक्रिया प्रणाली को अपनाने के साथ-साथ सामूहिक स्वामित्व की धारणा का समर्थन किया। रेडियो प्रसारकों ने समुदाय से प्राप्त पत्रों को पढ़ा एवं उन पर चर्चा की और यदि कोई क़ानूनी प्रश्न पूछे गए हों तो उनके जवाब दिए।

स्वतंत्र रूप से, इन खण्डों ने कई उद्देश्य पूर्ण किए। लेकिन उनकी विशिष्ट व्यवस्था ने रान रेडे के परिवर्तन के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने का काम किया। पहले खण्ड ने किसी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके बाद के खण्ड ने इन अधिकारों के उल्लंघन की पहचान की। अगले खण्ड ने इन उल्लंघनों को सम्बोधित करने के तरीकों और रणनीतियों को स्पष्ट किया। काल्पनिक खण्ड ने एक पारम्परिक सांस्कृतिक माध्यम से सामाजिक-क़ानूनी मुद्दों को सम्बोधित करते हुए मनोरंजन प्रदान किया। अन्तिम खण्ड ने न केवल अधिक संवाद की अनुमति दी, बल्कि एक आधार भी प्रदान किया, जिस पर क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा के लिए कार्यवाही की रणनीति तैयार की गई।

रान रेडे टीम का डांग में रिकॉर्डिंग स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस, और प्रशासनिक केन्द्र ढूँढ़ने का निर्णय भी उतना ही महत्वपूर्ण था। सम्पूर्ण कार्यालय, स्टूडियो, और सम्पादन कक्ष स्थानीय सामग्रियों से बनाए गए थे और इसके लिए निर्माण के स्थानीय तौर-तरीकों का उपयोग किया गया था। यह कार्यक्रम के स्वामित्व की भावना को बढ़ाने और बढ़ी हुई भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक साभिप्राय प्रयास था। इसने एक यह महत्वपूर्ण सन्देश भी लोगों तक भेजा, कि रान रेडे ने पारम्परिक सांस्कृतिक प्रथा और ज्ञान के महत्व को व्यक्त किया और

उसका सम्मान किया। किसी ध्वनिरोधी रिकॉर्डिंग स्टूडियो (soundproofed recording studio) के निर्माण के लिए स्थानीय सामग्रियों के उपयोग ने स्थानीय स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों की उपयुक्तता और पर्याप्तता का संकेत दिया जिसे निम्न दर्जे और बेकार समझने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी।

संचालन

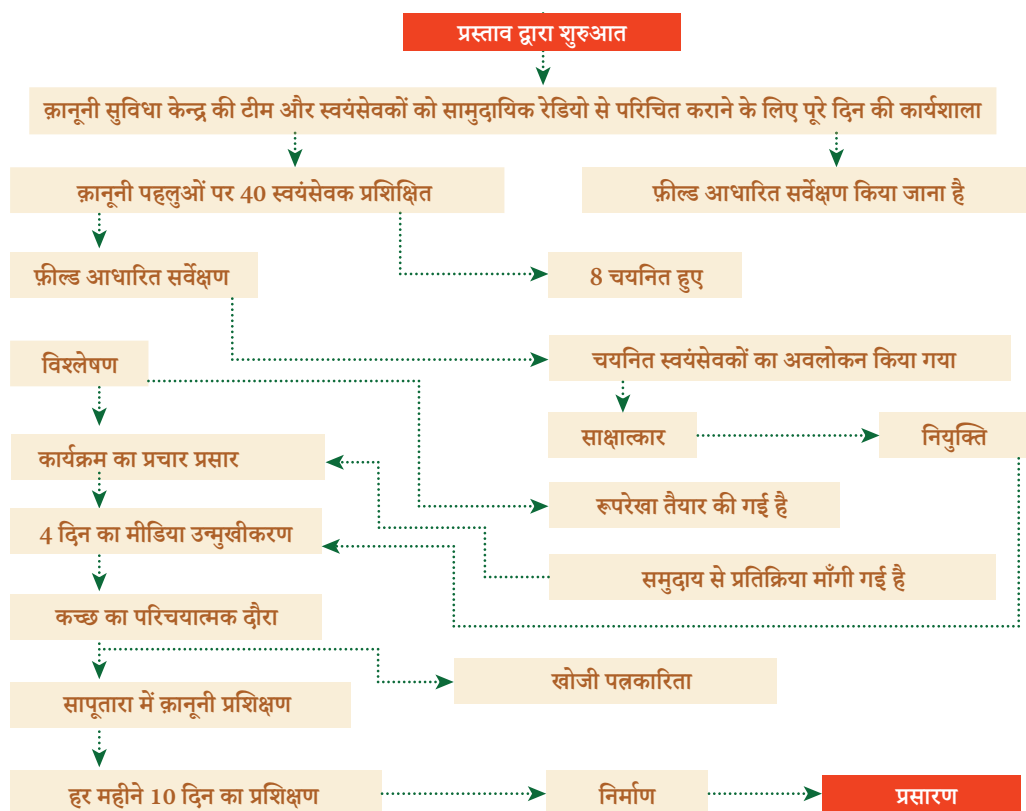


हमारे भीतर एक आग जल गई थी और यह वह आग थी जिसने चीज़ों को गतिशील बनाए रखा। हम सभी को एक साथ एक छतरी के नीचे लाकर डांग को उसकी निष्क्रियता से जगाना चाहते थे।

- जगन पटेल, रेडियो निर्माता, रान रेडे



अपनी महत्वाकांक्षी रूपरेखा और एजेंडा को देखते हुए, इसके संचालन में रान रेडे द्वारा महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया जाना निश्चित था। एक समर्पित टीम की पहचान की गई, और एक व्यवस्थित संचालन योजना तैयार की गई। इस योजना को सुचित्रित रूप से नीचे दर्शाया गया है :



फ़्लोचार्ट:

क्रियान्वयन में चुनौतियाँ और बाधाएँ

डांग के सामाजिक, भौगोलिक, और राजनीतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए, टीम पूरी तरह से अवगत थी कि रान रेडे के क्रियान्वयन में अनिवार्य रूप से बड़ी चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, भविष्य में सामने आने वाली स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय केन्द्र, दृष्टि, और कच़्छ महिला विकास संगठन के प्रशिक्षकों एवं समन्वयकों की टीम उपयुक्त रूप से तैयार की गई। जबकि, रेडियो निर्माण और प्रसारण की जटिलताओं के कारण तकनीकी समस्याओं का अनुमान लगाना आसान था, रान रेडे के निर्माताओं, पत्रकारों, और स्वयंसेवकों के बीच विश्वास और नेतृत्व का निर्माण करने में,

शुरुआती दौर में टीम को वास्तव में संघर्ष करना पड़ा। एक और गम्भीर बाधा कुछ भागों से आने वाली शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया थी। रान रेडे के अनोखे सामाजिक-क़ानूनी जागरूकता निर्माण और कार्यवाही अनुसन्धान में शामिल होने के प्रयासों से निहित स्वार्थ वाले स्थानीय लोगों को परेशानी हुई और स्थानीय शक्ति की गतिशीलता बाधित हुई, जिसके परिणामस्वरूप इसकी उपस्थिति और गतिविधियों के विरुद्ध आक्रामक प्रतिक्रियाएँ हुईं।

रान रेडे टीम के सामने आई चुनौतियों को चार श्रेणियों में रखा जा सकता है। यह कठिनाइयाँ और समस्याएँ न तो अलग-थलग हैं, और न ही थीं, और प्रत्येक श्रेणी के तत्त्वों ने अन्य श्रेणियों के तत्त्वों पर परस्पर प्रभाव डाला।

- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- तकनीकी और व्यवस्थागत (logistics) मुद्दे
- निहित स्वार्थ वाले समूहों की ओर से सुधार विरोधी प्रतिक्रिया
- अन्तर्वैयक्तिक टकराव

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

जबकि टीम के सदस्यों को रेडियो उपकरण और सम्पादन सॉफ्टवेयर के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान करने पर पर्याप्त समय लगाया गया था, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य था अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से और आदिवासी पहचान (जो एक क्रूर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का लक्ष्य बना हुआ है) के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित करते हुए मुद्दों के समाधान के लिए निर्माताओं, संवाददाताओं, और स्वयंसेवकों की टीम की क्षमता का निर्माण करना। रान रेडे कार्यक्रम की रुपरेखा का अर्थ प्रभावी स्थानीय पत्रकारिता को एक आदत और तरीके के रूप में टीम में विकसित करना था। यह एक चुनौती साबित हुई क्योंकि टीम और प्रशिक्षकों ने प्रभावी संचार कौशल प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, स्पष्ट रूप से बोलने और सार्थक रूप से तथा आत्मविश्वास के साथ अपनी अभिव्यक्ति में उन्हें कठिनाई महसूस हो रही थी।



शुरु में, मुझे एक कहानी को कवर करने में तीन से चार घण्टे लगते थे। लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ, मैं यही काम केवल आधे घण्टे में ही करने लगा।

- सांतु गायकवाड़, रेडियो निर्माता, रान रेडे



इसी तरह, अधिकारों के बारे में एक दृष्टिकोण का विकास और क़ानूनी ज्ञान की प्राप्ति महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थीं, और सामाजिक न्याय केन्द्र और क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा द्वारा क़ानूनी क्षमता निर्मित करने और एक चरणबद्ध तरीक़े से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित योजना निर्मित कर स्थापित की गई थी।

प्रशिक्षण की ज़रूरतों में लगातार बदलाव आया और अक्सर इसे हर रोज़ परिवर्तित किया गया। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रयासों के साथ-साथ, रेडियो स्थापित करने और समस्त संचालन के निरीक्षण के लिए तैयारी और ज़मीनी कार्य बेरोकटोक जारी रहे।



हमने दिन के समय प्रशिक्षण लिया और शाम के समय देर तक काम किया। इस तरह हमने समय की कमी की बाधा पर नियंत्रण पाया और सुनिश्चित किया कि परियोजना समय पर शुरू हो जाए।

रमेश धूम, रेडियो निर्माता, रान रेडे



प्रतिभागियों के बीच विश्वास निर्माण की प्रक्रिया में, मैंने लगातार अपना विश्वास निर्मित किया। प्रत्येक स्तर पर, उनके सवाल यही रहे, “क्या ऐसा होगा? क्या हम यह कर सकते हैं?”

मेहुल मकवाना, मीडिया प्रशिक्षक, दृष्टि



तकनीकी और व्यवस्थागत (logistics) मुद्दे

रेडियो उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास करना रान रेडे टीम के लिए एक चुनौती थी। सम्पादन और एपिसोड निर्माण के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण पर बहुत अधिक मात्रा में समय और प्रयास लगे। दृष्टि के सदस्यों ने लगातार प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की। महत्वपूर्ण खामियों या उन स्थानों की पहचान करने के लिए कच्छ में कच्छ महिला विकास संगठन के सामुदायिक रेडियो के संचालन के अनुभव का लाभ उठाया गया जहाँ ठोस तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं के साथ-साथ रान रेडे टीम के

सदस्यों की पृष्ठभूमि के कारण, कम्प्यूटर दक्षता और तकनीकी कौशल विकसित करने में समय लगा।



अपने जीवन में पहली बार मैंने एक कम्प्यूटर देखा। मुझे लगा कि यह एक टेलीविज़न सेट है। लेकिन जल्दी ही मैंने जाना कि इसे कैसे संचालित करते हैं और आज जब मैं कम्प्यूटर डेस्क पर बैठती हूँ और अपने रेडियो के लिए एक पूरा एपिसोड सम्पादित करती हूँ तो मुझे अपने ऊपर गर्व होता है।

सुनीता बागुल, रेडियो निर्माता, रान रेडे



इस तरह की समस्याओं के साथ, व्यवस्थागत (logistics) चिन्ताओं ने रान रेडे को शुरु से ही डरा दिया। पहले, डांग में कठिन इलाक़े का मतलब था कि रेडियो प्रसारण का फैलाव सीमित एवं कमज़ोर था और इसमें अकसर समस्याओं का सामना करना पड़ता था। रान रेडे का प्रसारण सूरत के एक रेडियो स्टेशन से किया जाता था। इसका अर्थ था कि कुछ क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाक़ों की वजह से, रेडियो रिसेप्शन रुक-रुक कर हो रहा था। दूसरा, मौसम जटिलता पैदा करने वाला एक और कारक था। भारी वर्षा की अवधि में, विशेष रूप से वार्षिक मानसून के दौरान, रेडियो रिसेप्शन की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती थी, जिससे प्रसारण मुश्किल हो जाता था। आखिरकार, रान रेडे टीम को बड़ी व्यवस्थागत समस्याओं से जूझना पड़ा था। रेडियो कार्यक्रम डांग में निर्मित होने और उनका प्रसारण सूरत से होने के कारण, टीम ने तैयार किए कार्यक्रम को प्रसारण के लिए सूरत स्टेशन पहुँचाने की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष किया।

निहित स्वार्थ समूहों की प्रतिक्रियाएँ

जिन मुद्दों पर रान रेडे कार्य कर रहा था, उनकी प्रकृति और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले संवाद, अनिवार्य रूप से स्थानीय सत्ता गतिकी में खलबली पैदा करते हैं। स्थानीय माफ़िया, ज़िला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, और रान रेडे द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली सामाजिक-क्रान्ती सक्रियता ने स्थानीय सूक्ष्म-राजनीतिक शक्तियों को हक्का-बक्का कर दिया। इन समूहों की तरफ़ से सुधार विरोधी प्रतिक्रियाएँ अपेक्षित थीं, और वह प्रत्याशित रूप से सामने आईं। टीम ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, आदि की घटनाओं को उजागर किया और खोजकर लाई गई इन जानकारीयों के प्रसारण ने एक गम्भीर प्रतिक्रिया भड़का दी। एक उदाहरण में, रान रेडे द्वारा स्थानीय जुआ व्यवसाय में धोखाधड़ी और संगठित अपराध पर की गई जाँच-पड़ताल को लेकर इस गोरखधन्धे में लिप्त समूहों के सदस्यों द्वारा रान रेडे के एक निर्माता जगन पर हमला किया गया था। शुरुआती चरणों में, ज़िला प्रशासन और अन्य सरकारी

निकायों के साथ संवाद करना मुश्किल था। यह आंशिक रूप से रान रेडे की बदलाव लाने की क्षमता के कारण था। सरकारी अधिकारी इसकी शक्ति से सावधान थे और इसलिए उन्होंने इससे दूरी बनाए रखना ठीक समझा।



पहले चरण के दौरान सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं के साक्षात्कार लेना एक समस्या थी। वे हमसे बात करने के काफ़ी ख़िलाफ़ थे। लेकिन अब ज़्यादा समय तक वे हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते।

- दिलीप गायेन, रेडियो निर्माता, रान रेडे



अन्तर्वैयक्तिक टकराव

एक कार्यक्रम के रूप में रान रेडे का सामूहिक स्वामित्व था। इसका अर्थ यह था कि इसमें कठोर पदानुक्रम मौजूद नहीं थे जो आमतौर पर अधिकांश अन्य प्रयासों को निर्धारित करते हैं, यहाँ तक कि सामाजिक-कानूनी क्षेत्र के भीतर भी। हालाँकि, इसके ज़बरदस्त फ़ायदे रहे हैं (जिनमें से कई के बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है), इसका अर्थ यह भी है कि ज़िम्मेदारियों, भूमिकाओं, कर्तव्यों, और, सबसे महत्वपूर्ण बात, सीमाओं पर बातचीत लगातार जारी थी। रान रेडे की संरचना में आन्तरिक रूप से अन्तर्वैयक्तिक टकराव की सम्भावना थी, मुख्य रूप से अहंकारों का टकराव और स्व-निर्दिष्ट महत्त्व से उत्पन्न होने वाले टकराव। इसे पूरी तरह से टालने के लिए पद्धतियाँ या प्रक्रियाएँ निर्धारित करने में बहुत अधिक समय लगाने के बजाय, रान रेडे टीम ने इन टकरावों को एक सामुदायिक स्वामित्व वाले कार्यक्रम के एक केन्द्रीय, और अपरिहार्य हिस्से के रूप में मान्यता दी। इस वास्तविकता के इर्द-गिर्द एक कारगर प्रक्रिया विकसित करना मुख्य चुनौती थी।

पैमाना, सामग्री, और पहुँच

अपने चरम पर, रान रेडे के एक लाख से अधिक सुनने वाले व्यक्ति थे। हालाँकि, स्वयं के स्वामित्व में कोई रेडियो स्टेशन नहीं होना और अन्य स्टेशन पर सिर्फ़ प्रसारण अधिकार रखने का अर्थ था कि रान रेडे उस स्टेशन की इच्छानुसार शेड्यूलिंग के अधीन था। श्रोतागण पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि अधिकतम श्रोताओं तक पहुँचने के उद्देश्य से रान रेडे के कार्यक्रम विशेष समय पर प्रसारित करने की रूपरेखा निर्धारित की गई थी। कार्यक्रम शाम 6.00 से 7.00 बजे तक प्रसारित किया जाता था। इस स्लॉट को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसमें अधिकतम महिलाएँ कार्यक्रम सुन सकती थीं। शाम 6.00 बजे तक, महिलाएँ खेतों में और घर पर अपना काम पूरा कर चुकी होती थीं और रेडियो सुनने के लिए एक समूह

के रूप में गाँव में एक केन्द्रीय स्थान पर इकट्ठा होने की स्थिति में होती थीं। हालाँकि, शेड्यूलिंग में परिवर्तनों के साथ, यह फ़ायदा उपलब्ध नहीं रहा। इसी तरह, समय के साथ, टेलीविज़न पर व्यावसायिक रेडियो और व्यावसायिक कार्यक्रमों की बाढ़ का अर्थ था कि रान रेडे को बढ़ती हुई “प्रतिस्पर्धा” का सामना करना पड़ा और एक श्रोता आधार के लिए होड़ करने पर बाध्य होना पड़ा जो व्यावसायिक रेडियो, व्यावसायिक टेलीविज़न, और सामुदायिक रेडियो के बीच तेज़ी से विभाजित हो रहा था।

अपने चरम पर, रान रेडे 400 से अधिक गाँवों में पहुँच गया। इसमें वलसाड, नवसारी, सूरत, नर्मदा, और तापी ज़िलों के कई गाँवों के साथ डांग के सभी 311 गाँव शामिल थे। सीमा के उस पार, महाराष्ट्र राज्य में, डांग की सीमा से लगे गाँवों को भी यह प्रसारण प्राप्त हुए, और चूँकि इन सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा एक ही भाषा बोली जाती थी, इसलिए रान रेडे का परिवर्तनकारी सन्देश इन गाँवों के निवासियों तक भी पहुँचा।



कार्यक्रम की सामग्री ऐसी थी जिसने प्रासंगिक ज़रूरतों, सामयिक मुद्दों, और उभरती चिन्ताओं पर प्रतिक्रिया दी। उदाहरण के लिए, गर्मियों के महीनों के दौरान एक मुद्दे के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (National Rural Employment Guarantee Act—NREGA), 2005 को लिया गया था, क्योंकि तब राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम कार्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, चूँकि कृषि भूमि फ़सल चक्रों के बीच के दौर में होती है। इसी तरह, दीवाली और होली के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की खोज की घटनाएँ

बढ़ती हैं, और इसलिए इस अवधि के दौरान कार्यक्रम में इस मुद्दे पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है। एक वार्षिक उत्सव, डांग दरबार, से ठीक पहले के प्रसारण दरबार पर केन्द्रित रहते हैं और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले अन्य खण्डों की संख्या कम कर दी गई। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे प्रसंगों पर भी इस तरह के विशेष कार्यक्रम बनाए गए थे। यहाँ तक कि काल्पनिक खण्ड 'तिव्रपदा ना तमाशा' को स्थानीय अस्थाई सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था। आधार-रेखा सर्वेक्षण और रान रेडे टीम के अनुभवों ने इस तरह का ढाँचा विकसित करने और समय- या मौसम-विशिष्ट मुद्दों, विषयों-वस्तुओं, और प्रसंगों की पहचान करने में मदद की।



रान रेडे—ग्राम भ्रमण

रान रेडे की प्रभावोत्पादकता का केन्द्र गाँवों में श्रोता समूहों का निर्माण था जो एक साथ आते थे और निर्धारित समय पर कार्यक्रम सुनते थे। श्रोता समूहों को रान रेडे टीमों के सदस्यों और स्वयंसेवकों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती थी और मध्यस्थता की जाती थी। यह समूह रान रेडे के परिवर्तन के सिद्धान्त के चक्राकार ढाँचे की पूर्णता के केन्द्र बिन्दु थे। मुख्य रूप से (हालाँकि विशेष रूप से नहीं) इन श्रोता समूहों के माध्यम से यह सम्भव हुआ कि अन्याय के मामले सामने आए, जिन पर क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा द्वारा आगे कार्यवाही की जा सकी। प्रत्येक श्रोता समूह में सुविधाप्रदाताओं और मध्यस्थों को प्रसारण की सामग्री के बारे में पहले ही जानकारी दे दी जाती थी और वे प्रश्नों की तैयार सूची के साथ सुनवाई सत्र में पहुँचते थे। प्रसारण समाप्त होने के बाद, उनके द्वारा यह प्रश्न पूछे जाते और प्रसारण की सामग्री पर एक चर्चा आयोजित की जाती थी। इन चर्चाओं के माध्यम से, अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की पहचान की गई, और फिर वहीं उसी समय या तो विशिष्ट सलाह प्रदान की गई अथवा क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा के सदस्यों से सम्पर्क किया गया, जो मामलों में आगे कार्यवाही करते थे। श्रोता समूहों के बिना, रेडियो कोई एकल आयामी माध्यम होता, जिसमें कोई प्रभावी

स्थानीय भागीदारी नहीं होती और ग़लतियों के निवारण की कोई गुंजाइश नहीं होती। रान रेडे को एक संवादात्मक, प्रतिवर्ती प्रक्रिया के रूप में विकसित करने में इन समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



गुरुवार को हम सब मिलते हैं और रेडियो सुनते हैं। यह हमारे लिए प्रसारित किया जा रहा है और दी जा रही जानकारी काफ़ी उपयोगी है। इसने हमारे गाँव में कड़ियों की ज़िन्दगी बदल दी है।

- प्रतिनिधि, महिला समूह, हलमुंडी गाँव (फ़ोन के माध्यम से)



प्रभाव : ऐतिहासिक और निरन्तर

सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन पर केन्द्रित किसी कार्यक्रम के प्रभाव का मात्रात्मक रूप से आकलन करना अकसर मुश्किल होता है जो एक प्रमुख रणनीति के रूप में क़ानून के सहारे का उपयोग करता है। इस तरह के कार्यक्रमों द्वारा लाए गए परिवर्तन मोटेतौर पर अप्रत्यक्ष होते हैं और कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के बाद लम्बे समय तक जारी रहते हैं। और रान रेडे के साथ यही हुआ है। प्रभाव मुख्यतः गुणात्मक हैं और अधिकांश भाग में तरीक़ों में उन बदलावों से सम्बन्धित हैं जिन तरीक़ों से समुदाय के सदस्य स्वयं से, एक दूसरे से, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से राज्य से सम्बन्धित होते हैं। इस कारण से, हमने चार प्रमुख सम्बन्धपरक क्षेत्रों में रान रेडे के प्रभाव की रूपरेखा नीचे दी है : व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय, और राज्य।

व्यक्तिगत

रेडियो निर्माता, रिपोर्टर, और रान रेडे टीम के स्वयंसेवक अपने समुदायों के भीतर शक्तिशाली परिवर्तनकर्ता बन जाते हैं। महत्वपूर्ण नेतृत्व और संचार कौशल विकसित करने, विशेष रूप से जटिल मुद्दों को स्पष्ट करने और प्रभावी ढंग से समझाने की उनकी क्षमता को पैना करने से, उन्हें अपने प्रभाव को बढ़ाने और अपने समुदायों के भीतर अपनी हैसियत बढ़ाने में मदद मिलती है। वे इस हैसियत का उपयोग अधिकारों के एक दृष्टिकोण और आदिवासी पहचान के सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण तथा आदिवासी स्थिति का एक बहुअक्षीय उत्पीड़न के रूप में प्रचार करने के लिए करते हैं। आज तक, वे प्रभावशाली सामुदायिक अगुआ बने हुए हैं और उन्होंने न केवल समुदाय के भीतर और सामुदायिक प्रथा के क्षेत्र में, बल्कि कई सरकारी

निकायों और नागरिक समाज संगठनों में नेतृत्व के पदों को भी सँभाला है। उदाहरण के लिए, रान रेडे की एक रेडियो निर्माता मंगलाबेन पवार निर्गुणमद गाँव में अपने काम के माध्यम से क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा के साथ सक्रिय बनी हुई हैं।

मैं इतनी शर्मीली थी कि पाँच लोगों के एक समूह का सामना करना अकसर मेरे रोंगटे खड़े कर देता था। लेकिन आज मैं प्रभावशाली तरीक़े से किसी भी गाँव में एक समूह चर्चा का प्रबन्ध कर लेती हूँ।

मंगलाबेन पवार, रेडियो निर्माता, रान रेडे

रान रेडे टीम के सदस्यों के रूप में, समुदाय के सदस्यों ने सरकारी अधिकारियों का सामना करने और उन्हें चुनौती देने के साथ-साथ साक्षात्कार आयोजित करने, चर्चाओं की रूपरेखा तय करने, और ग्राम सभाओं तथा दौरो के आयोजन जैसे व्यवहारिक कौशल (soft skills) विकसित करने में आत्मविश्वास अर्जित किया। रान रेडे की एक रेडियो निर्माता, सविता राठौड़, ने पुलिस के साथ मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज की चोरी का पर्दाफ़ाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सुनिश्चित किया कि उचित क़ानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

मैंने साक्षात्कार लेने की शैली सीखी कि कैसे शुरुआत करनी है और बातचीत से कैसे किसी उद्देश्य को सामने लाना है। शुरुआत में, मैं जो पूछती थी बस प्रश्नों का एक सेट भर होता था, लेकिन कुछेक कहानियों के बाद चीज़ें बदलीं और मैंने उसकी ख़ासियतों को जाना।

सविता राठौड़, रेडियो निर्माता, रान रेडे

परिवार और समुदाय

व्यक्तिगत परिवर्तन परिवार और समुदाय के भीतर परिवर्तन लाने वाली शक्ति है। रान रेडे की प्रभावी अनुवर्ती प्रक्रियाओं के साथ-साथ इसके कार्यक्रम के प्रारूप का अर्थ था कि प्रसारण स्वयं सामुदायिक या सन्तानोचित कार्यवाही (filial action) के लिए प्रेरणा का एक स्रोत

था। उदाहरण के लिए, रान रेडे प्रसारण सुनने के बाद संगीता धूम ने, अपने पति और ससुराल वालों के हाथों हुई घरेलू हिंसा को सम्बोधित करने के लिए क़ानूनी सलाह केन्द्र से सम्पर्क किया, और क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा की सहायता से उसका उसके पति के परिवार के साथ समझौता हुआ। इसी तरह, रान रेडे से प्रेरित होने के बाद, माली गाँव की उर्मिला पवार ने लैंगिक हिंसा के विरुद्ध लड़ाई में अपने गाँव की महिलाओं के बीच एक सशक्त नेतृत्व भूमिका निभाई। समुदाय के सदस्यों ने भी अन्याय की घटनाओं के सम्बन्ध में क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा से सम्पर्क किया, जिनके आधार पर मामले दर्ज किए गए थे। उदाहरण के लिए, सन्तुबेन गावित ने अपनी भूमि से सम्बन्धित एक मामले के सम्बन्ध में क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा से सम्पर्क किया।

लेकिन अब तक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह आए हैं कि समुदाय के सदस्यों ने कैसे एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण विकसित किया और अन्याय के निवारण के लिए सामूहिक कार्यवाही में जुटे रहे। वनजा तांबा गाँव में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार को सम्बोधित करने के लिए समुदाय के युवाओं ने मिलकर रैली निकाली। खानपुर में, समुदाय के तीन युवा सदस्यों ने संदिग्धों की खोज से सम्बन्धित क़ानून को बेहतर ढंग से समझने के लिए क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा से सम्पर्क किया और इसके तहत क़ानून और दण्ड के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए गाँव में एक बैठक आयोजित (क़ानूनी सलाह केन्द्र के एक क़ानून सहायक की मदद से) की। पूर्व में पकड़ी गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज चोरी की घटना ने भी अन्य गाँवों में महिलाओं के समूहों को प्रेरित किया कि वे भी इसी तरह की सतर्कता और जवाबदेही तथा पारदर्शिता लागू करने के प्रयास करें।

इसी तरह से, रान रेडे के प्रसारणों की विषय वस्तु के बड़े परिवर्तनकारी-प्रभाव थे। यह अपने श्रोताओं के बीच एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के विकास में सहायक था, मुख्यतः सांस्कृतिक अधिकारों पर एक संवाद जिसने आदिवासी सांस्कृतिक प्रथा की पहचान मानवाधिकार से जुड़े एक प्रश्न के रूप में की, उसे बरकरार रखा, और बढ़ावा दिया। डांगी समाज ने “हिन्दूकरण” के शक्तिशाली प्रभाव का सामना किया है, और अब भी इसका सामना कर रहा है। इस प्रभाव का मुकाबला करने और आदिवासी पहचान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग के रूप में पारम्परिक सांस्कृतिक प्रथा और ज्ञान प्रणालियों को पुनः केन्द्रित करने में, रान रेडे एक प्रभावी शक्ति बन गया। रेडियो के उपयोग का अर्थ यह भी था कि यह परिवर्तनकारी सन्देश युवाओं तक पहुँचा, और रान रेडे के माध्यम से डांगी के युवाओं का क़ानूनी सशक्तिकरण और उनकी सक्रियता सम्भव हुई। सबसे महत्वपूर्ण रूप से, रान रेडे ने स्वामित्व की एक सामुदायिक भावना पैदा की। उत्पीड़न के एक साझा अनुभव के आधार पर गाँवों के बीच एकजुटता कायम करके, इसने सक्रियता के लिए एक आधार, प्रेरणा, सशक्तिकरण, और सामूहिक कार्यवाही के लिए संसाधन प्रदान किए।

राज्य

सामुदायिक परिवर्तन और सामूहिक कार्यवाही अनिवार्य रूप से प्रणालीगत परिवर्तन की माँग की दिशा में ले गई। समुदाय के सदस्यों ने जल्दी ही महसूस किया कि वे शासन की एक क्रूर और भ्रष्ट प्रणाली के चंगुल में फँस गए थे, जिसने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें नज़रअन्दाज़ करना, उनकी उपेक्षा करना, और हाशिए पर धकेला जाना जारी है। लेकिन क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा के सहयोग से, सामूहिक क़ानूनी कार्यवाही कुछ क्षेत्रों में प्रणालीगत परिवर्तन लाने में मददगार रही थी। उदाहरण के लिए, रान रेडे सुनने के बाद भेंडमाल गाँव में, शैलेश गावित ने स्थानीय दुग्ध सहकारी समिति के सचिव के खिलाफ़ एक शिकायत के साथ क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा से सम्पर्क किया। क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा की मदद से, भेंडमाल में समुदाय ने सचिव को बेदखल करने के लिए दुग्ध सहकारी समिति को सफलतापूर्वक पुनर्गठित किया। सामूहिक कार्यवाही के लिए प्रेरित होने वाले सामुदायिक सदस्यों के साथ-साथ, सरकारी अधिकारी (जो स्वयं समुदाय के सदस्य थे) भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। वन विभाग के एक अधिकारी, जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखना चाहा, ने जंगल माफ़िया को बेनकाब करते हुए रान रेडे को एक पत्र लिखा। यह जानकारी प्रसारित की गई और इसने व्यापक सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहित किया, जिसमें लोगों के वनोपज के अधिकारों की माँग की गई।



डांग में कोई न्यायालयीन प्रकरण दायर करना अपने-आप में एक अत्यन्त कठिन कार्य था। जहाँ 95 प्रतिशत आबादी आदिवासी हो और निरक्षरता व्याप्त हो, वहाँ कोई भी लोगों से यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो न्यायालय जाएँगे और क़ानूनी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे।

सुरेश कोकानी, वकील, क़ानूनी सलाह केन्द्र, आहवा



रान रेडे का व्यापक उद्देश्य, यानी, क़ानूनी और सांस्कृतिक जागरूकता का निर्माण, इन चार प्रमुख सम्बन्धपरक क्षेत्रों के माध्यम से पूरा किया गया था जिनके भीतर इसके प्रभावों को सबसे प्रभावशाली ढंग से महसूस किया गया था।

संगठनात्मक अधिगम और आगे का रास्ता

शुरुआत में, रान रेडे ने ग़ैर-क़ानूनी कृत्यों को सम्बोधित करते हुए एक शक्तिशाली डांगी पहचान को बढ़ावा देने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए एक सांस्कृतिक अधिकार-आधारित ढाँचे के भीतर क़ानूनी जागरूकता निर्मित करने का कठिन कार्य आरम्भ किया। चुना गया

तरीका यह था कि एक मज़बूत क़ानूनी और सांस्कृतिक जागरूकता निर्मित करने के बाद श्रोता समूहों और क़ानूनी सलाह केन्द्र—आहवा के माध्यम से तेज़ और प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही की जाए। इस पद्धति के अनुसार कार्य करते हुए, रान रेडे को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें विशेष रूप से तकनीकी मुद्दों और क्षमता-सम्बन्धी समस्याएँ शामिल थीं। लेकिन रान रेडे परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रमुख संगठनात्मक निचोड़ यह था कि प्रौद्योगिकी और समुदाय की अन्तर्निहित ताक़त के एक प्रभावी मिश्रण के माध्यम से भूगोल, मानव संसाधन, पूँजी, और अन्य आदानों की अलंघ्य प्रतीति होने वाली बाधाओं को लगभग पूरी तरह से दरकिनार किया जा सकता था। साथ ही, रान रेडे के सहजीवी मॉडल (symbiotic model) की ज़बरदस्त सफलता—सांस्कृतिक कायाकल्प के साथ क़ानूनी जागरूकता को जोड़ना—ने इस तरह की रणनीति की व्यवहार्यता के प्रति संगठन और उसके सदस्यों तथा हितधारकों को आश्चस्त किया। इसने एक ही ढाँचे के भीतर बाद के एक लम्बे समय के लिए जुड़ाव का आधार तैयार किया। रान रेडे मॉडल से मिली सीखों, और उसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए, डांग में क़ानून, समाज, और संस्कृति के बीच अन्तराफलक, टकरावों, और विरोधाभासों का पता लगाने के लिए एक हस्तक्षेप की रूपरेखा तैयार कर हस्तक्षेप विकसित किया गया था, यानी, क़ानूनी हस्तक्षेप में संस्कृति को एक केन्द्रीय श्रेणी के रूप में रखना।

जैसा कि पिछला खण्ड बताता है, दीर्घ काल के लिए न कि केवल टीम के सदस्यों की, बल्कि संगठन की भी क्षमता बढ़ाने के साथ रान रेडे वह बदलाव भी लाया जिनके महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव थे। इसी तरह, अन्य सामुदायिक रेडियो के लिए रान रेडे की सफलता एक ऐसी मिसाल थी जिसने उनके लिए भी सम्भावनाओं को प्रकट किया और प्रेरित किया कि वे इसे दोहराएँ, जोकि क़ानूनी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक रणनीतिक युगांतरकारी घटना साबित हुई। अपनी आवाज़ मुखर करने को आतुर सीमान्त और अरक्षित समुदायों के लिए रान रेडे की प्रासंगिकता बरकरार है।

सामाजिक न्याय केन्द्र, डांग, गुजरात

सामाजिक न्याय केन्द्र (Centre for Social Justice—CSJ) एक सामाजिक-क़ानूनी, ग़ैर-सरकारी संगठन है, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग (Institute for Development Education and Learning—IDEAL) द्वारा आरम्भ किया गया है। सामाजिक न्याय केन्द्र भारत में अपनी तरह के पहले संगठनों में से एक है जो सीमान्त लोगों के अधिकारों हेतु लड़ने के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग करता है। सामाजिक न्याय केन्द्र ने पहले 1993 में पूरे गुजरात में क़ानूनी केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से काम करना शुरू किया। संगठन की दृष्टि है : मानव अधिकारों की संस्कृति को सुदृढ़ बनाना और एक ऐसा सर्व-समावेशी बहुलतावादी समाज निर्मित करना जो हिंसा, अन्याय, भेदभाव, पूर्वाग्रहों, और रुढ़िबद्धता से मुक्त हो।

न्याय तक पहुँचने के मार्ग में अवरोधों को दूर करने के लिए प्रणालीगत बदलाव लाने के लिए संगठन क़ानून का उपयोग करता है, विशेष रूप से सीमान्त समुदायों के लिए। सामाजिक न्याय केन्द्र के हस्तक्षेपों की विस्तृत सीमा है जिसमें शामिल हैं : क़ानूनी सहायता प्रदान करना, शिकायती दस्तावेज़ तैयार करने में सहायता करना और तथ्यान्वेषण में अग्रणी भूमिका निभाना, मुकदमे दायर करना, सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करना, पात्रता के दावों को आगे बढ़ाना, क़ानूनी जागरूकता फैलाना, सार्वजनिक पैरवी अभियान, युवा वकीलों और क़ानून सहायकों (paralegals) को प्रशिक्षित करना, नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों की पहचान करना और मानवाधिकारों के हनन के प्रहरी के रूप में सेवा प्रदान करना। सामाजिक न्याय केन्द्र न केवल सामाजिक-आर्थिक और नागरिक-राजनीतिक अधिकारों के प्रवर्तन के माध्यम से अरक्षित समुदायों के सशक्तिकरण में सहायता करता है, बल्कि (न्याय के एक व्यापक पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोण [restorative view] से), समुदाय के भीतर और समुदायों के बीच सत्ता की गतिकी के एक दीर्घकालिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से भेदभाव और हिंसा कारित करने वाले सामाजिक सम्बन्धों को पुनः व्यवस्थित करने में भी संलग्न होता है।

1.2 जब परिवर्तन का नेतृत्व युवा करते हैं:

मुंबई के एक होनहार युवा संगठन की यात्रा को समझना

यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (YUVA), महाराष्ट्र

सारांश

यह केस स्टडी युवाओं के नागरिकता अधिकारों के दावे और इस्तेमाल की जाँच करती है। यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (Youth for Unity and Voluntary Action—YUVA) सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले युवाओं को उनके जीवन की दिशा खुद तय करने में सक्षम बनाती है। इसमें सम्बद्ध होने, सहभागिता करने, और व्यक्ति से परिवार इकाई तक, समुदाय से बड़े समाज, शहर, और उससे आगे तक अलग-अलग स्तरों पर कार्यवाही का ज़िम्मा लेना शामिल है। युवा संगठनों के निर्माण की प्रक्रिया से परिवर्तन आया है, और हम ऐसे ही एक युवा समूह, मालवणी युवा परिषद, के गठन और विकास तथा परिवर्तन लाने और प्रभाव डालने के लिए सम्बद्ध शहर स्तरीय समूहों की स्थापना पर प्रकाश डालेंगे।

जब परिवर्तन का नेतृत्व युवा करते हैं—परिचय : युवाओं का जश्र

मालवणी युवा परिषद (Malvani Yuva Parishad—MYP) की सदस्य असमा और ज़रीन 12 अगस्त 2018 को एक लम्बे लेकिन रोमांचक दिन के पूरा होने के बाद घर लौटीं। मुंबई और नवी मुंबई (अंबुजवाड़ी, परेल, चारकोप, लल्लूभाई कम्पाउंड, विले पार्ले, बेलापुर, आदि) के अन्य युवाओं के साथ उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2018 मनाते हुए दिन बिताया था। अपने हमउम्र साथियों के साथ, सुबह उन्होंने आसपास के इलाकों में क्रीड़ाएँ, चर्चाएँ, और खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियाँ आयोजित कीं। शाम के समय, वे “सेफ़ स्पेसेस फॉर यूथ” (Safe Spaces for Youth) विषय पर एक शहर स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के एक पैनल और युवाओं ने चर्चा की कि कैसे वे सभी एक साथ काम कर सकते हैं। दिन के आयोजनों में शहरभर के विभिन्न युवा समूहों के 300 से अधिक युवाओं की सक्रिय सहभागिता देखी गई।

महज़ चार साल पहले, असमा और ज़रीन युवाओं की इस तरह की शहर-व्यापी चर्चाओं और गतिविधियों के आयोजन की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। उन्होंने यह सोचा भी न होगा कि उनके घर के पास बालवाड़ी (child care centre) में उनके छोटे समूह की बैठकें, अधिक परिवर्तन लाने के वादे के साथ किसी बहुत बड़े और उद्देश्यपूर्ण कार्य में तब्दील हो जाएंगी। जैसे कि सीमान्त पृष्ठभूमि की लड़कियाँ जो अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, अपने परिवारों की सहायता करने की आशा कर रही हैं, और उत्पीड़न एवं पुरुषों की अवांछनीय घूरती निगाहों से बचने की कोशिश कर रही हैं, वे पहले से ही कई सामाजिक दबावों से लड़ रही थीं। वे सोच भी नहीं सकती थीं कि ऐसा भी दिन आएगा जब एक संगठन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने में लड़के उनके सहभागी होंगे, जिससे वे सभी सम्बन्धित थे।

यह समझने के लिए कि यह परिवर्तन कैसे हुए थे, आइए हम बीते समय की ओर लौटकर उस समय युवाओं के जुड़ाव की स्थिति और प्रचलित शहरी वास्तविकताओं की जाँच करते हैं।

यह सब कहाँ शुरू हुआ : मालवणी

उत्तर-पश्चिमी मुंबई का एक उपनगर, मालवणी, मलाड क्रीक के पश्चिम में और कॉर्पोरेट पार्क, माइंडस्पेस (MindSpace) के पास स्थित है। समुद्र तट के पास, पश्चिम में नौसेना के स्वामित्व वाली भूमि है, जबकि उत्तर में मालवणी मछली पकड़ने वालों का गाँव और मरवे गाँव हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन मलाड है (इस क्षेत्र में मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 3.6 किमी)। मलाड का क्षेत्रफल 2.82 वर्ग किमी है, जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, अनुमानतः 27 बस्तियों में 3,95,000 लोग रहते हैं।ⁱⁱⁱ

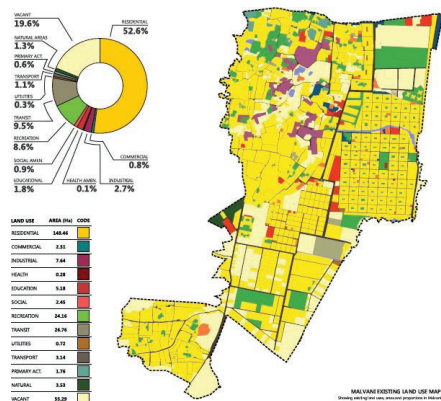
मालवणी का 1924 का एक नक्शा, उत्तर-पूर्वी हिस्से को छोड़कर जो आरक्षित वन के रूप में चिह्नित है, इस क्षेत्र को मुख्य रूप से दलदली भूमि के रूप में दर्शाता है। 2019 का एक नक्शा दिखाता है कि 1920 के दशक के बाद से इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए हैं। 1970 के दशक के बाद से, बस्तियों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, ज़्यादातर पुनर्वास कॉलोनियों के रूप में। द सैन्क्शंड डेवलपमेंट प्लान (The Sanctioned Development Plan, 1991-2001) में, मुंबई महानगरपालिका (Municipal Corporation of Greater Mumbai—MCGM) ने सार्वजनिक आवास के लिए बड़े क्षेत्र आवंटित किए। कुछ सालों बाद, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (Maharashtra Housing and Area Development Authority—MHADA) ने MHADA कॉलोनी विकसित की, जिसमें निम्न-, मध्यम-, और उच्च-आय वाले वर्गों के लोगों के लिए आवास प्रस्तावित किए गए। 1990 के दशक के बाद से, सीमान्त पृष्ठभूमि के और लोग बड़ी संख्या में मालवणी आने लगे और न्यू भाब्रेकर नगर, अंबुजवाड़ी, और आजमी नगर में बसने लगे हैं। यह बस्तियाँ तेज़ी से और अनियंत्रित रूप से बढ़ी हैं, जिससे एक अव्यवस्थित शहरी फैलाव निर्मित हुआ है जिसमें

आमतौर पर ऐतिहासिक रूप से सीमान्त समुदायों की आबादी है जो उच्च घनत्व वाली बस्तियों (अनौपचारिक बस्तियों) में रहती है, और संसाधनों की कमी से जूझती है तथा उनका जीवन-स्तर बहुत ही खराब है।

आज जब मालवणी समाचारों में दिखाई देता है, तो इसके सन्दर्भ में जो सबसे आम शब्द और वाक्यांश उपयोग किए जाते हैं, वे हैं : ज़बरन बेदखली, बीमारी, स्वच्छता के घटिया इन्फ़्रास्ट्रक्चर, घटिया कचरा प्रबन्धन, बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच की कमी, स्कूल छोड़ने वाले, अपराध, हिंसा, दंगे करना। लोकप्रिय कल्पना में, मालवणी में रहने वाले लोगों को “अतिक्रमणकारियों” और “अवैध नागरिकों” के रूप में देखा जाता है, और शहर के प्रचलित विकास वर्णनों ने यहाँ रहने वाले लोगों के संघर्षों को और अदृश्य बनाकर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है।

हाल के वर्षों में निवासियों की माँगों के समाधान के लिए कुछ प्रयासों के बावजूद, बुनियादी सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान करने से पहले भी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। स्थानीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासियों का है जिनके पास अपने निवास स्थान की वर्तमान जगह का उल्लेख करने वाले क़ानूनी दस्तावेज़ों की कमी होती है या जो बार-बार ज़बरन बेदखली के कारण ऐसे दस्तावेज़ीकरण से दूर (वंचित) कर दिए गए हों। यह अक्सर लोगों को शहर में रहने और काम करने के उनके अधिकार से वंचित करने का एक और कारण बन जाता है, भले ही यह उनका श्रम ही है जो मुंबई की मेगासिटी को बनाए रखता और उसे ऊर्जा देता है।

यूथ फ़ॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (Youth for Unity and Voluntary Action—YUVA) ने 1998 में मालवणी में अपने हस्तक्षेप शुरू किए। हमारा काम आसपास के कुछ ख़ास इलाक़ों में केन्द्रित है और इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना और सार्वभौमिक मानवाधिकारों तथा बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुँच को आसान बनाना है। हमारे साथ संलग्न लोगों में युवा एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं, और उनके साथ हमारे हस्तक्षेप का महत्व अगले भाग में समझाया गया है। सामाजिक परिवर्तन के लिए युवाओं की सामूहिक कार्यवाही और सक्रिय सहभागिता सुगम बनाने के लिए हमारे प्रयास युवाओं को मज़बूत बनाने और उनकी क्षमताओं का निर्माण करने पर केन्द्रित रहे हैं। युवाओं के साथ हमारे काम के विभिन्न स्तरों पर कई परिणाम प्राप्त हुए हैं जो जारी हैं, क्योंकि हम उनके सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ जुड़े रहना जारी रखते हैं।



मानचित्र 1. मालवणी : वर्तमान भू उपयोग
मानचित्र (स्रोत : Malvani People's Plan, KRVA and YUVA, 2014)



छायाचित्र 1. मालवणी के भीतर (स्रोत : YUVA)

युवाओं के साथ जुड़ाव क्यों?

हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का घर है, 10-24 साल के आयु समूह में 356 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं।^{iv} प्रत्येक पाँचवाँ भारतीय एक किशोर (10-19 वर्ष) है और हर तीसरा भारतीय एक युवा व्यक्ति (10-24 वर्ष) है।^v एक युवा-बहुल जनसांख्यिकी भारत के लिए असंख्य अवसर और चुनौतियाँ पेश करती है। इस युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य, शिक्षा, और कल्याण में निवेश करना, और उनके अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को बनाए रखना, देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि उनकी क्षमता का प्रभावी ढंग से दोहन किया जाए तो युवाओं की इस अधिक संख्या को अपार उत्पादकता में बदला जा सकता है। हालाँकि, सार्थक रोज़गार के अभाव का परिणाम बड़े पैमाने पर अशान्ति भी हो सकता है। युवा परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक हैं, जो ऊर्जा और अपने समाजों एवं समुदायों की बेहतरी के लिए काम करने की इच्छा से ओतप्रोत हैं। फिर भी उनकी आवाज़ को दबाने, और यहाँ तक कि उनके प्रयासों को ग़लत दिशा में मोड़ने के प्रयास किए जाते हैं, जिसका परिणाम एक कुण्ठित और स्वार्थी आबादी हो सकती है, जो नफ़रत और असहिष्णुता के चक्र को आगे बढ़ा सकती है।

वर्षों से, प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों द्वारा अपने स्वयं के निहित स्वार्थों के अनुरूप युवाओं को बार-बार अपनी चालाकी का शिकार बनाया जाता रहा है। उनकी अपर्याप्त जानकारी, और अवसरों (आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, आदि) तक उनकी पहुँच की कमी का उपयोग यथास्थिति बनाए रखने के लिए किया गया है, जो उन्हें बेहतर सम्भावनाएँ तलाशने और

नागरिकों के रूप में प्राप्त उनके अधिकारों का पूर्ण इस्तेमाल करने से वंचित करती है। कर्तव्यनिष्ठा के अभाव और शक्ति की कमी के कारण, युवाओं का उन वर्गों द्वारा शोषण किया जाता है जो उनके साथ चालबाज़ी करने और उन्हें अपने वश में रखने से लाभान्वित होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत सरकार का स्किल इंडिया कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य 2022 तक 402 मिलियन युवाओं को कौशल प्रदान करना है, में प्रशिक्षण, मूल्यांकन, और प्रमाणन के स्तर घटिया पाए गए, भले ही लक्ष्य प्राप्त होने की रिपोर्ट दी गई थी।^{vi} युवाओं के विषय में इसी तरह के अलग-अलग और सतही प्रयासों को ऐसे प्रयासों के रूप में पेश किए जाने की सम्भावना है, जो विकास की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागियों और योगदानकर्ताओं के रूप में आगे आने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय, उद्देश्यहीन को निर्देश देते और अनभिज्ञ या विसामान्य व्यवहार को ठीक करते हैं।

मालवणी के मामले में भी, विजातीय समुदायों में युवा सबसे अरक्षित समूहों में से हैं। वे दो तरह से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं क्योंकि वे एक ओर आर्थिक और सामाजिक रूप से, साथ ही धार्मिक आधारों पर, मुख्य धारा के समाज से कटे हुए हैं और दूसरी ओर वे अपने ही लोगों की तरफ़ से किए जाने वाले भेदभाव का सामना करते हैं। शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पर्याप्त पहुँच के बिना, वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों में फँसे हुए हैं, कर्तव्यनिष्ठ और सशक्त नागरिकों के रूप में विकसित होने में असमर्थ हैं, और इस तरह से अभाव का दुष्चक्र अनवरत चलता रहता है।

युवाओं में असमानता के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए, और युवाओं के माध्यम से संचालित और युवाओं पर केन्द्रित साधनों के माध्यम से युवाओं की सकारात्मक, विघटनकारी शक्ति को सुगम बनाने के लिए, YUVA इस क्षेत्र में अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। हमारे हस्तक्षेप बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों, शासन में जवाबदेही, और युवा विकास के लिए युवाओं की सहभागिता पर आधारित हैं। हमारी दृष्टि है युवाओं को उनकी क्षमता हासिल करने में सक्षम बनाना, उन्हें समस्या-समाधान प्रक्रिया का हिस्सा बनने में समर्थ बनाना, और उन्हें आन्दोलन का स्वामित्व संभालने में मदद करना ताकि अन्ततः वे इसे स्वतंत्र रूप से संचालित करें और आगे बढ़ाएँ। सक्रिय युवा सहभागिता को प्रोत्साहित करने और सुगम बनाने का हमारा प्राथमिक लक्ष्य इस विश्वास पर आधारित है कि जो लोग प्रत्यक्ष रूप से समस्याओं का सामना करते हैं, वे पर्याप्त प्रशिक्षण, सहायता, और ज्ञान के बल पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे योग्य होते हैं।

युवाओं के साथ YUVA का काम इसके प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक है। मुंबई के एक पश्चिमी उपनगर जोगेश्वरी की बस्तियों में शुरू हुई एक युवा कार्य परियोजना के माध्यम से 1984 में संगठन अस्तित्व में आया था। हमारा पैना अवलोकन और देशभर में (विशेषकर मुंबई में) शहरीकरण और विकास प्रक्रियाओं में हमारी सहभागिता, और कई हितधारकों के साथ हमारी

संलग्नता ने युवाओं से सम्बन्धित चिन्ताओं की हमारी समझ को बढ़ाया है। यह हमें बेहतर रणनीति बनाने और खुद को समर्थ बनाने की अनुमति देता है ताकि हम इस बढ़ती और गतिशील आबादी के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संलग्न हो सकें और न्यायोचित एवं समावेशी शहरों का सह-निर्माण सुगम बना सकें। युवा नागरिकता की कल्पना व्यापक अर्थों में की जाती है, और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि युवा अपने नागरिकता अधिकारों के बारे में पूरी तरह जागरूक हों, और इनकी माँग करने में सक्रिय हों, इसके महत्व पर बार-बार बल दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, हमारे काम में युवाओं की ज़रूरतों के अनुरूप विविधता आई है। इसका पूरा प्रभाव केस स्टडी के 'अर्ली अचीवमेंट्स' (Early Achievements) खण्ड में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

मालवणी में प्रारम्भिक निष्कर्ष

2014 में, YUVA ने मालवणी की सबसे बड़ी बस्ती अंबुजवाड़ी में लगभग 4,200 युवाओं (15 से 29 वर्ष की आयु के बीच के) का एक आधार-रेखा सर्वेक्षण^{vii} किया। हमें पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 61 प्रतिशत युवा औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हो गए थे क्योंकि उनकी इसमें रुचि नहीं थी, जबकि 17 प्रतिशत जल्दी शादी हो जाने के कारण बाहर हो जाने के लिए बाध्य हो गए थे। उत्तरदाताओं में से 45 प्रतिशत कुछ कमा नहीं कर रहे थे और सर्वेक्षण में शामिल कुल महिलाओं में से 65 प्रतिशत महिलाएँ गृहिणियाँ थीं। जब उनकी रुचि के क्षेत्र के बारे में पूछा गया, तो केवल 10 प्रतिशत ने ही इस बारे में बात की और अपनी प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। उत्तरदाताओं में से अधिकांश कम्प्यूटर चलाना सीखना चाहते थे, और दूसरी सबसे बड़ी माँग सिलाई कक्षाओं के लिए थी। कई उत्तरदाताओं ने किसी भी व्यवसाय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, लेकिन ऐसा कोई कौशल अपनाने में रुचि व्यक्त की जो उन्हें एक स्थाई आजीविका का साधन प्रदान कर सके।

हमारे लम्बे सहयोग, व्यापक जुड़ाव, और ठोस प्रयासों की बदौलत, हमने युवाओं और समुदाय के अन्य सदस्यों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। युवाओं ने हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना समय लिया, और बदले में हमने सावधानी रखी कि इस प्रक्रिया में जल्दबाज़ी नहीं करें या ज़ोर नहीं डालें, बल्कि मददगार सुविधाप्रदाता बने रहें। युवा लड़कियों के साथ जुड़ना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उनमें से कई अपने घरों से कभी नहीं निकली थीं। उनका जीवन आमतौर पर अपने घर की चारदीवारी के भीतर बीता था, जिससे बाहरी लोगों का उनके साथ बातचीत करना मुश्किल हो जाता था। हमने अभिभावकों के साथ-साथ समुदाय के अन्य युवाओं के साथ घीमी गति से लेकिन व्यापक जुड़ाव शुरू किया, ताकि समुदाय में हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य को बेहतर ढंग से समझने और उसका मूल्यांकन करने में उनकी मदद कर सकें। इससे विश्वास विकसित करने और सम्बन्ध बनाने में मदद मिली, और धीरे-धीरे कई अभिभावक अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने और सामुदायिक युवा बैठकों का हिस्सा बनने की अनुमति देने लगे।

सैद्धान्तिक सन्दर्भ

युवाओं के साथ YUVA के कार्य में एक बहुआयामी स्तरीय दृष्टिकोण है और यह कई रूपरेखाओं का अनुसरण करता है जो विशिष्ट रूप से मालवणी की अनूठी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित की गई हैं। यह YUVA की कार्यप्रणाली के अनुरूप हैं :

- व्यापक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए बस्ती स्तर पर एक 360-डिग्री का एकीकृत विकास मॉडल जिसमें अन्तःसम्बन्धित क्षेत्रों—सशक्तिकरण, आवास, आजीविका, शासन—में हस्तक्षेप शामिल हैं
- भारतीय नागरिक समाज के लिए लोकतांत्रिक क्षेत्रों के सिकुड़ने के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए एक प्रमुख एकजुटता-निर्माण रणनीति के रूप में नेटवर्कों और संगठनों का गठन और उन्हें मज़बूती प्रदान करना
- समावेशी और न्यायसंगत नीति निर्माण पर संवाद संचालित करने के लिए साक्ष्य-आधारित ज्ञान पर आधारित नीति अनुसन्धान और पैरवी

मालवणी में युवाओं से सम्बन्धित कार्य, जो शहरभर में और उससे परे युवाओं के साथ हमारे बड़े जुड़ाव का हिस्सा है, इस ढाँचे के भीतर स्थित है। हमारा काम युवाओं को राजनीतिक चेतना के साथ जोड़ते हुए उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करना, और उन्हें समालोचनात्मक चिन्तन करने, प्रश्न पूछने, और उनके आत्मनिर्णय की खोजबीन में उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही में संलग्न होने के लिए मौका प्रदान करना है। यह न्याय और सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्तों द्वारा मार्गनिर्देशित है। यह अपने नागरिकता अधिकारों एवं सभी सम्बन्धित ज़िम्मेदारियों और दायित्वों को क़ायम रखने के लिए सीमान्त आबादी का सशक्तिकरण सम्भव बनाने का प्रयास करता है। हमारे काम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए शहर स्तर के नेटवर्कों, अभियानों, और पैरवियों में युवाओं को जोड़ना है।

हस्तक्षेप व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सहयोग करने पर केन्द्रित हैं। अधिकार-आधारित सशक्तिकरण प्रक्रियाओं को विकसित करने के अलावा, शिक्षा, कौशल वृद्धि, और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें, और स्थाई आजीविका विकल्प तलाशने में सक्षम हों। संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव बनाने के लिए, अन्य नागरिक समाज भागीदारों, सरकारी विभागों, निजी क्षेत्र, और अन्य हितधारकों के साथ नेटवर्क निर्मित करने को प्रोत्साहित किया जाता है और इसका दायित्व लिया जाता है। इन प्रयासों में वे मूल्य अन्तर्निहित हैं जिन्हें हम इस कार्य के माध्यम से युवाओं के मन में बैठा देने की उम्मीद करते हैं—लोकतंत्र, लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता, और वैज्ञानिक स्वभाव।



युवाओं के साथ काम करने के लिए YUVA का ढाँचा :

सशक्तिकरण	मूल्य	विकास
• सहयोग एवं भागीदारी	• लोकतंत्र	• कैरियर मार्गदर्शन
• व्यक्तियों और संगठनों का नेतृत्व निर्माण	• लैंगिक न्याय	• छात्रवृत्ति सहायता
• राजनीतिक चेतना विकसित करना	• सामाजिक न्याय	• सतत शिक्षा
• समालोचनात्मक चिन्तनशीलता और प्रश्न पूछना	• पर्यावरणीय स्थिरता	• रोज़गार के लिए कौशल प्रशिक्षण
	• धर्मनिरपेक्षता	• बाज़ार सहूलयता सुगम करना
	• वैज्ञानिक स्वभाव	



YUVA के युवा-उन्मुख कार्य की कार्यप्रणाली ट्रूडी कूपर (Trudi Cooper) के “फ्रेमवर्क फॉर पॉजिटिव सेप्टिकल रिफ्लेक्शन” (framework for positive sceptical reflection) के साथ संरेखित की गई है, जिसका उद्देश्य सिर्फ आलोचना प्रस्तुत करने के बजाय समालोचना के माध्यम से युवाओं सम्बन्धी कार्य के मॉडल को बेहतर बनाना है।^{viii} सन्देह और अविश्वास को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, और उन्हें चिन्तनशील कार्य से जोड़ा जाता है, जिसका उद्देश्य युवा कर्मियों (और संस्था में युवाओं को) को स्थापित मानदण्डों और कार्यप्रणालियों पर प्रश्न पूछने और विरोधाभासों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे “निर्णय लेने में उपयोगी मार्गदर्शन” कर सकें।

निरन्तर आलोचनात्मक प्रश्न पूछना और चिन्तनशीलता युवाओं सम्बन्धी कार्य के मॉडल को तेज़ी से बदलती दुनिया में लचीला और अनुकूलनीय बनाती है, जिससे इसकी स्थाई प्रासंगिकता और मूल्य सुनिश्चित होते हैं।

अपने निबन्ध “व्हाटैवर हैपन्ड टू रेडिकल यूथ वर्क?” (Whatever happened to radical youth work?) में, टोनी जेफ्स (Tony Jeffs) एक महत्वपूर्ण चिन्ता व्यक्त करते हैं, यानी, युवाओं के कार्य को कैसे संगठन की शक्ति का अवमूल्यन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो संगठन के बजाय व्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित करता है, और इस विचार को मज़बूत करने का प्रयास करता है कि बड़ी प्रणालियों के सामने व्यक्ति नियंत्रण के अधीन और शक्तिहीन होते हैं।^{ix} भारतीय सन्दर्भ में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे, लोगों की पहचान पर हमले, विपरीत विचारों को नियंत्रित करने और असन्तोष को दबाने के प्रयासों, और विविध एवं जटिल वास्तविकताओं का एक सरलीकृत और सजातीय दृश्य पेश करने के प्रयासों को देखते

हुए लगता है कि यह कई स्तरों पर किए जाने वाले ठोस हमले हैं। इन स्थितियों में, जबकि व्यक्तिगत पहचान को बढ़ावा देना और बनाए रखना अत्यावश्यक है, संगठनों का निर्माण और मज़बूती सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो राजनीतिक दबाव का प्रतिरोध कर सकें और लोगों के संघर्षों को आगे ले जा सकें। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी सहभागिता के लिए घटते हुए क्षेत्रों के साथ, युवाओं की सीमित स्वायत्तता को देखते हुए, युवा नागरिकता के दावे में सामूहिक प्रतिनिधित्व की एक बहुत बड़ी भूमिका है, विशेष रूप से कई शहरी वास्तविकताओं के सन्दर्भ में, जैसे—आवास और श्रम क्षेत्रों की अनौपचारिकता, शहरी गरीबों के साथ असमानता, भेदभाव, और उन्हें हाशिए पर धकेला जाना।

युवाओं के साथ हमारे काम का इस बात की समझ से करीबी सम्बन्ध है कि “विभिन्न परिस्थितियों में बाधा की लैंगिक संरचनाएँ कैसे काम करती हैं”, यह समझना कि सीमान्त युवा महिलाएँ उन्हें प्रदान किए गए संसाधनों से कैसे प्रभावित होती हैं, और यह बदले में उनकी क्षमताओं को कैसे आकार देता है। व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास का “निरीक्षण करना और उसे मापना मुश्किल” है, लेकिन महिलाओं के प्रतिनिधित्व और हासिल किए जा सकने योग्य परिणामों पर प्रभाव (सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तित्व विकास, इत्यादि) का अध्ययन और मूल्यांकन किया जा सकता है। हमारे काम और नैला कबीर (Naaila Kabeer) द्वारा उनके निबन्ध में लिखी गई बात में काफ़ी समानताएँ पाई जाती हैं : “व्यवहारिक आजीविका उपलब्धियों... और अधिक रणनीतिक परिवर्तनों के बीच अन्तर करना मुश्किल है, जो अन्तर्निहित शक्ति सम्बन्धों को छूते हैं और इसलिए बाधा की संरचनाओं के लिए उनके निहितार्थ हैं।”^x

युवाओं के साथ YUVA का काम ब्रायन बेल्टन (Brian Belton) की “रिलेटिव पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी” (relative political neutrality) की धारणा के विपरीत है,^{xi} क्योंकि हमारे जुड़ाव का स्पष्ट उद्देश्य युवाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ा रहा है। उन्हें समालोचनात्मक चिन्तन में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यहाँ तक कि युवा कार्यकर्ताओं को लम्बे समय से चले आ रहे दृष्टिकोणों को चुनौती देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है अगर यह विचार अस्थिर या अव्यवहारिक पाए जाते हैं, और विभिन्न, अनपेक्षित, या अप्रत्याशित परिणामों पर पहुँचने के लिए एक सहभागी लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर उन पर सवाल उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। युवाओं के राजनीतिकरण को सकारात्मक रूप से देखा जाता है, ताकि वे उनके द्वारा सहे जा रहे विभिन्न प्रकार के भेदभाव, असमानता के मुद्दों, और अन्याय के सवालों पर चिन्तन और उनका सामना कर सकें। यह हमें संयुक्त राष्ट्र के 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके मिशन “लीव नो वन बिहाइंड” (leave no one behind) की दिशा में सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ काम करने में मदद करता है।^{xii}

मालवणी युवा परिषद : एक संक्षिप्त पूर्ववृत्त

जब हमने 2013 में मालवणी में युवाओं के साथ जुड़ना शुरू किया, हमारे उद्देश्य स्पष्ट थे। हमारा उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और ऐसे संगठन स्थापित करने में मदद करना था जो युवाओं के लिए अपने अधिकारों और माँगों का नियंत्रण तथा स्वामित्व हासिल करना सम्भव बनाएँ। हम युवाओं को समर्थ बनाना चाहते थे और उन्हें 360-डिग्री के विकास मॉडलों और पक्षसमर्थन में शामिल करना चाहते थे।

हमारे शुरुआती कार्य युवाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने और सहायक सदस्यों के रूप में उन्हें और उनकी चिन्ताओं को सुनने पर केन्द्रित थे। उस समय, क्षेत्र में कुछ स्थानीय युवा समूह थे, और कई युवाओं ने अपने करीबी समूह या परिचितों के दायरे के बाहर के लोगों के साथ कभी बातचीत नहीं की थी।

YUVA द्वारा बुलाई गई कुछ शुरुआती बैठकों के बाद, तीन बस्तियों—भाब्रेकर नगर, अंबुजवाड़ी, और चारकोप—के युवाओं ने अपने सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के बारे में एक नुककड़ नाटक करने का फैसला किया; उनका इरादा अलग-अलग बस्तियों में जाकर वहाँ के लोगों से बात करने का था। सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों द्वारा प्रतिदिन सहे जाने वाले उत्पीड़न पर आधारित पहले नाटक 'दस्तक' का उत्साहपूर्वक पूर्वाभ्यास किया गया, और अगले दो महीनों में सप्ताहान्त के दौरान नाटक के 84 प्रदर्शन हुए। उन शुरुआती दिनों में कई गलतियाँ हुईं। प्रस्तुति कौशल में निपुणता की कमी थी, क्योंकि आमतौर पर युवा स्वयं सीखे हुए कलाकार थे। फिर भी, एक सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि नाटक देखने वाले कई युवाओं ने इन युवाओं के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। उन शुरुआती दिनों को याद करते



छायाचित्र 2. अपने शुरुआती दिनों से ही, महत्वपूर्ण शहरी मुद्दों को, विशेषकर युवाओं से सम्बन्धित, रचनात्मक ढंग से स्पष्ट करने के लिए मालवणी युवा परिषद नुककड़ नाटक कर रही है। (स्रोत : YUVA)

हुए मालवणी युवा परिषद के एक सदस्य बाला आखड़े कहते हैं, “मैंने कम-से-कम आठ से दस बार ‘दस्तक’ देखा होगा, लेकिन दूर से। नाटक में कुछ ऐसा था जिसने मुझे आकर्षित किया, लेकिन मुझे यह यकीनी तौर पर नहीं पता था कि यह क्या था, या मैं इसके बारे में कैसा महसूस करता था। उस समय, मैं एक बहुत ही अलग व्यक्ति था। मैं खुद लड़कियों को सीटी मारता था।”

युवाओं की एक दूसरे के साथ जुड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर, उनके लिए जल्द ही एक एकल-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें 117 युवाओं ने भाग लिया जिन्होंने पूरे दिन पहचान-निर्माण और नेतृत्व गतिविधियों में भाग लिया। इसके बाद, युवाओं ने अपनी-अपनी सम्बन्धित बस्तियों में सक्रिय होते हुए एक खुले संगठन का विकास करना शुरू कर दिया।

समुदायों में हाशिए पर रहने वाले युवाओं (किशोरियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, शहरी गरीबों, वंचित जातियों) तक पहुँचने पर विशेष ध्यान देते हुए, युवाओं की सक्रियता के प्रयास पूरे समय जारी रहे, और युवाओं के हितों तथा चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से गतिविधियों की योजना बनाई गई। परिचयात्मक दौरों (exposure visits) ने शुरुआती समूह-निर्माण प्रक्रिया में मदद की। यह दौरे उन जगहों के थे जहाँ आन्दोलनों की उत्पत्ति हुई थी, और उन शहरों के थे जहाँ नायक (leaders) तैयार हुए थे। युवाओं को बी. आर. अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, शिवाजी, बिरसा मुंडा, और फ़ातिमा शेख जैसे क्रान्तिकारियों और बदलाव कर्ताओं के जीवन और संघर्ष से परिचित कराने के लिए यह दौरे आयोजित किए गए थे।

कौशल प्रशिक्षण की बढ़ती माँग के साथ-साथ सशक्तिकरण पहलों में बढ़ती रुचि के जवाब में समुदाय में कई पाठ्यक्रम शुरू किए गए। सिलाई के पाठ्यक्रम, ब्यूटीशियन कक्षाओं, और मेहँदी कक्षाओं ने लड़कियों को आकर्षित करने में मदद की (यहाँ तक कि जो पहले कभी अपने घर से नहीं निकली थीं) जबकि कम्प्यूटर और मोबाइल-रिपेयरिंग कक्षाएँ लड़कों में अधिक लोकप्रिय थीं। पारम्परिक लैंगिक रुढ़ियों और अपेक्षाओं के अनुरूप लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम पेश करना एक साभिप्राय निर्णय था, क्योंकि इससे अभिभावकों के लिए अपनी बेटियों को अपने घर की सीमाएँ छोड़कर बाहर जाने की अनुमति देना आसान हो गया। इन्हें महिलाओं के लिए सुरक्षित व्यवसायों के रूप में देखा गया था, और भले ही उन्हें पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, पाठ्यक्रम से प्राप्त अपने ज्ञान और प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए वे सम्भवतः घरेलू व्यवसाय स्थापित कर सकती थीं। एक बार जब युवा नियमित रूप से विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लेने लगे, तो उन्हें युवा समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और धीरे-धीरे उन्हें उस समय संचालित युवाओं से सम्बन्धित कार्यों की तरफ़ ले जाना आसान हो गया।

युवाओं के साथ नियमित बैठकें की गईं, ताकि उन्हें एक दूसरे से नियमित रूप से मिलने का अभ्यास हो जाए, और वे एक दूसरे की उपस्थिति में बिना हिचकिचाहट अपनी भावनाएँ और चिन्ताएँ व्यक्त करने में पर्याप्त सहजता महसूस करने लगे। जबकि शुरुआती बैठकों में लड़कियों को ज़ोर से बात करने में असुविधा होती थी, समय के साथ वे समूह के सामने अधिक निश्चिन्त हो गईं और अपनी बातें सबके सामने व्यक्त करने लगीं। जैसे-जैसे वे न केवल अपने युवा समूह में, बल्कि घर में, स्कूल में, और अन्य स्थानों पर खुद को अभिव्यक्त करने लगीं, वे आत्मविश्वास अर्जित करने लगीं।



छायाचित्र 3. मालवणी युवा परिषद के सदस्यों के लिए परिचयात्मक दौरे सीखने और संवाद करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। (स्रोत : YUVA)

युवाओं को उनकी मौजूदा मान्यताओं पर सवाल उठाने और लिंग, लोकतंत्र, मूल्यों, और जिन मुद्दों का वे सामना कर रहे थे उन पर चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। युवा समूहों को अपने संगठन की पहचान पर चिन्तन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। कभी-कभी प्रतिभागियों को बहुत समय तक उनकी सामूहिक कार्यवाही की शक्ति का अहसास तक नहीं होता था, ऐसी स्थिति में उन्हें कार्य से जोड़ने और सामूहिक कार्य तथा एकजुटता निर्मित करने में मदद करने के लिए विभिन्न खेल एक उपयोगी माध्यम थे। उदाहरण के लिए, दो टीमों ने किन्हीं भी बाहरी वस्तुओं का उपयोग किए बिना सदस्यों की सबसे लम्बी पंक्ति बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा की। दुपट्टे, जूते, और फ़ीते उतर गए, और खेल भावना में प्रवेश करते ही युवा हँसने लगे। वे अब तक कभी अनुभव नहीं की गई आज़ादी और खुलेपन की ऐसी अनुभूति के साथ एक दूसरे के निकट आए, जिससे समय के साथ मज़बूत दोस्ती की नींव पड़ी।

समूहों को और मज़बूत करने के लिए, अलग-अलग युवा समूहों के 40 युवाओं ने मालवणी के लिए एक युवा मंच स्थापित करने के लिए एक कार्यशाला में भाग लिया। जबकि चर्चाओं को शुरू में आकार लेने में समय लगा, अन्त में विभिन्न युवा समूहों ने विलय करने की आवश्यकता महसूस की, और इस प्रकार औपचारिक रूप से 2014 में मालवणी युवा परिषद अस्तित्व में आई। सदस्यों ने नए निकाय के लिए विभिन्न नामों पर चर्चा की और एक मतदान के बाद अन्ततः मालवणी युवा परिषद पर सहमति बनी।

मालवणी युवा परिषद में सीखना कभी भी किसी कक्षा की चार दीवारों तक सीमित नहीं रहा। बल्कि, नुककड़ नाटकों, परिचयात्मक दौरों, फ़िल्म प्रदर्शनों, संवादात्मक गतिविधियों, और पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए अन्य प्रारूपों के माध्यम से सीखने का कार्य होता है। उदाहरण के लिए, पुणे में एक परिचयात्मक दौरे के दौरान लड़कियों को पुरुषों के लिए एक पारम्परिक प्रशिक्षण सुविधा तक पहुँच से वंचित कर दिया गया, जिसके कारण उनके घर लौटते ही लैंगिक दृष्टिकोण से मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। जैसे-जैसे युवा अधिक नियमित रूप से मिलने लगे और आत्मविश्वास अर्जित किया, उन्होंने पूछना शुरू किया कि वे अपने समुदायों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अक्सर, युवाओं ने YUVA के कर्मचारियों से उनके विचारों और राय के बारे में पूछताछ की, और मामूली असहमतियाँ भी हुईं। हालाँकि, कार्यक्रम के एक सुविधाप्रदाता के रूप में और न कि कार्यक्रम के एक संचालक के रूप में YUVA की भूमिका स्पष्ट रही, और इसने विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित करने में युवाओं की मदद की।

जैसे ही समूह की संख्या और क्षमता में वृद्धि हुई, किसी YUVA स्टाफ़ सदस्य की मदद के बिना, बैठकें नियमित रूप से होने लगीं। युवा अपनी बैठकों के संचालन में और अधिक प्रक्रिया-उन्मुख और व्यवस्थित हो गए, चर्चा की जाने वाली मद्दों के लिए एक एजेंडा तैयार करने लगे, प्रत्येक बैठक के कार्यवाही विवरण लिखने लगे, प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों का कोरम निर्धारित करने लगे, आदि। स्थानीय क्षेत्रों और आसपास के संसाधनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्होंने अपने आसपास के इलाके के मानचित्रण की क़वायद के कार्य हाथ में लिए।

अपनी स्थापना के चार साल बाद, मालवणी युवा परिषद ने स्थानीय समुदाय और उससे भी परे कई हस्तक्षेप किए हैं। आइए, उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर नज़र डालते हैं।

प्रारम्भिक उपलब्धियाँ

मालवणी के युवाओं के जीवन में मालवणी युवा परिषद एक मज़बूत प्रेरक शक्ति रही है। समूह की उपस्थिति, वृद्धि, गतिविधियाँ, और पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्यों ने व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर युवाओं के जीवन को प्रभावित किया है, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है।

व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर बदलाव

व्यक्तित्व विकास : मालवणी युवा परिषद का सबसे परिवर्तनकारी प्रभाव शायद इसके सदस्यों के जीवन को आकार देने में इसका प्रभाव रहा है। व्यक्तिगत पहचान के विकास के साथ-साथ युवा समूह की पहचान निर्मित करना, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं। व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप लागू किए गए थे। समूह की संस्कृति का विकास और बुनियादी मूल्यों के एक समूह के साथ इसके संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक स्थाई संस्था के रूप में समूह का अस्तित्व कायम रहे।

युवा समूह के सदस्यों ने ज़िम्मेदारी की उस भावना का उल्लेख किया, जो कि मालवणी युवा परिषद ने उनमें विकसित की है। असमा अंसारी कहती हैं, “जब मुझे 2014 में समूह के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो मेरी उत्तेजना की कोई सीमा नहीं थी। मुझे इस पद के लिए चुने जाने पर बहुत खुशी हुई।” उनके मुँहों से निपटने के मालवणी युवा परिषद के सक्रिय प्रयासों ने उनमें स्वामित्व की भावना विकसित की है। सदस्य भी YUVA के साथ सहयोग कर रहे हैं, गतिविधियों और प्रक्रियाओं के सह-निर्माण में मदद कर रहे हैं। मालवणी युवा परिषद के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने विभिन्न YUVA परियोजनाओं पर स्वयंसेवकों के रूप में काम करते हुए सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी समझ और ज्ञान का योगदान दिया है।

जब मालवणी युवा परिषद की कुछ महिला सदस्यों ने मुंबई के बाहर उनकी पहली कार्यशाला में भाग लिया, तो उन्होंने स्वतंत्रता और विश्वास की भावना का उल्लेख किया जिसका उन्हें अनुभव हुआ। कई सालों तक, उन्होंने महसूस किया था कि उनके पास अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा, जैसे-जैसे लड़कों और लड़कियों के बीच संवाद बढ़ा, उन्होंने लैंगिक सम्बन्धों और गतिशीलता की एक व्यापक समझ हासिल की, और बिना किसी अटपटेपन के एक दूसरे के साथ खुलकर संवाद किया।

जल्दी शादी के मुद्दे से निपटने के लिए आजीविका के अवसर (विशेष रूप से लड़कियों के लिए) प्रदान करना : मालवणी में युवाओं को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण है वे क्षेत्र जहाँ से वे आते हैं, और शैक्षिक एवं रोज़गार के अवसरों तक उनकी

पहुँच की कमी। इसका परिणाम रोज़गार के क्षेत्र में असमान पहुँच के रूप में सामने आता है। इसके अलावा, मालवणी के कई क्षेत्रों में, लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है (भले ही वे शादी की क़ानूनी उम्र पूरी नहीं करती हों, यानी, 18 वर्ष की नहीं हुई हों)। वे बहुत ही कम उम्र से घर तक सीमित रहती हैं, और उनके जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता की कोई सम्भावना नहीं रहती है।

ऐसे युवाओं को आजीविका-सृजन के अवसरों का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उनके लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रत्येक पाठ्यक्रम की रूपरेखा कई मूल्य-आधारित अवधारणाएँ प्रस्तुत करने के लिए भी तैयार की गई थी। कक्षा का एक वर्ग किसी ऐसे खेल और गतिविधियों के लिए तत्पर होता जिससे पहचान और नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद मिले। पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद भी, स्थानीय युवाओं ने पाठ्यक्रम करने वाले अपने साथियों के सम्पर्क में रहने और उन लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की, जो पहले से युवा समूह में शामिल नहीं हुए थे।

पाठ्यक्रमों के कुछ बैच ख़त्म होने के तुरन्त बाद, उन्होंने कौशल प्रशिक्षण की तुलना में बहुत अधिक प्रदान करने वालों के रूप में ख्याति अर्जित कर ली, और इसने अधिक युवाओं को आकर्षित किया जिन्होंने पाठ्यक्रमों में नाम दर्ज कराने के प्रयास किए। मालवणी युवा परिषद ने किसी सह-शिक्षा और एक दूसरे के साथ साझा करने की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए युवाओं को एक साथ लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे ज्ञान सृजन और ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण हुआ। पहुँच और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने लोगों के घरों के करीबी स्थानों पर कक्षाएँ आयोजित कीं।

महत्त्वपूर्ण शहरी दृष्टिकोण विकसित करना : शहरी परिदृश्य तेज़ी से रूपान्तरित किया जा रहा है, और इसमें भूमिका निभाने वाली विभिन्न प्रकट और अप्रकट प्रक्रियाओं को समझना महत्त्वपूर्ण है ताकि बेहतर ढंग से समझा सके कि बदलती परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए और एक न्यायसंगत एवं समावेशी समाज का आदर्श प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी ढंग से कैसे काम करना चाहिए। मालवणी युवा परिषद के सदस्यों ने शहरी परिदृश्य के अपने ज्ञान को समृद्ध करने के लिए बहुत-सी कार्यशालाओं, संवादात्मक सत्रों, और प्रशिक्षणों में भाग लिया है। मालवणी युवा परिषद के कुछ सदस्यों ने YUVA के सिटी कारवाँ (शहरी क्राफ़िले), जो युवाओं की मदद और सहभागिता से समावेशी शहरों के सह-निर्माण पर एक पाठ्यक्रम है, में भाग लिया है जो शहरी वातावरण की जटिलताओं और इसमें व्यक्ति की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए है। चूँकि मालवणी युवा परिषद के सभी आन्दोलन और अभियान शहरी क्षेत्र में स्थित हैं, युवा अपने कार्यों और अनुभवों के आधार पर, लगातार नए दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, और नए जोश व उत्साह से शहर के साथ जुड़ रहे हैं। युवा सदस्य कई कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेते रहे हैं। अब तक दो युवाओं

ने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में भाग लिया है और वैश्विक समुदाय के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तीन युवा राष्ट्रीय सम्मेलनों का हिस्सा रहे हैं, और आठ ने राज्य स्तर पर मालवणी युवा परिषद का प्रतिनिधित्व किया है।

समुदाय-स्तर के बदलाव

नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण : समुदाय में वर्षों से नशीली दवाओं का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। मालवणी युवा परिषद के सदस्यों ने समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए इस विषय पर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन करने का फैसला किया, और उन्होंने नशे की बिक्री करने वाली सभी स्थानीय दुकानों का मानचित्रण किया। वे स्कूल के शिक्षकों से लेकर नागरिक समाज के साझेदारों तक समुदाय में विभिन्न हितधारकों के साथ यह तय करने के लिए जुड़े कि इस मुद्दे से सहयोगात्मक तरीके से कैसे निपटा जा सकता है। नाटक का कई बार मंचन किया गया और समुदाय द्वारा इसे सराहा गया। हालाँकि, ड्रग डीलरों को दबोचना हमेशा आसान नहीं था, क्योंकि वे समुदाय के कई सदस्यों के साथ करीब से जुड़े हुए थे और हर बार मालवणी युवा परिषद सदस्यों से बच निकलने में कामयाब रहे।



छायाचित्र 4. असमा अंसारी (दाएँ से द्वितीय), मालवणी युवा परिषद सदस्य, ने वर्ल्ड अरबन फ़ोरम (World Urban Forum—WUF) 9, मलेशिया, 2018 में युवाओं से सम्बन्धित कार्य पर एक सत्र में भाग लिया (स्रोत : YUVA)

एक मौक़े पर, एक युवा सदस्य पर नशेड़ियों के एक समूह द्वारा हमला किया गया था। युवा समूह ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कुछ समय के लिए पुलिस सुरक्षा प्राप्त की। जिस क्षेत्र में हमला हुआ था, वह एक त्यक्त स्थान था जहाँ नशेड़ी बार-बार आते थे। युवा सदस्यों ने इस स्थान को पहले साफ़ करके पुनः उपयोग योग्य बनाने, और फिर अपनी खेल

गतिविधियों के लिए उपयोग करने के बारे में सोचा। समय के साथ, यह घटना आज तक के सबसे शक्तिशाली आन्दोलनों में से एक, शहर-व्यापी स्थान का दावा करने वाले आन्दोलन (अगले बिन्दु में विस्तृत रूप से वर्णित), की दिशा में ले गई।

खेल, आत्म-अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के लिए रिक्त स्थानों का दावा करना : बच्चों के खेलने का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार है।^{xiii} हालाँकि, शहर में खेलने के स्थानों की कमी और ऐसे स्थानों तक पहुँच की कमी एक वास्तविकता है। कई वर्षों तक, मालवणी में समुदायों ने ऐसे स्थानों की माँग की थी जिनका बच्चों और युवाओं द्वारा एक समावेशी और लोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। 2016 में, क्षेत्र के युवाओं ने ब्लॉक III में खेलने के लिए एक स्थान को पुनः उपयोग योग्य बनाया, जो पहले नशेड़ियों और बदमाशों द्वारा उपयोग किया जाता था, और औपचारिक रूप से उसका उपयोग स्थानीय युवाओं और बच्चों के रचनात्मक विकास के लिए स्थान के रूप में किया जाने लगा। इस जगह अब 40-50 बच्चे और युवा लगातार आते हैं। समुदाय ने भी अपनी गतिविधियों का संचालन यहाँ करना शुरू कर दिया है, जिससे स्थान का समावेशी तरीके से विकास करने में मदद मिली। 2017 में YUVA की मदद से आयोजित शहर-व्यापी युवा मंच पर अपने अनुभव साझा करने के साथ स्थानों पर दावा करने के आन्दोलनों की शुरुआती सफलता की खबर शहर के अन्य हिस्सों में फैल गई। युवाओं द्वारा कई स्थानों को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है और आत्म-अभिव्यक्ति एवं सम्बद्ध अधिकारों के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित स्थानों के रूप में उनका उपयोग किया जा रहा है।^{xiv} यह आन्दोलन जारी है जिसे कई युवा समूहों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। मालवणी युवा परिषद का इरादा शहर के युवाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित स्थानों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्य में सक्रिय रूप से सहभागिता करने और नेटवर्क के भीतर दूसरों की सहायता करने का है।

एक अधिक लैंगिक-न्यायसंगत समुदाय की ओर : पहले, स्थानीय समुदायों की कई लड़कियों को स्कूल जाने, या घर के कामों में अपने अभिभावकों की मदद करने के अलावा किसी और कारण से अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। घरों में उनके एकाकी जीवन ने उनके बौद्धिक विकास को अवरुद्ध कर दिया और उनकी सामर्थ्य एवं सम्भावनाओं को सीमित कर दिया। उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वे खुद को अभिव्यक्त कर सकें और अन्य युवाओं के साथ जुड़ सकें। जैसे-जैसे मालवणी युवा परिषद द्वारा समुदायों के बीच अपने नुककड़ नाटकों का प्रदर्शन किया जाता रहा, युवाओं के साथ खेल और गतिविधियाँ आयोजित की जाती रहीं, और नए कार्यों एवं पहलों की शुरुआत की गई, लड़कियाँ धीरे-धीरे समूह में शामिल होने लगीं। YUVA के युवा कार्य स्टाफ़ ने भी समुदाय में घरों का दौरा करने और परिवारों से अपनी बेटियों को सामुदायिक केन्द्रों में तथा युवा समूहों के साथ समय बिताने की अनुमति देने के बारे में बात करने का इरादा किया। अभिभावकों को सोच और मानसिकता में बदलाव के लिए राज़ी करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन धीरे-धीरे अधिक लड़कियाँ मालवणी युवा परिषद में शामिल हो गईं और उन्होंने विभिन्न प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।

ज़रीन अंसारी, जो शुरुआत से ही मालवणी युवा परिषद की एक सदस्य हैं, बताती हैं, “मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, और मेरा जीवन केवल घर तक ही सीमित था। जब मैंने युवा समूह के साथ काम करना शुरू किया, तो मैंने दूसरों को भी इसी तरह की स्थितियों में देखकर प्रोत्साहित महसूस किया। नुककड़ नाटक के पहले कुछ पूर्वाभ्यास, जिनका मैं एक हिस्सा थी, के दौरान मैं काफ़ी घबराई। समय के साथ, मुझमें बहुत आत्मविश्वास आ गया और अब मैं समुदाय में घरों में भी जाती हूँ और अभिभावकों को प्रोत्साहित करती हूँ कि वे अपनी बेटियों को समूह के साथ समय बिताने दें।”

मालवणी युवा परिषद विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करने तथा लैंगिक दृष्टिकोण और बारीक़ियों (nuances) को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इन पहलुओं को जीवन के एक प्राकृतिक हिस्से के रूप में, और युवाओं से सम्बन्धित कार्य के एक अभिन्न अंग के रूप में लैंगिकता, प्रेम, और रिश्तों पर खेल और उचित चर्चाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। लैंगिक-अल्पसंख्यक समूहों से सम्बन्धित व्यक्तियों की पहचान, और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा ने उनके प्रति हमदर्दी और समझ को बढ़ाया है।

लड़कियों ने अपने अधिकारों की माँग के लिए पुरज़ोर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और इसका परिवारों एवं समुदायों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अभिभावक अब बेटियों द्वारा अपनी पढ़ाई जारी रखने का विकल्प चुने जाने को अधिक स्वीकार कर रहे हैं। कुछ ने अपनी बेटियों की शादी में देरी करने का समर्थन किया है और इसके बजाय उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। पहले का समुदाय युवा लड़कों और लड़कियों के बीच आपसी मेलजोल के बहुत ख़िलाफ़ था, लेकिन आज वे बड़े पैमाने पर इस तरह के मेलजोल और संवाद को स्वीकार कर रहे हैं। अब वे विपरीत लिंग के सदस्यों को एक साथ देखते हैं तो युवाओं को टोकते और शर्मसार नहीं करते हैं। यौन उत्पीड़न पर अधिक चर्चा और प्रस्तुतियों की बदौलत, समुदाय ने सुरक्षित स्थान स्थापित करने में मदद के लिए सक्रिय उपाय करना शुरू कर दिया है, और सड़कों पर लड़कियों पर मारी जाने वाली सीटियाँ या छेड़छाड़ काफ़ी कम हो गई हैं। जो लड़कियाँ पहले सिर्फ़ पुरुषों और लड़कों की निगाह से बचने के लिए पड़ोस के लम्बे, घुमावदार मार्ग अपनाती थीं, अब वे काफ़ी स्वतंत्र रूप से आना-जाना कर सकती हैं।

धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देना : मालवणी में रहने वाले लोगों में से कई लोगों की कमज़ोर स्थिति और अल्पसंख्यक पहचान, और एक दूसरे के साथ उनके सीमित सामाजिक संवाद के चलते (जो अकसर उनके काम, व्यापार, या रोज़गार के दायरे से आगे नहीं बढ़ता है), इन बस्तियों में धार्मिक तनाव हमेशा बना रहता है, और अकसर फूटकर सामने आ जाता है। जैसा कि बाला कहते हैं, “कई वर्षों तक मेरे चाचा सुझाव देते रहते थे कि मैं मालवणी चला

जाऊँ, लेकिन मैं अनिश्चित था क्योंकि वे जिस इलाके की सिफ़ारिश कर रहे थे, उसमें मुस्लिम-बहुल आबादी थी। यहाँ तक कि आखिरकार वहाँ चले आने के बाद भी, मैं वास्तव में यहाँ के युवाओं के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करता था।” खुद को कमज़ोर और असुरक्षित महसूस करने वाला बाला अकेला नहीं था। कई अन्य लोग उसकी तरह डर और अविश्वास महसूस करते थे।

जुड़ाव के वर्षों बाद, और विभिन्न माध्यमों (सामुदायिक बैठकों, गतिविधियों, प्रतियोगिताओं, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटकों) और रचनात्मक सन्देश के माध्यम से, युवा अब नियमित रूप से एक दूसरे से सम्पर्क रखते तथा संवाद करते हैं, और अब वे ही हैं जो साम्प्रदायिक सद्भाव के सन्देश का प्रचार करते हैं। पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के उनके सच्चे प्रयासों ने अन्य युवाओं को उनके समूहों से जुड़कर अन्य समुदायों तक सन्देश पहुँचाने के लिए प्रेरित किया। हर साल, युवा रमज़ान के महीने में इफ्तारी समारोह का आयोजन करते हैं। गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान वे स्थानीय मण्डलों में नुक्कड़ नाटक करते हैं, और इस प्रक्रिया में अधिक समुदाय के सदस्यों तक पहुँचते हैं। विभिन्न धार्मिक समुदायों के त्योहारों को लोगों को एकजुट करने के अवसरों के रूप में देखा जाता है।

प्रणालीगत परिवर्तनों की ओर

बुनियादी अधिकारों के बारे में जागरूकता और इसके लिए कार्यवाही को बढ़ावा देना, और कल्याणकारी उपायों तक पहुँच सम्भव बनाना : युवा सार्वभौमिक मानवाधिकारों और उनके लिए लड़ने की आवश्यकता के विषय में अपने समुदाय के सदस्यों के साथ जुड़ाव जारी रखते हैं। क़ानूनी और अन्य प्रक्रियाओं के विषय में अपनी जानकारी की बदौलत उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ज़बरन बेदखली का विरोध करने के प्रयासों में भाग लिया है, और उन्होंने अपने समुदाय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार (Right to Information—RTI) आधारित आवेदन प्रस्तुत करने का कार्य भी सक्रिय रूप से हाथ में लिया है। वे लगातार स्वयं के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि वे बेहतर तरीक़े से समझ सकें कि उनके अधिकारों को कैसे क़ायम रखा जा सकता है और संरक्षित किया जा सकता है।

मालवणी में बस्तियों में सुरक्षित पेय जल तक पहुँच सबसे अधिक चिन्ता का विषय है। इससे बच्चे और युवा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा करने की आवश्यकता का अर्थ है अपने समय का बलिदान करना, अपनी समय सारणी को समायोजित करना, और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शिक्षा से समझौता करना कि उनके परिवारों के पास दिनभर के लिए पर्याप्त पानी है। जब बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal

Corporation—BMC) ने आखिरकार पानी के कनेक्शन के लिए आवेदनों की प्रक्रिया शुरू की, तो युवाओं ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही मुंबई की बस्तियों में पानी की समान पहुँच के लिए एक बड़े शहर-व्यापी अभियान में भाग लिया। शहर में ऐसे आन्दोलनों के लिए उनकी प्रतिबद्धता कायम है जो उनकी माँगों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, और लोगों की आवाज़ को विस्तार दे रहे हैं ताकि उन्हें अधिक व्यापक रूप से सुना जा सके।

मालवणी में कई लोगों के सामने एक और मुद्दा राशन के प्रावधान और आपूर्ति का है। मालवणी युवा परिषद ने इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। सबसे पहले, उन्होंने दुकान के मालिकों के साथ जुड़ाव कायम किया और नियमित चर्चा एवं सूचनाप्रद सत्रों के माध्यम से देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System—PDS) के विषय में अपनी समझ को गहरा किया। इसके बाद, उन्होंने रात में अपने समुदायों के लिए सरल प्रस्तुतियाँ देना शुरू कर दिया, ताकि दिनभर के काम के बाद मित्र और रिश्तेदार इन आयोजनों में शामिल हो सकें। युवाओं ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और राशन प्रणाली तक जनता की पहुँच को आसान बनाने के लिए निर्मित किए गए विभिन्न क़ानूनी प्रावधानों पर चर्चा की। मालवणी युवा परिषद के सदस्यों ने विभिन्न समाजों में अभियानों के माध्यम से घर-घर जाकर समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों, के साथ जुड़ाव कायम किया, और उपयोगी जानकारी प्रदान की जिस पर समुदाय कार्यवाही कर सकता था।

नीतियों और योजनाओं पर कार्य करना : मुंबई विकास योजना (Mumbai Development Plan—MDP) की संशोधन प्रक्रिया के दौरान, जिसे आधिकारिक तौर पर संशोधित मसौदा विकास योजना (Revised Draft Development Plan) 2034 के रूप में जाना जाता है, युवाओं ने स्थानीय सरकार को सम्बोधित एक शहर-व्यापी अभियान के माध्यम से रचनात्मक रूप से अपनी माँगों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया।^{xv} उन्होंने न सिर्फ़ खुले स्थानों, अध्ययन केन्द्रों, और सामुदायिक केन्द्रों (जो उनकी तात्कालिक ज़रूरतें थीं) जैसी सुविधाओं के लिए भूमि आरक्षण माँगा, बल्कि बृहत् समुदाय में योजना के मुद्दों के महत्व के बारे में जागरूकता भी निर्मित की। उन्होंने जनता को अवगत कराने और शिक्षित करने के लिए संशोधित मसौदा विकास योजना 2034 पर अभियान संचालित किए, समुदाय के भीतर संवाद शुरू किया, और स्थानीय सरकार को इस संवाद के परिणामों से अवगत कराया। मालवणी युवा परिषद के साथ अपने अनुभव की बदौलत, और विशेष रूप से अपने आसपास के इलाक़ों में स्थानिक वितरण के बारे में उन्होंने जो कुछ सीखा, युवा बड़े स्तर (बारीक़ियों) पर सोचने में सक्षम हो गए थे। 2017 में, YUVA के समर्थन से, उन्होंने मनोरंजन सम्बन्धी और अन्य ज़रूरतों (इस खण्ड में पहले विस्तार के साथ वर्णित) के लिए स्थान, खुली और सार्वजनिक जगहें दोनों को पुनः उपयोग योग्य बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया। तब से उन्होंने अपने आसपास और सड़कों के किनारे, और पुलों के नीचे ख़ाली स्थानों का दावा किया है। इन स्थानों का या तो

दुरुपयोग किया जा रहा था या उनका उपयोग ही नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय प्रशासन में उनके सक्रिय जुड़ाव ने उन्हें अपने आसपास भूमि के इस्तेमाल के तरीके और इस मुद्दे का प्रबन्ध करने, इस पर बातचीत करने, और इसका प्रचार करने हेतु पैरवी करने के लिए प्रेरित किया।

मालवणी में अब तक 1,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, पाँच रोज़गार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, और प्रशिक्षण के बाद 250 से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के कार्यों में नियोजित किया गया है। 150 से अधिक युवाओं ने छात्रवृत्तियाँ प्राप्त की हैं। पहले औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हो चुके 100 से अधिक युवा मुक्त विश्वविद्यालय में लौट आए हैं या दूरस्थ शिक्षा मॉड्यूल के लिए नामांकित हुए हैं। हमारा काम पिछले कुछ वर्षों में दस से अधिक भागीदारों की सहायता आगे बढ़ा है।

चुनौतियाँ और टकराव

मालवणी युवा परिषद की स्थापना हुए कई महीने बीत चुके थे। कई चर्चाएँ और गतिविधियाँ आयोजित की गई थीं। युवाओं ने सक्रियता से सहभागिता की थी, अन्य लोगों को भी साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए समुदाय का समर्थन माँगा। हालाँकि, कुछ गड़बड़ तो थी। अब भी मालवणी युवा परिषद की अपनी एक अलग पहचान नहीं थी।

इस मुद्दे के समाधान के लिए, YUVA ने मालवणी युवा परिषद की पहचान बनाने के लिए एक और कार्यशाला आयोजित की। संवैधानिक मूल्यों के महत्त्व पर सत्र आयोजित किए गए, और किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान निर्मित करने को देश के एक नागरिक के रूप में उसकी बड़ी पहचान से जोड़ा गया था। कार्यशाला के दौरान एक निर्वाचन आयोजित कर मालवणी युवा परिषद के लिए नायकों (leaders) की एक समिति चुनी गई। जबकि पहचान निर्मित करने के इन प्रारम्भिक चरणों को लागू किया जा रहा था, आन्तरिक टकराव उभरने लगे। कुछ सदस्य नेतृत्व के ढाँचे से नाखुश थे और उन्होंने मालवणी युवा परिषद से अलग होने का फैसला किया। मालवणी युवा परिषद के लिए यह एक महत्वपूर्ण सबक था, क्योंकि समूह शुरू से ही सहभागी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित कर रहा था। फिर भी, मालवणी युवा परिषद द्वारा इन मूल्यों का पालन करने के बावजूद, युवाओं का एक वर्ग अलग-थलग महसूस कर रहा था। समूह के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण था कि वह अतीत में झाँककर यह आकलन करे कि भविष्य में सभी के बीच सहमति क़ायम करने और एक साथ काम करने के लिए क्या क़दम उठाए जाने चाहिए। युवाओं ने चर्चा की कि कैसे कुछ युवा सदस्यों के नेतृत्व कौशल को प्राथमिकता दी गई थी और कैसे नेतृत्व की एक दूसरी पंक्ति के निर्माण पर ध्यान देना भी आवश्यक था।

परस्पर विरोधी हित और विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले युवा भी कई बार असहमतियों में पड़ गए। हालाँकि, जैसे-जैसे वे अधिक अभियान और आन्दोलन आयोजित करने में एक दूसरे के साथ जुड़ते गए, युवाओं ने पाया कि उनके बीच और अधिक सामान्य आधार हैं तथा उनके लिए एक दूसरे के साथ अधिक परिपक्वता और आपसी सम्मान के साथ संवाद करना सम्भव हो गया।

यह कुछ चुनौतियाँ हैं जो समूह के कामकाज के शुरुआती वर्षों में सामने आई थीं। जैसे-जैसे यह बढ़ता गया और विकसित होता गया, मालवणी युवा परिषद के सामने नई और अधिक कठिन चुनौतियाँ आना अवश्यभावी है, और तदनुसार इनसे निपटने की आवश्यकता होगी।

सीखें

युवा सशक्तिकरण की प्रक्रियाओं के साथ YUVA के जुड़ाव के आधार पर, हमने मान लिया कि हम मालवणी में युवाओं के साथ परिवर्तन की एक क्रमिक प्रक्रिया में जुड़ने में सक्षम होंगे। हालाँकि, मालवणी के युवाओं के साथ हमारे रास्ते ने एक अलग दिशा ले ली है। पिछले कुछ वर्षों में, पारम्परिक “प्रभाव” बदल गए हैं और स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। सोशल मीडिया का प्रभाव, समूह का बढ़ता भगवाकरण, और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच असुरक्षा की एक गहराती भावना युवाओं के सामने आने वाली रोज़मर्रा की कुछ चुनौतियाँ हैं। इनके जवाब में, हमने समकालीन मुद्दों के समाधान के लिए कार्य के अपने तरीकों को बदला है। युवाओं की बेहतर ढंग से मदद करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए हम लगातार अपने प्रशिक्षण और सहायता प्रक्रियाओं को अद्यतन कर रहे हैं, और उन्हें स्थानीय समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ढाल रहे हैं। मालवणी युवा परिषद के साथ हमारे जुड़ाव से मिली सीखों ने हमें शहरभर के अन्य युवा समूहों के साथ हमारी अन्तःक्रिया में बदलावों को लागू करने में मदद की है। इन नए लचीले और अनुकूलनीय दृष्टिकोणों ने उन्मुक्त चर्चा और बहस के लिए मंच प्रदान करते हुए शहर स्तरीय मंचों के निर्माण के लिए अलग-अलग समूहों को एक दूसरे के करीब लाने में भी मदद की है।

YUVA द्वारा प्रशिक्षित युवा अब रिफ़ेशर शिविरों और अनुकूलन सत्रों के माध्यम से युवाओं के नए बैचों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सक्रिय रूप से उनके मुद्दों को उठाने के YUVA के प्रयासों से प्रोत्साहित होकर, अन्य युवाओं ने संगठन से सम्पर्क किया है और अपने विचार साझा किए कि वे जिन मुद्दों का सामना कर रहे हैं, उन्हें उस संगठन द्वारा उसी तरह निपटाया जा सकता है जिससे वे सम्बन्धित हैं या जिसे वे गठित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मालवणी में लड़कियों ने व्यक्तिगत क्षेत्रों में पुरुषों के वर्चस्व के मुद्दे को बार-बार उठाया। यह अन्ततः एक और युवा समूह (नक्षत्र—Nakshatra) के गठन का कारण बना, जो विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों पर केन्द्रित था। समूह ने महिलाओं के अधिकारों की एक हिमायती सावित्रीबाई फुले की जयन्ती पर रेटिंग कार्ड अभियान जैसी सरल लेकिन

प्रभावी पहलें आरम्भ कीं। इस दिन, लड़कियों ने अपनी माताओं के लिए एक रेटिंग कार्ड बनाया और घर-घर जाकर अपनी माताओं को उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। अभियान एक भावनात्मक चर्चा के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कई माताओं ने अपनी बेटी के सशक्तिकरण का समर्थन करने का वचन दिया।

मालवणी में हमारे प्रारम्भिक कार्य मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों पर थे। YUVA ने इच्छुक युवा सदस्यों को अन्य संगठनों द्वारा संचालित कौशल-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा। हालाँकि, जैसे-जैसे मालवणी में युवाओं के साथ YUVA का संवाद बढ़ा, सशक्तिकरण की पहल के अलावा कौशल प्रशिक्षण की माँग भी बढ़ी। YUVA के लिए युवाओं की इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने हस्तक्षेपों का अनुकूलन करना और अधिक सामान्य अर्थों में उन्हें सशक्त बनाना महत्वपूर्ण था ताकि वे उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके।

इससे पहले, YUVA द्वारा किए गए हस्तक्षेप समुदाय में लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए ज्ञान-निर्माण पर अधिक केन्द्रित थे। समय के साथ, अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान मुड़ा है। अब व्यक्तिगत क्षमताएँ विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से जीवन कौशल और दृष्टिकोण विकास से सम्बन्धित। व्यक्ति के विचार और दृष्टिकोण विकसित करने पर सत्र पहले से ही जारी हैं, यानी, यह समझना कि आन्तरिक, मानसिक और दृष्टिकोण सम्बन्धी परिवर्तनों के द्वारा किस प्रकार अधिक स्थाई परिवर्तन करे और प्राप्त किए जा सकते हैं और ज्ञान-निर्माण एवं कौशल विकास की पहलों में ये मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास पर सत्र व्यक्तिगत रुचि के क्षेत्रों (जैसे कठपुतली बनाने) से सम्बन्धित और ऐसे हैं जो पक्षसमर्थन के प्रयासों (जैसे—वीडियो बनाना और फोटोग्राफी) को मज़बूती प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

मालवणी युवा परिषद वर्तमान में अपना संविधान और दृष्टि पत्र तैयार करने में लगी हुई है, ताकि यह समूह के सभी भावी कार्यों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम कर सकें। युवा इस बात के लिए योजना का विस्तृत विवरण तैयार कर रहे हैं कि किस तरह उनके मूल्यों को और मज़बूती से स्थापित किया जाए और उन्हें किस तरह आगे ले जाकर विभिन्न स्थानों में अलग-अलग मुद्दों पर उनके काम में लागू किया जाए। मालवणी युवा परिषद की योजना निकट भविष्य में खुद का पंजीयन कराने की है। सदस्य सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शहर में एक मज़बूत उपस्थिति विकसित करने, समूह के संचालनों का विस्तार करने, नेटवर्किंग गतिविधियों में संलग्न होने, और अधिक हितधारकों के साथ काम करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। नेतृत्व की एक तीसरी पंक्ति भी विकसित और प्रशिक्षित की जा रही है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर विभिन्न स्तरों पर मज़बूत नेतृत्व उपलब्ध हो सके। युवा सदस्यों का व्यक्तिगत विकास एक और प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

युवा परिवर्तन YUVA के युवाओं सम्बन्धी कार्य का दीर्घकालिक लक्ष्य बना हुआ है। इसे प्राप्त करने के लिए, पहला क़दम मालवणी युवा परिषद की स्थापना करने का था और आसपास के एक बड़े निम्न-आय वाले इलाक़े में युवा पुरुषों और महिलाओं की सहभागिता को आसान बनाना था, जहाँ युवाओं के पास अपनी क्षमता के उचित उपयोग के लिए न तो अवसर है और न ही का साधन। जैसा कि इस केस स्टडी से पता चलता है, इस प्रक्रिया के आरम्भिक परिणाम व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों स्तरों पर परिवर्तन थे। परिवर्तनों का अगला दौर सामुदायिक स्तर पर देखा गया। यह परिवर्तन स्थानीय समुदायों के बीच विभिन्न धार्मिक पहचानों को स्वीकार करने, लैंगिक मानदण्डों को चुनौती देने, स्थानीय लोगों के लिए नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई शहरी योजनाओं की समझ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को चुनौती देने, इत्यादि पर आधारित था। इन परिवर्तनों ने युवाओं को सरकारी प्रणालियों, नौकरशाहों, पुलिस, मीडिया, और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाया है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्रमिक है, लेकिन निरन्तर जारी है। यह युवाओं के साथ हमारे कार्यों में परिवर्तन के सिद्धान्त में हमारे विश्वास को सुदृढ़ बनाता है। यह हमें मुंबई में युवा सशक्तिकरण की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए और अधिक करने के लिए प्रेरित भी करता है।



छायाचित्र 5. मालवणी युवा परिषद के सदस्य अपने संगठन के तीसरे स्थापना दिवस का उत्सव मनाते हुए, 2017 (स्रोत : YUVA)

आभार

परिवर्तन लाने के लिए स्व-प्रेरित प्रयासों में उनके विश्वास के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयासों के उनके स्वामित्व के लिए, परिवर्तन के लिए उनके उदार सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए, और इस केस स्टडी में अपनी यात्रा के अत्यन्त विस्तारपूर्वक दस्तावेज़ीकरण

हेतु सहमति देने के लिए मालवणी युवा परिषद के प्रति YUVA आभारी है। हम अपने सभी भूतपूर्व और वर्तमान युवा कार्यकर्ता सदस्यों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी प्रतिबद्धता के कारण युवाओं के साथ अथक रूप से काम किया है। बीते कुछ वर्षों के सामूहिक प्रयासों से शहरी क्षेत्रों में युवा कार्यवाही की शक्ति की एक चमकदार मिसाल के रूप में मालवणी युवा परिषद की उत्पत्ति और विकास हुआ है।

- i. Shirodkar, S. (2018, August 18). Engaging on safe spaces for youth. YUVA blog. Retrieved from <https://medium.com/@yuvaonline/engaging-on-safe-spaces-for-youth-7a65a2c3f6f3>
- ii. KRVIA and YUVA (2014). Malvani people's plan. Mumbai: KRVIA and YUVA. <http://yuvaonline.org/wp-content/uploads/2017/03/Malvani-Peoples-Plan-Complete.pdf>
- iii. D'Souza, D. (2015, December 15). It isn't a slum demolition—it's the destruction of homes and lives. Scroll.in. Retrieved from <https://scroll.in/article/775747/it-isnt-a-slum-demolition-its-the-destruction-of-homes-and-lives>
- iv. Economic Times (2014, November 18). India has world's largest youth population: UN report. Economic Times. Retrieved from <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-has-worlds-largest-youth-population-un-report/articleshow/45190294.cms>
- v. Chandramouli, C. (2011). Adolescents and youth in India: Highlights from Census 2011. Census of India, 2011. Retrieved from http://www.censusindia.gov.in/2011- Documents/PPT_World_Population/Adolescents_and_Youth_in_India_Highlights_from_Census_2011.pptx
- vi. Mallapur, C. (2017, July 26). High targets and wasted funds: The problems with the Skill India programme. Scroll.in. Retrieved from <https://scroll.in/article/844871/high-targets-and-wasted-funds-the-problems-in-the-skill-india-programme>
- vii. YUVA (2014). A situational analysis of health, education and

livelihood in Ambujwadi. Mumbai: YUVA.

- viii. Cooper, T. (2012). Models of youth work: A framework for positive sceptical reflection. *Youth and Policy*, 1(109), 98–117. Retrieved from http://www.youthandpolicy.org/wp-content/uploads/2017/06/cooper_models_of_youth_work.pdf
- ix. Jeffs, T. (2002). Whatever happened to radical youth work? *Concept*, 12(2). Retrieved from <http://concept.lib.ed.ac.uk/article/view/2363/3483>
- x. Kabeer, N. (2018, September). Gender, livelihood capabilities and women's economic empowerment: Reviewing evidence over the life course. *Gender & Adolescence: Global Evidence*. Retrieved from <https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2018/09/Economic-Empowerment-Report-WEB.pdf>
- xi. Belton, B. (2010). *Radical youth work: Developing critical perspectives and professional judgement*. Dorset: Russell House Publishing.
- xii. Leave No One Behind Partnership (n. d.). *Leave no one behind: Why we've come together*. The Leave No One Behind Partnership. Retrieved from <https://action4sd.org/leavenoonebehind/>
- xiii. S. Chatterjee. (2013, October 17). For healthy development, give children their right to play. *Hindustan Times*. Retrieved from <https://www.hindustantimes.com/india/for-healthy-development-give-children-their-right-to-play/story-ANsmgHd4mnxxVINUZEpp1J.html>
- xiv. Yuvaonline (n. d.). #UprootedChildhoods—Claiming spaces for play. YUVA blog. Retrieved from <https://medium.com/@yuvaonline/claiming-spaces-for-play-a1f543c5eebb>
- xv. Marina, J. (2018, September 6). Young people's participation: Critical for responsive city planning. *Urbanet*. Retrieved from <https://www.urbanet.info/mumbai-youth-participation-urban-planning/>

यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (YUVA), महाराष्ट्र

यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (Youth for Unity and Voluntary Action—YUVA) एक गैर-लाभकारी विकास संगठन है जो अरक्षित समूहों को उनके अधिकारों तक पहुँच में सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संगठन गरीबी को समाप्त करने और विकासशील देशों में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए शहरी गरीबों, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, और जन-केन्द्रित शहरी शासन और योजना पर ध्यान केन्द्रित करता है। 1984 में मुंबई में स्थापित हुआ YUVA वर्तमान में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम और नई दिल्ली राज्यों में कार्य कर रहा है।

YUVA शहरी गरीबों के साथ जुड़ाव के लिए एक स्थान निर्मित चाहता है ताकि वे स्वयं के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकें। इस दिशा में YUVA की योजना प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए जन संगठनों का निर्माण करने, जागरूकता निर्माण के लिए लोकप्रिय शिक्षा का संचालन करने, प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञान, बुनियादी अधिकारों और ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पहुँच प्रदान करने की है। YUVA विकास पर संवाद में संलग्न लोगों के संगठन को प्रोत्साहित करता है, जिससे समुदायों में स्व-निर्धारित और निरन्तर सामूहिक कार्यवाही सुनिश्चित होती है। इस कार्य में पक्षसमर्थन और नीति निर्धारण के लिए सिफ़ारिशें करना भी शामिल है।

सन्दर्भ निर्धारित करना

2. सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताओं के केस स्टडीज़

भारत ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों के मामले में प्रगति की है, विशेष रूप से शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने, और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के सम्बन्ध में। हालाँकि, बड़ी चुनौतियाँ बरकरार हैं।

पहली, भारत बीमारी के दोहरे बोझ का सामना करता है : मलेरिया, डेंगू, और तपेदिक जैसे संचारी रोगों के कारण रुग्णता और मृत्यु दर अब भी अस्वीकार्य रूप से अधिक हैं, साथ ही मधुमेह, हृदय रोग, और कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों का बोझ बढ़ता जा रहा है। प्राथमिक देखभाल सम्बन्धी नेटवर्क की उपेक्षा एक बड़ी चिन्ता है जो कई बीमारियों के होने को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, साथ ही साथ अस्पताल-आधारित देखभाल की तुलना में उन्हें और अधिक किफ़ायती ढंग से उनका निदान और इलाज सम्भव बना सकता है।

दूसरी, स्वास्थ्य सेवा की लागत में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है : स्वास्थ्य देखभाल के लिए अपनी जेब से भुगतान करने की आवश्यकता हर साल लाखों भारतीयों के ग़रीबी रेखा से नीचे आने के प्रमुख कारणों में से एक है। इसका मुख्य कारण एक मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की कमी है जो सुलभ, वहन करने योग्य (किफ़ायती) हो और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हो। परिणामस्वरूप, स्थिति ऐसी है कि ग़रीबों को भी देखभाल सेवाओं के लिए निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के पास जाना पड़ता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक निर्धारकों के कारण स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय असमानताएँ पाई जाती हैं। समय के साथ, जाति, वर्ग, लिंग, और निवास के आधार पर स्वास्थ्य सम्बन्धी असमानताएँ घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। उदाहरण के लिए, एक साल की उम्र से पहले एक बच्ची की मृत्यु का ख़तरा ग्रामीण उत्तर प्रदेश में केरल की बच्ची की तुलना में चार गुना ज़्यादा है (उत्तर प्रदेश में महिला मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 43 है जबकि केरल में यह 10 है)।

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों विशेषज्ञों द्वारा लम्बे समय से की जा रही एक सिफ़ारिश यह है कि सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है जो सबसे अधिक सीमान्त आबादी की ज़रूरतों को पूरा करे। सबसे पहली भारतीय राष्ट्रीय

स्वास्थ्य नीति (Indian National Health Policy—INHP, 1983) ने एक जन-केन्द्रित व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रणाली स्थापित करने की सिफ़ारिश की जो निवारक और प्रोत्साहक देखभाल के साथ-साथ बुनियादी उपचारात्मक देखभाल प्रदान करे। इसका मतलब न केवल उच्च गुणवत्ता की समुदाय-आधारित सेवाएँ प्रदान करने वाला एक कार्यात्मक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क है, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों जैसे—स्वच्छ पानी और स्वच्छता, टीकाकरण, पोषण सेवाएँ इत्यादि प्रदान करना है।

दुर्भाग्य से, इस प्रकार की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए संसाधन कभी भी उपलब्ध नहीं कराए गए, जो स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और उसके इस्तेमाल की सामर्थ्य के सन्दर्भ में स्वास्थ्य सम्बन्धी निष्पक्षता सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product—GDP) के लगभग 1.2% पर स्थिर हो गया है, हालाँकि उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए अच्छी गुणवत्ता की निवारक, प्रोत्साहक, और बुनियादी उपचारात्मक देखभाल के लिए सभी आदान (inputs) उपलब्ध कराने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 2-3% के बीच खर्च करना आवश्यक है।

वर्तमान में स्वास्थ्य प्रणाली के सामने आने वाली एक बड़ी महत्वपूर्ण बाधा सभी स्तरों पर पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी है। कार्मिकों के प्रशिक्षण में सिर्फ तकनीकी कौशल ही नहीं सिखाए जाने चाहिए बल्कि इससे देखभाल की समग्र गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से, डॉक्टरों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक निर्धारकों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से लैंगिक दृष्टिकोण से। वैश्विक प्रमाण बताते हैं कि महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों (उदाहरण के लिए, दर्द) के प्रति चिकित्सकों की बिरादरी की उदासीनता ने एक विश्वास की कमी पैदा कर दी है जो महिलाओं के स्वास्थ्य की माँग करने वाले व्यवहार को बाधित करती है। उदाहरण के लिए, प्रसव के दौरान प्रसूति सम्बन्धी क्रूरता महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों और उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के चुनाव को गम्भीरता से प्रभावित करती है। इस खण्ड में पहली केस स्टडी, चिकित्सा शिक्षा और नैदानिक अभ्यास में लैंगिकता को एकीकृत करना : सेंटर फॉर इन्क्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स (Centre for Enquiry into Health and Allied Themes—CEHAT) द्वारा प्रसूति विभाग और स्त्री रोग विभाग में परिवर्तन लाना, इस मुद्दे को सम्बोधित करने वाले एक शक्तिशाली परिवर्तनकारी हस्तक्षेप का वर्णन करती है। केस स्टडी महाराष्ट्र के औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग (Obstetrics and Gynaecology—OB-GYN) विभाग की है, जो स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक निर्धारकों के दृष्टिकोण को आसान बनाने में सफल रहा। सामान्य तौर पर, चिकित्सा

शिक्षा का दायरा चिकित्सा के जैव-चिकित्सा मॉडल तक सीमित है और समय की आवश्यकता है कि चिकित्सा शिक्षा के सभी विषयों में लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत किया जाए। यह हस्तक्षेप पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदीकरण मॉड्यूल के साथ ही लिंग संवेदनशील नैदानिक प्रोटोकॉल को शामिल करते हुए चिकित्सा शिक्षा में परिवर्तन का एक उदाहरण है। विभाग के कामकाज में इन उल्लेखनीय परिवर्तनों से महिलाओं की देखभाल के लिए प्रदान की जाने वाली देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

अन्य बाधा, जिसका पहले उल्लेख किया गया है, एक वास्तविक तौर पर जन-केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली बनाने में विफलता रही है। स्वास्थ्य परिणामों को गम्भीर रूप से प्रभावित करने वाले कई कारक स्थानीय वास्तविकताओं से जुड़े होते हैं; लेकिन यह राज्य या राष्ट्रीय स्तरों पर स्वास्थ्य लक्ष्यों के निर्धारण में गुम हो जाते हैं। ऐसी चुनौतियों के विभिन्न आयामों को पहचानना और समझना, एक समाधान तैयार करना, और उस समाधान को लागू करने के लिए स्थानीय ज्ञान, विज्ञान, और सामुदायिक जुड़ाव के एक विशेष संयोजन की आवश्यकता होती है। इस खण्ड में दूसरी केस स्टडी, धार, मध्य प्रदेश में एक हस्तक्षेप लोक विज्ञान संस्थान (People's Science Institute—PSI) द्वारा क्रियान्वित समुदाय-आधारित सुरक्षित पेय जल आपूर्ति के माध्यम से फ्लोरोसिस शमन का वर्णन करती है जो ऐसा एक विशेष संयोजन करने में सफल रहा है। यह हस्तक्षेप तकनीकी सहायता से भूजल प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके परिणामस्वरूप फ्लोरोसिस की समस्या का एक किफ़ायती और स्थाई समाधान हुआ—जो ज़मीन से खींचे गए पीने के पानी में फ्लोराइड की उच्च सान्द्रता के कारण विकलांगता कारित करने वाली लेकिन नज़रअन्दाज़ कर दी जाने वाली बीमारी है। केस स्टडी दर्शाती है कि वैज्ञानिक ज्ञान और साक्ष्य द्वारा निर्मित की गई जागरूकता किसी समुदाय को एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में बेहतर कार्य करने में समर्थ बना सकती है, जो कि इस मामले में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था और फ्लोरोसिस का शमन है।

2.1 चिकित्सा शिक्षा और नैदानिक अभ्यास में लैंगिकता को एकीकृत करना:

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में परिवर्तन

सेंटर फ़ॉर इन्क्वायरी इनटू हेल्थ एंड अलाइड थीम्स (CEHAT), महाराष्ट्र

सारांश

स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक निर्धारकों की स्थापित भूमिका के बावजूद, भारत में न तो चिकित्सा शिक्षा और न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं ने इसका संज्ञान लिया है। इन सामाजिक निर्धारकों की ग़ैर-मान्यता के कारण सामान्य रूप से रोगियों और विशेष रूप से सीमान्त समुदायों एवं वर्गों के रोगियों के साथ उपचार और देखभाल के वितरण में कई तरह से पक्षपात हुए हैं। विद्वानों ने चिकित्सा के क्षेत्र को लैंगिक-नेत्रहीन और पुरुष-पक्षधर माना है क्योंकि चिकित्सा ज्ञान जगत पुरुष शरीर को आदर्श के रूप में देखता है, जिसमें पुरुषों के अनुभवों को बीमारी के संकेतों और लक्षणों का वर्णन करने का आधार बनाया गया है। यह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (जिसे आगे औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज कहा गया है) में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की एक केस स्टडी है जो पूर्वस्नातक चिकित्सा छात्रों के शिक्षण में लैंगिक दृष्टिकोण को आसान बनाने में सफल रहा और जिसने नैदानिक अभ्यास को लैंगिक जानकारी-आधारित बनाने के साथ-साथ महिलाओं की ज़रूरतों के प्रति लैंगिक संवेदनशील बनाकर इसे परिवर्तित कर दिया गया। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के कामकाज में किए गए कुछ आमूलचूल परिवर्तनों में शामिल हैं—परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर सभी के लिए व्यापक गर्भनिरोधक सेवाएँ विभाग (Comprehensive Contraceptive Services for All Department) करना, सम्मानजनक मातृत्व देखभाल की अवधारणा लागू करना, यौन हिंसा के उत्तरजीवियों के लिए मेडिको-लीगल केयर (medico-legal care) की स्थापना, और हिंसा का सामना कर रही गर्भवती महिलाओं के लिए पहली पंक्ति की देखभाल शामिल करना। इस साक्ष्य-आधारित कार्यप्रणाली ने न केवल रोगी-प्रदाता सम्बन्ध को बढ़ाया है, बल्कि इन सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए सकारात्मक स्वास्थ्य अनुभव और परिणाम भी उत्पन्न किए हैं।

चिकित्सा शिक्षा और नैदानिक अभ्यास में लैंगिकता को एकीकृत करना : सन्दर्भ

पिछले दो दशकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक निर्धारकों के दृष्टिकोण का उदय हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization—WHO) के कमीशन ऑन सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ़ हेल्थ (Commission on Social Determinants of Health, 2005-2008) ने स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों (Social Determinants of Health—SDH) को “उन स्थितियों के रूप में जिनमें लोग जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, रहते हैं, काम करते हैं और बूढ़े होते (उम्र पूरी करते) हैं” और “इन परिस्थितियों के मूल संचालकों” के रूप में परिभाषित किया है। (पृष्ठ 26)। दूसरे शब्दों में, यह चिकित्सीय देखभाल से अलग कारक हैं जो आबादी के स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करते हैं। बड़ी मात्रा में साहित्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों और स्वास्थ्य के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणात्मक सम्बन्धों का समर्थन करता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी पक्षपात, जो विभिन्न जनसंख्या समूहों की स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति में अन्यायपूर्ण और प्रणालीगत अन्तर है, उचित कार्यवाही (WHO, Commission on Social Determinants, 2008) के माध्यम से सम्बोधित या समाप्त किया जा सकता है; यह सामाजिक कारकों का परिणाम है। विविध जनसंख्या समूहों में विभिन्न स्वास्थ्य लक्ष्यों का समान वितरण सम्भव बनाने के लिए इन कारकों को सम्बोधित करना महत्वपूर्ण है। यह भली भाँति सिद्ध किया जा चुका है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप जो रोगियों के सामाजिक सन्दर्भ और उनकी स्थितियों पर विचार करने में विफल रहते हैं, रुग्णता और मृत्यु दरों में कमी लाने में योगदान नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के डेटा (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण [National Family Health Survey—NFHS]) स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि दस्त, रक्ताल्पता, शिशु मृत्यु दर, और मातृ मृत्यु दर निम्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों वाले परिवारों में अधिक व्याप्त हैं (जनसंख्या विज्ञान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान [International Institute for Population Sciences—IIPS] and इनर सिटी फंड [Inner City Fund—ICF, 2017])।

स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करने में सामाजिक निर्धारकों की भूमिका पर साहित्य ने लैंगिकता को स्वास्थ्य में पक्षपातों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना है। चूँकि लैंगिक अन्तर के परिणाम महिलाओं के लिए अधिक घातक हैं, साहित्य में मुख्य रूप से महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य की पैरवी करने वालों द्वारा लिंग और लैंगिकता के बीच भेद करने की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों के विकास में इस पर विचार पर ज़ोर दिया जा सके। सामान्य तौर पर, जैविक कारकों के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। हालाँकि, भारत सहित दक्षिण एशियाई परिस्थितियों में, यह लाभ रद्द हो जाता है क्योंकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की जीवन प्रत्याशा से कम या बराबर है। कई अध्ययनों में महिलाओं के स्वास्थ्य पर लैंगिक भूमिकाओं के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है

(WHO, 2009)। गर्भावस्था और प्रसव की स्थितियाँ महिलाओं से सम्बन्धित विशिष्ट स्थितियाँ हैं और यह सामान्य जैविक प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा जोखिम उत्पन्न करती हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियों के महिलाओं पर अधिक गम्भीर परिणाम होते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी निम्न पहुँच होती है। महिलाओं की सीमित लैंगिक भूमिकाओं और समाज में उनकी निम्न स्थिति के कारण स्वास्थ्य की देखभाल सम्बन्धी उपायों या सेवाओं के उपयोग के बारे में उनका निर्णय लेने का अधिकार भी कम होने की सम्भावना रहती है (सेनारथ और गुणवर्दना [Senarath and Gunawardena], 2009)। भारतीय सन्दर्भ में, कई अध्ययनों ने बीमारियों और उनके उपचार में लैंगिक विषमताओं पर प्रकाश डाला है (भट और ज़ेवियर [Bhat and Xavier], 2003; महाराणा और लदूसिंह [Maharana and Ladusingh], 2014; साकिया, मोरध्वज और बोरा [Saikia, Moradhvaj and Bora], 2016)। इन अध्ययनों ने स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में व्याप्त लैंगिक असमानताओं को सम्बोधित करने की आवश्यकता है।

चिकित्सा के क्षेत्र में लैंगिक पक्षपात के स्वास्थ्य के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। चिकित्सा क्षेत्र की अकसर एक ऐसे क्षेत्र के रूप में आलोचना होती है जो नैदानिक अभ्यास, अनुसन्धान, स्वास्थ्य कार्यक्रम वितरण, चिकित्सा शिक्षा, और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में लैंगिक पहलू को ध्यान में नहीं रखता। यह पुरुषों का पक्षधर है, क्योंकि उपलब्ध ज्ञान पुरुषों पर केन्द्रित है और इसे अकसर महिलाओं के लिए सामान्यीकृत किया जाता है, इस प्रकार इसमें महिलाओं की विशिष्ट शारीरिक बनावट की अनदेखी की जाती है। यह लैंगिक पक्षपात के पहलू पर विचार नहीं करता है जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच में अतिरिक्त अवरोध पैदा होता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों को अकसर प्रजनन सम्बन्धी मामलों और गर्भावस्था से सम्बन्धित समस्याओं से ही जोड़कर देखा जाता है, इस प्रकार महिलाओं की अन्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं को अनदेखा किया जाता है, जिनमें उनकी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी ज़रूरतें भी शामिल हैं (वेरडोंक एवं अन्य [Verdonk et al.], 2008)।

संक्षेप में, लैंगिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखे जाने पर पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य सम्बन्धी असमानताओं के सन्दर्भ में जैविक और सामाजिक कारकों के बीच कोई अन्तर नहीं है। लैंगिक भूमिका विचारधारा, जिसे पुरुष और महिला रोगियों के प्रति स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (Healthcare Providers—HCPs) के रवैए के रूप में परिभाषित किया गया है, इन असमानताओं को अधिक स्पष्ट करती है (वेरडोंक एवं अन्य, 2009)। महिला रोगियों को अत्यधिक काम की अपेक्षा करने वाले के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक जानकारी चाहने वाले के रूप में देखा जाता है (फॉस और होफॉस [Foss and

Hofoss], 2004) और व्यवहार तथा भावनाओं जैसे अनियंत्रित कारकों को उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है (बेनरुड और रेड्डी [Benrud and Reddy], 1998)। महिलाओं के प्रति स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का नकारात्मक रवैया महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल की माँग करने से रोकने वाले (हतोत्साहित करने वाले) एक कारक के रूप में कार्य करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में लैंगिक दृष्टिकोण की कमी से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किए जाने वाले प्रावधान और उन तक पहुँच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम पुरुषों की सीमित भागीदारी के कारण अपनी सेवाओं में लैंगिक निष्पक्षता को नहीं जोड़ पाया है (गर्ग एवं सिंह [Garg and Singh], 2014)। गर्भपात सेवाओं तक पहुँचने वाली महिलाओं के प्रति स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का नकारात्मक रवैया सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है (सेबेस्टियन, खान एवं सेबेस्टियन [Sebastian, Khan and Sebastian], 2013)।

चिकित्सा शिक्षा में लैंगिक एकीकरण : परिवर्तन की आवश्यकता

स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार MBBS (चिकित्सा स्नातक, शल्यक्रिया स्नातक—Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery) पाठ्यक्रम में सामाजिक शिक्षा निर्धारकों को एकीकृत करके और स्वास्थ्य से उनके सम्बन्ध को मान्यता देकर भारत में स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। लैंगिक जानकारी-आधारित पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को स्वास्थ्य पर लैंगिक प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक बनने में सक्षम बनाएगा और उन्हें अपने चिकित्सीय अभ्यास में लैंगिक दृष्टिकोण से विचारों को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा (ज़ैलेक, फ़िलिप्स और लुफ़ेबुह [Zelek, Phillips and Lefebvre], 1997)। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में लिंग, वर्ग, जाति, धर्म, और लिंग-भेद की भूमिका को पहचानने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को सक्षम बनाने, और उसके बाद उनके चिकित्सा कार्य में लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित और एकीकृत करने के लिए यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। लिंग-विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए और सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत के लिए यह एक पूर्वापेक्षा है (बिकेल [Bickel], 2001)। इस मुद्दे के महत्व के बावजूद, भारत में पूर्वस्नातक चिकित्सा शिक्षा का दायरा चिकित्सा के एक बायोमेडिकल मॉडल तक सीमित है जिसमें रोगजनकों और उपचार के तौर-तरीकों जैसे स्वास्थ्य के समीपवर्ती निर्धारकों पर ज़ोर दिया जाता है। 2002 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य में लैंगिक पक्षपातों को कम करने के लिए एक लैंगिक नीति लागू करने की प्रतिबद्धता प्रकट की। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नायकों की एक परामर्श बैठक बुलाई गई जो इस निष्कर्ष पर पहुँची कि स्वास्थ्य में लैंगिक निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि सेवा-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में लैंगिकता को एकीकृत किया जाए। इस बात पर एक आम सहमति थी कि चिकित्सा शिक्षा के सभी विषयों में लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत किया

जाना चाहिए और चिकित्सकों को पेशेवर जीवन में निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों ने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के सेवा-पूर्व प्रशिक्षण में लैंगिक विचारों को एकीकृत करने के लिए पहल की। फिलीपींस और थाईलैंड सहित विकासशील देशों ने भी इसी तरह की पहल की।

यह पहले पूर्वस्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम (ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड) को एकीकृत करने का प्रयास करती हैं, चिकित्सा पाठ्यक्रम में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (तुर्की) जैसे विशिष्ट विषयों को लागू करती हैं, और महिलाओं के खिलाफ़ घरेलू हिंसा (Violence Against Women—VAW) (फिलीपींस) को सम्बोधित करती हैं। चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता को सम्बोधित करने वाली शुरुआती पहलों में से एक अमरीका में सन् 2000 में एसोसिएशन ऑफ़ प्रोफ़ेसर्स ऑफ़ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स (Association of Professors of Gynecology and Obstetrics—APOG) द्वारा की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा छात्रों को लिंग और लिंग-भेद के फ़र्क़ को पहचानने की शिक्षा देकर महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल को अनुकूलतम बनाना था। पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस तरीक़े से तैयार की गई थी कि चिकित्सा छात्रों को पैथोफ़िजियोलॉजी, एटिओलॉजी, (pathophysiology, aetiology) और अन्तर-सम्बन्धी निदान (differential diagnosis) तथा सामान्य, गम्भीर और महिला-विशिष्ट स्थितियों के लिए निदान और उपचार पर चर्चा करने के लिए ज्ञान से सुसज्जित किया जा सके और छात्रों में प्रमुख स्वास्थ्य क्षमताएँ निर्मित करने के प्रयास किए गए। लैंगिक और सांस्कृतिक अन्तरों को पहचानना और रोगियों की चिकित्सीय स्थिति पर सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत लिंग-आधारित भूमिकाओं के प्रभाव को समझना इन सभी विषयों के शिक्षण में सामान्य विषयवस्तु थी।

एक अन्य उदाहरण मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी (Monash University) और कनाडा में जेंडर एंड हेल्थ कोलेबोरेटिव करिकुलम प्रोजेक्ट (Gender and Health Collaborative Curriculum Project—GHCCP) के बीच सहयोग है; जिसमें से GHCCP कनाडा स्थित ओंटारियो प्रान्त के छह मेडिकल स्कूलों के संकाय और छात्रों का कार्य है। इस संयुक्त उद्यम के तहत, चिकित्सा पाठ्यक्रम में लैंगिकता को एकीकृत करने के लिए इसी तरह के प्रयास किए गए थे। सहयोग के परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षकों, छात्रों, और लैंगिकता एवं स्वास्थ्य में रुचि रखने वालों के लिए सामग्रियों का संग्रह तैयार किया गया। पाठ्यक्रम सामग्री की रूपरेखा इस तरह से तैयार की गई कि इसे छात्रों के लिए अपने-आप में पूर्ण मॉड्यूल के एक सेट के रूप में पढ़ाने के साथ-साथ एक लिंग-एकीकृत चिकित्सा पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा सके।

2002 में, फिलीपींस अपने चिकित्सा और नर्सिंग पाठ्यक्रमों में घरेलू और पारिवारिक हिंसा से जुड़ी चिन्ताओं को एकीकृत करने वाले पहले दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में से एक बन गया। सामुदायिक चिकित्सा, मनोचिकित्सा, औषधि, बाल चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, स्त्री रोग, और कानूनी चिकित्सा के विषयों से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में इन चिन्ताओं को एकीकृत करने की अपील की गई थी। पाठ्यक्रम के अन्त में, छात्रों से सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, लैंगिक-संवेदनशील, और सहानुभूतिशील चिकित्सकों और नर्सों के रूप में विकसित होने की अपेक्षा की जाती थी और यह भी कि उनमें प्रभावी संवाद और परामर्श कौशल भी विकसित होंगे।

2003-04 में, थाईलैंड ने MBBS के छः वर्षीय पाठ्यक्रम के पूर्वस्नातक चिकित्सा छात्रों के लिए लिंग-एकीकृत चिकित्सा शिक्षण शुरू करने का फैसला किया। उनके चिकित्सा पाठ्यक्रम में अब जातीयता, यौन अभिविन्यास, लिंग-भेद, और यौन शोषण के स्वास्थ्य सम्बन्धी परिणामों को पहचानने जैसे विषय शामिल हैं।

भारत में, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज़ एंड टेक्नॉलॉजी (Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology), त्रिवेंद्रम के अच्युत मेनन सेंटर फॉर हेल्थ साइंस स्टडीज़ (Achutha Menon Centre for Health Science Studies) द्वारा 2002 में चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता को एकीकृत करने की एक पहल की गई थी। सेंटर फॉर इन्क्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स इस पहल में भागीदारों में से एक था। इस तीन वर्षीय परियोजना के तहत, विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गईं, जैसे—लैंगिक संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक लैंगिक-संवेदनशील व्यवस्था के लिए मानदण्ड विकसित करना, चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए लैंगिक-संवेदनशील प्रशिक्षणों का आयोजन, और एक लैंगिक दृष्टिकोण से भारतीय चिकित्सा पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करना। इस परियोजना के परिणामस्वरूप प्रशिक्षित चिकित्सा शिक्षकों का एक पूल निर्मित किया गया, जिन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में अपने सम्बन्धित विषयों में लघु प्रशिक्षण और अभिविन्यास किए।

CEHAT ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर प्रतिक्रियास्वरूप चिकित्सा पेशेवरों के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर कई पहलों की अगुवाई की है तथा घरेलू और यौन हिंसा से उपजी समस्याओं का जवाब देने के लिए साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली मॉडलों का प्रदर्शन किया है। एक अस्पताल-आधारित संकटकालीन केन्द्र, दिलासा, मुंबई महानगरपालिका और CEHAT की एक संयुक्त पहल थी, जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को संवेदनशील बनाने और घरेलू हिंसा को एक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे के रूप में समझने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित की गई थी। सन् 2014 में, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission—NUHM) ने मुंबई के 11 अस्पतालों में इस मॉडल को दोहराया। अन्य

राज्यों ने भी दिलासा के मॉडल को अपनाया है। लिंग-आधारित हिंसा से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के साथ काम करने का यह अनुभव चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता पर परियोजना शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी।

इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, CEHAT ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund—UNFPA), महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान निदेशालय (Directorate of Medical Education and Research—DMER), और नासिक स्थित महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (Maharashtra University of Health Sciences—MUHS) के सहयोग से महाराष्ट्र में MBBS पाठ्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता को एकीकृत करने के लिए एक परियोजना शुरू की। इस परियोजना की अवधारणा अलग ढंग से की गई थी ताकि चिकित्सा शिक्षकों की क्षमताओं का निर्माण करके चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता को एकीकृत किया जा सके। इस परियोजना की शुरुआत चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान निदेशालय, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और अन्य विशेषज्ञों जैसे प्रमुख हितधारकों के लिए एक कार्यशाला के साथ की थी ताकि उनके इनपुट प्राप्त किए जा सकें। यह सहमति व्यक्त की गई कि चिकित्सा शिक्षा में लैंगिक एकीकरण CEHAT तथा चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान निदेशालय की एक संयुक्त पहल होनी चाहिए, चिकित्सा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और दृष्टिकोण में परिवर्तन के सन्दर्भ में प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए मॉड्यूल का परीक्षण कुछ चुनिन्दा चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जाना चाहिए।

परियोजना के बारे में

चिकित्सा शिक्षा में लैंगिक एकीकरण (Gender in Medical Education—GME) परियोजना महाराष्ट्र के चुनिन्दा चिकित्सा महाविद्यालयों में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य चिकित्सा संकाय और चिकित्सा छात्रों को स्वास्थ्य में लैंगिक निष्पक्षता के प्रति संवेदनशील बनाना था जो बाद में लैंगिक ज्ञानकारी पर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में जाने में सहयोगी होंगे। इसका उद्देश्य MBBS पाठ्यक्रम में लैंगिक दृष्टिकोणों को एकीकृत करके लिंग / लिंग-भेद में अन्तर, लैंगिक चयन, गर्भपात तक पहुँच, और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में लैंगिक संवेदनशीलता और जागरूकता हासिल करना था।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य थे :

1. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (Training of Trainers—ToT) कार्यक्रम के माध्यम से लैंगिक दृष्टिकोणों और महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों पर चिकित्सा संकाय की क्षमता का निर्माण।

2. उन MBBS छात्रों को लैंगिक दृष्टिकोण के शिक्षण की सुविधा प्रदान करना जो लिंग-संवेदी प्रशिक्षणों से गुज़र चुके थे। चिकित्सा शिक्षा में लैंगिक मुद्दों और दृष्टिकोणों को एकीकृत करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के साथ-साथ किसी लैंगिक-एकीकरण युक्त पाठ्यक्रम से गुज़रने वाले चिकित्सा छात्रों के ज्ञान और दृष्टिकोणों में बदलाव लाने की भी उम्मीद की गई थी।

अवधारणा के स्तर पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान निदेशालय, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राज्य महिला आयोग, और भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद (Indian Council of Medical Research—ICMR) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं, और लैंगिकता एवं स्वास्थ्य पर काम करने वाले संगठनों के साथ सितम्बर 2011 में चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता परियोजना पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजित की गई थी। कार्यशाला में, चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता परियोजनाओं के बारे में कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ सामने आईं। एक अनुशंसा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (Training of Teachers—ToT) के एक कार्यक्रम के विकास की थी जो पाँच विभागों पर केन्द्रित था : फ़ॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी (Forensic Medicine and Toxicology—FMT), मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (Preventive and Social Medicine—PSM), ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकॉलॉजी, और साइकियाट्री (Psychiatry)। इन विषयों को इसलिए चुना गया क्योंकि वे पूर्वस्नातक शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा हैं।

अवधारणा चरण के बाद हस्तक्षेप चरण हाथ में लिया गया, जिसमें MBBS छात्रों द्वारा लैंगिक दृष्टिकोण अपनाने और छात्रों को ये मॉड्यूल पढ़ाए जाने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए लैंगिक-एकीकरण युक्त मॉड्यूलों का विकास शामिल था।

परियोजना की शुरुआत में, चिकित्सा शिक्षकों को विशिष्ट तत्वों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जैसे—लिंग और लिंग-भेद के बीच अन्तर को समझना, स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार में लैंगिक भूमिका को पहचानना, और यह समझना कि पुरुषों, महिलाओं, और पुरुषों एवं महिलाओं के सीमान्त समूहों (विपरीतलिंगी, मध्यलिंगी, लैंगिक अल्पसंख्यक) द्वारा स्वास्थ्य का अनुभव अलग तरह से कैसे किया जाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य संचारी रोगों जैसे—यौन संचारित संक्रमण (Sexually Transmitted Infections—STI), प्रजनन पथ संक्रमण (Reproductive Tract Infection—RTI), और ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (Human Immunodeficiency Virus—HIV) और लिंग के उनके सम्बन्धों को समझना था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के संकेतों तथा लक्षणों को पहचानने और स्वास्थ्य प्रणाली को एवं उसके भीतर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के परिणामों को सूचित करने के कई तरीकों

पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। यह महत्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य से उनके महत्वपूर्ण सम्बन्धों के बावजूद वर्तमान में MBBS पाठ्यक्रम से नदारद हैं। संक्षेप में, लैंगिक मुद्दों पर प्रशिक्षण के क्षेत्र निम्नलिखित थे :

1. विभिन्न रोगों को समझने और उनका इलाज करने के लिए लिंग-आधारित विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित करना
2. स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा जिन रुढ़ियों का पालन किया जाता है उन्हें पहचानना और स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताओं को दूर करने में लैंगिक संवेदनशीलता विकसित करना
3. लिंग-भेद की अवधारणा की एक गहरी समझ विकसित करना
4. विविधतापूर्ण समूहों (पुरुषों, महिलाओं, विपरीतलिंगी, समलिंगी सम्बन्धों वाले लोगों) के लिए लिंग-संवेदी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना
5. महिलाओं और लड़कियों के लिए गर्भपात सेवा प्रदान करने में लैंगिक संवेदनशीलता शामिल करना
6. विभिन्न समूहों की यौन स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना
7. लिंग-आधारित हिंसा (Gender-Based Violence—GBV) को पहचानना और उसके सम्बन्ध में एक संवेदनशील तरीके से कार्यवाही करना।

परियोजना के घटक

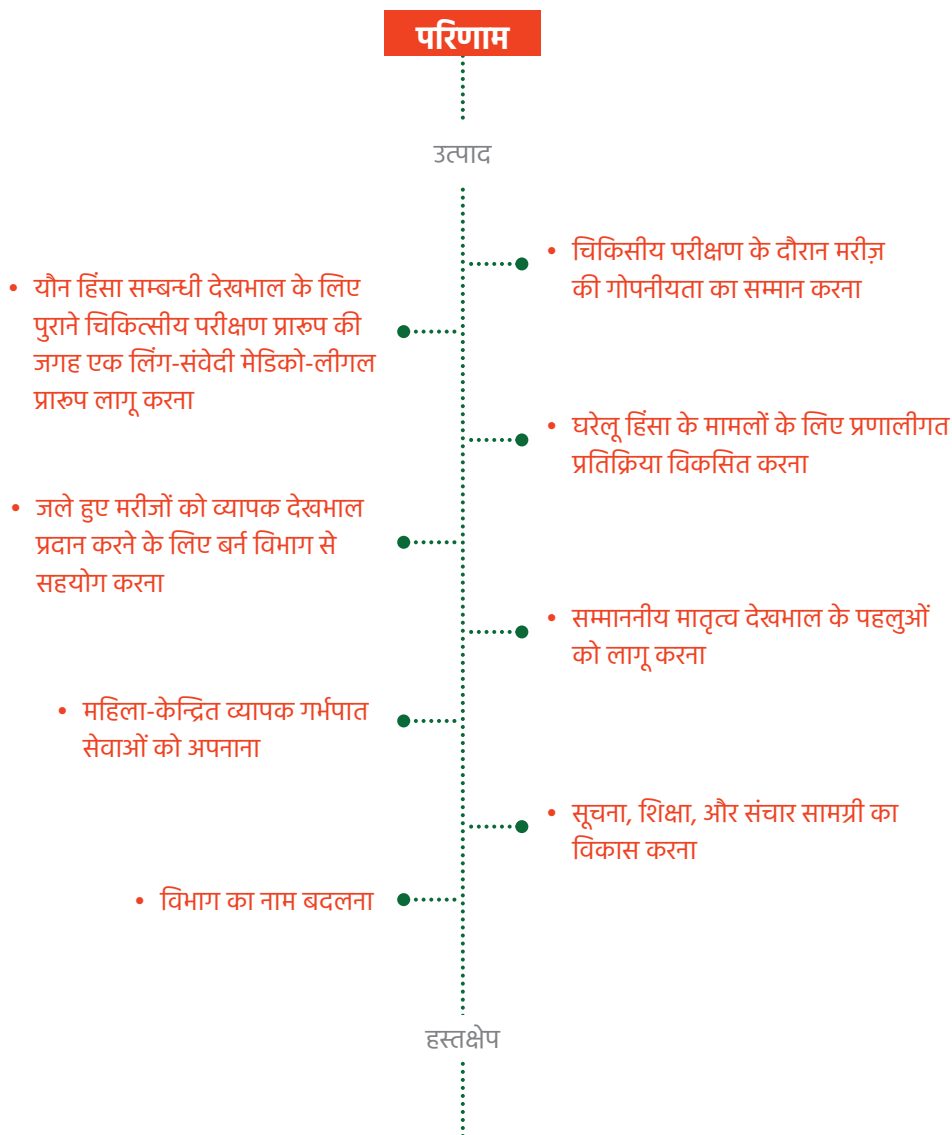
प्रशिक्षण के बाद, चिकित्सा शिक्षकों ने विशेषज्ञों के साथ यह आकलन करने के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा की कि पूर्वस्नातक छात्रों को पढ़ाने में लैंगिक पहलुओं को कैसे और कहाँ शामिल किया जाए। यह विशालकाय कार्य सभी पाँच विषयों, यानी स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान, फ़ोरेसिक विज्ञान और विष विज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा, मनोरोग, और आन्तरिक चिकित्सा के लिए किया गया था। चिकित्सा शिक्षकों का दृढ़ मत था कि छात्रों को अकादमिक विषयों को पढ़ाने के साथ-साथ, क्लीनिकों में और उनके व्यवहारिक पाठों में उनका मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होगा जहाँ वे रोगियों के साथ संवाद करते हैं। इससे यह निर्धारित करने के विशिष्ट तरीकों का इस्तेमाल करना सम्भव होगा कि क्या छात्रों ने लैंगिक चिन्ताओं को समझा और उन्हें आत्मसात किया है।

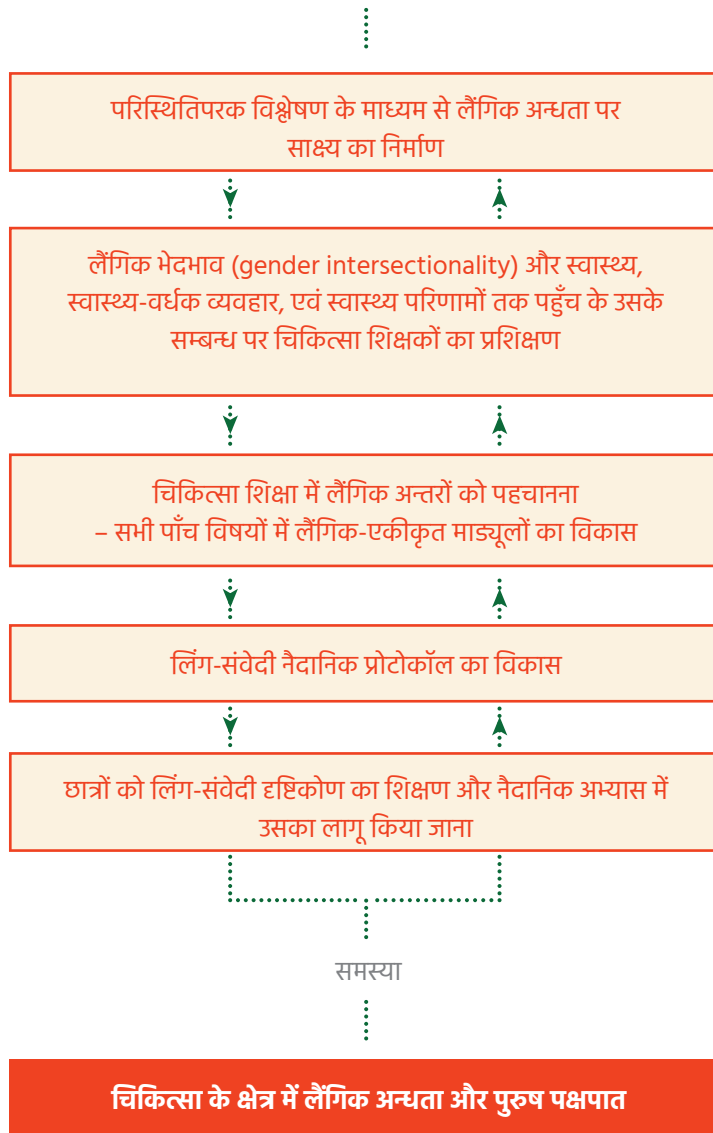


परिवर्तन का सिद्धान्त

चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता परियोजना के एक भाग के रूप में, प्रसूति और स्त्री रोग सहित पाँच विषयों में लिंग-संवेदी नैदानिक प्रोटोकॉल (अनुलग्नक 1 देखें) लागू किए गए थे। 2015 में इसकी शुरुआत करते हुए, प्रशिक्षित शिक्षकों ने नैदानिक अभ्यास में बदलाव लाने के लिए अपने सहयोगियों को संवेदनशील बनाया और प्रशिक्षित किया।

औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज में प्रसूति और स्त्री रोग सम्बन्धी प्रैक्टिस





केस स्टडी के बारे में

यह केस स्टडी मरीज़ प्रबन्धन में लिंग-संवेदी अभ्यास निर्मित करने और प्रोफ़ेसर्स, लेक्चरर्स, रेज़िडेंटों और इंर्नो सहित सभी स्तरों पर चिकित्सकों में लिंग-संवेदी दृष्टिकोण को समाहित करने के लिए औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के चिकित्सा शिक्षकों के प्रयासों का वर्णन करती है। बाद में नर्सों और सहायक कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया था।

दस लाख से अधिक की आबादी वाला औरंगाबाद महाराष्ट्र का पाँचवाँ सबसे बड़ा शहर है। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (Government Medical College Hospital—GMCH) महाराष्ट्र के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में से एक है और राज्य में सबसे बड़ा तृतीयक देखभाल अस्पताल (tertiary care hospital) है, जिसे चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान निदेशालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। अस्पताल में 1,177 बिस्तर हैं। सन् 2017 में औसतन 58,000 बाह्य रोगी प्रतिमाह यहाँ आते थे।

केस स्टडी से पता चलता है कि जब चिकित्सा शिक्षक चिकित्सीय अभ्यास में लैंगिकता सम्बन्धित विचारों को शामिल करने की ज़रूरत के बारे में आश्वस्त होते हैं तब मरीजों की बड़ी संख्या, खराब बुनियादी ढाँचे और अपर्याप्त स्टाफ़ के बावजूद वे लैंगिक-ज्ञानकारी आधारित सेवाएँ स्थापित और प्रदान करके बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस पहल के उत्साही पक्षसमर्थक जैसे—प्रसूति और स्त्री रोग विभाग प्रमुख (Head of the Department—HOD) और उनकी OB-GYN टीम प्रदर्शित करती है कि विभाग के कामकाज में वे कैसे उल्लेखनीय बदलाव लाने में सफल रहे हैं।



परिवर्तन का स्थान

परिवर्तन की प्रासंगिकता

यह उल्लेखनीय है कि सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals—SDG), जो एक वैश्विक कार्यवाही के लिए आह्वान करते हैं, साथ ही सभी के स्वास्थ्य और कल्याण (लक्ष्य 3) और लैंगिक समानता (लक्ष्य 5) को भी सम्बोधित करते हैं। यूनिवर्सल

हेल्थ कवरेज (Universal Health Coverage—UHC) के लिए शासनादेश भी सभी भारतीय नागरिकों (योजना आयोग, उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट [Planning Commission, HLEG Report], 2011) के लिए “न्यायसंगत” पहुँच सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में लैंगिक विचार को रेखांकित करता है।

प्रसूति देखभाल और गर्भपात सेवाओं के प्रावधान में लैंगिक संवेदनशीलता, साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रतिक्रियास्वरूप देखभाल, की आवश्यकता निम्नलिखित द्वारा साबित होती है। औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में नैदानिक अभ्यास में परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हैं।

1. लिंग-संवेदी प्रसूति सम्बन्धी देखभाल: इस बात के ज़्यादा-से-ज़्यादा सबूत मिल रहे हैं कि महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान निम्न देखभाल सेवाएँ प्राप्त होती हैं, जिसमें दुर्व्यवहार, अपमान, और उपेक्षा शामिल हैं (बोहरेन एवं अन्य [Bohren et al.], 2015)। इस तरह की प्रथाओं से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर गिरता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा का अधिकार प्रभावित होता है। इस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रत्येक महिला के गरिमापूर्ण और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के अधिकार को दोहराने के लिए “द प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ़ डिसरिस्पेक्ट एंड एब्यूज़ ड्यूरिंग फेसिलिटी-बेस्ड चाइल्डबर्थ” (The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth) शीर्षक से एक वक्तव्य जारी किया (WHO, 2014)। इसने सन् 2018 में ‘डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन्स : इन्ट्रापार्टम केयर फॉर अ पॉजिटिव चाइल्डबर्थ एक्सपीरियंस’ (WHO recommendations : Intrapartum care for a positive childbirth experience) (WHO, 2018) शीर्षक से सिफ़ारिशों का एक संग्रह भी जारी किया। इन सिफ़ारिशों में न केवल प्रसव-पीड़ा के प्रबन्धन के लिए नैदानिक दिशा-निर्देश शामिल हैं, बल्कि इसमें सम्मानजनक मातृत्व देखभाल के पहलू भी शामिल हैं। वे प्रसव को एक महिला-केन्द्रित, मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण से देखते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देते हैं कि महिलाओं के लिए प्रसव का अनुभव दुर्व्यवहार और अपमान से मुक्त हो, और यह एक सकारात्मक अनुभव हो जो एक सुरक्षित वातावरण में प्राप्त हो। भारत में भी, हाल ही में, सरकार द्वारा सकारात्मक प्रसव अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। मार्च 2018 में, भारत सरकार ने मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने, और मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने वाली महिलाओं की सन्तुष्टि को बढ़ाने के उद्देश्य से “लक्ष्य” कार्यक्रम (LaQshya—Labour Room Quality Improvement Initiative) लागू किया है।

इस सन्दर्भ में, विभाग के स्तर पर सम्मानजनक मातृत्व देखभाल के पहलुओं को शामिल करते लिंग-संवेदी सेवाओं का क्रियान्वयन एक साक्ष्य-आधारित मॉडल विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में दोहराया जा सकता है।

2. गर्भपात सेवाएँ: गर्भपात को भारत में 1972 से क़ानूनी मान्यता है, फिर भी असुरक्षित गर्भपात देश में मातृ मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण है (हैन्शॉ एवं अन्य [Henshaw et al.], 2009)। हालाँकि सरकार ने गर्भपात सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने की कोशिश की है, लेकिन कई बाधाएँ हैं जो महिलाओं को असुरक्षित परिस्थितियों में गर्भपात कराने पर मजबूर करती हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गर्भपात यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (Sexual and Reproductive Health—SRH) का एक अनिवार्य घटक है, और अब भी स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सभी जगह सेवा का प्रावधान एक समान नहीं है। भारतीय सन्दर्भ में, गर्भपात तक पहुँच पर कई अध्ययनों में अस्पताल स्तर पर विभिन्न रक्षात्मक अभ्यास पाए गए हैं जो गर्भपात कराने की इच्छुक महिलाओं को हतोत्साहित करने वाले कारकों के रूप में कार्य करते हैं। इन पद्धतियों में गोपनीयता की कमी और गर्भपात के लिए पति या किसी रिश्तेदार पर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए ज़ोर डालना शामिल है, भले ही गर्भ का चिकित्सीय समापन (Medical Termination of Pregnancy—MTP) क़ानून के तहत गर्भपात अनिवार्य हो। इसके अलावा, कई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ केवल इस शर्त पर गर्भपात सेवाएँ प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं कि प्रक्रिया के बाद महिलाएँ नसबन्दी या कॉपर अन्तःगर्भाशयी युक्ति यानी कॉपर-टी (Intrauterine Device—IUD) को अपनाएँ (आयंगर एवं अन्य [Iyengar et al.], 2015)। इसके अलावा, स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा महिलाओं को उनकी अपनी पसन्द की कोई गर्भपात विधि की पेशकश नहीं की जाती। आमतौर पर, सार्वजनिक अस्पतालों में गर्भपात की सबसे पसन्दीदा विधि फैलाव और खुरचना (dilation and curettage) है, जिसके लिए भर्ती होने की आवश्यकता होती है, और इसलिए चिकित्सीय गर्भपात कराने की इच्छुक महिलाओं को निजी चिकित्सकों या झोलाछाप चिकित्सकों के पास जाने को बाध्य होना पड़ता है (दुग्गल एवं रामचंद्रन [Duggal and Ramachandran], 2004)।

इन मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए, इन सेवाओं तक पहुँचने में महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं को पहचानने और सुरक्षित गर्भपात की पहुँच में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है।

3. महिलाओं के प्रति हिंसा और स्वास्थ्य परिणाम: साहित्य से प्राप्त होने वाले साक्ष्य इंगित करते हैं कि घरेलू हिंसा बीमारी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ज़िम्मेदार होती है क्योंकि इसका उत्तरजीवियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई

अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि घरेलू हिंसा से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, और यौन स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।

इस तरह की हिंसा के परिणाम चोट, ज़ख्म, फ्रैक्चर, जलना, योनि को क्षति पहुँचना, मनोरोग की स्थितियाँ, गर्भपात, इत्यादि होते हैं। भारत में प्रजनन योग्य आयु की महिलाओं की मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में से एक हिंसा है। महिलाओं को जलाना, ज़हर देना, चाकू से हमला करना, और आत्महत्या के लिए उकसाना कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिनमें परिवार के भीतर महिलाएँ मार दी जाती हैं। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव जन्म के समय बच्चों का वज़न कम होने से लेकर रक्ताल्पता तक, अवसाद से लेकर आत्महत्या तक, अस्पष्ट शारीरिक शिकायतों से लेकर गम्भीर बीमारियों जैसे—पेडू की सूजन (pelvic inflammatory) सम्बन्धी बीमारियों तक, बार-बार गर्भपात से लेकर क्रॉनिक पेन सिंड्रोम (chronic pain syndrome) तक, अनचाहे गर्भधारण और असुरक्षित गर्भपात से लेकर एचआईवी / एड्स तक, गर्भावस्था की जटिलताओं से लेकर मातृ मृत्यु तक, स्मृति लोप से लेकर उच्च दुश्चिन्ता (heightened anxiety) तक, कामुकता के डर से लेकर निम्न आत्मसम्मान तक होते हैं। वास्तव में, दुर्व्यवहार के मनोवैज्ञानिक परिणामों पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है और यह असम्बोधित रह जाते हैं। इनमें अवसाद, दुश्चिन्ता विकार, अभिघातजन्य तनाव सम्बन्धी विकार (post-traumatic stress disorder), आत्महत्या की प्रवृत्तियाँ और क्रॉनिक पेन की शिकायतें शामिल हैं (जैसे कि पीठ में दर्द, जो बार-बार होने वाले दुर्व्यवहार का एक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकता है)। हिंसा के कारण होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायतों और चोटों हेतु उपचार प्राप्त करने के लिए, महिलाएँ स्वास्थ्य सुविधा के लिए सम्पर्क करती हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिला द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की सम्भावना उन महिलाओं की तुलना में अधिक है जो हिंसा का सामना नहीं कर रही हैं। भारत के सात शहरों में किए गए एक बहु-स्थल अध्ययन के अनुसार, हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की लगभग आधी (45.3 प्रतिशत) महिलाओं ने चोटों की जानकारी दी जिनको इलाज की आवश्यकता है (INCLEN, 2000)। मुंबई के एक सरकारी शहरी अस्पताल में आपात विभाग के आपातकालीन पुलिस रजिस्टर में दर्ज महिलाओं के मामलों की जाँच करने वाले एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 15 साल से अधिक उम्र की दो-तिहाई महिलाओं (66.7 प्रतिशत या 497/745) के मामले निश्चित रूप से या सम्भवतः घरेलू हिंसा के मामले थे (डागा एवं अन्य [Daga et al.], 1999)। इसलिए स्वास्थ्य पेशेवर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं तक पहुँचने के लिए एक रणनीतिक स्थिति में हैं, जो कि हिंसा से बचे किसी उत्तरजीवी के लिए सबसे निश्चित और सम्भवतया जल्द-से-जल्द उपलब्ध होने वाला सम्पर्क है। हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की शीघ्र पहचान, और अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होना जारी रहता हो तो

स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा उचित मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के प्रावधान के माध्यम से इन महिलाओं के सामने आने वाले अधिक गम्भीर स्वास्थ्य परिणामों की रोकथाम की जा सकती है।

इसके अलावा, दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायतों का महत्वपूर्ण प्रलेखन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर किया जा सकता है। दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिला यदि क़ानूनी कार्यवाही करने का विकल्प चुनती है तो उसके द्वारा इस तरह के प्रलेखन का उपयोग न्यायालय में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। प्रलेखन के बारे में विस्तृत विवरण अन्य सत्रों में साझा किए गए हैं।

परिवर्तन

जैसे-जैसे चिकित्सा शिक्षकों द्वारा लिंग-एकीकृत पाठ्यक्रम का शिक्षण प्रदान किया जा रहा था, प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के चिकित्सा शिक्षकों ने अपने नैदानिक अभ्यासों को अधिक गम्भीर रूप से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कई मौजूदा नैदानिक पद्धतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। एक मान्यता थी कि जब लिंग-एकीकृत मॉड्यूलों का शिक्षण चल रहा है, तब चिकित्सा छात्र इस तरह के परिप्रेक्ष्य को आत्मसात करने में तभी सक्षम होंगे, जब वे विभाग में महिलाओं को दी जाने वाली नैदानिक देखभाल में परिवर्तनों का अवलोकन करेंगे। इसके चलते विभाग के स्तर पर क़दम-दर-क़दम परिवर्तन किए गए।

1. यौन हिंसा सम्बन्धी देखभाल के लिए पुराने चिकित्सीय परीक्षण प्रारूप की जगह एक लिंग-संवेदी मेडिको-लीगल प्रारूप लागू करना : चिकित्सा शिक्षक आश्वस्त थे कि वे बलात्कार के परीक्षण की पुरानी कार्यप्रणाली की तरफ़ वापस नहीं जा पाएँगे, जहाँ मरीज़ का पूर्ववृत्त सरसरी तौर पर माँगा जाता है और केवल साक्ष्य इकट्ठा किए जाते हैं। लैंगिक एकीकरण के एक भाग के रूप में, उन्होंने छात्रों को बलात्कार या यौन हिंसा को न केवल एक क़ानूनी मुद्दे के रूप में बल्कि एक गम्भीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में भी देखना सिखाया था, क्योंकि अवांछित गर्भधारण, यौन संचारित संक्रमण, चोट, और अन्य प्रकार के आघात इसके परिणाम हैं। इसलिए, शिक्षकों ने इसे व्यवहार में बदलने की आवश्यकता को पहचाना। पहले क़दम के रूप में, परीक्षण करने और देखभाल प्रदान करने के लिए उन्होंने बाह्य रोगी विभाग (Outpatient Department—OPD) की हलचल से दूर एक निर्दिष्ट स्थान स्थापित किया। दूसरा क़दम यह था कि इस तरह का परीक्षण करने और उपचार प्रदान करने के लिए हर समय एक प्रशिक्षित चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एक बेहद व्यस्त अस्पताल में, इस तरह का परीक्षण करने के लिए अतिरिक्त चिकित्सक

रखना असम्भव था। इस प्रकार, ड्यूटी रोस्टर (duty roster) में बदलाव कर एक चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई जो पहले से ही ड्यूटी पर हो और एक अतिरिक्त चिकित्सक उसकी मदद करे; जब पहला डॉक्टर यौन हिंसा से सम्बन्धित कार्य कर रहा होगा तब दूसरा उसके अन्य कर्तव्य संभाल लेगा। एक नया प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि सभी जाँचें एक ही दिन में की जाएंगी और बलात्कार के उत्तरजीवी को किन्हीं भी आगे की जाँचों के लिए पुनः नहीं बुलाया जाएगा। यह कार्यप्रणाली में एक आमूल बदलाव था, क्योंकि भारत के अधिकांश अस्पताल अभी भी या तो उत्तरजीवी को भर्ती करते हैं या उसे अगले दिन बुलाते हैं। यह कार्यप्रणाली अस्पताल के लिए सुविधाजनक है, लेकिन उत्तरजीवी के लिए अत्यन्त कष्टप्रद है। विभाग ने मनोसामाजिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए 'दिलासा कक्ष' नाम से एक परामर्श कक्ष भी स्थापित किया है। चूँकि हिंसा के ऐसे मामलों में जवाबी कार्यवाही के लिए कोई परामर्शदाता उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह सेवाएँ प्रदान करने के लिए मौजूदा सामाजिक सेवा अधीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था।

2. चिकित्सा परीक्षा के दौरान रोगी की गोपनीयता का सम्मान करना : सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा छात्रों के एक समूह की मौजूदगी में मरीजों की जाँच की जाती है क्योंकि भारत में पारम्परिक रूप से कई वर्षों से इसी तरह व्यवहारिक शिक्षण प्रदान किया जाता है। हालाँकि, इस सबमें, रोगी की गोपनीयता का बहुत कम विचार किया जाता है। लिंग-एकीकृत प्रशिक्षण ने चिकित्सा शिक्षकों को अपने विभाग के सभी कार्यक्षेत्रों में "गोपनीयता" की धारणा को मज़बूती प्रदान करने में सक्षम बनाया है। विभाग प्रमुख के शब्दों में, "यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था और अब मुझे अहसास होता है कि इसे लागू करना इतना आसान था।" एक परीक्षण के दौरान, कमरे में चिकित्सक के प्रवेश करने के बाद महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाता था, लेकिन इस कार्यप्रणाली को अब बदल दिया गया है। एक महिला परिचारिका या नर्स महिला को कमरे में तैयार करती है और शरीर के केवल उस हिस्से को उजागर करती है जिसका परीक्षण किया जाना है। प्रत्येक बिस्तर के स्तर पर पर्दे लगाए गए हैं ताकि व्यक्तिगत रोगियों के लिए भी गोपनीयता हो। अतीत में, चिकित्सकों को अक्सर महसूस होता था कि चूँकि प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में सभी मरीज़ महिलाएँ होती हैं, इसलिए गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब लैंगिक दृष्टिकोण से स्थिति का विश्लेषण किया गया, तो उन्हें इस कार्यप्रणाली को बदलने की आवश्यकता का अहसास हुआ। यह कोई बड़ा बुनियादी ढाँचागत बदलाव नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण और रवैए से सम्बन्धित बदलाव है, और यह एक मरीज़ की गोपनीयता को महत्त्व देने से सम्बन्धित बदलाव है। चिकित्सा छात्रों को प्रशिक्षित करने में एक चिकित्सक के लिए सबसे आम कार्यप्रणाली यह थी कि वह

छात्रों के सामने कोई शारीरिक स्थिति का संकेत देने के लिए रोगी का एक व्यवहारिक परीक्षण करे और फिर उपचार प्रदर्शित करे। लेकिन इसका स्थान अब कौशल प्रयोगशाला द्वारा ले लिया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India—MCI) की तरफ़ से यह आवश्यक होने के बावजूद, कई चिकित्सा महाविद्यालयों के पास प्रसूति और स्त्री रोग विभागों में ऐसी कौशल प्रयोगशालाएँ नहीं हैं जहाँ शिक्षक छात्रों को परीक्षण करने के तरीक़े महिला रोगियों के बजाय पुतलों पर सिखाते हैं। कौशल प्रयोगशाला चिकित्सा छात्रों को जननांग परीक्षण जैसी प्रक्रियाओं के संचालन में अपना कौशल पैना करने में मदद करती है।

3. जले हुए रोगियों को व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए बर्न विभाग के साथ

सहयोग : जलने की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं को शल्य क्रिया (surgery) वार्ड में रखा जाता है। ऐसे मामलों में जिनमें महिलाएँ गर्भवती हैं और जली हुई हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञों की पहले की कार्यप्रणाली में गर्भावस्था का आकलन करना और एक रिपोर्ट प्रदान करना शामिल था। संक्षेप में, “जलने” का पहलू किसी शल्य चिकित्सक द्वारा देखा जाता था, जबकि “गर्भावस्था” का पहलू स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा देखा जाता था। औषधीय उपचार के अलावा उपचार के प्रबन्धन पर कोई अभिसरण नहीं था। किसी लैंगिक दृष्टिकोण को समझने और उसे आत्मसात करने की बदौलत, प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के चिकित्सा शिक्षक जलने की रिपोर्ट करने वाली गर्भवती महिलाओं के मामलों का आकलन अब घरेलू हिंसा के सम्भावित मामलों के रूप में करने की आवश्यकता को पहचानने लगे हैं। इसने चिकित्सकों को रोगी के जलने की घटना के पूर्ववृत्त और उसके द्वारा अनुभव की गई घरेलू हिंसा के बारे में पूछने, और शारीरिक परीक्षण के निष्कर्षों का प्रलेखन करने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। यह एक महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण क़दम है, क्योंकि अक्सर प्रजनन योग्य उम्र की जो महिलाएँ जलने की रिपोर्ट करती हैं उन्हें चिकित्सकों और नर्सों द्वारा घरेलू हिंसा की सम्भावना के बारे में पूछताछ के बिना “दुर्घटना” का शिकार मान लिया जाता है। यह कार्यप्रणाली अब बर्न यूनिट द्वारा भी अपनाई गई है, जहाँ सभी जले हुए रोगियों के लिए एक प्रारूप विकसित करने की दिशा में एक झुकाव है।

4. घरेलू हिंसा के शिकार लोगों की पहचान और उसके जवाब में कार्यवाही करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया :

हिंसा के मामलों को सँभालने के लिए विभाग के चिकित्सा शिक्षकों को संवेदनशील बनाया और प्रशिक्षित किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान हिंसा का मातृत्व स्वास्थ्य और गर्भावस्था के परिणामों पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और इसलिए चिकित्सक अब प्रसवपूर्व देखभाल (Antenatal Care—ANC) प्रदान करते समय नियमित रूप से इसके बारे में पूछताछ करते हैं। प्रशिक्षण ने स्वास्थ्य देखभाल

प्रदाताओं के सन्देह सूचकांक को बढ़ाने में मदद की है जिसमें उन्हें महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य शिकायतों को पहचानना सिखाया जाता है जो हिंसा से जुड़ी हो सकती हैं। एक संवेदनशील तरीके से वे महिलाओं से घर पर होने वाली हिंसा के बारे में पूछते हैं और उन्हें प्रथम-पंक्ति का मनोसामाजिक सहयोग प्रदान करते हैं। मेडिको-लीगल शिकायत (Medico-Legal Complaint—MLC), जिसका साक्ष्यिक मूल्य होता है, घरेलू हिंसा के सभी मामलों में दर्ज की जाती है। उत्तरजीवियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभाग में एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है, और इस परामर्शदाता द्वारा नर्सों को महिलाओं को मनोसामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा है।

5. महिला-केन्द्रित व्यापक गर्भपात सेवाओं की स्थापना : भारत के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में, गर्भ के चिकित्सकीय समापन, जिसे गर्भपात भी कहा जाता है, तक पहुँच आसान नहीं है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन क़ानून वयस्क महिलाओं को गर्भपात सेवाओं तक पहुँच की अनुमति देता है। इसमें पति या सास के हस्ताक्षर प्राप्त करने, महिला के अविवाहित होने पर पुलिस में शिकायत करने, और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं को गर्भपात सेवाओं से वंचित करने जैसी शर्तें व्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भवस्था के एक उन्नत चरण (दूसरी तिमाही) में अस्पताल पहुँचने वाली महिलाओं के मामले में एक बालक की इच्छा के कारण लिंग-चयनात्मक गर्भपात कराने की आशंका होती है। कुछ अस्पतालों में भी “गर्भनिरोधक नहीं, गर्भ का चिकित्सीय समापन नहीं” (No contraception, no MTP) का एक अलिखित नियम भी है।

औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज ने कई सकारात्मक बदलाव अपनाए और पुरानी एवं रक्षात्मक कार्यप्रणालियों के स्थान पर अधिक महिला-केन्द्रित और लैंगिक-जानकारी आधारित सेवाएँ स्थापित कीं।

प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में गर्भपात सेवाओं तक कोई सशर्त पहुँच नहीं है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन सेवाओं का लाभ चाहने वाली महिलाओं के लिए बन्ध्याकरण या कॉपर टी या कॉपर आईयूडी का अन्तर्वेशन अनिवार्य नहीं है। महिलाओं को परामर्श दिया जाता है और परिवार नियोजन के सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे जानकारी-आधारित निर्णय ले सकें। महिला की सहमति से, पति को गर्भनिरोधकों का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में भी बताया जाता है और उसे बार-बार गर्भधारण के महिला पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बताया जाता है।

गर्भ के चिकित्सकीय समापन को लिंग-चयनात्मक गर्भपात से नहीं जोड़ा गया है। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता गर्भपात की माँग में देरी का कारण समझने के लिए एक व्यापक पूर्ववृत्त लेते हैं। यह जानकारी एक निर्धारित प्रारूप में एक रजिस्टर में ठीक से रखी जाती है।

गर्भ के चिकित्सकीय समापन के मामले में, अब केवल महिला से सहमति ली जाती है। इससे पहले, रिकॉर्ड पर पति के हस्ताक्षर होने पर ज़ोर दिया जाता था और परिणामस्वरूप कई मामलों में महिला कभी वापस नहीं आ पाती थी। चूँकि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं ने गर्भपात के सम्बन्ध में एक महिला के फैसले के इर्द-गिर्द की परिस्थितियों की अधिक समझ विकसित कर ली है, केवल महिला से सहमति ली जाने लगी है। गर्भपात के तरीकों के सन्दर्भ में भी, टीम अब शल्यक्रिया के बजाय चिकित्सीय गर्भपात और मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन (Manual Vacuum Aspiration—MVA) का उपयोग करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। विभाग यह सुनिश्चित करता है कि चिकित्सीय गर्भपात से सम्बन्धित दवाएँ नियमित रूप से उपलब्ध रहें, इस प्रकार महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच को एक वास्तविकता बनाया गया है।

औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज ने यौन हिंसा के उन मामलों में गर्भ के चिकित्सीय समापन की सेवाएँ पूरी सक्रियता से प्रदान की हैं जहाँ गर्भावस्था 28 सप्ताह से अधिक हो चुकी हो। विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और ऐसे कई मामलों में प्रयास किए क्योंकि उन्हें बलात्कार के परिणामस्वरूप होने वाली किसी गर्भावस्था को जारी रखने के नकारात्मक प्रभावों का अहसास था। पिछले दो वर्षों में, 20 से 28 सप्ताह के बीच की गर्भावस्था वाली आठ गर्भवती महिलाओं ने विभाग से विशेषज्ञ की राय लेने के बाद अदालत के आदेश के माध्यम से गर्भपात कराने की क़ानूनी अनुमति प्राप्त की।

इन महिलाओं को विभाग से सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ प्राप्त हुईं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में कई अस्पताल एक उन्नत गर्भावस्था के मामले में सक्रिय क़दम नहीं उठाते हैं, यहाँ तक कि इस बात की पूरी जानकारी के बावजूद भी क़दम नहीं उठाते कि गर्भावस्था बलात्कार का एक परिणाम है। इस सन्दर्भ में, औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज ने एक स्पष्ट उदाहरण प्रदान किया है कि ऐसा मामला कैसे संभाला जाना चाहिए।

6. विभाग का नाम बदला जाना एक महत्वपूर्ण और युगांतरकारी परिवर्तन है : विभाग का नाम बदला जाना सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक था। विभाग का नाम परिवार नियोजन विभाग से बदलकर सभी के लिए व्यापक गर्भनिरोधक सेवा केन्द्र (Comprehensive Contraceptive Services for All Centre) कर दिया गया।

यह एक महत्वपूर्ण क़दम है क्योंकि विभाग का मानना है कि गर्भनिरोध, गर्भपात सेवाओं सहित, केवल परिवार का आकार सीमित करने तक ही सीमित नहीं है और गर्भनिरोधक की ज़रूरत सभी महिलाओं को है। मानवाधिकार के दृष्टिकोण के सन्दर्भ में, नाम में परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 'परिवार नियोजन' शब्द को अधिक समावेशी शब्द 'गर्भनिरोधक' से बदल देता है, जो सभी व्यक्तियों की गर्भनिरोधक ज़रूरतों को सम्बोधित करता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो पारम्परिक पारिवारिक इकाई के दायरे से बाहर रह जाते हों।

7. सम्मानजनक मातृत्व देखभाल के पहलुओं को लागू करना: चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता परियोजना विभाग में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को महिला रोगियों द्वारा सहे जा रहे अपमान और दुर्व्यवहार के मुद्दे को समझने और सम्बोधित करने में सक्षम बनाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी अस्पताल के ढाँचे में महिलाओं को प्रसव के दौरान अधिक कुशल और सम्मानजनक देखभाल प्राप्त हो, उन्होंने सम्मानजनक मातृत्व देखभाल के मुख्य घटकों को लागू किया।

प्रसवपूर्व बाह्य रोगी विभाग में महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था निर्मित करना: प्रसवपूर्व बाह्य रोगी विभाग में, पहले बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी; गर्भवती महिलाओं को लम्बे समय तक खड़े रहना पड़ता था। जैसे ही चिकित्सक आता था, मरीज़ उसके कमरे की तरफ़ दौड़ते थे। इससे चिकित्सकों और रोगियों के बीच बहुत अधिक टकराव पैदा होता था, नर्सों द्वारा रोगियों को क़तार में नहीं लगने और आमतौर पर अशान्ति उत्पन्न करने के लिए डाँटा जाता था। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिंग संवेदीकरण के साथ यह स्थिति बदल गई, क्योंकि उन्हें इस बात का अहसास होने लगा कि महिलाओं को अस्पताल पहुँचने में कई घण्टे लगते हैं; बेंचों और बैठने की जगहों की व्यवस्था लागू करके प्रतीक्षा अवधि को सहनीय बनाया जा सकता है ताकि महिलाओं और उनके परिजनों को आराम मिले और वे भी बाह्य रोगी विभाग में भीड़ न लगाएँ। यह व्यवस्था चिकित्सकों और महिला रोगियों दोनों के लिए मददगार पाई गई।

उपचार के लिए गम्भीर रोगियों की छँटाई (triaging—ट्राइएजिंग) की व्यवस्था लागू करना: किसी रोगी के लिए देखभाल की तात्कालिकता निर्धारित करने के लिए गम्भीर रोगियों की छँटाई (triage—ट्राइएज) प्रारम्भिक या प्राथमिक मूल्यांकन है। पहले आओ, पहले पाओ (first come, first serve) के आधार की तुलना में, ट्राइएज उन मरीज़ों को उपचार में प्राथमिकता देकर प्रत्येक व्यक्तिगत रोगी के लिए लाभ को अधिकतम करने पर केन्द्रित होता है जिनकी ज़रूरत सबसे तात्कालिक होती है। गम्भीर रोगियों और नियमित रोगियों के बीच अन्तर करने के लिए, विशेष रूप से प्रसूति कक्ष में, ट्राइएज महत्वपूर्ण होता है। ट्राइएज

इंडेक्स को तैयार करने के लिए सभी महिलाओं की जाँच शून्यकाल में (at 0 hour) की जाती है। अत्यधिक काम का बोझ और कर्मचारियों की कमी होने पर चिकित्सकों और नर्सों की ज़िम्मेदारियों को विभाजित करने में भी ट्राइएज सहायक होता है। ट्राइएजिंग के लिए विभाग ने प्रसूति वार्ड से सटा एक स्थान आवण्टित किया है। इसमें कुछ प्रसूति बिस्तरों के साथ एक स्वागत क्षेत्र (reception area) है। इससे स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को समय पर देखभाल प्रदान करने और चिकित्सकों के बीच कार्यभार के समान वितरण में भी मदद मिली है।

प्रसूति कक्ष में सभी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी-आधारित सहमति एकीकृत करना: सामान्य तौर पर, प्रसव के दौरान की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए सहमति प्राप्त करना अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यदि इस पर कोई ध्यान दिया जाता है, तो इसे किसी प्रकार की आक्रामक प्रक्रिया को करने के लिए परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बारे में एक औपचारिकता भर माना जाता है। महिलाओं को प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी संगत जानकारी प्रदान कर उनसे सहमति लेने के लिए रेज़िडेंट चिकित्सक को प्रशिक्षित किया जाता है। अब, प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग से सहमति ली जाती है और यह कार्य एक नैतिक तरीके से संचालित किया जाता है।

साक्ष्य-आधारित प्रसव की शुरुआत: प्रसव के अति-चिकित्सकीकरण, जिसमें भगछेदनों और सीज़ेरियन प्रसवों (episiotomies and caesarean sections) जैसे हस्तक्षेपों का अत्यधिक या अनुचित उपयोग शामिल है, रुग्णता और मृत्यु दर में योगदान कर सकते हैं। मातृत्व देखभाल पर साहित्य ने व्यापक भगछेदनों, प्रसव के बाद चीरों में टाँके लगाना, और बिना निश्चेतना (anaesthesia) भगछेदन को एक शारीरिक दुर्व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है। औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज में, विभाग के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को साक्ष्य-आधारित चिकित्सा प्रणाली अमल में लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। गर्भवती महिलाओं के अनावश्यक भगछेदन और सीज़ेरियन प्रसव घटाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। साक्ष्य-आधारित मापदण्डों जैसे कि प्रसूति पूर्ववृत्त, प्रसव-वेदना की शुरुआत, भ्रूण की स्थिति, नवजात शिशुओं की संख्या, और गर्भकालीन आयु के आधार पर आवश्यकता का आकलन करने के लिए विभाग नियमित सीज़ेरियन ऑडिट करता है।

पहले से मौजूद बिस्तरों को प्रसव शय्याओं में बदलना और प्रसव-वेदना से गुज़र रही महिलाओं को उनकी पसन्द की स्थिति अपनाने की अनुमति देना: प्रसूति-कक्ष में बिस्तरों में बदलाव किए गए हैं ताकि महिलाओं को प्रसव के दौरान आराम महसूस हो। प्रसूति के लिए

फ़र्श पर घुटने टेकने जैसी स्थितियाँ चुनने की स्वतंत्रता का महिला के आराम के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और प्रसूति की प्रगति को गति देता है। प्रसव स्थिति का चुनाव प्रसूति के अनावश्यक प्रेरण की आवश्यकता को भी कम करता है। इसका परिणाम ग्राहकोन्मुखी मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में प्रकट होता है जिसका सम्बन्ध बेहतर सन्तुष्टि और सुविधा-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में वृद्धि से होता है। विभाग का लक्ष्य प्रसव के दौरान बैठने की स्थिति (squatting position) को अपनाना है, जो बिना चीरफाड़ योनिक प्रसव में मदद करता है।

प्रसव के जन्म के बाद माँ और नवजात शिशु को एक साथ रखना: बच्चे को दो से तीन मिनट के लिए माँ के पेट पर रखा जाता है और फिर शिशु तथा माँ दोनों के लिए परिणाम में सुधार लाने के लिए गर्भनाल (umbilical cord) को जकड़ दिया (clamped) जाता है। गर्भनाल को जकड़ने में विलम्ब और प्रसव के तुरन्त बाद बच्चे को माँ के पेट पर रखने से प्रसव के बाद रक्त की कम क्षति होती है, जिससे माँ और नवजात शिशु में रक्ताल्पता पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है।

प्रसव-वेदना से गुज़र रही महिलाओं को अपनी इच्छानुसार भोजन और तरल पदार्थों का सेवन करने की अनुमति देना: पहले की कार्यप्रणाली में प्रसव-वेदना के दौरान इस चिन्ता के कारण भोजन और तरल पदार्थ का सेवन प्रतिबन्धित कर दिया जाता था कि सामान्य निश्चेतना के दौरान पेट की सामग्री फेफड़ों में न आ जाए। हालाँकि, इसके पक्ष में कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं है और इसलिए महिलाओं की पसन्द का सम्मान करने के लिए विभाग में कार्यप्रणाली बदल दी गई।

एक प्रसव साथी उपलब्ध करना: आमतौर पर प्रसूति-कक्ष में एक सख्त “प्रवेश निषेध” नीति होती है और विभाग के बाहर मौजूद सभी लोगों के लिए इसे दर्शाने वाला कोई संकेत लगा रहता है। प्रसव-प्रक्रिया से गुज़र रही महिलाएँ अन्दर होती हैं जबकि उनके परिजन बाहर इन्तज़ार करते हैं। प्रसूति में कई घण्टे लगते हैं, और अन्दर प्रसव-प्रक्रिया से गुज़र रही महिला और बाहर इन्तज़ार कर रहे उसके परिजनों की चिन्ता और तनाव बढ़ रहे होते हैं। कर्मचारियों की कमी को देखते हुए, नर्सों और चिकित्सकों को बड़ी संख्या में महिलाओं की प्रसूति करानी होती है और यह सम्भव नहीं होता कि हर एक महिला की देखभाल में एक अलग व्यक्ति लगा हो। इससे काफ़ी गुस्सा और निराशा पैदा होती है। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, एक प्रसव साथी (birth companion) की अवधारणा प्रस्तुत की गई जिसमें प्रसव-प्रक्रिया से गुज़र रही महिला की सहायता उसके परिवार की एक अनुभवी

महिला द्वारा की जाती है जो प्रसव-प्रक्रिया की अवधि के दौरान उसके साथ मौजूद रहती है। महिलाओं को अपनी पसन्द के साथी के सहयोग और प्रोत्साहन के साथ प्रसव का अनुभव प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया जाता है। साहित्य में इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि एक प्रसव साथी की उपस्थिति से मातृ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है, जिसमें सामान्य प्रसव की सम्भावना बढ़ना, प्रसव में कम समय लगना सुनिश्चित होना, और स्तनपान की जल्दी शुरुआत को प्रोत्साहित करना शामिल है। प्रसव साथियों को प्रसव के दौरान खतरे के संकेतों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे कर्तव्य पर उपस्थित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को सचेत कर सकें। संक्रमण से बचाव के लिए प्रसव साथी को दस्ताने और गाउन प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं ने नैतिक सहारा प्रदान करने वाले किसी प्रसव साथी की मौजूदगी में प्रसव के अनुभव को सकारात्मक बताया है।

8. सूचना, शिक्षा, और संचार (Information, Education, and

Communication—IEC) सामग्री का विकास: विभाग ने बाह्य रोगी विभाग में इन्तज़ार कर रहे रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार की सूचना, शिक्षा, और संचार सामग्री तैयार की है। सूचना, शिक्षा, और संचार सामग्री में महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं, जैसे कि पूर्व-प्रसवाक्षेप (pre-eclampsia), के शुरुआती लक्षण शामिल हैं।

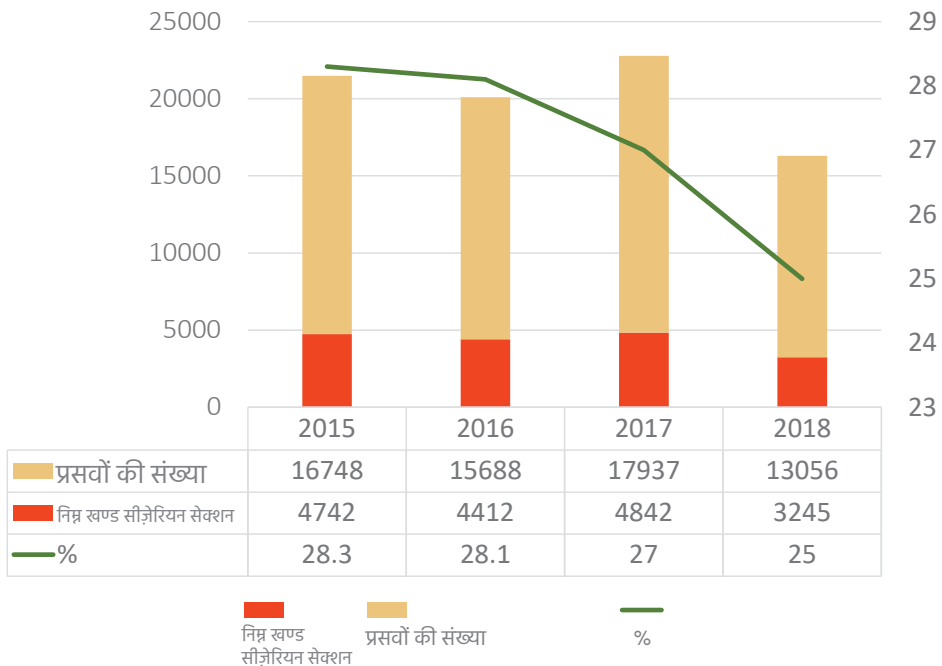
चिकित्सीय कार्यप्रणाली में किए गए परिवर्तनों के परिणाम :

1. मानक परिचालन प्रक्रियाओं (Standard Operating Procedures—SOPs)

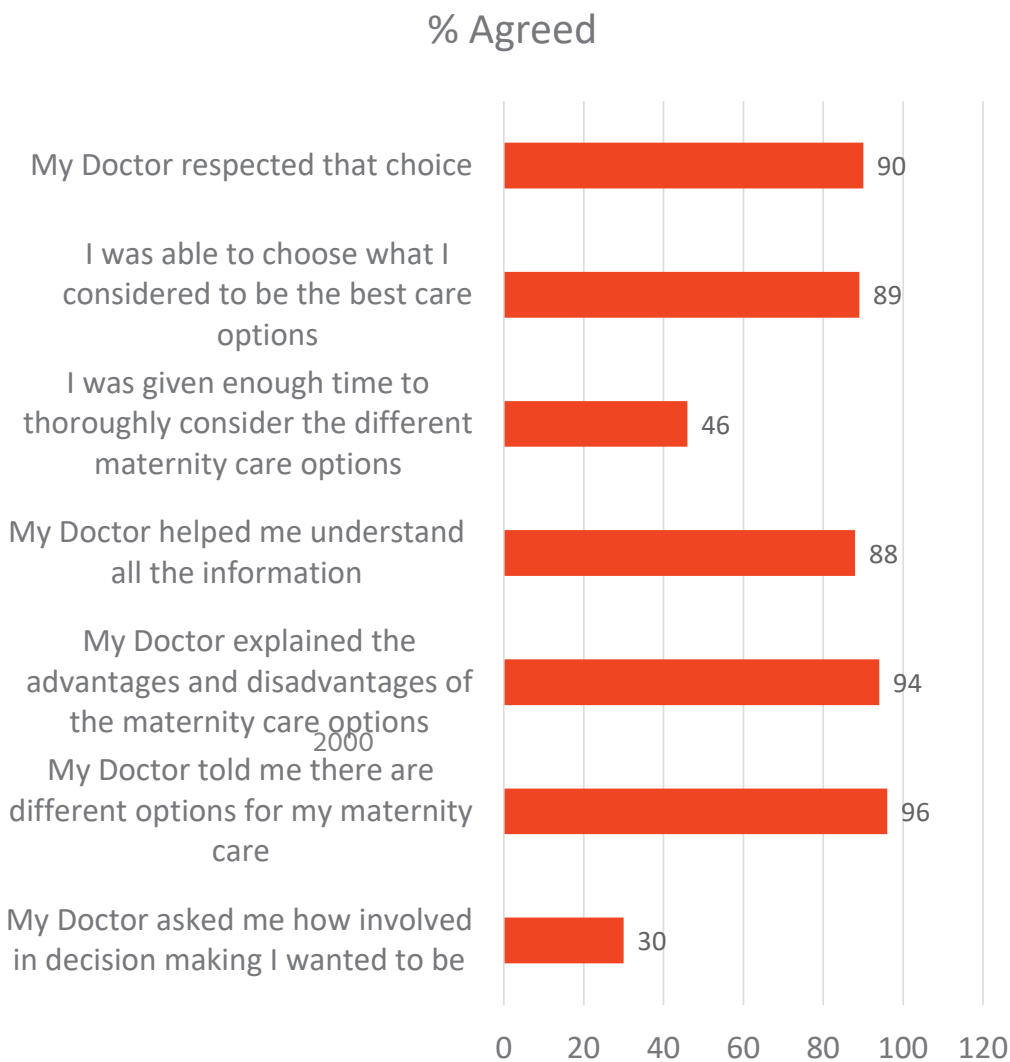
का विकास करना: यह रेज़िडेंट चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ पुस्तिका है जो मरीज़ों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के मामले में सबसे आगे है। मानक परिचालन प्रक्रिया नियमावली (SOP Manual) में 44 अध्याय हैं और इसमें 45 स्थितियाँ सँभालने के लिए विस्तृत निर्देश शामिल हैं। यह न केवल नैदानिक अभ्यास के क्षेत्र में अन्तर्दृष्टियाँ प्रदान करती है, बल्कि किसी के कार्यभार के प्रबन्धन, चिकित्सकों के खिलाफ़ की जाने वाली हिंसा से निपटने, और सरकारी योजनाओं के कामकाज की समझ से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करती है। मानक परिचालन प्रक्रिया नियमावली बेहतर देखभाल और अधिक प्रभावी रोगी परिणामों को बढ़ावा देने में सहायक है। यह प्रसवपूर्व बाह्य रोगी विभाग, प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, और प्रसवोत्तर देखभाल (Postnatal Care—PNC) कक्ष के उचित संचालन के बारे में गहन जानकारी प्रदान करती है।

2. साक्ष्य-आधारित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना : विभाग ने साक्ष्य-आधारित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विशेष मामलों के अलग-अलग अभिलेख रखना शुरू किया है। यह अभिलेख छात्रों को जटिल मामलों को सँभालने की पेचीदगियाँ सीखने में मदद करते हैं। इसके अलावा, स्नातकोत्तर छात्रों को ऐसे शोध निबन्ध विषय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उपचार में जैवचिकित्सीय कारकों (biomedical factors) के साथ सामाजिक कारकों का परीक्षण करते हों।

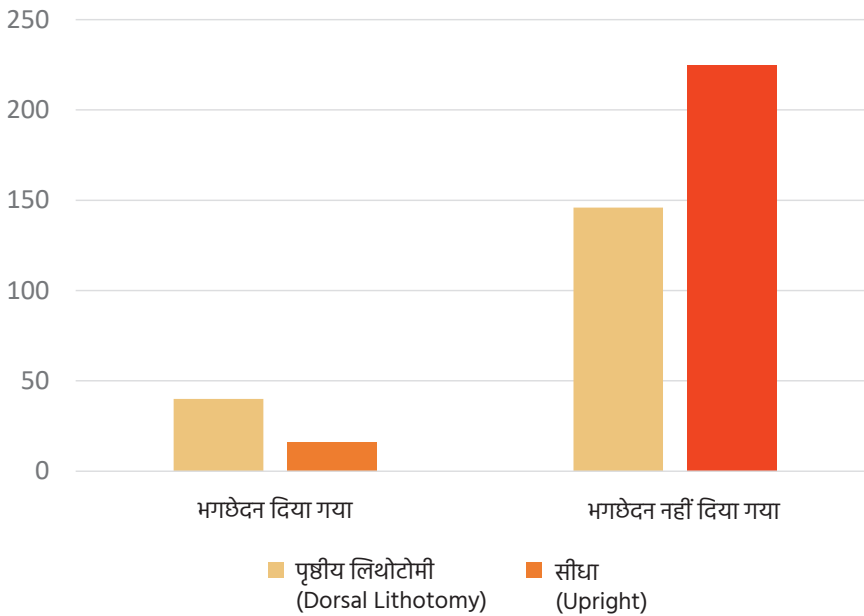
3. प्रभाव दर्शाने के लिए साक्ष्य तैयार करना: विभाग नियमित रूप से अपने डेटा का विश्लेषण करता है ताकि अपने नैदानिक अभ्यास में परिवर्तन लागू करने के प्रभाव सम्बन्धी साक्ष्य तैयार किए जा सकें। इसने हाल ही में 300 महिलाओं का सर्वेक्षण किया जिसका उद्देश्य विभाग की सेवाएँ प्राप्त करने के उनके अनुभव के बारे में जानना था।



सीज़ेरियन द्वारा प्रसूति की दर 28% से गिरकर 25% हो गई है।



यह उस सर्वेक्षण के परिणाम हैं जिसमें देखभाल चाहने वाली महिलाओं के अनुभव का आकलन किया गया है।



यह ग्राफ़ दर्शाता है कि 22.5% महिलाओं को पृष्ठीय लिथोटोमी स्थिति में भगछेदन की आवश्यकता पड़ी वहीं सीधी स्थिति में भगछेदन की आवश्यकता केवल 7.2% महिलाओं को पड़ी।

चुनौतियों पर क़ाबू पाना :

सन् 2014 और 2018 के बीच बदलाव की कहानी आसान नहीं रही है। चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता पहल में भाग लेने वाले चिकित्सा शिक्षकों द्वारा लागू किए गए बदलावों को काफ़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। विभाग में प्रति वर्ष 16,000 प्रसव कराए जाते हैं जिसके कारण मरीज़ों का काफ़ी अधिक भार है, और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मामले भेजे जाते हैं। विभाग में चिकित्सक-रोगी अनुपात काफ़ी कम है। परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं ने इस तरह की पहलों को एक अतिरिक्त बोझ माना। इस मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए, लैंगिक-प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सा शिक्षकों ने एक दिलचस्प रणनीति अपनाई; उन्होंने एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की जो नियमित और कठिन परिस्थितियों से निपटने में चिकित्सकों की सहायता करती है। ऐसी कोई मानक परिचालन प्रक्रिया पहले अस्तित्व में नहीं थी, और इसलिए विभिन्न इकाइयों के बीच संवाद बहुत सरसरी था, इकाइयों के प्रमुखों के रोगियों के प्रबन्धन के अपने-अपने तरीक़े थे। मानक परिचालन प्रक्रिया के

विकास और अनुकूलन से प्रक्रिया में एकरूपता आई है। अन्य चिकित्सकों से फ़ीडबैक माँगने से भी मानक परिचालन प्रक्रिया का स्वामित्व हो गया है। इसने विभिन्न विभागों के बीच एक स्वस्थ, सामंजस्यपूर्ण, और सहयोगी कामकाजी माहौल तैयार किया है।

पहली चुनौती स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की टीम को नैदानिक परिवर्तन करने की आवश्यकता, और इसका महत्व समझाने की थी। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता अक्सर यह मानते हैं कि उनकी भूमिका केवल बीमारी और उसके शारीरिक प्रदर्शन (physical manifestation) के इलाज के लिए है।

चिकित्सक अक्सर मरीज़ों से उनका चिकित्सीय पूर्ववृत्त पूछते हैं लेकिन अन्तर्निहित सामाजिक कारकों और कारणों को समझे बिना। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को दिया जाने वाला पारम्परिक चिकित्सा प्रशिक्षण उन्हें किसी प्रभावी या संवेदनशील तरीके से स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को सम्बोधित करने के लिए तैयार नहीं करता है। प्रारम्भिक चरण में, लैंगिक-प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सा शिक्षकों की उनके साथियों द्वारा हँसी उड़ाई जाती थी जिन्होंने उन्हें ऐसे “लैंगिक” चिकित्सकों के रूप में खारिज कर दिया था जिनके पास बहुत अधिक समय है और इसलिए “लैंगिक” मुद्दों में लिप्त हो सकते हैं। लेकिन चिकित्सा शिक्षकों ने अपने साथियों को मॉड्यूल देखने और प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करके धीरे-धीरे कुछ प्रगति की है, जिसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे लेकिन स्थिर बदलाव आने लगे।

विभाग को एक टीम के रूप में काम करना पड़ता है, जिसमें चिकित्सक, नर्स और सहायक स्टाफ़ मिलकर एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। हालाँकि, कुछ पहलुओं के बारे में नर्सों की तरफ़ से काफ़ी प्रतिरोध हुआ जैसे—प्रसव साथियों की उपस्थिति की और महिलाओं को प्रसूति की अपनी पसन्द की स्थिति चुनने की अनुमति देना। उनकी आपत्तियाँ अधिक भीड़ हो जाने के डर, वार्ड से बच्चों के चोरी हो जाने के डर, और अप्रशिक्षित परिजनों वगैरह को अन्दर आने देने के बारे में भी चिन्ता से सम्बन्धित थीं। सम्पूर्ण स्टाफ़ के बीच एक संवाद के बाद, यह निर्णय लिया गया कि जोखिम मूल्यांकन के आधार पर प्रसव साथी को अनुमति दी जाएगी। वार्ड में महिला के निकट प्रसव साथी की उपस्थिति के लाभों पर भी चर्चा की गई; यह किसी भी आपात स्थिति की निगरानी में नर्सों की मदद करेगा और शीघ्र स्तनपान आसान बनाएगा। चिकित्सा शिक्षकों ने विभिन्न वॉट्सएप समूह बनाए ताकि नर्सों को उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई के बारे में सचेत कर सकें। ऐसे समूह रेज़िडेंट्स के लिए भी बनाए गए ताकि वे उनके नियमित मामलों पर चर्चा कर सकें, जिनमें उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ भी शामिल थीं। इस सामूहिक साझाकरण ने बेहतर कार्यप्रणालियों पर बहुत सारी जानकारी का आदान-प्रदान सम्भव बनाया है और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को साक्ष्य-आधारित कार्यप्रणालियाँ अपनाने के लिए प्रेरित किया है। विभाग के काम को WHO, UNFPA, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations International Children's

Emergency Fund—UNICEF), और व्हाइट रिबन एलायंस (White Ribbon Alliance) जैसे संगठनों से अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। पहल की अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति ने स्वास्थ्य सुविधा के वरिष्ठ प्रशासकों का ध्यान आकर्षित किया है जो अब इस परियोजना से भी जुड़े हैं।

बुनियादी ढाँचा : सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएँ अकसर अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे से ग्रस्त होती हैं, और यह एक विवादास्पद मुद्दा है और औरंगाबाद स्वास्थ्य सुविधा में एक बड़ी समस्या भी है। विभाग के प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता उनके पास उपलब्ध सीमित संसाधनों की सहायता से कुछ बदलाव लाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने बदलावों को प्राथमिकता देते हुए और सरकार से प्राप्त निधियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए उनके लिए रणनीति बनाई। प्रत्येक शल्य चिकित्सक के लिए एक निधि होती है, जो 100 रुपए प्रति प्रकरण होती है, लेकिन कोई भी चिकित्सक यह धन नहीं लेता है और इसके बदले उसे सामान्य निधि में डाल देता है, जिसका इस्तेमाल विभाग में विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाता है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि इस पहल की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता के कारण, विभाग विभिन्न संगठनों से धन जुटाने में समर्थ रहा है।

लिंग-संवेदी नैदानिक कार्यप्रणालियों को लागू करने का अनुभव

चिकित्सा शिक्षकों ने कहा कि चिकित्सा छात्रों को सिखाई जाने वाली लिंग-एकीकृत पाठ्यसामग्री के प्रति उन्हें ईमानदार होने की ज़रूरत थी। इसलिए, नैदानिक परिवर्तन आवश्यक थे। एक बार जब उन्होंने नैदानिक अभ्यास में परिवर्तन किया, तो उन्होंने देखा कि उनके साथियों और छात्रों ने उन्हें स्वीकार और आत्मसात किया। दृष्टिकोण ऊपर से नीचे का नहीं था, बल्कि यह समावेशी था। नैदानिक अभ्यास में स्थाई परिवर्तन लाने के लिए यह महत्वपूर्ण सबक हैं।

इस सम्बन्ध में, औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के प्रमुख ने कहा, “बार-बार प्रजनन संक्रमणों के मामले में, चिकित्सक महिलाओं को गर्भाशयोच्छेदन (hysterectomy) की सलाह देते थे या उन्हें बताते थे कि यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। अब इन समस्याओं को लैंगिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और छात्रों को महिलाओं को विश्वास में लेना और अन्तर्निहित कारणों का पता लगाना सिखाया जाता है।”

उन्होंने अपनी पहले की कार्यप्रणाली का वर्णन किया जब नैदानिक स्थितियों को लैंगिक दृष्टिकोण से देखने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था : “मैं अकसर एक से अधिक बार गर्भपात की इच्छा प्रकट करने वाली महिलाओं को डॉट देता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया।”

विभाग के अन्य शिक्षक, जो एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं, ने कहा, “इससे पहले, मैं कुछ महिलाओं द्वारा की गई अस्पष्ट शिकायतों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब मैं धरेलू हिंसा की घटनाओं को समझ सकता हूँ।”

सुविधा के स्तर पर परिवर्तनों के प्रभाव के माध्यम से देखभाल की गुणवत्ता में सुधार को मापा जा सकता है। प्रसूति के दौरान सीज़ेरियन प्रसवों और अनावश्यक हस्तक्षेपों में कमी आई है। प्रसवों की संख्या, स्तनपान की शीघ्र शुरुआत, और गर्भावस्था के बेहतर परिणामों में वृद्धि हुई है।

पहल की मान्यता

लिंग-संवेदी नैदानिक सेवाएँ लागू करने की पहल को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने स्वीकार किया है। इसे भारत सरकार द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। उप आयुक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में सम्मानजनक मातृत्व देखभाल प्रदान करने की पहल का अध्ययन करने के लिए विभाग का दौरा किया। केन्द्र सरकार इसे एक मॉडल के रूप में मान्यता देने की योजना बना रही है जिसे अन्य स्थानों पर अपग्रेड किया जा सकता है।

हाल ही में इस पहल को एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में भी कवर किया गया था, जिसमें चिकित्सकों, नर्सों, और मरीजों के अनुभव दर्शाए गए थे। देखें: <https://www.ndtv.com/video/shows/ndtv-special-ndtv-india/motherhood-service-and-respect-482864>

आभारोक्ति

हम उन सभी व्यक्तियों और संगठनों के योगदान के लिए उनका आभार मानते हैं जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा में लैंगिक एकीकरण पहल के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया। डॉ. प्रवीण शिंगारे, पूर्व निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान निदेशालय, मुंबई, महाराष्ट्र के प्रति उनके दृढ़ सहयोग के लिए हम उनके अत्यन्त आभारी हैं, जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता पहल का सफल क्रियान्वयन सम्भव हो सका।

हम चिकित्सा शिक्षकों के योगदान के विशेष रूप से आभारी हैं जिन्होंने पूर्वस्नातक चिकित्सा छात्रों के लिए लिंग-एकीकृत मॉड्यूल विकसित करने और उसकी शिक्षा प्रदान करने में सहभागिता की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद से डॉ. श्रीनिवास गडप्पा, डॉ. सोनाली देशपांडे, और डॉ. बीना कुरील; गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मिराज से डॉ. नंदकिशोर गायकवाड़ और डॉ. प्रिया देशपांडे; स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल मेडिकल कॉलेज (Swami Ramanand Teerth Rural Medical College), अंबाजोगाई, ज़िला बीड, महाराष्ट्र से डॉ. शैलेश वैद्य और डॉ. दीपाली देव को हमारा विशेष धन्यवाद।

नागपुर, धुले, कोल्हापुर, और नवी मुंबई में चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा शिक्षा में लैंगिक एकीकरण शिक्षकों के योगदान को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सभी पाँच विषयों यानी सामुदायिक चिकित्सा, फ़ोरेंसिक चिकित्सा और विष विज्ञान, स्त्री रोग और प्रसूति, चिकित्सा, और मनोचिकित्सा में चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता को एकीकृत करने की बृहत् परियोजना में भाग लिया। हम डॉ. अशोक जाधो, डॉ. भरत चव्हाण, डॉ. ऋषिकेश वाडके, डॉ. सारिका पाटिल, डॉ. सुष्मिता भट्टाचार्य, डॉ. कपिलेश्वर चौधरी, डॉ. नीलेश तुमराम, डॉ. विश्वजीत पवार, डॉ. अनुजा थॉमस, डॉ. अनिल जोशी, डॉ. दर्पण कौर, डॉ. जीवन पवार, और डॉ. राजकिरण सालुंखे का उनकी भागीदारी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं।

शोध प्रणाली की सूक्ष्म समीक्षा, डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए हम लैंगिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉ. सुंदरी रवींद्रन और डॉ. रेणु खन्ना, CEHAT प्रोग्राम डेवलपमेंट कमेटी (Program Development Committee—PDC), डॉ. पद्मिनी स्वामीनाथन, डॉ. विभूति पटेल, डॉ. पद्म प्रकाश, और डॉ. यू. विंध्य के आभारी हैं।

नैतिकता समीक्षा के लिए हम संस्थागत नैतिकता समिति (Institutional Ethics Committee—IEC) के सदस्यों : डॉ. अनंत भान, डॉ. निलंगी नरेन सरदेशपांडे और डॉ. सुरिंदर जायसवाल, और अनुसन्धान ट्रस्ट (Anusandhan Trust—AT) संस्थागत नैतिकता समिति सचिवालय के आभारी हैं।

चिकित्सा शिक्षा में लैंगिकता पहल की अगुवाई करने वालों : डॉ. रवि वासवानी, डॉ. जगदीश एन. रेड्डी, डॉ. कामाक्षी भाटे, डॉ. पद्मजा सामंत, डॉ. नीरजा चौधरी, डॉ. शुभश्री श्री बालकृष्ण, और डॉ. सुचित्रा दलवी के प्रति हम अपना विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

संलग्नक

प्रसूति और स्त्री रोग क्लीनिक मदों में लिंग-संवेदी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए जाँच सूची	हाँ	नहीं	लागू नहीं
<p>गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए लागू प्रक्रियाएँ :</p> <p>रोगी से बात करने के लिए श्रव्य और दृश्य गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला एक बन्द स्थान उपलब्ध कराएँ,</p> <p>उदाहरण के लिए, पर्दे, कुछ हद तक साउंडप्रूफिंग</p> <ul style="list-style-type: none"> • पूर्ववृत्त लेते समय • पेट और पेडू परीक्षण के दौरान। <p>सुनिश्चित करें कि रिश्तेदारों या साथ के व्यक्तियों की उपस्थिति में बात करने के अलावा आप अकेले रोगी से भी बात करें।</p>			
<p>रोगी से प्राप्त जानकारी की गोपनीयता रखें: सुनिश्चित करें कि रोगी द्वारा किसी भी रूप में दी गई जानकारी, चाहे मौखिक, लिखित, रिकॉर्ड की गई, या कम्प्यूटर पर स्टोर की गई हो, गोपनीय रहती है और रोगी की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं की जाती है।</p> <p>रोगी के बारे में अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ, अन्य रोगियों के सामने, परिजनों या दोस्तों के साथ चर्चा न करें।</p> <p>नाबालिगों और व्यक्तियों के मामले में, क़ानूनी मुद्दों वाले मामलों में, जानकारी उनके माता-पिता और / या अभिभावकों के साथ साझा की जानी चाहिए, और इन रोगियों को भी इस जानकारी के प्रकटीकरण के कारण और आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।</p> <p>रोगियों को इस बारे में अवगत कराएँ, और उनके द्वारा दी गई जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को सम्प्रेषित किए जाने के कारण भी उन्हें बताएँ और यह जानकारी इनके साथ साझा करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करें :</p> <ul style="list-style-type: none"> • अन्य चिकित्सक • साथी और परिजन • पुलिस / वकील 			

प्रसूति और स्त्री रोग क्लिनिक मदों में लिंग-संवेदी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए जाँच सूची	हाँ	नहीं	लागू नहीं
<p>एचआईवी+ स्थिति, घरेलू हिंसा या यौन शोषण की घटना, और आत्महत्या के विचारों और / या आत्महत्या के पिछले प्रयासों से सम्बन्धित जानकारी परिवार में अन्तरंग व्यक्तियों को सूचित की जानी चाहिए।</p> <p>यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, यानी मासिक धर्म का पूर्ववृत्त, प्रसव / गर्भावस्था सम्बन्धी विवरण, संवेदनशील तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए।</p>			
<p>गैर-आलोचनात्मक रवैया बनाए रखें, संवेदनशील रहें, और गर्भपात, लिंग चयन, यौन अभिविन्यास, यौन प्रथाओं, और लैंगिक पहचान के बारे में खुलासे की गोपनीयता बनाए रखें।</p> <p>शारीरिक परीक्षण ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए जो रोगी की गोपनीयता और गरिमा का सम्मान करता हो।</p>			
<p>श्रव्य और दृश्य गोपनीयता सुनिश्चित करें। रोगी को भली भाँति ढँकना सुनिश्चित करें।</p> <p>जहाँ भी आवश्यक हो, सहचरी / संरक्षिका (chaperone) की उपस्थिति सुनिश्चित करें।</p> <p>संकेत, प्रक्रिया का विवरण समझाने के बाद जानकारी-आधारित सहमति प्राप्त करें।</p> <p>पर्याप्त चिकनाई (lubrication), पर्याप्त तापमान वाले उपकरण सुनिश्चित करें (गर्म / ठण्डे उपकरणों का उपयोग न करें)।</p>			
<p>निष्कर्ष समझाएँ, संवेदनशील तरीके से परीक्षण करने के बाद निदान और आगे की प्रबन्धन योजनाओं पर चर्चा करें, और यह पुष्टि करने के लिए प्रतिपरीक्षण करें कि रोगी समझता है।</p>			
<p>नैदानिक स्थितियाँ कैसी भी हों, परीक्षण के दौरान रोगियों / ग्राहकों के बारे में गैर-आलोचनात्मक रहें, उदाहरण के लिए, यौन संचारित संक्रमण, बगैर शादी गर्भावस्था। सभी रोगियों के साथ भाषा और व्यवहार में सम्मान दर्शाएँ।</p>			
<p>महिला की स्वायत्तता—परीक्षण से इंकार करने का उसका अधिकार—का सम्मान करें। रोगी की इच्छानुसार एक महिला या पुरुष प्रदाता / चिकित्सक सुनिश्चित करें।</p>			

प्रसूति और स्त्री रोग क्लिनिक मर्दों में लिंग-संवेदी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए जाँच सूची	हाँ	नहीं	लागू नहीं
<p>गर्भावस्था-गर्भपात के दौरान गर्भावस्था की वांछनीयता का आकलन</p> <ul style="list-style-type: none"> • यदि अवांछित है, तो महिला को विकल्प चुनने की स्वायत्तता देते हुए गर्भावस्था के समाप्ति / जारी रखने के विकल्पों पर संवेदनशीलता के साथ चर्चा करें। 			
<ul style="list-style-type: none"> • यदि महिला गर्भावस्था की समाप्ति चाहती है, तो गर्भ के चिकित्सीय समापन का प्रस्ताव रखें या उसके लिए उपयुक्त सेवाओं को देखें। • गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए जीवनसाथी / अन्य की सहमति पर ज़ोर न दें। • गर्भपात सेवा के लिए गर्भनिरोधक स्वीकार करने की शर्त न रखें। <p>गर्भावस्था के दौरान—प्रसवपूर्व देखभाल : घरेलू उल्लंघन (domestic viol) के लिए सभी गर्भवती महिलाओं की जाँच की जानी चाहिए।</p> <p>प्रसूति के दौरान श्रव्य और दृश्य गोपनीयता सुनिश्चित करें।</p> <p>महिला को भली भाँति ढँकना सुनिश्चित करें।</p> <p>प्रसूति की प्रगति के बारे में, किसी भी जटिलता के बारे में एक संवेदनशील तरीके से जानकारी प्रदान करें और किसी भी प्रक्रिया / हस्तक्षेप के लिए सहमति प्राप्त करें।</p> <p>महिला के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करें।</p> <p>बिना सोचे समझे प्रक्रियाएँ करने से बचें, उदाहरण के लिए, एनीमा, शेविंग, नियमित भगछेदन। प्रसव साथी को हर समय प्रसूति कक्ष में मौजूद रहने दें।</p> <p>स्थिति, दर्द से राहत, आदि के बारे में महिला की पसन्द का सम्मान करें।</p>			
<p>गर्भनिरोधक सेवाएँ</p> <p>महिला के साथ सभी उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करें, और यदि वह चाहे तो उसके साथी के साथ भी इन पर चर्चा करें</p> <p>जानकारी-आधारित सहमति प्राप्त करें और लाभों, दुष्प्रभावों, और जटिलताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करें।</p>			

प्रसूति और स्त्री रोग क्लिनिक मदों में लिंग-संवेदी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए जाँच सूची	हाँ	नहीं	लागू नहीं
चाही गई गर्भनिरोधक सेवा की व्यवस्था / उसके लिए रेफ़रल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि गर्भनिरोधक सेवा का प्रावधान किसी तरह की ज़बरदस्ती या शर्त के अधीन नहीं हो।			
किशोरावस्था सम्बन्धी सेवाएँ : वैवाहिक स्थिति, यौन व्यवहारों, यौन अभिविन्यास, गर्भ निरोधक के लिए अनुरोध के सम्बन्ध में ग़ैर-आलोचनात्मक रवैया कायम रखें। सेवाओं का प्रावधान—सूचना, गर्भनिरोधक, गर्भपात, माता-पिता / अभिभावक को जानकारी के प्रकटीकरण के विषय में किशोर की सहमति			

सन्दर्भ (References)

Benrud, L. M., & Reddy, D. M. (1998). Differential explanations of illness in women and men. *Sex Roles*, 38(5–6), 375–386.

<https://doi.org/10.1023/A:1018753720941>

Bhat, P. N. M., & Xavier, A. J. F. (2003). Fertility decline and gender bias in northern India. *Demography*, 40(4), 637–657.

<https://doi.org/10.2307/1515201>

Bickel, J. (2001). Gender equity in undergraduate medical education: A status report. *Journal of Women's Health & Gender-Based Medicine*, 10(3), 261–270. <https://doi.org/10.1089/152460901300140013>

Bohren, M. A., Vogel, J. P., Hunter, E. C., Lutsiv, O., Makh, S. K., et al. (2015). The mistreatment of women during childbirth in health facilities globally: A mixed-methods systematic review. *PLOS Medicine*, 12(6) (20150630): e1001847.

<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001847>

Daga, A. S., Jejeebhoy, S. J., & Rajgopal, S. (1999) Domestic violence against women: An investigation of hospital casualty records, Mumbai. *Journal of Family Welfare*, 45(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/097206340100300114>

Duggal, R., & Ramachandran, V. (2004). The abortion assessment project—India: Key findings and recommendations. *Reproductive Health Matters*, 12(24 Suppl), 122–129.

DOI: 10.1016/S0968-8080(04)24009-5

Foss, C., & Hofoss, D. (2004). Patients' voices on satisfaction: Unheeded women and maltreated men? *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 18(3), 273–280. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00290.x>

Garg, S., & Singh, R. (2014). Need for integration of gender equity in family planning services. *Indian Journal of Medical Research*, 140(Suppl1), 147–151.

International Institute for Population Sciences (IIPS) and ICF. (2017). National Family Health Survey (NFHS-4), 2015–16: India. Mumbai: IIPS. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR339/FR339.pdf>

International Clinical Epidemiologists Network (INCLIN) (2000). Domestic violence in India, Part 3: Violence against women and girls. A summary report of a multi-site household survey. Washington, D.C.: International Centre for Research on Women and the Centre for Development and Population Activities.

Iyengar, K., Paul, M., Iyengar, S. D., Klingberg-Allvin, M., Essén, B., Bring, J., et al. (2015). Self-assessment of the outcome of early medical abortion versus clinic follow-up in India: A randomised, controlled, non-inferiority trial. *Lancet Global Health*, 3(9), PE537–E545. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(15\)00150-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00150-3)

Maharana, B., & Ladusingh, L. (2014). Gender disparity in health and food expenditure in India among elderly. *International Journal of Population Research*, 2014, Article ID 150105, 8 pages.

<https://doi.org/10.1155/2014/150105>

Planning Commission (2011). High Level Expert Group Report on Universal Health Coverage for India. Instituted by the Planning Commission of India. New Delhi: Government of India. Available from:

http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_uhc0812.pdf

Henshaw, S. K., Joyce, T. J., Dennis, A., Finer, L. B. & Blanchard, K. (2009). Restrictions on Medicaid funding for abortions: A literature review. Guttmacher Institute. Retrieved 30 August 2019 from

<https://www.guttmacher.org/report/restrictions-medicaid-funding-abortion-literature-review>

Saikia, N., Moradhvaj, & Bora, J. K. (2016). Gender difference in health-care expenditure: Evidence from India Human Development Survey. *PLoS ONE*, 11(7), e0158332.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158332>

Sebastian, M. P., Khan, M. E., & Sebastian, D. (2014). Unintended pregnancy and abortion in India: Country profile report. STEP UP Research Report. New Delhi: Population Council.

<https://doi.org/10.31899/rh4.1052>

Senarath, U., & Gunawardena, N. S. (2009). Women's autonomy in decision making for health care in South Asia. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 21(2), 137–143.

<https://doi.org/10.1177/1010539509331590>

Verdonk, P., Benschop, Y. W. M., De Haes, J. C. J. M., & Lagro-Janssen, A. L. M. (2008). Making a gender difference: Case studies of gender mainstreaming in medical education. *Medical Teacher*, 30(7), 194–201.

<https://doi.org/10.1080/01421590802213206>

World Health Organization (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (2009). Women and health: Today's evidence tomorrow's agenda. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (2014). The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513809/>

Zelek, B., Phillips, S. P., & Lefebvre, Y. (1997). Gender sensitivity in medical curricula. Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne, 156(9), 1297–1300.

सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स (CEHAT), महाराष्ट्र

CEHAT (सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स—Centre for Enquiry into Health and Allied Themes) अनुसन्धान ट्रस्ट द्वारा 1994 में स्थापित किया गया अनुसन्धान केन्द्र है। CEHAT स्वास्थ्य और सम्बद्ध विषयों पर अनुसन्धान, प्रशिक्षण, सेवा और पैरवी में शामिल है। CEHAT का उद्देश्य सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक और ठोस स्वास्थ्य नीति अनुसन्धान करना और गरीबों एवं वंचितों की भलाई की कार्यवाही को बढ़ावा देना, जन स्वास्थ्य आन्दोलनों को मज़बूती प्रदान करना, और स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को हकीकत बनाना है। संगठन की रणनीतियों में शामिल हैं :

1. स्वास्थ्य के विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक पहलुओं पर अनुसन्धान और पक्षसमर्थन परियोजनाएँ शुरू करना;
2. स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे सुलभ बनाकर और निष्पक्षता के साथ एवं नैतिक तरीके से प्रदान किया जा सकता है, यह प्रदर्शित करने के लिए प्रत्यक्ष सेवाएँ और कार्यक्रम स्थापित करना;

3. डेटाबेस और प्रासंगिक प्रकाशनों के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीयों का प्रसार। CEHAT में सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक और ठोस अकादमिक स्वास्थ्य अनुसन्धान और स्वास्थ्य कार्यवाही वंचित जनता के कल्याण, जन स्वास्थ्य आन्दोलनों को मज़बूती प्रदान करने, और स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को साकार करने के लिए है। CEHAT में सभी प्रयास अकादमिक दृढ़ता के साथ समझौता किए बिना लोगों की सहभागिता के लिए स्थान निर्मित करने का प्रयास करते हैं।

2.2 मध्य प्रदेश के धार ज़िले में समुदाय-आधारित सुरक्षित पेय जल आपूर्ति के माध्यम से फ्लोरोसिस शमन

लोक विज्ञान संस्थान (People's Science Institute—PSI) उत्तराखंड

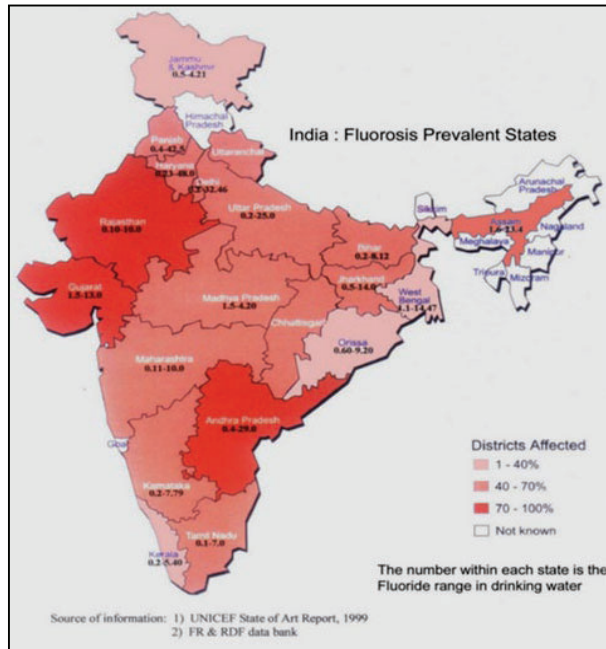
सारांश

फ्लोरोसिस एक बीमारी है जो हैण्डपम्प और ट्यूबवेल जैसे स्रोतों या उपकरणों के माध्यम से ज़मीन से खींचे गए पेय जल में फ्लोराइड की उच्च सान्द्रता के कारण होती है। इसके परिणामस्वरूप शारीरिक विकृतियाँ होती हैं जो न केवल लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और दर्जे को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ प्रस्तुत केस स्टडी मध्य प्रदेश के धार ज़िले की है, जहाँ यह विकलांगता कारित करने वाली बीमारी (crippling disease) ज़्यादातर अरक्षित आबादी समूहों और बच्चों को प्रभावित करती है। इसका प्रमुख कारण भूजल पर लोगों की निर्भरता है जिसमें फ्लोराइड का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards—BIS), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार (Government of India—GoI) द्वारा निर्धारित 1.5 मिग्रा / लीटर के मानक से बहुत अधिक है।¹ फ्लोरोसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फ्लोराइड-सुरक्षित पानी का सेवन करने से इस बीमारी को रोका या कम किया जा सकता है। हैण्डपम्प-आधारित फ्लोरीनहरण इकाइयों (defluoridation units) की स्थापना जैसे हस्तक्षेप उनके कठिन संचालन और रखरखाव (Operation and Maintenance—O&M) के कारण इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक असफल रहे हैं।² लोक विज्ञान संस्थान (People's Science Institute—PSI), देहरादून ने 2013-18 के दौरान सफलतापूर्वक धार ज़िले के 17 गाँवों में समुदाय-आधारित सुरक्षित पेय जल आपूर्ति प्रणालियाँ फ्रैंकवाटर, यूके (FRANK Water, UK), एक सुरक्षित जल और स्वच्छता दानदाता संगठन, के वित्तीय सहयोग से कार्यान्वित कीं तथा 10 और गाँवों में काम का विस्तार कर रहा है। हस्तक्षेप हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययनों (hydrogeological studies), और मूत्र फ्लोराइड निगरानी (urinary fluoride monitoring), जल स्रोतों के प्रबन्धन के लिए ग्राम स्तरीय संस्थानों के निर्माण, और फ्लोराइड-सुरक्षित स्रोतों का उपयोग करने वाली

समुदाय-आधारित जल आपूर्ति प्रणालियों को अपनाने पर आधारित थे। लोक विज्ञान संस्थान की पहल ने भूजल संसाधनों के विकेंद्रीकृत प्रबन्धन का एक सफल उदाहरण स्थापित किया है और यह फ्लोरोसिस के लिए एक स्थाई और किफ़ायती समाधान का वादा करता है।

मध्य प्रदेश के धार ज़िले में समुदाय-आधारित सुरक्षित पेय जल आपूर्ति के माध्यम से फ्लोरोसिस शमन - पृष्ठभूमि

भारत में, फ्लोराइड से दूषित पानी के सेवन से 25 मिलियन से अधिक लोगों को गम्भीर स्वास्थ्य समस्याएँ होने का अनुमान है।³ यह बीमारी भारत के 20 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 230 ज़िलों में स्थानिक (endemic) है⁴ (चित्र 1)। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय पेय जल के लिए भूजल पर निर्भर हैं और कई स्थानों पर चट्टानों के नीचे मौजूद खनिजों के कारण पानी में फ्लोराइड की अधिकता है। फ्लोराइड के 1.5 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक स्तर वाले पानी के लम्बे समय तक सेवन से हड्डियों और दाँतों की विकृतियाँ होती हैं।



चित्र 1 : भारत में फ्लोसिस की व्यापकता

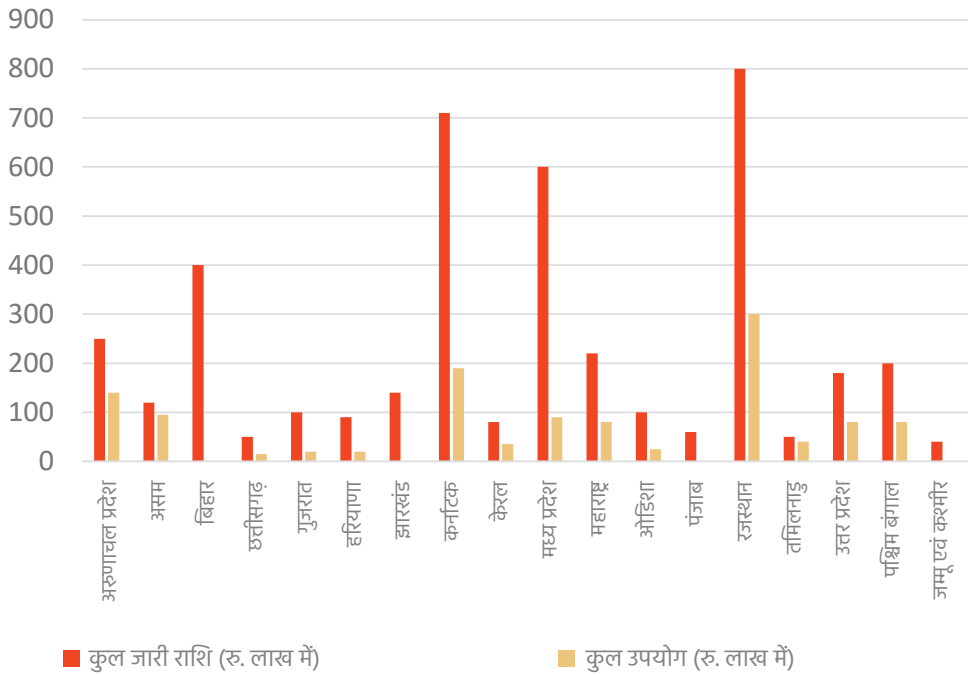
कई ग्रामीण क्षेत्रों में, हैण्डपम्पों और ट्यूबवेलों के माध्यम से निकाला गया भूजल पेय जल का एकमात्र स्रोत होता है। इन क्षेत्रों में, फ्लोराइड सन्दूषित भूजल स्वास्थ्य सम्बन्धी एक गम्भीर चिन्ता के रूप में उभरा है। फ्लोराइड मुख्य रूप से पानी के उपभोग के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। हालाँकि शरीर में फ्लोराइड का प्रवेश खाद्य उत्पादों के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन पेय जल इसका प्रमुख स्रोत है और इसलिए इसका प्रमुख कारण है।

फ्लोराइड सन्दूषित भूजल के उपभोग के परिणामस्वरूप दन्त, कंकालीय (skeletal) और गैर-कंकालीय फ्लोरोसिस होता है। कंकालीय फ्लोरोसिस शरीर की हड्डियों और प्रमुख जोड़ों जैसे—गर्दन, रीढ़ की हड्डी, कन्धे, कूल्हे, और घुटने को प्रभावित करता है, जिससे जोड़ों में तेज़ दर्द, सख्ती या कठोरता होती है, और आंशिक विकलांगता और यहाँ तक कि कभी-कभी पूर्ण विकलांगता भी हो जाती है। दन्त फ्लोरोसिस ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है, जो धब्बेदार और विकृत दाँतों के रूप में प्रकट होता है। बच्चों की चयापचय सक्रिय और संवहनी हड्डियाँ वयस्कों की तुलना में तेज़ी से और अधिक दर से फ्लोराइड जमा करती हैं।¹⁵ फ्लोराइड के भयानक प्रभाव हो सकते हैं, जिससे कर्बुरित दाँत और अस्थिसंधिशोथ (mottled teeth and osteoarthritis) की समस्याएँ हो सकती हैं।¹⁶ इससे बहुत हल्का पेट दर्द हो सकता है और शरीर में एंज़ाइमों को भी नुकसान पहुँचा सकता है।¹⁷ शारीरिक विकलांगताओं और विकृतियों का आजीविकाओं, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, और प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। साथ ही पीड़ितों को सामाजिक कलंक का भी सामना करना पड़ता है।

1937 से, जब भारत में कंकालीय फ्लोरोसिस का पहला मामला सामने आया था, इस समस्या को कम करने के लिए सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। 2008-09 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा एक नई स्वास्थ्य पहल के रूप में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (National Programme for Prevention and Control of Fluorosis—NPPCF) शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, गम्भीर रूप से प्रभावित राज्यों को फ्लोरोसिस शमन के लिए सहायता प्रदान की गई थी। 2014 में, 18 राज्यों, को धनराशियाँ जारी की गईं,¹⁸ लेकिन अधिकांश राज्यों द्वारा इन धनराशियों का कम उपयोग किया गया (चित्र 2), जो सम्बन्धित सरकारी विभागों द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी दर्शाता है।

अधिशोषण (adsorption), आयन विनिमय, सक्रियित एल्यूमिना, अवक्षेपण, और विपरीत परासरण (osmosis) जैसी फ्लोरीनहरण विधियाँ उनके कठिन संचालन और रखरखाव के कारण काफ़ी हद तक असफल रही हैं। इसके अलावा, वे महँगे हैं और इनके कुछ पारिस्थितिक नुकसान हैं जो बड़े पैमाने पर उनके उपयोग को सीमित करते हैं, खासकर सीमान्त क्षेत्रों में।

फ्लोरोसिस का कोई इलाज नहीं है। लेकिन यदि बीमारी की शीघ्र पहचान कर ली जाए और यदि सुरक्षित पेय जल के प्रावधान तथा उचित खाद्य हस्तक्षेप के माध्यम से फ्लोराइड के अत्यधिक सेवन को रोकने के लिए क़दम उठाए जाएँ तो फ्लोरोसिस आसानी रोका जा सकता है।



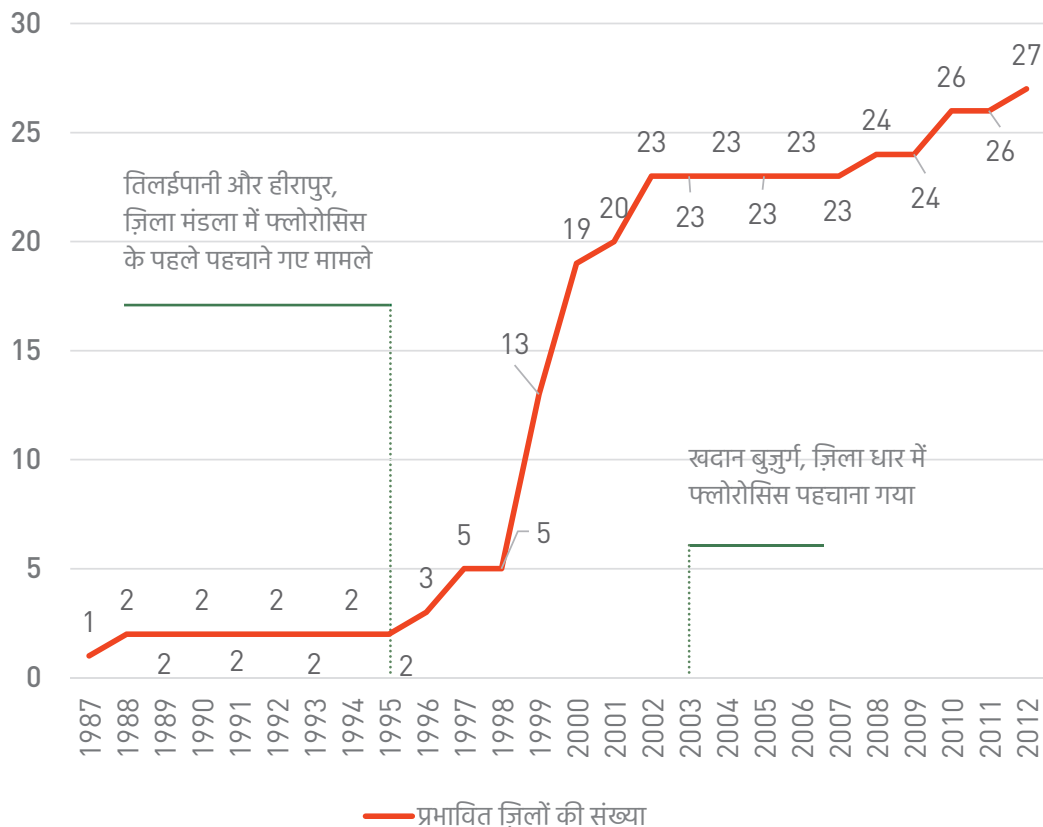
मध्य प्रदेश में फ्लोराइड सन्दूषित ज़िलों की संख्या में वृद्धि

परिचय

मध्य प्रदेश फ्लोरोसिस प्रभावित राज्यों में से एक है (चित्र 1)। राज्य में प्रति वर्ष 1000 मिमी से कम वर्षा होती है, जिसका गम्भीर और मुख्य परिणाम है सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता का संकट। हालाँकि राज्य से सात प्रमुख नदियाँ बहती हैं, पेय जल की ज़रूरतों की पूर्ति लगभग पूरी तरह से (99 प्रतिशत के आसपास) भूजल निष्कर्षण के माध्यम से की जाती है।⁹

मध्य प्रदेश में फ्लोरोसिस का अस्तित्व पहली बार 1997 में पाया गया था। वाटरएड इंडिया (WaterAid India) की 2005 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के 22 ज़िलों में 4,018 गाँवों के 7,746 जल स्रोत ऐसे थे जो भूजल में फ्लोराइड सन्दूषण से प्रभावित थे।¹⁰ तब से, राज्य में फ्लोराइड प्रभावित ज़िलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2012 में, मध्य प्रदेश में कुल 50 ज़िलों में से 27 ज़िले फ्लोराइड प्रभावित थे (चित्र 3)।

मध्य प्रदेश में फ्लोराइड सन्दूषित ज़िलों की संख्या में वृद्धि



चित्र 3 : मध्य प्रदेश में फ्लोराइड प्रभावित ज़िलों का रुझान

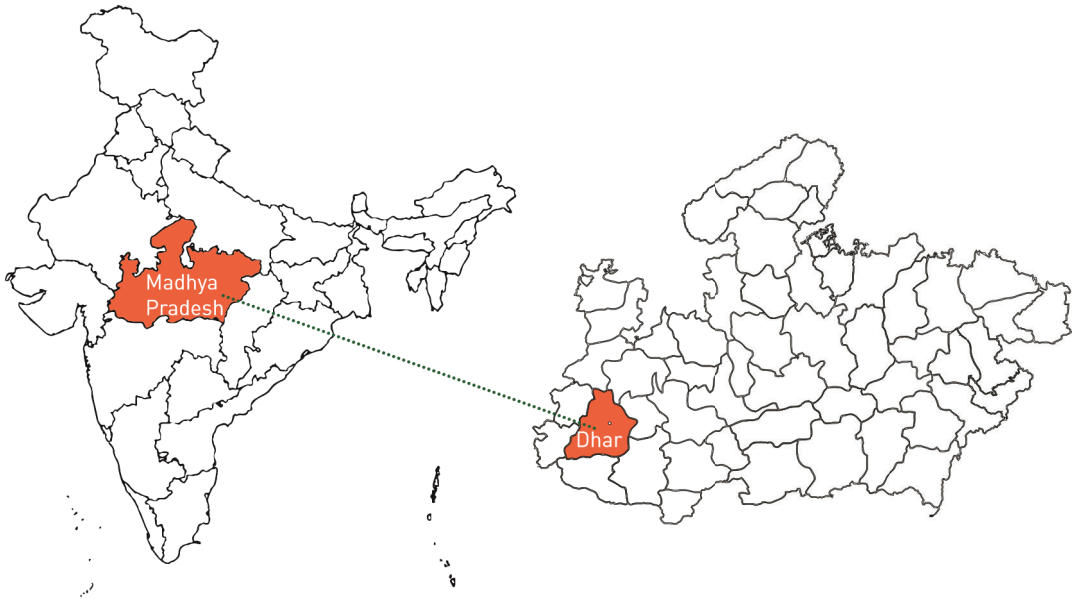
स्रोत : Fluorosis Mitigation History in Madhya Pradesh by India Natural Resource Economics Management (INREM) Foundation and CSIR-National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Support UNICEF, Bhopal

भूवैज्ञानिक रूप से, मध्य प्रदेश राज्य कुछ प्रमुख फ्लोराइड खनिज-धारक चट्टानों जैसे कि डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट, गनीस, और ग्रेनाइट (Deccan trap basalt, gneiss, and granite) पर स्थापित है।¹¹ चट्टान-जल अन्तःक्रिया और लम्बे समय टिकाव के कारण, स्वाभाविक रूप से भूजल में फ्लोराइड की उच्च सान्द्रता पाई जाती है, विशेष रूप से अधिक गहरे जलभरों (aquifers) में। निरन्तर जनसंख्या वृद्धि से पेय जल की अधिक आवश्यकता होगी और सम्भवतः भूजल पर निर्भरता बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्रों

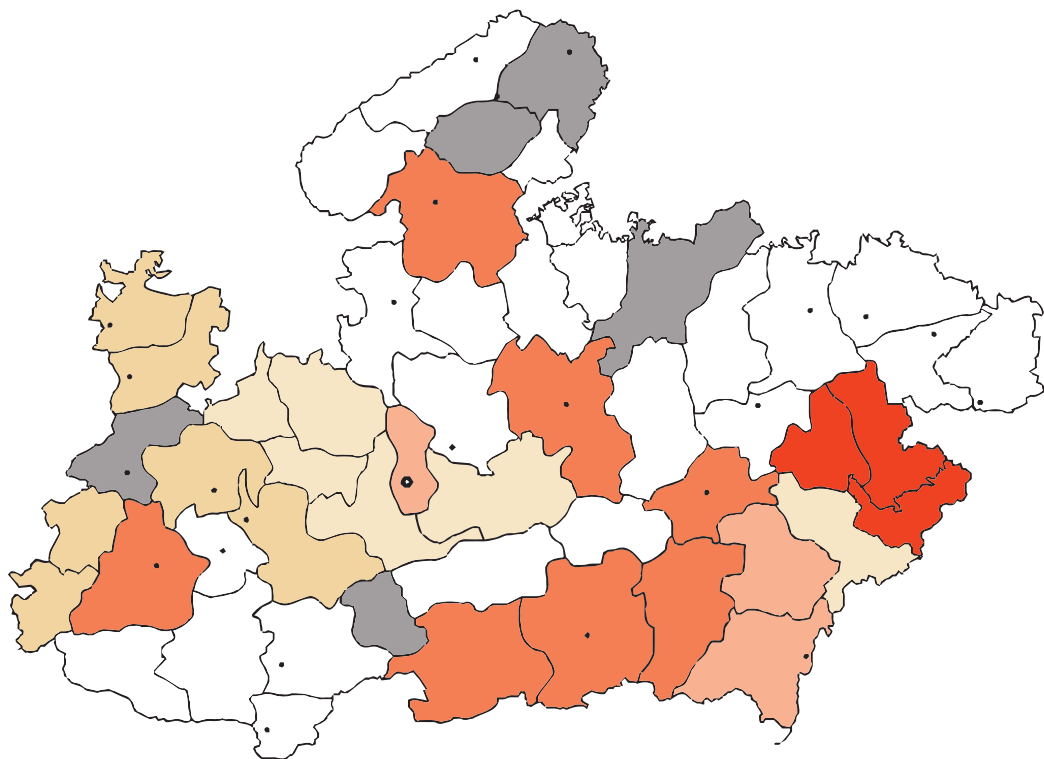
और जनसंख्या समूहों में वृद्धि होगी। इसलिए, इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुरक्षित पेय जल स्रोतों की पहचान और समुदाय-आधारित जल आपूर्ति प्रणालियाँ विकसित करते हुए फ्लोरोसिस शमन की आवश्यकता महसूस की गई।

परियोजना क्षेत्र और उद्देश्यों के बारे में

क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह “भारत के दिल” के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में 46 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें से तीन की पहचान “विशेष रूप से अरक्षित आदिवासी समूहों” के रूप में की गई है। भील सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। उनकी सबसे अधिक आबादी झाबुआ ज़िले में पाई जाती है, इसके बाद उनकी सबसे अधिक आबादी धार में है।¹² उनके मुख्य व्यवसाय कृषि और मज़दूरी हैं।



चित्र 4: मध्य प्रदेश में धार की अवस्थिति



- फ्लोराइड, लवणता और लौह तत्त्व**
 ज़िला: राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, डिंडोरी
- फ्लोराइड और लवणता**
 ज़िला: झाबुआ, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर
- फ्लोराइड और लौह तत्त्व**
 ज़िला: मंडला, बालाघाट
- फ्लोराइड**
 ज़िला: धार, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, सागर, शिवपुरी
- लौह तत्त्व**
 ज़िला: उमरिया, शहडोल
- लवणता**
 ज़िला : रतलाम, हरदा, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड

चित्र 5: मध्य प्रदेश में पानी की गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित ज़िले

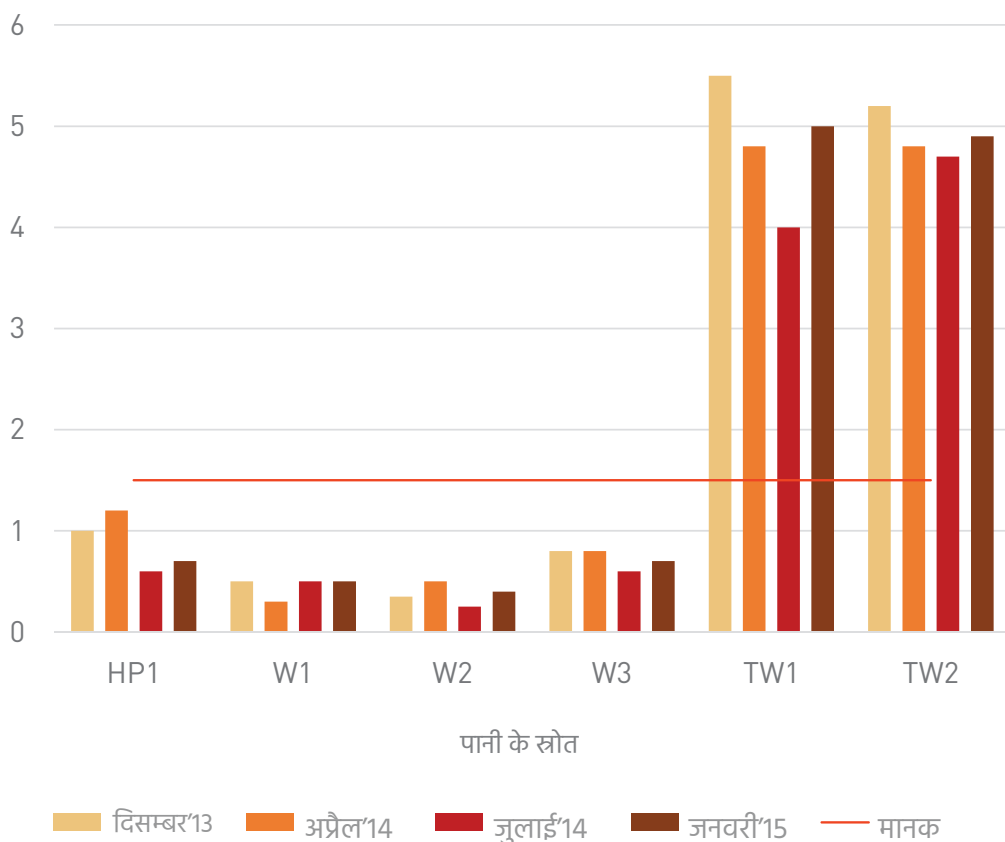
धार ज़िला राज्य के दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र (22° 35' N, 75° 20' E) में स्थित है (चित्र 4)। इसमें 13 ब्लॉक (विकासखण्ड), आठ तहसीलें, और एक हजार से अधिक गाँव शामिल हैं। यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है और सामान्यतया हर साल जनवरी से जून के बीच पानी की कमी से ग्रस्त होता है। लोग भूजल पर निर्भर हैं, जिसे वे परम्परागत रूप से खुले कुओं से खींचते हैं। सिंचित कृषि में वृद्धि के साथ, भूजल स्तर धीरे-धीरे गिर गया है। गर्मियों में आमतौर पर कुएँ सूख जाते हैं, जिसके कारण लोग अधिक गहरी खुदाई करने और हैण्डपम्पों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होते हैं। चूँकि बिजली ने अधिक गहरे जलभरों से पानी खींचना सम्भव बना दिया है, इसलिए धार में ट्यूबवेल लगाए गए। यह पानी के वे गहरे स्रोत (हैण्डपम्प और ट्यूबवेल) हैं जिनमें वास्तव में फ्लोराइड की सान्द्रता अधिक है। एक अध्ययन के अनुसार, 2 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक 1.5 मिग्रा / लीटर की तुलना में धार ज़िले में भूजल में औसतन फ्लोराइड सान्द्रता 4.07 मिग्रा / लीटर है। चित्र 5 मध्य प्रदेश में जल गुणवत्ता की समस्याओं से प्रभावित ज़िले दर्शाता है और धार ऐसा ही एक संकटग्रस्त ज़िला है।

धार में फ्लोरोसिस शमन करने में मदद करने के लिए, लोक विज्ञान संस्थान, देहरादून, भारत और FRANK Water, UK ने 2013 के अन्त में फ्लोराइड प्रभावित समुदायों को सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के लिए एक पहल शुरू की। इसका समग्र उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के माध्यम से सर्वाधिक ज़रूरतमन्दों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले फ्लोराइड-सुरक्षित पेय जल तक पहुँच प्रदान करना था। वैज्ञानिक जाँच इस पहल का आधार थी।

मुद्दे

लोक विज्ञान संस्थान द्वारा इस क्षेत्र में जल विज्ञान और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के अध्ययन किए गए थे। इन अध्ययनों से पता चला कि इस क्षेत्र में भूगर्भीय सन्दूषण (geogenic contamination) और जल स्रोत की गहराई के बीच आनुपातिक सम्बन्ध है, क्योंकि गहरे स्रोतों में भूमिगत चट्टानों के साथ अधिक सम्पर्क होता है। इसीलिए यहाँ अधिकांश गहरे जल स्रोतों जैसे ट्यूबवेलों और हैण्डपम्पों में उथले जल स्रोतों जैसे—खोदे गए कुओं की तुलना में फ्लोराइड की उच्च सान्द्रता (1.5 मिग्रा / लीटर से अधिक) होती है (चित्र 6 धार ज़िले में डहेरिया गाँव में विभिन्न जल स्रोतों में फ्लोराइड सान्द्रता दर्शाता है)।

ग्राम डहेरिया, ज़िला धार



चित्र 6: विभिन्न जल स्रोतों में फ्लोराइड सान्द्रता
HP-हैण्डपम्प, W-कुआँ, TW-ट्यूबवेल

स्रोत	फ्लोराइड सान्द्रता (मिग्रा / ली)	गहराई	उपयोग
कुएँ	0.3 से 0.7	20 - 60 फीट	सिंचाई
हैण्डपम्प	1.6 से 11	200 - 300 फीट	पेय जल
ट्यूबवेल	5 से 8	160 - 430 फीट	पेय जल एवं सिंचाई

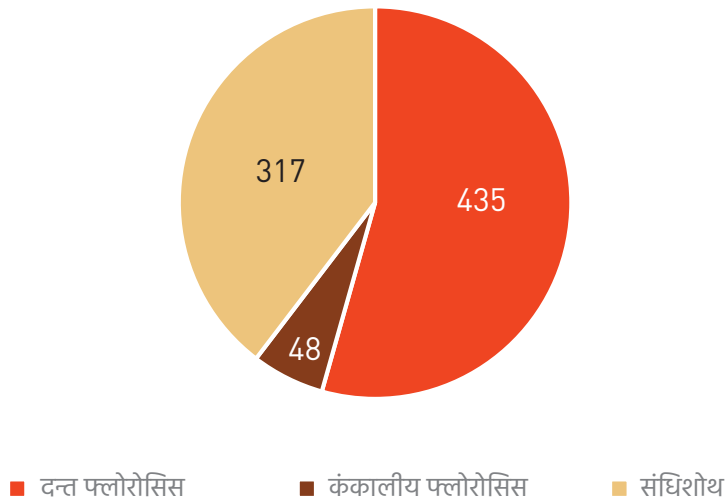
• भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पेय जल में फ्लोराइड के लिए निर्धारित मानक 1.5 मिग्रा / ली
चित्र 7 : पानी की गहराई और पानी की गुणवत्ता के बीच सम्बन्ध

हालाँकि, यह देखा गया कि असुरक्षित स्रोतों, जैसे—हैण्डपम्प और ट्यूबवेल, का उन तक पहुँच में आसानी के कारण पेय जल और घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा था जबकि सुरक्षित स्रोतों (कुओं) का उपयोग ज़्यादातर सिंचाई (चित्र 7) के लिए किया जा रहा था।

दूसरे, हमारे काम से पहले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department—PHED) जैसी कुछ एजेंसियों द्वारा धार के 56 गाँवों में हैण्डपम्प-संलग्न फ्लोरीनहरण इकाइयाँ (handpump-attached defluoridation units) स्थापित करके फ्लोरोसिस-शमन उपाय शुरू किए गए थे (स्रोत : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत संवाद)। हालाँकि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का हस्तक्षेप वांछित स्तर की सफलता प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि कार्यक्रम की रूपरेखा में सामुदायिक सहभागिता के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी और न ही उचित संचालन और रखरखाव के लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि स्थापित इकाइयाँ कुछ समय के बाद बेकार हो गईं।

स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताएँ

लोक विज्ञान संस्थान द्वारा 2013 में सात गाँवों—कालापानी, बड़ीचेत्री, डहेरिया, मालपुरा, बाँकपुरा, संकोटा, और कछवान्या में किए गए एक परिवार सर्वेक्षण, जिसमें 3,332 लोगों को शामिल किया गया है, के अनुसार, 24 प्रतिशत सर्वेक्षण आबादी दन्त और कंकालीय फ्लोरोसिस से प्रभावित थी (चित्र 8)। बच्चे सर्वाधिक असुरक्षित जनसंख्या समूह के रूप में पाए गए।



चित्र 8 : सर्वेक्षित गाँवों में फ्लोरोसिस के मामले

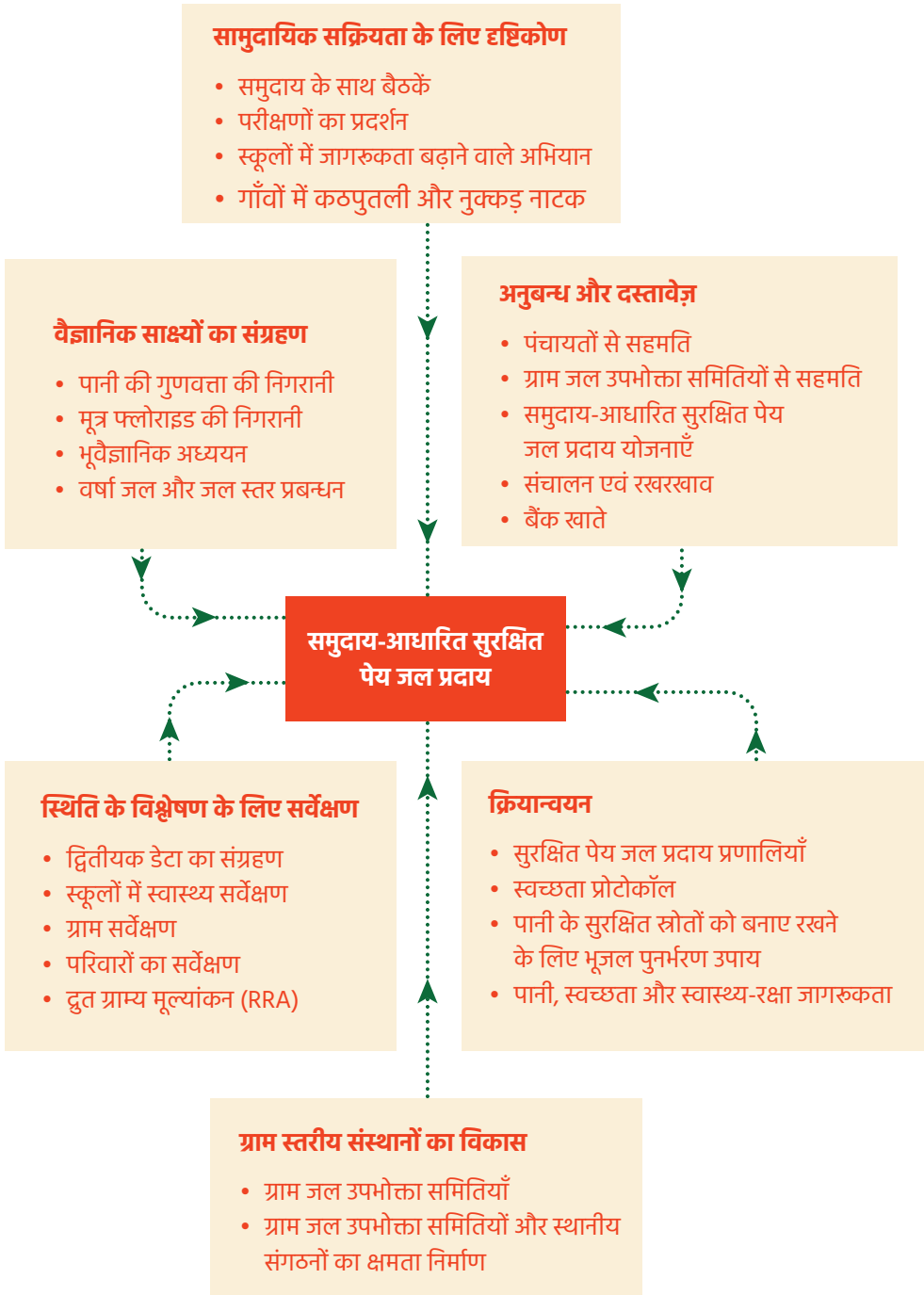
दृष्टिकोण

शुरुआत में यह कार्यक्रम सहभागी भूजल प्रबन्धन (Participatory Groundwater Management—PGWM) के सिद्धान्तों पर आधारित था, जिसमें भूजल को एक सामान्य-पूल संसाधन (common-pool resource) के रूप में मान्यता देना, भूजल सन्दूषण की सीमा का आकलन करने के लिए स्थानीय जल विज्ञान (hydrogeology) का अध्ययन करना, और स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए भूजल के सतत और न्यायोचित उपयोग की दिशा में काम करना शामिल है। आरम्भ में, FRANK Water, UK के वित्तीय सहयोग से एक प्रायोगिक कार्यक्रम धार ज़िले में कालापानी, बड़ीचेत्री, और डहेरिया गाँवों के लिए तैयार किया गया। 2018 में, एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन (Integrated Water Resources Management—IWRM) दृष्टिकोण लागू किया गया; इसमें सामुदायिक भागीदारी, जल विज्ञान अध्ययन, भूजल पुनर्भरण, और स्वास्थ्य रक्षा जागरूकता शामिल हैं।

उपयोग में लाए गए दृष्टिकोण की विशिष्टता

किसी फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र में इस अवधारणा का उपयोग सम्भवतः अपनी तरह का पहला था। यहाँ, जल विज्ञान का उपयोग फ्लोराइड खनिज-धारक चट्टानों की गहराई और जल सन्दूषण को सहसम्बन्धित करने के लिए किया गया था। लोगों के स्वास्थ्य पर हस्तक्षेपों के प्रभाव को मापने के लिए एक उपकरण के रूप में मूत्र फ्लोराइड निगरानी का उपयोग किया गया था।

दूसरे, फ्लोरीनहरण इकाइयों की स्थापना या वर्षा जल संग्रहण को अपनाने के बजाय कुँ के पानी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। कारण सरल था : बदलाव लाना मुश्किल है और बनाए रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। करीबी चीज़ें वे हैं जिनके लोग आदी हैं, जो उनके लिए “प्राकृतिक” हैं, अधिक सम्भावना यह है कि वे नई कार्यप्रणालियों और आदतों को अपनाएँगे, क्योंकि यह परिवर्तन उनके जीवन में उल्लेखनीय बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। सम्पूर्ण प्रणाली स्वयं समुदायों द्वारा संचालित और प्रबन्धित की जाती है। इस तरह का सहभागी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैण्डपम्पों से जुड़ी फ्लोरीनहरण इकाइयों की स्थापना की तुलना में सुरक्षित, टिकाऊ, और कम खर्चीला है।



चित्र 9 : समुदाय-आधारित सुरक्षित पेय जल आपूर्ति लागू करने के लिए उपयोग में लाई गई पद्धति

कार्यप्रणाली

कार्यप्रणाली में द्वितीयक जानकारी का संग्रह, परियोजना क्षेत्र में एक फ़ील्ड स्टेशन की स्थापना, और समस्या के मूल कारण को समझने के लिए लगातार क्षेत्र का दौरा करना शामिल थे (चित्र 9)। इन गतिविधियों के बाद स्कूलों में एक दन्त और कंकालीय सर्वेक्षण, पानी की गुणवत्ता की निगरानी, और जल विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन किए गए। यह क़वायदें फ्लोरोसिस से प्रभावित गाँवों को सूचीबद्ध करने के लिए की गई थीं। स्कूलों को एक सर्वेक्षण स्थल के रूप में चुनने का औचित्य यह था कि इन स्कूलों में आने वाले छात्र आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं। इस प्रकार दन्त या कंकालीय फ्लोरोसिस प्रभावित छात्रों की पहचान फ्लोरोसिस प्रभावित गाँवों को आसानी से सूचीबद्ध करने में मदद करती। द्रुत ग्राम्य मूल्यांकन (Rapid Rural Appraisal—RRA) तथा कठपुतली और नुक्कड़ नाटकों जैसे साधन समुदायों को सक्रिय करने के लिए उपयोग में लाए गए थे। व्यापक और प्रभावी सामुदायिक सक्रियता के परिणामस्वरूप ग्राम स्तर की मज़बूत संस्थाएँ विकसित हुईं, बेहतर संचालन और रखरखाव प्रणालियाँ विकसित हुईं तथा गाँव के भीतर और यहाँ तक कि दो गाँवों के बीच भूजल संसाधनों का अधिक निष्पक्ष बँटवारा हुआ।

गतिविधियों का विवरण

- 1. द्वितीयक जानकारी का संग्रह और क्षेत्र के दौरे:** के साथ शुरू करने के लिए, लोक विज्ञान संस्थान टीम ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से मुलाक़ात की और उनसे जल-गुणवत्ता के आँकड़े एकत्रित किए। उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर, धार ज़िले के दो ब्लॉकों, मनावर और धरमपुरी में एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया, ताकि पानी के स्रोतों, स्वच्छता की स्थिति, लोगों की आर्थिक स्थिति, और आवश्यक हस्तक्षेपों की व्यवहार्यता के सन्दर्भ में गाँवों का विहंगावलोकन किया जा सके।
- 2. फ़ील्ड कार्यालय की स्थापना:** प्रयोगशाला कार्य के संचालन के लिए और लोक विज्ञान संस्थान कर्मियों को आवास प्रदान करने के लिए धामनोद में एक फ़ील्ड कार्यालय की स्थापना की गई, जो परियोजना स्थल के करीब है। पानी और मूत्र की गुणवत्ता का परीक्षण करने और लक्षित समुदाय के साथ लगातार संवाद की सुविधा के लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई थी।
- 3. स्कूलों में दन्त और कंकालीय सर्वेक्षण:** पानी की गुणवत्ता (मूल रूप से फ्लोराइड सन्दूषण) के सन्दर्भ में धार ज़िले में संकटग्रस्त ब्लॉकों की पहचान के बाद, अगला काम इन दो ब्लॉकों के उन गाँवों को खोजना था जो फ्लोराइड से अत्यधिक प्रभावित हैं और उन समुदायों की पहचान करना जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से, धरमपुरी और मनावर ब्लॉक के 20 स्कूलों में मुख्य रूप से दन्त और कंकालीय सर्वेक्षण

सहित एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वेक्षण प्रारूप तैयार किया गया। इसमें दन्त और कंकालीय फ्लोरोसिस के लक्षणों और पेय जल के उन स्रोतों के विवरण से सम्बन्धित प्रश्न शामिल थे, जहाँ से परिवार घरेलू उपयोग के लिए पानी एकत्र करते थे। दन्त फ्लोरोसिस की स्थिति के बारे में जानकारी में संदिग्ध, हल्के, मध्यम, और गम्भीर लक्षणों के रूप में वर्गीकरण शामिल किया गया (चित्र 10)। कंकालीय फ्लोरोसिस के मामलों की पहचान करने के लिए कुछ शारीरिक परीक्षण किए गए। स्कूल सर्वेक्षण के आधार पर, हमने दन्त और कंकालीय फ्लोरोसिस से प्रभावित 40 से अधिक गाँवों को सूचीबद्ध किया। इन 40 गाँवों में से, दन्त फ्लोरोसिस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 29 गाँवों को आगे के अध्ययन के लिए चुना गया।



चित्र 10 : दन्त फ्लोरोसिस लक्षणों का वर्गीकरण

4. ग्राम सर्वेक्षण: 29 चयनित गाँवों में परिवारों, आबादी, अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति श्रेणी के लोगों की संख्या, पेय जल स्रोतों के प्रकार, स्वच्छता की स्थितियाँ, आदि की जानकारी एकत्र करने के लिए एक ग्राम सर्वेक्षण किया गया। ग्राम सर्वेक्षण का विवरण तालिका 1 में दिया गया है। उपलब्ध जल स्रोतों के प्रकार और स्थिति के आधार पर, इन स्रोतों पर लोगों की निर्भरता, फ्लोरोसिस की गम्भीरता, स्वच्छता की स्थितियाँ, आदि, कुछ गाँव पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए चुने गए।

5. पानी की गुणवत्ता की निगरानी: चयनित गाँवों में फ्लोराइड और पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थों का स्तर जानने के लिए जल स्रोतों का परीक्षण किया गया (तालिका 2)। स्टैण्डर्ड अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन (American Public Health Association—APHA) प्रोसीजर्स¹³ का उपयोग नमूने एकत्र करने और कुछ मापदण्डों

की तुलना में नमूनों का परीक्षण करने के लिए किया गया। जल गुणवत्ता सम्बन्धी जो आँकड़े प्राप्त हुए उनके आधार पर, गाँवों को द्रुत ग्राम्य मूल्यांकन, परिवार सर्वेक्षण, ग्राम सभाओं की बैठकों, विस्तृत जल गुणवत्ता निगरानी, भूवैज्ञानिक अध्ययन, मूत्र विश्लेषण, और जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों के लिए चुना गया।

तालिका 1 : सर्वेक्षित गाँवों की सूची

स.क्र.	गाँव	ब्लॉक	जनसंख्या	विभिन्न जाति श्रेणियों का %			
				अजा	अजजा	अपिव	सामान्य
1	पलासिया	धरमपुरी	1,780		80	20	
2	खोकरया	धरमपुरी	800		10		
3	कछवान्या	धरमपुरी	2,000	10	90		
4	हीरापुर	धरमपुरी	782		10		
5	बागवान्या	धरमपुरी	2,000	10	80	10	
6	ढापला	धरमपुरी	1,240	20	50	30	
7	सेमलदाह	धरमपुरी	2,500	8	15	75	2
8	डोंगरगाँव	धरमपुरी	1,300	18	70	10	2
9	चित्यावर	धरमपुरी	3,625		80	20	
10	पंढानिया	धरमपुरी	1,176	10	75	12	3
11	डहेरिया	धरमपुरी	750	2	70	28	
12	बासवी	धरमपुरी	556	1	98	1	
13	अहमदपुरा	धरमपुरी	665		10		
14	सुरजापुर	धरमपुरी	2,100	2	98		
15	बंजारी	उमरबन*	1,200		10		
16	संकोटा	धरमपुरी	1,275		10		
17	तारापुर	धरमपुरी	3,500	12	80	5	3
18	लोहारी	धरमपुरी	1,200	20	60	10	10
19	बाँकपुरा	धरमपुरी	800	3	73	12	12
20	बलवाड़ी	धरमपुरी	5,000	10	80	10	
21	मेहगाँव	धरमपुरी	1,600	13	75	12	
22	गुजरी	धरमपुरी	2,925	10	15	75	

स.क्र.	गाँव	ब्लॉक	जनसंख्या	विभिन्न जाति श्रेणियों का %			
				अजा	अजजा	अपिव	सामान्य
23	इमलीपुरा	धरमपुरी	600		10		
24	जामुनिया	धरमपुरी	1,458	20	80		
25	कुसुमला	धरमपुरी	3,960	17	80	3	
26	मालपुरा	धरमपुरी	500		10		
27	बड़ीचेत्री	उमरबन*	335	75	25		
28	कालापानी	उमरबन*	825		10		
29	रामधाम	उमरबन*	3,428	3	89		8

जनसंख्या डेटा स्रोत : ग्राम सरपंच और सचिव से ग्राम जनगणना आँकड़े प्राप्त।

* उमरबन ब्लॉक मनावर ब्लॉक की पंचायत के अन्तर्गत आता है।

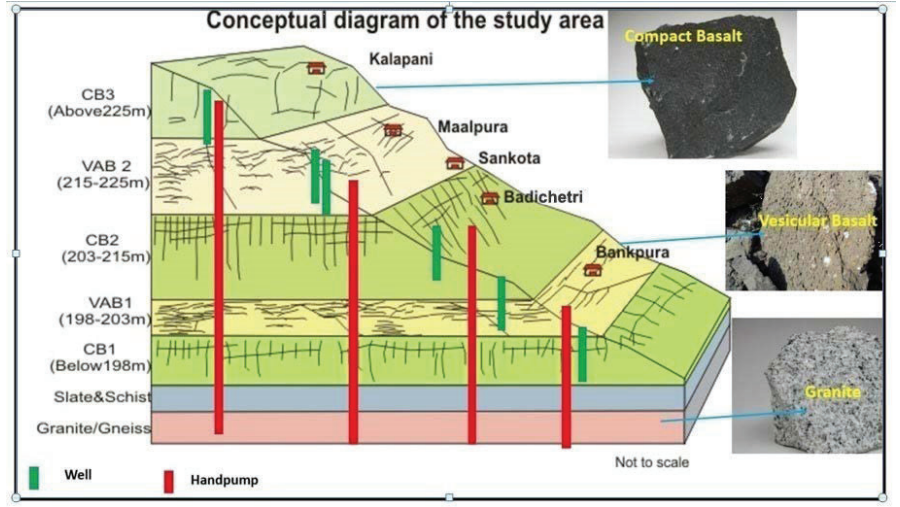
तालिका 2 : पेय जल के विभिन्न स्रोतों की जल गुणवत्ता का प्रोफाइल

स.क्र.	ग्राम	स्रोतों के प्रकार	स्रोतों की संख्या	पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ (मिग्रा / ली)	फ्लोराइड (मिग्रा / ली)
1	ढापला	हैण्डपम्प	8	139-967	0.19-1.29
		कुआँ	1	694	0.78
		ट्यूबवेल	0	-	-
2	बागवान्या	हैण्डपम्प	5	452-2460	0.21-1.21
		कुआँ	0	-	-
		ट्यूबवेल	1	815	1.45
3	हीरापुर	हैण्डपम्प	7	295-605	0.40-4.66
		कुआँ	2	370-438	0.69-0.73
		ट्यूबवेल	1	527	1.10
4	बलवाड़ी	हैण्डपम्प	5	297-486	0.29-3.55
		कुआँ	1	556	0.61
		ट्यूबवेल	0	-	-
5	संकोटा	हैण्डपम्प	3	258-383	2.87-6.87
		कुआँ	1	277	0.96
		ट्यूबवेल	0	-	-

स.क्र.	ग्राम	स्रोतों के प्रकार	स्रोतों की संख्या	पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ (मिग्रा / ली)	फ्लोराइड (मिग्रा / ली)
6	मालपुरा	हैण्डपम्प	3	451-517	0.56-3.21
		कुआँ	1	564	0.58
		ट्यूबवेल	1	539	1.02
7	बाँकपुरा	हैण्डपम्प	3	414-855	1.44-7.87
		कुआँ	2	423-501	0.53-0.58
		ट्यूबवेल	0	-	-
8	कछवान्या	हैण्डपम्प	1	585	6.89
		कुआँ	3	115-669	0.77-1.5
		ट्यूबवेल	1	639	2.8
9	डहेरिया	हैण्डपम्प	0	-	-
		कुआँ	1	430	0.46
		ट्यूबवेल	1	785	5.59
10	बड़ीचेत्री	हैण्डपम्प	4	311-475	0.56-7.92
		कुआँ	2	485-527	0.27-0.58
		ट्यूबवेल	0	-	-
11	कालापानी	हैण्डपम्प	3	451-654	0.46-11.1
		कुआँ	3	283-474	0.23-0.60
		ट्यूबवेल	0	-	-

फ्लोराइड का मानक मान = 1.5 मिग्रा / ली; पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ (TDS) = 500-2000 मिग्रा / ली; लाल रंग से दर्शाए गए आँकड़े फ्लोराइड का उच्च स्तर दिखाते हैं।

भूवैज्ञानिक अध्ययन: पानी की गुणवत्ता की निगरानी के परिणामों को सहसम्बद्ध करने और सुरक्षित पेय जल स्रोतों की पहचान के लिए एक क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और भूजल विज्ञान सम्बन्धी विशेषताओं की विस्तृत जानकारी आवश्यक है। हमारे भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि इस क्षेत्र में चट्टान के दो प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं: आग्नेय और ग्रेनाइट। इनमें विभिन्न खनिज होते हैं। आग्नेय चट्टानें मिट्टी के नीचे चट्टान की ऊपरी परत में स्थित हैं। अधिकांश कुएँ भी इसी परत में हैं। ग्रेनाइट चट्टानें चट्टान की निचली परत में स्थित हैं। फ्लोराइट (fluorite), एक फ्लोरीन-धारक खनिज, ग्रेनाइट चट्टान में मौजूद होता है और भूमिगत जल में घुल जाता है। अधिकांश हैण्डपम्प और ट्यूबवेल इस परत (चित्र 11) में स्थित हैं। इसीलिए कुओं की तुलना में हैण्डपम्पों और ट्यूबवेलों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई।



चित्र 11 : धार ज़िले का भूजल विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन

द्रुत ग्राम्य मूल्यांकन (RRA): पानी से सम्बन्धित मुद्दों (पानी की गुणवत्ता, पानी के उपयोग, पानी के स्रोत, पानी की उपलब्धता, स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी स्थितियाँ) की पहचान के लिए, सूचीबद्ध किए गए गाँवों में द्रुत ग्राम्य मूल्यांकन संचालित किया गया।

परिवार सर्वेक्षण: एक परिवार (घर-घर जाकर) सर्वेक्षण करने का उद्देश्य परिवारों की संख्या, परिवार के सदस्यों की शिक्षा और रोज़गार की स्थिति, पेय जल स्रोतों, पेय जल सम्बन्धित मुद्दों, पानी सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याओं, जल उपचार हस्तक्षेप स्वीकार करने की तत्परता, स्वच्छता की स्थितियाँ, आदि के बारे में जानकारी एकत्र करना था। इस उद्देश्य के लिए एक प्रश्नावली का उपयोग किया गया। सर्वेक्षण में कुल 1,040 परिवारों में से 612 परिवारों (3,332 लोगों) को शामिल किया गया।

मूत्र फ्लोराइड की निगरानी: गैर-प्रतिक्रियाशील प्लास्टिक पात्रों (कंटेनरों) में मूत्र नमूने एकत्र किए गए। प्रायोगिक कार्यक्रम के दौरान, छह गाँवों से कुल 500 मूत्र नमूने (कालापानी से 78, बड़ीचेत्री से 95, मालपुरा से 79, बाँकपुरा से 58, डहेरिया से 145, और संकोटा से 45 नमूने) लेकर फ्लोराइड की मौजूदगी का स्तर जानने के लिए उनका विश्लेषण किया गया। कुल 500 मूत्र नमूनों में से 256 नमूने महिलाओं के थे और 244 नमूने पुरुषों के थे।

प्रायोगिक गाँवों का चयन: उपरोक्त गतिविधियों के संचालन के बाद अन्ततः, कालापानी, बड़ीचेत्री और डहेरिया के तीन प्रायोगिक गाँवों को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर चुना गया:

- फ्लोरोसिस से सबसे अधिक प्रभावित गाँव
- पेय जल के फ्लोराइड-सुरक्षित स्रोतों की कम संख्या; पीने और खाना पकाने हेतु पानी के लिए हैण्डपम्पों और ट्यूबवेलों पर अधिक निर्भरता
- घरों से सुरक्षित जल स्रोत की दूरी
- गाँवों में उपलब्ध संसाधन
- जलापूर्ति योजनाओं की व्यवहार्यता
- समुदायों का सीमान्त स्वरूप
- कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समुदायों की तत्परता
- कार्यक्रम की स्थिरता की सम्भावना

सामुदायिक सक्रियता : गाँवों का चयन करने के बाद, फ्लोरोसिस और सुरक्षित पेय जल की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कठपुतली और नुक्कड़ नाटकों का उपयोग किया गया। यह सबसे कठिन काम था और इसमें बहुत समय लगा क्योंकि लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके पीने के पानी के कारण उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ हो रही हैं।

तालिका 3 : चयनित गाँवों का एक प्रोफ़ाइल

ग्राम	परिवार	जनसंख्या	विभिन्न जाति श्रेणियों का प्रतिशत				पानी के संसाधन	संसाधनों की संख्या
			अजा	अजजा	अपिव	सामा.		
कालापानी	100	825	0	100	0	0	कुआँ	3
							हैण्डपम्प	3
							ट्यूबवेल	0
बड़ीचेत्री	65	335	75	25	0	0	कुआँ	2
							हैण्डपम्प	4
							ट्यूबवेल	0
डहेरिया	150	750	2	70	28	0	कुआँ	1
							हैण्डपम्प	0
							ट्यूबवेल	1

इन गाँवों में घर-घर जाकर एक अभियान संचालित किया गया और हाथ धोने के अभ्यास भी कराए गए जिनका उद्देश्य स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य-रक्षा, और शौचालयों के उपयोग के महत्त्व के बारे में जागरूकता फैलाना था।

हस्तक्षेप

प्रमुख हस्तक्षेपों में निम्नलिखित शामिल थे:

ग्राम-स्तर के संस्थानों का विकास: फ्लोरोसिस के मुद्दे के बारे में परिवारों एवं समुदायों के जागरूक और आश्वस्त हो जाने के बाद, तीनों गाँवों—कालापानी, बड़ीचेत्री और डहेरिया में ग्राम जल उपभोक्ता समितियाँ (Water User Committees—WUCs) गठित की गईं। समितियों का उद्देश्य ग्राम स्तर पर जल सेवाओं को नियमित करना था। इन समितियों के लिए बैंक खाते खोले गए।

समझौतों पर हस्ताक्षर: प्रत्येक गाँव में पंचायत से एक सहमति पत्र प्राप्त किया गया, ताकि हम अपना काम आधिकारिक रूप से शुरू कर सकें। ग्राम जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र भी प्राप्त किए गए। प्रत्येक गाँव में, लोगों द्वारा स्वयं संचालन और रखरखाव योजनाएँ तैयार की गईं।

- ग्राम जल उपभोक्ता समितियों के नियम और ज़िम्मेदारियाँ परिभाषित करना : निम्नलिखित नियमों और ज़िम्मेदारियों पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई : पहचाने गए सुरक्षित जल स्रोत से जलापूर्ति दिन में दो बार निश्चित घण्टों में की जाएगी।
- तय की गई धनराशि का संग्रह और उसे ग्राम जल उपभोक्ता समिति के बैंक खाते में जमा करना।
- जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए तथा मोटर ऑपरेटर को मासिक आधार पर भुगतान करने के लिए एकत्रित धन का उपयोग।
- पानी का उपयोग केवल पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
- पानी का उपयोग बागवानी, सिंचाई, या निर्माण गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।
- शादियों और अन्य कार्यों के दौरान, ग्राम जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों से अनुमति लेने के बाद ही पानी प्राप्त किया जाएगा।
- पानी की टंकियों की महीने में दो बार सफाई की जाएगी।
- कुओं का क्लोरीनीकरण महीने में एक बार किया जाएगा।
- जल स्रोतों के पास खुले में शौच की रोकथाम की जाएगी।
- ग्राम जल उपभोक्ता समिति नियमित बैठकें करेगी और अपनी गतिविधियों की उचित अभिलेख पुस्तकें (record books) संधारित करेगी।

समुदाय-आधारित सुरक्षित पेय जल आपूर्ति का क्रियान्वयन: तीन प्रायोगिक गाँवों में जल परीक्षण के माध्यम से सुरक्षित पेय जल स्रोतों की पहचान की गई। यह स्रोत वे कुएँ थे जो ग्रामीणों के निजी स्वामित्व में थे। सरकारी कुएँ भी थे। पानी में फ्लोराइड सन्दूषण के पूरे मुद्दे और गाँवों में सुरक्षित जल स्रोतों की उपलब्धता के महत्त्व को समझने के बाद, ग्रामीणों ने

अपनी स्वयं की जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाई, यानी, उन्होंने योजना बनाई कि जल आपूर्ति प्रणाली के लिए कौन-से कुएँ से पानी निकाला जाना चाहिए ताकि यह अधिकांश निवासियों तक पहुँचाया जा सके। कालापानी गाँव में, एक निजी कुएँ के मालिक, उदय सिंह, ने अपने गाँव में जल आपूर्ति प्रणाली के लिए अपना कुआँ दान कर दिया, क्योंकि आसपास कोई भी सरकारी कुआँ नहीं था। बड़ीचेत्री और डहेरिया में, सरकारी कुएँ का उपयोग करने की योजना थी। प्रत्येक गाँव में तीन पेय जल आपूर्ति टंकियाँ स्थापित की गईं, जिनमें इस उद्देश्य के लिए चुने गए कुओं से पानी लिया जाता था। लोगों द्वारा टंकियों का विधिवत उद्घाटन किया गया। हाथ धोने जैसी कुछ स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी जागरूकता गतिविधियाँ भी क्रियान्वित की गईं।



बाहरी लोग अकसर अपनी बेटियों की शादी हमारे गाँव में करने में संकोच करते हैं क्योंकि यह एक अभिशप्त गाँव के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि यह स्थिति बदलेगी। मुझे उम्मीद है कि हम इस सामाजिक कलंक से छुटकारा पाएँगे। हमारे गाँव में फ्लोरोसिस प्रभावित लोग कम होंगे और यह सबसे अच्छे गाँवों में से एक होगा। मैं इस दिन के लिए लोक विज्ञान संस्थान की शुक्रगुज़ार हूँ।

- सकू बाई, कालापानी गाँव की रहवासी



प्रमुख परिणाम

- एक कार्यप्रणाली का विकास जिसे अन्य क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है
- वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर भूजल पुनर्भरण के उपायों को अपनाया जाना
- नियोजन और क्रियान्वयन प्रक्रिया में स्थानीय लोगों का समावेश (चित्र 13 और 14)
- सुरक्षित पेय जल का न्यायसंगत वितरण
- कार्यात्मक जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थापना
- गाँव के भीतर एक सार्वजनिक स्रोत से पानी साझा करना
- लोगों में स्वास्थ्य-रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना

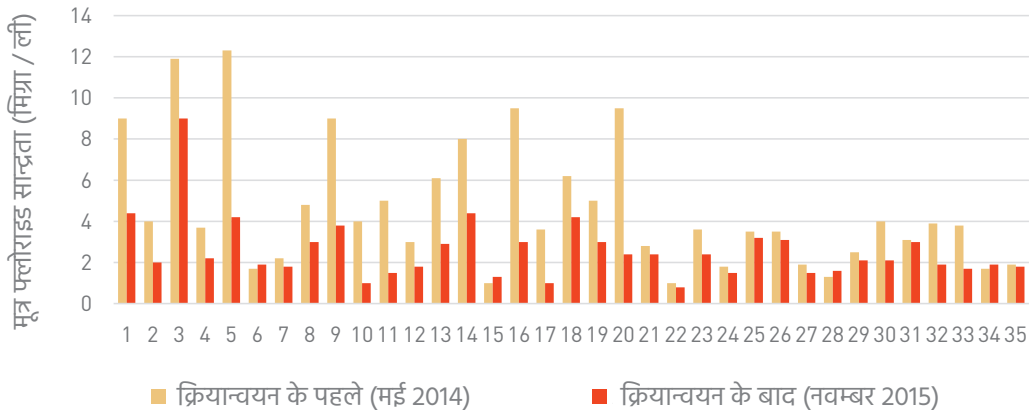
प्रमुख उपलब्धियाँ थीं:

1. समुदाय-प्रबन्धित पेय जल आपूर्ति प्रणालियाँ
 - सभी तीन परियोजना गाँवों के समुदायों द्वारा तैयार संचालन और रखरखाव योजना
2. जल स्रोतों का बँटवारा
 - कालापानी गाँव में एक ग्रामीण द्वारा एक कुएँ का दान
 - गाँव के भीतर पानी का उचित बँटवारा
 - दो गाँवों के बीच एक सार्वजनिक कुआँ साझा करना
3. भूजल प्रबन्धन
 - ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध कि स्रोत कुएँ के पानी का उपयोग बागवानी, सिंचाई, निर्माण, या अन्य उद्देश्यों के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि तात्कालिकता न हो।

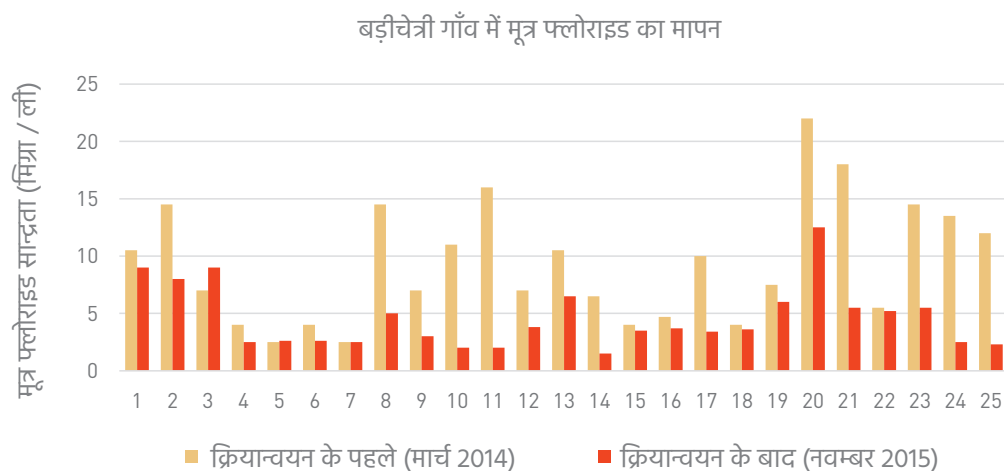
प्रभाव

1. **स्वास्थ्य में सुधार:** परियोजना आरम्भ होने के आठ महीने के भीतर, मानव मूत्र फ्लोराइड में कमी देखी गई (चित्र 12 और 13), जो शरीर द्वारा फ्लोराइड के कम सेवन का संकेत है।

कालापानी गाँव में मूत्र फ्लोराइड का मापन



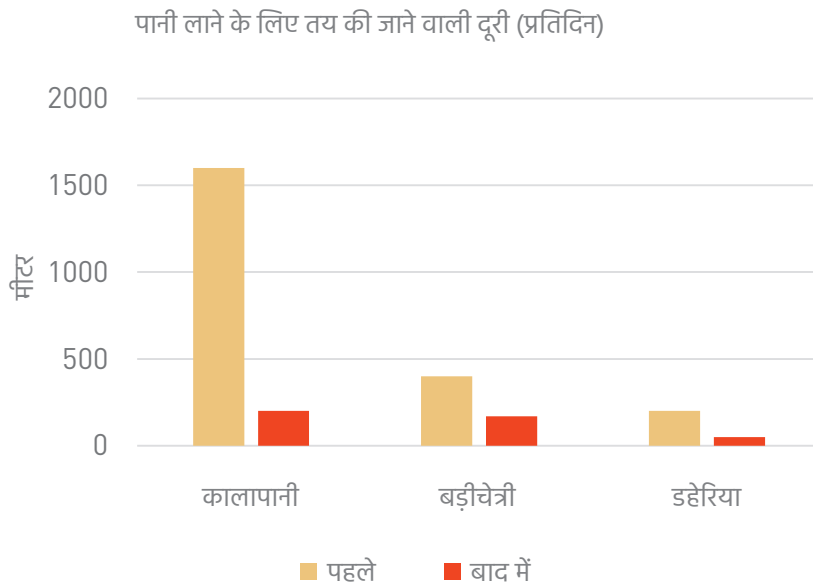
चित्र 12 : कालापानी गाँव में मूत्र फ्लोराइड में कमी



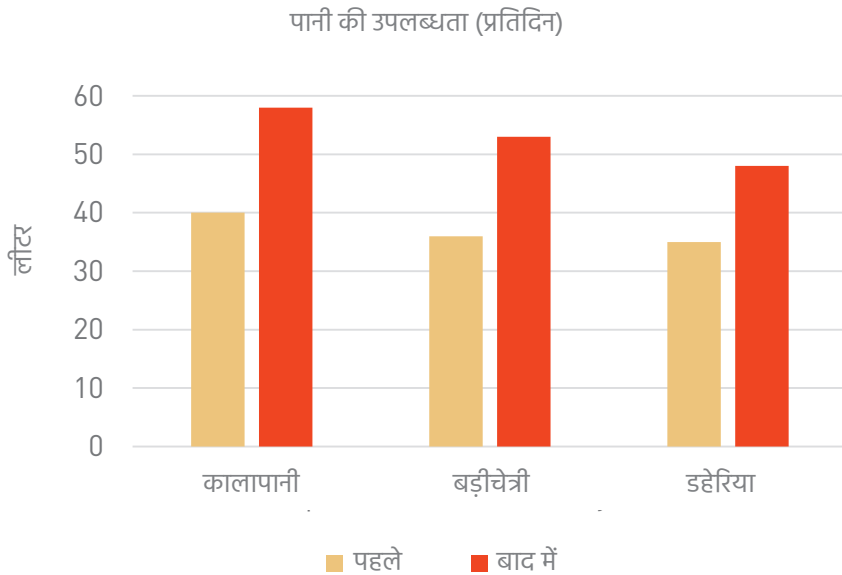
चित्र 13 : बड़ीचेत्री गाँव में मूत्र फ्लोराइड में कमी

2. सुरक्षित पेय जल तक पहुँच में सुधार: तीन प्रायोगिक गाँवों में प्रभाव का एक आकलन किया गया। इस उद्देश्य के लिए एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। वर्तमान में उपलब्ध पानी की गुणवत्ता और इस पानी के उपभोग के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की गई थी। नमूना आकार 225/315 (गाँवों का 71.4 प्रतिशत कवरेज) था। सुरक्षित पेय जल आपूर्ति प्रणाली के क्रियान्वयन से पहले और बाद की स्थितियों की तुलना की गई। एकत्र किए गए आँकड़ों से पता चला कि तीनों गाँवों में प्रतिदिन पेय जल लाने के लिए तय की जाने वाली दूरी में काफी कमी आ गई थी (चित्र 14)। पहले महिलाओं और बच्चों को खाना पकाने हेतु पानी इकट्ठा करने के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 2 किमी की यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन लोक विज्ञान संस्थान परियोजना ने पानी की उपलब्धता बढ़ा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के कठिन परिश्रम में कमी आई (चित्र 15)। अब महिलाओं के पास कुछ उत्पादक कार्यों में संलग्न होने के लिए अधिक समय उपलब्ध था। स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता के कारण, वे जलजनित बीमारियों से कम पीड़ित थीं और दवा पर खर्च घटा था (चित्र 16)।

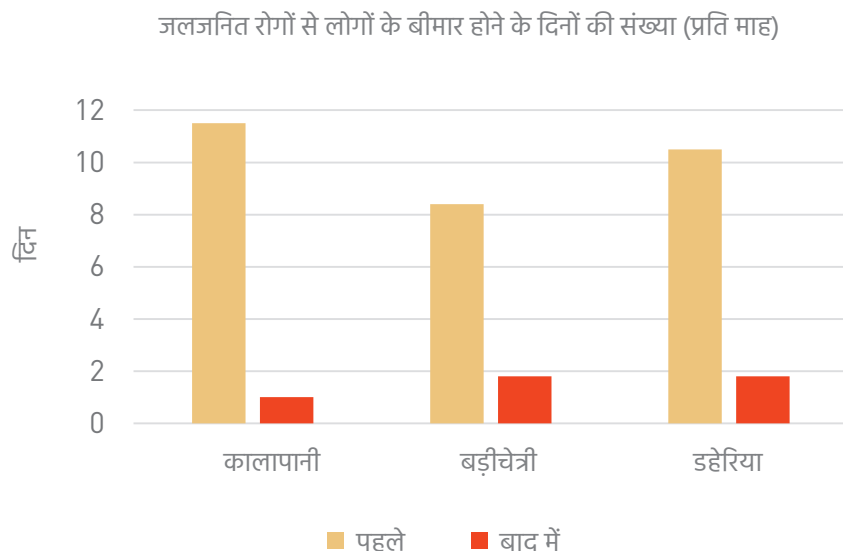
प्रभाव मूल्यांकन के परिणाम:



चित्र 14 : प्रतिदिन पानी लाने के लिए तय की जाने वाली दूरी में कमी

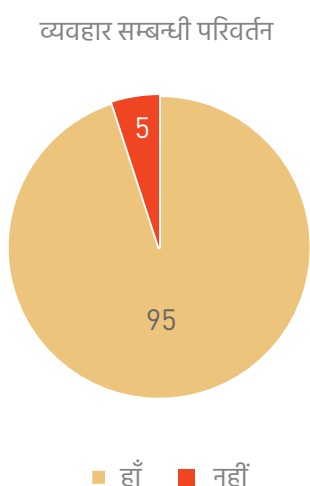


चित्र 15 : पेय जल आपूर्ति प्रणाली के क्रियान्वयन के बाद पानी की उपलब्धता में वृद्धि



चित्र 16 : दवा पर होने वाले खर्च में कमी

3. व्यवहार सम्बन्धी परिवर्तन: लोगों में व्यवहार सम्बन्धी परिवर्तन भी देखे गए। सर्वेक्षण के दौरान, 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे शौच के बाद हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं और घर पर ही एक शौचालय की आवश्यकता महसूस करते हैं (चित्र 17)।



चित्र 17 : सर्वेक्षण के व्यवहार सम्बन्धी परिवर्तन दर्शाने वाले परिणाम

4. ज़िला प्रशासन द्वारा की गई पहलें: इन गाँवों में किए गए कार्यों पर ध्यान दिया गया और सराहा गया। ज़िला कलेक्टर ने कालापानी गाँव के स्वयं सहायता समूह (Self-Help Group—SHG) को 203 शौचालयों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किए।

कुछ स्थानीय चिकित्सक फ्लोरोसिस के शिकार लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया और गम्भीर रूप से प्रभावित 23 लोगों की निःशुल्क शल्यक्रिया की घोषणा की।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस शमन और नियंत्रण कार्यक्रम (National Fluorosis Mitigation and Control Programme—NFMCP) के तहत, स्थानीय चिकित्सकों को फ्लोरोसिस के कारणों, लक्षणों, और उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिवसीय ज़िला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन धार में 17 अगस्त 2015 को सामुदायिक सेवा और स्वास्थ्य विभाग (Department of Community Services and Health) द्वारा किया गया।

5. सूचना प्रसार और जागरूकता निर्माण: प्रसार के उद्देश्य से एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से सूचना और डेटा एकत्र और अभिलेखित किए गए। नीचे कुछ प्रकाशित केस स्टडीज़ (published case studies) की लिंक दी गई हैं, जिनमें से सभी India Water Portal वेबसाइट पर स्थान पाने में सफल रहे हैं।

- Safe water to fight fluorosis, 12 July 2018

बासुबाई और उनके बच्चों को फ्लोरोसिस से लड़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वह थी पेय जल तक पहुँच।

<http://www.indiawaterportal.org/articles/safe-water-fight-fluorosis>

- **Setting safe sanitation example, 12 July 2018**

ग्रामीणों ने दोहरे गड्ढे वाले शौचालय (twin pit latrine) का निर्माण किया और व्यवहार परिवर्तन और सुरक्षित स्वच्छता के विषय में दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया।

<http://www.indiawaterportal.org/articles/setting-safe-sanitation-example-0>

- **Well water makes a difference, 9 October 2017**

फ्लोरोसिस से प्रभावित एक गाँव विशेषज्ञों की मदद से फ्लोराइड-सुरक्षित पानी पीने के महत्त्व को समझता है।

<http://www.indiawaterportal.org/articles/well-water-makes-difference>

- **How water brought a village together, 11 June 2016**

बाँकपुरा के ग्रामीणों की अब स्वच्छ पेय जल तक पहुँच है। दीर्घावधि में, यह निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

<http://www.indiawaterportal.org/articles/how-water-brought-village-together>

- **Bringing potable water to villagers of Dhar, 1 June 2016**

फ्लोरोसिस प्रभावित ग्रामीण अब राहत की साँस ले सकते हैं। उनके दरवाज़े पर सुरक्षित पेय जल का सपना एक वास्तविकता बन गया है।

<http://www.indiawaterportal.org/articles/bringing-potable-water-villagers-dhar>

- **Using community support to battle fluoride contamination, 8 December 2015**

मध्य प्रदेश के दक्षिणी आदिवासी इलाके में सूखाग्रस्त ज़िले धार में भूजल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा पाई जाती है।

<http://www.indiawaterportal.org/articles/using-community-support-battle-fluoride-contamination>

- **How Bandu Singh recovered hope, 8 July 2015**

मध्य प्रदेश के धार ज़िले के 31 गाँवों में स्थानिक फ्लोरोसिस मौजूद है। यह कहानी है कि कैसे एक गाँव अपना स्वास्थ्य और गरिमा पुनः प्राप्त कर रहा है।

<http://www.indiawaterportal.org/articles/how-bandu-singh-recovered-hope>

- <http://hindi.indiawaterportal.org/node/49601>

- <http://hindi.indiawaterportal.org/node/49600>

- <http://hindi.indiawaterportal.org/node/49598>

कार्य को बढ़ाना

प्रभाव के अध्ययन के परिणाम कार्य को बढ़ाने के सन्दर्भ में काफ़ी उत्साहजनक थे। 2014 से 2018 के दौरान धार में और गाँवों में काम बढ़ाया गया। हालाँकि, जल्द ही यह महसूस किया गया कि इस क्षेत्र को न केवल सुरक्षित पेय जल आपूर्ति और पानी, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य-रक्षा पहलों की आवश्यकता है, बल्कि भूजल पुनर्भरण उपायों की भी आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़िले में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है, यानी जून से सितम्बर तक। इसलिए, भूजल पुनर्भरण के लिए अधिशेष जल केवल दक्षिण-पश्चिम मानसून के महीनों के दौरान उपलब्ध होता है। 14 वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। यह सोचा गया था कि भूजल पुनर्भरण के प्रयासों से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि विलयन प्रभाव (dilution effect) के कारण पानी में फ्लोराइड की सान्द्रता घटाने में मदद मिलेगी। इसलिए, 2018 में सुरक्षित पेय जल आपूर्ति प्रणालियों, भूजल पुनर्भरण उपायों, तथा पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा के लिए Arup, UK के सहयोग और मार्गदर्शन से फ्लोरोसिस को कम करने के लिए एक समग्र या एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन दृष्टिकोण अपनाया गया। एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) और लक्ष्य 6.5 (जल संसाधन प्रबन्धन) से सम्बन्धित है। इसमें छह चरण की प्रक्रिया शामिल है, जो तालिका 4 में वर्णित है।

तालिका 4

चरण	गतिविधि	गतिविधि का विवरण
1	आवश्यकता का आकलन और सर्वेक्षण दौरा (Recce Visit)	साहित्य की समीक्षा, द्वितीयक स्रोतों से डेटा का संग्रहण; गम्भीर रूप से प्रभावित गाँवों का चयन करना; अनौपचारिक ग्राम बैठकें; पानी उपयोग के बारे में गाँवों से जानकारी का संग्रहण, उपलब्ध जल संसाधन, जल स्तर, जलग्रहण क्षेत्र का प्रकार, स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी स्थिति; पेय जल गुणवत्ता की निगरानी; दन्त और कंकालीय सर्वेक्षण
2	अन्तरिम रिपोर्ट	आवश्यकताओं के आकलन और सर्वेक्षण दौरे की समीक्षा; एक अन्तरिम रिपोर्ट तैयार करना; परियोजना गाँवों का चयन
3	विस्तृत फ़ील्ड दौरे	आधार-रेखा सर्वेक्षण, सामाजिक और संसाधन मानचित्रण, जागरूकता अभियान, सामुदायिक सक्रियता, पानी की गुणवत्ता और मूत्र फ्लोराइड की निगरानी, ग्राम-स्तरीय संस्थाएँ, जल संसाधन सूची, फ़सल और सिंचाई के स्वरूप

चरण	गतिविधि	गतिविधि का विवरण
4	भूजल विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन	भूवैज्ञानिक क्रॉस-सेक्शन, जलभर मानचित्रण
5	जल सन्तुलन आकलन	पानी की माँग और आपूर्ति में अन्तर, फ़सलों के लिए पानी की ज़रूरतों, भूजल पुनर्भरण क्षमता का आकलन
6	क्रियान्वयन और संचालन एवं रखरखाव	एकत्र की गई सभी सूचनाओं का संक्षिप्तीकरण, समुदाय-आधारित सुरक्षित पेय जल आपूर्ति योजनाएँ, भूजल पुनर्भरण संरचनाओं की रूपरेखा और अनुमान, जलग्रहण प्रबन्धन तथा पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा समाधान, संचालन और रखरखाव योजनाएँ, योजनाओं का क्रियान्वयन, ग्राम-स्तर के संस्थानों का सुदृढीकरण, निगरानी, सीखना, मूल्यांकन और प्रभाव का आकलन।

पहुँच

पिछले छह वर्षों के दौरान, 17 गाँवों में काम किया गया है, जिसमें 8,175 लोगों की आबादी वाले 1,335 परिवारों को समाविष्ट किया गया। इसके अलावा, 1,950 लोगों की आबादी वाले 332 परिवारों के सात गाँवों के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन दृष्टिकोण पर आधारित ग्राम जल सुरक्षा योजनाएँ तैयार की जा रही हैं।

चुनौतियाँ

• **पंचायत और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से सहायता:** हमें पंचायत या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कोई वित्तीय या भौतिक सहायता नहीं मिल सकी, हालाँकि मौखिक रूप से वे हमारी मदद करने के लिए सहमत हो गए थे। भूजल पुनर्भरण उपायों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। सम्बन्धित सरकारी विभागों द्वारा अभिसरण के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

• **सामुदायिक सक्रियता:** हम धार में सीमान्त समुदायों के साथ और उनके लिए काम कर रहे हैं। ज़िले के ग़रीब गाँवों में शौचालयों, अस्पतालों, और अच्छे स्कूलों जैसी बुनियादी सुविधाओं की मौजूदगी लगभग न के बराबर है। लोग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्धित हैं। उनमें से अधिकांश अनपढ़ हैं और दिहाड़ी मज़दूर के रूप में काम करते हैं। वे घोर ग़रीबी में, एक मुश्किल भरा अनिश्चित जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी प्राथमिकता कमाई करना है ताकि वे अपना पेट भर

सकें। इन सब समस्याओं के साथ, फ्लोरोसिस का फैलाव भी है, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनकी स्थिति ऐसी थी जिसमें चुनौती के साथ-साथ एक लाचारी भी थी। उन्हें सक्रिय बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनकी प्राथमिकताएँ अलग थीं। स्वच्छ पानी उनके लिए एक उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, यानी यह उतना महत्वपूर्ण या तात्कालिक मुद्दा नहीं था जो उन्हें हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। एक ऐसे मुद्दे पर उनके साथ काम करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि उनकी प्राथमिकताएँ हमारी प्राथमिकताओं से अलग थीं।

• **स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य-रक्षा:** व्यक्तिगत स्वास्थ्य-रक्षा, स्वच्छता की अच्छी प्रथाओं, शौचालयों के उपयोग, आदि के महत्व के बारे में लक्षित समुदायों को समझाना बहुत मुश्किल है। सदियों पुरानी मान्यताओं और प्रथाओं की व्यापकता के कारण ग्राम समुदाय को सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना आसान नहीं है। जब वे लोग आसानी से परित्यक्त क्षेत्रों या खेतों में शौच कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ शौचालयों के निर्माण के बावजूद उन्हें इन शौचालयों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना एक चुनौती है। सामुदायिक सक्रियता एक सतत और समय खपाने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय, संसाधन, समर्पण, और धैर्य की आवश्यकता होती है।

• **लोगों से मिलने के लिए समय की उपलब्धता:** चूँकि अधिकांश लोग आजीविका कमाने के लिए शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए वे लोक विज्ञान संस्थान कर्मियों और स्टाफ़ से मिलने तथा बात करने के लिए या तो सुबह लगभग 8.00 बजे या शाम 6.00 बजे के बाद ही उपलब्ध होते हैं। महिलाएँ ज़्यादातर अपने क्षेत्रों में व्यस्त रहती हैं। दिन के दौरान, केवल छोटे बच्चे, कुछ वृद्ध पुरुष और महिलाएँ ही घर पर उपलब्ध होते हैं। इसलिए एक अच्छी उपस्थिति में ग्राम या सामुदायिक बैठकें आयोजित करना मुश्किल होता है।

• **प्रशिक्षण:** पानी की आपूर्ति प्रणालियों का उचित और समय पर संचालन और रखरखाव ; कुओं आदि का नियमित क्लोरीनीकरण, आदि सुनिश्चित करने के लिए समुदायों को उन नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना एक चुनौती है, जो उन्होंने स्वयं निर्धारित किए हैं। आहारिय पूरकों (dietary supplements) के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और खेतों में जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी शरीर में फ्लोराइड संचय के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण क़दम हैं।

सीखे गए सबक

- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हैंडपम्प-संलग्न फ्लोरीनहरण इकाइयों (handpump-fitted defluoridation units) का उपयोग करके फ्लोरोसिस को कम करने का प्रयास करता है, लेकिन यह न तो सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने या क़ायम रखने में सक्षम है और न ही स्थापित इकाइयों के उचित संचालन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेने में सक्षम है।
- लोक विज्ञान संस्थान की पहल के माध्यम से यह सीख मिली कि रसायन-आधारित और लागत-प्रधान फ्लोरीनहरण इकाइयों के उपयोग के बिना भी सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना सम्भव है।
- वैज्ञानिक ज्ञान और साक्ष्य, और कुछ हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप होने वाले लाभों, जिनका दावा किया गया हो, के आधार पर वास्तविक प्रदर्शन लक्षित समुदाय को स्वयं इस तरह के परियोजना कार्य में लम्बे समय के लिए शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने में मददगार हो सकते हैं। जब लोगों के सामने पानी की गुणवत्ता और मूत्र परीक्षणों के प्रदर्शन किए गए, तो उन्होंने समझाई जा रही बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया।
- इस क्षेत्र के एक भूवैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्षों जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य ने हमें अपनी बात साबित करने में मदद की कि हैंडपम्प आधारित फ्लोरीनहरण इकाइयाँ फ्लोरोसिस की समस्या हल नहीं करेंगी। भूगर्भीय सन्दूषण को भूवैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से जाँचने की और उन्हें इस क्षेत्र में जल स्रोतों की गहराई के साथ सहसम्बद्ध करने की आवश्यकता है ताकि पीने के पानी के सुरक्षित स्रोतों की पहचान की जा सके। इससे हैंडपम्पों की खुदाई और फ्लोरीनहरण इकाइयाँ स्थापित करने पर सरकार का खर्च घट सकता है। सबक यह है कि हमें धार के फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्रों में पानी के उथले स्रोतों को संरक्षित करने, बढ़ावा देने, और सुगम बनाने की आवश्यकता है।
- भूजल पुनर्भरण के प्रयासों से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि विलयन प्रभाव के फलस्वरूप पानी में फ्लोराइड सान्द्रता को कम करने में मदद मिलेगी।
- पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा भी सुरक्षित पेय जल आपूर्ति कार्यक्रमों में शामिल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है।

निष्कर्ष

भूजल का सतत उपयोग और इसकी गुणवत्ता के मुद्दे इन दिनों अत्यधिक चिन्ता का विषय हैं, खासकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण के सन्दर्भ में। फ्लोराइड के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए पीने के पानी के सुरक्षित स्रोतों को भागीदारी के एक दृष्टिकोण के आधार पर बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है। इस प्रयास को टिकाऊ बनाने के लिए, इन जल आपूर्ति प्रणालियों का संचालन और रखरखाव स्थानीय समुदायों द्वारा किए जाने को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है, जैसा कि वर्तमान में धार ज़िले में लोक विज्ञान संस्थान द्वारा किया जा रहा है। धार ज़िले के गाँवों में लोक विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के कारण रसायन-आधारित और लागत-प्रधान फ्लोरीनहरण इकाइयों के उपयोग के बिना सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता में सुधार हुआ है।

इस तरह के कार्यक्रमों की सफलता के लिए जागरूकता निर्माण और सामुदायिक नेतृत्व वाली कार्यवाही आवश्यक है, तथा फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण आबादी के पानी के संकट को समाप्त करने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन दृष्टिकोण का तेज़ी से विस्तार आवश्यक है। नीति निर्माताओं और नागरिक समाज संगठनों को एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन दृष्टिकोण के बारे में बताने के लिए पैरवी भी आवश्यक है। सरकारी प्रमुख कार्यक्रमों में एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन दृष्टिकोण को अपनाने से फ्लोरोसिस शमन और भूजल संसाधनों के स्थाई प्रबन्धन का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस तरह की भागीदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सुरक्षित, टिकाऊ, और हैण्डपम्प-संलग्न फ्लोरीनहरण इकाइयों की स्थापना की तुलना में कम खर्चीला है, जो कुछ समय बाद खराब हो जाती हैं।

आभारोक्ति

इस परियोजना में शामिल टीम में डॉ. अनिल गौतम, अनीता शर्मा, पूजा रघुवंशी, अमृता मिश्रा, हीना कन्नौज, शरद यादव, और दलपत मुवेल शामिल थे। डॉ. अनिल गौतम ने परियोजना स्टाफ़ को दन्त और कंकालीय सर्वेक्षण, जागरूकता अभियान, मूत्र फ्लोराइड विश्लेषण और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के साथ-साथ फ्लोराइड प्रभावित गाँवों का चयन करने के लिए प्रशिक्षण देकर काम शुरू किया।

सन्दर्भ (References)

1. Indian Standard Drinking Water Specification (Second Revision) IS 10500: 2012. (2012). Bureau of Indian Standards, New Delhi
2. <http://cgwb.gov.in/Documents/WQ-standards.pdf>
3. Jinwal, A., & Dixit, S. (2009). An assessment of fluoride concentrations in different districts of Madhya Pradesh, India. *International Journal of Chemical Sciences*, 7(1), 147–154.
4. Fluoride Action Network (2012). Skeletal fluorosis in India and its relevance to the west.
5. <https://fluoridealert.org/articles/india-fluorosis/>
6. National Health Portal. (2016). Fluorosis. <https://www.nhp.gov.in/disease/non-communicable-disease/fluorosis>
7. Teotia, M., Teotia, S. P., & Singh, K. P. (1998). Endemic chronic fluoride toxicity and dietary calcium deficiency interaction syndromes of metabolic bone disease and deformities in India: year 2000. *Indian Journal of Pediatrics*, 65(3), 371–381.
8. Fluoride Action Network. (no pub. date). Arthritis.
9. fluoridealert.org/issues/health/arthritis. Accessed 7 July 2019
10. Jones, D. (1999). Fluoride: Damning new evidence. Excerpted from “What doctors don’t tell you”, March 1999.
11. https://www.nofluoride.com/what_doctors_donot_tell.cfm. Accessed 7 July 2019.
12. Press Information Bureau (2014). Control of fluorosis: Year wise Fund Release and Total Expenditure to States/Districts under NPPCF. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
13. <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=107823>
14. Das, K. (2012). Drinking water and sanitation in rural Madhya Pradesh: Issues and challenges for policy. *Journal of Rural Development*, 31(3), 287–304.
15. Khanna, A., & Khanna, C. (2005). Water and sanitation in Madhya Pradesh: A profile of the state, institutions, and policy environment. New Delhi: WaterAid, India Country Programme.

16. Ground Water Year Book – Madhya Pradesh (2016–17). Central Ground Water Board, North Central Region, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India, January 2018, 7.
17. <http://cgwb.gov.in/Regions/GW-year-Books/GWYB-%202016-17/M.P.pdf>
18. Madhya Pradesh, Data Highlights: The Scheduled Tribes, Census of India 2001. Government of Madhya Pradesh.
19. http://censusindia.gov.in/Tables_Published/SCST/dh_st_madhya_pradesh.pdf
20. American Public Health Association, American Water Works Association, & Water Environment Federation (1992). APHA Method 9221: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (18th ed.). American Public Health Association Washington, D.C., 1992, file:///C:/Users/Malini/Downloads/apha.method.9221.1992.pdf Accessed 7 July 2019.
21. District Ground Water Information Booklet, Dhar District, Madhya Pradesh (2013). Central Ground Water Board, North Central Region, Bhopal, Ministry of Water Resources. http://cgwb.gov.in/District_Profile/MP/Dhar.pdf

लोक विज्ञान संस्थान (PSI), उत्तराखंड2

1988 में स्थापित, लोक विज्ञान संस्थान (People's Science Institute—PSI) एक गैर-लाभकारी अनुसन्धान और विकास संगठन है। इसकी गतिविधियाँ उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के मध्य-पश्चिमी हिमालयी राज्यों और पश्चिमी उड़ीसा के गरीबी वाले ज़िलों पर केन्द्रित होने के साथ सम्पूर्ण भारत में फैली हुई हैं। परिचालन मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है।

लोक विज्ञान संस्थान की अनेक परियोजनाएँ चल रही हैं जो प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, पर्यावरणीय गुणवत्ता निगरानी, आपदा शमन एवं प्रतिक्रिया और नवीन प्रौद्योगिकियों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं को विकसित करने पर केन्द्रित हैं। लोक विज्ञान संस्थान में फ़ील्ड परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार, कार्य के नए क्षेत्रों की पहचान, और नई प्रौद्योगिकियों एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए अनुसन्धान किया जाता है। इसका विस्तृत दायरा कई विषयों तक फैला हुआ है जिसमें जल प्रबन्धन की परम्पराओं के अध्ययन, खाद्य सुरक्षा, केन्द्रीय-पश्चिमी हिमालय में महिलाओं के कार्य के स्वरूपों, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता और शहरीकरण से लेकर पर्वतीय समुदायों द्वारा जल और वन के

एकीकृत प्रबन्धन पर कार्य अनुसन्धान, धान की खेती की उत्पादकता बढ़ाने, भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System—GIS) सॉफ्टवेयर का विकास, और भूकम्प-सुरक्षित ग्रामीण घरों एवं मध्यवर्ती आकार के शक्ति-चालित वाटर पम्प (hydrams) की रूपरेखा (design) तक शामिल हैं।

सन्दर्भ तय करना

3. लैंगिक चिन्ताओं पर केस स्टडीज़

भारत में मानव विकास के परिणामों में सुधार करने के लिए सामान्य तौर पर और विशिष्ट रूप से लैंगिक निष्पक्षता के सन्दर्भ में किए गए सामाजिक हस्तक्षेपों ने कई झटके झेले हैं—स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों का ठहराव, कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी, सूक्ष्म वित्त और सूक्ष्म उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना, मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप आदि। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अधिक लड़कियाँ स्कूलों में हैं, जिन राज्यों में बाल लिंगानुपात ख़राब था, उनमें सुधार होने लगा है, अब पहले से कहीं अधिक महिलाएँ सूक्ष्म वित्त और सूक्ष्म उद्यमशीलता के दायरे में हैं, और पिछले दशक में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय रूप से काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले दो दशकों में सभी चुनावों में मतदान में महिलाओं की हिस्सेदारी से, और महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पदों के चुनाव लड़ने और जीतने से पता चलता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है।

इन उत्साहजनक सुधारों के बावजूद, अब भी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, जो कि दुनिया में सबसे कम है, के बारे में गम्भीर चिन्ताएँ हैं, और समाज में महिलाओं की समग्र स्थिति बहुत निम्न होने कारण भी गम्भीर चिन्ताएँ हैं। पितृसत्ता के शिकंजे द्वारा आज भी महिलाओं को घर की चारदीवारी के भीतर रखा जाना और साथ ही उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाना जारी है। हम कार्यबल में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए बाधाओं को कैसे कम करते हैं, और समाज में उनकी समग्र स्थिति भी सुधारते हैं?

साहित्य का एक बढ़ता अंग बताता है कि पितृसत्तात्मक समाजों में, महिलाओं के लिए सम्पत्ति के अधिकार उनकी सामाजिक स्थितियाँ सुधार सकते हैं। इस सन्दर्भ में सम्पत्ति के अधिकार से आशय क़ानूनी अधिकारों तथा वास्तविक क़ब्ज़े और महिलाओं द्वारा भूमि एवं घरों पर नियंत्रण से है। विशिष्ट रूप से, कृषि समाजों में, जहाँ भूमि सामाजिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, भूमि पर महिलाओं के प्रभावी स्वामित्व के उनकी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने में गुणात्मक प्रभाव हो सकते हैं, और निर्णय लेने एवं परिवार के भीतर और बाहर आर्थिक सौदेबाज़ी में यह उनके मत को अधिक निश्चयात्मक कथन बना सकता है। भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व के अन्य पूरक लाभ भी हैं—घरेलू हिंसा में कमी और लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करना। एशिया, अफ़्रीका, और लैटिन अमरीका के कई देशों के अध्ययनों ने इन निष्कर्षों की पुष्टि की है।

उत्पादक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा और कौशल में हस्तक्षेप लागू किए जाएँ, राज्य और निगमित क्षेत्र (corporate sector) में ऐसी सकारात्मक कार्यवाही की जाए जिससे कार्यबल में अधिक संख्या में महिलाएँ शामिल हों, और ऐसी स्थितियाँ निर्मित हों जो प्रसव के बाद कार्यबल में महिलाओं के ठहराव में सहायता करें। अध्ययनों से पता चलता है कि लम्बे सवैतनिक मातृत्व अवकाश के साथ-साथ कार्यस्थल पर भली भाँति संचालित शिशु देखभाल सुविधाएँ भी कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश और ठहराव की दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं।

जबकि अध्ययन हमें बताते हैं कि क्या करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, यह तेज़ी से स्पष्ट हो रहा है कि उनका अधिक-से-अधिक लाभ उठाने के लिए स्थिति अनुसार नागरिक समाज कार्यकर्ताओं, राज्य और निगमित क्षेत्र के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। न तो सरकार और न ही नागरिक समाज या निगमित निकाय वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा क्यों है? अनुभवों से, हम सीखते हैं कि परिवर्तन तब अधिक टिकाऊ होते हैं जब प्रमुख हितधारक परिवर्तन की प्रक्रिया के सक्रिय एजेंट बन जाते हैं; इसके साथ ही यह नीति, संस्थागत प्रक्रिया, और मानव व्यवहार में परिवर्तन में मदद करता है।

यहाँ प्रस्तुत दो मामले उपरोक्तानुसार करने का प्रयास करते हैं। केस स्टडी गुजरात स्थित वर्किंग ग्रुप ऑफ़ वीमेन फॉर लैंड ओनरशिप (Working Group of Women for Land Ownership—WGWLO) द्वारा लिखी गई थी, जो राज्य और महिला संगठनों के सहयोगात्मक कार्य के माध्यम से भूमि पर महिलाओं के प्रभावी अधिकार सुरक्षित करने का एक प्रयास है। यह मामला स्वभूमि केन्द्र (Swabhumi Kendra) नाम की एक नवाचारी संस्थागत व्यवस्था का चित्रण करता है, जो भूमि पर उनके वैध क़ानूनी अधिकारों का दावा करने के लिए महिलाओं को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। वर्किंग ग्रुप ऑफ़ वीमेन फॉर लैंड ओनरशिप के सदस्य संगठनों की ज़मीनी-स्तर पर सामाजिक सक्रियता के फलस्वरूप यह स्वभूमि केन्द्र राज्य की वैधता के साथ-साथ जनता के बीच सामाजिक वैधता का भी लाभ उठाते हैं।

eWIT द्वारा प्रस्तुत दूसरी केस स्टडी महिलाओं के सबसे बड़े स्वयं सहायता कार्यक्रमों में से एक—कुडुंबश्री, केरल के आईटी उद्योग और एक स्थानीय नागरिक समाज संगठन के बीच एक और सहयोगात्मक कार्य का उदाहरण है जिसका उद्देश्य एक आईटी पार्क में शिशु देखभाल सुविधाएँ स्थापित करना है। यह सुविधाएँ सीमान्त समूहों की महिलाओं को काम के गरिमापूर्ण अवसर प्रदान करती हैं, साथ ही आईटी पार्क में महिला कार्यबल के ठहराव को प्रोत्साहित करती हैं।

दोनों हस्तक्षेप कई हितधारकों के बीच साझेदारी की बुनियाद पर खड़े किए गए हैं, और उन दोनों में, महिलाओं के नागरिक समाज संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्तर को पाटने के लिए दोनों एक नया संस्थागत पारिस्थितिकी-तंत्र (eco-system) बनाने का प्रयास प्रस्तुत करते हैं। वे सीखने और प्रेरणा की महान मिसालें पेश करते हैं।

3.1 सीसी हब: एक आईटी पार्क में एक चाइल्ड केयर हब

आईटी और आईटीईएस में महिलाओं का सशक्तिकरण (eWIT), केरल ⁵

सारांश

सितम्बर 2012 में, केरल के त्रिवेंद्रम में टेक्नोपार्क परिसर (Technopark campus) में विभिन्न आईटी कम्पनियों में काम करने वाली महिलाओं के एक समूह ने आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया तथा आईटी और आईटीईएस में eWIT—आईटी और आईटीईएस में महिलाओं का सशक्तिकरण (Empowering Women in IT & ITeS) का त्रिवेंद्रम चैप्टर आरम्भ किया।

यह eWIT, चेन्नई की एक शाखा है, जिसकी एक दशक लम्बी विरासत है और लैंगिक संवेदीकरण, सामाजिक समावेश, और महिला सशक्तिकरण में काफी अनुभव है।

प्लेटफॉर्म स्थापित करने के पीछे प्रेरक विचार था व्यक्ति की पूर्ण क्षमता का स्तर प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से जुड़ना, विचार करना, और एक दूसरे की सहायता करना।

एक गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत इस गैर-लाभकारी समिति का एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की सुविधा के लिए बुनियादी ढाँचे सम्बन्धी और सेवा सहायता प्रदान करना है। इसमें डे केयर सेंटर (day care centres) स्थापित करना शामिल है। चूँकि आईटी परिसर में इसकी गहरी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और यह कामकाज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी था, क्योंकि इसने महिला पेशेवरों के बीच कर्मचारी संघर्षण (employee attrition) और प्रतिभा पलायन को बढ़ावा दिया, eWIT ने इस मुद्दे को उठाने और एक ऐसा समाधान निकालने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता दर्शाई जो व्यवहार्य हो एवं आईटी और आईटीईएस उद्योग के लिए अनुकरणीय हो।

शिशु देखभाल केन्द्र (Child Care Hub—CC Hub) एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership—PPP) कार्यक्रम के रूप में eWIT द्वारा संचालित एक सामाजिक समावेश परियोजना है। इसे केरल में टेक्नोपार्क और आईटी उद्योग तथा महिलाओं के लिए केरल सरकार द्वारा संचालित ज़मीनी स्तर पर सक्षमता निर्माण

कार्यक्रम कुडुंबश्री (Kudumbashree) से समर्थन प्राप्त है। वैश्विक कम्पनियों जैसे—Allianz, IBS, QuEst, और UST Global द्वारा आईटी परिसर में फिट-आउट स्पॉन्सरशिप सहयोग (fit-out sponsorship support) प्रदान किया जाता है, और बेबी शॉप द्वारा खिलौने प्रदान किए जाते हैं।

इस परियोजना ने समाज के दो स्तरों की महिलाओं को एक दूसरे के करीब लाने और उन्हें एक दूसरे को सक्षम और सशक्त बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित करने में भूमिका निभाई है।

टैक वर्ल्ड में युवा माताओं के लिए एक डे केयर सेंटर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है ताकि वे मातृत्व अवकाश से काम पर लौटने के बाद अपने पेशे को आगे बढ़ा सकें और एक बेहतर कार्य-जीवन सन्तुलन (work-life balance) बनाए रख सकें।

एक डे केयर सेंटर इलाक़े की सीमान्त वर्गों की महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर और बेहतर जीवन स्तर अवसर भी प्रदान करता है।

यह एक ख़ूबसूरती से की गई संकल्पना पर आधारित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से हासिल किया गया है जो सभी के लिए एक जीत की स्थिति है।

इस प्रायोगिक मॉडल को एक आत्म-संधारणीय (self-sustainable) लाभ केन्द्र के रूप में सफलतापूर्वक संचालित किया गया था। यह भारत में समुदायों के लिए अनुकरणीय है। सफलता का मूल इसे एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रम के रूप में संचालित करने में निहित है, जिसमें एक ग़ैर-लाभकारी, ग़ैर-व्यावसायिक उद्यम के रूप में सामुदायिक हस्तक्षेप शामिल हो। यह सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, और सामुदायिक विकास एवं प्रगति के बिन्दुओं को जोड़ता है।

सीसी हब : आईटी पार्क में एक चाइल्ड केयर हब—प्रस्तावना

यह एक सादगीपूर्ण डे केयर सेंटर, त्रिवेंद्रम, केरल स्थित टेक्नोपार्क में चाइल्ड केयर हब की कहानी है, जिसे एक प्रायोगिक मॉडल के रूप में स्थापित किया गया था और जो सामाजिक समावेश के क्षेत्र में एक बाज़ी पलटने वाला (game-changer) साबित हुआ, जिसने ज़मीनी स्तर के एक हस्तक्षेप के माध्यम से महिला सशक्तिकरण सम्भव बनाया।

सिंधु एक मछली पकड़ने वाले समुदाय से सम्बन्धित है और वह त्रिवेंद्रम के वलियावेली में तटीय क्षेत्र में रहती है, जो टेक्नोपार्क से लगभग 5 किमी दूर है।

टेक्नोपार्क भारत में अग्रणी और सबसे हरा-भरा आईटी पार्क है। इसमें 50,000 से अधिक आईटी पेशेवर कार्यरत हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जो 300 से अधिक कम्पनियों के लिए काम करती हैं।

सिंधु ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और सिलाई एवं अन्य कौशलों का कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 22 साल की उम्र में उसने जॉन्स से शादी की जो एक राजमिस्त्री और एक दैनिक जुआरी था, और आखिरकार दो बेटियों की माँ बन गई। उसने कई तरह के कष्ट झेले और कई चुनौतियों का सामना किया। कोई नियमित या सुनिश्चित आय न होने के कारण, वह अपने परिवार का भरण-पोषण करने, जो गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line—BPL) था, और दो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था करने में संघर्षरत रहती थी।

इस समय, अगस्त 2014 में, स्थानीय कुडुंबश्री इकाई इलाके में महिलाओं के पास पहुँची, जिसने क्षेत्र में सीमान्त समुदायों से बेरोज़गार महिलाओं के लिए एक डे केयरटेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की।

अपनी दो छोटी लड़कियों के साथ साक्षात्कार के लिए पहुँचने पर सिंधु ने देखा कि लगभग 100 इच्छुक डे केयरटेकर की एक बड़ी भीड़ चयन केन्द्र पर इन्तज़ार कर रही थी। उसने अपनी बारी के लिए धैर्यपूर्वक लम्बा इन्तज़ार किया।

इस बीच, कुडुंबश्री और eWIT की महिलाओं के पैनल ने प्रशिक्षण के पहले बैच के लिए 20 उम्मीदवारों को चुना, जो एक सप्ताह में शुरू होने वाला था।

साक्षात्कार पैनल के सदस्यों ने सिंधु की दुर्दशा पर ध्यान दिया और उसकी नेकनीयती से प्रभावित हुए जब उसने एक नया कौशल और व्यवसाय सीखने में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का वादा किया। अपनी कठिन परिस्थितियों पर जीत हासिल करने और अपने परिवार एवं खुद के रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए उसने कड़ी मेहनत करने का दृढ़ निश्चय कर रखा था।

दो महीने की प्रशिक्षण अवधि के बाद, सिंधु को चुना गया और उसने प्रायोगिक डे केयर सेंटर, चाइल्ड केयर हब में एक डे मॉम (day mom) के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू की।

2015 की शुरुआत में यह त्रिवेन्द्रम के टेक्नोपार्क में एक सामाजिक समावेश सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के रूप में शुरू हुआ।

अब, लगभग चार साल नौकरी करने के बाद, सिंधु एक आत्मविश्वास से भरी महिला के रूप में मिलती है, जो अपने जीवन की ज़िम्मेदारी खुद संभाल रही है। वह अपने परिवार की एक कमाने वाली सदस्य है जिसे एक नियमित और काफ़ी अच्छा वेतन मिलता है। वह एक दोपहिया वाहन चलाकर काम पर जाती है और समुद्र किनारे एक नया मकान बनाने में अपने पति को सहयोग प्रदान कर रही है। दो युवा बेटियों की कामकाजी माँ के रूप में, वह उनके लिए एक प्रेरणास्रोत है। बेटियाँ, जो एक स्थानीय स्कूल में क्रमशः 5वीं और 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं, बड़ी होकर आईटी पेशेवर बनने की आकांक्षा रखती हैं।

सिंधु के लिए, जीवन ने पूरी तरह से अप्रत्याशित मोड़ लिया है और बेहतरी के लिए बदलाव आया है, सबकुछ एक झूलाघर (crèche) की वजह से है जो उसके पड़ोस में नए युग के प्रौद्योगिकी पार्क में एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है।



Teens of Today - Parenting Session - by Haripriya Naresh
Post session interaction with participants – April 2018



यात्रा

शुरुआत

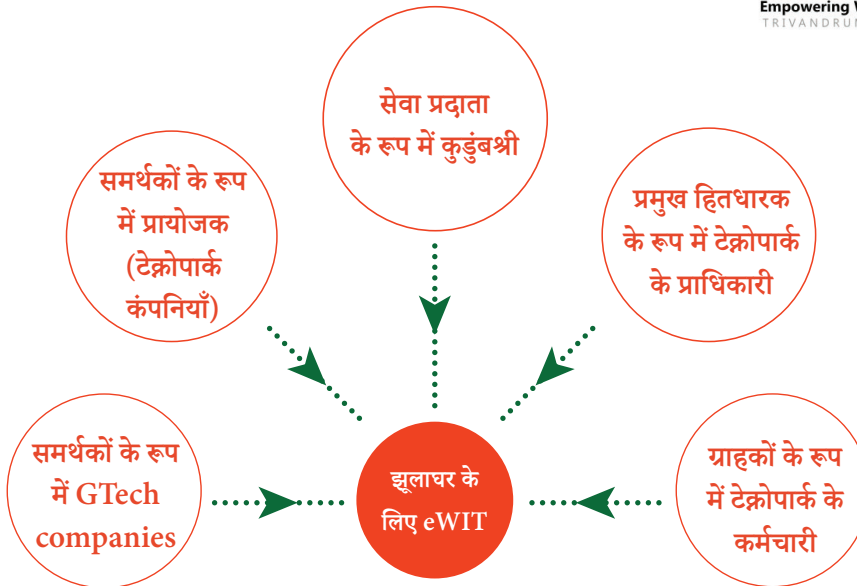
eWIT त्रिवेंद्रम चैयर ने दुनिया के प्रत्येक आईटी पार्क में महसूस की जा रही गहरी आवश्यकता को सम्बोधित करने का फैसला किया—एक विश्वसनीय और सुरक्षित स्थान प्रदान करना जहाँ कामकाजी माताएँ और खासकर मातृत्व अवकाश के बाद लौटने वाली माताएँ, इस अपेक्षा में अपने शिशुओं को छोड़ सकें कि उनके बच्चों की बच्चे अच्छी तरह देखभाल की जाएगी।

2013 में व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility study) के लिए अनुसन्धान और डेटा संग्रहण किया गया। परिसर में महिला कर्मचारियों के बीच किए गए सर्वेक्षण से सकारात्मक निष्कर्षों से लैस, eWIT ने एक सामाजिक समावेश परियोजना के रूप में डे केयर सेंटर संचालित करने के लिए एक उपसमूह स्थापित करने का निर्णय लिया।

उपसमूह में कोर टीम के छह सक्रिय सदस्य और विभिन्न कम्पनियों की महिलाएँ शामिल थीं जिनके पास अलग-अलग योग्यताएँ थीं, लेकिन सभी एक दूसरे की पूरक थीं। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट (dream project) को एक साथ साकार करने के लिए अपना समय, ऊर्जा, और प्रयास लगाना शुरू कर दिया।

सीसी हब : सहयोग मॉडल—सार्वजनिक-निजी भागीदारी

ewit
Empowering Women in IT
TRIVANDRUM CHAPTER



फरवरी 2014: विभिन्न हितधारकों और उद्योग के विशेषज्ञों से विवरण एकत्र करने के बाद परियोजना का एक विस्तृत खाका तैयार किया गया।

हितधारकों को खोजने और अपने समय के आगे की एक अवधारणा के लिए उनकी स्वीकृति और उसमें सक्रिय सहयोग और सहभागिता के लिए उनकी सम्मति प्राप्त करने के लिए eWIT संचालक मण्डल के सदस्य एक मिशन पर लग गए।

यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग छह महीने का अथक प्रयास और कड़ी मेहनत करनी पड़ी कि सभी हितधारक अवधारणा और परियोजना दोनों की समझ के साथ समूह में शामिल हों।

सहयोग

सितम्बर 2014 तक, टेक्रोपार्क और कुडुंबश्री परियोजना में भागीदार के रूप में शामिल हो चुके थे, जिसे एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल के रूप में स्थापित किया गया था। eWIT ने इस सुविधा के लिए 1,100 वर्ग फीट की एक जगह के लिए टेक्रोपार्क के साथ एक लीज़ अनुबन्ध किया और प्रशिक्षित चाइल्ड केयरटेकरर्स सहित संचालन में सहायता के लिए कुडुंबश्री के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding—MoU) पर हस्ताक्षर किए।

कैंपस में मौजूद Allianz Cornhill Information Services Pvt Ltd, IBS Software Services Pvt Ltd, QuEst Global Engineering Services Pvt Ltd, और UST Global जैसी आईटी कम्पनियाँ इस सुविधा केन्द्र की आन्तरिक व्यवस्था के आरम्भिक निवेश की पूर्ति के लिए प्रायोजकों के रूप में शामिल हुईं।

S Squared Architects से जुड़ी त्रिवेन्द्रम की प्रसिद्ध वास्तुकार सुमी शाजी ने एक प्रेरणादायक इंटीरियर डिज़ाइन अवधारणा के साथ एक आदर्श बाल-हितैषी सुविधा की रूपरेखा तैयार करने में अपना सहयोग प्रदान किया।

इन सभी को एक साथ लाना

सितम्बर 2014 में, कुडुंबश्री ने चाइल्ड केयरटेकर प्रशिक्षण में एक प्रमाणपत्र कार्यक्रम की घोषणा की और प्रायोगिक बैच में शामिल होने के लिए स्थानीय समुदाय की महिलाओं से आवेदन बुलाए। eWIT और कुडुंबश्री की महिलाओं के एक पैनल ने लगभग 100 आवेदकों की स्क्रीनिंग की और एक पूरे दिन की प्रक्रिया में प्रायोगिक बैच के लिए इलाके की 20 महिलाओं का चयन किया और अक्टूबर में प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की।

चिन्तनशील अधिगम के कार्यों से जुड़ी एक अनुभवात्मक प्रशिक्षण संस्था रेफ्लेक्टिव लर्निंग प्रैक्टिसेज़ इन एजुकेशन एंड लर्निंग (Reflective Learning Practices in Education and Learning—RACE), बेंगलूरु की प्रबन्ध निदेशक, अपर्णा विश्वनाथन ने महिलाओं के व्यापक सशक्तिकरण की पहलों के हिस्से के रूप में ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण और उनमें उद्यमिता विकास के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवा प्रदान की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को अनुकरण और प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्लूमिंगडेल (Bloomingdale) की संस्थापक कुमारी सेल्वी और उनकी डे केयर फेसिलिटी, ब्लूमिंग डेल (Blooming Dale), जो आसपास के क्षेत्र में सेवा देने वाला एक स्थापित निजी डे केयर सेंटर है, को चुना गया था।

इस प्रकार, निम्न आय वर्ग की 25 से 55 वर्ष आयु समूह की 20 महिलाओं की 45 दिनों की यात्रा शुरू हुई, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोणों से एक पूर्ण परिवर्तन का कारण बन गई।

पेशेवर रूप से डिज़ाइन किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल 45 दिनों की अवधि के थे। प्रतिभागियों के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य-रक्षा और सजने-सँवरने के साथ प्रशिक्षण की शुरुआत की गई, जो इन महिलाओं को खुद को करीब से देखने के लिए प्रेरित करता था, जिसमें अपने पैरों और पैर के नाखूनों से शुरुआत करते हुए अपने हाथों, मुँह, और बालों तक ध्यान देना होता था। यह मॉड्यूल कई प्रतिभागियों के लिए पूरी तरह से नया था और इसमें एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन के लिए दैनिक स्नान और व्यक्तिगत सजने-सँवरने के महत्त्व पर ज़ोर दिया। इस प्रशिक्षण का एक गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि स्वयं के द्वारा सावधानीपूर्वक निखारे गए हाथों और पैरों को महिलाओं ने शान से दिखाना शुरू किया, साथ ही अपने जीवनसाथी, बच्चों, और परिवार के सदस्यों को अपने पैरों पर ध्यान देने और घर पर चप्पल पहनना शुरू करने के लिए प्रेरित किया—बिना कोई बहाना बनाए—घर के अन्दर और बाहर के लिए अलग-अलग चप्पल।

बाल रोग विशेषज्ञों, बाल मनोवैज्ञानिकों, और प्रेरक वक्ताओं सहित अन्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल का हिस्सा थे।

प्रशिक्षण मॉड्यूल 45 दिनों का था और पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य देखभाल, कल्याण, आपातकालीन नर्सिंग सहायता, और ग्राहक देखभाल शामिल किए गए।

प्रशिक्षुओं ने डे केयर प्रक्रिया और एक चाइल्ड केयरटेकर के व्यक्तिगत कर्तव्यों, भूमिकाओं, और ज़िम्मेदारियों पर कक्षा-कक्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया।

उन्होंने ब्लूमिंग डेल में भी प्रायोगिक अनुभव प्राप्त किया, जिससे उन्हें बच्चों और अभिभावकों दोनों की माँग को समान रूप से पूरा करने के लिए अपने कार्य अनुभव को आगे बढ़ाने में मदद मिली।

क्रियान्वयन

प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षकों द्वारा किए गए मूल्यांकन और प्रदान की गई फीडबैक के आधार पर, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 20 महिलाओं में से आठ केयरटेकर को टेक्नोपार्क परिसर में चाइल्ड केयर हब के प्रायोगिक सुविधा केन्द्र में शामिल होने के लिए चुना गया।

इस बीच, 1 मार्च 2015 को चुनिन्दा लोगों के लिए शुभारम्भ (soft launch) करने की योजना के साथ आन्तरिक व्यवस्था काम पूर्णता की ओर अग्रसर था।



Visit by the eWIT Chennai team : October 2015



सभी आठ केयरटेकर को फरवरी में ही चाइल्ड केयर हब में ले लिया गया था। वे झूलाघर में अन्तिम परिष्करण कार्य (finishing work) में सक्रिय रूप से शामिल थीं, फ़र्नीचर और अन्य सामग्रियों का चयन करने में और मार्च में चुनिन्दा लोगों के लिए शुभारम्भ के संचालन में मदद कर रही थीं।

यह सुविधा मार्च 2015 में चुनिन्दा लोगों के लिए आरम्भ की गई, कुछ महीनों के भीतर, यह पूरी क्षमता से कार्य करने लगी, और यह दौर तब से अब तक जारी है।

चाइल्ड केयर हब अब अपने संचालन के चौथे वर्ष में है। इसने कभी भी अधिभोग दर (occupancy rate) में गिरावट का अनुभव नहीं किया और न ही इसके सेवा स्तरों में कोई गिरावट आई है, जो कार्यस्थल पर ऐसी गुणवत्तापूर्ण सुविधा की उच्च माँग के प्रत्यक्ष संकेतक हैं जो कर्मचारियों को बेहतर कार्य-जीवन सन्तुलन प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रवेश के लिए अग्रिम पंजीकरण की लम्बी प्रतीक्षा सूची और बड़े बच्चों के अभिभावकों द्वारा अपने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल के बाद की देखभाल की सुविधा के लिए लगातार अनुरोध करना, देशभर में सभी उद्योगों में महिलाओं के अनुकूल, समान अवसरयुक्त एक कार्यस्थल विकसित करने में इस हस्तक्षेप कार्यक्रम की सामर्थ्य का प्रमाण हैं।

मातृत्व हितलाभ (संशोधन) अधिनियम (Maternity Benefits [Amendment] Act), 2017 और कार्यस्थल के निकटवर्ती स्थान पर एक झूलाघर उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश को देखते हुए, अधिक-से-अधिक संगठन इस उद्यम का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। वे राज्य में औद्योगिक और आईटी पार्कों में मॉडल को दोहरा रहे हैं। कई कम्पनियों ने अब अपनी मानव संसाधन (Human Resource—HR) नीतियों में बदलाव किए हैं, जिसमें उन कर्मचारियों के लिए शिशु देखभाल खर्च की प्रतिपूर्ति के विकल्प शामिल हैं जो छोटे बच्चों की माँ हैं।

परिसर और संकल्पना

विस्तार (spectrum) के एक छोर पर

- केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में इंजीनियरिंग और विज्ञान स्नातकों जैसे उच्च शिक्षित पेशेवर बड़ी संख्या काम करते हैं।
- प्रवेश स्तर पर, इस आईटी पार्क में कार्यबल में महिलाओं—जो इंजीनियरिंग, तकनीकी, और विज्ञान की विधाओं में स्नातक हैं, की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। वे समान रूप से सक्षम, गतिशील, और महत्वाकांक्षी हैं, और आईटी उद्योग में अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही प्रमुख पेशेवर उपलब्धियों की आकांक्षी हैं।
- जैसे-जैसे वर्ष बीतते हैं, और प्रगति होती है पेशे में पदोन्नति होती है, पर्यवेक्षी और मध्य प्रबन्धन भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 25 प्रतिशत तक गिर जाता है। उच्चतर स्तरों पर, यह लगभग अदृश्य हो जाता है, उच्चतम स्तर (C suite) पर यह मात्र 2 प्रतिशत रह जाता है।
- **मूल कारण:** अपने पेशे में चरम पर स्थित किसी महिला के जीवन में शादी और बच्चे के जन्म जैसी घटनाएँ, उसके पेशेवर विकास पर अत्यन्त विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। महिलाओं का बहुत अधिक प्रतिशत अपने पेशे से दूर होने का विकल्प चुनता है, क्योंकि वे फूलते-फलते पेशे के मुकाबले बच्चे के पालन-पोषण को प्राथमिकता देती हैं। पाँच

साल बाद, जब उनके बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, और यह महिलाएँ अपना पेशा पुनः शुरू करने के लिए तैयार होती हैं, तो उन्हें यह एक बड़ी चुनौती लगती है। इस बीच तेज़ी से हुए प्रौद्योगिकीय और अन्य परिवर्तनों का सामना करना उन्हें मुश्किल लगता है। प्रायः कई महिलाओं के लिए काम पर लौटने या पुनः काम शुरू करने का अर्थ है आरम्भ बिन्दु पर लौटना।

- **प्रमुख उत्तोलक (Key lever):** औद्योगिक पार्कों और आईटी पार्कों में, बच्चे की देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे और सेवा सहायता की उपलब्धता अत्यधिक सीमित है या उनका पूर्ण अभाव है, या असामान्य रूप से निम्न स्तरीय है। जो लोग एकल परिवारों से आते हैं और जो आजीविका कमाने शहर की तरफ़ प्रवास करते हैं उन्हें एक विश्वसनीय सहायता प्रणाली के अभाव के कारण अपने बहुत छोटे बच्चों की देखभाल के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं को अपनी नौकरियाँ छोड़ने और परिवार के कमाई नहीं करने वाले सदस्य बने रहने पर मजबूर होना पड़ता है, इस प्रकार उनकी पेशेवर आकांक्षाएँ विफल हो जाती हैं।
- **नतीजा:** वित्तीय सन्दर्भ में, यह विशेष रूप से कम्पनी के लिए प्रतिभा पलायन से सम्बन्धित उल्लेखनीय नुकसान और आमतौर पर अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान के रूप में परिवर्तित होता है। इसके अलावा, यह महिलाओं और उनके परिवारों के लिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह से एक व्यक्तिगत क्षति है।

विस्तार के दूसरे छोर पर

- आजीविका कमाने और अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान करने के अत्यन्त सीमित अवसरों के कारण निम्न-आय वर्ग की गृहिणियाँ एक अप्रयुक्त कर्मचारी समूह बनी रहती हैं।
- केरल में, इसकी उच्च साक्षरता दर के साथ, निम्न-आय वर्ग की एक युवा गृहिणी का औसत शैक्षिक स्तर 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण है। इनमें से पचास प्रतिशत स्नातक या तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त हैं, जिनके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण में कोई डिप्लोमा या प्रमाणपत्र है। वे ज़्यादातर नर्सिंग सहायक, दाइयाँ, दर्ज़ी, ब्यूटीशियन, आँगनवाड़ी शिक्षक, और आशा कार्यकर्ता (Accredited Social Health Activist [ASHA]—मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) हैं।
- इस अप्रयुक्त कार्यबल में अपना समय, कौशल, और ऊर्जा का योगदान करने की क्षमता है। यह एक बहुत ही इच्छुक भाग (willing segment) है जो सही अवसर को झपटने के लिए तैयार है। यह ज़मीनी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

कुटुंबश्री द्वारा पहले ही ज़मीनी स्तर की सूक्ष्म-उद्यम इकाइयों की शक्ति का प्रदर्शन किया जा चुका है। कुटुंबश्री इलाके की महिलाओं को उचित मूल्य की कैंटीन, अचार बनाने की इकाइयाँ, और सिलाई करने की इकाइयाँ स्थापित करने के लिए एक साथ आने में सहयोग प्रदान करती है। यह कौशल और क्षमताओं के आधार पर महिलाओं को अपशिष्ट इकट्ठा करने वाले और ऑटो एवं टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए प्रशिक्षित भी करती है।

परियोजना के मॉडल

एक उच्च कुशल महिला पेशेवर एक बेहतर कार्य-जीवन सन्तुलन प्राप्त करने और अपने पेशे में पूरी क्षमता से कार्य करने में सक्षम होगी बशर्ते उसे एक ऐसी सहायता प्रणाली प्रदान की जाती है जो पेशे के प्रारम्भिक दौर में जीवन की प्रमुख घटनाओं, जैसे—गर्भावस्था, प्रसव, और बच्चे की देखभाल का सामना करने में उसकी मदद करे, और उसे उस समय भी अभिभावकीय देखभाल के विकल्प और स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करे जब वह अपनी मध्यम आयु में हो और मध्य-प्रबन्धकीय स्तर पर कार्यरत हो।

आईटी और आईटीईएस उद्योग अब इस प्रतिभा पलायन और अपने कार्यबल में लैंगिक अन्तर के बारे में तेज़ी से जागरूक हो रहा है, और इसलिए महिला कर्मचारियों, जो एक अनमोल प्रतिभा समूह हैं, को ऐसी लैंगिक विविधता और महिला-केन्द्रित नीतियों के माध्यम से अपने यहाँ बनाए रखने के लिए प्रवृत्त है जो एक बेहतर कार्य-जीवन सन्तुलन की पेशकश करती हैं। सरकारें भी लैंगिक-संवेदनशील श्रम क़ानूनों को मज़बूत करने, महिलाओं के अनुकूल कार्यस्थलों के विकास के लिए विस्तारित मातृत्व देखभाल और बच्चे की देखभाल सुविधाएँ प्रदान करने, और सभी के लिए समान अवसर निर्मित करने के लिए लैंगिक विविधता और समावेश को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही हैं।

हालाँकि, 2014 में जब चाइल्ड केयर हब परियोजना की संकल्पना की गई थी, तब मातृत्व हितलाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017, जिसके द्वारा कम्पनियों के लिए डे केयर सुविधाएँ होना अनिवार्य कर दिया था, पारित नहीं किया गया था, और इसलिए कम्पनियों पर परियोजना लागू करने का कोई नियामक दबाव नहीं था।

टेक्नोपार्क का विशाल परिसर 50,000 से अधिक पेशेवरों का कार्यस्थल है। इस कार्यबल में 40 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

टेक्नोपार्क में काम करने वाली 20,000 महिलाओं में से 30 प्रतिशत महिलाओं का किसी भी समय जीवन की घटनाओं, जैसे—गर्भावस्था और युवा मातृत्व से गुज़रने का अनुमान रहता है। इसका मतलब है 10,000 युवा अभिभावकों के रूप में सम्भावित लक्षित दर्शक। किसी महानगर में, ऐसे युवा अभिभावकों का प्रतिशत बहुत अधिक होने की सम्भावना है जो अपने

विस्तारित या संयुक्त परिवार के सहयोग के बिना अकेले रहते हैं। त्रिवेन्द्रम में भी, लगभग 25 से 30 प्रतिशत ऐसे पेशेवर कार्यबल में शामिल हैं, जो राज्य के अन्य हिस्सों और देश के अन्य भागों से यहाँ स्थानान्तरित हुए हैं, और इसलिए उनके पास सहारा लेने के लिए परिवार-आधारित सहयोग प्रणाली नहीं है। यह लक्षित समूह पेशेवर संघर्षण के प्रति अत्यधिक प्रवृत्त है, और महिलाएँ अक्सर अपने कार्यस्थल के आसपास गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर सुविधा के अभाव में शिशु देखभाल पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अपना पेशा छोड़ देती हैं। यह बहुत अधिक संख्या है और माँग-आपूर्ति का अन्तर आसपास के क्षेत्र में लगातार तेज़ी से बढ़ रही शिशु देखभाल सुविधाओं द्वारा भी नहीं पाटा जा सकता।

यह केस स्टडी न केवल टेक्नोपार्क, त्रिवेन्द्रम में कामकाजी महिलाओं की कहानी है, बल्कि पूरे भारत में, महानगरों, और ग़ैर-महानगरों में समान रूप से, और किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि यह एक वैश्विक तथ्य है।

हमारे पास आईटी पार्कों और औद्योगिक पार्कों, जहाँ महिलाओं का एक पेशेवर कार्यबल केन्द्रित है, के आसपास स्थानीय गृहिणियों के बीच एक अप्रयुक्त कार्यबल मौजूद है। महिलाओं का यह अप्रयुक्त समूह एक सम्भावित प्रतिभा समूह निर्मित करता है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है और शिशुओं तथा वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए तैयार किया जा सकता है, इस प्रकार युवा पेशेवर जोड़ों के लिए सहयोग प्रणाली बन सकता है, जिनके पास घर पर विश्वसनीय सहयोग प्रणालियों की कमी है।

यह गृहिणियाँ यदि पेशेवर रूप से व्यक्तिगत स्वास्थ्य-रक्षा, सजने-सँवरने, चाइल्ड केयर, और नर्सिंग देखभाल में प्रशिक्षित हैं, तो परिवार के सहयोग का एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकती हैं, जो कि पूर्व में बड़े संयुक्त परिवारों में बिना प्रयास ही उपलब्ध था। यह स्थानीय महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर का एक नया मार्ग प्रशस्त करता है, जो अन्यथा अपनी कमज़ोर सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण एक नियमित आय और एक सम्मानजनक नौकरी से वंचित हैं।

इन सभी बिन्दुओं को जोड़ते हुए, किसी सामाजिक समावेश कार्यक्रम के रूप में एक ज़मीनी स्तर के हस्तक्षेप की संकल्पना की गई जो दो अलग-अलग सामाजिक स्तरों से आने वाली महिलाओं को सशक्त बनाता है ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। परियोजना संचालित करने के लिए धुरी के रूप में, एक ग़ैर-लाभकारी संगठन eWIT के साथ-साथ टेक्नोपार्क, कुडुंबश्री, और आईटी पार्क से संचालन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शामिल करते हुए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल के रूप में इस संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान पूर्ण किया जा सका।

चुनौतियाँ : नियंत्रण और विजय प्राप्ति

परियोजना अपने हिस्से में आने वाली कठिनाइयों और असफलताओं से गुजरी है, जिन्हें यहाँ परियोजना प्रबन्धन के अनुभवों, सबक, और सन्दर्भ के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के रूप में प्रलेखित किया गया है।

- हितधारक प्रबन्धन:** भागीदार संगठनों की कार्यशैली विस्तार के एक छोर पर स्थित सरकारी विभागों और विस्तार के दूसरे छोर पर स्थित गैर-सरकारी संगठनों से बहुत अलग थी, और निगमित निकायों से पूरी तरह से अलग थी। सभी तीन बहुत अलग-अलग कार्य शैलियों में तालमेल क़ायम करना, शक्तियों पर ध्यान केन्द्रित करना, और एक सामान्य आधार पर अभिसरण करना एक बड़ी चुनौती थी। इस कार्य के लिए यह आवश्यक था कि eWIT संचालक मण्डल के सदस्यों अपने सर्वोत्तम हितधारक प्रबन्धन कौशल का उपयोग करें, साथ ही काफ़ी समय और प्रयास लगाए जाएँ।
- सरकार से अनुमोदन:** संकल्पना के चरण में, सरकारी विभागों में निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तनों के कारण परियोजना अवरुद्ध हुई। जब वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों द्वारा परियोजना के प्रस्ताव की जाँच की गई तब सिद्धान्त रूप में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता आधिकारिक हस्ताक्षरों के साथ वास्तविक दस्तावेज़ में परिवर्तित नहीं हुई। फलस्वरूप, परियोजना दल को कई अवसरों पर शुरुआती बिन्दु पर लौटना पड़ा, लेकिन उनका हठ, दृढ़ संकल्प, और योजना के प्रति दृष्टि की स्पष्टता क़ायम रही।
- वित्तीय चुनौतियाँ:** क्रियान्वयन के चरण में किए गए ग़ैर-बजटीय खर्चों के परिणामस्वरूप प्रायोजन प्रतिबद्धता के माध्यम से जुटाए गए धन की कमी हो गई। शुरुआत में, टेक्नोपार्क परिसर में कुछ निगमित निकायों ने परियोजना में गहरी रुचि दिखाई थी और वे आन्तरिक व्यवस्थाओं के लिए प्रायोजकों के रूप में शामिल थे। हालाँकि, उनकी प्रतिबद्धता के बावजूद, आवश्यक धनराशि की कमी बनी हुई थी। वित्तीय चुनौतियों को बढ़ाते हुए, टेक्नोपार्क के साथ पट्टा समझौता (lease agreement) हस्ताक्षर करते समय, एक अप्रत्याशित वैधानिक व्यय अचानक सामने आया। हालाँकि इस परियोजना को एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रम कहा जाता है, लेकिन टेक्नोपार्क के अधिकारी वैधानिक भुगतानों, जैसे—स्थान के लिए प्रतिभूति राशि या विद्युत लाइसेंस के लिए अवधान राशि, के लिए कोई छूट नहीं दे सकते थे, जो कुछ लाख रुपए होती है। यह आन्तरिक व्यवस्थाओं की लागत पर एक अतिरिक्त बोझ था।

अब दो विकल्प थे।

पहला विकल्प यह था कि इन वैधानिक भुगतानों से छूट पाने का अनुरोध करने के लिए सरकार के उच्चतर अधिकारियों के सामने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में समय और प्रयास लगाए जाएँ, हालाँकि परिणाम अनिश्चित था। यहाँ चुनौती यह थी कि वांछित राशि का भुगतान न करने की वजह से समयान्तर, और छूट के अनुरोध पर एक निर्णय का इन्तज़ार और परियोजना पर आगामी प्रभाव से निपटना होगा। यह परियोजना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोपार्क अधिकारी आन्तरिक व्यवस्थाओं सम्बन्धी कार्य, और आन्तरिक रूपरेखा के लिए वैधानिक जमा के भुगतान, और समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सुविधा केन्द्र सौंपते।

दूसरा विकल्प था अग्रिम वैधानिक भुगतान करना और परियोजना के लिए घोषित समयसीमा के अनुसार बढ़ना, एवं घाटे की पूर्ति करने हेतु वित्तपोषण के लिए परिसर के अन्दर और बाहर के शुभचिन्तकों से अधिक प्रायोजन प्राप्त करना।

- परियोजना टीम ने अतिरिक्त धन जुटाने के लिए एक प्रायोजन मुहिम शुरू करने का फैसला किया, और सौभाग्य से और दरवाज़े खुल गए। परियोजना की क्षमता को देखते हुए और इस कार्यक्रम में धुरी इकाई के रूप में eWIT द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर, सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक ने घाटे की राशि को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत योगदान द्वारा परियोजना में सहयोग करने की पेशकश की। इस सदस्य ने शहर की एक ब्रांडेड बेबी शॉप का हवाला भी दिया, जो परियोजना में सहयोग करने के लिए राज़ी हुई; दुकान ने बड़ी मात्रा में खिलौने प्रदान करके आन्तरिक व्यवस्था की लागत को काफ़ी हद तक घटाने में मदद की। मौजूदा प्रायोजकों ने चुनिन्दा लोगों के लिए सुविधा के शुभारम्भ के बाद प्रारम्भिक दुर्बल चरण के दौरान सुविधा की परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए प्रायोजन राशि में वृद्धि की। इस प्रकार, परियोजना दल परियोजना की समयसीमा को आगे बढ़ाए बिना, वित्तीय संकटों पर आसानी से क़ाबू पाने में सफल रहा।

- **व्यावसायिक दर पर किराए:** परिसर में चाइल्ड केयर सेंटर जैसी बुनियादी सुविधा हेतु * किराए में छूट के लिए eWIT ने आईटी विभाग, केरल सरकार के सम्मुख एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसमें मातृत्व हितलाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 में हुए बदलावों का सन्दर्भ दिया गया, जिसमें कार्यस्थल पर डे केयर सेंटर की व्यवस्था करना नियोक्ता की ज़िम्मेदारी है। दो साल बाद इस अभ्यावेदन के परिणाम आए और चाइल्ड केयर हब के संचालन का परिदृश्य बदल गया। इस अभ्यावेदन को अभिभावकों और अन्य हितधारकों का समर्थन मिला, और इस मामले में eWIT ने अथक प्रयास जारी रखे। फलस्वरूप, केरल सरकार ने अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि वे परिसर के भीतर बाल देखभाल केन्द्र स्थापित करने के लिए किराया-मुक्त स्थान प्रदान

करें; हालाँकि, आवण्टित स्थान के लिए संचालन और रखरखाव शुल्क अब भी देय हैं। इस परिपत्र के पूर्वव्यापी प्रभाव ने, जिसने चाइल्ड केयर हब की शुरुआत से ही उसकी किराया राशि माफ़ कर दी, चाइल्ड केयर हब की बैलेंस शीट को लाल से हरे रंग में बदलने में मदद की।

- **स्टाफ़-सम्बन्धी खर्च:** स्टाफ़-सम्बन्धित खर्चों में साल-दर-साल होने वाली वृद्धि से तभी निपटा जा सकता है जब किरायों से पैसा बचाया जा सके। क्षमता योजना के विवेकपूर्ण ढंग किए गए प्रबन्धन ने स्टाफ़ से सम्बन्धित खर्चों को नियंत्रित रखने में और गुणवत्तापूर्ण सेवा के उच्च मानक क़ायम रखने में भी मदद की है, जो एक सेवा-प्रधान डे केयर सुविधा की सफलता का प्रमाण चिह्न है।

अन्य आईटी कम्पनियों में नई डे केयर सुविधाओं में पर्यवेक्षी भूमिकाओं में पेशे की बेहतर सम्भावनाएँ खोजने में वरिष्ठ स्टाफ़ सदस्यों की मदद करने और ख़ाली स्थानों को चाइल्ड केयरटेकरों के लिए प्रशिक्षु स्तर के स्टाफ़ से वापस भरने से स्टाफ़ सम्बन्धी खर्च नियंत्रित रखने में मदद मिली है, यानी, यह साल-दर-साल अन्तर्वाह (inflow) के 60% से अधिक नहीं हुआ है।

चाइल्ड केयर हब कर्मचारियों के कल्याण और ठहराव के उच्च स्तर क़ायम रखने में eWIT सफल रहा है, जिससे उच्च स्तर की ग्राहक सन्तुष्टि और नेट प्रमोटर स्कोर (Net Promoter Score—NPS) सम्भव हुए हैं, क्योंकि यह एक लाभ-प्रेरित वाणिज्यिक उद्यम नहीं है, बल्कि इसकी परिकल्पना महिलाओं के सशक्तिकरण, बाल कल्याण, और सामाजिक समावेश के लिए एक मॉडल पहल के रूप में की गई है।

- **ख़तरे के तहत परियोजना व्यवहार्यता:** जब परियोजना की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तब इसकी परिकल्पना एक सहयोगात्मक मॉडल के रूप में की गई जिसमें सरकारी अधिकारियों का सहयोग अपेक्षित था।
- हालाँकि, परियोजना में प्रमुख भूमिका निभाने वाले eWIT को आईटी विभाग की तरफ़ से परियोजना में उसकी साझेदारी की प्रतिबद्धता के बारे में स्पष्ट रूप से कोई लिखित दस्तावेज़ प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल सकी। इसके परिणामस्वरूप परियोजना का लागत लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis—CBA) डॉवाडोल स्थिति में रहा, क्योंकि टेक्नोपार्क ने डे केयर सेंटर के लिए आवण्टित स्थान के लिए अपना मानक वाणिज्यिक किराया तथा संचालन और रखरखाव शुल्क लिया। केवल किराए के लिए आवण्टित यह राशि ही राजस्व का 20 प्रतिशत हो जाती थी।
- इस परियोजना में, सुविधा में स्वीकार्य बच्चों की संख्या और प्रवेश एवं मासिक शुल्क स्थिर खर्च हैं, जिसमें पहले पाँच वर्षों तक वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। हालाँकि, किराए और कर्मचारियों के खर्च (राज्य में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए संशोधित

न्यूनतम वेतन और वैधानिक खर्चों सहित) परिवर्तनशील घटक हैं, जिसके परिणामस्वरूप साल-दर-साल खर्च बढ़ा है, और इस तरह वित्तीय रूप से परियोजना के अव्यवहार्य हो जाने का खतरा मँडराता रहा है।

- चाइल्ड केयर सुविधा जैसे एक सेवा-उन्मुख उद्यम में बेहतर ग्राहक और हितधारक प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण संसाधन कायम रखने की आवश्यकता के साथ-साथ वेतन और हितलाभों की उच्च लागत का अर्थ एक वहनयोग्य शुल्क ढाँचे के अधीन एक गुणवत्तापूर्ण डे केयर सुविधा संचालित करने की लागत के मामले में एक अतिरिक्त बोझ है।
- कार्यान्वयन के बाद के चरण के पहले दो वर्षों में, परियोजना दल को निम्नलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ा : आईटी परिसर में उच्च किराया; वेतन और हितलाभों की उच्च लागत; और बेहतर ग्राहक एवं हितधारक प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों का ठहराव कायम रखने में चुनौतियाँ।

सफलता के कारक : मॉडल को कायम रखना

इस मॉडल को कायम रखने और ग्राहकों द्वारा बढ़ती माँग को पूरा करने में मदद करने वाले प्रमुख उत्तोलक हैं:

- **गैर-लाभकारी अवधारणा—गैर-वाणिज्यिक उद्यम:** चूँकि इस परियोजना का उद्देश्य सामाजिक समावेश है, इसलिए वित्तीय मामलों में पारदर्शिता कायम रखी जाती है। अन्य सुविधाओं द्वारा दी जाने वाली समान सेवाओं की तुलना में सुविधा का लाभ उठाने के लिए मासिक शुल्क एक उचित स्तर पर रखा जाता है। सुविधा शुरू होने के बाद से शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। निधियों के अन्तर्वाह का बहिर्वाह से विवेकपूर्ण तरीके से मानचित्रण किया जाता है। राजस्व का एक बड़ा हिस्सा (60 प्रतिशत से अधिक) चाइल्ड केयरटेकरों के वेतन और हितलाभों पर खर्च किया जाता है। संचालन और रखरखाव की लागत को राजस्व के 20 प्रतिशत की सीमा में नियंत्रित रखा जाता है।
- **किए जाने वाले अतिरिक्त खर्चें हैं:** बाल रोग विशेषज्ञ के दौरे, चिकित्सीय सत्रों, और अभिभावकों के सत्रों के लिए तथा वर्ष के दौरान त्योहारों और विशेष अवसरों के आयोजन के साथ ही एक डे केयर सेंटर के संचालन से सम्बन्धित विनियामक और वैधानिक व्यय। साल-दर-साल, एक सुरक्षित निधि (शुद्ध लाभ), जिसमें राजस्व का 10 से 15 प्रतिशत शामिल होता है, कार्यक्रम आयोजित करने, सेमिनार संचालित करने, और चाइल्ड केयर

हब संचालित करने वाले आईटी तथा आईटीईएस समुदाय के लिए महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजनाओं को लागू करने के लिए अलग रखी जाती है।

- **अभिभावकों और केयरटेकरों के बीच स्वामित्व की भावना:** चाइल्ड केयर हब का प्रशासन सामूहिक रूप से हितधारकों की एक समिति द्वारा प्रबन्धित किया जाता है, जहाँ अभिभावक और केयरटेकर अपनी चिन्ताएँ व्यक्त करते हैं और सुधार के लिए अनुशंसाएँ प्रस्तुत करते हैं। यह स्वामित्व की भावना को बढ़ाता है और अभिभावक तथा केयरटेकरों द्वारा उद्यम की सफलता के लिए सामूहिक ज़िम्मेदारी स्वीकार करना सम्भव बनाता है।

- **नाज़ुक-स्पर्श प्रबन्धन और शासन:** भले ही eWIT, कुडुंबश्री, टेक्नोपार्क, और अन्य प्रायोजक कम्पनियाँ संचालक परिषद का हिस्सा हैं, लेकिन प्रतिदिन के संचालन में हितधारकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सीमित है। यह विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन और ज़िम्मेदारियों के प्रत्यायोजन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है।

इसके अलावा, इन प्रभावशाली हितधारकों की प्रबल उपस्थिति चाइल्ड केयर हब की विश्वसनीयता को मज़बूती प्रदान करती है, जिससे यह इलाके में व्यावसायिक रूप से संचालित अन्य डे केयर सुविधाओं के बावजूद युवा तकनीकी विशेषज्ञ अभिभावकों के लिए पसन्दीदा विकल्प है।

- **उद्योग और समुदाय द्वारा सहयोग:** सामाजिक समावेशन के उद्देश्य से एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी उद्यम के रूप में, चाइल्ड केयर हब ने विशेष रूप से टेक्नोपार्क समुदाय और सामान्य रूप से आईटी एवं आईटीईएस उद्योग में उत्साह जगा दिया है।

मॉडल का मूल्यांकन करने और सफलता के कारकों का आकलन करने के लिए कुडुंबश्री परियोजना दलों की तरह केरल राज्य योजना मण्डल (Kerala State Planning Board—KSPB) और केरल राज्य समाज कल्याण मण्डल (Kerala State Social Welfare Board—KSSWB) के प्रतिनिधि नियमित रूप से चाइल्ड केयर हब का दौरा करते हैं, ताकि इस पहल को पूरे केरल और अन्य उद्योगों में दोहराया जा सके। इस खुलासे से ग्राहकों, हितधारकों, और उद्योग में संरक्षकों के बीच परियोजना की दृश्यता और विश्वसनीयता विकसित करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

यह एक पूरी तरह से अनुकरणीय मॉडल है, अत्यधिक टिकाऊ है, निवेश पर दीर्घकालिक सामाजिक लाभ (Social Return on Investment—SROI) प्रदान करता है, और वित्तीय लाभ के अवसर पैदा करता है।

1,100 वर्ग फुट जगह में एक छोटी-सी सुविधा 30 बच्चों को समायोजित कर सकती है और स्थानीय समुदाय की आठ से 10 महिलाओं को रोज़गार दे सकती है, जो उच्च सुरक्षा वाले आईटी पार्कों की सीमाओं के भीतर दो पालियों (सुबह और शाम) में काम करती हैं।

इस मॉडल को ऐसी किसी भी संस्था द्वारा अपनाया जा सकता है जिसमें 500 से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हों, जो अलग-अलग पालियों में काम करती हों, या इलाक़े की कई कम्पनियों द्वारा इसे अपनाया जा सकता है जो अपने महिला कार्यबल की सहायता करने के लिए एक सामुदायिक चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए एक साथ आते हैं।

मॉडल आत्म-संधारणीय (self-sustainable) है, जिसमें सुविधा स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए के प्रारम्भिक निवेश की आवश्यकता है। इस राशि को कम्पनी प्रायोजनों या वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज वाले व्यावसायिक ऋण के माध्यम से जुटाया जा सकता है।

यह पहल महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाकर, आसपास के इलाक़े में महिलाओं को कई सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुँचाएगी।

इससे किसी अत्यधिक कुशल पेशेवर वातावरण में कार्य करने वाले कार्यबल में और निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

पहल की सफलता को मापने के यह प्रमुख उत्तोलक हैं।

भावी मार्ग

eWIT चाइल्ड केयर हब कार्य के पैमाने और कार्यक्षेत्र के विस्तार की आकांक्षा रखता है।

इस सामाजिक समावेशन कार्यक्रम के अगले चरण में, eWIT चाइल्ड केयर हब टीम की टेक्नोपार्क परिसर में एक चिल्ड्रन्स लर्निंग सेंटर (Children's Learning Centre) स्थापित करने की योजना है ताकि तकनीकी विशेषज्ञ अभिभावकों के स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल के बाद की देखभाल की सुविधा प्रदान की जा सके।

आईटी और आईटीईएस उद्योग में काम करने वाले पेशेवरों की पाली के अनियमित समय और घर पर पर्याप्त सहायता प्रणाली की कमी को देखते हुए, कई युवा बच्चों के अभिभावक, विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों के, आज विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। यह सुविधा उनके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

लर्निंग सेंटर बच्चों के लिए ई-लर्निंग सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरियाँ, प्ले स्टेशन, आउटडोर खेलों के साथ ही सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने, शौक पूरा करने, और छिपी प्रतिभाओं का पता लगाने के अवसर प्रदान करेगा।

स्थानीय समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए यह पहल पुनः एक आजीविका अवसर प्रस्तुत करेगी।

eWIT चाइल्ड केयर हब की योजना सरकार से परियोजना सहायता और अनुदान तथा विभिन्न आईटी कम्पनियों से प्रायोजन प्राप्त कर इस पहल का दूसरा चरण शुरू करने की है।

अनुलग्नक : सन्दर्भ सामग्री (Annexure: Reference materials)

1. eWIT CC Hub, Journey in pictures Journey through pictures—eWIT CCH
2. गिबी जॉन, एक काफ़ी पुरानी उपभोक्ता से प्राप्त प्रशंसा पत्र, जिन्होंने अपने बेटे जो तीन साल तक चाइल्ड केयर हब मॉम्स में था के प्री-केजी स्कूल में दाखिल होने पर एक भावनात्मक विदाई टिप्पणी साझा की।
3. Times of India, Thiruvananthapuram, September 2014

Kudumbashree lends a hand to techies

Creche In Technopark By Next Month

THIRUVANANTHAPURAM

Thiruvananthapuram: The trials of balancing work and child care are still fresh in the minds of Rani Sasikumar and Parvathy Pillai, IT professionals in their 40s at Technopark. The office-bearers of the Trivandrum chapter of e-WIT—a forum for empowering women in IT—had taken up the initiative for a creche inside their campus, which will be launched in the second week of January.

The forum has roped in Kudumbashree workers in the neighbourhood for managing the creche, which is expected to be a boon for thousands of techies. On Monday, it launched a 30-day training programme for caregivers in association with Kudumbashree Mission. The first batch comprises 20 Kudumbashree workers, residing in the neighbourhood, who will

manage the creche in shifts.

A core committee of the forum, led by president Sindhuja R Varma, had selected the caregivers after an aptitude test and interview. “We have tied up with a professional agency, RAACE, based in Bangalore to impart soft skills and beha-

vioural training. It will be leading the classes,” Sindhuja said.

The training will also include practical sessions on child care handled by paediatricians and child psychologists.

“We plan to employ eight candidates shortlisted after the training

programme to manage the creche initially. We intend to admit 25 children in the first batch,” Sindhuja said.

e-WIT programme manager Rani Sasikumar said the playschool, of 1,000-sq ft area, was being set up inside the Thejaswini building with the support of sponsoring companies.

Technopark chief executive K.G. Girish Babu said most employees at the facility had toddlers. “Though they can seek the help of babysitters, many of them fail to give proper care to kids. The creche is a welcome initiative as it assures them that their kids are nearby and safe. This will also help them to concentrate more in their work,” he said.

Girish Babu and e-WIT had signed the memorandum of understanding for the creche in September.

The training programme was inaugurated by Kudumbashree Mission executive director K.B. Valsalakumari at the head office of the mission at Medical College on Monday. RAACE founder Aparna Vishwanath was also present.

(With inputs from Arja UR)



TRAINING PROGRAMME: President of e-WIT, Trivandrum chapter, Sindhuja R Varma interacts with Kudumbashree workers during a training session on Monday

प्रकाशित आलेख

4. Video: Child Care Hub empowering women from two social strata:
<https://www.youtube.com/watch?v=IOAVqCYIsaM>
5. eWIT Trivandrum—networking platform for empowering women in IT and ITeS industry <http://ewittvm.co.in/>
6. Articles on LinkedIn on everyday role models to create awareness on giving back to society. <https://www.linkedin.com/pulse/superwomen-everyday-role-models-who-change-my-life-viswanathan/>

आईटी और आईटीईएस में महिलाओं का सशक्तिकरण (eWIT), केरल

आईटी में महिलाओं का सशक्तिकरण (Empowering Women in IT—eWIT) आईटी / आईटीईएस उद्योग से जुड़ी वरिष्ठ महिला पेशेवरों के एक समूह द्वारा संचालित एक स्वैच्छिक और गैर-लाभकारी मंच है। eWIT का गठन मार्च 2006 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ़ इंडिया (Software Technology Parks of India—STPI), चेन्नई के सहयोग से किया गया था।

यह एक ऐसा मंच है जो विशेष रूप से आईटी उद्योग में महिलाओं के मुद्दों को सम्बोधित करता है। eWIT विचारों के आदान-प्रदान और अग्रणी पहल करने का प्रयास करता है ताकि आईटी उद्योग में महिलाओं की क्षमता खुलकर प्रकट हो और उनके विकास को गति प्रदान की जा सके।

3.2 खुद के खेतों पर मज़दूर से भूस्वामी बनना:

गुजरात में महिला किसानों की आजीविका को बढ़ावा देना

वर्किंग ग्रुप फॉर वीमेन एंड लैंड ओनरशिप (WGWLO), गुजरात

सारांश

वर्किंग ग्रुप फॉर वीमेन एंड लैंड ओनरशिप (Working Group for Women and Land Ownership—WGWLO) का गठन 2003 में इस मुद्दे पर निरन्तर कार्यवाही और नीतिगत पैरवी के लिए एक केन्द्रित, बहु-स्तरीय, सामूहिक मंच की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। गुजरात-आधारित 13 गैर-सरकारी संगठनों की प्रारम्भिक सदस्यता के साथ शुरू करते हुए, WGWLO नेटवर्क में 41 गैर-सरकारी संगठनों / समुदाय-आधारित संगठनों (NGO / CBO) और व्यक्तियों को शामिल किया गया है। यह केस स्टडी इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे WGWLO, संगठनों और ग्रामीण महिलाओं के समूहों का एक नेटवर्क, महिलाओं के भूमि के स्वामित्व के एकमात्र मुद्दे से परे चला गया और इसने अपने संचालन के क्षेत्र का विस्तार किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन महिलाओं के पास खुद की ज़मीन है वे पूँजी और अन्य संसाधनों तक पहुँचने में भी सक्षम हों और इस तरह वे अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकें। मामले के अध्ययन में पारिवारिक स्तर पर और सरकारी तंत्र दोनों में महिलाओं की पहचान “किसान” के रूप में निर्मित करने के WGWLO के सदस्यों के सामूहिक प्रयासों, और इस उद्देश्य के लिए संगठन द्वारा अपनाई गई रणनीतियों, उनके प्रभाव, और परिणाम के रूप में उभरने वाली सीखों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का वर्णन भी किया गया है। यह दस्तावेज़ सदस्य संगठनों—नवजीवन आदिवासी महिला मंच सागबारा, ज़िला नर्मदा; महिसागर ज़िले के संतरामपुर में सारथी (सागबारा और संतरामपुर दोनों ही आदिवासी क्षेत्र हैं); और बावला, अहमदाबाद ज़िले के बावला महिला विकास संगठन के निरीक्षणों, और उनके साथ संवाद पर आधारित है। तीनों स्थानों पर फ़ील्ड दौरों और महिला भूस्वामियों के साथ बातचीत यह समझने के लिए की गई कि महिलाओं ने अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए स्व भूमि केन्द्र (Swa Bhoomi Kendra—SBK) की सेवाओं तक पहुँच कैसे स्थापित की।

महिला, भूस्वामित्व, और 'किसान' के रूप में महिलाएँ: आन्तरिक सम्बन्ध

2011 की जनगणना के अनुसार, 74 प्रतिशत ग्रामीण महिला कार्यबल कृषि में संलग्न है। यह प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि पुरुष बड़ी संख्या में गैर-कृषि गतिविधियों की तरफ़ मुड़ रहे हैं या काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। विभिन्न फ़सलों और क्षेत्रों में, प्रति एकड़ कृषि भूमि पर खपने वाले पुरुष-दिवसों की तुलना में महिला-दिवस अधिक हैं। इस तथ्य के बावजूद कि भारत में लगभग 98 मिलियन महिलाएँ कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं और सम्पूर्ण कृषि उपज के लगभग दो तिहाई और डेयरी उत्पादों के लगभग तीन चौथाई उत्पादन के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक पूँजी, जो कि भूमि है, में उनका हिस्सा काफी कम है। भारत की छियासी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि निजी स्वामित्व में है, और अभी भी स्वामित्व के स्वरूप की प्रबल पितृसत्तात्मक प्रकृति पर सवाल नहीं उठाया जाता है। हालाँकि समस्त ग्रामीण परिवारों में ऐसे परिवारों का हिस्सा 32 प्रतिशत से अधिक है जिनकी मुखिया महिलाएँ हैं, लेकिन महिलाओं के पास 13 प्रतिशत से कम खेती योग्य भूमि है। 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी उत्तराधिकारियों के बीच सम्पत्ति का समान वितरण अनिवार्य होने के बावजूद यह स्थिति पाई जाती है।

इसलिए, उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद, महिलाओं को “किसानों” के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है और न ही उन्हें किसानों के रूप में किसी भी पात्रता तक पहुँच प्राप्त है क्योंकि हमारे पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें कृषि भूमि का स्वामी होने की अनुमति नहीं है। महिला किसानों का विशाल योगदान पहचाना नहीं गया है। जब कृषक महिलाएँ ऋण के लिए आवेदन करती हैं या अपनी भूमि जोत का विस्तार और अपनी पैदावार में सुधार करने के लिए कोई अन्य उत्पादक संसाधन पाने का प्रयास करती हैं तब ज़मीन जायदाद के हक की कमी एक बाधा साबित होती है। भूमि सुधार या भूमि पुनर्वितरण प्रक्रियाओं में महिलाओं की अक्सर उपेक्षा की जाती है। जब सरकारी परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने के बाद लोगों को स्थानान्तरित किया जाता है, तो महिलाओं के भूमि अधिकारों को शायद ही कभी स्वीकारा जाता है। यहाँ तक कि जब इस तरह के अधिकारों को मान्यता दी जाती है और महिलाओं को ज़मीन स्वीकृत की जाती है, तो शक्तिशाली स्थानीय निहित स्वार्थ आमतौर पर यह सुनिश्चित करते हैं कि वे उसे जोत न सकें, खासकर अगर महिलाएँ उन समूहों से सम्बन्धित हैं जो पारम्परिक रूप से भेदभाव के शिकार हैं। ये भेदभावपूर्ण प्रथाएँ हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में इतनी गहराई तक सन्निहित हैं कि वे लोग ही पितृसत्तात्मक मूल्यों में विश्वास करते हैं और महिलाओं को उनके न्यायसंगत दावों से बेदखल करने के लिए प्रणालीगत प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, जिन पर यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि बेटियों को उनके न्यायसंगत दावों से वंचित नहीं किया जाए।

राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं ने कृषि भूमि अधिकारों में लैंगिक असन्तुलन दूर करने और सुधारने के प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति (National Policy for the Empowerment of Women, 2001), जिसने महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बीजिंग डिक्लरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (Beijing Declaration and Platform for Action, 1995) को अपनाया, ने एक ओर निर्धारित लक्ष्यों और सम्बन्धित प्रक्रियाओं के बीच मौजूदा अन्तर को, और दूसरी ओर महिलाओं की स्थिति की वास्तविकता को रेखांकित किया। महिलाओं के समूहों द्वारा अकृषित कृषि भूमि के पट्टे और बटाईदारी को नियमित करके महिलाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में एक खण्ड शामिल किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) ने भी कृषि में महिलाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

भूमि सुधारों, ग़रीबी-विरोधी कार्यक्रमों, और पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को भूमि के सीधे हस्तान्तरण के लिए प्रावधान किए गए। इस लक्ष्य को वास्तविकता में परिवर्तित करने के उद्देश्य से बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में आगे क़दम बढ़ाए गए।

गुजरात ने एक लैंगिक निष्पक्षता नीति (Gender Equity Policy—नारी गौरव नीति) अपनाई है। यह नीति दोहराती है कि महिलाओं के लिए आर्थिक संसाधनों के अवसर, पहुँच, और हक़ की कमी निष्पक्ष और सतत विकास में एक अवरोध का काम करती है। यह नीति भूमि, सम्पत्ति, और अन्य सामान्य सम्पत्ति संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण और स्वामित्व में वृद्धि के प्रयासों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। और फिर भी यह सच्चाई बरकरार है कि भूस्वामित्व बहुत कम—मुश्किल से 13 प्रतिशत है—और महिलाओं को “किसान” के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

स्व भूमि केन्द्र एक दृष्टिकोण के रूप में

यह माना जाता है कि ग्राम और ब्लॉक राजस्व अधिकारी अपने अधिकारों का दावा करने वाली महिलाओं के लिए मार्गदर्शक बल होंगे। हालाँकि, राजस्व प्रक्रियाएँ इतनी जटिल हैं कि महिलाओं के लिए यह समझना कठिन होता है कि कैसे आगे बढ़ा जाए और इस कारण उनका नुक़सान होता है। इसके अलावा, महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के कई उदाहरणों में परिवार के सदस्य शामिल रहते हैं, जिन्हें कार्यवाही करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किए जाने की आवश्यकता है। इन दोनों भूमिकाओं के निर्वहन में महिलाओं के दृष्टिकोण, उनकी ताक़तों और बाधाओं के बारे में समझ की आवश्यकता होती है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, WGWLO ने राजस्व और राजस्व-सम्बन्धी मामलों से निपटने के लिए 2007-08 में समुदाय आधारित क़ानून सहायक कार्मिकों (Para Legal Workers—PLWs) का एक संवर्ग (cadre) तैयार करना शुरू किया। यह क़ानून सहायक कार्मिक महिलाओं के भूमि

अधिकारों के बारे में महिलाओं और पुरुषों के बीच जागरूकता पैदा करते हैं और उन महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिन्हें सलाह और मदद की आवश्यकता होती है। अब तक, WGWLO ने 114 क़ानून सहायक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है।

इसके अलावा, WGWLO ने महसूस किया कि महिलाओं के लिए कई संसाधन केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित किए गए हैं, फिर भी ऐसे केन्द्रों की कमी है जो भू राजस्व से सम्बन्धित मामलों में महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हों, जो ज़रूरत पड़ने पर महिला के रिश्तेदारों के सामने मामले उठाते हों और जो भूमि-आधारित आजीविका-वृद्धि के अधिकारों का उपयोग करने में महिलाओं को सक्षम बनाते हों।



कई वर्षों तक, WGWLO के सदस्य संगठनों से जुड़े क़ानून सहायक कार्मिकों ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के भू अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने और महिलाओं की क़ानूनी काज़ग़ी कार्यवाही की तैयारी करने में उनकी सहायता करने का काम किया। 2013 में, एक संस्थागत प्रक्रिया, स्व भूमि केन्द्र, सेंटर फॉर लैंड, लीगल लिटरेसी, एंड एक्सेस टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेस बाय वीमेन (Centre for Land, Legal Literacy, and Access to Productive Resources by Women), ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया गया, और महिला संगठनों द्वारा इस दृष्टिकोण से संचालित किया गया कि ब्लॉक स्तर के राजस्व और कृषि अधिकारियों के साथ मज़बूत सम्बन्ध बनाकर WGWLO के सदस्यों द्वारा उठाए गए महिलाओं के भूस्वामित्व सम्बन्धी मुद्दों के दायरे और पहुँच का विस्तार हो। इस प्रकार स्व भूमि केन्द्र एक “स्थान” है

(स्थानीय समुदाय-आधारित संगठन के कार्यालय में स्थित या ब्लॉक राजस्व अधिकारी के परिसर में क़ानून सहायक कार्मिकों को आवण्टित एक स्थान) जहाँ महिलाएँ अपनी उन समस्याओं से निपटने हेतु मदद लेने के लिए आती हैं जो निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं:

- महिलाओं का भूस्वामित्व का अधिकार
- महिला किसानों के रूप में उत्पादक संसाधनों तक पहुँच

पाँच वर्षों से अधिक समय से, 15 सदस्य ग़ैर-सरकारी संगठन या ज़मीनी स्तर के महिला संगठन इस तरह के स्व भूमि केन्द्र संचालित कर रहे हैं। यह सभी ब्लॉक स्तर पर स्थित हैं, और उन क़ानून सहायक कार्मिकों द्वारा संचालित हैं, जिन्हें WGWLO नेटवर्क द्वारा केन्द्रीय रूप से प्रशिक्षित किया गया है, और वे स्थानीय महिलाओं के संगठनों से जुड़े हैं।

स्व भूमि केन्द्र और इसके आजीविका बढ़ाने के प्रयास

1. कृषि मज़दूरों से महिला भूस्वामी बनने तक

WGWLO के सदस्य संगठनों की तीन केस स्टडीज़ नीचे दी गई हैं जो नेटवर्क द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण दर्शाती हैं।

सारथी, संतरामपुर: सारथी (Sarathi) 1988 से संतरामपुर में सक्रिय है, जो लगातार महिलाओं और आदिवासियों के साथ उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। सारथी ने बचत और ऋण समूहों के निर्माण के साथ कार्य की शुरुआत की। बाद में यह समूह सरकारी कार्यक्रमों में मिला दिए गए और अब अभिकरण (Agency) से स्वतंत्र रूप से संचालित हैं। 2007-08 में, सारथी को एकल नारी मंच (Ekal Nari Manch) नामक एक मंच एकल महिलाओं हेतु स्थापित करने के लिए बाहरी रूप से समर्थित एक कार्यक्रम के तहत समर्थन मिला। लगभग उसी समय, सारथी ने सरकारी सहयोग से, महिलाओं को सूचना और क़ानूनी सहायता आधार प्रदान करने के लिए एक केन्द्र स्थापित किया। यह केन्द्र संतरामपुर के ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ बाज़ार लगता है और ससुराल वालों तथा पतियों से परेशान महिलाएँ बार-बार इस केन्द्र पर आती हैं। 2013 में, स्व भूमि केन्द्र भी इस केन्द्र में संचालित किया गया था। इस प्रकार केन्द्र पर बार-बार आने वाली महिलाओं को यह अवसर भी मिला कि उनके भू अधिकारों के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।

मंजुलाबेन को अपनी भूमि वापस मिली

“मुझे पता है कि मेरे नाम पर जो भूमि है वह उत्पादक नहीं है, लेकिन बिना संघर्ष वह भूमि मुझे क्यों नहीं मिलती?” विधवा मंजुलाबेन ने पूछा जो छह बच्चों की माँ हैं। उनके पति की चार साल पहले मृत्यु हो गई थी और वे काफ़ी कठिनाई से घर और खेती का प्रबन्धन करती हैं। उनकी दो बड़ी बेटियाँ अहमदाबाद चली गईं और निर्माण स्थलों पर आकस्मिक दिहाड़ी

मज़दूर के रूप में काम करने लगीं। उनकी आय की बदौलत ही परिवार को वर्तमान संकट से निपटने में मदद मिल रही है। इस साल सूखे के कारण भूमि के उस टुकड़े पर कुछ पैदावार नहीं हुई जिसे उसने अन्ततः अपने नाम पर दर्ज कराया था।

मंजुलाबेन को इस भूमि के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसके सामने इधर कुआँ उधर खाई जैसी स्थिति थी : एक तरफ़, वह एक अनपढ़ महिला थी; और दूसरी तरफ़, सामाजिक रुढ़ि ने पति के निधन के तुरन्त बाद उसके घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। परिवार भूमि के उस टुकड़े पर खेती करने लगा, जो भू अभिलेखों में उसके पति के नाम दर्ज था, लेकिन उसका नाम भू अभिलेखों में नहीं था। भू विरासत पर अभियान वर्साई जुंबेश (जुंबेश का अर्थ है अभियान) के दौरान, सारथी के क़ानून सहायक कार्मिकों ने मंजुलाबेन से मुलाक़ात की और उसके बाद उनके संघर्ष में मदद की।

मंजुलाबेन के पास भू अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं थे। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र गुम हो गया था। शपथ पत्र बनवाने के लिए उसके जीजा आगे नहीं आ रहे थे। दोनों क़ानून सहायक कार्मिकों ने आवश्यक काग़ज़ी कार्यवाही पूरी कराने के लिए कड़ी मेहनत की। लगभग तीन महीने तक इधर-उधर भागने के बाद, गाँव के भू राजस्व अधिकारी ने आख़िरकार उसका नाम उसकी बेटियों के नाम के साथ विरासत विलेख में दर्ज किया।

अधिकांश किसानों की भूमि ऊबड़-खाबड़ जगहों एवं निर्जन इलाक़ों में स्थित है, और इसलिए कृषि कार्य हमेशा उनके लिए एक कठिन समस्या रहा है। इसके अलावा, संतरामपुर के गाँवों में अधिकांश किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं है और कृषि औज़ारों की भी कमी है। वे अपनी कड़ी मेहनत के ज़रिए बुवाई के लिए भूमि तैयार करते हैं। मंजुलाबेन के मामले में, उन्हें अपनी दो वयस्क बेटियों का भी सहयोग प्राप्त था। परिवार दूसरों की ज़मीन पर भी काम करता है, ताकि बदले में अपनी भूमि की जुताई के लिए उन्हें दूसरे किसानों से आवश्यक सहयोग मिल सके। इस साल, बारिश कम हुई थी और इसलिए परिवार की कड़ी मेहनत और निवेश से कोई लाभ नहीं मिला। अधिकांश किसान एक जैसी स्थिति का सामना करते हैं, हालाँकि कुछ थोड़ी बेहतर स्थिति में होते हैं क्योंकि उनकी जल स्रोतों तक कुछ पहुँच होती है और उनके पास भूमि की सिंचाई के लिए आवश्यक यंत्र भी होते हैं।

स्व भूमि केन्द्र की रूपरेखा के अनुसार, सारथी ने अपने स्वयं के ग्रामीण महिला समूह से दो ग्रामीण महिला सदस्यों को नियुक्त किया जिन्होंने प्रयासों की अगुवाई करने के लिए WGWLO से नियमित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। महिला क़ानून सहायक कार्मिक, जो भू अभिलेखों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान से लैस हैं और क़ानूनी शब्दावली से अच्छी तरह से वाक़िफ़ हैं, गाँवों से अपने पुरुष समकक्षों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त रूप से

आश्वस्त और सक्षम थीं। पाँच गाँवों में सारथी का अभियान, महिलाओं को उनके केन्द्र पर आने का निमंत्रण, और ग्राम स्तर पर संवाद के आयोजन से महिलाओं को विरासत में भूमि प्राप्त करने के अपने अधिकारों की माँग करने में मदद मिली। इस मुद्दे के साथ-साथ भूमि के विभाजन, उत्पादक संसाधनों तक पहुँच, और स्थाई खेती और किसानों पर अभियान चलाए गए।

यह सब सारथी और उसके दो अग्रणी क़ानून सहायक कार्मिकों के लिए कोई आसान काम नहीं रहा है। उन्हें हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा:

i. पितृसत्तात्मक व्यवस्था: उनसे उनके इरादों के बारे में सवाल पूछे गए, खासकर स्थानीय नेताओं द्वारा। महिलाओं द्वारा भूस्वामित्व विवाद का एक बड़ा विषय है, और कई पुरुष नेताओं ने विनम्रतापूर्वक सारथी के क़ानून सहायक कार्मिकों को ऐसे मामलों में दखल न देने के लिए कहा। यह ख़ैर इस बात का सबूत था कि हमारी यह समझ सही नहीं है कि आदिवासी समाज समतावादी होता है।

ii. सामाजिक मुद्दे: विस्तारित परिवार के सदस्य अक्सर विधवाओं पर चुड़ैल होने का कलंक लगाते हैं तथा इस तरह उन्हें अपने घरों और गाँवों से बाहर कर देते हैं, और उसके बाद विधवा की भूमि पर अपना दावा करते हैं। हालाँकि, यह आशा की जाती है कि अब इन महिलाओं के नाम पर भूमि होने के कारण, उनके ख़िलाफ़ अत्याचार कम हो जाएँगे और शायद समय के साथ ख़त्म हो जाएँगे। कमज़ोर आर्थिक स्थिति कई विधवा महिलाओं के लिए एक बड़ी बाधा भी थी, जिनके पास आजीविका हासिल करने का लगभग कोई साधन नहीं था और जिन पर बड़े परिवारों का भरण पोषण करने की ज़िम्मेदारी का बोझ था।

iii. प्रक्रियात्मक कठिनाइयाँ: प्रक्रियाएँ सरल नहीं थीं, और कई स्तरों पर अवरोध थे। ज़्यादातर मामलों में पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों, और यहाँ तक कि ग्राम स्तर के नेताओं ने अक्सर हलफ़नामों के गवाह के रूप में सेवा प्रदान करने से इंकार कर दिया। भू अभिलेख अधिकारी भी मददगार नहीं थे, क्योंकि क़ानून सहायक कार्मिकों का नियमों का ज्ञान उन्हें किसी भी तरह की “अतिरिक्त आय” वसूलने से रोकता था जो वे पहले वसूल करते थे। महिलाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज़ दाख़िल करने की लागत वहन करना और भी मुश्किल था।

iv. भौगोलिक बाधाएँ: क़ानून सहायक कार्मिकों को महिला किसानों के घरों पर कई बार जाना पड़ता था, जो आमतौर पर बहुत दूर होते थे। इन घरों तक पहुँचना आसान नहीं था। पहुँच मुश्किल थी क्योंकि स्थिति यह थी कि एकल व्यक्तिगत परिवार भी पहाड़ी इलाक़ों में फैले हुए हैं, जैसा कि संतरामपुर के अधिकांश आदिवासी गाँवों में पाया जाता है। जब क़ानून सहायक कार्मिकों ने घरों के दौरे किए, तब अक्सर महिलाएँ घर पर नहीं थीं और इसके परिणामस्वरूप और देरी हुई।

इन कठिनाइयों के बावजूद, केन्द्र का एक प्रभावशाली कीर्तिमान है। सरकार के साथ 2015 में सिर्फ़ एक अभियान में, सारथी की दो क़ानून सहायक कार्मिकों ने 170 विवाहित बेटियों और 14 अविवाहित बेटियों के साथ 98 विधवा महिलाओं के मामले भू अभिलेखों में दर्ज कराने में सफलता हासिल की। इसके अलावा, शिविरों के आयोजन और गाँवों में स्व भूमि केन्द्र की उपस्थिति ने 155 महिलाओं सहित 86 परिवारों के नाम भूस्वामियों के रूप में दर्ज कराने में मदद की। पिछले डेढ़ साल में, सारथी ने 59 महिलाओं : 23 विधवाओं, 30 बेटियों, और छह महिलाओं को अपने पतियों के साथ संयुक्त नाम से भूस्वामित्व सुनिश्चित किया है। अब तक, इसने 500 से अधिक महिलाओं को भूस्वामित्व सुनिश्चित किया है।



नवजीवन आदिवासी महिला मंच, ब्लॉक सागबारा, ज़िला नर्मदा

गुजरात में नर्मदा ज़िले के सागबारा ब्लॉक में स्थित नवजीवन महिला महासंघ महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों में हमेशा सबसे आगे रहा है। यह आगा ख़ान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम (Aga Khan Rural Support Programme—AKRSP) के प्रयासों से महिलाओं के साथ और महिलाओं के द्वारा विकास के एजेंडा (agenda) को मुख्य धारा में लाने के लिए उभरा। इस महासंघ को बढ़ावा देने के प्रयास 1999 में शुरू हुए। आज, 18 वर्षों बाद, महिलाओं का महासंघ एक ऐसा बल है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वे न केवल महिलाओं के भूस्वामित्व के अधिकार के मामले में शामिल हैं, बल्कि उन्होंने महिलाओं को उनके अपने खुद के सांस्कृतिक सन्दर्भ के दायरे के भीतर न्याय सुनिश्चित करने के लिए आन्दोलन का नेतृत्व भी किया है।

महासंघ ब्लॉक के 97 में से 55 गाँवों में संचालित है। यह 2004 से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (Societies Registration Act), 1960 के अधीन एक पंजीकृत संगठन है। महासंघ स्वयं महिला सदस्यों द्वारा शासित है, और अपने सदस्यों की बचत और साख निर्मित करने में इसने एक बड़ी भूमिका निभाई है, जैसा कि अधिकांश स्वयं सहायता समूह महासंघ करते हैं। इसके अलावा, इसने आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम की तरफ से बायोगैस और फलोद्यान लगाने की दो बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाकर क्रियान्वित की है।

यह प्रयास अत्यधिक सफल रहे। दो वर्षों में, महासंघ ने 300 से अधिक बायोगैस संयंत्र लगाने का कार्य पूर्ण किया किया और 250 परिवारों को गाँवों में फलोद्यान लगाने में मदद की। महासंघ के सदस्यों द्वारा गुजरात के मांडवी में कच्छ महिला विकास संगठन (Kutch Mahila Vikas Sangathan—KMVS) का एक भ्रमण, बायोगैस संयंत्र और फलोद्यान के क्षेत्र से परे जाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पदाधिकारियों ने महसूस किया कि महिलाओं के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उनका पहला क़दम सरकार से अनुरोध करना था कि वह उन गाँवों में से एक में सड़क के बुनियादी ढाँचे में सुधार करे जहाँ यह संचालित था। इसने एक संगठन के रूप में महासंघ के लिए दृश्यता हासिल करने में मदद की जो बचत और साख से परे भी काम करा सकता था।

शर्मिलाबेन द्वारा अपने अधिकारों का दावा करना

38 वर्षीया शर्मिलाबेन गुजरात के नर्मदा ज़िले के बकटुरा नामक एक छोटे-से आदिवासी गाँव की निवासी है। वह अपने माता-पिता की इकलौती सन्तान है। उसके परिवार के पास 2.5 एकड़ की एक छोटी भूमि है जिसमें वह शुष्कभूमि कृषि करता है। शर्मिलाबेन ने बचपन से ही खेती करने में अपने माता-पिता की मदद की। शादी होने जाने के बाद, वह अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहने के लिए दूसरे गाँव चली गई। लेकिन चूँकि खेती में उसके माता-पिता की मदद करने के लिए कोई और नहीं था, इसलिए उसने शादी के बाद भी खेती करने में उनकी मदद करना जारी रखा।

शर्मिलाबेन के पिता की 2009 में मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब बिलकुल अकेली पड़ गई और उनका स्वास्थ्य ख़राब हो रहा था। इसलिए शर्मिलाबेन ने अपने माता-पिता के गाँव लौटने का फैसला किया और अपनी माँ के साथ रहने लगी। बाद में, उसका पति भी अपनी पत्नी और सास का साथ देने के लिए इस गाँव में आ गया।

शर्मिलाबेन ने पारिवारिक भूमि पर खेती जारी रखी। लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई। उसके चाचा और चचेरे भाई चाहते थे कि भूमि के स्वामित्व का अधिकार उन्हें हस्तान्तरित किया जाए। शर्मिलाबेन ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भूमि उसके परिवार की थी, और यह कि वह इन सभी वर्षों के दौरान उस पर खेती कर रही थी। इससे शर्मिलाबेन और उसके

चाचाओं के बीच विवाद पैदा हो गया। दुर्भाग्य से, शर्मिलाबेन के पास अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए कोई क़ानूनी दस्तावेज़ नहीं था। 2010 में, शर्मिलाबेन ने अपने परिवार की भूमि के क़ानूनी स्वामित्व का दावा करने के लिए सम्बन्धित विभागों को एक आवेदन प्रस्तुत किया। कुछ दस्तावेज़ों पर उसके चाचाओं के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। उन्होंने साफ़ इंकार कर दिया। समय बीत गया। शर्मिलाबेन के चाचा और चचेरे भाई उन्हें भूमि देने के लिए उस पर दबाव डालते रहे।

2017 में, नवजीवन आदिवासी महिला मंच (Navjeevan Adivasi Mahila Manch—NAMM) द्वारा समर्थित स्व भूमि केन्द्र ने गाँव में भूस्वामित्व के बारे में जागरूकता निर्मित करने के लिए एक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान शर्मिलाबेन को केन्द्र और इसके काम के बारे में पता चला। उसने मदद के लिए केन्द्र से सम्पर्क किया। स्व भूमि केन्द्र की क़ानून सहायक कार्मिकों की टीम ने उसे उनके मार्गदर्शन में फिर से अपना आवेदन जमा करने की सलाह दी। उन्होंने उन दस्तावेज़ों को तैयार करने में भी उसकी मदद की जो उसके पहले वाले आवेदन में मौजूद नहीं थे। शर्मिलाबेन के चाचा दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से इंकार करते रहे। गाँव के नेताओं ने उसके चाचाओं का पक्ष लिया। लेकिन क़ानून सहायक कार्मिकों ने शर्मिलाबेन, उनके चाचाओं, और ग्राम समुदाय के बीच संवाद सुगम बनाने में मदद की।

उनके प्रयासों से आखिरकार लाभ हुआ। शर्मिलाबेन को उनके नाम पर भूमि का हक़ मिला। अब जब शर्मिलाबेन को मालिकाना हक़ मिल गया है, तो उसकी योजना विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की है, ताकि वह अपनी कृषि पद्धतियों में सुधार कर सके और उत्पादकता बढ़ा सके।

एक और बड़ा क़दम, जो ज़िला विकास अधिकारी (District Development Officer—DDO) की मदद से सम्भव हुआ था, शॉपिंग प्लेस (shopping place) का निर्माण था जहाँ महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य इकट्ठे होकर अपनी उपज का व्यापार कर सकें और अपने कौशलों का विनिमय कर सकें। यह सम्पत्ति महासंघ के हाथों में है, हालाँकि इस सम्पत्ति पर न्यायोचित दावे से महिला सदस्यों को बेदखल करने के कई प्रयास किए गए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, महासंघ को कई स्रोतों से पर्याप्त समर्थन मिला है। एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank—ADB) के एक अनुदान ने कृषि उपकरण किट उद्यम को प्रायोजित किया। ट्रैक्टर, जो अनुदान का एक हिस्सा था, का प्रबन्धन समूह द्वारा किया जाना था, और यह सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका थी कि ब्लॉक में ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों को योजना के तहत निर्धारित दर पर ट्रैक्टर की सेवाएँ मिलें। ट्रैक्टर सुविधा आरम्भ हुए लगभग एक दशक हो चुका है।

2014 में, ब्लॉकों के विकास के लिए गुजरात सरकार की विकाशिल तालुका योजना (Vikashil Taluka Scheme—VTS) के तहत, महासंघ को चार और ट्रैक्टरों को संचालित करने के लिए सहयोग मिला।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development—NABARD) के एक और बड़े अनुदान का उपयोग अधिक बचत और साख समूह स्थापित करने के लिए किया गया। इन सभी प्रयासों ने न केवल इसके सदस्यों के बीच महासंघ की स्थिति को मज़बूत किया, बल्कि एक ऐसी संस्था के रूप में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने में भी मदद की, जो सरकारी योजनाओं के हितलाभ पहुँचाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने में सक्षम थी।

2013 में, WGWLO ने नवजीवन आदिवासी महिला मंच से सागबारा में एक स्व भूमि केन्द्र शुरू करने के लिए सम्पर्क किया। WGWLO के दो पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे उन्हें भू अभिलेख प्रणालियों और विरासत से सम्बन्धित क़ानूनों की आवश्यक समझ के साथ-साथ व्यापक सरकारी ढाँचे और भूमि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिकारों का दावा करने के बारे में जानकारी मिली।

महासंघ ने, स्व भूमि केन्द्र के सहयोग से, अपने गाँवों की महिलाओं को उनके भूमि की विरासत के अधिकार के दावे करने में सहायता करने का निर्णय लिया। महासंघ के प्रयासों से न केवल महिलाओं को, बल्कि गाँवों में पुरुषों को भी लाभ हुआ। सागबारा में स्व भूमि केन्द्र स्थापित करने के पाँच साल के भीतर, महासंघ ब्लॉक में 357 परिवारों तक पहुँच गया है। 2015 में, केवल एक ब्लॉक में, जब गुजरात सरकार ने विरासत की प्रविष्टियों के लिए एक अभियान चलाया, तो महासंघ ने सुनिश्चित किया कि कोई भी महिला छूट न जाए, जो कि आमतौर पर होता था। केवल 15 दिनों की अवधि में, उन्होंने सरकार द्वारा ब्लॉक में की गई कुल 730 विरासत प्रविष्टियों में महिलाओं की 217 विरासत प्रविष्टियाँ सुनिश्चित कीं। परिवारों के सदस्यों की इन विरासत प्रविष्टियों ने बेटियों और विधवाओं को भूमि पर एक न्यायोचित अधिकार प्रदान किया है, जो कि सागबारा जैसी एक ग्रामीण व्यवस्था में सबसे मूल्यवान सम्पत्ति है जो आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पिछले डेढ़ साल में, अपने अभियानों और ग्राम पंचायतों के साथ काम करने के परिणामस्वरूप, महासंघ ने 73 विधवाओं, 47 बेटियों, और पति के साथ पत्नी के संयुक्त स्वामित्व के 20 मामलों सहित 140 महिलाओं को भूस्वामित्व सुनिश्चित किया है।

नवजीवन महासंघ के स्व भूमि केन्द्र ने बाद में इस अभियान को उन सभी गाँवों तक पहुँचाया जहाँ वह सक्रिय था। इसने एक योजना तैयार की और ग्रामीण स्तर पर राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया। यह कार्य तलाठी (Talati—ग्राम राजस्व अधिकारी), गाँव के

निर्वाचित नेताओं, और इन गाँवों में महिलाओं के समूहों के साथ परामर्श करते हुए किया गया था। गाँवों में मौतों के अभिलेख प्राप्त किए गए और विरासत के लम्बित मामलों की पहचान करने के लिए राजस्व और भू अभिलेखों के साथ प्रति-सत्यापित किया गया। प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और आवश्यक कागज़ी कार्यवाही के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देने के लिए ग्राम राजस्व अधिकारियों के साथ इन गाँवों में बैठकें आयोजित की गईं। महासंघ ने अपनी सभी महिला सदस्यों के साथ-साथ सहायता माँगने वाले पुरुषों को भी सहायता प्रदान की। क़ानूनी पेशेवरों की सहायता से मोलभाव के बाद तय की गई दरों पर राजस्व अधिकारियों की सहायता से ग़ैर-न्यायिक मुद्रांकित पत्रों पर शपथ पत्र तैयार किए गए। इसने एक प्रक्रिया को आसान बना दिया जिसे राजस्व अधिकारियों द्वारा अकसर जटिल बना दिया जाता है। परिणामस्वरूप, सागबारा ब्लॉक में की गई 730 वारसाई (विरासत प्रविष्टियों) में, फेडरेशन के प्रयासों ने 217 वारसाई पूरी करने में मदद की। इसके अलावा, नवजीवन महासंघ द्वारा वारसाई के 120 और मामले उठाए गए। यह अब महिलाओं के लिए अलग भूमि सर्वेक्षण संख्या प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है, क्योंकि कई सरकारी योजनाएँ “प्रति सर्वेक्षण संख्या केवल एक” के टैग (tag) के साथ आती हैं। यह एक कठिन काम है क्योंकि इसमें सह-स्वामियों की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन महासंघ को सफलता का भरोसा है। अन्त में, महासंघ ने कई सदस्यों को विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कागज़ी कार्यवाही का भी ध्यान रखा है।

बावला महिला विकास संगठन (BMVS), बावला, अहमदाबाद

WGWLO द्वारा प्रशिक्षित स्व भूमि केन्द्र कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद ज़िले के बावला ब्लॉक में केसरड़ी गाँव में स्थाई कृषि प्रथाओं पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम ने टिकाऊ कृषि के महत्त्व और उस चक्र पर प्रकाश डाला जो इसके लिए आवश्यक है, साथ ही सघन धान प्रणाली (System of Rice Intensification—SRI) पर भी प्रकाश डाला। सघन धान प्रणाली को मेडागास्कर विधि के नाम से भी जाना जाता है।

प्रशिक्षण से बावला महिला विकास संगठन (Bavla Mahila Vikas Sangathan—BMVS) की एक अग्रणी नेता सविताबेन को अन्य स्थाई कृषि पद्धतियों के उपयोग के साथ सघन धान प्रणाली अपनाने की भी प्रेरणा मिली। हालाँकि, उनके पति ने यह कहते हुए इंकार कर दिया, “तुमको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होगा।” फिर भी, सविताबेन ने सघन धान प्रणाली अपनाने के लिए आगे बढ़ने पर ज़ोर दिया और अपनी ज़मीन के एक हिस्से पर इस पद्धति को आजमाने में सफल रहीं। फिर सविताबेन और उनके पति दोनों ने उन प्रथाओं को सीखा जिनका पालन करना आवश्यक था, और एक बीघा में सघन धान प्रणाली का उपयोग करके धान की रोपाई की और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। इससे उन्हें अत्यधिक प्रेरणा मिली। अगले वर्ष, पति-पत्नी दोनों ने कपास के लिए स्थाई कृषि



स्व भूमि केन्द्र, बावला महिला विकास संगठन की क़ानून सहायक कार्मिक (PLWs) भूस्वामित्व पर एक महिला किसान के दस्तावेज़ तैयार करती हुई (ज़िला अहमदाबाद के ब्लॉक राजस्व परिसर, बावला में)

पद्धतियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। कमज़ोर मानसून के बावजूद, जब अन्य संकर बीजों और रसायन-आधारित कृषि से बहुत कम उत्पादन हुआ, तो उन्हें अपनी कपास की फ़सल के अच्छे परिणाम मिले।

बावला महिला विकास संगठन द्वारा चलाए जा रहे स्व भूमि केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रदर्शनों से 80 से अधिक ऐसी महिला किसानों को प्रेरित किया गया है।

अहमदाबाद से थोड़ी ही दूर ग्राम स्तरीय स्वयं सहायता समूहों, बावला महिला विकास संगठन का संघीय निकाय अहमदाबाद ज़िले के बावला तालुका में 25 गाँवों की 1,500 से अधिक महिलाओं के साथ काम करता है। यह संगठन 1997 में शुरू हुई एक पहल के अंश के रूप में अस्तित्व में आया जब एक ग़ैर-सरकारी संगठन, कर्म संघ (Karma Sangh) ने इन गाँवों की महिलाओं के साथ काम किया और उन्हें क़ानूनी साक्षरता प्रदान की। जो महिलाएँ उस वक़्त क़ानूनी साक्षरता प्राप्त करने वाली पहली महिलाएँ थीं, वे आज बावला महिला विकास संगठन के लिए काम कर रही हैं और इस संघीय निकाय की पदाधिकारी भी हैं। सम्पूर्ण बचत कोष का प्रबन्धन करने के लिए, जो 2018 में 4 मिलियन रुपए था, अभिकरण को एक अलग ट्रस्ट और सोसायटी के रूप में पंजीकृत कराया गया। इसके अलावा, अभिकरण शुरुआत से ही महिलाओं के मुद्दों पर काम करता आ रहा है। 4 मिलियन रुपयों की निधि का

उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए सदस्यों को पैसा उधार देने के लिए किया जाता है। फंड से प्राप्त ब्याज से होने वाली आय का उपयोग महासंघ (BMVS) के अन्य उद्देश्यों और गतिविधियों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

महासंघ बचत और साख सम्बन्धी गतिविधियाँ संचालित करता है। यह बावला में एक परामर्श केन्द्र भी संचालित करता है जहाँ घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की उनके मामलों के समाधान में सहायता की जाती है।

2002 में WGWLO की स्थापना के बाद से ही बावला महिला विकास संगठन उसका सदस्य रहा है। 2013 में, जब WGWLO ने स्व भूमि केन्द्रों की शुरुआत की, तो संगठन ने केन्द्रों को संचालित करने की इच्छा व्यक्त की। यह क्षेत्र, अहमदाबाद के करीब होने के कारण, 2002 से तेज़ी से उद्योगीकरण का साक्षी रहा है और वहाँ भूमि एक कीमती संसाधन बन गई है। समृद्ध खनिज निक्षेप वाली भूमि उपजाऊ भी है। सिंचाई नहरों की एक भली भाँति विकसित प्रणाली की बदौलत, और इस नहर प्रणाली का फतेहवाड़ी बैराज (साबरमती वासना बैराज) के साथ कनेक्शन होने के कारण, जो गाँवों तक पहुँचता है, अच्छी पैदावार के साथ भूमि हर साल कम-से-कम दो फ़सलों का उत्पादन करती है। खरीफ़ के मौसम में धान और रबी के मौसम में गेहूँ की खेती की जाती है। इस प्रकार, यहाँ तक कि एक बीघा भूमि (पाँच बीघा यानी एक हेक्टेयर) एक मूल्यवान संसाधन है क्योंकि यह एक परिवार की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि गाँव औद्योगिक क्षेत्रों के करीब स्थित हैं, स्थानीय उद्योग युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, कृषि कार्य अब अधिकांश परिवारों में महिलाओं की ज़िम्मेदारी बन गया है। वैसे ही, जैसे भूमि के साथ महिलाओं का सम्बन्ध पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है। अधिकांश पुरुषों के लिए, ज़मीन एक व्यापार योग्य पारम्परिक वस्तु है, क्योंकि ज़मीन की कीमतों में उनकी कल्पना से परे वृद्धि हुई है।

पिछले पाँच वर्षों में, बावला महिला विकास संगठन ने महिलाओं और पुरुषों दोनों को आधिकारिक भू अभिलेखों में उनके विरासत के अधिकार दर्ज कराने में सहायता प्रदान की है। अधिकांश मामलों में, यह आसान नहीं रहा है। बावला महिला विकास संगठन के अनुसार, स्थानीय ग्राम स्तरीय राजस्व अधिकारी वह नहीं करते हैं जो उनसे अपेक्षित है। कुछ मामलों में अभिलेख अद्यतन नहीं किए गए हैं, और कुछ मामलों में उन्हें दो पीढ़ियों तक अद्यतन नहीं किया गया है। कई परिवारों द्वारा परिवार के सदस्यों की मृत्यु दर्ज नहीं कराई गई है। आवश्यक कागज़ी कार्यवाही पूरी करने के लिए क़ानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी के साथ-साथ इधर-उधर भागदौड़ और, कुछ मामलों में काफ़ी खर्च करने की आवश्यकता होती है। क़ानूनी ठग (legal sharks) हर किसी को धोखा देते हैं और जानबूझकर मामलों को इतना उलझा देते हैं कि जो लोग अभिलेख में अपने नाम शामिल कराना चाहते हैं उन्हें यह समय और धन की बर्बादी प्रतीत होती है। कई लोग अभिलेखों में अपने नाम दर्ज कराने के लाभ के बजाय परिवार

के किन्हीं अन्य सदस्यों के नाम पर दर्ज भूमि जोतना जारी रखते हैं। यह व्यवस्था पुरुष-प्रधान परिवारों में स्वीकार्य हो सकती है, क्योंकि परिवारों के सदस्यों (विस्तारित सम्बन्ध) के बीच यह समझ रहती है कि भूमि पर परिवार के सदस्य के स्वामित्व के अधिकार की निरन्तरता क़ायम रखने को मान्यता दी जाए। हालाँकि, भूमि के क़ानूनी स्वामित्व के बारे में इस तरह की स्पष्टता की कमी का परिणाम अकसर सम्पत्ति से महिलाओं, विशेषकर बेटियों और विधवाओं, की बेदखली होता है। चूँकि महिलाएँ कम शिक्षित हैं, उन्हें क़ानूनी मामलों के बारे में कम जानकारी है, और वे क़ानूनी शब्दावली से अच्छी तरह वाक़िफ़ नहीं हैं, अतः उनके लिए सम्पत्ति के दावे करना और साबित करना बहुत मुश्किल है।

बावला महिला विकास संगठन प्रशासन को ब्लॉक राजस्व कार्यालय के परिसर में उन्हें एक स्थान प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए मनाने में कामयाब रहा। बावला महिला विकास संगठन के क़ानून सहायक कार्मिकों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि अब वे समुदाय में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जैसे ही बावला महिला विकास संगठन की महिला सदस्य, सरकारी कार्यालय में एक मेज़ और कुर्सी लगाकर सप्ताह में दो बार बैठने, और क़ानूनी प्रक्रियाओं के बारे में आवश्यक जानकारी रखने लगीं, ब्लॉक राजस्व कार्यालय आने वाली महिलाएँ उनसे सम्पर्क करने लगी थीं। क़ानून सहायक कार्मिकों ने उनसे सम्पर्क करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सहायता प्रदान की, लेकिन इस शर्त पर कि किसी भी भूमि मामले में महिला का दावा भी होना चाहिए। संयोगवश क़ानून सहायक कार्मिकों की जानकारी में ऐसे मामले भी आए जिनमें महिलाओं को उनके न्यायोचित दावों से वंचित करने के लिए अतीत में भू अभिलेखों में जाली प्रविष्टियाँ की गई थीं; धोखे से भूमि बिक्री के मामले थे; और ऐसे मामले भी आए जहाँ पीढ़ियों से भू अभिलेख अद्यतन नहीं किए गए थे। चीज़ों को ठीक करने के लिए धैर्य, चातुर्य, और प्रशासन के साथ काम करने की इच्छा और क्षमता की आवश्यकता थी।

प्रशासन, विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारी, क़ानून सहायक कार्मिकों की पहल के समर्थक थे। उन्होंने कनिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर सहयोग करने और बिना विलम्ब किए काम पूरा करने का कहकर मामलों को हल किया। बावला महिला विकास संगठन कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को निःशुल्क सहायता प्रदान की। स्थानीय क़ानूनी ठगों ने काग़ज़ी कार्यवाही करने के लिए बहुत अधिक शुल्क लिया, जिसकी राशि सैकड़ों और यहाँ तक कि हज़ारों रुपए थी। यह काग़ज़ी कार्यवाही अब बहुत सस्ती दरों (क़ानूनी दरों के अनुसार) पर की गई। जैसे ही स्व भूमि केन्द्र के काम की चर्चा ब्लॉक राजस्व अधिकारी के परिसर (जहाँ यह स्थित था) से बाहर फैली, वकीलों और अन्य एजेंटों ने मामले क़ानून सहायक कार्मिकों को स्थानान्तरित कर दिए। क़ानूनी विशेषज्ञों ने भी विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में क़ानून सहायक कार्मिकों से परामर्श किया, क्योंकि यह क़ानून सहायक कार्मिक न केवल भूमि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित थे, बल्कि विभिन्न समस्याओं को घटाने में भी अनुभवी थे, और इसलिए ऐसे मामलों में बहुत अधिक जानकार थे। दोनों क़ानून सहायक कार्मिकों के लिए यह एक गर्व की बात

थी। उनमें से एक, सुमित्राबेन ने खुद की समस्याओं का अनुभव किया था, और भूमि के लिए सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। वह सभी क़ानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी से लैस हैं, और अब अन्य महिलाओं की तरफ़ से उसी तरह से लड़ती हैं। उन्हें संगठन का समर्थन प्राप्त है, जिसकी इलाक़े में अच्छी ख़ासी प्रतिष्ठा है।

महिला किसानों के लिए भूस्वामित्व सुगम बनाने से लेकर भूमि की उत्पादकता बढ़ाने तक

महिलाओं को भूमि प्राप्त करने में मदद करना और फिर उसे उनके नाम पर पंजीकृत कराना आजीविका सम्बन्धी चुनौती का एक पक्ष है। महिला भूस्वामियों की आजीविका तब संभलती है जब उनके संसाधनों में अन्य पूँजीगत संसाधन जोड़े जाते हैं। सामूहिक नेटवर्क WGFWO द्वारा प्रशिक्षित स्व भूमि केन्द्रों के क़ानून सहायक कार्मिकों ने आजीविका सम्बन्धी चुनौती के इस पक्ष को भी सम्बोधित करने में सहायनीय कार्य किया है।

संस्थागत सुविधाओं, यानी, राज्य सरकार की कृषि योजनाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए विभिन्न औपचारिकताएँ पूर्ण करना आवश्यक है। जानकारी तक अनुचित पहुँच और आधिकारिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी की कमी के कारण यह एक मुश्किल काम हो जाता है। इन बाधाओं के बावजूद, क़ानून सहायक कार्मिकों ने पिछले पाँच वर्षों में उन 214 महिला किसानों के नाम I-Khedut पोर्टल के तहत किसानों के रूप में पंजीकृत कराने में मदद की है, जिनके पास स्वयं के नाम के भू अभिलेख थे। यह पंजीकरण किसानों को पंजीकरण संख्या प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो आगे सभी सरकारी सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन के लिए सन्दर्भ बन जाते हैं।

सारथी द्वारा शुरू किए गए स्व भूमि केन्द्र ने भी महिला किसानों के लिए अपने सम्पर्कों का विस्तार किया है ताकि वे सरकारी कृषि योजनाओं के तहत अपने अधिकारों का लाभ ले सकें। I-Khedut पोर्टल के तहत पंजीकरण ने मंजुलाबेन के परिवार जैसे परिवारों को एक ताड़पत्री, एक प्लास्टिक जैसी चादर जो कई मायनों में परिवार की मदद करती है, तक पहुँचने में मदद की है। यह बहुत महँगा नहीं है, लेकिन महिला किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें श्रेष्ठिग के बाद भूमि पर गिरा हुआ अनाज उठाने की मेहनत से बचाती है।

इसी तरह, स्व भूमि केन्द्र ने संतरामपुर में 124 महिला भूस्वामियों की मदद की है। इसने पिछले पाँच वर्षों के दौरान 120 से अधिक विधवा महिलाओं के नाम भू अभिलेखों में शामिल करने और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सम्भव बनाने में मदद की है जो अपने संसाधन बढ़ाने में महिला किसानों की मदद करती हैं और स्थाई आजीविका के लिए भूमि का समुचित उपयोग करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करती हैं।

इसके अलावा, सारथी ने अन्य 217 परिवारों की बेटियों की उनके नाम सूचीबद्ध कराने में मदद की है और इस तरह परिवार की सम्पत्ति पर उनके न्यायोचित दावों पर लगातार नज़र रखी जाती है।

चुनौतियाँ कई हैं, खासकर जब स्व भूमि केन्द्र महिला किसानों के साथ काम करता है : इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकारी योजनाओं के तहत आवेदन करने से योजनाओं तक पहुँच या उनके लाभ या उनकी पात्रता मिल ही जाएगी। सरकारी विभागों द्वारा जारी की जाने वाली आवेदकों की अन्तिम सूची में प्रत्येक आवेदक को सम्बन्धित वस्तु की खरीद का विवरण प्रस्तुत करना होता है। उन्हें पूरी राशि का भुगतान करके वस्तु खरीदनी होती है, जिसके बाद सरकार सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति करती है। एक महिला किसान जिसने 3 अश्व शक्ति (हॉर्सपावर) की एक मोटर खरीदने के लिए आवेदन किया था, वह भुगतान की पूरी राशि की व्यवस्था नहीं कर सकी और उसे लाभ से वंचित होना पड़ा। किसानों, विशेषकर महिला किसानों, के कई मामले हैं जो आवश्यक धन की पूरी राशि की व्यवस्था नहीं कर सके और इसलिए आधिकारिक समय सीमा से पहले सौदा पूरा करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लाभ प्राप्त करने से वंचित किया गया।

अन्त में, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती लाभार्थियों के खातों में राशि जमा करा पाने में होने वाली देरी से निपटने की रही है। देरी का अर्थ है कि लाभ लेने के उद्देश्य से उधार ली गई राशि पर महिला किसानों को ब्याज देना पड़ता है। इस तथ्य को देखते हुए कि इन महिलाओं की औपचारिक ऋण स्रोतों तक बहुत सीमित पहुँच है, यह देरी और इसके परिणाम उनकी स्थिति को बद से बदतर ही बनाते हैं।

पिछले चार वर्षों में, नवजीवन महासंघ, जो स्व भूमि केन्द्र संचालित करता है, ने सरकार द्वारा स्थापित I-Khedut पोर्टल के तहत 775 महिला किसानों का पंजीकरण कराने में मदद की है। पोर्टल के तहत एक किसान के रूप में पंजीकरण विभिन्न भूमि-आधारित सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है। पंजीकरण प्रक्रिया में व्यापक कागज़ी कार्यवाही की आवश्यकता होती है। यद्यपि पंजीकरण ऑनलाइन किया जाता है, पंचायत कार्यालय में, नवजीवन महासंघ द्वारा औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं। एक बार किसान के रूप में I-Khedut पोर्टल के तहत पंजीकृत होने के बाद, खेदुत पंजीकरण पत्रक (khedut registration patrak) जारी कर दिया जाता है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध लाभों तक पहुँचने के लिए प्राथमिक क़दम है। आवेदन जमा किए जाने के बाद भी, योजनाओं का लाभ पाने के लिए कई क़दम और प्रक्रियाएँ पूर्ण करना होती हैं, जिनके लिए महिला किसानों को व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होती है। पिछले पाँच वर्षों में, 1,274 महिला किसानों ने इन कृषि योजनाओं का लाभ लिया। स्व भूमि केन्द्र के संचालन के पहले वर्ष 2013-14 में, इस तरह की योजनाओं के तहत किए गए दावों से महासंघ की पाँच

महिला किसान सदस्यों को 149,000 रुपये की सहायता प्राप्त हुई। यह उस सम्पत्ति के मूल्यांकन की मात्रा दर्शाता है जिसके लिए महिला किसानों द्वारा स्व भूमि केन्द्र के सहयोग से दावा किया गया।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण (Agriculture Technology Management Agency-ATMA) परियोजना के माध्यम से भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण परियोजना के तहत, बीज किट प्राप्त कर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण समूहों के सदस्यों को प्रदान की जाती हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण समूहों के सदस्य ग्राम स्तरीय स्वयं सहायता समूहों के सदस्य भी हैं। उन्होंने इन किटों को बारी-बारी से लेने की प्रणाली विकसित की है। सदस्यों में परस्पर सम्मान, सामंजस्य, और एकता विकसित हुई है। फलस्वरूप, उनकी सामाजिक पूँजी मज़बूत हुई है। इसके अलावा, किसान प्रशिक्षण केन्द्र (Farmer Training Centre—FTC) और कृषि विज्ञान केन्द्र (Krishi Vigyan Kendra—KVK) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण समूह नियमित रूप से भाग लेते हैं। महासंघ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण परियोजना के तहत अपने सभी समूहों को शामिल करने का प्रयास कर रहा है।

पिछले चार वर्षों में, बावला महिला विकास संगठन ने कई महिलाओं की सरकारी योजनाओं तक पहुँच बनाने में मदद की है। 110 महिला किसानों की कुल सदस्यता वाले छह समूह कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण से सम्बद्ध हैं। यह महिला किसान कभी भी जानकारी साझा करने वाली संस्थाओं के सम्पर्क में नहीं आईं। उन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद अपने खेतों पर और अधिक प्रभावी ढंग से खेती करने के बारे में नई जानकारी और एक महत्वपूर्ण समझ हासिल की है। उनके नाम पर भू अभिलेख दर्ज होने से कुछ महिलाओं को सहकारी बैंकों से कृषि ऋण प्राप्त करने में मदद मिली है।

स्व भूमि केन्द्र ने I-Khedut पोर्टल पर 137 महिला किसानों के पंजीकरण कराने में मदद की है। अब तक, 64 महिला किसान सदस्यों ने भौतिक संसाधनों का लाभ प्राप्त किया है जिनमें तेल से चलने वाले इंजन, वाटर पम्प, भण्डारण पात्र, और ताड़पत्री शामिल हैं। इस पहुँच से महिला किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने और कृषि प्रथाओं में सुधार करने में बहुत मदद मिली है।

स्व भूमि केन्द्र के माध्यम से महिला किसानों की आजीविका को बढ़ावा देना : सीख

तीन स्थानों पर महिलाओं के ज़मीनी स्तर के तीन समूहों और संगठनों के प्रयासों से हमें इस बात के पर्याप्त सबूत प्राप्त होते हैं कि स्व भूमि केन्द्रों ने वास्तव में आजीविका के ढाँचे के कई पहलुओं पर काम किया है।

आजीविका ढाँचे के अनुसार, आजीविका वृद्धि तब अधिक प्रभावी होती है जब पूँजी—प्राकृतिक, वित्तीय, भौतिक, मानवीय, और संस्थागत—तक उन लोगों की पहुँच हो जिनकी आजीविका को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊपर वर्णित केस स्टडीज़ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि स्व भूमि केन्द्र द्वारा किए गए रणनीतिक प्रयासों से यह सम्भव हुआ है।

भौतिक सम्पत्तियों तक पहुँच

गुजरात सरकार द्वारा स्थापित I-Khedut पोर्टल के तहत किसानों, पुरुषों और महिलाओं दोनों, का पंजीकरण उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए स्व भूमि केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क आवेदन करने की योग्यता प्रदान करता है। इससे महिला किसानों को विभिन्न प्रकार की भौतिक सम्पत्तियों तक पहुँच प्राप्त करने में मदद मिली है, जिनमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, विद्युत इंजन, और डीजल इंजन शामिल हैं। नवजीवन आदिवासी महिला मंच के पास भी चार ट्रैक्टर हैं, जो अप्रैल, मई और जून के महीनों में बुवाई के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर महिला किसानों को प्रदान किए जाते हैं। 15 स्व भूमि केन्द्रों ने मिलकर 7,500 से अधिक महिला किसानों को भौतिक सम्पत्तियों तक पहुँचने में सक्षम बनाया है, जो कि आमतौर पर केवल पुरुष किसानों को उपलब्ध होती हैं।

महिला किसानों के कठिन परिश्रम को कम करने और महिला किसानों को भौतिक सम्पत्तियों तक सामूहिक पहुँच प्रदान करने के विचार के साथ तीनों स्थानों पर कृषि उपकरण बैंक (Agriculture Tool Bank—ATB) स्थापित किए गए, जिनका उनके पास सामान्य रूप से अभाव रहता है। इससे महिला किसानों को न केवल खेतों में काम करने में लगने वाले समय और ऊर्जा को कम करने में मदद मिली, बल्कि इन उपकरणों तक पहुँच प्राप्त करने में पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम करने में भी मदद मिली, खासकर जब उनके पति दूर हों या अन्यथा उपलब्ध नहीं हों। महासंघ ने सरकारी कार्यक्रम के तहत ये भौतिक सम्पत्तियाँ (अपनी मशीनरी के साथ ट्रैक्टर) प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के कोष से 7.8 लाख रुपए निवेश किए हैं। कृषि उपकरण बैंकों द्वारा 500 से अधिक किसानों को उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।



भौतिक सम्पत्तियों तक पहुँच में भी स्थानीय संसाधनों जैसे—नीम के पत्तों, गोबर, और जैव-कीटनाशक तैयार करने के लिए गोमूत्र, जैव-विकास संवर्धक, आदि तक पहुँच भी शामिल है। यह एक और मूल्यवर्धित सेवा है जो धन और बाज़ार पर, साथ ही पुरुषों पर महिला किसानों की निर्भरता कम करने में मदद करती है।

संस्थानों और नेटवर्क तक पहुँच

किसानों के सामने एक बड़ी समस्या ऐसे उपयुक्त संस्थानों का अभाव, और इन संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के बीच सम्बन्धों की कमी है, जो उनकी आजीविका को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सामान्य रूप से महिलाओं के लिए, और विशेष रूप से महिला किसानों के लिए, यह स्थिति कहीं अधिक गम्भीर है। उनकी सीमित गतिशीलता और अत्यधिक कार्यभार के कारण, वे बाहरी दुनिया से जुड़ नहीं पाती हैं। बहुत हद तक, स्व भूमि केन्द्रों के हस्तक्षेपों और महिला संगठनों के प्रयासों ने इस मुद्दे को सफलतापूर्वक हल करने में मदद की है।

WGWLO अपने-आप में एक नेटवर्क है, और इसलिए स्व भूमि केन्द्र के सभी क़ानून सहायक कार्मिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वे हर तिमाही में मिलते हैं। बैठकें न केवल जानकारीयों (inputs) के आदान-प्रदान के लिए बल्कि एक दूसरे से सीखने और साझा करने के लिए भी मंच हैं। इसने महिला किसानों और उनके अग्रणियों के बीच सम्बन्ध निर्मित किए हैं जो पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अब अग्रणी कम-से-कम 12 ज़िलों में महिला किसानों से जुड़े

हुए हैं। जब वे किन्हीं मुद्दों या समस्याओं का सामना करते हैं, तो वे सलाह और मार्गदर्शन लेने के लिए सीधे एक दूसरे को बुलाते हैं। इन सम्बन्धों के निर्मित होने से स्व भूमि केन्द्रों के सदस्यों का समग्र विश्वास बढ़ा है।

ब्लॉक की महिला किसान वर्ष में कम-से-कम दो बार स्व भूमि केन्द्र द्वारा आयोजित अभियानों और ज़िला स्तरीय सम्मेलनों में मिलती हैं। इस नेटवर्किंग ने उन्हें कई अच्छी महिला किसानों के साथ जुड़ने और एक दूसरे से सीखने और जानकारी का आदान-प्रदान करने में मदद की है।

ब्लॉक, ज़िला, और राज्य स्तर पर कृषि विभागों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, बैंकों, और राजस्व विभागों के साथ सम्पर्क ने महिलाओं और ग्रामीण स्तर के संस्थानों के सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाया है।

WGWLO ने राज्य के विभागों और एजेंसियों के साथ सम्बन्ध भी निर्मित किए हैं, जिसके माध्यम से स्व भूमि केन्द्र के क़ानून सहायक कार्मिक भी जुड़े हुए हैं। इसके कारण, ब्लॉक और ज़िला स्तरों पर उनके संस्थागत सम्पर्क मज़बूत हुए हैं। वे सीधे ज़िला कृषि अधिकारी, कलेक्टर, और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण के साथ भेंट और चर्चा करती हैं, जो साधारण महिला किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दरअसल, सभी तीन स्थानों पर, सरकारी अभिकरण अब महिला किसानों को कृषि मेलों, कृषि रथों, आदि में सीधे आमंत्रित करते हैं। स्व भूमि केन्द्रों ने कड़ी मेहनत करते हुए सरकारी संस्थानों के बीच महिला किसानों की यह पहचान बनाई है।

स्वदेशी बीजों को बढ़ावा देने और राज्य के उन क्षेत्रों से बीज प्राप्त करने, जहाँ उनकी उपलब्धता है, से भी महिला किसानों और स्व भूमि केन्द्रों के क़ानून सहायक कार्मिकों के विश्वास और जानकारी में वृद्धि हुई है, और इसने उन्हें अहसास कराया कि वे सभी जुड़े हुए हैं।

वित्तीय संसाधनों तक पहुँच

किसी के स्वयं के नाम पर भूमि होना महत्वपूर्ण है, और भूमि पर यह क़ानूनी हक़ बड़े सामाजिक परिवर्तनों की शुरुआत करने में मदद कर सकता है। भूस्वामित्व ने महिला किसानों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (Primary Agricultural Cooperative Societies—PACS) से किफ़ायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। चूँकि बावला महिला विकास संगठन और नवजीवन महासंघ दोनों ही महिला स्वयं सहायता समूहों के महासंघ हैं, इसलिए उनके सदस्यों को साख़ तक पहुँच की गारंटी है। कुछ महिला भूस्वामियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card—KCC) मिलना शुरू हो गया है, जिससे साख़ तक उनकी पहुँच बढ़ गई है।

मानव संसाधनों तक पहुँच

यह स्व भूमि केन्द्र संचालित करने वाले क़ानून सहायक कार्मिकों की ओर से महिला किसानों की भूमि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि और कृषि सम्बन्धी क़ानूनी प्रक्रियाओं, स्थाई कृषि प्रथाओं के साथ ही सरकारी संरचना, प्रक्रियाओं, और योजनाओं के ज्ञान को सन्दर्भित करता है।

WGWLO से केन्द्रीकृत प्रशिक्षण आदानों की बदौलत, भूमि और राजस्व मामलों के बारे में क़ानूनी जानकारी रखने, और विरासत आदि का दावा करने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की एक अच्छी समझ से स्व भूमि केन्द्र के क़ानून सहायक कार्मिकों को काफ़ी लाभ हुआ है और उनकी स्थिति मज़बूत हुई है। संगठनों और स्व भूमि केन्द्र से जुड़े समूहों की महिलाएँ सभी महिला किसानों को I-Khedut पोर्टल के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, और उनके न्यायोचित अधिकारों का दावा करने के लिए दस्तावेज़ों को इकट्ठा करने में भी उनकी मदद करती हैं।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण के किसान हित समूहों में महिला किसानों की सदस्यता और किसान मित्रों के रूप में महिलाओं के चयन ने कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक ज्ञान तक महिला किसानों की पहुँच बढ़ाई है। कई गाँवों की महिला किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं, और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण परियोजना के तहत उन्हें बेहतर बीज किटों के माध्यम से सहायता भी दी गई है। नवजीवन महासंघ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण के माध्यम से प्राप्त किट अपने सदस्यों के बीच बारी-बारी से वितरित करता है, ताकि समूह का प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी कार्यक्रम से लाभान्वित हो। महिला किसान मित्रों को दिए गए अतिरिक्त आदानों से पुरुष किसानों को भी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली है। महासंघ का कृषि केन्द्र महिलाओं के पास मौजूद जानकारी का एक परिणाम है। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा महिला किसानों के साथ और उनके लिए संचालित कई कार्यक्रमों ने महिला किसानों की मानव पूँजी को बढ़ाया है; यह मानव पूँजी पहले कभी सुलभ नहीं थी।

बावला महिला विकास संगठन और सारथी के मामले में भी यही स्थिति रही है, जहाँ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण और कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ सम्बन्धों ने न केवल महिला किसानों की मानव पूँजी को बढ़ाया है, बल्कि “किसानों” के रूप में भी उनकी पहचान स्थापित की है, जिसने खुद उनके आत्मविश्वास को काफ़ी हद तक बढ़ाया है।

स्थायी कृषि प्रथाओं के लिए सम्पूर्ण हस्तक्षेप की रूपरेखा महिला किसानों की पारम्परिक जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। स्थानीय संसाधनों के साथ जैव-बीज उपचार, जैव-विकास संवर्धक और जैव-कीटनाशक तैयार करना इन महिला किसानों के लिए सीखने का एक नया क्षेत्र रहा है। तीनों ही स्व भूमि केन्द्रों, जिनके सदस्य WGWLO नेटवर्क द्वारा केन्द्रीय

रूप से प्रशिक्षित हैं, ने इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे किसानों को विशिष्ट किस्म के बीज प्रदान करते हैं और इन बीजों ने कृषि उपज बढ़ाने में मदद की है और इसके फलस्वरूप किसानों की आजीविका में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

जबकि इस केस स्टडी ने उदाहरण के रूप में तीन स्थानों पर ध्यान केन्द्रित किया है, WGWLO 12 ज़िलों में गहनता से काम कर रहा है और इसने 15 स्व भूमि केन्द्रों की स्थापना में सहयोग किया है। WGWLO के सदस्य गैर-सरकारी संगठनों और महिला संगठनों द्वारा पाँच वर्षों से अधिक समय से केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। भूस्वामित्व प्राप्त करने के लिए केन्द्रों ने सामूहिक रूप से 7,000 से अधिक महिलाओं की सहायता की है; I-Khedut पोर्टल के तहत खुद को पंजीकृत कराने में 13,000 से अधिक महिला किसानों की सहायता की है; और पिछले पाँच वर्षों में 7,500 से अधिक महिला किसानों को उत्पादक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

यह मामला स्व भूमि केन्द्र जैसी एक विशिष्ट संस्थागत प्रक्रिया का प्रभाव प्रदर्शित करता है ताकि महिलाओं का भूस्वामित्व और उत्पादक संसाधनों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित हो, जो एक कृषक परिवार की आजीविका के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, जो अब भी मुख्यतः एक कृषि अर्थव्यवस्था है। ये मामला यह भी दर्शाता है कि अरक्षित समूहों की आजीविका बढ़ाने के लिए एक अभिकरण को कई मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है। इस बहुआयामी दृष्टिकोण ने स्व भूमि केन्द्रों की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। कृषि के महिलाकरण और महिला किसानों की बढ़ती संख्या के सन्दर्भ में, ऐसी प्रक्रियाएँ वास्तव में वक्त की पुकार हैं; वे कृषि-आधारित परिवारों की आजीविका में वृद्धि करती हैं। देश के सामने मौजूद कृषि संकट के साथ, किसानों तक पहुँचने के लिए स्व भूमि केन्द्रों जैसे केन्द्रों का दायरा भी विस्तारित किया जा सकता है, खासकर आत्महत्या के खतरे वाले क्षेत्रों में, जहाँ महिला किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं।

उत्पन्न पूँजी की मात्रा बहुत विशाल है क्योंकि स्व भूमि केन्द्र एक नेटवर्क, WGWLO, के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं। नियमित आदान उपलब्ध कराने और सदस्यों के बीच साझा करने तथा सीखने की सुगमता के लिए इस तरह के केन्द्र और नेटवर्क स्थापित किए जाने चाहिए। यह महिलाओं को भूमि पर विरासत का दावा करने का अधिकार सुनिश्चित करेगा, एक ऐसा अधिकार जिससे उन्हें वंचित कर दिया गया है। स्व भूमि केन्द्र अन्य उत्पादक संसाधनों का दावा करने में भी महिला किसानों की सहायता प्रदान करते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय और मानवीय निवेश की आवश्यकता होती है। सरकारी विभागों और विकास अभिकरणों को लम्बी अवधि के लिए महिला किसानों हेतु आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए निवेश और दूरगामी प्रयास करने की आवश्यकता है।

यह केस स्टडी इस बात को सिद्ध करती है कि मंजुलाबेन, शर्मिलाबेन, और सविताबेन जैसी लाखों महिला किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए स्व भूमि केन्द्र जैसी प्रक्रियाएँ अत्यन्त आवश्यक हैं।

वर्किंग ग्रुप फॉर वीमेन एंड लैंड ओनरशिप (WGWLO), गुजरात

2002 में शुरू किया गया वर्किंग ग्रुप फॉर वीमेन एंड लैंड ओनरशिप (Working Group for Women and Land Ownership—WGWLO), महिलाओं के भू अधिकारों के मुद्दे के इर्द-गिर्द ज़मीनी स्तर पर सतत कार्यवाही और नीति की पैरवी करने के लिए प्रतिबद्ध संगठनों का एक नेटवर्क है, जो भूमि एवं अन्य उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और स्वामित्व के लिए महिलाओं को सक्षम बनाता है। WGWLO गुजरात राज्य में स्थित है और इसमें गुजरात के कुल 33 ज़िलों में से 17 में 40 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों, समुदाय-आधारित संगठनों, और विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों की एक विविधतापूर्ण सदस्यता है।

WGWLO महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के साथ-साथ आजीविका बढ़ाने के दृष्टिकोण से महिलाओं के भूस्वामित्व के मुद्दे को सफलतापूर्वक सम्बोधित करने में समर्थ रहा है। 2009 के बाद से, भू अधिकारों के एजेंडे का विस्तार प्रचलन में आया है—महिलाओं के निजी भूमि के स्वामित्व से, नेटवर्क ने महिलाओं के भू अधिकारों को किसी लैंगिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक भूमि तक विस्तारित किया है, जिसमें वन भूमि, सामान्य भूमि, और सरकारी भूमि शामिल है। स्थाई कृषि के लिए महिला किसानों के साथ काम करते हुए भू अधिकारों और उत्पादक संसाधनों के अधिकार का एजेंडा धीरे-धीरे विस्तारपूर्वक प्रस्तुत और समेकित किया गया। मौजूदा दूसरे नेटवर्कों के साथ रणनीतिक गठजोड़ के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए नेटवर्क अपनी सामूहिक ताक़त का उपयोग करते हुए सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों, और जनसंचार माध्यमों को प्रभावित करता है।

सन्दर्भ तय करना

4. शैक्षिक हस्तक्षेपों की केस स्टडीज़

भारत में, औपनिवेशिक काल में स्कूली शिक्षा प्रणाली ने एक अधिक संस्थागत रूप की स्थापना के बाद से शैक्षिक संवाद में बदलावों के साथ-साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलाव देखे हैं। स्वतंत्रता के बाद भी, औपनिवेशिक प्रणाली की कई विशेषताएँ—स्कूली शिक्षा की विविध प्रणालियाँ, केन्द्रीकृत नौकरशाही प्रशासन, बृहत्तर व्यवस्था में शिक्षक की एक सीमान्त भूमिका, द्वि-भाषा नीति, और मामूली ढंग से विकसित शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएँ—कायम रहीं, और शैक्षिक सुधारों की राह में चुनौतियाँ खड़ी करती रहीं।

स्वतंत्रता के बाद स्कूली शिक्षा प्रणाली राज्य की एक अधिक केन्द्रीय भूमिका, ऐतिहासिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, और सार्वभौमिकता की ओर धीरे-धीरे क़दम बढ़ाने की साक्षी रही है। यह किसी मौजूदा शिक्षा प्रणाली के परिदृश्य से दूर होने की एक बेचैनी भरी प्रगति थी, जो स्कूली शिक्षा के बजाय उच्च शिक्षा की ओर दृढ़ता से उन्मुख थी, और इसमें अब भी निष्पक्षता, या यहाँ तक कि समानता के बजाय मज़बूत बहिष्करण के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए, एक अर्थ में, 1990 के दशक तक, स्कूल शिक्षा प्रणाली ने एक अत्यधिक उच्च स्तरीकृत समाज की मौजूदा असमानताओं को दूर करने के बजाय अपेक्षाकृत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक समूहों के लिए स्थितिगत लाभों को मज़बूती प्रदान करना जारी रखा।

1990 के दशक में कई स्तरों पर बदलाव हुए। आर्थिक मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ और निजी 'अंग्रेज़ी-माध्यम' की शिक्षा के लिए आकांक्षाएँ बढ़ने लगीं। इस अवधि में शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी जिसने वसूल किए जाने वाले शुल्क और अन्य विशेषताओं की एक श्रृंखला के आधार पर स्कूल प्रणाली को विविध प्रदाताओं के रूप में वर्गों में वर्गीकृत किया गया जो अब सामाजिक वर्गों के बीच भुगतान करने की अलग-अलग क्षमता वालों को सेवाएँ प्रदान करती हैं। उसके साथ-साथ, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (Universalisation of Elementary Education—UEE) के इर्द-गिर्द हुए अन्तर्राष्ट्रीय संवाद ने राष्ट्रीय राजनीतिक और नीतिगत परिदृश्य में अधिक व्यापकता प्राप्त की। शैक्षिक सुधारों को सार्वभौमिकता के अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए बड़े पैमाने पर केन्द्र-प्रायोजित शिक्षा योजनाओं का सिलसिला शुरू किया गया।

इन योजनाओं ने, शैक्षिक आदानों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ, विशेष रूप से अब तक उपेक्षित सामाजिक समूहों के बीच स्कूली शिक्षा के प्रावधान और पहुँच का अत्यधिक विस्तार किया। इस प्रकार, इस अवधि में यह हुआ कि, सरकारी स्कूलों में सीमान्त समूहों की उपस्थिति में विस्तार हुआ, जो मुख्य रूप से स्थानीय भाषा में शिक्षा की पेशकश कर रहे थे, साथ ही इन स्कूलों को छोड़कर धीरे-धीरे मध्यम वर्गों के बच्चे बड़े पैमाने पर उभरते निजी स्कूलों में जाने लगे जो कथित तौर पर 'अंग्रेज़ी-माध्यम' में शिक्षा की पेशकश करते थे। स्कूल प्रणाली के विस्तार के साथ अन्य प्रणालीगत परिवर्तन नहीं हुए जो साथ-साथ मुख्य रूप से वंचित पृष्ठभूमियों से आने वाले पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले बच्चों की सहायता कर सकें। परिणामस्वरूप, शिक्षा की गुणवत्ता मुख्य चुनौतियों में से एक हो गई जिसका सामना वर्तमान स्कूली शिक्षा प्रणाली कर रही है।

ऐसा नहीं है कि हाल के दशकों में शैक्षिक संवाद में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण हैं 2000 और 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं (National Curriculum Frameworks) के माध्यम से एक अधिक बाल-केन्द्रित पाठ्यचर्या का समर्थन, और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education Act—RTE), 2009 के माध्यम से शैक्षिक अधिकारों के प्रति एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का अधिनियमन करना। हालाँकि, कई प्रणालीगत कारक और विरोधाभासी बल और दबाव बरकरार हैं, और जिनकी ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रणालीगत स्तर पर, शिक्षकों की शिक्षा और पेशवरों के रूप में शिक्षकों की भूमिका दोनों का धीरे-धीरे अवमूल्यन हुआ है, जिनमें से पहला शिक्षक तैयार करने और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए मज़बूत संस्थागत व्यवस्थाओं के विकास के बिना शिक्षकों की शिक्षा, और दूसरा सह-शिक्षकों की एक प्रणाली के समर्थन के माध्यम से तथा स्कूल प्रणाली में शिक्षकों के काम के आसपास की चुनौतियों को सम्बोधित करने के लिए प्रबन्धकीय और नियंत्रण-आधारित समाधानों के माध्यम से हुआ है। इसलिए, हाल के दशकों के प्रगतिशील पाठ्यक्रम सुधारों को न तो व्यवहार में परिवर्तित किया गया है और न ही मौजूदा प्रणाली में उस हद तक अवशोषित किया गया है जितना उन्हें किया जाना चाहिए था। इसी तरह, एक विशाल, विविधतापूर्ण, और स्तरीकृत देश के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की एक समान व्यवस्था के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताएँ अनुपातिक नहीं रही हैं। नतीजतन, स्कूली शिक्षा अभी भी प्रणाली में निहित तनावों से भरी हुई है, जहाँ राज्य के अधिकार-आधारित शासनादेश और शिक्षा की लोकहित की विशेषताओं पर उसके व्यापक ज़ोर का सह-अस्तित्व बाज़ार की ताक़तों और शिक्षा के अधिक संकीर्ण उद्देश्यों के साथ होता है जिनकी इन ताक़तों द्वारा पुष्टि और पूर्ति की जाती है।

इस खण्ड में दो केस स्टडीज़ स्कूली शिक्षा प्रणाली के भीतर उपरोक्त संक्रमण और चुनौतियों के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित होती हैं। क़दम, द स्टेप-अप प्रोग्राम ऑफ़ ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया (Kadam, The Step-Up Programme of Humana People to People India), अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है कि भारत में सार्वभौमीकरण और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों के बावजूद, बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं, और इसलिए, ऐसे सन्दर्भ में राज्य के प्रयासों में कौन-से पूरक जोड़े जा सकते हैं। इन प्रयासों में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सन्दर्भ-विशिष्ट, शिक्षा-विज्ञान सम्बन्धी मज़बूत पहल की आवश्यकता स्पष्ट है। प्रासंगिक रूप से एकीकृत हस्तक्षेपों के लिए इसी तरह की आवश्यकता कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम (Kaigal Education and Environment Programme—KEEP) की केस स्टडी से स्पष्ट है जो विशेषकर सीमान्त समूहों के लिए विभिन्न चुनौतियों—पारिस्थितिक, आजीविका सम्बन्धी, और शैक्षणिक—को सम्बोधित कर सकें। यह कार्यक्रम दिखाता है कि कैसे उर्ध्वगामी, बहु-आयामी, लेकिन उसके साथ समग्र प्रयास, वंचित समूहों के शिक्षा और जीवन दोनों के इर्द-गिर्द और अधिक स्थाई तरीके से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दोनों केस स्टडीज़ स्कूली शिक्षा में काम करने वालों के लिए विशिष्ट रूप से, और सामान्य रूप से विकास के लिए शिक्षा की प्रकृति के बारे में सवाल उठाती हैं, जो नुकसानों के विशिष्ट सन्दर्भों में सशक्तिकरण करने वाली एवं टिकाऊ होगी और वे भूमिकाएँ जो ग़ैर-राज्य कार्यकर्ता ऐसे सन्दर्भों में निभा सकते हैं।

4.1 शिक्षा, संरक्षण, और आजीविका के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की केस स्टडी

कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम (KEEP), आंध्र प्रदेश

सारांश

कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम (Kaigal Education and Environment Programme—KEEP) की संकल्पना एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में 2008 में शिक्षा, संरक्षण, और स्थाई आजीविका को सम्मिश्रित करते हुए की गई थी। ये सभी सामाजिक पारिस्थितिक सिद्धान्तों में समाहित हैं। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य (Kaundinya Wildlife Sanctuary) के किनारे क्रियान्वित किया गया है। यहाँ के समुदाय सीमान्त मिश्रित समुदाय हैं, जिनमें से कई अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ हैं। यानदी आदिवासी समुदाय इस क्षेत्र का प्रमुख आदिवासी समूह है। परिवर्तन का अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि मानव समुदाय स्थानीय पारिस्थितिकी का एक अभिन्न अंग हैं और इसलिए स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थाई हस्तक्षेप आवश्यक हैं और इनमें उन समुदायों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए जिनके अधिकार और ज़िम्मेदारी उस पारिस्थितिकी की रक्षा और संरक्षण करना है जिसका वे एक हिस्सा हैं।

केस स्टडी हस्तक्षेप के तीन अलग-अलग अक्षों—संरक्षण, शिक्षा और आजीविका—का वर्णन करती है। हालाँकि, यह याद रखा जाना चाहिए कि यह हस्तक्षेप स्वतंत्र नहीं हैं। सांस्कृतिक स्थिरता, आर्थिक स्वतंत्रता, और आदिवासी समुदायों की सामाजिक स्वीकृति इन तीनों हस्तक्षेपों के एक साथ काम करने पर निर्भर है।

हस्तक्षेप की अवधि में, कार्यक्रम ने विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण की स्थिति में सुधार किया है, जो 14,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र कवर करता है, 60 गाँवों में 26,000 से अधिक लोगों पर असर डालता है। हस्तक्षेप का 300 से अधिक आदिवासी परिवारों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है; इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्थापित सामुदायिक उद्यम ग्रामीण और वन-आधारित आजीविका में सहयोग प्रदान कर रहा है। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि अपने पर्यावरण के साथ मनुष्य के सम्बन्ध को बदलना अब सतत विकास की आधारशिला के रूप में जाना जाता है।

शिक्षा, संरक्षण, और आजीविका के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की केस स्टडी—दो साँपों की कहानी

अगस्त 2008 की बात है। एक पर्यटक कैगल कंज़र्वेशन सेंटर (Kaigal Conservation Centre, जिसे आगे केन्द्र या कैगल केन्द्र कहा गया है) आया, वह साँपों के बारे में अतिउत्साही था। कैगल में फ़ील्ड कोऑर्डिनेटर ने, जो एक शौकिया पशु सरीसृप विज्ञानवेत्ता (herpetologist) था, कार्यालय भवन की टाइल वाली छत से एक साँप देखा और पर्यटक को बताया। प्रजाति अपरिचित लग रही थी और उन्हें सन्देह था कि यह एक नई प्रजाति हो सकती है।

आख़िरकार दो महीने बाद उन्होंने साँप को पकड़ लिया। यह केन्द्र में एक रोमांचक दिन था जब यह पुष्टि की गई कि साँप एक नई प्रजाति का है। इस प्रकार साँपों की विविधता का अध्ययन करने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम में कैगल सेंटर के सदस्यों, आदिवासी बच्चों के अधिगम केन्द्रों में शिक्षकों, और छात्रों ने भाग लिया।

कुछ वर्ष फ़ास्ट-फ़ॉरवर्ड (fast-forward) करके जनवरी 2012 में चलते हैं। ऋषि वैली स्कूल (Rishi Valley School) के छात्र एक पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कैगल संरक्षण केन्द्र (Kaigal Conservation Centre) में मौजूद थे। शिक्षक से संरक्षण जीवविज्ञानी (conservation biologist) बने जयपाल, और एक अन्य फ़ील्ड कोऑर्डिनेटर दो बड़े बैग के साथ केन्द्र पहुँचे। जैसे ही छात्रों ने यह देखा उनकी आँखें आश्चर्य से फटी रह गईं और शायद वे कुछ डर भी गए, दोनों व्यक्तियों ने बैग खोला और ध्यान से एक अजगर निकाला जिसे वे स्थानीय गाँव से बचाकर लाए थे। जयपाल ने अजगर को एक बच्चे की तरह प्यार से सहलाते हुए बताया कि कैसे उसे ग्रामीणों को अजगर को जंगल में वापस छोड़ने, उसे चोट नहीं पहुँचाने के लिए मनाना पड़ा। वन विभाग के अधिकारियों के आने और इसे ले जाने के लिए इन्तज़ार करते हुए अजगर को केन्द्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था।

संरक्षण, शिक्षा, और समुदाय के प्रति एक दृष्टिकोण दो अलग-अलग प्रतीत होने वाली इन घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। शिक्षा, आजीविका, और संरक्षण मूल रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में एकीकृत हैं, जो सतत विकास के लिए उर्ध्वगामी, समुदाय के नेतृत्व में संचालित एक शैक्षिक कार्यक्रम के लिए एक मॉडल प्रदान करते हैं।

और यही कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम की कहानी है।

शुरुआत

कार्यक्रम की नींव, आंध्र प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली एक अनुसूचित जनजाति, यानदी जनजाति, के दो जानकारों के सरल किन्तु शक्तिशाली शब्दों से प्रेरित थी।

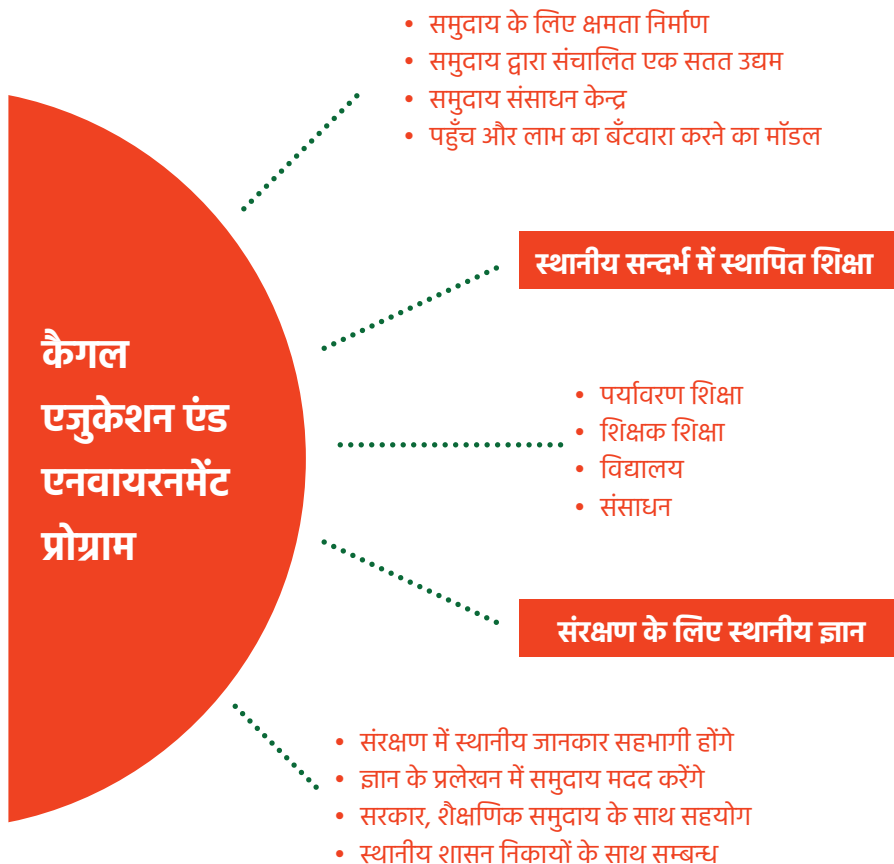
जब मुगिलुपोडालरेवू गाँव में मुफ्त पौधारोपण करने गई टीम ने अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाने पर सुब्बारायप्पा के घर के बाहर शरण ली तो उसने पूछा था, “आप हमसे बीज और जंगलों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप हमारे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं?” मुगिलुपोडालरेवू एक आदिवासी गाँव है, जो चित्तूर ज़िले में कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है, जो सबसे नज़दीकी मण्डल मुख्यालय बिरेडुईपल्ली से लगभग 7 किमी दूर है, और यानदी समुदाय का घर है।

“हमारे बच्चों को अच्छे-से शिक्षा दें। उन्हें जंगलों के बारे में शिक्षा दें,” पेड़ लगाने वाली उसी टीम के सामने मुगिलुपोडालरेवू गाँव से 17 किलोमीटर दूर कल्लीगुट्टा गाँव में दुगेप्पा ने आग्रह किया, जब वह बच्चों के सीखने के लिए एक कोना तैयार करने के लिए अपना बकरी रखने

का छप्पर साफ़ कर रहा था। कल्लीगुट्टा एक सुदूर आदिवासी गाँव है, जो कि बिरेड्डीपल्ली से लगभग 15 किमी दूर स्थित है और यह भी यानदी लोगों का घर है।

इन दो सुझावों और प्रस्तावों के साथ कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम की यात्रा शुरू हुई।

एक परिस्थितिविज्ञानी और द वैली स्कूल (The Valley School) में जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने वाली सुधा को कौडिन्य वन्यजीव अभयारण्य के पास एक स्थान पर कैगल संरक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए कहा गया। यह 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों की बात है जब बड़े पैमाने पर बस्तियों के विनाश के हानिकारक प्रभावों को और अनदेखा करना सम्भव नहीं था। जब छात्रों का पहला जत्था इस क्षेत्र की जैव विविधता का प्रलेखन करने, भूमि का नक्शा बनाने, और भूमि के उपयोग का प्रलेखन करने के लिए कैगल पहुँचा तो उन्होंने एक क्षेत्र में, जिसे मोटेतौर पर और लगभग लापरवाही से झाड़ीदार जंगल या बंजर / बेकार भूमि (wasteland) कहा जाता था, अनुपजाऊ भूमि के विशाल हिस्से देखे। कृष्णमूर्ति



फ़ाउण्डेशन इंडिया (Krishnamurti Foundation India—KFI) के सहयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme—UNDP) से प्राप्त एक अनुदान से, सुधा, उनके सहकर्मी प्रेमनाथ और भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India—WII) के विशेषज्ञों के साथ-साथ स्थानीय समुदायों ने क्षेत्र की जैव विविधता का प्रलेखन किया, एक जीवाणु प्लाज़्मा बैंक (Germ Plasma Bank—GPB) स्थापित किया और एक सहभागी संरक्षण कार्यक्रम (Participatory Conservation Programme—PCP) शुरू किया। लक्ष्य था अनुपजाऊ भूमि पर और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं से जुड़ना और उन्हें पूरा करना तथा 200 एकड़ अनुपजाऊ भूमि के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए उनके साथ संयुक्त रूप से कार्य करना। परियोजना ने एक बीज बैंक, एक वन पौधशाला, और संरक्षण एवं स्थानीय जैव विविधता के बारे में जागरूकता निर्मित करने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया। जैव विविधता संरक्षण के लिए किसी सहभागी दृष्टिकोण का यह एक नमूना था जिसने स्थानीय जानकारी प्राप्त की और उसका प्रलेखन किया। परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, कृष्णमूर्ति फ़ाउण्डेशन इंडिया ने भूमि के लिए एक केयरटेकर नियुक्त करने और संरक्षण के लिए बजटीय प्रावधान करने का भी निर्णय लिया। और यह वह बिन्दु है जहाँ कार्यक्रम समाप्त हो गया होता।

लेकिन दो आदिवासी बुजुर्गों के शब्दों ने कार्यक्रम का दायरा और प्रकृति बदल दी।

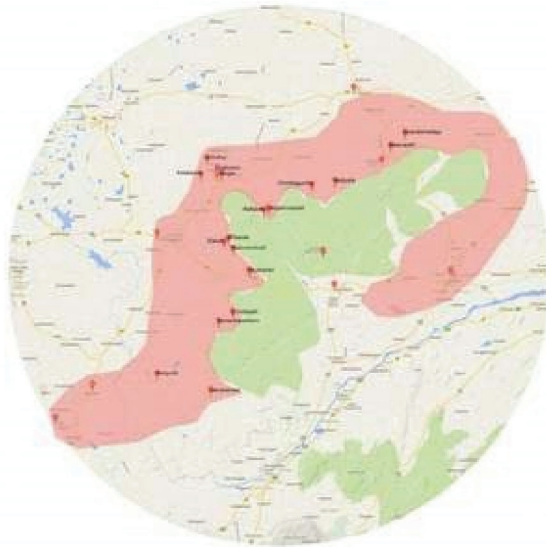
हालाँकि, कैगल केन्द्र पर मौजूद टीम के लिए इन शब्दों ने महज़ उस बात की पुष्टि की और उसे प्रबलित किया जो उनके दिमाग़ में पहले से थी। यह दृढ़ विश्वास था कि मनुष्यों और वनों के बीच पारस्परिक रूप से स्थाई सम्बन्ध बनाने के लिए, पारिस्थितिक दृष्टि से पुनर्स्थापना एवं सतत विकास प्रतिमान और कार्यप्रणालियाँ विकसित करने तथा अपनाने के लिए समुदाय के साथ और गहरे जुड़ाव की आवश्यकता है। इस तरह कैगल में हस्तक्षेप की संकल्पना 2008 में की गई जो तीन मान्यताओं पर आधारित थी—शिक्षा जो समुदाय के महत्त्व की पुष्टि करती हो, संरक्षण जिसे समुदाय का सहारा प्राप्त हो, और आजीविका जो स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी को सहारा, सुरक्षा, और पोषण प्रदान कर सके।

कार्यक्रम का एक विहंगावलोकन

पर्यावरणीय दुर्दशा और पृथ्वी के जीवन पर उसका प्रभाव आज मानव के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। दुनियाभर में वन और निर्जन क्षेत्र बहुत दबाव ग्रस्त हैं और जैव विविधता को बचाना एवं बढ़ाना एक ऐसी चिन्ता है जिसकी तरफ़ अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है। इस चुनौती का जवाब देने का अर्थ है लोगों को सतत विकास के विशिष्ट महत्त्व के बारे में शिक्षित करना और इसमें अनेक परस्पर सम्बन्धित आयाम—कौशल, आजीविकाएँ, पारिस्थितिकी, समुदाय, निष्पक्षता, और न्याय—भी शामिल हैं। भारत जैसे एक

विशाल, विषमतापूर्ण, और विविधतापूर्ण देश में, जातिगत पदानुक्रम, आर्थिक स्थितियाँ, और लैंगिक असमानताएँ अतिरिक्त बाधाएँ खड़ी करती हैं।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य से सटे आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के बीच कार्यरत कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऐसा ही एक हस्तक्षेप है। इसका उद्देश्य लोगों को जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास का बीड़ा उठाने के लिए शिक्षित करना है। कार्यक्रम ने पालमानेर शहर के पास कैगल घाटी में और उसके आसपास काम किया है, जहाँ कृष्णमूर्ति फ़ाउण्डेशन इंडिया ने कैगल संरक्षण केन्द्र की स्थापना की है। यह क्षेत्र तीन तरफ़ से कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य (एक हाथी अभयारण्य) के जंगलों से घिरा हुआ है और चौथी तरफ़ आंध्र प्रदेश में पालमानेर और कुप्पम को जोड़ने वाले राजकीय राजमार्ग (state highway) से घिरा हुआ है। यह कार्यक्रम द वैली स्कूल में पर्यावरण विज्ञान के छात्रों के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम (outreach programme) के रूप में शुरू हुआ। संरक्षण के लिए सामाजिक पारिस्थितिकीय सिद्धान्तों पर आधारित एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में 2008 में इसकी पुनः संकल्पना की गई। कार्यक्रम की मुख्य धारणा समुदायों और विचारों को एक साथ लाकर स्थिर समुदायों के निर्माण के लिए काम करने की है।



कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को एक साथ लाने और सामूहिक ज्ञान के निर्माण में योगदान देने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ काम किया है। इसके कारण निवास स्थान की बहाली, क्षमता निर्माण एवं स्थानीय समुदायों के कौशल संवर्धन, और स्थानीय पंचायतों के दायरे में जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाने में लोगों की जागरूकता और भागीदारी में वृद्धि हुई है। समुदाय द्वारा संचालित स्थानीय उद्यम ने स्थाई वन प्रबन्धन और जैव संसाधनों के बँटवारे के लिए एक मॉडल की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। आदिवासी बच्चों के लिए स्कूलों ने सुनिश्चित किया है कि आदिवासी गाँवों के सभी बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करें।

स्थान और सन्दर्भ

कैगल गाँव तक जाने के लिए बेंगलूरु से 140 किलोमीटर की तीन घण्टे की यात्रा करनी पड़ती है, फिर भी यह एक अलग ही दुनिया है। आप बेंगलूरु-चेन्नई राजमार्ग से मुलबागल के पास से मुड़ते हैं और घुमावदार सड़क पकड़ते हैं जो आपको आंध्र प्रदेश में ले जाती है। एकल-पथ (single-lane) सड़क के दोनों ओर खेतों की क़तार हैं, जिनकी वर्तमान में कृष्णा नदी से पानी लाने वाली पानी की एक नहर बिछाने के कारण मरम्मत चल रही है। यह सड़क पालमानेर-कुप्पम राजकीय राजमार्ग से मिलती है; कैगल गाँव इस राजमार्ग से दूर स्थित है।

कैगल घाटी, कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हस्तक्षेप क्षेत्र, पूर्व में पालमानेर और पश्चिम में आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में कुप्पम के बीच विस्तारित है। हस्तक्षेप के अन्तर्गत आने वाले लगभग सभी गाँव कौडिन्य वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से लगे हुए हैं, जो नक्शे में हरे रंग में दर्शाया गया है।

स्थानीय जैव विविधता

कैगल केन्द्र एक घाटी में स्थित है, जिसमें से एक छोटी नदी गुज़रती है, जो अन्त में पलार नदी में मिल जाती है। छोटी नदी से एक जलप्रपात बनता है जो कैगल जलप्रपात (Kaigal Falls) के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय समुदायों द्वारा पवित्र माना जाता है और इसके पानी को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है।

वन और वन्यजीव : गीली और सूखी पर्णपाती और झाड़ीदार वनस्पतियाँ इस क्षेत्र की विशेषता हैं, जिन्हें छोटी धाराओं और सहायक नदियों, झीलों, और तालाबों जैसे मौसमी जल स्रोतों द्वारा सिंचित किया जाता है। सबसे अधिक पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में अल्बिज़िया अमारा (Albizia amara—तेलुगु में चिगेरे), राइटिया टिंक्टोरिया (Wrightia tinctoria—तेलुगु में वीपेली), पोंगामिया पिनाता (Pongamia pinnata—तेलुगु में कण्णा), सैपिंडस इमर्जिनेटस (Sapindus emarginatus—तेलुगु में कूगट्टीक्काई), टेमेरिंडस इंडिका

(*Tamarindus indica*—तेलुगु में चिन्टकाई), और होलोपटीलिया इंटैग्रीफोलिया (*Holoptelea integrifolia*—तेलुगु में तबसी) शामिल हैं। सामान्य झाड़ियाँ रैन्डिया ड्युमेटोरम (*Randia dumetorum*—तेलुगु में मंगा चेट्टू), टोडालिया एशियाटिका (*Toddalia asiatica*—तेलुगु में मिरप्पाकांड), डोडोनिया विस्कोसा (*Dodonaea viscosa*—तेलुगु में बंदेरी चेट्टू), डाइक्रसटेचिस सिनेरिया (*Dichrostachys cinerea*—तेलुगु में नेल्ला जम्मी), ग्मेमिना एशियाटिका (*Gmelina asiatica*—तेलुगु में अदावी गुम्माडी), कैन्थियम पर्विफ्लोरम (*Canthium parviflorum*—तेलुगु में सिन्ना बालुसु), कैलोट्रोपिस गिगेंटिया (*Calotropis gigantea*—तेलुगु में जिल्लेडु), और लैंटाना कैमरा (*Lantana camera*—साधारण लैंटाना) हैं। सिज़िजियम क्यूमिनाइ (*Syzygium cumini*—तेलुगु में नेरेडी) और टर्मिनलिया अर्जुना (*Terminalia arjuna*—तेलुगु में थेल्ला मद्दी) आमतौर पर जल निकायों के पास पाए जाते हैं।

वनो में वनस्पतियों और जीवों की बहुत विविधता है। इस क्षेत्र के कुछ लुप्तप्राय और संकटापन्न वनस्पतियाँ डेकालेपिस हेमिल्टोनी (*Decalepis hamiltonii*—तेलुगु में मारडी गड्डा), गार्डेनिया ग्युमीफेरा (*Gardenia gummiifera*—तेलुगु में चिन्ना बिक्की), गार्डेनिया लैटीफोलिया (*Gardenia latifolia*—तेलुगु में पेड्डा बिक्की), मधुका इंडिका (*Madhuca indica*—तेलुगु में विपा), शोरिया तुम्बगिया (*Shorea tumbuggaia*—तेलुगु में जलारी), शोरिया टेलुरा (*Shorea tellura*—तेलुगु में जलारी), ग्लोरियोसा सुपरबा (*Gloriosa superba*—तेलुगु में गोरम्मा गड्डा), टर्मिनलिया चेबुला (*Terminalia chebula*—तेलुगु में कर्काकाई), और क्लोरोझायलोन स्वीटेनिया (*Chloroxylon swietenia*—तेलुगु में बिली मनु) हैं।

यह क्षेत्र संकट में पड़ी जीव प्रजातियों जैसे—एशियाई हाथी, दुबले-पतले बन्दर, जंगली कुत्ते, रीछ, सितारा कछुआ, रॉक पायथन, भारतीय वर्मी (इंडियन अर्माडिलो—*Indian armadillo*), उड़ने वाले साँप की नई प्रजाति (क्रिसोपीलिआ टैप्रोबानिका—*Chrysopelea taprobanica*), और सुनहरी छिपकली जैसी कई खतरनाक प्रजातियों का घर है।

समुदाय

यहाँ के समुदाय सीमान्त समुदायों का मिश्रण हैं और कई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं। यानदी आदिवासी समुदाय प्रमुख आदिवासी समूह है। अधिकांश यानदी वनोपज के संग्रहकर्ता हैं और स्थानीय जैव विविधता एवं पारम्परिक औषधीय पद्धतियों की गहरी जानकारी रखते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय विभिन्न प्रकार के गैर-काष्ठ वनोपज (Non-Timber Forest Produce—NTFP) जैसे कि फल, पत्ते, छाल, कन्द, शहद, और आरक्षित

वनों से राल का संग्रहण है। वे गिरिजन सहकारी निगम, आदिम जाति कल्याण विभाग (Girijan Cooperative Corporation, Tribal Welfare Department), आंध्र प्रदेश सरकार को इस वनोपज की आपूर्ति करते हैं या इसे स्थानीय बाज़ारों में बेचते हैं। वन के बारे में उनका ज्ञान—उसकी पारिस्थितिकी और जैव विविधता का ज्ञान—अपार और अमूल्य है। वे पारम्परिक औषधीय पौधों के बारे में अपने ज्ञान और उनके उपयोग के लिए सुविख्यात हैं। चूँकि यानदी समुदाय वनोपज के पारम्परिक संग्राहक और चिकित्सक (healer) हैं, इसलिए इस समुदाय के साथ काम करने से जंगल की भलाई पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है।

वन क्षेत्रों और जल स्रोतों के करीब रहने से यानदियों को शिकार और मछली पकड़ने के तरीकों का व्यापक ज्ञान है। जैव-संसाधन उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, और वे जानते हैं कि इन संसाधनों की पहचान कैसे की जाए, ढूँढ़ा कैसे जाए, और उनकी सतत प्राप्ति कैसे सुनिश्चित की जाए। वे भोजन और चिकित्सीय सामग्री में भी इनका उपयोग करते हैं।



आमतौर पर, संसाधनों का संग्रहण करने का कार्य एक सामूहिक गतिविधि है, जो युवा पीढ़ी को पारम्परिक ज्ञान हस्तान्तरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।ⁱⁱⁱ समय के साथ, यह पारम्परिक ज्ञान विभिन्न विकासात्मक अनिवार्यताओं के कारण लुप्त^{iv} होता जा रहा है।

कार्यक्रम कैसे प्रबन्धित किया जाता है

कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम छह सदस्यों की एक कोर टीम द्वारा क्रियान्वित गया है जिसमें द वैली स्कूल के शिक्षक और स्थानीय समुदाय के सदस्य दोनों शामिल हैं।

एक कोर टीम, जिसमें स्थानीय गाँवों के सदस्य शामिल हैं, कार्यक्रम में शामिल हुई और इसके साथ बनी रही, तथा विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया। वे शिक्षित युवा और युवतियाँ थीं, जिन्होंने हाई स्कूल पूरा किया था, और किसी सार्थक काम की तलाश कर रहे थे। कैगल के कोर ग्रुप में जयपाल, कृष्णमूर्ति, पुष्पा, और सुमित्रा थे जो दिन-प्रतिदिन के संचालन के साथ-साथ समुदाय-केन्द्रित गतिविधियों में शामिल थे। इस टीम ने कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए विभिन्न समुदायों के लोगों का एक नेटवर्क भी तैयार किया। द वैली स्कूल के शिक्षाविदों—सुधा, प्रेमनाथ, श्रीरंजनी, और कृष्णन—और बेंगलूरु के वैज्ञानिकों और शिक्षकों के एक समूह को सलाहकार समूह में शामिल किया गया, जिसने इस कोर ग्रुप के साथ-साथ विस्तारित समुदाय के साथ काम किया। कार्यक्रम में शुरुआत से ही सहभागी प्रक्रियाएँ, जैसे सहयोगी ज्ञान निर्माण और साथ-साथ सीखना एवं साझा करना, शामिल थीं। जानकारी साझा करने और सहयोग से काम करने के लिए आदिवासी परिवारों और ग्रामीण समुदायों को एक साथ लाया गया; जो हमारे अत्यधिक स्तरीकृत समाज में कोई आसान काम नहीं है।

ज्ञान निर्माण की सहयोगात्मक प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय, प्राथमिक रूप से यानदी आदिवासी समुदाय के बुजुर्ग शामिल थे। इन बुजुर्गों ने बाहरी शोधकर्ताओं के साथ बातचीत की जिन्होंने जंगल सम्बन्धी डेटा के प्रलेखन में मदद की। स्थानीय गैर-आदिवासी भी इस प्रक्रिया में भागीदार थे, क्योंकि जिन समुदायों के साथ काम किया गया उनमें से कुछ मिश्रित समुदाय थे जिनमें जनजातीय और अन्य जाति के लोग शामिल थे। कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर शैक्षणिक संस्थानों, पारिस्थितिकी, वानिकी, कृषि, और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर केन्द्रित अनुसन्धान संस्थानों, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठनों, वन विभाग और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority—NBA) के साथ भी काम किया गया। आजीविका कार्यक्रम ने भी विभिन्न संस्थानों और इसी तरह के संगठनों के साथ सम्बन्ध बनाए। विद्यालयों की स्थापना प्रतिष्ठित शिक्षाविदों से परामर्श के बाद और द वैली स्कूल एवं ऋषि वैली स्कूल के निकट सहयोग से की गई। पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक

प्रशिक्षण, और स्कूल के दैनिक संचालन एवं गतिविधियों के लिए कैगल फ़ाउण्डेशन इंडिया के स्कूलों में लागू अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के अनुसार ढाला गया और स्वतंत्रता एवं आपसी सम्मान के माहौल में सीखने पर ज़ोर दिया गया।

परिवर्तन का सिद्धान्त

परिवर्तन का अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि मानव समुदाय स्थानीय पारिस्थितिकी का एक अभिन्न अंग हैं, और इसलिए समुदायों की आवश्यकताओं और माँगों के जवाब में स्थाई हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से विकसित होना चाहिए, और हस्तक्षेपों में अनिवार्य रूप से इन समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका यह अधिकार और ज़िम्मेदारी है कि वे उस पारिस्थितिकी की सुरक्षा और संरक्षण करें, जिसका वे एक हिस्सा हैं।



“यानै सामी वंधुदुचु । नांग अथ कुंबुट्टु मराट्टु मेला ईरी उकंडुकुट्टोम । राथिरि पूरा अंगे इरुन्धोम । कलैला अन्दा सामी किलंबी पोयिडुक्कु ।” (“हाथी भगवान आया । हमने उसे प्रणाम किया, उससे प्रार्थना की, और एक पेड़ पर चढ़ गए । पूरी रात हम पेड़ पर थे । अगली सुबह, हाथी चला गया ।”) इस तरह नागम्मा ने एक हाथी के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया जब वह औषधीय पौधे इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई । जब आदिवासी लोग जंगल में जाते हैं, तो वे अक्सर कुछ दिनों तक एक विस्तारित अवधि के लिए ऐसा करते हैं ।

उनके पति, चिन्नन्ना, कहते हैं, “जंगल में सबकुछ था । वहाँ काफ़ी शहद था, हम कई सारी चीज़ें इकट्ठा कर सके । हमें लगा ही नहीं कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत थी । हमने कभी किसी और चीज़ की तलाश नहीं की, और हम जंगलों से दूर आ गए ।”

चिकित्सा करने वाले इस जोड़े के शब्द जीवन के सभी रूपों के लिए उनकी श्रद्धा और करुणा का, साथ ही साथ प्राकृतिक दुनिया के साथ उनके सम्बन्ध का भी उदाहरण देते हैं । और यह वह रिश्ता है जिसे कार्यक्रम द्वारा प्रेरित करने, मज़बूत बनाने, और उसमें सहयोग देने का प्रयास किया गया ।



सहभागी विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण, समुदायों और स्थानीय हितधारकों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से परियोजनाओं की रूपरेखा और क्रियान्वयन में उनकी भूमिका पर ज़ोर देते हैं।^v टिकाऊ और आत्मनिर्भर समुदायों के निर्माण के लिए पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए संरक्षण के दृष्टिकोणों की माँगों के साथ समुदाय की आवश्यकताओं का सन्तुलन क़ायम करना आवश्यक है। पारम्परिक ज्ञान^{vi} भी संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों में वनों के सतत प्रबन्धन में महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस प्रकार कार्यक्रम ने समुदायों के साथ जंगल की अपनी समझ को गहरा करने, और संरक्षण गतिविधियों में सहयोग करने हेतु अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए काम करना शुरू किया। आदिवासी गाँव के बच्चों को एक औपचारिक शिक्षा और नए कौशल प्रदान करने के लिए स्कूल स्थापित किए गए। स्थानीय समुदायों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करने और एक स्थाई तरीक़े से वनोपज प्राप्त करने, सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल्यवर्धन और इसे बेचकर स्थानीय समुदायों हेतु आय उत्पन्न करने के लिए एक समुदाय-आधारित उद्यम स्थापित किया गया। वन संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक स्वतंत्रता के सतत उपयोग को सम्भव बनाता है। आजीविका के अवसरों में विविधता लाने से यह सुनिश्चित होता है कि पर्यावरण ख़राब नहीं हो और स्थिर समुदायों का अस्तित्व क़ायम रहे। शिक्षा समुदाय के लिए व्यापक सम्भावनाओं के द्वार खोलती है और स्थानीय लोगों के लिए सावधानी के साथ जंगल का उपयोग करना सम्भव बनाती है। इस प्रकार सतत विकास के लिए एक मॉडल उभर कर सामने आया।

समुदाय के लिए और उसके साथ संरक्षण

दुनियाभर में वनों और जंगलों पर अत्यधिक दबाव है, और जैव विविधता एवं वनाच्छादित क्षेत्र को बचाना और बढ़ाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, हमारा यह मानना है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण उन लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक है जो आर्थिक रूप से वनों पर निर्भर हैं। कार्यक्रम ने यह भी माना कि समुदाय की सामूहिक स्मृति और पारिस्थितिकी एवं वन प्रबन्धन प्रथाओं के बारे में उसकी जानकारी के साथ-साथ जागरूक और सामिप्राय के मेल द्वारा ही वन विविधता का संरक्षण और पुनरुद्धार सम्भव है। इसलिए संरक्षण कार्यक्रम शुरुआत से ही—समुदायों, संस्थानों, वैधानिक निकायों, और वन विभाग—के साथ गठबन्धन निर्माण पर केन्द्रित था।



अन्य पौधशालाओं से अलग एक पौधशाला

सुधा कैगल केन्द्र में थी, और वहाँ के सर्वप्रथम फ़्रील्ड कोऑर्डिनेटर, कृष्णमूर्ति के साथ काम की योजना बना रही थी, तभी एक शाम सुब्बारायप्पा और सुब्बन्ना मुगिलुपोडालरेवु गाँव से उनसे मिलने आए।

सुब्बारायप्पा ने कहा, “देखिए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पेड़ों के बारे में बताऊँगा जो आपको उगाना चाहिए। मैं जंगल से पौधे लाऊँगा। जलारी मनु, यह सुगंधित फूल है और उगाए जाने योग्य है। बज्जी मंगा स्तनपान कराने वाली माताओं और मवेशियों के लिए अच्छा है। करक्कई और थांद्रा दोनों औषधीय गुण वाले हैं। धूपम, एर्रापोलीची.....” वह विभिन्न पेड़ों, पौधों, और झाड़ियों के नाम बताते चले गए।

कृष्णमूर्ति को यह विचार तुरन्त पसन्द आ गया और वे कई रातों तक सुब्बारायप्पा और सुब्बन्ना के साथ जंगलों में गए और पौधे इकट्ठा किए। इस तरह हमने अपनी वन पौधशाला में और पौधे जोड़े।

जलारी मनु की कहानी हमें जंगलों की विशालता की याद दिलाती है और हमें विनम्रता से भर देती है। कृष्णमूर्ति आदिवासी बुजुर्गों के साथ एक पहाड़ी पर गए जो एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ जलारी मनु ने उगकर एक मूल चूषक इकट्ठा किया, और हमने इसे केन्द्र के पीछे वाले हिस्से में लगाया। साल-दर-साल, हमने इसे बड़ी प्रत्याशा के साथ बढ़ते हुए देखा और इसकी निगरानी की। जब कलियाँ दिखाई दीं, तो यह एक जश्न की एक वजह थी।

हालाँकि, कलियाँ फूल नहीं बनीं। हम हताश लेकिन दृढ़ संकल्पी थे, हमने इसे पौधशाला में पुनः उगाया और ध्यान से जंगल में पौधे लगाए। पौधे मर गए।

हम अभी भी जलारी मनु को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जंगल और इसकी विविधता के प्रति हमारी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई है।



कार्यक्रम ने तीन मुख्य दृष्टिकोणों—मूल स्थान से परे संरक्षण, वन जैव विविधता के प्रलेखन, स्थानीय जैव विविधता के इर्द-गिर्द सहयोगात्मक जानकारी जुटाने, पर्यावरण शिक्षा—के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण पर काम किया। जंगलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, कार्यक्रम ने जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर खाइयाँ बनाने, वृक्षारोपण करने, और बीज

बिखेरने का काम किया। इनमें से कई गतिविधियाँ स्कूलों या अधिगम केन्द्रों के शिक्षकों द्वारा संचालित की गईं।

मूल स्थान से परे संरक्षण

कार्यक्रम में बहुत पहले, आदिवासी बुजुर्गों के निकट सहयोग से क्षेत्र की जैव विविधता पर एक डेटाबेस तैयार किया गया था। डेटाबेस का उपयोग संकटापन्न और लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करने के लिए किया गया। फिर कार्यक्रम के तहत एक बीज द्रव्य बैंक (Germ Plasm Bank) बनाया गया, एक पौधशाला स्थापित की गई, और वनीकरण की गतिविधियाँ भी शुरू की गईं।

बीज बैंक

कैगल केन्द्र में बीज, कन्द, चूषक, आदि के रूप में देशी वनस्पतियों की 250 से अधिक प्रजातियों के बीज द्रव्य (बीजों) का संग्रह होता है। औषधीय रूप से महत्वपूर्ण देशी प्रजातियों के पुनरुत्पादन के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है।

इन्हें पौधशाला में विकसित किया गया है और इनमें से कई को केन्द्र के अधीन आने वाले क्षेत्र में वनीकरण स्थलों में पुनः रोपा गया जहाँ वे अब अच्छी तरह स्थापित हो गए हैं। पुनर्वनरोपण स्थलों पर पेड़ और झाड़ियाँ अब कई फल और बीज पैदा कर रहे हैं—जो एक स्थाई बीज द्रव्य संरक्षण प्रयास का पहला चरण है।

वन पौधशाला

वन पौधशाला विभिन्न देशी पौधों के लिए पुनरुत्पादन तकनीकों पर शोध, और अपने प्राकृतिक आवास में प्रत्यारोपण के लिए स्वस्थ पौधे विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करती है। पौधशाला लगभग 6,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली है। इसमें 50 प्रतिशत शेड कवर के साथ-साथ नए पौधों और नई बीज क्यारियों के लिए ट्री कवर भी हैं। लगभग 100 प्रजातियों के पौधों के लिए पौधशाला तकनीकें स्थापित की गई हैं। पौधशाला में पौधों की कम-से-कम 200 प्रजातियाँ विकसित की गई हैं और सार्वजनिक भूमि पर एवं जनजातीय गाँवों में वनीकरण प्रयासों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पौधशाला में विकसित किए गए सभी औषधीय पौधों और पेड़ों की प्रजातियों के लिए पुनरुत्पादन तकनीकें और सफल प्रत्यारोपण के तरीके स्थापित किए गए हैं। कई स्थानीय लोगों और छात्रों को बीजों के संरक्षण और पौधशाला के विकास एवं रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इच्छुक व्यक्तियों और संस्थानों को पौधे वितरित किए जाते हैं। भूमि पुनःस्थापन, जल संरक्षण, और वनीकरण कार्य के लिए इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

औषधीय पौधों का जड़ी-बूटी उद्यान

पौधों के बारे में स्थानीय पारम्परिक ज्ञान के साथ-साथ पारम्परिक चिकित्सा में विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक जड़ी-बूटी उद्यान (herb garden) स्थापित किया गया। सैक्चुअरी स्कूलों (Sanctuary Schools) के छात्रों और आदिवासी समुदायों की महिलाओं एवं युवाओं द्वारा जड़ी-बूटी उद्यान के ढाँचे को कई स्थानों पर दोहराया गया है। उन्होंने अपने स्कूलों और घरों में, निजी भूमि पर, तथा आदिवासी गाँवों में जड़ी-बूटी उद्यानों की स्थापना की है।

पारम्परिक ज्ञान का प्रलेखन

वन जैव विविधता

घटनाविज्ञान (Phenology) चक्रीय और मौसमी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, विशेष रूप से जलवायु और पौधों एवं पशु जीवन के सम्बन्ध में, जिसमें पौधों के फलने-फूलने पर मौसमी परिवर्तनों के प्रभाव शामिल हैं। यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि समुदाय को पौधों के फलने-फूलने के मौसम की जानकारी होनी चाहिए और यह बीज संग्रह के लिए भी आवश्यक है। 2010 के बाद से स्थानीय लोगों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन में व्यक्तिगत रूप से चिह्नित 170 पौधों में बदलावों का समय-समय पर अभिलेखन कर 17 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के सम्बन्ध में यह जानकारी व्यवस्थित रूप से एकत्र की गई है। संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी बुजुर्गों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है जिन्होंने जंगलों और पौधों के बारे में अपने पारम्परिक ज्ञान को साझा किया। इस ज्ञान को प्रलेखित किया गया है और इस जानकारी के आधार पर कई देशी औषधीय पौधे विकसित किए गए और उनकी संख्या में वृद्धि की गई।

स्थाई कटाई प्रथाओं का प्रलेखन

32 जनजातीय गाँवों में फ़िल्ड अध्ययन किए गए ताकि लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली स्थाई कटाई प्रथाओं को समझा जा सके। कार्यक्रम ने जाना कि वनों की रक्षा का मतलब वनों पर निर्भर लोगों की आजीविकाओं के प्रति संवेदनशील होना है। इसमें वन स्थिरता की चिन्ताओं को सम्बोधित करने के साथ-साथ पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों दृष्टि से जैव-संसाधन की वास्तविक लागत को प्रतिबिम्बित करने वाली वनोपज का उचित मुआवज़ा प्रदान करना शामिल था।

पारम्परिक वन संग्राहकों ने अक्सर वनोपज और जैव-संसाधनों की कटाई उन तरीकों से की, जिनसे सम्बन्धित प्रजातियों की वन आबादी की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। हालाँकि, वाणिज्यिक शोषण के परिणामस्वरूप वनों पर बढ़ते दबाव के साथ, अब जैव-संसाधनों की

कटाई उन तरीकों से की जा रही है, जो वनों की स्थिरता के लिए ख़तरा पैदा करते हैं और जनजातीय आजीविकाओं को नष्ट करते हैं। नीचे वर्णित आजीविका कार्यक्रम संरक्षण और पर्यावरण सम्बन्धी इन अत्यावश्यक चिन्ताओं से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। टिकाऊ प्रथाओं के प्रलेखन की इस परियोजना का उद्देश्य यह ज्ञान संकलित करना था कि जैव-संसाधनों को पारम्परिक रूप से कैसे काटा जाता था और वे किस प्रकार के जैव-संसाधन थे जो पहले काटे जाते थे और अब भी काटे जाते हैं। इस तरह की एक समुदाय-आधारित डेटा-संग्रहण क़वायद का समुदायों के जीवन जीने के तरीकों और उनके पारम्परिक ज्ञान के बारे में उनकी आत्म-स्वीकृति की भावना पर भी एक लाभप्रद प्रभाव पड़ा। इस तरह एकत्र किए गए प्राथमिक ज्ञान का उपयोग स्थाई वन प्रबन्धन प्रथाओं को विकसित करने के लिए किया जा सकता है और शायद इच्छुक समुदायों के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है जो वन-आधारित आजीविका को स्थाई रूप से अपनाएँगे।

स्थानीय शासन संस्थानों के भीतर संरक्षण को संस्थागतस्वरूप प्रदान करना

स्थायी वन प्रबन्धन प्रथाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के साथ जैव संसाधनों को साझा करने के लिए निष्पक्ष प्रथाओं को अब एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी जा रही है, और इसे जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) में व्यक्त किया गया है।

जैव विविधता मण्डलों (Biodiversity Boards) द्वारा पंचायत स्तर पर जैव संसाधनों का प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में जैव विविधता प्रबन्धन समितियों (Biodiversity Management Committees—BMCs) की स्थापना की जा रही है। जब जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ अपनी भूमिकाओं और कार्यों को ठीक से समझेंगी, तो उनके पास अपने क्षेत्रों के भीतर विभिन्न जैव-संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने की क्षमता होगी और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबन्धन समितियों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले इन संसाधनों के लिए उचित मूल्य भी निर्धारित किए जा सकेंगे। इस प्रकार जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ ज़मीनी स्तर पर जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से पूरा और क्रियान्वित करने के लिए काम करेंगी। कैगल प्रोग्राम आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड (Andhra Pradesh State Biodiversity Board—APSBB) के लिए एक तकनीकी संसाधन समूह (Technical Resource Group—TRG) रहा है और जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ स्थापित करके और समुदायों के बीच जैव विविधता अधिनियम, 2002 के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए उसने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की इस महत्वपूर्ण पहल में सहयोग किया है।

सामुदायिक-ज्ञान आधारित डेटाबेस तैयार करना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से, कार्यक्रम ने पंचायत स्तर पर एक लोक जैव विविधता रजिस्टर (Peoples' Biodiversity Register—PBR)^{vii} और ज़िला स्तर पर एक विनिमय योग्य संसाधन रजिस्टर (Tradeable Resources Register—TRR) बनाने में मदद की। यह प्राथमिक डेटाबेस देशभर में विकसित किए गए हैं और इनका उद्देश्य स्थानीय जैव-संसाधनों के साथ-साथ उन पर निर्भर समुदायों का संरक्षण करना है। उनमें प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या, मौजूदा पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों, जानकारों, किसानों, और चिकित्सकों एवं उनकी कार्यप्रणालियों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है।



सहयोगात्मक ज्ञान सृजन

- औषधीय पौधों और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करना
- जानकारों का नेटवर्क बनाना
- समुदाय-आधारित संगठनों से सम्बन्ध
- स्थानीय जैव विविधता के सामुदायिक ज्ञान की पुष्टि



इन डेटाबेसों में स्थानीय भूमि के उपयोग के अद्यतन नक्शों के साथ-साथ जैव विविधता डेटा शामिल हैं और यह व्यापक प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से विकसित किए गए थे। यह क़वायद विभिन्न हितधारकों—स्थानीय समुदाय, वन विभाग, स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय सरकारी निकायों, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित वैधानिक निकायों, और कार्यक्रम अनुसन्धान टीम के विशेषज्ञों—को एक साथ लाने में कामयाब रही। ज्ञान सृजन की इस प्रक्रिया ने डेटा संग्रहण और अनुसन्धान के वैज्ञानिक तरीकों के विषय में इन समुदायों के युवाओं और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के अलावा स्थानीय समुदायों की स्वदेशी ज्ञान प्रणाली कायम रखने में मदद की। एम. कोथुर, वेंगामवरिपल्ली, और कांगुंडी जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के लिए लोक जैव विविधता रजिस्टर विकसित करने, और चित्तूर तथा अनंतपुरम ज़िलों के लिए विनिमय योग्य संसाधनों की जानकारी एकत्र करने के लिए संचालित किए गए फ़ील्ड अध्ययनों से हमें नए जैव-संसाधनों (मूल्य संवर्धन के लिए) की पहचान करने के आवश्यक अवसर प्राप्त हुए। फ़ील्डवर्क ने अपार अवसर प्रदान किए, जिसके परिणामस्वरूप बहुत ही जानकार लोगों के साथ सम्बन्ध बने, और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।

समुदायों के साथ सम्पर्क निर्माण के लिए शिक्षा

आदिवासी समुदायों के लिए प्रासंगिक रूप से उचित शिक्षा

टिकाऊ होने के लिए, समुदाय के पास कार्यक्रम का 'स्वामित्व' होने और सम्बन्धित संचालनों एवं गतिविधियों में सहयोग करने की आवश्यकता है।

आदिवासी समुदायों के पास प्राकृतिक संसार और स्थानीय जंगलों के बारे में अत्यन्त मूल्यवान स्वदेशी ज्ञान का ज़बरदस्त भण्डार है, और वे स्थानीय पारिस्थितिकी तथा अपनी जीवन शैली के बीच सम्बन्ध को सहज रूप से समझते हैं। हालाँकि, स्कूलों, विकास कार्यक्रमों, और, हाल ही में मीडिया के माध्यम से आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ उनके लिए पढ़ना-लिखना सीखने और एक अधिक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की कथित आवश्यकता है।

स्कूलों को तीन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा :

- एक उत्तरदायी, प्रासंगिक, और दिलचस्प पाठ्यक्रम विकसित करना जो छात्रों के और जिन समुदायों से वे आते हैं उनके ज्ञान, जीवन के अनुभवों, और पारम्परिक कौशलों को महत्व देता हो;
- औपचारिक स्कूली शिक्षा की प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को समझने में मदद करने के लिए समुदाय के साथ काम करना;
- शिक्षक विकास की प्रक्रियाओं की ऐसी रूपरेखा तैयार करना जो अधिगम में सुविधाप्रदाताओं के रूप में उनकी भूमिका में मदद करे जिसमें स्कूल के प्रत्येक सदस्य का विकास हो सके, सीखे, और रूपरेखा यह मानती हो कि शिक्षकों का विकास अपने-आप में स्कूलों का एक उद्देश्य है।

मुगिलुपोडालरेवु और कल्लीगुट्टा गाँवों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत दो प्राथमिक स्कूल स्थापित और पंजीकृत किए गए। इन्हें समुदाय के सहयोग से स्थापित किया गया, जो अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का इच्छुक था। स्कूल के लिए भूमि समुदाय द्वारा उपलब्ध कराई गई और स्कूल का बुनियादी ढाँचा विभिन्न दान दाताओं से प्राप्त दान से विकसित किया गया।



सैक्चुरी स्कूलों की दूरदृष्टि

1. स्थानीय ज्ञान को स्कूल के पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा स्कूल को शिक्षा पर सामुदायिक संवाद को प्रभावित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्कूल की मुख्य गतिविधियों में से एक वन अध्ययन है जहाँ गाँव के बुजुर्ग छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद करते हैं और अपना ज्ञान उनके साथ साझा करने के लिए उन्हें जंगलों में ले जाते हैं।
2. शिक्षक सहानुभूति रखने वाले वयस्क होने चाहिए जो आदिवासी समुदायों के बच्चों को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करें और उनके साथ सम्मान और सौम्यता का व्यवहार करें। स्थानीय गैर-आदिवासी समुदायों के शिक्षक होने से विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने में मदद मिलती है।
3. आदिवासी समुदाय बहुभाषी हैं, और शिक्षा का माध्यम बच्चे की पहली भाषा में होना चाहिए। अंग्रेज़ी को वरिष्ठ छात्रों के लिए दूसरी भाषा के रूप में पेश किया जा सकता है। खेलने, समुदाय-आधारित कार्य, रचनात्मक खोज, और मौन, चिन्तन एवं आत्मनिरीक्षण के लिए छात्रों और शिक्षकों दोनों को अवसर उपलब्ध होना चाहिए।
4. कौशल-आधारित कार्य, जैसे-सिलाई और कसीदाकारी का परिचय-जो स्कूल को स्थानीय महिलाओं के एक उद्यम से जोड़ता है, अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए, जिससे छात्रों और शिक्षकों को सार्थक कार्यों का महत्व समझने में सक्षम बनाया जा सके।



स्कूलों ने छात्रों को पढ़ने और लिखने के आयु-उपयुक्त कौशलों के अलावा खेल से लेकर रचनात्मक गतिविधियों जैसे चित्रकला, मिट्टी के बर्तन बनाना, संगीत, और व्यावहारिक हस्त शिल्पों से परिचित कराया है। छात्रों को संरचित आयोजनों में भाग लेने तथा शैक्षणिक, कला, और खेलों में शामिल करके अपने गाँव के बाहर की दुनिया के साथ सम्पर्क में आने के लिए

प्रोत्साहित किया जाता है।

स्कूल पाठ्यक्रम में प्रकृति संरक्षण को एकीकृत करना

स्कूल समुदाय के साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ ही पानी, ईंधन और अपशिष्ट प्रबन्धन के मुद्दों को उठाने और सम्बोधित करने के कार्य में भी संलग्न रहे। स्कूलों का इको-स्कूल कार्यक्रम (Eco-schools programme) में पंजीकरण किया गया, जो फ़ाउण्डेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (Foundation for Environment Education—FEE) का एक अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम है। इसका मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क में है। यह विभिन्न पर्यावरणीय विषयों को सम्बोधित करने में स्कूलों का मार्गदर्शन करता है, और स्थिरता को स्कूली जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए एक सरल ढाँचा प्रदान करता है। स्कूलों द्वारा उठाए गए पर्यावरणीय विषय—जैव विविधता, ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबन्धन, जल और स्वस्थ जीवन—थे।

इको-स्कूल कार्यक्रम का प्रभाव पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में परियोजना अवधि से इतना आगे बढ़ गया कि यह मुख्य स्कूल पाठ्यक्रम में पारिस्थितिक चिन्ताओं को प्रदर्शित करने में सक्षम रहा और इसने उन्हें पाठ्यक्रम में एकीकृत करने में भी मदद की, और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर समुदाय और स्कूलों को जोड़ा है। इसने शिक्षकों का पेशेवर और व्यक्तिगत विकास भी सम्भव बनाया है, और पर्यावरण की देखभाल के महत्त्व के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ाई है।



एक सामुदायिक केन्द्र के रूप में स्कूल

छात्रों के साथ बातचीत के दौरान, हमने यह पता लगाने का प्रयास किया कि कैसे एक गैर-पदानुक्रमित कक्षा-कक्ष और एक सहानुभूति रखने वाला शिक्षक आदिवासी समुदाय के पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले बच्चों के मनोसामाजिक सन्दर्भ को बदलने में मदद कर सकते हैं। स्कूलों ने समुदाय के भीतर शिक्षा पर संवाद को बदलने का एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदान दिया है। साक्षात्कार में आए कई छात्रों ने उनके द्वारा स्कूल में प्राप्त शिक्षा से जुड़ी आकांक्षाओं की बात की। उनमें से कुछ अपने गाँव को बदलना चाहते थे, कुछ अच्छे शिक्षक बनना चाहते थे, और इसके अतिरिक्त कुछ ने अच्छी नौकरियाँ पाने की बात कही। उनमें से एक ने कहा कि वह समाज की भलाई में योगदान देना चाहती थी, और दूसरा वन अधिकारी बनना चाहता था।

सभी छात्रों ने अपने माता-पिता के साथ स्कूल के बारे में चर्चा करने की जानकारी दी, एक ऐसा कार्य जो अधिक स्थाई प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। यह दर्शाता है कि बच्चे अपने परिवार के साथ स्कूल के बारे में बात करने को पर्याप्त महत्वपूर्ण समझते हैं और यह कि स्कूल समुदाय के लिए प्रासंगिक है।

एक चाँदनी रात में, शाम लगभग 8.00 बजे, सुब्बारायप्पा आदिवासी गाँव मुगिलुपोडालरेवु में एक कमरे के चमनठी स्कूल में प्रवेश करते हैं। वे मुस्कुराते हैं और कमरे में इकट्ठे अन्य वयस्कों के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षक एक कक्षा को सम्बोधित कर रहा है जो उस कक्षा से काफ़ी अलग है जिसे वह दिन में पढ़ाता है। सुब्बारायप्पा कहते हैं, “अगर मैं पढ़ता हूँ, तो दूसरे मेरा अनुसरण कर सकते हैं और वे भी सीखेंगे,” जैसा कि उन्होंने कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ अपनी यात्रा पर एक वीडियो साक्षात्कार के लिए तैयारी करते वक़्त और वनोपज के एक आदिवासी संग्राहक की जीवन शैली के बारे में बताया।

17 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गाँव कल्लीगुट्टा का दृश्य भी उतना ही दिलचस्प है, जहाँ आदिवासी महिलाएँ प्रतिदिन पढ़ना और लिखना सीखने के लिए पारिजातम सैंक्चुअरी स्कूल (Parijatham Sanctuary School) आती हैं, और जहाँ उन्हें अपने ही बच्चों में से एक के द्वारा पढ़ाया जाता है। “मैं अपने घर के बाहर बैठकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ूँगी, भले ही आपका कोई स्कूल न हो। आप कृपया हमें सिखाना जारी रखें, हम आएँगे,” राजम्मा, एक यानदी आदिवासी महिला, गर्व के साथ कहती हैं।



पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम

पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम स्कूलों और छात्रों के साथ एक स्थाई और पारिस्थितिक दृष्टि से उत्तरदायी जीवन शैली से सम्बन्धित सम्भावनाएँ, चुनौतियाँ, और रणनीतियाँ साझा करने के उद्देश्य से शुरू हुआ। कार्यक्रम समुदायों को एक साथ लाता है, और सीखने के लिए नए सन्दर्भ निर्मित करता है, खासकर शहरी पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए। प्रतिभागियों को साधारण परिस्थितियों में प्रकृति के करीब रहने का अवसर प्रदान करना; प्राकृतिक पर्यावरण के साथ फिर से जोड़ना; और प्राकृतिक संसार के साथ हमारे सम्बन्धों को प्रत्यक्ष रूप से समझाना इस कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य हैं।



एक चिकित्सक, हैदर पाशा, के साथ जानकारी का प्रलेखन, जो पशुओं के उपचार में विशेषज्ञ हैं

कार्यक्रम में शामिल गतिविधियाँ और अनुभव युवाओं को प्राकृतिक संसार की सुन्दरता और व्यवस्था का अवलोकन करने और उसे सराहने का अवसर प्रदान करते हैं। उनकी रुपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि वे जीवन के सभी रूपों के प्रति संवेदनशीलता को गहराई प्रदान करें, सम्मान विकसित करें, और उनके बारे में जिज्ञासा पैदा करें।

कार्यक्रम अलग-अलग अवधि के हैं, और उनका दायरा समूह की प्रकृति—छात्र, प्रशिक्षु (interns), या शिक्षक—पर निर्भर करता है। प्रत्येक कार्यक्रम की सामग्री समूह की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। सैक्चुअरी स्कूलों के शिक्षक और आजीविका पहलों के सदस्य इन कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। गतिविधियों में प्रकृति का शान्तिपूर्वक अवलोकन करने के लिए वनों की लम्बी पैदल सैर और वन संरक्षण कार्य में भागीदारी (वर्षाजल खाइयों का निर्माण, वन पौधशाला में काम करना, वनीकरण करना, आदि) शामिल हैं।

प्रतिभागियों को जैव विविधता अध्ययन में भी शामिल किया जाता है। वे आदिवासी समुदायों और सैक्चुअरी स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद करते हैं। वे खेतों में जाते हैं और किसानों के साथ काम करते हैं तथा स्थानीय शिल्प सीखते हैं।

प्रतिभागी, विशेष रूप से शहरी स्कूलों के छात्र, पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक सन्तुलन के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं, जीवन के विभिन्न रूपों के बारे में अधिक जागरूक और उन्हें स्वीकार करने वाले बनते हैं, और वन्य जीवन के बारे में अपने डर पर क़ाबू पाते हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसार का अनुभव प्राप्त करते हैं और प्रकृति की सुन्दरता की सराहना करते हैं। उन्हें अहसास होता है कि जंगलों और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के लिए ख़तरा बहुत

वास्तविक है, और वे समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। गाँवों में वयस्कों के साथ-साथ सैक्युअरी स्कूलों में बच्चों के साथ व्यापक संवाद कार्यक्रम में शामिल है।

आजीविका कार्यक्रम

स्थिर समुदायों के लिए आजीविका

ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के एकीकरण को कई देशों में लागू किए जा रहे विकास मॉडल की तरफ वापस लाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में, ग्रामीण आजीविकाओं के अवसर पैदा करने और बनाए रखने के लिए ऐसे प्रासंगिक कौशल आवश्यक हैं जो इस सन्दर्भ में संरक्षण में सहयोग प्रदान कर सकें।^{viii} देशभर में जैव-भौगोलिक क्षेत्रों की विशाल विविधता को देखते हुए, भारत जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। सदियों से, लोगों का जीवन उनके स्थानीय परिवेशों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की आजीविकाएँ प्रचलन में हैं। इनमें पारम्परिक शिल्प और कला के विभिन्न स्वरूप, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना, वन-आधारित आजीविकाएँ, लोक चिकित्सा, और औषधीय परिपाटियाँ शामिल हैं। पिछली तीन शताब्दियों में उद्योगीकरण, शहरीकरण, और तेज़ी से हुए आर्थिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भू-उपयोग के स्वरूपों और भूस्वामित्व अधिकारों में बड़े बदलावों के बावजूद, कई लोग आज भी अपनी पारम्परिक आजीविकाओं में लगे हुए हैं।

आजीविका के पारम्परिक स्वरूपों का संरक्षण की पारम्परिक प्रथाओं और स्थानीय पारिस्थितिकी की एक आन्तरिक समझ के साथ करीबी सम्बन्ध है। गैर-काष्ठ वनोत्पाद संग्रहण की कई पारम्परिक प्रथाओं में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रक्रियाएँ अन्तर्निहित हैं। हालाँकि, जंगलों, उपजाऊ खेतों, आर्द्रभूमि, मौसमी नदियों, और इन सभी प्राकृतिक आवासों द्वारा पोषित जीवन के विविध रूपों में तेज़ी से कमी के साथ, पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविकाओं के बीच यह सहजीवी सम्बन्ध लगातार नष्ट हो रहा है, और इसके साथ ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों की सम्बद्ध ज्ञान प्रणाली भी लुप्त हो रही है। इसके अलावा, कच्चे गैर-काष्ठ वनोत्पादों के लिए कम पारिश्रमिक का अर्थ है कि पहले से ही घटते जा रहे जैव संसाधनों की अधिक कटाई पर अधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। लोगों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त कमाई करने में समर्थ होने के लिए बड़ी मात्रा में वनोपज एकत्र करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, कच्चे माल के लिए कम बाज़ार मूल्य और उच्च आय प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कटाई के एक दुष्चक्र से प्राकृतिक जैव-संसाधनों का अति-दोहन और कमी हो जाती है। जंगल की दुर्दशा के कारण लोगों का अधिक शोषण होने लगता है और इसके परिणामस्वरूप अधिक तेज़ी से तथा अधिक व्यापक दुर्दशा होती है। यह दुष्चक्र जंगल को और साथ ही उस समुदाय की आजीविका को नष्ट कर

देता है जो उस पर निर्भर करता है, और इससे आजीविका की तलाश में पलायन होता है—जो सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से विनाशकारी है।



कालिम्बी रास्ता दिखाता है

बोरी में जंगल से एकत्र किए गए 20 किलो जंगली फल थे। मामला सभी खाने योग्य फल लाने का था, और वे वहाँ थे, सभी बोरी में बँधे थे। कैगल की टीम ने फलों को भाप से पकाया, बीज निकले, मसला, और छाना, तथा फिर मिश्रण को पाँच घण्टे तक लकड़ी की आग पर उबलते हुए धैर्यपूर्वक देखा।

इस प्रकार कैगल में पहली बार कालिम्बी जैम बनाया गया। यह कई उत्पादों में से एक था जो अन्ततः एक नए उद्यम की स्थापना की ओर ले जाएँगे। केन्द्र के लोगों ने खुद से पूछा : क्या स्थानीय और वनोत्पादों को उन उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है जो समुदायों द्वारा बाज़ार में ले जाई जाने वाली कच्ची उपज की तुलना में अधिक मूल्य दिला सकें? क्या यह रूपान्तरण उपज की जीवनावधि बढ़ा सकता है? क्या उनके उत्पादों पर अधिक प्रतिफल समुदायों को संरक्षण एवं वनोपज की और

सतत कटाई के लिए प्रोत्साहित करेगा?

एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता थी जो यह प्रदर्शित कर सके कि जंगल का स्थाई उपयोग समुदाय को अन्य आर्थिक अवसर प्रदान कर सकता है, जो ग्रामीण और आदिवासी लोगों को बड़े समुदाय का हिस्सा होने के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान कायम रखने की अनुमति दे।

और इसलिए एक स्वयं-सहायता समूह का विचार उभरा।



इस उद्यम का उद्देश्य टिकाऊ आजीविकाओं के विकास और महिलाओं एवं युवाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के लिए एक समुदाय-केन्द्रित दृष्टिकोण का विकास और पोषण करना है। कार्यक्रम नए व्यवसाय निर्मित करने और मौजूदा आजीविकाओं को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए आसपास के गाँवों के युवा वयस्कों और महिलाओं के साथ काम कर रहा है। स्थानीय समुदायों के साथ काम करते हुए, कार्यक्रम ने



प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं कल्लीगुट्टा गाँव की महिलाएँ

प्रमुख ग़ैर-काष्ठ वनोत्पाद प्रजातियों की पहचान की, ग़ैर-काष्ठ वनोत्पादों के स्थानीय उपयोगों का प्रलेखन किया, और साधारण मूल्यवर्धन के माध्यम से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पाद बनाए।

2009 में, आजीविका निर्माण की पड़ताल करने के लिए पहली महिला कैगल टीम में शामिल हुई। वह कैगल गाँव की एक युवती थी जो पूर्व में वन संरक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित किए गए आउटरीच कार्यक्रम से प्रेरित थी। 2010 में, कैगल ट्रस्ट सेल्फ़ हेल्प ग्रुप (Kaigal Trust Self Help Group—KTSHG) का गठन उन तरीकों का पता लगाने के लिए किया गया जिनके माध्यम से स्थानीय उत्पाद और वन जैव-संसाधनों का प्रसंस्करण किया जा सके और उन्हें बाज़ार ले जाया जा सके। कैगल ट्रस्ट सेल्फ़ हेल्प ग्रुप एक छोटी-सी पहल थी, जिसमें लगभग चार या पाँच लोगों से मुख्य समूह निर्मित होता था। इसने लगभग 25 यानदी संग्राहकों के एक समूह के साथ नेटवर्क बनाया, जिसने प्रारम्भिक चरण के दौरान कैगल ट्रस्ट सेल्फ़ हेल्प ग्रुप को आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति की। आज, कैगल ट्रस्ट (KTSHG का परिवर्तित नाम) का सालाना कारोबार 25 लाख रुपये है और यह आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के 12 महिलाओं और पुरुषों के एक समूह के साथ काम करता है।

उत्पादों को बनाने और बेचने के अलावा, इस कार्यक्रम ने आदिवासी और सीमान्त कृषक समुदायों की महिलाओं एवं युवाओं के एक समुदाय-आधारित उद्यम के गठन और क्षमता

निर्माण में मदद की है। वे एक उचित मूल्य पर जैव-संसाधन और कृषि उत्पाद प्राप्त करते हैं, साधारण मूल्यवर्धन तकनीकों का उपयोग करते हैं, और अन्तिम उपभोक्ताओं तक यह उत्पाद पहुँचाते हैं। स्थानीय महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित कर इस उद्यम में नियोजित किया जाता है, जो एक स्थानीय स्वयं सहायता समूह के सिद्धान्तों के अनुरूप संगठित किया जाता है।

सामुदायिक कौशल विकास

महिलाओं और युवा वयस्कों को अचार और विशेष रूप से बहुतायत में उपलब्ध स्थानीय उपज के लिए विकसित अन्य परिरक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए वनोत्पादों के मूल्यवर्धन के विभिन्न तरीके सिखाए गए। महिलाओं और बड़ी लड़कियों को सिलाई, और कढ़ाई सिखाई गई। इसके अलावा, उन्होंने बुनाई, क़सीदाकारी, टोकरी बनाना, और मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। इन कौशलों का उपयोग वे हाथ से क़सीदाकारी, सिलाई कर बेचने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री का उत्पादन करने के लिए करती हैं। पौधे, विशेष रूप से औषधीय पौधे और देशी फल, सब्ज़ियाँ और फूलों के पौधे उगाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कैगल ट्रस्ट के सदस्यों को पैकिंग और मार्केटिंग, स्टॉक कीपिंग, अकाउंट्स, और सेल्स रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण दिया गया है। कैगल ट्रस्ट स्कूलों में बच्चों के लिए कौशल विकास में सहयोग करता है और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ा हुआ है। सदस्य गर्व के साथ बताते हैं कि उन्हें अपना स्वयं का व्यवसाय संचालित करना अच्छा लगता है।

पहुँच और लाभ के सहभाजन का मॉडल

कैगल ट्रस्ट अपना कच्चा माल विभिन्न पंचायतों से प्राप्त करता है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत, इसने वन भूमि से एकत्र किए जाने वाले जैव संसाधनों के बारे में आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के साथ पहुँच और लाभ के सहभाजन का समझौता (Access and Benefit Sharing Agreement—ABSA) किया है। इस सामुदायिक उद्यम में, स्थानीय महिलाएँ और युवा जैव-संसाधनों तक पहुँच के लिए और उन्हें उत्पादों के रूप में बाज़ारों में ले जाने से पहले उनमें मूल्यवर्धन के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करते हैं। यह लोगों को एक साथ लाने के साथ-साथ कौशल के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामुदायिक केन्द्र के रूप में कार्य करता है।^{ix} स्थानीय उद्यम एक पहुँच और लाभ सहभाजन प्रक्रिया के लाभों को प्रदर्शित करने में सक्षम रहा है जो सम्भवतः इसी तरह के सामुदायिक नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए एक मॉडल हो सकता है जो स्थानीय और वन जैव-संसाधनों पर निर्भर हैं।

बदलाव के व्यक्तिगत वर्णन

यह कार्यक्रम एक बहुत ही तात्कालिक उद्देश्य के साथ आरम्भ हुआ, जो यह था कि भूमि की रक्षा करने के लिए—वृक्ष लगाए जाएँ, चराई को न्यूनतम किया जाए, और पर्यटन के प्रभाव को भी कम किया जाए—कैगल जलप्रपात यहाँ का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। इस कार्यक्रम की संकल्पना करने वाली टीम के लिए, यह कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सहारा मात्र था। परिवर्तन अधिक जटिल और अधिक गहरा था, व्यक्ति और समुदाय को बदलने वाला, और साथ ही साथ, स्थानीय पारिस्थितिकी के साथ उसके सम्बन्ध, और उसके भीतर उनकी स्थिति की पुष्टि कर रहा था और उसमें बदलाव ला रहा था।

कैगल घाटी में अधिक बारिश होती है। कैगल संरक्षण केन्द्र में रसोई के पास से जंगल की ढलानों को देखते हुए जयपालप्पा गर्व के साथ कहते हैं, “वे कहते हैं कि कैगल में अब अधिक बारिश होती है क्योंकि अब यहाँ अधिक पेड़ हैं।” एक दशक की अवधि में किए गए वनीकरण, छात्रों और स्थानीय समुदायों के काम की बदौलत, केन्द्र को अब पहचान पाना मुश्किल है जो उस वृक्ष एक बंजर परिदृश्य था जब छात्रों का पहला समूह यहाँ पहुँचा था। उन्हें खुद के भरोसे छोड़ दिया गया, तो जंगल वापस बढ़ गए हैं; यह सचमुच इतना आसान है।

जयपालप्पा को पता होना चाहिए। उसने कई महीनों तक जंगलों में घूमकर 13 से अधिक पेड़ों की प्रजातियों से सम्बन्धित घटनाविज्ञानी डेटा (phenological data) का प्रलेखन किया। वन विभाग कैगल केन्द्र की पौधशाला से पौधे लेता है। जयपाल ने एक किशोर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और उसने 12वीं कक्षा पूरी कर ली थी ताकि वह “कोई भी” काम कर सके। पिछले कुछ वर्षों में, उसने पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियाँ हासिल कीं और एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया। अब वह पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने के अलावा दो स्कूलों के संचालन का निरीक्षण करता है। उसने फ़ील्ड वर्क के तरीके सीखे हैं, साँपों को संभालता है, और छात्रों के लिए फ़ील्ड-आधारित कार्यक्रम संचालित कर सकता है। शिक्षा के प्रति गहरी लगन के साथ, वह छात्रों के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है और उसका मानना है कि सैक्चुरी स्कूल ऐसे स्थान हैं जहाँ छात्र अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीख सकते हैं, और जहाँ वे इसमें अपनी सही जगह पाने में सफल हो सकते हैं। वह यह कहते हुए तेज़ी से चला गया कि अब वह बेंगलूरु से आने वाले छात्रों को दिखाने के लिए एक साँप ढूँढ़ेगा।

हाँ। एक सरल शब्द में, रघुपति ने बताया कि अहमदाबाद, गुजरात में एक ग्रेनाइट-पॉलिशिंग फर्म की नौकरी छोड़ने के बाद जब वह अपने गाँव लौटा तो उसके लिए जीवन कैसे बदल गया। करीब 13 साल की उम्र तक रघु मुगिलुपोडालरेवु शिक्षा केन्द्र में एक शर्मीले छात्र था, लेकिन उसने हाई स्कूल जाने से इंकार कर दिया। उसके हाथ जादू पैदा कर सकते थे—पौधशाला में पौधों के साथ, कढ़ाई के धागे के साथ, क़सीदाकारी में, मिट्टी के साथ, और एक

स्केचिंग पेंसिल के साथ। उसने आजीविका कार्यक्रम में काम किया जब यह पहली बार 2008 में शुरू हुआ—बोतलों में शहद भरने और पौधशाला की देखभाल का काम। एक दिन वह एक ग्रेनाइट-पॉलिशिंग फर्म में काम करने के लिए अहमदाबाद भाग गया। लेकिन, बस अचानक, वह कैगल केन्द्र लौट आया, पौधशाला और अपने बचपन के उसी जंगल में। वह क्यों चला गया था यह समझाने में वह असमर्थ है, लेकिन वह दृढ़ता से कहता है कि वह यहाँ रहने के लिए आया है। वह अब जयपाल के साथ पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम संचालित करता है, बच्चों को वन पौधशाला क्रायम रखने के महत्त्व के बारे में सिखाता है और उन्हें जंगलों में ले जाता है।

मैं कहीं भी जाकर काम नहीं करूँगी। सुमित्रा ऐसा कहती है जिसकी ताक़त उसकी नन्ही काया को झुठलाती है। मुगिलुपोडालरेवु शिक्षण केन्द्र में एक शिक्षक के रूप में कार्यक्रम में अपने प्रवेश के बारे में बात करते हुए उसने कहा, “मैंने पहली बार प्रवेश लेने पर सोचा कि यह किस तरह का स्कूल है।” तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एक शिक्षिका थी और उसने दूसरे गाँवों में भी शिक्षण केन्द्र स्थापित करने और प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करने में मदद की। आजीविका कार्यक्रम की पहली सदस्य के रूप में, उसने सभी कौशल सीखे—सिलाई, क़सीदाकारी, शहद प्रसंस्करण, अचार बनाना, पैकिंग, बिक्री, और लेखांकन। अब वह सम्पूर्ण कार्य का प्रबन्धन करती है। उसकी माँ कैंसर से मर रही थी, लेकिन सुमित्रा टीम के साथ, बिना किसी रासायनिक योजक के ताज़ा गुड़ छानने और इकट्ठा करने के लिए बाहर गई हुई थी। वह बताती है, “मुझे गुड़ छानने और इकट्ठा करने के लिए वहाँ होना चाहिए—उसमें कोई कीचड़ नहीं होना चाहिए।” सुमित्रा ने स्थानीय समुदायों की महिलाओं और पुरुषों की एक टीम बनाई है जो अपने काम पर गर्व करते हैं। जब इस केस स्टडी के लिए साक्षात्कार किया गया, तो उन सभी ने एक बात कही—कि उनके जुड़ाव ने भीतर उनके लिए कुछ बदल दिया है। उन सभी ने इस बारे में बात की कि उन्होंने क्या सीखा है और वे कौन हैं। पुष्पा कहती है, “आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं प्रबन्ध कर सकती हूँ।” वह एक एकल अभिभावक है जिसने अपनी बच्ची को यह प्रेरणा देते हुए बड़ा किया है कि वह भी सीखने का वही मार्ग अपनाए जो उसने खुद अपनाया था। “मैं एक इंटर पास थी। अब मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है।” पुष्पा अब कम्प्यूटर पर बहीखाता रखना सीख रही है।

“मैंने क्या नहीं सीखा है?” कृष्णमूर्ति ने अपनी यात्रा के बारे में पूछे जाने पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम के युवा समन्वयक से लेकर एम. कोथुर गाँव के सरपंच होने तक की यात्रा का उल्लेख किया। “मैंने जो कुछ भी सीखा है, वह यहाँ काम करने से ही सीखा है—कोई भी काम ठीक से कैसे किया जाए, यह मैंने यहीं सीखा है। मुझे लोगों से बात करने, मिलने में डर लगता था। जब हमने यह स्थान आरम्भ किया, तब यह एक पर्यटन स्थल था। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थीं जो अच्छी नहीं थीं। वहाँ से, हमने यहाँ यह कार्यक्रम और स्थान स्थापित किए।” लगभग 2010 तक जब तक वह सरपंच नहीं चुने गए

तब तक कृष्णमूर्ति ने कार्यक्रम के साथ पूर्णकालिक काम किया, लेकिन वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गतिविधियों से जुड़े रहे। “जब छात्र पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए आते हैं, तो इससे समुदायों को फ़र्क पड़ता है। वे यहाँ आने वाले छात्रों को आते और काम करते हुए देखकर खुश होते हैं। हम अच्छा काम करने के लिए जाने जाते हैं,” वे गर्व के साथ कहते हैं।

समुदाय उद्यम का स्वामी है। “कैगल ट्रस्ट को आपूर्ति करना शुरू करने के बाद, मैं पैसे बचाने में सक्षम हूँ। मैंने बकरियाँ ख़रीदी हैं। मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं”, कैगल से लगभग 40 किमी दूर नादमनथरम गाँव के रघुरमैया कहते हैं। “आप हमें समय पर और ठीक तरह से भुगतान कर रहे हैं। इससे मदद मिलती है। यदि आप नियमित रूप से संग्रहण [वनोपज] करते हैं, तो हम नियमित रूप से जंगलों में जा सकते हैं। यही काम हम ठीक से करना जानते हैं। आप हमारी महिलाओं को कोई कौशल सिखाकर गाँव में भी एक केन्द्र स्थापित क्यों नहीं करते?” उन्होंने मुझसे पूछा। चाहे वह शहद बेचने वाला आदिवासी हो, वेंकटगिरि कोटा में तेल चक्की का मालिक हो, या तीर्थम का किसान हो, यह बिलकुल स्पष्ट है कि समुदाय के सदस्य अपने उत्पाद कैगल ट्रस्ट को बेचने से लाभान्वित हो रहे हैं।

“मैं इन्हें [मेरे उत्पाद] बहुत कम मुनाफ़े पर कैगल ट्रस्ट को देता हूँ।” मैं उस काम का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो हमारे किसानों का सहयोग करता है और उन्हें यहाँ सुरक्षित रखता है। आपने [मुझसे] ख़रीदना शुरू किया, उससे पहले मैं सिर्फ़ छोटे-मोटे काम कर रहा था। अब आप [मेरे उत्पाद] नियमित रूप से ख़रीदते हैं, मेरी तेल की चक्की नियमित रूप से चलती है। मेरी दुकान पहले से बेहतर चल रही है। आप जो कर रहे हैं, उससे किसानों की मदद हो रही है,” तीर्थम के चावल आपूर्तिकर्ता बालाजी ने भी इसी तरह के विचार दोहराए।

मैं अपने कॉलेज का आनन्द लेती हूँ। सरिता जब कल्लीगुट्टा स्कूल में मुझसे मिलने आती है तो वह बहुत शर्माती है। उसने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (National Institute of Open Schooling—NIOS) के माध्यम से अपनी दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसने एक कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया, जिससे उसे नर्सिंग की डिग्री मिलेगी।

मैं उन्हें सिखाऊँगी। यह बात चंद्रकला ने कही जब हमने उससे पूछा कि क्या वह कल्लीगुट्टा में सामुदायिक संसाधन केन्द्र का संचालन करेगी। वह शुरू से ही कल्लीगुट्टा स्कूल की छात्रा थी। यहाँ से उसने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की, और अब एक स्नातक कार्यक्रम में नामांकन कराया है। वह एक शिक्षक बनने की आशा रखती है। वह अपने गाँव को एकजुट कर उसे एक अधिक स्वस्थ, अधिक शान्तिपूर्ण स्थान बनाने की दिशा में काम करने में मदद करना चाहती है।

निष्कर्ष

- विकास के एक स्थाई मॉडल के लिए समुदाय को एकीकृत तरीके से शामिल करने की आवश्यकता होती है। हमारे हस्तक्षेप का एक सीधा प्रभाव पड़ा है जिसे छात्रों के शैक्षिक प्रक्षेपवक्र (educational trajectory) और स्थानीय समुदायों के सदस्यों की सार्थक आजीविकाओं में देखा गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवर्तन समुदायों द्वारा कार्यक्रमों और गतिविधियों पर प्रतिक्रिया करने के तरीकों में अन्तर्निहित होते हैं। संरक्षण और शिक्षा के लिए सामुदायिक सक्रियता को टिकाऊ विकास की एक प्रभावी विधि के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह हस्तक्षेप मूलभूत और एकीकृत भी रहे हैं। हमारे स्कूल शिक्षक संरक्षण और जैव विविधता प्रलेखन में सक्रिय रूप से संलग्न हैं जबकि आजीविका उद्यम के सदस्य स्कूलों को सहयोग प्रदान करते हैं, और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्तियों (resource persons) के रूप में भूमिका निभाते हैं। एकीकरण महज़ एक कार्यनीतिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि कार्यक्रम के अन्तर्निहित दर्शन को भी प्रतिबिम्बित करता है।
- एक सहानुभूतिपूर्ण स्कूली वातावरण आदिवासी समुदायों के लिए सार्थक शिक्षा में मददगार हो सकता है। शिक्षक स्वयं परिवर्तन लाने वाले एजेंट बन गए हैं। कई शिक्षक स्कूल की वजह से उनके जीवन में आए अन्तर को स्वीकार करते हैं। उनमें से कुछ आजीविका कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। समुदायों की लड़कियाँ शादी के बाद अपने गाँवों में वापस चली जाती हैं क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का महत्व समझती हैं। लड़कियों की शादी की उम्र तेज़ी से आगे बढ़ी है। शैक्षिक ढाँचे के प्रति एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाने से, जिसमें शिक्षक, छात्र, अभिभावक, और स्थानीय समुदाय शामिल हैं, छात्रों के ठहराव और उनके जुड़ाव के सन्दर्भ में बेहतर शैक्षिक परिणाम हासिल हो सकते हैं। समुदाय के साथ रिश्ता स्थापित करने से शुरू होने वाले एक दीर्घकालीन रिश्ते से स्कूल को वैधता प्राप्त होती है और उसे एक ऐसे संसाधन संस्थान के रूप में अपने विकास में सक्षम बनाता है जो किसी आदिवासी समुदाय में विकास, शिक्षा, और कौशल विकास के लिए एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण अपना सकता है।
- समुदाय अधिक सशक्त हो रहे हैं। स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी, के खेती और अन्य सीमान्त आबादी के संरक्षण और आजीविका के बीच सम्बन्धों के बारे में समुदाय अधिक जागरूक हो रहे हैं। यह पारम्परिक ज्ञान के लोप को देखते हुए विशेष रूप

से प्रासंगिक है। सहभागी प्रक्रियाएँ और स्थानीय नेतृत्व तथा स्वायत्तता सामूहिक ज्ञान सृजन की कुंजी हैं। यह प्रक्रियाएँ ज्ञान सृजन के लिए साधन और साध्य दोनों हैं। सहानुभूतिपूर्ण प्रबन्धन दृष्टिकोण, जो समुदाय के जीवन, भाषा, और ज्ञान के तरीकों, इच्छित लक्षित लाभार्थियों को स्वीकार करते या उन्हें महत्त्व देते हैं, समुदाय का विश्वास जीतने और सम्पर्क निर्मित करने तथा सभी हितधारकों के साथ सम्बन्ध बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

- निरन्तर क्षमता निर्माण महत्त्वपूर्ण है। प्रभावी और सार्थक सहयोगात्मक ज्ञान प्रक्रियाओं के लिए निरन्तर और दृढ़ क्षमता निर्माण आवश्यक है। साम्प्रदायिक प्रयासों ने संस्थानों और विभिन्न ज्ञान प्रणालियों के लोगों को एक साथ लाने के लिए आपसी सहयोग करने और एक दूसरे से सीखने में समुदायों की मदद की है। सीखना और साझा करना एक दो-तरफ़ा प्रक्रिया है और पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक है, जबकि साथ ही यह नए दृष्टिकोणों और तरीकों से तथा उनके बारे में सीखने के अवसर प्रदान करती है।



परिणामों का एक संक्षिप्त आशुचित्र

1. जिस क्षेत्र में केन्द्र संचालित होता है, उस क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्र बढ़ गया है; पारिस्थितिकी तंत्र का 14,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
2. 60 से अधिक गाँव विभिन्न हस्तक्षेपों से प्रभावित हुए हैं; 300 आदिवासी परिवारों पर असर पड़ा है। दो गाँवों में 3 से 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। आदिवासी स्कूलों के बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाने वाले छात्र हैं, और कई आगे हाई स्कूल जाते हैं। लगभग 30 छात्रों ने अपनी दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; उनमें से लगभग 10 कॉलेज में हैं।
3. अब आजीविका कार्यक्रम का सालाना कारोबार 25 लाख रुपये का है और 12 आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लोग इसके लिए काम करते हैं। यह जैव विविधता संरक्षण के लिए एक पहुँच और लाभ सहभाजन समझौते के लाभों का प्रदर्शन करने वाला शायद पहला सामुदायिक उद्यम है।

4. कैगल प्रोग्राम स्थानीय जैव विविधता प्राधिकरण के लिए एक संसाधन संगठन के रूप में उभरा है, जो जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के गठन के माध्यम से स्थानीय पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्धन में विशेषज्ञता विकसित करता है।*



इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखने से ज्ञान प्रणालियों के प्रतिच्छेदनों को गरिमा और सम्मान के साथ तथा पारिस्थितिक और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित एक सशक्तता प्रदान करने वाले तरीके से संगठित, प्रबन्धित, और निर्देशित करने में मदद मिल सकती है।

समाप्ति नोट (Endnote)

- i. It was identified only four years earlier as a new species—the Sri Lankan flying snake or the Indian flying snake, *Chrysopelea taprobanica*.
- ii. Thalari, C., & Thiripalu, P. (2018) Dispersion, knowledge erosion and identity crisis: Adaptive strategies and struggles of the Yanadi. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 7(1), pp. 33-39.
[http://www.ijhssi.org/papers/vol7\(1\)/Version-2/E0701023339.pdf](http://www.ijhssi.org/papers/vol7(1)/Version-2/E0701023339.pdf)
- iii. Vedavathy, S. (2010) Displaced and marginalised: Protecting the traditional knowledge, customary laws and forest rights of the Yanadi tribals of Andhra Pradesh. Herbal Folklore Research Centre, Tirupati, Andhra Pradesh, India.
<https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/SPE-Pop-540-003.pdf>
- iv. Savithramma, N., Yugandhar, P., Hari Babu, R., & Siva Prasad, K. (2014). Validation of indigenous knowledge of Yanadi tribe and local villagers of Veyilingalakona: A sacred grove of Andhra Pradesh, India. *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 6(11), 382-388.
- v. Ondrik, R. S., Participatory approaches to national development planning. Asian Development Bank.
http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/226262-1143156545724/Brief_ADB.pdf
- vi. Parrotta, J., Yeo-Chang, Y., & Camacho, L. D. (2016) Traditional knowledge for sustainable forest management and provision of ecosystem services. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management*, 12(1-2), 1-4.
- vii. Pfund, J. L., Koponen, P., O'Connor, T., Boffa, J. M., van Noordwijk, M., & Sorg, J. P. (2008) Biodiversity Conservation and Sustainable Livelihoods in Tropical Forest Landscapes. In: Laforzezza, R., Sanesi, G., Chen, J., & Crow T.R. (eds), *Patterns and Processes in Forest Landscapes*. Springer, Dordrecht.

https://link.springer.comchapter/10.1007/978-1-4020-8504-8_17

- viii. Pfund, J. L., Koponen, P., O'Connor, T., Boffa, J. M., van Noordwijk, M., & Sorg, J. P. (2008) Biodiversity Conservation and Sustainable Livelihoods in Tropical Forest Landscapes. In: Laforzezza, R., Sanesi, G., Chen, J., & Crow T.R. (eds), Patterns and Processes in Forest Landscapes. Springer, Dordrecht.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8504-8_17
https://link.springer.com chapter/10.1007/978-1-4020-8504-8_17

- ix. Community Empowerment through Sustainable Livelihood Generation Using Diverse Traditional Knowledge Systems, Detailed Report prepared by the KFI for the Project funded under GEF-UNDP-SGP. Unpublished project report.

कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम (KEEP), आंध्र प्रदेश

फ़ाउण्डेशन फॉर एजुकेशन, इकोलॉजी एंड लाइवलीहुड (Foundation for Education, Ecology and Livelihood—FEEL) 2014 में एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट (Public Charitable Trust—PCT) के रूप में पंजीकृत किया गया। संगठन का व्यापक उद्देश्य स्थाई ग्रामीण समुदायों के माध्यम से और उनके लिए जीवन-सेवा और पारिस्थितिक रूप से पुनर्स्थापनात्मक शिक्षा में सहयोग प्रदान करना है।

फ़ाउण्डेशन फॉर एजुकेशन, इकोलॉजी एंड लाइवलीहुड ने कृष्णमूर्ति फ़ाउण्डेशन इंडिया के कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम के संचालन का दायित्व संभाला है। कैगल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 2002 से कृष्णमूर्ति फ़ाउण्डेशन इंडिया के करिकुलर आउटरीच प्रोग्राम (curricular outreach program) के रूप में और आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य से सटे आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के बीच काम कर रहा है।

4.2 कदम स्टेप-अप प्रोग्राम

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया (HPPI), दिल्ली

सारांश

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया (Humana People to People India—HPPI) 1998 में भारत में पंजीकृत एक गैर-लाभकारी, विकास संगठन है। इसका प्रमुख कार्यक्रम, कदम स्टेप-अप प्रोग्राम (Kadam Step-Up Programme), स्कूल से बाहर रह गए बच्चे (Out-of-School Children—OOSC) के लिए एक हस्तक्षेप है। भारत में, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों का मुद्दा एक बड़ी चुनौती और जटिल सामाजिक समस्या है। बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 2010 में प्रभावी हुआ, 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को अनिवार्य करता है। आवश्यकता मूल्यांकन और सर्वेक्षण के माध्यम से, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान करके, अपने केन्द्रों पर स्कूल से बाहर रह गए बच्चों का नामांकन करके, बच्चों को त्वरित शिक्षण के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए उन्हें आयु-उपयुक्त स्तर पर सम्बन्धित कक्षाओं में मुख्य धारा में शामिल करने से पहले उनके सीखने के अन्तराल को पाटने के लिए, और औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उनके ठहराव के लिए आगे की कार्यवाही करते हुए कदम एक आशाजनक और प्रभावी समाधान प्रदान करता है।

जो एक दशक से अधिक समय पहले एक उत्साहपूर्ण और आदर्शवादी सामाजिक कल्याण हस्तक्षेप के रूप में शुरू हुआ, वह आज स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के मुद्दे से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र, कदम, के रूप में विकसित हो चुका है। हाल के दिनों में इसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development—MHRD) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, कई राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया है, और कई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रशंसा की गई है।

कदम की यह केस स्टडी कार्यक्रम के छोटे विवरणों पर प्रकाश डालती है जो कई परिवारों में उल्लेखनीय और सार्थक बदलाव लाने में सफल रहे हैं। सच ही कहा गया है कि “छोटे कदमों से एक बड़ी छलंग लगाई जा सकती है।” इसी तरह, कदम कई वंचित बच्चों और उनके परिवारों के जीवन में सुधार लाने में सफल रहा है।

जीवन का एक नया पड़ा

अपने 12 वर्षीय बेटे, विकास के बालों में उंगलियाँ फेरते हुए चंद्रिका देवी की आँखों में आँसू उमड़ पड़े, “अब मेरी सारी उम्मीदें इसी पर टिकी हुई हैं,” आँसू पोंछते हुए वह कहती है।

कुछ सालों पहले चंद्रिका का बड़ा बेटा पूर्वी भारत में बिहार के मधुबनी ज़िले में अपने गाँव लौटते समय रहस्यमय तरीके से ग़ायब हो गया। वह मिला ही नहीं। चंद्रिका और उनके पति उत्तर भारत में हरियाणा राज्य के तेज़ी से विस्तारित हो रहे शहर गुरुग्राम (पूर्व में गुड़गाँव) में दिहाड़ी मज़दूर हैं। नौ वर्षीय बेटे विशाल सहित चार सदस्यों का परिवार धीरे-धीरे सबसे बड़े बेटे के लापता होने के दुःखद सदमे से उबर रहा है।

“घटना के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। पढ़ाई में मेरी रुचि पूरी तरह ख़त्म हो गई,” विकास याद करते हुए बताता है। “मेरे अधिकांश दिन उन निर्माण स्थलों के आसपास मेरी उम्र के अन्य बच्चों के साथ खेलने और मटरगश्ती करने में बीत रहे थे, जहाँ मेरे माता-पिता काम करते हैं।” ऐसे ही एक दिन, कदम के एक शिक्षक स्कूल से बाहर रह गए बच्चों पर एक सर्वेक्षण करने के लिए चंद्रिका के घर आए। चंद्रिका ने बताया, विकास के बारे में पूछताछ करने के बाद, शिक्षक ने माता-पिता को पास के सामुदायिक केन्द्र में चलाए जा रहे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया।

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया (Humana People to People India—HPPI) के कदम केन्द्र स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान करते हैं, और शैक्षणिक विषयों तथा सामाजिक कौशलों पर सालभर के प्रशिक्षण के बाद, किसी औपचारिक स्कूल में आयु-उपयुक्त कक्षा में प्रवेश लेने में बच्चों की मदद करते हैं। विकास कहता है, “शुरुआत में, मैं केन्द्र से जुड़ने को लेकर थोड़ा बेचैन था। लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ, मैंने देखा कि केन्द्र पर शिक्षक नई गतिविधियों और खेलों के माध्यम से गणित और अंग्रेज़ी जैसे विषय पढ़ा रहे थे। यह स्कूल में हमें पढ़ाए जाने के तरीके से बहुत अलग और कहीं अधिक दिलचस्प था।”

आज, केन्द्र में लगभग एक वर्ष बिताने के बाद, विकास पास के एक सरकारी स्कूल में एक आयु-उपयुक्त कक्षा में नामांकित होने के रास्ते पर अग्रसर है।

वह कहता है, “फिर से एक स्कूल में शामिल होने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास, सीखने के स्तर, और सामाजिक कौशल हासिल करने में मेरी मदद करने के लिए मैं कदम प्रोग्राम का बहुत आभारी हूँ।” उसकी माँ गर्व से मुस्कुराती है, जो भविष्य के लिए उसके आत्मविश्वास और आशा को प्रतिबिम्बित करती है।

विकास की कहानी भारत में बहुत से स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में से कुछ को महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाने का एक उत्साहवर्धक उदाहरण है। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया जैसे कई संगठन सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहे हैं और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को मूलभूत शिक्षा और बुनियादी कौशल प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं जो उन्हें शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में शामिल होने में सक्षम बनाएगा ताकि वे सीख सकें और जीवन में प्रगति कर सकें।

कदम स्टेप-अप प्रोग्राम—पृष्ठभूमि

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया एक विकास संगठन है, जो भारत में 21 मई 1998 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया।

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया एक गैर-राजनीतिक, गैर-धार्मिक निकाय है जो नागरिक समाज के हिस्से के रूप में काम करता है ताकि वंचित लोगों और समूहों का जीवन बेहतर बनाने के लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जा सके। एक कार्यक्रम के रूप में इस मिशन की औपचारिक संकल्पना शुरू करने से बहुत पहले ही ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, जो कभी स्कूल नहीं गए थे। 2005 में, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया प्रशिक्षकों की एक टीम ने हरियाणा के रेवाड़ी में पारम्परिक यौनकर्मियों (नट और कंजरी) जैसी जनजातियाँ, जो पीढ़ियों से इस काम में लगी हुई हैं) की एक कॉलोनी का दौरा किया। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि समुदाय के 12 से 16 वर्ष आयु समूह के कई बच्चे सुव्यवस्थित ढंग से से कपड़े पहने हुए थे और अपनी स्थानीय बोली में धाराप्रवाह बोल रहे थे। जब उनसे उनकी शिक्षा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे “कभी स्कूल नहीं गए”। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया की टीम ने अपने सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के आसपास बंजारों और अन्य प्रवासी समुदायों के कई “शिविरों” से सम्बन्धित बच्चों की पहचान की। फिर क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और इन बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने का काम प्रशिक्षकों के एक अन्य समूह को सौंप दिया गया।

राजस्थान के अलवर ज़िले में बहरोड़ के आसपास के क्षेत्रों में किए गए एक सर्वेक्षण, जहाँ एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थित था, से खुलासा हुआ कि कई स्थानीय बच्चे काम कर रहे थे और कभी स्कूल नहीं गए थे। उनमें से कई कूड़ा उठाने वाले थे, दुकानों और कारखानों में काम करते थे, या खेत में अपने माता-पिता की मदद करते थे। 7 से 14 वर्ष आयु समूह के इन बच्चों के लिए प्रारम्भिक विचार इन्हें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने का था, ताकि वे पढ़-लिख सकें और समझ सकें कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उन्हें किसी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सिखाने का विचार नहीं था।

इसे ध्यान में रखते हुए, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने 2006 में बहरोड़ में दो केन्द्र स्थापित किए। व्यापक सामुदायिक सक्रियता की बदौलत, इन कामकाजी बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों को इन केन्द्रों पर जाने की अनुमति देने के लिए राज़ी किया गया, जहाँ उन्हें साक्षरता और संख्यात्मक शिक्षा प्रदान की गई। चूँकि केन्द्रों का समय लचीला रखा गया था, अपनी सुविधानुसार कुछ बच्चे सुबह आते थे और अन्य दोपहर में आते थे। केन्द्र सफल थे। वे सफल इसलिए नहीं थे कि एक सुनियोजित कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा था, बल्कि इसलिए सफल थे क्योंकि बच्चों ने वही सीखा जो वे सीखना चाहते थे। यह बच्चे थे जो अपना भविष्य बदलना चाहते थे, और ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने यह सब एक ऐसा माहौल बनाकर किया, जिसमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने की बात आने पर शिक्षक और छात्र दोनों एक ही तरह से सोचते थे, और पाठ्यक्रम के प्रति दोनों का समान दृष्टिकोण था।

बहरोड़ से एकैडमी फॉर वर्किंग चिल्ड्रन (Academy for Working Children—AWC) की स्थापना का विचार उभरा। 2007 में, फ़िनलैंड में ह्यूमाना के सहयोगी संगठन की सहायता से और विदेश मंत्रालय, फ़िनलैंड से प्राप्त वित्तपोषण से, एकैडमी फॉर वर्किंग चिल्ड्रन की संकल्पना की गई। तीन वर्षों में, दो केन्द्र, क्रमशः जयपुर और नीमराना दोनों राजस्थान में, खोले गए। प्रत्येक केन्द्र में लगभग 250 बच्चे नामांकित थे। केन्द्रों ने लचीले समय के साथ काम करना शुरू किया और बाद में सुबह 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक का समय निर्धारित किया। इस समय, अब तक थोड़े बेतरतीब ढंग से चल रहे कार्यक्रम को कुछ आकार और दिशा दी गई। पाठ्यपुस्तकों में वर्णित अवधारणाओं पर आधारित कार्य कार्ड के रूप में तैयार किए गए। यह कार्ड-आधारित कार्य सीखने का एक प्रभावी माध्यम साबित हुए और चरण-दर-चरण सीखने के कार्यक्रम के निर्माण में यह पहला चरण था, जिसे यूनिसेफ़ की मल्टी-ग्रेड मल्टी-लेवल (Multi-Grade Multi-Level—MGML) शिक्षण पद्धति की तर्ज पर तैयार किया गया था, और यह गतिविधि-आधारित शिक्षण (Activity-Based Learning—ABL) पर भी आधारित था, जिसका उपयोग छत्तीसगढ़ स्थित केन्द्र पर किया जा रहा था। यह वह समय था जब कदम प्रोग्राम ने विभिन्न एजेंसियों से मान्यता प्राप्त की और फ़िनलैंड (2009–2011) और डेल (2009 से) से आर्थिक सहायता प्राप्त की। यह वह समय भी था जब कदम प्रोग्राम गुरुग्राम (गुड़गाँव), हरियाणा और गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था।

इस बीच, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रवृत्त किया गया और 2010 में लागू हुआ। इसने बच्चों की औपचारिक शिक्षा के प्रावधान को एक मज़बूत प्रोत्साहन दिया। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया का कार्यक्रम बच्चे द्वारा संचालित (child-driven) अधिगम के एक ठोस दर्शन पर आधारित है। हालाँकि, इसमें अब भी मानकीकृत अधिगम की एक विशिष्ट सामग्री के संग्रह का अभाव था। इसके अलावा, मापनीयता (scalability) की बात आने पर सीखने की कार्ड-आधारित प्रणाली बोज़िल प्रतीत होती थी, और वक्ता की पुकार कुछ ऐसा

बनाए जाने की थी जो सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan—SSA) के साथ संरेखित राज्यों की शिक्षा प्रणाली के साथ मिलकर काम करते हुए स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को मुख्य धारा में लाने में मदद करे। कदम स्टेप-अप प्रोग्राम की संकल्पना इन कमियों और अन्तरालों को सम्बोधित करने के लिए की गई थी।

कदम स्टेप-अप प्रोग्राम की शुरुआत

विगत वर्षों की घटनाओं और सीखों पर आधारित, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने 2011 में कदम संकल्पना पत्र (Kadam Concept Paper) तैयार किया और कदम पाठ्यक्रम की विषयवस्तु पर काम करना शुरू किया। कदम के लिए विषय निर्धारित किए गए और पूरी टूलकिट की रूपरेखा तैयार की गई, उनका फ़ील्ड परीक्षण किया गया, और अन्ततः 2014 के अन्त तक गुरुग्राम केन्द्र में क्रियान्वित करने के लिए उन्हें विकसित किया गया। इस प्रकार, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के लिए कदम प्रोग्राम का जन्म हुआ।

2014 में, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने हरियाणा में मेवात ज़िले में ह्यूमाना इटली और तवोला वाल्डीज़ (Tavola Valdese) तथा विदेशों के कुछ व्यक्तियों के सहयोग से 300 लड़कियों के लिए कदम केन्द्रों की स्थापना की। कपड़ा-पुनर्चक्रण उद्योग (textile-recycling industry) में काम करने वाले प्रवासी अभिभावकों के 250 बच्चों के लिए 2015 में UFF, नॉर्वे (U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge) के सहयोग से हरियाणा के पानीपत में कदम केन्द्र स्थापित किए गए। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया के लिए अगला बड़ा कदम मध्य प्रदेश में 2015-16 में भारती फ़ाउण्डेशन के साथ एक साल की साझेदारी की स्थापना था। गुरुग्राम में डेल-सहायतित केन्द्र ने कदम को अपनाया, जैसा कि डच संगठन सिम्पैनी द्वारा सहयोग प्राप्त केन्द्रों ने पानीपत में किया था। इसके तुरन्त बाद ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया की एजुकेट ए चाइल्ड (Educate a Child—EAC) के साथ साझेदारी शुरू हुई। 2016 में, एजुकेट ए चाइल्ड, भारती फ़ाउण्डेशन, और ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते में, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने एजुकेशन एबव ऑल फ़ाउण्डेशन (Education Above All Foundation—EAAF) के माध्यम से एजुकेट ए चाइल्ड के साथ एक प्रतिष्ठित साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एजुकेट ए चाइल्ड ने हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region—NCR) में तीन साल की अवधि में स्कूल से बाहर रह गए 30,000 बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सहयोग प्रदान किया। अक्टूबर 2016 में, राज्य में स्कूल से बाहर रह गए 30,000 बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने में सहयोग करने के लिए एक सह-वित्तपोषित मॉडल (co-funded model) अपनाने के लिए तीन साल की अवधि के लिए हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding—MoU) पर हस्ताक्षर किए

गए। बाद में, 15 से अधिक भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility—CSR) फंड के माध्यम से कदम प्रोग्राम को सहयोग प्रदान किया।

2017 की दूसरी तिमाही में शुरुआत करते हुए, मानव विकास संसाधन मंत्रालय और तत्कालीन सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत, पूरे देश में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को मुख्य धारा शामिल करने की चुनौतियों पर विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन नई दिल्ली और पाँच आंचलिक क्षेत्रों में आयोजित किए गए जहाँ प्रमुख संगठनों को उनके योगदान, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, शिक्षा, और योजनाओं पर प्रस्तुतियाँ देने के लिए आमंत्रित किया गया। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया इन सम्मेलनों का एक उल्लेखनीय हिस्सा था, और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को मुख्य धारा में लाने में इसकी भूमिका सचिव और अन्य शीर्ष शासकीय अधिकारियों द्वारा स्वीकारी गई।

हरियाणा के अलावा, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और यह इन राज्यों में राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जम्मू और कश्मीर में, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने राज्य सरकार के विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और जून 2019 में काम शुरू किया जाएगा। 2019 के अन्त तक, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया स्कूल से बाहर रह गए 45,000 बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने और विभिन्न राज्यों में कदम के विभिन्न केन्द्रों पर स्कूल से बाहर रह गए लगभग 80,000 बच्चों का नामांकन करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

वर्तमान परिदृश्य और कदम स्टेप-अप प्रोग्राम की आवश्यकता

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 किसी औपचारिक स्कूल में पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम के लागू होने के बावजूद, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की मौजूदगी एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि यह भारत में राज्य सरकारों के लिए उन बच्चों तक पहुँचने और उन्हें औपचारिक शिक्षा की प्रणाली में शामिल करने की निरन्तर चुनौती है, जो या तो कभी स्कूल गए ही नहीं, या जो विभिन्न कारणों से स्कूल से बाहर हो गए हैं।

स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की परिभाषा और उपयोग में लाए गए डेटा स्रोत के आधार पर, भारत में इन बच्चों की संख्या के अनुमानों में बहुत अधिक भिन्नता है। जबकि 2014 की यूनिसेफ़ की एक रिपोर्ट स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की संख्या 17.7 मिलियन बताती है, उसी वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्टⁱⁱ यह संख्या 6 मिलियन बताती है। 6 मिलियन के एक अपेक्षाकृत संकुचित अनुमान पर भी, प्राथमिक स्कूल जाने की आयु के स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की संख्या सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के भारत सरकार के प्रयासों के मार्ग में एक प्रमुख अवरोध है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की दी गई सबसे व्यापक रूप से स्वीकारी गई परिभाषाⁱⁱⁱ है :



6-14 वर्ष उम्र का एक बच्चा स्कूल से बाहर रह गया माना जाएगा यदि वह किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कभी भी नामांकित नहीं हुआ हो या नामांकन के बाद अनुपस्थिति के कारणों की पूर्व सूचना दिए बिना 45 दिन या अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहा हो।^{iv}



इससे पहले कि हम स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करें, दो चिन्ताजनक परिदृश्यों को समझना आवश्यक है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद भी जारी रहे हैं। पहले परिदृश्य में, कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के सर्वेक्षणों से पता चला है कि सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में अधिगम का स्तर लगातार निम्न बना हुआ है। न्यूनतम स्वीकार्य बुनियादी कौशल प्राप्त किए बिना लगभग आधे बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा के आठ साल बाद स्कूल छोड़ देते हैं। एक बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आयु सीमा पार हो जाने के बाद उन्हें स्कूल वापस लाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अन्ततः इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाते हैं। हाल के एक अध्ययन^v से पता चलता है कि स्कूल से बाहर रह गए बच्चों में से 37 प्रतिशत स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं और उनमें से 63 प्रतिशत ने स्कूल में नामांकन के तीन साल के भीतर स्कूल छोड़ दिया। इसी अध्ययन में इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया कि स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के 45 प्रतिशत ने कभी स्कूल में नामांकन कराया ही नहीं और 18 प्रतिशत स्कूल से बाहर रह गए बच्चे नामांकन कराने के बावजूद कभी भी स्कूल नहीं गए। दूसरा परिदृश्य उन बच्चों से सम्बन्धित है जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा। यह और भी चिन्ताजनक है क्योंकि इन बच्चों को अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए कोई रास्ता खोजने और इस कारण भविष्य में अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार का कोई अवसर नहीं मिला। आज भी, हज़ारों बच्चे सड़कों पर, बस अड्डों, और रेलवे प्लेटफ़ॉर्मों पर निरुद्देश्य भटकते पाए जाते हैं; वे अत्यधिक अरक्षित हैं, अपराध जगत के सम्पर्क में आते हैं और अन्याय,

गरीबी और उत्पीड़न के शिकार हैं। कई बच्चे घर से भाग जाते हैं और गलत हाथों में पड़ जाते हैं। जहाँ तक लड़कियों का सम्बन्ध है, उनमें से ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों में रहने वाली कई लड़कियाँ घरेलू कामकाज और भाई-बहनों की देखभाल करने तक सीमित हैं। उन्हें सामाजिक मानदण्डों के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और इसलिए उन्हें स्कूल जाने की अनुमति नहीं होती है।

कुछ प्रमुख कारक, जो बच्चों को अपनी शिक्षा छोड़ने पर मजबूर करते हैं, गरीबी, पलायन, सामाजिक बाधाएँ, वित्तीय बाधाएँ, और शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में बच्चों और अभिभावकों दोनों की ओर से रुचि की कमी हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही हैं; मुफ्त और पोषक मध्याह्न भोजन, मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें, और छात्रवृत्तियाँ जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना; और समुदायों के व्यवहार परिवर्तन के लिए व्यापक अभियान आयोजित करना। हालाँकि, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की मौजूदगी अब भी एक चुनौती है।

बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने का एक और कारण गैर-अधिगम कारक है। वे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए और जो प्राथमिक स्कूल की शुरुआती कक्षाओं से बाहर हो गए, अगर उन्हें आयु-उपयुक्त कक्षाओं में फिर से स्कूल में नामांकित किया जाता है, तो उनका अधिगम का अन्तराल स्पष्ट दिखाई देता है, जो उनके वर्तमान अधिगम को बाधित करता है और उनका आत्मविश्वास घटाता है, और इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी अपर्याप्त समझ या उस अवधारणा की बुनियाद की कमी को देखते हुए ऐसे बच्चों से उच्च स्तर के अधिगम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अधिगम एक प्रगतिशील और सतत प्रक्रिया है, जो एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा की ओर ले जाती है। छात्रों के अधिगम अन्तरालों को सम्बोधित करना महत्वपूर्ण है और इसकी तरफ शिक्षक द्वारा तुरन्त ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है। जितना अधिक समय नष्ट होता है, कार्य प्रारम्भ करना उतना ही कठिन हो जाता है। इसलिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (Special Training Centres—STCs) की आवश्यकता है, जो अधिगम के अन्तरालों को पाटने और अपनी कक्षा के अन्य बच्चों के स्तर पर आने में ऐसे बच्चों की मदद करें।

महत्वपूर्ण यह है कि स्कूल से बाहर रह गए बच्चों और आयु-उपयुक्त मुख्य धारा में उन्हें शामिल करने के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए, सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरण व्यापक योजनाएँ तैयार करने के लिए मिलकर कार्य करें। औपचारिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन करने से पहले, उन्हें पहले विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में भर्ती करने की आवश्यकता है जो मुख्य धारा में शामिल होने में उनकी मदद के लिए विशेष रूप से स्थापित किए गए हैं। यह स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की तैयारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि विशेष प्रशिक्षण केन्द्र एक त्वरित पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के

लिए पूरी मदद प्रदान करते हैं। हालाँकि, इन सभी सुविधाओं की पेशकश के बावजूद, कई विशेष प्रशिक्षण केन्द्र दो कारणों से अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं : पहला, विशेष प्रशिक्षण केन्द्र की अकसर उपेक्षा की जाती है और / या प्राथमिक विद्यालयों के लिए इन्हें एक अतिरिक्त बोझ समझा जाता है; और दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान की औपचारिक प्रणाली, जो अधिगम के तीन से-छह से-नौ महीने के चक्र का पालन करती है, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिसमें अधिक लचीलेपन की आवश्यकता है।

समस्या समाप्त नहीं होगी। यदि स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के अधिगम के अन्तरालों के मुद्दे को वास्तव में प्रभावी ढंग से सम्बोधित नहीं किया जाता है, तो यह बढ़ती जाएगी। एक बार उनके अधिगम के अन्तराल पाटने के बाद आयु-उपयुक्त स्तरों पर उन्हें मुख्य धारा में उन्हें शामिल करना महत्वपूर्ण है ताकि शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में उनका ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। बच्चों को शिक्षा प्रणाली से बाहर निकलने से रोकने के लिए त्वरित शिक्षा का एक मज़बूत तंत्र आवश्यक है जो उन्हें बुनियादी अवधारणाओं की समझ का एक मज़बूत आधार प्रदान करे। समुदायों और अन्य हितधारकों तक पहुँच निर्मित कर बच्चों को स्कूल लाने के मुद्दे पर अधिक समग्र रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। बच्चों को शिक्षा की दिशा में ले जाने में मदद करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने और शिक्षा के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिभावकों, समुदायों, सरकारी स्कूलों के प्रमुखों, और ज़िला एवं ब्लॉक दोनों स्तरों पर अधिकारियों को एक साथ आने के लिए सक्रिय करने में एक लम्बा रास्ता तय करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सफल बनाने में योगदान करना होगा।

कदम स्टेप-अप प्रोग्राम



ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया के कदम स्टेप-अप प्रोग्राम की रूपरेखा उपरोक्त चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के अधिगम के अन्तरालों को नियंत्रित करने के लिए, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया कदम के माध्यम से दिलचस्प शिक्षा विज्ञान, लक्षित पाठ्यक्रम, और शिक्षण पद्धतियों पर आधारित एक मंच प्रदान करता है।

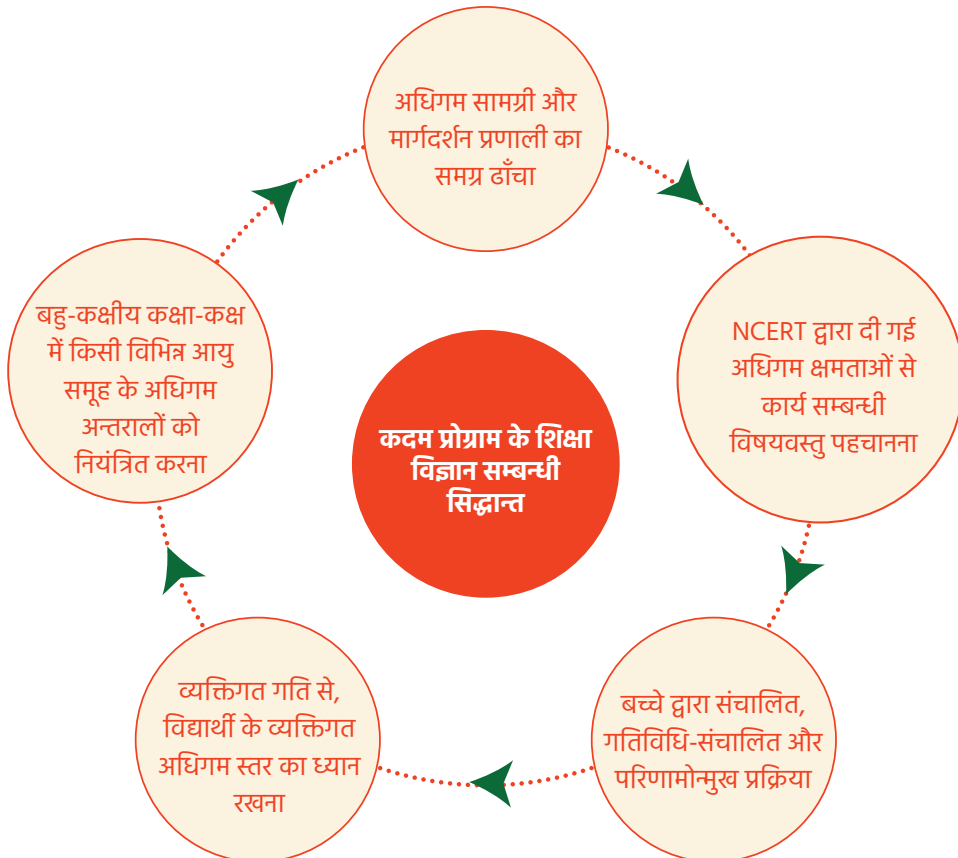
कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से गणित, पर्यावरण विज्ञान, हिन्दी, और अंग्रेज़ी में बच्चों के विषय कौशलों और ज्ञान में सुधार लाना है। यह छात्रों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने के लिए औपचारिक अधिगम और कौशल-आधारित अनुभवों का सम्मिश्रण करता है। यह छात्रों के

औपचारिक अधिगम कौशल को बढ़ाता है। यह शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में छात्रों की व्यक्तिगत गति और स्तर के अनुसार अधिगम के लिए एक पैकेज के रूप में प्रशासित किया जाता है।

कदम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework—NCF) 2005 में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। इसे विस्तृत बनाने और एक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training—NCERT) द्वारा विकसित क्षमताएँ इसमें शामिल की गई हैं। हालाँकि, चूँकि कदम एक त्वरित अधिगम कार्यक्रम है, इसलिए प्रति कक्षा प्रत्येक विषय के लिए 100 प्रतिशत क्षमताएँ शामिल करना व्यवहार्य नहीं था। इसके बजाय, लगभग 80 प्रतिशत क्षमताएँ शामिल की गई हैं और इन क्षमताओं के आधार पर अभ्यास विकसित किए गए हैं।

कदम स्टेप-अप प्रोग्राम का शिक्षा विज्ञान

कदम स्टेप-अप प्रोग्राम का शिक्षा विज्ञान कदम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर आधारित है, जो नीचे दर्शाए गए हैं :



कदम टूलकिट

कदम स्टेप-अप प्रोग्राम एक शिक्षण पैकेज है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- स्टूडेंट एक्टिविटी बुक्स:** यह प्रत्येक कक्षा के लिए पाँच किताबों का एक सेट है जो कदम स्टूडेंट बुक्स के नाम से जानी जाती हैं। जैसा कि 'कदम' नाम से पता चलता है, किताबें 1 से 10 चरणों (Steps) पर आधारित हैं। इस प्रकार, एक कक्षा के लिए प्रत्येक किताब के दो चरण हैं। कक्षा 1 में चरण 1 और 2 हैं; कक्षा 2 में चरण 3 और 4 हैं; कक्षा 3 में चरण 5 और 6 हैं; कक्षा 4 में चरण 7 और 8 हैं; और कक्षा 5 में चरण 9 और 10 हैं। यह पुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिए गए अधिगम परिणामों पर आधारित हैं। 'मेरी चेकलिस्ट' कदम स्टूडेंट बुक्स का एक अभिन्न अंग है। यह चरण 1 से चरण 10 तक, हर चरण की शुरुआत में प्रदान की जाती है। यह क्षमताओं की एक प्रगतिशील सूची है, जिन्हें कारनामों के रूप में वर्णित किया जाता है और जो कदम स्टूडेंट बुक्स में की जाने वाली गतिविधियों और अभ्यास का आधार बनते हैं। मेरी चेकलिस्ट छात्रों द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ने के दौरान किया जाने वाला एक प्रकार का स्व-मूल्यांकन है। यह एक सीखने की मार्गदर्शिका के रूप में छात्रों की मदद करता है कि वे स्वयं वह गतिविधि निर्धारित करें जिसके लिए वे प्रयास करना चाहते हैं। कक्षा की शुरुआत में शिक्षक उस गतिविधि पर चर्चा करता है जो छात्रों द्वारा की जाने वाली है और शिक्षार्थियों को मेरी चेकलिस्ट में दी गई अनुकूल क्षमता का हवाला देता है। एक बार जब छात्र गतिविधि / गतिविधियों को पूरा कर लेते हैं, तो वे मेरी चेकलिस्ट में सूचीबद्ध क्षमता के सामने वह तारीख लिखते हैं जिस दिन उन्होंने कार्य / कार्यों का प्रयास किया। शिक्षक यह सत्यापित करता है कि छात्रों ने कारनामे से सम्बन्धित गतिविधि / गतिविधियाँ पूरी कर ली हैं और उसके सामने अपने हस्ताक्षर करके इसकी पुष्टि करता है।
- टीचर्स मैनुअल:** शिक्षक की नियमावली (Teacher's Manual) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो शिक्षकों और अन्य संसाधन व्यक्तियों को कार्यक्रम के शिक्षा विज्ञान और संरचना के बारे में एक विस्तृत दृष्टिकोण और समझ प्रदान करता है। यह एक मार्गदर्शिका और सहायता साधन (guide and support tool) है जिसमें विभिन्न विषय-आधारित रणनीतियाँ, शिक्षण युक्तियाँ, गतिविधियाँ, और सोच-आधारित प्रश्न शामिल हैं। यह शिक्षकों को कदम प्रोग्राम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली से परिचित करता है और अधिगम को एक सक्रिय, दिलचस्प, और सार्थक गतिविधि बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करने में उनकी मदद करता है।

- **थीम बुक:** विषय से सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन में शिक्षकों की मदद करने के लिए, प्रत्येक माह के लिए विषय को नियोजित और लागू करने के लिए उन्हें एक विषय-वस्तु पुस्तिका (Theme Book) प्रदान की जाती है। एक बार जब कोई विषय लिया जाता है, तो छात्रों के स्तर के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाई जाती है। इस तरह, सभी बच्चे चल रही विषय-वस्तु से सम्बन्धित गतिविधियों में शामिल होते हैं। थीम बुक विषयों की योजना और क्रियान्वयन का विवरण प्रदान करती है। विषय-वस्तुएँ बच्चों में जीवन कौशल विकास को सम्बोधित करती हैं और साझाकरण, स्वीकृति, टीमवर्क, सक्रिय होने, और रचनात्मकता के दृष्टिकोणों, मूल्यों, और व्यवहार विकसित करने का एक अवसर प्रदान करती हैं।
- **माय प्रोग्रेस बुक:** माय प्रोग्रेस बुक (My Progress Book) एक पूर्ण मूल्यांकन पुस्तिका है, जो छात्र के शुरुआती स्तर के साथ-साथ छात्र द्वारा कार्यक्रम की अवधि में और उससे बाहर निकलने या उसके पूर्ण हो जाने पर छात्र द्वारा की गई प्रगति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं : नामांकन फ़ॉर्म, जिसमें छात्र का सम्पूर्ण सम्पर्क और व्यक्तिगत विवरण होता है; आधार-रेखा आकलन (Baseline Assessments)—स्तर 1 और 2, जो छात्र का अधिगम स्तर इंगित करता है और उसे कार्यक्रम के एक उपयुक्त शुरुआती चरण में रखता है; कक्षा अन्त्य परीक्षण (Grade End Tests), जो एक कक्षा के दो चरणों को पूरा करने के बाद छात्र का आकलन करते हैं (यह प्रत्येक कक्षा के बाद एक अन्तिम परीक्षा की तरह है) समापन-रेखा आकलन (Endline Assessments)—स्तर 1 और 2, जो कार्यक्रम से उसके बाहर निकलने पर छात्र की अन्तिम अधिगम प्रगति का आकलन करते हैं। इन्हें आधार-रेखा आकलन के परिणामों की तुलना में देखा जाता है, क्योंकि दोनों बिलकुल एक दूसरे के साथ प्रतिचित्रित किए जाते हैं (वे यह भी इंगित करते हैं कि छात्र कार्यक्रम के अन्त में आयु-उपयुक्त अधिगम के स्तर पर पहुँचा या नहीं) और छात्र को एक औपचारिक स्कूल में मुख्य धारा में शामिल करने और उसके ठहराव से सम्बन्धित अभिलेख।
- **ट्रैकिंग आर प्रोग्रेस चार्ट:** ट्रैकिंग आर प्रोग्रेस (Tracking our Progress—ToP) चार्ट, जो एक दीवार पर लटका रहता है, कदम प्रोग्राम में नामांकित प्रत्येक बच्चे की स्थिति और प्रगति की एक त्वरित झलक देता है। इसमें एक ट्रैकिंग चेकलिस्ट शामिल है जो प्रत्येक छात्र द्वारा की गई विषय-वार प्रगति को ट्रैक करती है, प्रत्येक चरण में छात्र द्वारा पूर्ण और प्राप्त की गई क्षमताओं की एक समग्र तस्वीर दर्शाती है। शिक्षक प्रारम्भिक कक्षाओं में चेकलिस्ट भरता है और उच्च कक्षाओं में छात्र यह कार्य करते हैं। विषय

स्थिति पर चेकलिस्ट प्रत्येक विषय के प्रत्येक चरण में छात्र द्वारा पूरे किए गए कार्यों की संख्या दर्शाती है। जैसे ही छात्र किसी चरण का एक कार्य (Feat) पूरा करता है, छात्र के नाम के सामने उस कार्य से सम्बन्धित बॉक्स शिक्षक या छात्र द्वारा भरा जाता है।

- **प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers—ToT):** शिक्षकों और अन्य संसाधन व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण संचालित करने के लिए ट्रेनर्स टूल (trainer's tool) सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दस्तावेज़ है। इसमें एक चेकलिस्ट के रूप में प्रश्नों की एक शृंखला शामिल है जिनका प्रशिक्षकों द्वारा जवाब दिया जाना होता है। दस्तावेज़ के अन्त में सही उत्तर भी दिए होते हैं, इसलिए कार्यक्रम के विभिन्न बिन्दुओं के बारे में पूरी स्पष्टता रहती है।

कदम मॉडल की विशिष्ट विशेषताएँ

समग्र शिक्षा : स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के लिए कदम प्रोग्राम प्राथमिक स्कूल स्तर पर गणित, पर्यावरण विज्ञान, हिन्दी, और अंग्रेज़ी पर ध्यान केन्द्रित करके बच्चों को उनके विषय कौशल और ज्ञान में सुधार करने में मदद करने का प्रयास करता है। कार्यक्रम छात्रों के औपचारिक अधिगम कौशल बढ़ाता है और यह अधिगम के एक पैकेज के रूप में प्रशासित किया जाता है ताकि बच्चे अपनी व्यक्तिगत गति और शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में अपने स्तर के अनुसार आगे बढ़ सकें। कदम अन्य कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि, छात्रों के संज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देने के साथ, यह उनके सामाजिक, भावनात्मक, और वास्तविक जीवन कौशल भी विकसित करता है। जीवन कौशलों का विकास विषयगत शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। अध्ययन के दौरान छात्रों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने के लिए औपचारिक अधिगम और कौशल-आधारित अनुभवों को सम्मिश्रित करके, कार्यक्रम छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यह दृष्टिकोण जीवन की वास्तविक स्थितियों के साथ अधिगम के तर्क और विश्लेषण को एकीकृत करता है।

समुदाय के साथ जुड़ने और अनुभव साझा करने से अधिगम बढ़ता और गहरा होता है। कार्यक्रम में कई आयोजन शामिल हैं—विषय-वस्तु दिवस (Theme Days), छात्र प्रतियोगिताएँ, और अभिभावक-शिक्षक बैठकें (Parent-Teacher Meetings—PTMs)—जिसमें विद्यालय में समुदाय के सदस्यों के साथ छात्रों की अन्तःक्रिया शामिल होती है। यहाँ पुस्तक से परे सीखना एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। गायन और पाठन, ड्राइंग और पेंटिंग, रचना और बनाना, पटकथा और भूमिका मंचन करना कुछ गतिविधियाँ हैं जो रचनात्मकता और समग्र अधिगम को प्रोत्साहित करती हैं। विभिन्न विषय-वस्तुओं के शीर्षक (headlines) (महीने का शीर्षक या विषय) के अन्तर्गत विषयगत शिक्षण, कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि शीर्षक कार्यक्रम के कौशल-निर्माण घटक को सम्बोधित करते हैं। वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की

रूपरेखा 2005 में दिए गए दिशा-निर्देशों से मेल खाते हैं। एक महीने का एक विषय-वस्तु शीर्षक लिया जाता है और विषय-वस्तु पर आधारित कार्यक्रम में छात्रों के स्तर के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाई जाती है। विषय-वस्तु निम्नलिखित दृष्टिकोण, मूल्य, और व्यवहार निर्मित करने का अवसर प्रदान करती है : साझाकरण, स्वीकृति, टीमवर्क, सक्रिय होना, रचनात्मकता, तर्क, और विश्लेषण, और इस प्रकार अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने में मदद करती है।

सम्पूर्ण कार्यक्रम 11 विषय-वस्तुओं में विभाजित किया गया है और प्रत्येक विषय-वस्तु एक माह चलती है। विषय-वस्तु इस उद्देश्य चुनी जाती है कि छात्रों को अपने व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में अधिक जानने और अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने में मदद मिले, जिसमें जीवित प्राणियों और निर्जीव चीजों दोनों की दुनिया शामिल होती है। विषय-वस्तुएँ पाठ्यक्रम के कई अन्य क्षेत्रों को जोड़ने में भी मदद करती हैं और इस प्रकार पाठ्यक्रम में अधिगम को जोड़ती हैं। वे अधिगम को अधिक स्वाभाविक बनाती हैं और कम खण्डित होने देती हैं। वे एक नई सम्बद्ध शब्दावली निर्मित कर अधिगम का उत्तरोत्तर विकास सम्भव बनाती हैं, जो बदले में, छात्रों को पढ़ने से बोलने, और विषय-वस्तु के विचार से जुड़े वाक्य लिखने में मदद करता है। कदम प्रोग्राम में उठाए गए कुछ विषय हैं : वह संसार जिसमें मैं रहती हूँ (The World I Live in); प्रकृति, स्वस्थ शरीर और अच्छी आदतें (Nature, Healthy Body, and Healthy Habits); रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में गणित (Maths in Everyday Life); पृथ्वी पर रहना (Living on Earth); लोग यात्रा, संवाद और काम कैसे करते हैं (How People Travel, Communicate, and Work)। यह विषय-वस्तुएँ आसपास की दुनिया और रोज़मर्रा की गतिविधियों के बारे में बच्चों की जागरूकता बढ़ाने में मदद करती हैं। विषय-वस्तुओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो रहे प्रभावी शिक्षण का पैमाना दर्शाती है और परिणाम इन गतिविधियों के दौरान पूर्ण किए जाने वाले कार्यों के रूप में सामने आते हैं, जिन्हें “उत्पादों” के रूप में भी जाना जाता है। हर महीने एक विषय-वस्तु सप्ताह (Theme Week) आयोजित किया जाता है। यह छात्रों को मासिक शीर्षकों पर चिन्तन करने और उनके काम का प्रदर्शन करने में मदद करता है।

व्यक्तिगत गति से, बहु-श्रेणीकृत शिक्षा : कदम प्रोग्राम एक बहु-श्रेणीकृत शिक्षण वातावरण के निर्माण के माध्यम से कक्षा-कक्ष में सम्पादित किया जाता है जहाँ बच्चे अपनी व्यक्तिगत गति से एक चरण से दूसरे चरण तक उत्तरोत्तर सीखते हैं। प्रत्येक बच्चे का अधिगम स्तर अलग-अलग होता है, और इसी तरह इस बात में भी भिन्नता होती है कि वे कार्यक्रम किस चरण से शुरू करते हैं और किस चरण में समाप्त करते हैं। इसलिए, कक्षा-कक्ष बहु-श्रेणीकृत हो जाता है।

व्यक्तिगत गति से अधिगम किसी बहु-श्रेणीकृत कक्षा-कक्ष का एक अनिवार्य तत्त्व है। चूँकि बच्चे सीखने के अलग-अलग स्तर पर होते हैं, उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से अपने तरीके और अपनी व्यक्तिगत गति से काम करने की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि कुछ बच्चे दूसरों की तुलना में अधिक तेज़ी से सीखते हैं, कुछ बच्चे नियमित होते हैं, और कुछ बच्चे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। छात्रों द्वारा व्यक्तिगत गति से अधिगम इसका जवाब है। कदम में बच्चे अपने कार्य पूर्ण करने के लिए अपना समय लेते हैं, उन्हें समय सीमा या समय सम्बन्धी किसी अन्य प्रतिबन्ध का पालन नहीं करना पड़ता, इस प्रकार उन्हें विभिन्न अवधारणाओं और अधिगम क्षेत्रों का पता लगाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

व्यक्तिगत गति से, बहु-श्रेणीकृत कक्षा-कक्ष की स्थिति में प्रभावी ढंग से अधिगम में लगे रहने के लिए, बच्चों की त्रिमूर्तियाँ (TRIOs) गठित की जाती हैं (अर्थात्, तीन बच्चे एक समूह बनाते हैं)। ध्यान रखा जाता है कि त्रिमूर्ति सदस्य विभिन्न शिक्षण स्तरों पर हों। टीमवर्क और साथ-साथ अधिगम (peer learning) छात्रों के व्यक्तिगत विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे बच्चों को न केवल सामाजिक रूप से व्यवहार्य बनाते हैं, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास अर्जित करते हैं। सामूहिक कार्य के इर्द-गिर्द ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया अपने कार्यक्रम निर्मित करता है जहाँ छात्र एक दूसरे के सहयोग और समन्वय में काम करते हैं। रॉरबैक एवं अन्य (Rohrbeck et al.) के अनुसार, “आधुनिक स्कूल प्रणालियों में साथ-साथ अधिगम का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसे अल्पसंख्यक समूहों को बेहतर ढंग से एकीकृत होने की अनुमति देने में प्रभावी बताया गया है, और साझा अनुभव ने सतत सकारात्मक संवाद की सम्भावना बढ़ाई है।”^{vi}

इसलिए, त्रिमूर्तियाँ कार्यक्रम के निष्पादन का एक अभिन्न अंग हैं। त्रिमूर्तियों में छात्र अपने व्यक्तिगत कार्य या सामूहिक परियोजना पर काम कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक बच्चा अपनी व्यक्तिगत गति से अधिगम कर सकता है और फिर भी वे एक टीम के रूप में काम कर सकते हैं। त्रिमूर्तियों में काम करने से छात्रों में सहयोग, समन्वय, और ज़िम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।

बाल-संचालित अधिगम: कदम प्रोग्राम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह बच्चों को पिछली शिक्षाओं को नई परिस्थितियों में लागू करने, अपने स्वयं के अनुभवों से सीखने, अपने दम पर कार्य पूरा करने की ज़िम्मेदारी लेने, और प्रक्रिया में आत्म-मूल्यांकन करने में मदद करता है। कई कार्यक्रम बाल-उन्मुखी हैं, और इनका बच्चों द्वारा संचालित होना ऐसी विशेषता है जो उनमें ज़िम्मेदारी और स्वामित्व की भावना पैदा करती है ताकि वे अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित कर सकें।

कदम में, बच्चे अपनी स्वयं की शिक्षा को दिशा देते हैं। अनुक्रम सरल है। स्टूडेंट बुक्स में दिए गए अभ्यास कार्य पूर्ण करने का प्रयास करने से पहले, बच्चे मेरी चेकलिस्ट में दी गई अधिगम क्षमताओं से गुजरते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे क्या करने जा रहे हैं; फिर वे सम्बन्धित क्षमता से सम्बन्धित अभ्यास पूर्ण करने का प्रयास करते हैं; एक बार जब सभी सम्बन्धित अभ्यास पूर्ण हो जाते हैं, तो छात्र मेरी चेकलिस्ट पर वापस जाते हैं और वह तारीख भरते हैं, जिस पर उन्होंने क्षमता के लिए सभी अभ्यास पूरे किए थे, इससे वे स्वयं का आकलन करते हैं। मेरी चेकलिस्ट में उनकी प्रविष्टि की बाद में शिक्षक द्वारा हस्ताक्षर के साथ पुष्टि की जाती है।

कदम प्रोग्राम का एक अन्य घटक जो बच्चों को अपना अधिगम स्वयं संचालित करने की अनुमति देता है, वह है ToP चार्ट। ToP चार्ट कार्यक्रम में बच्चों की स्थिति और प्रगति दर्शाता है। उन्होंने कार्यक्रम में कब प्रवेश किया, उन्होंने कैसे प्रगति की, और कब उनके बाहर निकलने का अनुमान है—यह सभी विवरण इस चार्ट में एक नज़र में दिखाई देता है। लगभग सात या आठ साल के छोटे बच्चों के मामले में ToP चार्ट या तो शिक्षक द्वारा भरा जाता है, या बड़े बच्चों के मामले में यह स्वयं छात्रों द्वारा भरा जाता है। बच्चे कार्यक्रम में अपने प्रवेश और विकास के स्तरों को चिह्नित करते हैं, जैसा कि शिक्षक द्वारा उन्हें प्रवेश और बहिर्गमन चरण के चक्रों (Entry and Exit Step circles) के छायांकन द्वारा दिया जाता है। जब बच्चे अपने प्रवेश चिह्न से शुरू होने वाले प्रत्येक विषय के लिए कार्य पूर्ण करते हैं, तो शिक्षक विषयों के लिए दिए गए कार्य के बॉक्स को छायांकित कर देते हैं। ToP चार्ट यह अनुमान लगाने में भी मदद करता है कि बच्चों को मुख्य धारा में कब शामिल किया जा सकता है।

अधिगम का एक लचीला वातावरण बनाना: कदम प्रोग्राम टीमवर्क विकसित करने और अपने दम पर या अपने साथियों की मदद से समस्याओं के समाधान खोजने के लिए कई तरह से बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। अधिगम के अलावा, यह बच्चों का व्यक्तिगत विकास सुविधाजनक बनाने में काफ़ी मदद करता है। कदम सेंटर पर अधिगम का वातावरण बच्चों की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए प्रासंगिक, और विचारशील है, और यह उनके पिछले अधिगम अनुभवों पर आधारित भी है। अधिगम की प्रभावोत्पादकता और निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बाल-प्रवर्तित शिक्षण दृष्टिकोण नियोजित हैं। अधिगम केवल कार्यक्रम में शिक्षार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय की मात्रा तक ही सीमित नहीं है। लचीला अधिगम कक्षा-कक्ष से बाहर निकलकर कई सामाजिक सन्दर्भों में प्रवाहित होता है जो अधिगम के प्रामाणिक अवसर प्रदान करते हैं।

कदम प्रोग्राम विशेष रूप से त्रिमूर्तियों के माध्यम से चलाया जाता है। तीन बच्चों से एक टीम निर्मित होती है और वे कार्यक्रम में निर्धारित किए गए अपने स्वयं के अधिगम लक्ष्यों के माध्यम से काम करते हैं। चूँकि त्रिमूर्ति के सदस्य अधिगम के अलग-अलग स्तरों पर होते हैं,

इसलिए वे आवश्यकता पड़ने पर अनिवार्य रूप से उन शिक्षार्थियों की मदद करते हैं जो उनसे पीछे हों और जब भी आवश्यकता पैदा हो। इससे साथियों द्वारा निर्देशित अधिगम के वातावरण में मदद मिलती है। कई गतिविधियों में इस बात की आवश्यकता भी पड़ती है कि त्रिमूर्तियाँ टीम के रूप में काम करें और कभी-कभी एक से अधिक त्रिमूर्तियाँ एक छोटा समूह बनाती हैं। इससे एक त्रिमूर्ति के भीतर अधिगम का लचीला वातावरण बनाने के साथ-साथ अन्य त्रिमूर्तियों के साथ भी अधिगम का लचीला वातावरण बनाने में मदद मिलती है। लचीला अधिगम है: (1) एक त्रिमूर्ति से दूसरे को अधिगम; और (2) एक नए त्रिमूर्ति सदस्य के लिए अधिगम। जब एक बच्चा मुख्य धारा में शामिल होने के लिए कार्यक्रम से बाहर निकलता है, तो त्रिमूर्ति में उसका स्थान कार्यक्रम में शामिल किसी अन्य बच्चे द्वारा भरा जाता है। यह त्रिमूर्ति के अधिगम प्रवाह को नहीं रोकता, क्योंकि त्रिमूर्ति के अन्य दो सदस्य नए सदस्य के साथ तुरन्त सहयोग और समन्वय पूर्वक काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी त्रिमूर्ति में अधिगम प्रवाह की गति कायम रखते हैं। इसलिए, कदम केन्द्रों में अधिगम का प्रवाह सक्रिय और संवादात्मक रहता है, जिससे हर समय अधिगम का एक लचीला वातावरण बना रहता है।

अधिगम के समन्वयक और सह-निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षक : कदम प्रोग्राम में एक शिक्षक की भूमिका पारम्परिक कक्षा-कक्ष शिक्षक की तुलना में अलग होती है। कदम प्रोग्राम में, शिक्षक की भूमिका एक समन्वयक के रूप में अधिक होती है जो बच्चों पर अपने विचार थोपने के बजाय उनके सन्देह को दूर करने के लिए मार्गदर्शन और मदद प्रदान करता है। शिक्षक बच्चों के लिए अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने, खोजने, और अनुभव करने के अवसर निर्मित करता है। बच्चों को महज़ “चाक और बात” (chalk and walk) विधि के माध्यम से नहीं सिखाया जाता है; इसके बजाय, वे स्वयं करके सीखते हैं। अधिगम की सम्पूर्ण प्रक्रिया बाल-उन्मुखी और बाल-संचालित है और इसका उद्देश्य विशिष्ट अधिगम परिणाम प्राप्त करना है।

कदम शिक्षक गतिविधियों का सह-निर्माता भी है, जो एक अनुकूल अधिगम वातावरण निर्मित करता है और औपचारिक अधिगम एवं सामाजिक कौशल प्राप्त करने में मदद करने के लिए बच्चों को दिलचस्प गतिविधियाँ प्रदान करता है। शिक्षक कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की मुख्य धारा में उनके शामिल होने और वहाँ उनका ठहराव बनाए रखने तक बच्चों को सहयोग प्रदान करता है।

कदम शिक्षक का मंत्र है: “यह अकादमिक की तुलना में बहुत अधिक है जिससे एक छात्र तैयार होता है।” कदम शिक्षक सामिप्राय एक ऐसा वातावरण निर्मित करता है, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए अनुकूल होता है, जो विनम्र और शिक्षित व्यक्ति तैयार करने में सहायक साबित होता है, जिसके लिए वह नीचे उल्लिखित मूल्य विकसित करता है और उनके साथ निम्नलिखित कार्य सतत रूप से करता है :

- बच्चों की बात सुनकर और उन्हें यह दर्शाकर सम्मान देना कि कोई उन चीज़ों की परवाह करता है जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।
- “सर्कल टाइम” (circle time—एक घेरा बनाकर बैठे छात्र) आवण्टित करना बच्चों के साथ जुड़ने और उनका अवलोकन करने का एक अच्छा तरीका है। (एक घेरा बनाकर बैठना एक दूसरे के साथ नयन-सम्पर्क बनाए रखने और एक दूसरे को सीधे सम्बोधित करने का एक उत्तम तरीका है।)
- छात्रों के साथ एक समस्या के माध्यम से सोचना महत्वपूर्ण है। केवल एक बना-बनाया समाधान पेश करने के बजाय, शिक्षक छात्रों के साथ स्थिति या समस्या साझा करता है और उनके द्वारा व्यक्त किए गए मतों पर विचार करता है। उनके द्वारा सुझाए जाने वाले किसी भी विचार या समाधान के गुण-दोषों के बारे में विचार करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना महत्वपूर्ण है।
- अक्सर बच्चों से बात करना, और उनसे पाठों से परे और कक्षा-कक्ष के बाहर बात करना महत्वपूर्ण है। उनसे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछना न केवल शिक्षक और बच्चों के बीच एक सम्बन्ध बनाता है, बल्कि बच्चों के लिए स्वयं को स्पष्ट रूप से और अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करने में भी मददगार होता है।

शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में ठहराव बनाए रखना: कदम का एक अन्य विशेष घटक है छात्रों के स्कूली शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल होने के बाद, औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उनका ठहराव, उन पर नज़र रखना और उनकी सहायता करना। एक बार जब बच्चे को एक आयु-उपयुक्त अधिगम स्तर पर मुख्य धारा में शामिल किया जाता है, तो कदम शिक्षक और संसाधन व्यक्ति अगले छह महीनों तक मासिक आधार पर स्कूल में बच्चे पर नज़र रखते हैं। एक नज़र रखने की उचित प्रणाली और एक रिपोर्टिंग प्रक्रिया माय प्रोग्रेस बुक के आवश्यक घटक हैं जिसमें बच्चे की प्रगति का अभिलेख रखा जाता है।

यह पाया गया है कि जब बच्चे को एक उचित आयु स्तर पर मुख्य धारा में शामिल किया जाता है, तो बच्चे द्वारा पढ़ाई छोड़ने की सम्भावना कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा सेतु पाठ्यक्रम से मिली बुनियादी शिक्षा के साथ नए शिक्षण को जोड़ने में सक्षम होता है। इसलिए, कदम में, अधिगम गतिविधियों की एक ऐसी मज़बूत प्रणाली प्रदान करने पर बहुत ध्यान दिया जाता है जो लम्बे समय तक बच्चे के लिए मददगार रहे, उन अवधारणाओं के लिए एक ठोस नींव का निर्माण करे जिन पर आगे की शिक्षा आधारित हो।

इस बात को भी प्राथमिकता दी जाती है कि कदम सेंटर (जो विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में सेवा प्रदान करते हैं) प्राथमिक विद्यालय परिसर के अन्दर स्थित हों। इससे बच्चे को स्कूल प्रणाली में अनुकूलित होने और स्वयं को उसका एक अंग महसूस करने में मदद मिलती है।

विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, यह एक प्रेरक कारक है जो स्कूल में प्रवेश के प्रति उत्साह पैदा करता है। इन बच्चों के अभिभावकों को एक झलक मिल जाती है कि सेतु पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उनका बच्चा कहाँ होगा। इस प्रकार, यह समुदाय को सक्रिय बनाने में मदद करता है, खासकर जब बच्चे पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं।

कदम स्टेप-अप कार्यक्रम का क्रियान्वयन मॉडल

राज्यों में कदम प्रोग्राम क्रियान्वित करने के लिए ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया के पास एक सुव्यवस्थित संरचनात्मक मॉडल उपलब्ध है, जिसका वर्णन निम्नानुसार है:

- स्तर 1 : संगठनात्मक संरचना में ज़मीनी स्तर पर कदम शिक्षक मौजूद होते हैं। प्रत्येक कदम सेंटर में 25-30 बच्चों के लिए एक शिक्षक होता है।
- स्तर 2 : 10 कदम केन्द्रों से 10 शिक्षकों की एक शिक्षक परिषद बनती है। एक कदम त्वरक (Kadam Accelerator—KA) शिक्षक परिषद का अध्यक्ष होता है और 10 कदम शिक्षकों की शिक्षक परिषद के लिए नेतृत्व, अन्तःकार्य प्रशिक्षण, सलाह, पर्यवेक्षण, और नियंत्रण के कार्य करता है।
- स्तर 3 : 40-80 कदम केन्द्रों वाले ज़िले को एक ज़िला संयोजक (District Organizer—DO) द्वारा समन्वित किया जाता है, जो ज़िला और ब्लॉक शिक्षा विभाग के साथ सम्पर्क करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है, और गुणवत्ता की गारंटी सुनिश्चित करता है।
- स्तर 4 : राज्य स्तर पर, एक राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई (State Project Management Unit—SPMU) हस्तक्षेप का नेतृत्व करती है। इसमें एक कार्यक्रम प्रबन्धक, एक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Management Information System—MIS) विशेषज्ञ, और एक कदम प्रशिक्षक होता है।
- स्तर 5 : राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यक्रम का नेतृत्व नई दिल्ली स्थित ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया मुख्यालय पर मौजूद राष्ट्रीय कदम टीम द्वारा किया जाता है, जिसमें कदम के अग्रणी व्यक्ति और प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रमुख शामिल रहते हैं।

कदम प्रोग्राम का रोलआउट गतिविधियों की एक प्रणालीगत योजना का अनुसरण करता है। यह गतिविधियाँ तीन चरणों में आयोजित की जाती हैं, अर्थात् चरण 1, चरण 2, और चरण 3।

चरण 1 : यह कार्यक्रम के रणनीतिक क्रियान्वयन में सहायक है। इस चरण के महत्वपूर्ण स्तर हैं :

- **चैनलों की सक्रियता:** कदम प्रोग्राम, इसके शिक्षा-विज्ञान और क्रियान्वयन, तथा विभिन्न अधिकारियों के साथ घनिष्ठ साझेदारी विकसित करने के विषय में राज्य परियोजना निदेशक (State Project Director—SPD), ज़िला परियोजना समन्वयक (District Project Coordinator—DPC), ब्लॉक संसाधन समन्वयक (Block Resource Coordinator—BRC), और क्लस्टर संसाधन समन्वयक (Cluster Resource Coordinator—CRC) का उन्मुखीकरण किया जाता है ताकि राज्य में कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम को कैसे क्रियान्वित किया जाए इस बारे में सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का उन्मुखीकरण किया जाता है, और उनके कार्यों और ज़िम्मेदारियों पर चर्चा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कदम केन्द्रों में आने वाले स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को औपचारिक स्कूल में उनकी आयु-अपयुक्त कक्षा में मुख्य धारा में शामिल किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्य धारा में शामिल किए जाने के छह महीने बाद तक स्कूल में उनका ठहराव हो।
- स्कूल से बाहर रह गए बच्चों और विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के क्षेत्रों की पहचान करना : स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की संख्या के आधार पर विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान करने के लिए ही नहीं, बल्कि स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के क्षेत्रों या कैचमेंट क्षेत्रों (catchment areas) की पहचान करने के लिए भी एक मज़बूत निगरानी तंत्र आवश्यक है। एक बार कैचमेंट क्षेत्रों का चयन करने के बाद, शिक्षकों / संसाधन व्यक्तियों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाता है।
- **संरचनात्मक घटक अपनाना:** कदम प्रोग्राम के संरचनात्मक घटक हैं :
 1. प्रत्येक कदम केन्द्र पर एक शिक्षक / संसाधन व्यक्ति और 25 से 30 छात्र होते हैं।
 2. आमतौर पर दो कदम केन्द्र एक साथ जोड़े जाते हैं और एक सरकारी स्कूल के परिसर में स्थित होते हैं।
 3. सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक कार्यक्रम के दैनिक क्रियान्वयन में कदम शिक्षकों / संसाधन व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करते हैं।
- **शिक्षकों और त्वरकों का चयन; और प्रशिक्षण का प्रावधान:** शिक्षकों / विशेषज्ञों की पहचान या तो राज्य द्वारा या राज्य और ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। सभी प्रशिक्षकों की न्यूनतम योग्यता एक बारहवीं परीक्षा प्रमाण-पत्र और ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (District Institute of Education and Training—DIET) या समकक्ष संस्थान से शिक्षा में दो साल का डिप्लोमा है। यह

महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षक और स्कूल से बाहर रह गए बच्चे समान कैचमेंट क्षेत्र से हों और स्थानीय भाषा बोलते हों। टीम को प्रारम्भिक प्रवेशन प्रशिक्षण (initial induction training) ज़िला संयोजकों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह एक व्यापक तीन दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और इसमें स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रशिक्षण शामिल है। वर्ष के दौरान त्रैमासिक अन्तराल पर प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान किया जाता है।

- **सर्वेक्षण में मदद:** स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान करने, और उनसे सम्बन्धित सभी विवरणों को स्कूल प्रमुखों / अधिकारियों से सत्यापित कराने, और फलस्वरूप कदम प्रोग्राम में उनके नामांकन में मदद करने के लिए घर-घर जाकर एक सर्वेक्षण किया जाता है। शिक्षकों / संसाधन व्यक्तियों के साथ एक मानक सर्वेक्षण प्रपत्र साझा किया जाता है। सर्वेक्षण में कैचमेंट क्षेत्र में स्थित प्रत्येक परिवार से विवरण प्राप्त किया जाता है, बिलकुल सही-सही या सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है, और समुदाय को सक्रिय भी बनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि सर्वेक्षण ऐसे समय आयोजित किया जाए जो परिवार के लिए सुविधाजनक हो (कई मामलों में, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के माता-पिता दोनों दिहाड़ी मज़दूरी करने जाते हैं और केवल शाम के समय ही उपलब्ध होते हैं)। यदि अभिभावक मौजूद नहीं हैं, तो सर्वेक्षणकर्ता किसी सुविधाजनक समय पर फिर से उनके घर जाते हैं। सर्वेक्षणकर्ता परिवार की देशी भाषा या मातृभाषा का उपयोग करते हैं ताकि उन्हें और सहजता महसूस हो; यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवार को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लाभों के बारे में समझाने में मदद मिलती है। जानकारी के प्रत्येक अंश की गम्भीरतापूर्वक जाँच की जाती है, उसका सत्यापन किया जाता है, और उसे सर्वेक्षण फ़ॉर्म में लिखा जाता है।

घर-घर जाकर सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद, स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की एक सूची तैयार की जाती है। यह सूची प्रत्येक बच्चे के सत्यापन के लिए सरकारी स्कूल के प्रमुखों / अधिकारियों के सामने प्रस्तुत जाती है कि क्या वह कभी स्कूल नहीं गया या उसने स्कूल छोड़ दिया था। जो बच्चे स्कूल गए थे उनकी स्कूल पंजीकरण संख्या (School Registration Number—SRN) ज्ञात की जाती है। जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए उनकी स्कूल पंजीकरण संख्या प्राप्त की जाती है। पहचान पत्र के रूप में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के आधार कार्ड बनवाए जाते हैं ताकि भविष्य में शिक्षा की प्रणाली में उन पर नज़र रखी जा सके, खासकर जब वे अन्य स्थानों पर जाते हैं या अपने गृहनगर लौटते हैं। जब सूची अनुमोदित हो जाती है, तो माय प्रोग्रेस बुक में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के लिए दिया गया नामांकन फ़ॉर्म अभिलेख रखने के प्रयोजनों के लिए भरा जाता है। 25-30 बच्चों और एक शिक्षक के साथ एक प्राथमिक विद्यालय के परिसर में एक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र या एक कदम केन्द्र स्थापित किया जाता है।

- **बच्चों का अधिगम स्तर ज्ञात करने के लिए उनका आधार-रेखा मूल्यांकन:** शिक्षा प्रणाली में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को मुख्य धारा में आयु-उपयुक्त आधार पर शामिल किए जाने की आवश्यकता है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा में शामिल करने से पहले उनके अधिगम के अन्तराल की पहचान करने के लिए उनके अधिगम स्तर ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, प्रत्येक बच्चे का अधिगम स्तर सुनिश्चित या निर्धारित करने के लिए स्कूल से बाहर रह गए बच्चों का एक आधार-रेखा मूल्यांकन किया जाता है। आधार-रेखा मूल्यांकन बच्चे को सेतु पाठ्यक्रम में उपयुक्त स्तर पर रखने में भी मदद करता है ताकि उसका अधिगम का अन्तराल ठीक ढंग से पाटा जा सके। प्रत्येक बच्चे को आधार-रेखा मूल्यांकन पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षक के साथ 15 मिनट का समय दिया जाता है।

चरण 2: कदम के दूसरे चरण में, बच्चे अपने अधिगम अन्तराल पाटने के लिए आवश्यक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम के सुनियोजित और प्रगतिशील चरणों में भाग लेते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे का सीखना और उसकी प्रगति पटरी पर है। बच्चे की सम्पूर्ण अधिगम यात्रा को लिखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और सभी नोडल अभिकरणों को उसकी जानकारी दी जाती है। इस चरण के महत्वपूर्ण स्तर हैं :

- **सेतु शिक्षा के प्रगतिशील कदम चरण:** बच्चों को आधार-रेखा मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर कार्यक्रम के उपयुक्त चरणों में रखा जाता है। वे अपने अधिगम स्तर से सम्बन्धित मुख्य क्षमताओं के आधार पर अपने स्वयं के अधिगम के स्वामी होते हैं और कार्यों के प्रयास करते हैं। उन्हें उन विषय-वस्तुओं में संलग्न करते हुए कौशल सिखाए जाते हैं जो पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होती हैं। एक बार जब बच्चा किसी चरण की क्षमताएँ प्राप्त कर लेता है, तो वह अधिगम के अगले चरण में शामिल किया जाता है।
- **छात्रों का प्रत्येक दो चरणों / प्रत्येक कक्षा के अन्त में मूल्यांकन:** सम्पूर्ण कदम प्रोग्राम के दौरान एक मज़बूत रैखिक मूल्यांकन प्रणाली (system of linear assessments) का पालन किया जाता है। कक्षा 1 से 5 के लिए पंच कक्षा अन्त्य परीक्षण (Five Grade End Tests) की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि प्राथमिक स्कूल की प्रत्येक कक्षा पूर्ण होने के बाद छात्रों की उपलब्धियों का परीक्षण किया जा सके। जैसे ही कोई छात्र किसी कक्षा के लिए आवश्यक कार्य पूर्ण करता है, उसका एक चरण समाप्ति परीक्षण (Step End Test) किया जाता है। प्रत्येक चरण समाप्ति परीक्षण का दोहरा उद्देश्य है : पहला, उस कक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अधिगम के स्तर की जाँच करना, और दूसरा, अगली कक्षा के लिए छात्र के लिए आवश्यक पूर्वपेक्षाओं की जाँच करना।

चरण 3: जब कदम केन्द्रों पर बच्चों के अधिगम अन्तरालों को पाट दिया जाता है, वे कार्यक्रम के चरण 3 में प्रवेश करते हैं, जो कदम केन्द्र से उनका निर्गम बिन्दु होता है।

इसके बाद, वे औपचारिक स्कूलों में एक नया चरण शुरू करते हैं।

- आयु- और कक्षा-उपयुक्त क्षमता निर्धारित करने के लिए समापन-रेखा मूल्यांकन:** जैसे ही बच्चा आयु-उपयुक्त अधिगम प्राप्त करता है और “स्कूल के लिए तैयार” हो जाता है, एक समापन-रेखा मूल्यांकन आयोजित किया जाता है। समापन-रेखा मूल्यांकन निर्गम स्तरीय मूल्यांकन होता है, जिसका आधार-रेखा मूल्यांकन के साथ सटीक मानचित्रण किया जाता है। यह कार्यक्रम की शुरुआत और कार्यक्रम के अन्त में बच्चे के अधिगम स्तर में अन्तर को निर्धारित करने में मदद करता है, इस प्रकार यह कदम प्रोग्राम की प्रभाविता और प्रभाव का एक पैमाना प्रदान करता है।
- स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल करना:** स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को उनके आयु-उपयुक्त अधिगम स्तर पर मुख्य धारा में शामिल करना आवश्यक है ताकि अपनी शिक्षा का सर्वोत्तम उपयोग करने में उनकी मदद की जा सके और उनका ठहराव सुनिश्चित किया सके। मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन बच्चा कदम प्रोग्राम में प्रवेश करता है। आधार-रेखा मूल्यांकन पूरा हो जाने पर बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ने की योजना में शामिल किया जाता है; इसमें बच्चे के प्रवेश और निर्गम स्तरों का निर्धारण करना शामिल है। पहले शुरू किया गया प्रलेखन कार्य बच्चे के नामांकन के पहले तीन महीनों के भीतर पूरा किया जाता है। समापन-रेखा मूल्यांकन पूर्ण कर लिए जाने के बाद, बच्चा एक आयु-उपयुक्त कक्षा में औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तैयार है। स्कूल के प्रधानाध्यापक के परामर्श से बच्चे को मुख्य धारा में शामिल करने के विषय में एक तिथि का चयन किया जाता है।
- ठहराव सम्बन्धी आगामी कार्यवाही:** मुख्य धारा में शामिल किए छात्र का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए छह महीने तक एक मासिक निगरानी कार्यक्रम का पालन किया जाता है। यह कदम प्रोग्राम का एक अनूठा पहलू है और कदम से आए स्कूल से बाहर रह गए बच्चों का ठहराव बनाए रखने में इसने अभूतपूर्व परिणाम दर्शाए हैं। कदम प्रशिक्षक मासिक आधार पर माय प्रोग्रेस बुक में ठहराव सम्बन्धी चार्ट भरता है और समय-समय पर सभी नोडल अभिकरणों के साथ अभिलेख साझा करता है।

कदम स्टेप-अप प्रोग्राम के परिचालन मॉडल

कदम प्रोग्राम तीन परिचालन मॉडलों का अनुसरण करता है। यह तीन मॉडल हैं :

- मॉडल 1. CSR / फ़ाउण्डेशन द्वारा वित्तपोषित:** इस मॉडल में, कार्यक्रम परिचालन की सम्पूर्ण लागत दाता अभिकरण (donor agency) द्वारा दी जाती है। CSR भागीदारों द्वारा प्रदान किए गए धन की सहायता से, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया कार्यक्रम क्रियान्वित करता है; वह स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान करता है, उन्हें सूचीबद्ध कर उनका सत्यापन कराता है, और प्राथमिक स्कूल में उनका नामांकन कराता है। वह कदम शिक्षकों के रूप में स्थानीय योग्य शिक्षकों या संसाधन व्यक्तियों की पहचान भी करता है, उन्हें भुगतान करता है, और समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षित करता है। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया कदम प्रोग्राम के विषय में समस्त सम्बन्धित सामग्री प्रदान करता है और कदम केन्द्र शुरू करने, संयोजित करने, और संचालित करने के लिए कार्य स्थल पर सहयोग भी प्रदान करता है। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया प्रणालीगत निगरानी और पर्यवेक्षण के साथ-साथ नियमित अन्तराल पर प्रभाव का आकलन करता है और सभी नोडल अभिकरणों को परिणामों की जानकारी प्रदान करता है।
- मॉडल 2. राज्य और CSR / फ़ाउण्डेशन द्वारा सह-वित्तपोषित:** इस मॉडल में, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया सम्बन्धित राज्य / ज़िला कार्यालयों के साथ साझेदारी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम क्रियान्वित करता है। कार्यक्रम के परिचालन के लिए राज्य भुगतान करता है और ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया अपने स्वयं के खर्चों के लिए भुगतान करता है। यह पूरे कार्यक्रम में राज्य को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है। यह राज्य केन्द्रों में कार्यक्रम के संचालन के लिए आवश्यक सामग्री की सॉफ्टकॉपी और अन्य चीज़ें प्रदान करता है; छपाई की लागत राज्य की सर्व शिक्षा अभियान निधि से चुकाई जाती है। कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्य उपलब्ध शिक्षकों या संसाधन व्यक्तियों की पहचान करता है या संसाधन व्यक्तियों को कार्य से जोड़ता है। उनके वेतन और वज़ीफ़ों का भुगतान राज्य द्वारा किया जाता है, और, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया नियमित अन्तराल पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। शिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन के खर्च CSR निधि से चुकाए जाते हैं। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया राज्य / ज़िला अधिकारियों के साथ सम्पर्क करने और कार्य करने तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनी स्वयं की संरचनात्मक टीम की पहचान करता है। यह राष्ट्रीय कदम टीम के साथ चर्चा सत्र भी आयोजित करता है। कदम राज्य टीम कार्यक्रम में सहयोग करती है और निगरानी भी करती है, तथा त्रैमासिक आधार पर एक

प्रबन्धन सूचना प्रणाली तैयार करती है, जिसकी लागत CSR निधि से चुकाई जाती है। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया कार्यक्रम की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्य का मार्गदर्शन करता है, जो स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान के साथ शुरू होता है और उनको मुख्य धारा में शामिल करने के साथ समाप्त होता है। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया विभिन्न चरणों में राज्य / ज़िला अधिकारियों का, विशेष रूप से कार्यक्रम की शुरुआत में, उन्मुखीकरण भी करता है।

- **मॉडल 3. परामर्श सम्बन्धी दृष्टिकोण:** इस मॉडल में, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया विभिन्न स्तरों पर राज्य के अधिकारियों को कार्यक्रम मॉड्यूलों और क्षमतावर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करते हुए राज्य के लिए एक परामर्शदाता निकाय के रूप में काम करता है।

कदम स्टेप-अप प्रोग्राम के क्रियान्वयन में सामने आने वाली कुछ चुनौतियाँ

कदम प्रोग्राम को विभिन्न राज्यों में बढ़ाने के मार्ग में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की परिभाषा राज्यों में अलग-अलग है और केन्द्र में भी भिन्न है। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी गई परिभाषा का अनुसरण करता है। नोडल अधिकारियों से स्कूल से बाहर रह गए बच्चों सम्बन्धी नवीनतम और प्रामाणिक डेटा एकत्र करना मुश्किल है। कदम केन्द्रों पर कार्यक्रम संचालित करने के लिए स्थानीय शिक्षकों की उपलब्धता एक और बड़ी चुनौती है। चूँकि कार्यक्रम अभिभावकों के साथ संवाद और उन्हें अपने बच्चों को कदम केन्द्रों पर भेजने के लिए राज़ी करने के प्रयास के साथ शुरू होता है, इसलिए स्थानीय बोली जानने वाले शिक्षकों की सख्त आवश्यकता होती है। अभिभावकों को विश्वास दिलाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। शिक्षकों और अन्य संसाधन व्यक्तियों को प्रबन्धन सूचना प्रणाली तैयार करने के लिए स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के विवरण (credentials) बिना किसी उलझन के प्राप्त करने, अभिलेखबद्ध करने, और सूचित करने के लिए प्रशिक्षित करना भी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। कभी-कभी कदम केन्द्रों के लिए शिक्षकों, धन, और अन्य संसाधनों के आवण्टन के सम्बन्ध में नोडल अभिकरणों के साथ संचार में विलम्ब हो जाता है। यह बाधाएँ कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उत्पन्न होती रहती हैं। सभी सम्बन्धित पक्षों को दायरे में शामिल कर उनका सर्वश्रेष्ठ हल निकाला जा सकता है।

कदम हस्तक्षेप अब तक

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मौजूद है, जहाँ उसने स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु कदम प्रोग्राम शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड,

और मध्य प्रदेश में कदम प्रोग्राम शुरू करने के लिए निजी संगठनों के साथ साझेदारी की है। जम्मू एवं कश्मीर में काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

विभिन्न राज्यों में कदम प्रोग्राम की नवीनतम जानकारी नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है :

जुलाई 2016 से, ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने 42,329 छात्रों को मुख्य धारा में सफलतापूर्वक शामिल किया और कदम केन्द्रों पर 63,499 बच्चों को नामांकित किया। विभिन्न अभिकरणों और निकायों द्वारा ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया के योगदान की प्रशंसा और सराहना की गई है।

कदम की राज्यवार स्थिति				
क्र.	राज्य	स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के नामांकन की कुल संख्या (परियोजना के आरम्भ से)	जुलाई 2019 तक मुख्य धारा में शामिल किए गए छात्र	% मुख्य धारा में शामिल किए गए
1	हरियाणा	51,348	34,435	67%
2	महाराष्ट्र	1,109	786	71%
3	राजस्थान	271	116	43%
4	दिल्ली	699	313	45%
5	उत्तर प्रदेश	4,056	1,767	44%
6	छत्तीसगढ़	3,704	2,869	77%
7	उत्तराखंड	63	-	0%
8	मध्य प्रदेश	2,249	2,043	91%
कुल		63,499	42,329	67%

कदम एक सफलता की कहानी क्यों है?

किसी भी कार्यक्रम, परियोजना, या हस्तक्षेप की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि कार्यक्रम केन्द्रों की स्थापना, नियंत्रण प्रक्रियाओं को परिभाषित और लागू करना, सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से संवाद करना, और निगरानी की एक ठोस प्रणाली अपनाना। कदम में, इन सभी आवश्यकताओं पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है और विस्तृत जानकारी (inputs) प्राप्त की जाती है, यही वजह है कि कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता मिली है।

कदम को प्रभावी और सफल बनाने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं :

- कदम का शैक्षणिक मॉडल स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के अधिगम अन्तराल को पाटने में प्रभावी है, ताकि उन्हें आयु-उपयुक्त अधिगम स्तर पर मुख्य धारा में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सके।
- कदम प्रोग्राम का अनुठा, समग्र दृष्टिकोण सामाजिक और जीवन कौशलों के साथ संज्ञानात्मक कौशल विकास को प्रोत्साहित करता है।
- कदम का परिचालन मॉडल मापनीयता के पहलू को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
- कदम स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को सफलतापूर्वक नियमित स्कूल दिनचर्या में शामिल करता है, क्योंकि कई बच्चे पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, और समुदायों तथा अन्य हितधारकों को सक्रिय बनाता है।
- स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के एक बार मुख्य धारा में शामिल हो जाने के बाद छह महीने तक लगातार उनके ठहराव पर नज़र रखी जाती है।
- कदम को सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की रूपरेखा और क्रियान्वयन में कुछ लाभ (leverage) प्राप्त हैं।

कदम प्रोग्राम के ये आवश्यक मापदण्ड इसे प्रभावी और कार्यकुशल बनाते हैं, जो औपचारिक स्कूलों में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के ठहराव की बेहतर दर सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया का विश्लेषण दर्शाता है, अब तक (सितम्बर 2018 तक), मुख्य धारा में शामिल किए गए छात्रों की ठहराव दर लगभग 85 प्रतिशत रही है। कदम प्रोग्राम उत्कृष्ट है, क्योंकि बच्चों के अधिगम पर ध्यान देने के अलावा, यह कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अपनी सम्पूर्ण प्रक्रिया में अभिभावकों, सरकारी अधिकारियों, और अन्य हितधारकों को भी शामिल करता है, जिसकी शुरुआत कदम केन्द्रों पर बच्चों के वास्तविक नामांकन से बहुत पहले हो जाती है। यह जुड़ाव कार्यक्रम को एक अलग पहचान प्रदान करता है, सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है, शिक्षार्थियों को शिक्षा का महत्त्व स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और इसमें शामिल सभी लोगों—अभिभावकों, समुदाय, स्कूल अधिकारियों, सरकारी एजेंसियों—में ज़िम्मेदारी की यह भावना विकसित करता है कि स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए।

दृष्टि

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने की अपनी दृष्टि साझा करता है। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया का विश्वास इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि कदम का समग्र दृष्टिकोण इसे एक स्थाई कार्यक्रम बनाता है। जैसे-जैसे शिक्षार्थी आत्मविश्वास हासिल करते हैं, वे अधिगम का आनन्द लेना शुरू करते हैं और औपचारिक शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसके साथ ही, शिक्षा के प्रति समुदाय की

प्रतिबद्धता भी मज़बूत होती है। जब स्कूल की दिनचर्या स्थापित हो जाती है, तो शिक्षार्थी और उनके परिवार स्कूल को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा मान लेते हैं, और बिना किसी सवाल के स्कूल कार्यक्रम का पालन करते हैं।

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्कूल से बाहर रह गए बच्चे अपनी अधिगम की खाई पाट सकते हैं ताकि वे नियमित स्कूलों में प्रवेश ले सकें और अन्य बच्चों के साथ सीख सकें। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया की योजना अगले पाँच से छह वर्षों में, स्कूल से बाहर रह गए 500,000 बच्चों के साथ काम करने और राज्य अधिकारियों एवं शिक्षकों को प्रक्रियाएँ तथा कार्य प्रणालियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करने की है जो बच्चों को यह सीखने में समर्थ बनाएगी कि वे ज़िम्मेदारी के साथ कैसे सीखें और एक स्वाभाविक प्रगति में ज्ञान का सृजन कैसे करें (सिर्फ ज्ञान का प्रदाता होने के बजाय ज्ञान का सृजन करने में बच्चे के साथ एक भागीदार बनना), एक तरह से यह वास्तव में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की भावना और विचार के अनुरूप है।

विकास की ही तरह (जिसकी कहानी संक्षेप में “जीवन का एक नया पट्टा” (A new lease of life) खण्ड में वर्णित है), जिसे कदम प्रोग्राम से लाभ हुआ, कई अन्य लोग अपनी बारी का इन्तज़ार कर रहे हैं। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को मुख्य धारा के स्कूलों में शामिल करने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है ताकि वे अपनी क्षमता को पूर्णतः विकसित कर सकें, अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया की उम्मीद यह है कि एक बार जब शिक्षार्थियों की पहली पीढ़ी बड़ी हो जाएगी, तो वे अन्य पीढ़ियों को अधिक साक्षर होने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे “स्कूल से बाहर रह गए बच्चे (OOSC)” जैसे शब्द अतीत की बात हो जाएंगे।

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया एक विकास संगठन है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत 21 मई 1998 से एक गैर-लाभकारी कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह एक गैर-राजनीतिक, गैर-धार्मिक संगठन है, जो सामाजिक विकास और गरीबी उन्मूलन हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के समग्र विकास के लिए कार्यरत है, विशेष रूप से शिक्षा, जीवन कौशल, आजीविका, महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, और पर्यावरणीय स्थिरता में समन्वित और केन्द्रित हस्तक्षेप। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निजी तथा सार्वजनिक संगठनों के साथ साझेदारी में काम करता है। वर्तमान में ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया भारत के 14 राज्यों में लगभग 74 परियोजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है, जिसकी पहुँच 2 मिलियन से अधिक लोगों तक है।

समाप्ति नोट (Endnotes)

- i. <https://thewire.in/education/the-un-report-on-out-of-school-kids-is-bad-news-for-india-but-the-real-picture-is-worse>
- ii. National Sample Survey of Estimation of Out-of-School-Children in the Age 6-13 in India (2014). Draft report by Social and Rural Research Institute and Educational Consultants India Limited. http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/National-Survey-Estimation-School-Children-Draft-Report.pdf (accessed 26 September 2018). Also see <https://www.cprindia.org/news/6124>
- iii. Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 / Sarva Shiksha Abhiyan Interventional Strategies for Special Training (2013). http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/OoSC.pdf (accessed 26 September 2018)
- iv. MHRD. Guidelines & Special Training and Definition of OoSC, Para 2.2, p. 2.
- v. National Sample Survey of Estimation of Out-of-School-Children in the Age 6-13 in India. <ssa.nic.in/pabminutes-documents/NS.pdf>
- vi. C. A. Rohrbeck, M. D. Ginsburg-Block, J. W. Fantuzzo, & T. R. Miller (2003). Peer-assisted learning interventions with elementary school students: A meta-analytic review. *Journal of Educational Psychology*, 95(2), 240-257.
Also see <http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/courses/ceredocs/oldwikis/9.peerInt.pdf>

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया (HPPI), दिल्ली

ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया (Humana People to People India—HPPI), 1988 में एक गैर-लाभकारी कम्पनी के रूप में पंजीकृत एक विकास संगठन है। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया का मिशन भारत में लोगों के साथ एकजुट होना है ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से ज़्यादा-से-ज़्यादा व्यापक अर्थ में विकास हो सके जिसका लक्ष्य है उन व्यक्तियों और समुदायों को ज्ञान, कौशल, और क्षमता हस्तान्तरित करना जिन्हें ग़रीबी और अन्य अमानवीय स्थितियों से उबरने के लिए सहायता की आवश्यकता है। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया परियोजनाओं में लोगों को साझेदारों के रूप में शामिल कर समाधान खोजने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आवश्यक स्थितियाँ निर्मित करने और एक न्यायसंगत तथा मानवीय जीवन के प्रति व्यक्तियों, परिवारों, और उनके समुदायों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करता है। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ग्रामीण और शहरी भारत में वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के समग्र विकास के लिए समन्वित, रणनीतिक दृष्टिकोणों से सामाजिक विकास और ग़रीबी उन्मूलन हस्तक्षेपों के माध्यम से कार्य करता है जो शिक्षा, जीवन कौशल, बेहतर आजीविका, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

सन्दर्भ तैयार करना

5. आजीविकाओं में हस्तक्षेप सम्बन्धित केस स्टडीज़

कई वर्षों से कृषि, पशुपालन, वनोपज-आधारित आजीविकाओं और हस्तशिल्प जैसी पारम्परिक आजीविकाओं की प्रचुरता रही है। इन व्यवसायों में लगे लोगों की पारम्परिक आजीविका को ख़तरा होने के कारण वे आजीविका के अतिरिक्त या वैकल्पिक साधनों की तलाश करने के लिए मजबूर हैं और लाभदायक रोज़गार पाने के लिए निरन्तर संघर्षरत रहते हैं।

ग़रीबों, हाशिए पर रहने वालों और अरक्षितों की आजीविकाओं में सुधार के लिए राज्य और ग़ैर-राज्य संगठनों ने कई कार्यक्रम और हस्तक्षेप लागू किए हैं। यह हस्तक्षेप कई रूपों में क्रियान्वित किए गए, जैसे—संसाधनों तक पहुँच में सक्षम बनाने वाले आदान (inputs), वित्तीय सेवाएँ एवं प्रौद्योगिकी, क्षमतावर्धन, आजीविका विविधीकरण को बढ़ावा देना, आदि—जो या तो अपने-आप में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं या इनमें से कम-से-कम दो हस्तक्षेपों के संयोजन के रूप में एकीकृत होकर कार्य करते हैं। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य आय में सुधार करना, और नक़दी प्रवाह की अनिश्चितता घटाना, ग़रीब परिवारों के बीच लचीलेपन को बढ़ावा देना और अन्ततः ग़रीबी में कमी लाना है।

आमतौर पर कई हस्तक्षेपों की कल्पना और उनका क्रियान्वयन 'एक ही हस्तक्षेप सभी के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त' दृष्टिकोण से की गई है जिसमें आशयित लाभार्थियों सम्बन्धी ज्ञान और आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया जा रहा है या बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे, सभी लाभार्थी समूहों में इस तरह के हस्तक्षेपों के परिणाम और लाभ एक समान नहीं रहे हैं और, कई मामलों में, वांछित प्रभाव प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान इस आभास के कारण विभिन्न सहभागी और सहयोगात्मक दृष्टिकोणों को बढ़ावा मिला कि जहाँ केन्द्रीकृत प्रयास सफल नहीं हो सके वहाँ विकेन्द्रीकरण और स्थानीय भागीदारी बेहतर ढंग से कार्य कर सकती है।

विकास के सहभागी दृष्टिकोणों और हस्तक्षेपों में स्थानीय समुदाय, सामाजिक क्षेत्र के संगठन, अनुसन्धान संगठन, सरकार, और अन्य हितधारक शामिल होते हैं। उनमें उत्पादन सम्बन्धी हस्तक्षेप, सेवा प्रदान करना, लोक शासन, स्थानीय संसाधनों का संरक्षण, क्षमतावर्धन, स्थानीय समुदायों की शिकायतों और चिन्ताओं को आवाज़ देना, आदि शामिल है। हालाँकि,

इस आधार पर सहभागी दृष्टिकोणों की आलोचना की गई है कि यह जिन समुदायों के साथ कार्य करते हैं मौजूदा शक्ति सम्बन्धों में उन समुदायों के पक्ष में बदलाव लाने के प्रयास करने और समुदायों को अपने जीवन, अधिकारों तथा आजीविकाओं का प्रभार लेने में सक्षम बनाने के बजाय समुदायों की भागीदारी को यंत्रवत तरीकों तक सीमित करते हैं।

दो केस स्टडीज़ 'कलेक्टिव यूनिटी ट्रायम्फ्स' (Collective unity triumphs) और 'कोलेबोरेटिव लर्निंग : अनलीशिंग सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट' (Collaborative learning : Unleashing sustainable transformative development) भागीदारी और विकेन्द्रीकरण के कई पहलुओं का पता लगाती और चित्रण करती हैं—लोगों का अभिकरण, सामुदायिक जुड़ाव और किसी हस्तक्षेप एवं सहयोग के सभी चरणों में विभिन्न हितधारकों के बीच सक्रिय भागीदारी का महत्त्व : सरकार, सामाजिक क्षेत्र के संगठन, अनुसन्धान संगठन, और समुदाय।

'कलेक्टिव यूनिटी ट्रायम्फ्स' (Collective unity triumphs—सामूहिक एकता की जीत होती है) केस स्टडी मालधारियों के बारे में है जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बन्नी के पशुपालक हैं। यह देहाती आजीविकाओं पर विभाजन, उद्योगीकरण और अदूरदर्शी हस्तक्षेपों के प्रतिकूल प्रभाव का वर्णन करता है, और मालधारियों ने राजनीतिक, पारिस्थितिक, और आर्थिक बाधाओं पर सामूहिक कार्यवाही एवं समुदाय के नेतृत्व में की गई पहलों के माध्यम से किस तरह जीत हासिल की। मालधारी समुदाय के बुजुर्गों को अपनी आजीविकाओं की अनिश्चित स्थिति का अहसास हुआ और सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से बन्नी भैंस की नस्ल के संरक्षण के लिए ठोस प्रयास किए, बन्नी के चरागाहों पर अपने अधिकार पुनः प्राप्त किए और समुदाय में अपनी पारम्परिक जीवन शैली के प्रति गौरव को बहाल किया। गुजरात में सीमान्त समुदायों के साथ काम करने वाले सामाजिक क्षेत्र के एक संगठन, सहजीवन (Sahjeevan) ने मालधारी समुदाय के प्रयासों में सहयोग प्रदान किया। इन प्रयासों का एक प्रमुख परिणाम बन्नी ब्रीडर्स एसोसिएशन (Banni Breeders Association—BBA) नामक एक समूह का पंजीकरण था, जिसमें 1000 से अधिक मालधारियों की सदस्यता थी। बन्नी ब्रीडर्स एसोसिएशन ने सामान्य सम्पत्ति संसाधनों पर समुदाय के अधिकारों की मान्यता और प्रत्येक गाँव में वन अधिकार समितियों के गठन के लिए सरकार के साथ परामर्श के लिए मार्ग प्रशस्त किया। भैंस की बन्नी नस्ल को पंजीकृत कराने के लिए (जिससे भैंस की कीमतें दोगुनी हो गई) और बन्नी के पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और प्रलेखन के लिए एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के लिए बन्नी ब्रीडर्स एसोसिएशन ने अकादमिक और अनुसन्धान संस्थानों तथा सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम किया।

‘कोलेबोरेटिव लर्निंग : अनलीशिंग सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट’ (Collaborative learning unleashing sustainable transformative development—सहयोगात्मक अधिगम : स्थाई और परिवर्तनकारी विकास को उजागर करना) केस स्टडी पश्चिम बंगाल के एक दूरस्थ वन्य गाँव चुरिनसोरो में काम करने के प्रोफ़ेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (Professional Assistance for Development Action—PRADAN) के अनुभवों के बारे में है। पहली केस स्टडी की तरह, यह केस भी विभिन्न हितधारकों के बीच विकास के सहयोगात्मक प्रयासों के महत्त्व पर प्रकाश डालता है, जिसमें स्थानीय समुदाय एक सार्थक और उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। विशेष रूप से, यह इस धारणा को दूर करता है कि अनुसन्धान शिक्षाविदों और विकास कार्य करने वालों से सम्बन्धित एक विशिष्ट क्षेत्र है और उन लोगों, विशेषकर महिलाओं, को शामिल करने के लिए एक मज़बूत तर्क देता है जिनके जीवन और कार्यों का अध्ययन किया जा रहा है। शोध हेतु प्रश्न और उद्देश्य निर्धारित करने के प्रत्येक स्तर पर छोटे भूमि धारक किसानों की गहन भागीदारी के माध्यम से, ‘शोधकर्ता के रूप में समुदाय’ की भूमिका शुरु से ही मज़बूती से स्थापित की गई। इस परियोजना का एक और अनूठा पहलू अनुसन्धान के प्रबन्धन, परियोजना में भागीदारी के स्तरों से सम्बन्धित निर्णय लेने, जानकारी साझा करने और निगरानी करने में स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित की गई महिला किसानों को शामिल किया जाना है। चार साल की परियोजना के परिणामस्वरूप भाग लेने वाले परिवारों के लिए फ़सल प्रणाली में बदलावों के माध्यम से भोजन की पर्याप्तता सुनिश्चित हुई है, भोजन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हुआ है, महिला किसानों के कठोर परिश्रम में कमी आई है और महिला सशक्तिकरण हुआ है।

सहजीवन और PRADAN की दो केस स्टडीज़ से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष यह है कि हस्तक्षेपों और कार्यों के सामुदायिक स्वामित्व के महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लोगों के अभिकरण को ग़ैर-सरकारी संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ और अन्य हितधारकों द्वारा उनके साथ मिलकर काम किया गया तथा उनके मौजूदा ज्ञान और कौशलों का दोहन करने, स्थानीय आवश्यकता-आधारित योजना तैयार एवं क्रियाचिंत करने और साथियों से सीखने को प्रोत्साहित किया करने में उनका सहयोग किया गया, उपरोक्त तरीक़े समुदायों में दीर्घकालिक और स्थाई सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं क्योंकि शीर्ष पाद विधियाँ (top down methods) समुदायों की अपनी आवश्यकताओं की ज़िम्मेदारी लेने की क्षमता को अनदेखा करती हैं। कोई सिर्फ़ यह अनुमान ही लगा सकता है कि यदि हस्तक्षेप इन संगठनों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होते और समुदाय महज़ एक निष्क्रिय लाभार्थी होता तो भी क्या ऐसा ही होता।

5.1 सहयोगात्मक अधिगमः

स्थाई और परिवर्तनकारी विकास को उजागर करना

प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट एक्शन (PRADAN), पश्चिम बंगाल¹

सारांश

अत्यधिक गरीबी और भुखमरी की व्यापकता कृषि-आधारित आजीविका को एक निर्णायक हस्तक्षेप बना देती है। हालाँकि, कृषि आजीविकाओं के लिए हस्तक्षेप अक्सर प्रौद्योगिकी और कृषि-विज्ञान सम्बन्धी समाधानों के रूप में पाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य होता है या तो बड़ी हुई आय या बड़ी हुई उत्पादकता। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में, अक्सर किसानों, विशेषकर महिला किसानों, की वास्तविक चिन्ताएँ अनुत्तरित ही रह जाती हैं। कृषि-आधारित आजीविकाओं की महत्वपूर्ण समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से सम्बोधित किया जा सकता है यदि सामुदायिक संगठन, विकासात्मक संस्थाएँ, और शोध संस्थाएँ समुदाय द्वारा पहचानी और व्यक्त की गई समस्याओं के प्रासंगिक समाधान खोजने के लिए सहयोगात्मक तरीके से काम करें।

यह केस स्टडी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में अयोध्या पर्वत में चुरिनसोरो नामक एक दूरस्थ वन्य-सीमान्त गाँव के निवासियों की आजीविका और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से किए गए एक हस्तक्षेप का वर्णन करती है। समुदाय, विकास अभिकरण, और विभिन्न अनुसन्धान संगठनों ने मिलकर बदलाव लाने का काम किया। किसानों द्वारा तैयार किए गए अनुसन्धान प्रश्नों के आधार पर, एक अनूठी किसान-केन्द्रित अनुसन्धान पद्धति अपनाई गई, जो इस विचार पर आधारित थी कि परिवर्तन लाने में महिला किसानों की क्षमता एक महत्वपूर्ण चालक (driver) थी। सहयोगात्मक कृषि, किसान द्वारा किसान से सीखना, और वैज्ञानिकों के साथ अन्तराफलक (interface) महिलाओं द्वारा स्वयं को द्वितीयक चालक समझने की आत्म-धारणा में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के साधन थे, ताकि वे स्वयं को कृषि उत्पादन का द्वितीयक चालक समझने के बजाय किसानों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, और परिवर्तनकारों के रूप में मुख्य चालक समझें।

1 कुंतलिका कुंभाकर और सुमिता कसाना के सहयोग से।

1. सहयोगात्मक अधिगम: स्थाई और परिवर्तनकारी विकास को उजागर करना—परिचय

आजीविका के कृषि-आधारित अवसरों की चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से सम्बोधित किया जा सकता है, जब हम ऐसे विषयों पर शोध करने वाले भागीदारों के साथ सहयोग करते हैं जो आजीविका के अवसर के लिए प्रासंगिक हैं, जैसे—कृषि, मिट्टी, और जल विज्ञान। आमतौर पर, अनुसन्धान और विकास (Research & Development—R&D) सम्बन्धी हस्तक्षेप सहयोग नहीं करते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि अनुसन्धान लक्षित समुदाय के साथ संयुक्त रूप से समस्याओं की पहचान करने, अनुसन्धान प्रतिभागियों के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्यवाही योजना तैयार करने, और फिर नियोजित कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस पर अनुसन्धान करने, या दूसरे शब्दों में, कार्यवाही अनुसन्धान करने के बजाय केवल समस्याओं के कारण उजागर करता है, या कुछ हस्तक्षेपों की जाँच करता है, जो विकास एजेंसियों द्वारा पहले ही किए जा चुके होते हैं। जब हम अपने अनुसन्धान उपक्रम में समुदाय को एक समान भागीदार और सहयोगी बनाते हैं, जब हम संयुक्त रूप से सीखते हैं और एक साथ विकसित होते हैं, तो हमारे पास समुदाय के नेतृत्व में स्थाई परिवर्तनकारी विकास का नुस्खा होता है, जो सक्रिय प्रयोग के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने के लिए लोगों की क्षमता बढ़ाता है।

यह केस स्टडी विकास परियोजना के लिए किसी कृषि अनुसन्धान की जाँच करती है जो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों, भारतीय गैर-सरकारी संगठनों—PRADAN और एडवांस्ड सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (Advanced Center for Water Resources Development and Management—ACWADAM), अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान संगठन वर्ल्ड वेज (WorldVeg—पूर्ववर्ती AVRDC), और सबसे महत्वपूर्ण रूप से छोटे भूमि धारक किसानों के बीच एक साझेदारी थी, जो अनुसन्धान के आशयित लाभार्थी थे। परियोजना की एक विशिष्ट और अभिनव विशेषता अनुसन्धान गतिविधि में किसानों का भागीदारों के रूप में गहरा जुड़ाव था। इस परियोजना ने किसानों को अनुसन्धान में भागीदार बनाने की एक प्रक्रिया विकसित की। इसने समुदाय के साथ जुड़ाव के सभी तरीकों में बुनियादी दृष्टिकोण के रूप में कोल्ब का अधिगम चक्र (Kolb's learning cycle) अपनाया। किसान के जुड़ाव की इस प्रक्रिया के परिणाम शोधकर्ता की प्रारम्भिक अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। अनुसन्धान प्रश्नों की पहचान करने के महत्वपूर्ण चरण के दौरान अधिक दृढ़ता, अनुसन्धान गतिविधि में निर्मित अधिगम के अवसरों की पहचान, अनुसन्धान के नतीजों का स्वामित्व, अनुसन्धान के नतीजों का किसान-से-किसान तक प्रसार, अभिकरण की बढ़ी हुई भावना और महिला किसानों का सशक्तिकरण, तथा स्वतंत्र नवाचार के लिए बढ़ी हुई क्षमता की एक स्थाई विरासत जो कृषि अनुसन्धान से परे है, इन परिणामों में शामिल थे।

II. सन्दर्भ: लोग और सामाजिक एवं पारिस्थितिक परिदृश्य

चुरिनसोरो गाँव पश्चिम बंगाल राज्य में पुरुलिया ज़िले में, अयोध्या पंचायत के बाघमुंडी ब्लॉक में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के सबसे दूरस्थ और सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। 2011 तक, यह नक्सली आन्दोलन का गढ़ था। इसकी एक सीमा झारखण्ड से जुड़ी हुई है, एक बहुत घना वन क्षेत्र है जिसके जंगलों और पहाड़ियों ने नक्सलियों को एक सुविधाजनक मार्ग प्रदान किया। सरकारी कार्यक्रम और सुविधाएँ लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थीं।

चुरिनसोरो गाँव के निवासी संथाल, हो, और बेदिया जैसे सजातीय आदिवासी समूह हैं, और अपनी विशेष पहचान कायम रखते हैं। वे व्यापक भेदभाव का सामना करते हैं और समाज की मुख्य धारा से अलग-थलग हैं। आजीविका विकल्पों की उनकी टोकरी अत्यधिक श्रमसाध्य है, जिसमें कम फ़ायदे के लिए कमर-तोड़ शारीरिक श्रम शामिल है। इन स्थितियों में महिलाओं को सबसे ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। उन्हें मज़दूरों के रूप में देखा जाता है, चाहे वे अपने खेतों में काम करें या दूसरों के खेतों में; चाहे वे लकड़ी और वनोपज इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाएँ या ज़मीन की खुदाई करें।

तालिका 1 : 2011 की जनगणना के अनुसार बाघमुंडी ब्लॉक का जनसांख्यिकीय विवरण

परिवारों की संख्या	27,508
कुल जनसंख्या	135,579
ग्रामीण जनसंख्या	135,579
अज्ञा + अज्ञा जनसंख्या (%)	35.46
साक्षरता दर (%) पुरुष	60
साक्षरता दर (%) महिला	35

लोग मिट्टी के घरों में, छप्पर या पक्की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं और उनके पास बहुत कम सम्पत्ति होती है। इस क्षेत्र की भाषा पश्चिम बंगाल के बाक़ी हिस्सों से बिलकुल अलग है और इसे कम विकसित माना जाता है। अक्सर इस क्षेत्र के लोगों को हेय दृष्टि देखा जाता है और ग़ैवार (असभ्य) माना जाता है।

इस क्षेत्र की विशेषता है उच्च लेकिन परिवर्तनशील वर्षा (1,100-1600 मिमी, 80 प्रतिशत जून-सितम्बर में होती है), मानसून के दौरान लगातार और कभी-कभी लम्बे शुष्क दौर, कम सिंचाई (क्षेत्र का ~8 प्रतिशत), उच्च अपवाह और मिट्टी का कटाव, सीढ़ीदार एकफ़सली धान भूमि, और जीविका कृषि। ऊँचाई पर स्थित भूमि अकसर अनुपजाऊ होती है और समग्र कृषि उत्पादकता में काफी कम योगदान देती है। ग़रीब किसानों की नीची भूमि तक पहुँच, यदि है, तो बहुत कम है, जहाँ चावल परम्परागत रूप से उगाया जाता रहा है। थोड़ा मशीनीकरण हुआ है; चावल के अलावा अन्य फ़सलों के बीज आमतौर पर हाथ से बोए जाते हैं; घास फूस हाथ से हटा दिया जाता है; और उर्वरक (यदि उपयोग किया जाता है) हाथ से डाले जाते हैं। इस क्षेत्र में खेती के निहित जोखिम के साथ, इन ग़रीब किसानों द्वारा जोखिम के अतिरेक के कारण आदानों का उपयोग करने में संकोच किया जाता जाता है। परिणामस्वरूप, ज़्यादातर ग्रामीण खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं, जिनकी खाद्यान्न आवश्यकता का केवल 50-60 प्रतिशत ही खेत की उपज से पूरा होता है। यह चालक व्यापक कुपोषण, साक्षरता के निम्न स्तर, विशेष रूप से लड़कियों में, और सीमित प्रयोज्य पारिवारिक आय के कारण चिकित्सा सेवाओं तक सीमित पहुँच में योगदान करते हैं। सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (Socio Economic and Caste Census—SECC) से प्राप्त अभावग्रस्तता का डेटा उचित आवास (D1), साक्षरता (D6), और आय के मुख्य स्रोत के रूप में शारीरिक श्रम (D7) के सन्दर्भ में अभाव का उच्च स्तर दर्शाता है।

III. अवधारणा

जटिल सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए, एक मापनीय, सन्दर्भ-उपयुक्त मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है जो समुदाय में स्थाई परिवर्तन सुनिश्चित करे, उनकी जल सुरक्षा को मज़बूत करे, और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनके लचीलेपन में मददगार हो। ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च (Australian Centre for International Agricultural Research—ACIAR) द्वारा संचालित प्रोजेक्ट LWR / 2002 / 100 के निष्कर्षों के आधार पर यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेस्टर्न सिडनी के प्रोफ़ेसर पीटर कॉर्निश (Prof. Peter Cornish) के नेतृत्व में यह शोध परियोजना 'वाटर हार्वेस्टिंग एंड बेटर क्रॉपिंग सिस्टम्स फॉर स्मालहोल्डर्स ऑफ़ द ईस्ट इंडिया प्लैटो' (Water harvesting and better cropping systems for smallholders of the East India Plateau) तैयार की गई थी (2006-11)। दोनों परियोजना सन्दर्भ क्षेत्र कमोबेश एक जैसे थे, सिवाय इसके कि चुरिनसोरो भौतिक दृष्टि से अधिक दूरस्थ था और बेहतर कृषि पद्धतियों से ग्रामीणों के सम्पर्क का अभाव अधिक व्यापक था। पहले की परियोजनाओं से चुरिनसोरो में अपनाए गए कुछ सबक थे:

- कृषि-आधारित आजीविका विकास पर काम करने में जटिल बदलाव लाना शामिल है और यह विस्तार के लिए वयस्क-शिक्षण सिद्धान्तों पर आधारित एक नए दृष्टिकोण की

माँग करता है, जिसमें किसानों के रूप में महिलाओं की सार्थक भागीदारी पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

- किसान अपनी स्वयं की अनूठी जलवायु-अनुकूल प्रणाली विकसित कर लेंगे, लेकिन उन्हें अपने जल संसाधनों को समझने (जिनमें स्थान और समय अनुसार भिन्नता होती है), और उनका फ़सल के विभिन्न विकल्पों के साथ मेल (दालों, सरसों, गेहूँ, और सब्जियों की प्रमाणित फ़िस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुँच) करने के लिए आवश्यक जानकारी से लैस और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी नई तकनीक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें विस्तार के लिए एक उपयुक्त, आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो किसानों की क्षमताओं और आकांक्षाओं के प्रति सम्मानपूर्ण हो।
- विस्तार अभिकरणों द्वारा एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जो किसानों को महज़ बताने के बजाय उन्हें सीखने की सुविधा प्रदान करे। इससे उनका आत्मविश्वास निर्मित होता है और स्वतंत्र अधिगम और नवाचार के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि होती है।
- महिलाओं के संस्थानों (स्वयं सहायता समूहों) को कृषि नवाचार के नायकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, उनकी भूमिका सूक्ष्म वित्त और महिलाओं के मुद्दों तक ही सीमित नहीं की जानी चाहिए, और न ही उन्हें केवल पुरुष किसानों तक पहुँचने के लिए साधनों के रूप में देखा जाना चाहिए।

उपरोक्त सबक़ों के आधार पर, इस परियोजना की रूपरेखा अनुसन्धान और विकास दोनों के परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार की गई थी। अनुसन्धान घटक ACIAR द्वारा वित्तपोषित किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वी भारत के पठार (East India Plateau—EIP) में तीन ज़िलों में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में शोध को परिष्कृत और मान्य करना था। यह प्रक्रिया किसान-नेतृत्व वाली अनुभवात्मक शिक्षा से प्रेरित है, जिसकी सुविधा PRADAN द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इसमें ऑस्ट्रेलियाई अनुसन्धान टीमों, एशियन वेजीटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (Asian Vegetable Research and Development Center—AVRDC),ⁱ ACWADAM,ⁱⁱ और बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय (Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya—BCKV),ⁱⁱⁱ का सहयोग प्राप्त है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अनुसन्धान परा-अनुशासनिक (transdisciplinary) है। परियोजना की अवधि चार वर्ष (2012-2016) थी।

परियोजना में कई पूरक दृष्टिकोणों से खूबियाँ ग्रहण करते हुए एक अनूठी किसान-केन्द्रित अनुसन्धान पद्धति विकसित की गई है, जिसमें सहभागी कार्यवाही अनुसन्धान (Participatory Action Research—PAR – Kurt Lewin), विकास के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट (Agricultural Research for Development—AR4D), और सामूहिक या

सामाजिक शिक्षण सिद्धान्त (Kolb's learning cycle) शामिल हैं। इन सभी पद्धतियों की एक सामान्य विशेषता सम्पूर्ण अनुसन्धान गतिविधि के केन्द्र बिन्दु के रूप में किसान पर ध्यान बनाए रखना है। हमारे दृष्टिकोण का मूल तत्त्व किसान के जुड़ाव की हमारी प्रक्रिया है।

निम्नलिखित सहित, अनुसन्धान प्रक्रिया के सभी पहलुओं में किसान शामिल हैं :

1. शोध प्रश्नों की पहचान और विकास करना
2. किसानों के खेतों में प्रायोगिक उपचार का संचालन करना और कृषि प्रबन्धन करना
3. डेटा संग्रह में सहायता करना और उपचार प्रभावों के अवलोकन संघारित करना
4. प्रयोगात्मक परिणामों की व्याख्या में योगदान करना और व्यवहारिक अन्तर्दृष्टि जोड़ना
5. शोध के परिणाम अन्य किसानों तक पहुँचाना।

हमारे किसान-केन्द्रित दृष्टिकोण के अनुरूप, परियोजना महिला किसानों के एक समूह के साथ काम करती है, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों के तहत समूहीकृत किया गया है। चुरिनसोरो में दो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें गाँव के लगभग सभी परिवारों के सदस्य समूहीकृत हैं। स्वयं सहायता समूह अधिगम और जानकारी साझा करने एवं आपसी मदद हेतु प्रणाली विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं; वे सामंजस्य और सामूहिकता को बढ़ावा देते हैं, जो सदस्यों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाते हैं। परियोजना ने सामुदायिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित किया, और स्वयं सहायता समूह वह मंच था जहाँ इन सामुदायिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया गया।

IV. संचालन

1. परियोजना की शुरुआत और अनुसन्धान के प्रश्नों और उद्देश्यों का निर्धारण

परियोजना का समग्र उद्देश्य स्थानीय किसानों को लचीली और अनुकूल फ़सल और पशुधन प्रणालियाँ विकसित करने में सक्षम बनाकर आजीविकाओं में सुधार लाना था जो उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करें, जिससे परिवार के स्तर पर जलवायु परिवर्तन / परिवर्तनशीलता के प्रति लचीलापन पैदा हो। इसके लिए पानी, मिट्टी, फ़सलों एवं पशुधन पर शोध, और किसान के स्तर पर इन सभी गतिविधियों के एकीकरण की आवश्यकता थी। इस प्रकार, परियोजना टीम में शामिल होने के लिए उपयुक्त भागीदारों की पहचान की गई। टीम में ACWADAM, AVRDC, BCKV, ACIAR और PRADAN के पेशेवर शामिल थे। प्रत्येक स्तर पर सहभागी दृष्टिकोण की

भावना कायम रखते हुए, परियोजना टीम के अन्य भागीदारों के साथ एक आरम्भिक कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में इस परियोजना में अपनाए जाने वाले मूल सिद्धान्तों की रूपरेखा बताई गई। यह थे:

- व्यक्ति पर और व्यक्ति के स्थानीय ज्ञान पर ध्यान केन्द्रित होगा।
- स्वयं सहायता समूह केन्द्र बिन्दु होगा और महिलाएँ अनुसन्धान का नेतृत्व करेंगी।
- आरम्भ में कोई बाहरी फ़सल नहीं लगाई जाएगी; इसके बजाय, मौजूदा फ़सलों की प्रकृति, दायरे, और विशेषताओं को समझने पर ध्यान दिया जाएगा।
- अनुसन्धान प्रश्न समुदाय की आकांक्षाओं से जुड़े होंगे।

ग्रामीणों को परियोजना से परिचित कराने के लिए, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह सदस्यों और उनके जीवनसाथियों व अनुसन्धान भागीदार को लक्षित करते हुए, कार्यशालाओं और बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इन बैठकों और कार्यशालाओं की रूपरेखा का पूर्व-निर्धारण किया गया, और इनमें समुदाय की भागीदारी, महिलाओं और पुरुषों दोनों की, सुनिश्चित की गई। PRADAN के पेशेवर इन आयोजनों के प्रमुख सूत्रधार थे, और उन्होंने ग्रामीणों के साथ परियोजना के विचार और उद्देश्यों पर चर्चा की। यह बात स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुँचाई गई कि परियोजना एक अनुसन्धान परियोजना थी जिसके परिणाम उस बिन्दु पर काफ़ी हद तक अज्ञात थे और किसान करते हुए सीखेंगे। इस परियोजना के गुण-दोषों और सीखने में सफलता सुनिश्चित करने के लिए लोगों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर भी बैठकों में चर्चा की गई।

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (Participatory Rural Appraisal—PRA) उपकरणों का उपयोग करते हुए, परियोजना के उद्देश्य को सामने रखते हुए समस्या का मानचित्रण किया गया, जिससे भूमि की विभिन्न श्रेणियों से जुड़ी भूमि सम्बन्धी समस्याएँ, उन भूमियों पर उगाई जाने वाली फ़सलें, उत्पादकता, सिंचाई, पशुधन, और ऐसी ही अन्य समस्याओं पर ग्रामीणों के साथ गहराई से चर्चा की गई। इन आयोजनों के दौरान, अनुसन्धान से जुड़े प्रश्नों और प्रयोगों की पहचान की गई, स्पष्ट किए गए, और समुदाय के साथ संयुक्त रूप से उनकी रूपरेखा तैयार की गई। एक शोधकर्ता के रूप में समुदाय की भूमिका शुरू से ही स्थापित की गई, और इस बात पर जोर दिया गया कि यह उनकी भूमि, उनकी कृषि, और उनका शोध था। अनुसन्धान परियोजना के लिए किसानों द्वारा व्यक्त किए गए मुद्दों में से कुछ थे:

1. मध्य भूमि और उच्च भूमि (midland and upland) क्षेत्रों में धान की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए : किसानों के पास केवल तीन से छह महीने के लिए पर्याप्त भोजन था, और उनकी अधिकांश भूमि मध्य-उच्च भूमि है। यह भूमि रोपे जाने वाले चावल के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है और अनियमित वर्षा के कारण चावल की फ़सलें अकसर बिगड़ जाती हैं।

2. मक्का को एक लाभदायक फ़सल कैसे बनाया जाए : मक्का इस क्षेत्र की एक पारम्परिक फ़सल है। यह मुख्य आहार का हिस्सा भी है, जिसका सेवन धान की अनुपलब्धता की स्थिति में दलिया के रूप में किया जाता है। हालाँकि, इसकी कम उत्पादकता एक समस्या थी। किसान मक्का को एक महत्वपूर्ण फ़सल के रूप में क़ायम रखना और इसकी उत्पादकता बढ़ाना चाहते थे।
3. क्या खरीफ़ के बाद दूसरी फ़सल लेना सम्भव है : किसान सरसों और अन्य फ़सलें उगाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि बिना सिंचाई के दो फ़सलें प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा।
4. टमाटर की खेती कैसे बेहतर बनाई जाए : किसान भूमि के छोटे टुकड़ों पर टमाटर की खेती करते थे, लेकिन वे अच्छा लाभ प्राप्त करने में असमर्थ थे। पानी और श्रम की कमी को देखते हुए वे भूमि के एक ही टुकड़े पर उत्पादकता बढ़ाना चाहते थे। एक और समस्या उनकी टमाटर की फ़सलों की अल्प भण्डारण अवधि थी, जिसके कारण वे उन्हें कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर थे। किसान टमाटर की उत्पादकता में वृद्धि करना चाहते थे और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार लम्बी भण्डारण अवधि वाले और एक जैसे आकार के टमाटर के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण करना चाहते थे।

इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, अनुसन्धान के उद्देश्यों की पहचान की गई और उन्हें स्पष्ट किया गया। यह उद्देश्य थे :

1. भूदृश्य में उपलब्ध जल संसाधनों (वर्षा, अवशिष्ट भू-जल) की परिवर्तनशीलता तथा मौसमीपन का विश्लेषण करने, और इस जानकारी को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जो फ़सल-प्रबन्धन के निर्णय लेने में किसानों के लिए सहायक हो, जोखिमों और अवसरों दोनों की पहचान करना।
2. धान की पारम्परिक खेती से खराब हुई मिट्टी को सुधारने के लिए चावल के बाद दूसरी फ़सल उगाने की सुविधा मिल सके।
3. फ़सल के विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करने के लिए स्थानीय किसानों के साथ काम करना, तत्परता और लचीलेपन पर ज़ोर देना, ताकि किसानों को बुवाई के अभिनव अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके।
4. उत्पादकता, संसाधन-उपयोग में कार्य-कुशलता, और पारिवारिक खाद्य सुरक्षा एवं आय के सन्दर्भ में नई एकीकृत फ़सल प्रणालियों से जुड़े अवसरों और जोखिमों का विश्लेषण करना।
5. प्रमाणन प्रक्रिया का अध्ययन करना : विकास कार्यक्रमों के प्रमाणन के प्रभावी और कार्य-कुशल तरीक़े विकसित करना, जो किसानों को खाद्य सुरक्षा, पारिवारिक आय, एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, और फ़सल उत्पादन को बढ़ाने वाले स्थानीय नवाचार विकसित करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें।

ब. शोधकर्ता किसानों और प्रयोग भूखण्डों का चयन

खेत पर की जाने वाली इस अनुसन्धान गतिविधि के लिए, PRADAN को ऐसे किसानों की आवश्यकता थी जो सहभागी बनने के लिए तैयार हों। परियोजना की शुरुआत से समुदाय के जुड़ाव ने किसानों के एकसमान भागीदार बनने के लिए मंच तैयार किया। परियोजना में पहला क़दम अनुसन्धान प्रश्नों की पहचान करना और उन्हें अन्तिम रूप देना था। अगला क़दम किसानों का चयन था। एजेंडे पर चर्चा करते समय, स्वयं सहायता समूहों ने एक दिलचस्प पहलू प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उनके सभी सदस्यों, यानी लगभग 30 परिवारों को, अनुसन्धान अध्ययन में शामिल किया जाना आवश्यक था। इसने हमें नए ढंग से सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के साथ प्रयोग और उनकी निगरानी हमारे लिए एक कठिन काम होगा। प्रारम्भ में, PRADAN ने दो प्रकार के किसानों को शामिल करने की योजना बनाई थी : पहले शोधकर्ता किसान थे, जो नई और अभिनव कृषि प्रणाली पर अनुसन्धान के लिए कार्य प्रणालियों के अनुशंसित पैकेज के साथ ACIAR और PRADAN के साथ शोध अध्ययन में भाग लेंगे; और दूसरे नियंत्रण किसान थे, जिन्होंने पारम्परिक कृषि का तरीका अपनाया।

एक चर्चा के बाद, PRADAN ने शोधकर्ता किसानों की तीन श्रेणियों का प्रस्ताव रखा। पहली श्रेणी में “मुख्य किसान शोधकर्ता” थे; इस श्रेणी से सम्बन्धित अनुसन्धान डेटा का संग्रहण गहनता से किया जाना था; दूसरी श्रेणी में “मध्यम किसान शोधकर्ता” थे; इस श्रेणी से सम्बन्धित अनुसन्धान डेटा केवल कुछ मापदण्डों पर एकत्र किए जाने थे; और तीसरी श्रेणी में “बुनियादी किसान शोधकर्ता” थे; इस श्रेणी का उत्पादन डेटा तुलना करने और फ़र्क देखने के उद्देश्य से पारम्परिक फ़सलों के नियंत्रण भूखण्डों की आवश्यकता को सम्बोधित करते हुए ज्ञात और एकत्र किया जाएगा जो पारम्परिक कार्य प्रणालियों का उपयोग करके उगाई जानी थीं। यह समूहीकरण महिलाओं को स्वीकार्य था, और उन्होंने परिवारों को अनुसन्धान में उनकी रुचि और उनके भूमि के आकार के आधार पर शीघ्र ही तीन श्रेणियों में विभाजित किया। भूमि के आकार से सम्बन्धित बिन्दु दिलचस्प था, क्योंकि काफ़ी समझदारी से, उन्होंने सोचा कि छोटे भू-खण्ड वाले किसानों को प्रयोगों का जोखिम नहीं लेना चाहिए। बाद में, परिवार अतिव्याप्त (overlap) हो गए। एक ही किसान के पास कभी-कभी मूल अनुसन्धान के लिए एक भूखण्ड और साथ ही नियंत्रण अनुसन्धान के लिए एक भूखण्ड था। यह बदलाव शोध अध्ययन की आवश्यकताओं और किसानों के बढ़ते उत्साह के जवाब में भी प्रस्तावित किया गया था।

गाँव की बस्ती के तीस परिवार शामिल किए गए, जिससे अनुसन्धान गतिविधियों का बेहतर प्रबन्धन सम्भव हुआ। उदाहरण के लिए, मवेशियों के चरने की समस्या को आसानी से निपटाया गया, जिसे सब्जियों और अन्य फ़सलों की खेती का विस्तार करने के मार्ग में एक प्रमुख

अवरोध माना जाता था। मवेशियों को चारा देने के लिए, ग्रामीणों ने छोटे भूखण्डों में नैपियर घास उगाई, जो अपने-आप में कृषि प्रणालियों और किसानों की मानसिकता में बदलाव का प्रतीक है।

किसानों के चयन के बाद, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को विभिन्न अनुसन्धान प्रयोगों के लिए भूमि और / या भूखण्डों का चयन करने का अवसर दिया गया। न्यूनतम भूमि की आवश्यकता मध्यम ऊँची भूमि श्रेणी की दशांश थी, जिसकी पहचान महिलाओं ने प्रबन्धन और प्रदर्शन में आसानी को ध्यान में रखते हुए की। एक समूह के रूप में निर्णय लेते हुए विभिन्न भूखण्डों पर प्रयोगों की योजना बनाना और संचालन करना आसान और सुविधाजनक बना।

स. अपनाई गई प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ

स्वयं सहायता समूह बैठक-अभिप्रेरण, सहभाजन, और निगरानी करने के लिए एक मंच: अनुसन्धान कार्यक्रमों के प्रबन्धन के लिए शीर्ष पर स्वयं सहायता समूह का होना कार्य के प्रमुख घटकों में से एक होने के साथ-साथ दृष्टिकोण का मुख्य केन्द्र बिन्दु था। स्वयं सहायता समूह की साप्ताहिक बैठक नियमित रूप से प्रगति के अद्यतनीकरण और उस पर चर्चा करने का मंच बन गई। प्रारम्भ में, PRADAN के पेशेवरों ने साप्ताहिक बैठकों में भाग लिया और बाद में, जब स्वयं सहायता समूह ने कार्यभार संभाला, वे हर पखवाड़े बैठकों में शामिल होते थे। PRADAN के पेशेवरों की सहायता से स्वयं सहायता समूह सदस्य प्रयोग का कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। प्रासंगिक निर्देशों के साथ, प्रत्येक प्रयोग का विवरण सावधानीपूर्वक समझाया गया, स्पष्ट किया गया, और उस पर चर्चा की गई। महिलाओं ने कार्यक्रम, निगरानी, और प्रगति के मूल्यांकन का कार्य संभाला। सामने आने वाली समस्याओं पर स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने चर्चा की और उनका समाधान किया। उन्होंने नियमित रूप से फ़ील्ड दौरों के माध्यम से फ़ील्ड अनुसन्धान (field research) के सभी घटकों का क्रियान्वयन, और इसके पालन तथा निगरानी में आवश्यक सटीकता सुनिश्चित की। महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की, अनुसन्धान का संचालन किया, और साप्ताहिक बैठकों में अपनी प्रगति का अद्यतन विवरण प्रदान किया।

महिलाएँ पुरुषों को प्रयोग और उसके घटकों का विवरण समझातीं और फिर संयुक्त रूप से इसे उनके साथ क्रियान्वित करती थीं। यह गतिविधि उनकी साप्ताहिक बैठक का एक हिस्सा बन गई, जिससे निगरानी और मूल्यांकन एक निर्बाध प्रक्रिया बन गई।

स्वयं सहायता समूह मंच अन्य भागीदारों द्वारा भी किसी भी तरह के संवाद के लिए नोडल मंच के रूप में स्थापित किया गया था। स्वयं सहायता समूह की साप्ताहिक बैठकों में, अनुसन्धान भागीदारों ने अपने शोध घटक समझाए। इरादा यह था कि इस मंच के माध्यम से महिला सदस्यों की क्षमता का विकास किया जाए और उन्हें साधारण भाषा में सभी प्रासंगिक तकनीकी और अन्य ज्ञान प्रदान किया जाए।



फ़ार्मर फ़िल्ड स्कूल (FFS)—सीखने, प्रयोग करने, और कार्य करने के लिए एक मंच : फ़ार्मर फ़िल्ड स्कूल (Farmer Field School—FFS) मॉडल प्रदर्शन के लिए अपनाया गया था। किसानों का स्कूल किसी विशिष्ट फ़सल या फ़सलों के एक विशेष समूह के आधार पर चलाया जाता था। जो महिलाएँ वह विशेष फ़सल उगाने की योजना बनातीं, वे किसानों के स्कूल में भाग लेती थीं। आमतौर पर फ़सल की वृद्धि के विभिन्न चरणों में चार या पाँच अलग-अलग प्रदर्शन किए जाते थे। प्रत्येक प्रदर्शन से पहले एक संक्षिप्त बैठक आयोजित की जाती थी, जिसमें महिलाएँ अपने फ़िल्ड के अनुभवों और पिछले प्रदर्शन से प्राप्त सीखों को साझा करती थीं। कार्य प्रणालियों का सम्पूर्ण पैकेज (Package of Practices—POP) चार या पाँच मॉड्यूलों में विभाजित किया गया था। इनमें से प्रत्येक को एक अलग प्रदर्शन में सिखाया जाता था। स्वयं सहायता समूह सदस्यों को विभिन्न कृषि उपकरणों और औज़ारों के उपयोग के तरीक़े का प्रशिक्षण दिया जाता था और उन्हें फ़ार्मर फ़िल्ड स्कूल में नई कृषि कार्य प्रणालियों

का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने और समझने के लिए साधारण उपकरणों एवं खेलों का सहारा लिया जाता था। उदाहरण के लिए, मिट्टी की नमी की अवधारणा समझाने के लिए स्पंज का उपयोग किया जाता था। इसी तरह, साधारण उपकरणों का स्थानीय भाषा में वर्णन किया जाता था ताकि स्वयं सहायता समूह सदस्य फ़सल प्रणाली और विभिन्न फ़सलों की पानी की आवश्यकताओं (चित्र 1) को समझ सकें। फ़ार्मर फ़ील्ड स्कूल का उद्देश्य कृषि कार्य करने के बारे में महिलाओं में अधिक आत्मविश्वास जगाना था, ताकि वे भी खुद को किसान के रूप में देख सकें और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। फ़ार्मर फ़ील्ड स्कूल से प्राप्त सबक स्वयं सहायता समूह में दोहराई जाती थीं ताकि सदस्य कार्य योजनाओं पर चिन्तन, उनका विश्लेषण, और उन्हें तैयार कर सकें। प्रत्येक स्तर पर प्लान-डू-ऑब्ज़र्व-रिफ्लेक्ट-प्लान (Plan-Do-Observe-Reflect-Plan) की चक्रीय प्रक्रिया का मूल प्रक्रिया के रूप में पालन किया जाता था।

अनुसन्धान भागीदारों में से एक AVRDC ने फ़सल विविधीकरण और उन्नत कृषि पद्धतियाँ प्रदर्शित करने के लिए स्वयं सहायता समूह सदस्यों के साथ अपनी बातचीत में फ़ार्मर फ़ील्ड स्कूल मॉडल अपनाया। ACWADAM स्टाफ़ ने भौम जल स्तर (water table) मापने, रिसाव और अवशिष्ट नमी के स्तरों का आकलन करने और सम्बन्धित उपकरणों का उपयोग करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया। अपनी अन्य परियोजनाओं में, ACWADAM इस काम के लिए एक अलग कर्मचारी नियुक्त करता। हालाँकि, यहाँ इसने महिलाओं की क्षमताओं का विकास किया, जो उनके लिए एक नया अनुभव और सीख थी। एक सदस्य के घर पर एक लघु मौसम केन्द्र स्थापित किया गया, और महिलाओं को इसे संचालित करने और रीडिंग लेने के लिए प्रशिक्षित किया गया। महिलाओं की निम्न साक्षरता दर उनके अभिलेख रखने और प्रमापकों (gauges) को पढ़ने में एक बाधा थी, लेकिन फिर भी अधिकतर सभी सदस्य जानकारी समझ जाते थे। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के परामर्श से डेटा की व्याख्या और विश्लेषण किया जाता था, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और पानी की गति एवं फ़सल की उत्पादकता से उसके सम्बन्ध के बारे में उनकी समझ में वृद्धि हुई।

कृषि सम्बन्धी मौसमी बैठक—एक सामुदायिक अधिगम मंच : यह बैठकें अनुसन्धान के एक चक्र के अन्त में आयोजित की जाती थीं, जो कृषिक मौसम के अन्त के साथ मेल खाता था। इन बैठकों में, सुविधाप्रदाता द्वारा विशिष्ट सामुदायिक टिप्पणियों की सुनवाई सुनिश्चित की गई। बैठकें पहले से तय की जाती थीं और इनमें सभी साझेदार—AVRDCS, ACWADAM, स्वयं सहायता समूह सदस्य और उनके जीवनसाथी—उपस्थित होते थे। PRADAN ने मुख्य सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाई। इन बैठकों की अवधि लगभग चार से पाँच घण्टे होती थी। यह चुरिनसोरो खरीफ़ मौसम के मध्य में और समीक्षा चिन्तन बैठक रबी मौसम में, और अनुसन्धान का एक चक्र पूर्ण होने पर, जो आमतौर पर कृषिक मौसम के अन्त के साथ मेल खाता था, आयोजित की जाती थीं। इसलिए सालाना कम-से-कम दो बैठकें होती थीं।

मध्य-सत्र की बैठकों में उन शोध प्रयोगों के बारे में चर्चा होती थी जो उस अवधि के दौरान किए जा रहे होते थे। इन बैठकों में बैठक की शुरुआत में फ़िल्ड के कामकाज की चर्चा शामिल थी जब सभी उपस्थित व्यक्ति अपनी टिप्पणियाँ साझा करते थे और इन पर अपना मत प्रकट करते थे। विशिष्ट सामुदायिक टिप्पणियाँ सुना जाना सुविधाप्रदाता द्वारा सुनिश्चित किया जाता था। पाँच WH (who, when, what, where, how—कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे) के ढाँचे का उपयोग करते हुए एक समालोचनात्मक चर्चा की जाती थी, जिसमें फ़िल्ड के कामकाज के अवलोकनों की सहायता ली जाती थी। सम्भावित समाधान और की जाने वाली कार्यवाहियों पर भी संयुक्त रूप से चर्चा की जाती थी।

खरीफ़ और रबी दोनों कृषि मौसमों सहित अनुसन्धान के एक चक्र के अन्त में आयोजित होने वाली मौसम के अन्त में की जाने वाली बैठक एक वार्षिक कार्यक्रम था, जिसमें सभी भागीदार उपस्थित रहते थे। रेखाचित्रों (graphs) और अन्य साधारण उपकरणों के माध्यम से डेटा साझा किया जाता था; वैज्ञानिक डेटा के साथ-साथ समुदाय की समझ का विश्लेषण किया जाता था। अनुभव का समेकन करते हुए आगामी वर्ष के लिए नई कार्ययोजनाएँ तैयार की जाती थीं।

द. सम्पर्कन, अधिगम मंच, और प्रमाणन

किसानों द्वारा प्रयोगों के लिए चुने गए भूखण्ड अधिकतर मुख्य सड़क पर स्थित थे, जहाँ अन्य ग्रामीणों के लिए पहुँचना आसान हो। इसलिए, कई किसानों में किए जा रहे प्रयोगों के बारे में उत्सुकता पैदा हुई और उन प्रयोगों के परिणामस्वरूप उपजी फ़सलों ने उनका ध्यान आकर्षित किया और उनकी रुचि जागृत हुई। आरम्भ में कुछ अनियोजित सम्पर्कन (exposure) हुए जब समुदाय ने अनौपचारिक रूप से अपने अनुभव साझा किए। द्वितीय वार्षिक आयोजन के दौरान, एक कार्यशाला के दौरान किसानों की तीन श्रेणियों के साथ कृषि पद्धतियों और किसानों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर एक फ़ोकस ग्रुप चर्चा (Focus Group Discussion—FGD) आयोजित किया गया : जिसमें अनुसन्धान से जुड़े किसान, नियंत्रण किसान, और अनुसन्धान से जुड़े किसानों के जीवनसाथी शामिल थे। इसका उद्देश्य एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना और अनुसन्धान से जुड़े तथा नियंत्रण किसानों की तुलना करना, जो परिवर्तन हुए थे उन परिवर्तनों के प्रति उनकी धारणा और प्रतिक्रिया का आकलन करना था। फ़ोकस ग्रुप चर्चा के दौरान, जब उनके जीवन में सकारात्मक बदलावों पर चर्चा हो रही थी, तब महिलाओं ने दूसरों के जीवन में इसी तरह के सकारात्मक बदलाव लाने में उनकी मदद करने का विचार प्रकट किया। इस प्रकार, एक अधिगम मंच का विचार उभरा, जो स्कूली शिक्षा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले “पेशेवर शिक्षण मंच” से प्रेरित था। लुइस स्टॉल एवं अन्य (Louise Stoll et al., 2006: 221) के शब्दों में : “पेशेवर शिक्षा विकसित करते हुए समुदाय सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण की उल्लेखनीय सम्भावना संजोए प्रतीत होते हैं।”^{iv}



चुरिनसोरो में समीक्षा चिन्तन बैठक

विभिन्न मंचों पर अपनी फ़ोरम बैठकों में स्वयं सहायता समूह संस्थानों ने किसानों को आमंत्रित करने के लिए अपने योजनाबद्ध कार्यक्रम के बारे में प्रचार-प्रसार किया ताकि किसान आकर उनकी जीवन बदल देने वाली उपलब्धियाँ देखें। यह निःशुल्क परिचयात्मक दौरे थे, जिसमें अन्य गाँवों के किसान और स्वयं सहायता समूह सदस्य गतिविधियों के बारे में जानने और उनका अवलोकन करने के लिए स्वयं आते थे। PRADAN पेशेवरों के साथ महिलाओं ने, दौरे और फ़ील्ड कामकाज के चरणों की रूपरेखा तैयार की। अपने स्वयं के अनुभवात्मक अधिगम के आधार पर, महिलाओं ने आगन्तुकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें विषय के बारे में अधिक गहराई से जानने में मदद मिली। महिलाओं ने यह भी निर्णय लिया कि परिचयात्मक दौरा कृषि के विषय तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने स्वयं के जीवन में आए बदलावों के बारे में भी बताया जा सकेगा। कुल मिलाकर, 28 परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 34 गाँवों में फैले सभी 90 स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया गया। अधिगम को व्यापक बनाने के लिए, कृषि मौसम की शुरुआत में जब भूमि तैयार की जा रही थी और बीज बोए जा रहे थे, प्रत्येक समूह को एक दौरा कराया गया। अगला दौरा कृषि मौसम के अन्त में कराया गया जब फ़सल पूरी तरह से पक चुकी थी और कटाई शुरू हो गई थी। महिला किसान शोधकर्ता अपनी जानकारी और अधिगम के बारे में आश्वस्त थे, जो यात्रा के दौरान परिलक्षित होता था जब वे आने वाले किसानों के सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते थे। कुछ ने आगन्तुकों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वे यह नई कार्य प्रणालियाँ अपनाना चाहते हों तो वे उन्हें सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

V. परिवर्तन और कायापलट

अ. आजीविका टोकरी और फ़सल प्रणाली में बदलाव

खाद्यान्न की पर्याप्तता किसानों की प्रमुख चिन्ता थी, और इसलिए धान की अधिक उपज हस्तक्षेप के बिन्दुओं में से एक था। किसान धान की खेती के लिए मध्य-तराई के बजाय मध्य-ऊँची भूमि का उपयोग करना चाहते थे। हालाँकि, वे पानी की अनुपलब्धता के कारण धान की खेती नहीं कर सकते थे। मिट्टी के प्रकार और पानी / नमी की उपलब्धता के आधार पर, तराई क्षेत्रों में सघन धान प्रणाली धान और मध्य-तराई और मध्य-उच्च भूमि और में एरोबिक डायरेक्ट सीडेड राइस (Aerobic Direct Seeded Rice—ADSR) की खेती करने का प्रस्ताव रखा गया। हालाँकि किसान सघन धान प्रणाली से परिचित थे, जिसकी वे तराई में खेती कर रहे थे, ADSR की अवधारणा उनके लिए नई थी। शुरु में उन्हें ADSR उगाने के बारे में सन्देह था, क्योंकि उन्हें लगता था इससे अच्छी उपज नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि धान की रोपाई के बजाय, उन्हें धान के बीज सीधे एक क़तार में बोना होंगे। उन्होंने यह अपनी पारम्परिक प्रसारण विधि के समान लगा, अब जिसका उपयोग वे कम उत्पादकता के कारण नहीं करते। पहले वर्ष में, केवल सात किसानों ने ADSR का प्रयोग किया। “ग्रामीणों ने सोचा कि हम ग़ुँगे थे। वे कहते थे कि यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको अच्छी उपज कैसे मिलेगी। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतनी ही अच्छी पैदावार मिलेगी,” एक स्वयं सहायता समूह सदस्य ने कहा जिसने ADSR का प्रयोग किया था। एक अन्य स्वयं सहायता समूह सदस्य ने कहा, “जो लोग स्वयं सहायता समूह का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने पहले साल में हम पर शक किया और हमारी हँसी उड़ाई।” हालाँकि, परिणाम तत्काल सामने आ गए, क्योंकि पहले वर्ष में उत्पादकता कम बारिश से प्रभावित हुई थी, और ADSR के तहत आने वाली मध्य-उच्च भूमि हरी भरी थी और उनमें अच्छी उपज हुई। दूसरे वर्ष में, कई किसानों ने ADSR का रुख किया; यहाँ तक कि नियंत्रण किसान भी ADSR आजमाना चाहते थे। सघन धान प्रणाली से किसानों के मध्य तराई क्षेत्रों में कई गुना उत्पादन हुआ, जिससे खाद्य सुरक्षा की अवधि में वृद्धि हुई,^v और ADSR ने भूख की अवधि घटाने में मदद की, जिससे गाँव में परिवारों को सम्पूर्ण खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई। चित्र 2vi खाद्य पर्याप्तता के सन्दर्भ में परिवारों की संख्या में बदलाव दर्शाता है। आँकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में 70 प्रतिशत परिवारों को 12 महीने खाद्य सुरक्षा और 30 प्रतिशत परिवारों को छह से 10 महीने के बीच खाद्य सुरक्षा प्राप्त है।

किसानों द्वारा व्यक्त दूसरी चिन्ता मक्का की खेती को पर्याप्त रूप से लाभदायक बनाने की थी ताकि वे इसे उगाना जारी रख सकें। कम उत्पादकता के कारण मक्के की खेती में गिरावट आ रही थी। किसानों को डर था कि अन्य मोटे अनाजों की तरह मक्का भी उनके आहार से गायब हो जाएगा। चूँकि मक्के का सांस्कृतिक महत्त्व है और यह एक पारम्परिक फ़सल रही है, इसलिए किसान मक्के की खेती को पर्याप्त लाभदायक बनाना चाहते थे ताकि इसे क़ायम

रखा जा सके। अन्तर-फ़सल में सहायता के लिए मक्के की क़तार बुवाई की गई और इससे खरपतवारों की अनियंत्रित वृद्धि भी कम हुई। महिलाओं ने पहली बार परिवार की आय में बढ़ोतरी करते हुए कई नई कृषि पद्धतियाँ जैसे कि फलीदार पौधों के साथ मक्के की अन्तर-फ़सल अपनाई। किसानों ने मक्के के साथ फलीदार पौधे उगाए। हेमलता दीदी नामक एक अनुसन्धान कृषक ने टिप्पणी की,

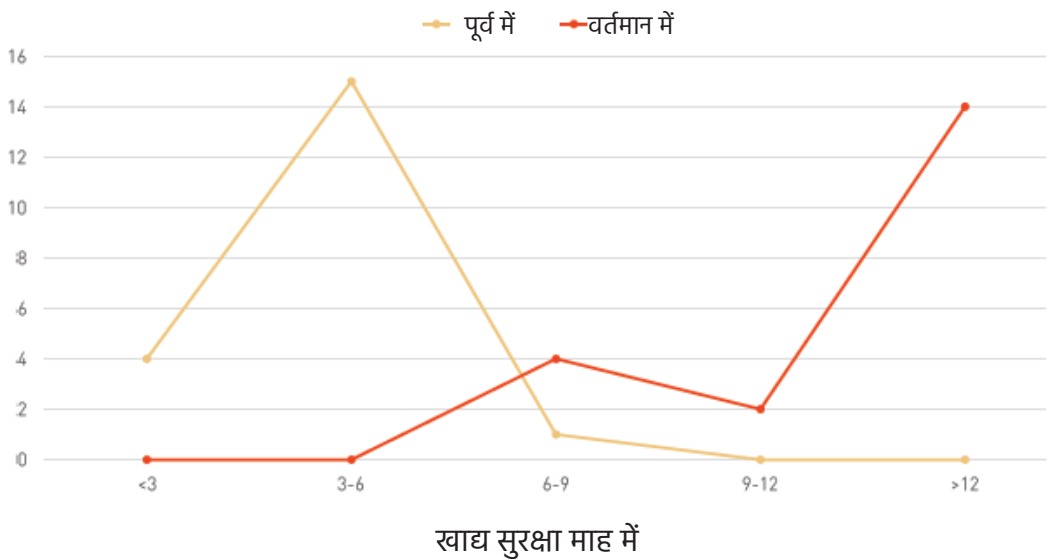


“पहले हमें लगा कि मक्के के उत्पादन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। हम कभी भी बुवाई के बाद भूखण्डों को नहीं देखते और निंदाई बहुत दुःखदायी थी, लेकिन अब अन्तर-फ़सल करने के साथ, हम मक्के के खेतों में अधिक बार जाते हैं और उपज भी अच्छी होती है।”



किसानों ने मक्के के साथ-साथ विभिन्न फ़सलों की खेती करने की भी कोशिश की, जैसे—फलियाँ, लोबिया, और हरी मटर। एक नई फ़सल के रूप में सोयाबीन को आजमाया गया, लेकिन वह विफल रही; बीज अंकुरित नहीं हुए। इसलिए किसानों ने एक स्थानीय फ़सल मक्के के साथ-साथ लोबिया और सेम की फली की खेती की।

खाद्य सुरक्षा में बदलाव



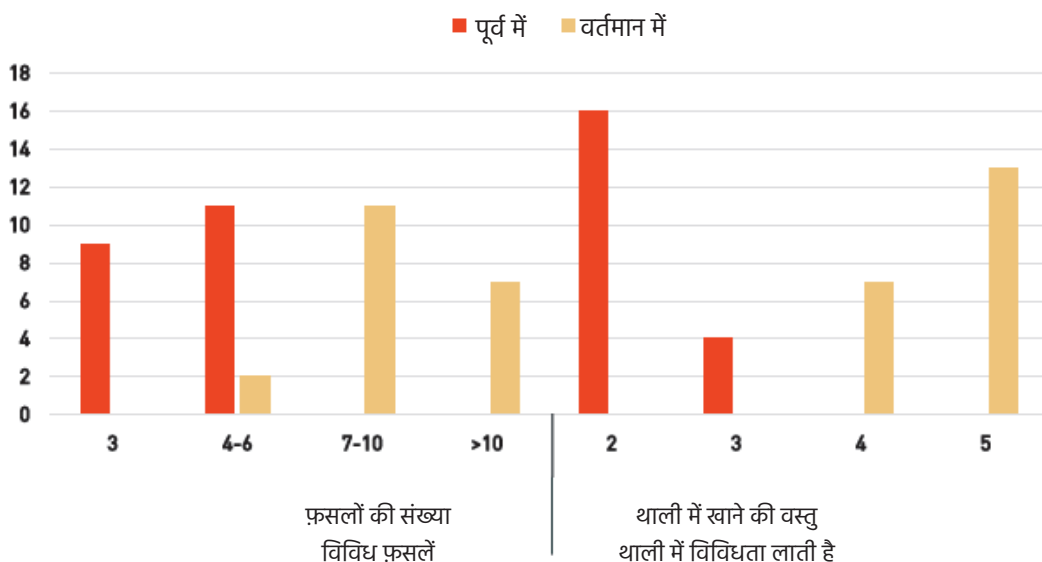
तीसरे शोध प्रश्न के लिए, टमाटर की एक स्थानीय किस्म का परीक्षण किया गया। गढ़े वाली विधि का उपयोग करते हुए टमाटर की खेती की गई, जिससे पौधों को बेहतर सहारा देने में मदद मिली, स्वस्थ पौधों की पैदावार हुई और बेहतर गोल फलों का उत्पादन हुआ।

किसानों को अन्य सज्जियों से भी परिचित कराया गया। बड़े हुए आत्मविश्वास के साथ, बाद के वर्षों में किसानों ने अपने दम पर विभिन्न किस्मों का परीक्षण किया और आजमाया। एक किसान ने कहा, “मैं इस किस्म का परीक्षण करना चाहता हूँ, इसलिए भले ही मैं कुछ हद तक उत्पादकता खो दूँ, मुझे पता चल जाएगा कि क्या उपयुक्त है।” उन्होंने बेलों के लिए गढ़े और जाली पर चढ़ाने की विधि (pit-and-trellis method) अपनाई। उन्होंने टमाटर की नई किस्मों के साथ-साथ कद्दू, मटर और गोभी भी उगाई। दालों जैसी नई अपनाई गई फ़सलों, जिसमें अरहर और चना शामिल हैं, ने परिवार के लिए नक़दी की आपूर्ति और खाद्य विविधता सुनिश्चित की।

ब. आहार और पोषण में बदलाव^{vii}

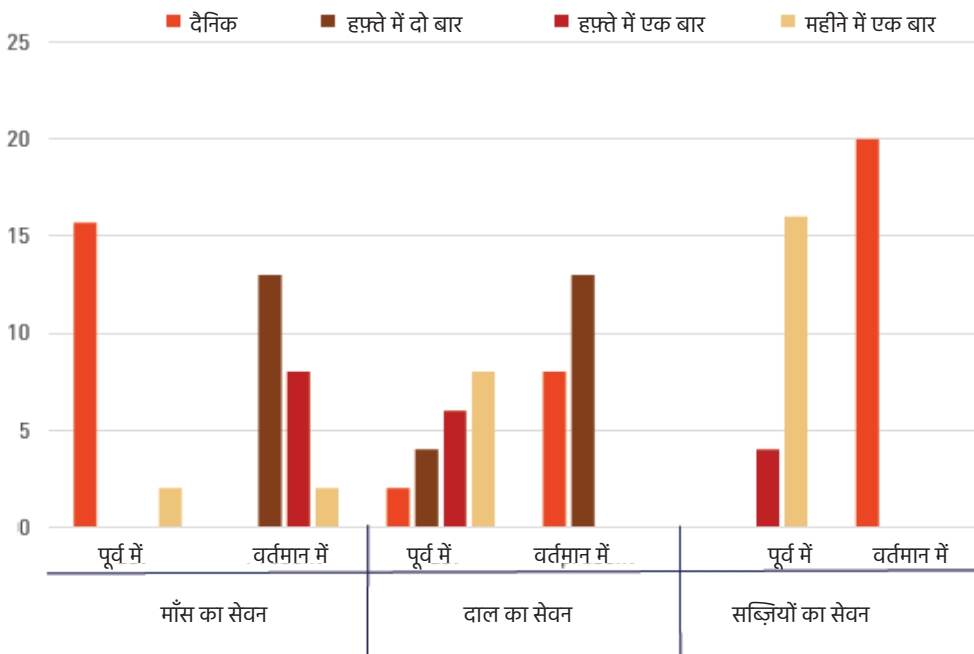
नई और अभिनव कृषि प्रथाओं ने परिवारों के लिए भोजन की पर्याप्तता और आहार एवं भोजन सेवन की गुणवत्ता और मात्रा के सन्दर्भ में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की (चित्र 3 देखें)।

फ़सलों एवं आहार में विविधता: एक तुलना



गाँव की महिलाओं का भोजन सेवन मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही मामलों में बेहतर हुआ। पाँच साल पहले, महिलाएँ और उनके परिवार एक दिन में एक बार भोजन करते थे, जिसमें केवल चावल के साथ नमक और कभी-कभी जंगली पत्तेदार हरी सब्जियों के साथ चावल होते थे। दिन के समय अपनी भूख शान्त करने के लिए, जब उपलब्ध हो, वे जंगली आलू या उबली हुई अर्ध-तरल मक्का खा लेते थे। हालाँकि, परियोजना के बाद, अब वे एक दिन में तीन बार भोजन करते हैं; वे सुबह चावल खाते हैं; दोपहर के भोजन के लिए उनके पास विभिन्न सब्जियों के साथ चावल होते हैं जिन्हें वे या तो खुद उगाते हैं या बाज़ार से खरीदते हैं; रात के खाने में चावल, सब्जियाँ, और दाल शामिल होती हैं। परिवार अब सेम की फली, मटर, कद्दू, तुरई (जिसका उन्होंने पहली बार सेवन किया है), लौकी, लोबिया, काबुली चना, पालक, कलमी शाक, और सरसों की पत्तियों का सेवन करते हैं। पिछले पाँच वर्षों में माँस की खपत में वृद्धि हुई है, जिसके विषय में 65 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके पास सप्ताह में दो या तीन बार माँस, अण्डे, और मछली उपलब्ध होते हैं, और 35 प्रतिशत परिवारों को महीने में दो या तीन बार यह खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं (चित्र 4 देखें)। इससे पहले, परिवार केवल त्योहारों के दौरान या जब कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता था तब ही माँस खाते थे। महिलाओं में अच्छे और पौष्टिक भोजन के लाभों के बारे में जागरूकता और ज्ञान काफ़ी अधिक है। हालाँकि महिलाएँ पिछले पाँच वर्षों की तुलना में अपने वर्तमान आहार को काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक पाती हैं और सोचती हैं कि माँस, मछली, अण्डा, दाल, सब्जियों (विशेष रूप से पत्तेदार हरी सब्जियों), दूध, और फलों के नियमित सेवन के माध्यम से उनके आहार में और सुधार लाने की आवश्यकता है।

आहार में सुधार



स. महिलाओं की स्थितियों में परिवर्तन

दिलचस्प बात यह है कि किसानों के साथ होने वाली शुरुआती बैठकों में महिला किसानों के कठिन परिश्रम को कम करने की आवश्यकता एक मुद्दे के रूप में नहीं उभरी। लेकिन चूँकि महिलाएँ अनुसन्धान का नेतृत्व कर रही थीं, उन्होंने जल्द ही इसे विभिन्न मंचों पर एक चिन्ता के रूप में उठाया। महिलाएँ अधिकतर बुवाई, रोपाई, निंदाई, और कटाई जैसे जी-तोड़ कामों में लगी रहती थीं। इसके बाद, कृषि में लाइन मार्कर, व्हील हो, कोनो वीडर, और कृषि की अर्थिंग-अप मशीन जैसे अभिनव उपकरणों के आ जाने से कृषि में महिलाओं की भूमिका के दायरे और प्रकृति में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिससे इसमें समय की खपत कम है और जी-तोड़ परिश्रम में भी कमी आई है। फलस्वरूप, महिलाओं के पास अब अपने लिए, अपने बच्चों, और परिवार के लिए अधिक समय है।

इन नए और नवोन्मेषी कृषि हस्तक्षेपों के कारण बेहतर लाभ मिलने लगा है, और जंगल एवं वनोपज पर महिलाओं की निर्भरता में काफी कमी आई है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, कल्याण, और सामान्य वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सोनामुंजी ने बताया, “महिलाएँ वनोपज एकत्र करने के लिए जंगल में और बेचने बाज़ार जाती थीं, लेकिन अब बेहतर कृषि और अधिक आय के कारण महिलाओं को जंगल में नहीं जाना पड़ता। यह हमारे लिए एक बड़ी राहत भी है और हम अपने बच्चों तथा परिवार की देखभाल कर सकती हैं।” महिलाओं ने बताया कि पहले उनके पास अपने और अपने बच्चों के लिए समय नहीं रहता था क्योंकि वे जंगलों में काम करने में बहुत व्यस्त रहती थीं। आमतौर पर, वे एक या दो महीने में एक बार कीचड़ से नहाते और अपने कपड़ों को राख और गर्म पानी से धोते थे। कृषि अनुसन्धान परियोजना में उनकी भागीदारी ने उनके लिए अधिक समय निकाल पाना और अधिक आय अर्जित करना सम्भव बनाया है, इसलिए वे अब अपना ख़्याल बेहतर ढंग से रख सकती हैं। “अब मेरे पास अपने लिए पर्याप्त समय है क्योंकि मुझे जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ और हर एक दिन साबुन से स्नान करती हूँ तथा अपने कपड़े धुलाई के साबुन से धोती हूँ। मैं स्वस्थ और अच्छा महसूस करती हूँ,” हेमलता मंडी ने सन्तोष व्यक्त किया। वे यह भी सुनिश्चित करती हैं कि उनके बच्चे स्वच्छ और स्वस्थ हों; वे उन्हें स्कूल भेजने से पहले हर दिन स्नान कराती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि वे साफ़ कपड़े पहनें।

परिवार में भोजन की सुनिश्चित आपूर्ति और बढ़ी हुई आय के फलस्वरूप, महिलाएँ अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि 80 प्रतिशत परिवार अब अपनी आय का अधिकांश हिस्सा बच्चों की शिक्षा और भोजन पर खर्च करते हैं। “भोजन के अलावा, मैं अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा एक निजी स्कूल में अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करती हूँ, जिसके लिए मैं 1,700 रुपये प्रति माह भुगतान करती हूँ,” साधमोनी दीदी ने बताया। महिलाओं की मानसिकता में एक विशिष्ट बदलाव दिखाई पड़ता है। पहले,

उनका मुख्य ध्यान बुनियादी अस्तित्व पर केन्द्रित था, लेकिन अब वे अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देती हैं और उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में भेजती हैं। उच्च जीवन स्तर और व्यक्तिगत कल्याण की इच्छा महिलाओं के जीवन का कायाकल्प करने वाले एक उल्लेखनीय परिवर्तन का प्रतीक है।

द. महिलाओं का सशक्तिकरण

इस सन्दर्भ में महिलाओं का सशक्तिकरण विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया जहाँ निर्णय लेने की शक्ति आय, व्यय, समय, श्रम, सम्पत्ति के स्वामित्व, कौशल, और नई कृषि तकनीकों के ज्ञान पर आधारित थी। भारतीय समाज की गहरी पितृसत्तात्मक प्रकृति को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि चुरिनसोरो में काम, आय, व्यय, श्रम, कौशल, शिक्षा, इत्यादि जीवन के सभी पहलुओं पर पुरुषों का नियंत्रण था। हालाँकि, स्वयं सहायता समूहों और कृषि अनुसन्धान परियोजना की शुरुआत ने ग्रामीणों को विभिन्न लैंगिक पहलुओं से परिचित कराया। परियोजना और स्वयं सहायता समूहों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के लिए जगह बनाई, जहाँ उन्होंने अपनी आय से बचत करना, कृषि गतिविधियों की योजना बनाना, और यह निर्णय लेना शुरू किया कि कौन-सी फ़सल उगाई जाए और कौन-सी तकनीक या प्रणाली अपनाई जाए। शोध अध्ययन के कार्यक्षेत्र और प्रकृति की योजना बनाने तथा निर्धारित करने में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में सुधार हुआ, और इसके फलस्वरूप पुरुषों सहित सम्पूर्ण समुदाय में महिलाओं के बारे में एक नई धारणा पैदा हुई। लगभग 75 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि अब उन्हें काफ़ी हद तक पुरुषों के बराबर माना जाता है। महिलाएँ अब घर पर निर्णय लेने में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, और कृषि तथा पारिवारिक खर्च से सम्बन्धित फैसलों में उनकी राय का महत्त्व बढ़ा है।



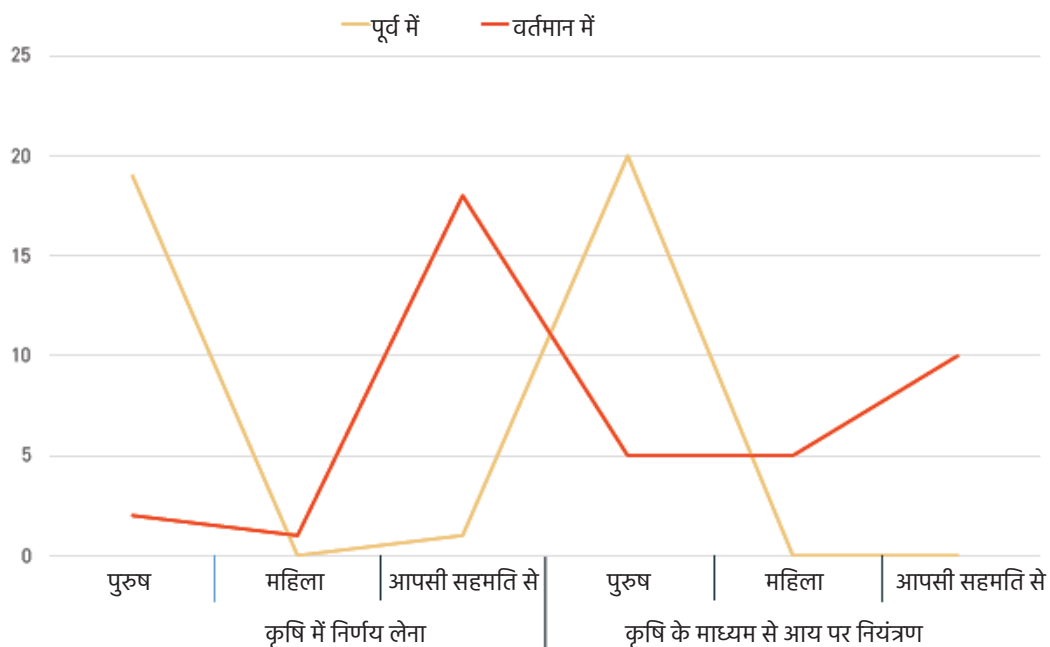
“यदि मैं उन्हें पैसा देती हूँ, तो वे उसे पीने में उड़ा देंगे। इसलिए मैंने घर खर्च की ज़िम्मेदारी संभाल ली है।”

– हेमलता



यह एक बेहतर, अधिक खुशहाल, और अधिक सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन सुनिश्चित करता है। दुनियाभर में किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं द्वारा नियंत्रित आय परिवार के लिए भोजन और स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक बार उपयोग में लाई जाती है, विशेष रूप से बच्चों के लिए।

निर्णय लेने में बदलाव



नई फ़सल प्रणाली और मशीनीकरण जैसे नवीन अभिनव कृषि हस्तक्षेप अपनाए जाने के साथ कृषि कार्य में परम्परागत लिंग-आधारित भूमिकाओं के वितरण में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। महिलाओं ने बताया कि बुवाई / रोपाई, निंदाई, कटाई, काटी गई फ़सलों का संग्रहण जैसे कृषि कार्य, जो महिलाओं के काम हुआ करते थे, अब पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा समान रूप से किए जाते हैं।



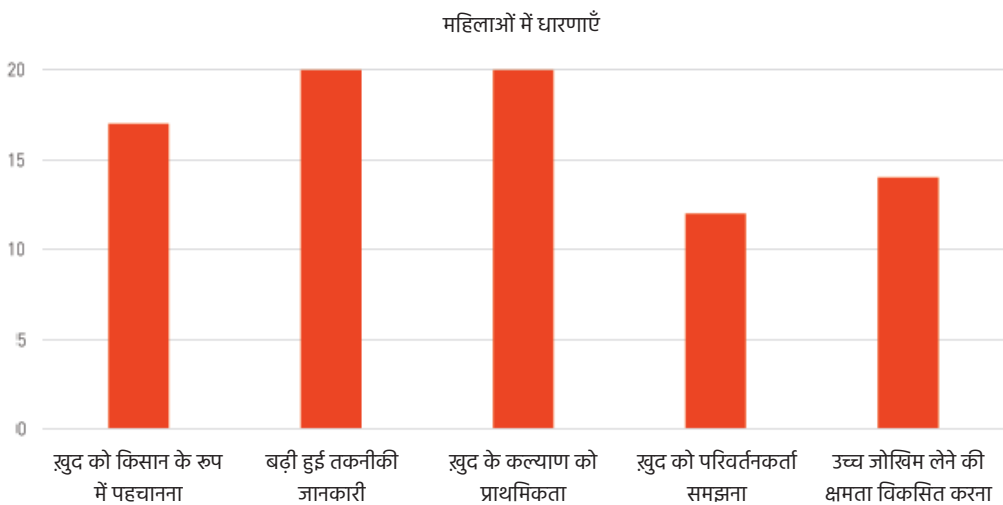
“अब निंदाई के मशीनी उपकरण आ जाने से पुरुष भी निंदाई करने लगे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है।”

एक बैठक के दौरान स्वयं सहायता समूह सदस्य



महिलाओं ने यह भी कहा कि वर्तमान में इस तरह भूमिका साझा करने के कारण वे गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान चरण में अपने कार्यभार को कम करने में सक्षम हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके कृषि के बेहतर ज्ञान ने उन्हें किसानों के रूप में मान्यता दिलाई है। उनमें से लगभग 80 प्रतिशत ने कहा कि आत्मविश्वास के साथ उन्होंने जो कुछ सीखा है उसे वे अन्य किसानों को सिखा सकती हैं।

एक समूह के रूप में, महिलाओं ने यह भी बताया कि उन्होंने कृषि परियोजना से जो कुछ सीखा है उसे वे अन्य गाँवों के अन्य महिला और पुरुष किसानों को भी सिखाती हैं। इन महिला समूहों ने रुपए 300 प्रति समूह प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक लेकर दूसरों को सिखाने का कार्य करके एक उद्यमिता मॉडल स्थापित किया है। महिलाओं का कहना है कि वे अच्छा और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करती हैं और अब अच्छी कृषि पद्धतियाँ जारी रखने, नई एवं उच्च मूल्य की नक़दी फ़सलें उगाने, अपनी उपज के लिए बाज़ारों तक पहुँच बनाने और आवास, बिजली, शौचालय, और सभी मौसमों में उपयोग योग्य सड़क जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने की आकांक्षा रखती हैं। इसके अलावा, कृषि सम्बन्धी अन्तराल को कम करने के लिए, वे एक सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए तैयार हैं जो उन्हें अतिरिक्त पानी प्रदान करेगी, और उनके कल्याण में वृद्धि करेगी। चित्र 6 उन 20 महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों की धारणाओं में परिवर्तन का चित्रण प्रस्तुत करता है जिनका साक्षात्कार लिया गया, और जिन्होंने फ़ोकस ग्रुप चर्चाओं में भाग लिया था।



इन महिलाओं ने जो परिवर्तन अनुभव किए वे उनका श्रेय स्वयं सहायता समूहों को देती हैं। महिलाओं के एक समूह का दावा किया कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान करने वाला दूसरा कारक है।



“एक समूह के रूप में, हम एक परिवार हैं। हम अपनी शक्तियाँ और कमज़ोरियाँ, दुःख और सुख साझा करते हैं।”

– अंजनी मंडी



स्वयं सहायता समूह महिलाओं को, पैसे बचाने और जब भी आवश्यक हो क़र्ज़ लेने की सुविधा प्रदान करता है, इस प्रकार यह उच्च ब्याज दरों पर साहूकारों से पैसे उधार लेने या क़र्ज़ के लिए भूमि गिरवी रखने की आवश्यकता को कम करता है। अपने स्वयं के धन का उपयोग करते हुए, जो उन्होंने एक साथ जमा किए हैं, वे लचीले पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ 12–24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दरों पर क़र्ज़ लेते हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अधिगम मंच है, जहाँ वे अपनी कृषि गतिविधियों और प्रयोगों की योजना बनाती हैं, और जहाँ वे अपने ठोस अनुभवों पर चिन्तन और उनकी समीक्षा करती हैं, ताकि आने वाले वर्ष में बेहतर उपज और अधिक आय प्राप्त हो सके।

VI. बाघमुंडी मॉडल का प्रमाणन

इस परियोजना के अनुभव और सीखों के आधार पर, PRADAN टीम ने अपनी कृषि आजीविका हस्तक्षेप की रूपरेखा अलग ढंग से तैयार की। टीम ने कृषि आजीविका हस्तक्षेपों में स्वयं सहायता समूह के समूहों को शामिल करने और समान भागीदारी को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए अपने सभी आठ संघों^{viii} में उपसंघ^{ix} स्तर के कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किए। प्रशिक्षण रूपरेखा में महिलाओं और विकास के इर्द-गिर्द समग्र अवधारणाएँ शामिल थीं। इसने कृषि कार्य में लैंगिक मुद्दों और लिंग-आधारित भेदभाव से परिचय कराया। इसमें पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं पर चर्चा की गई जो विभिन्न जेंडर साधनों का उपयोग करके कृषि से सम्बन्धित निर्णय लेते हैं। इसने अनुभवात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति का चित्रण किया। इसमें विभिन्न उन्नत कृषि गतिविधियों जैसे—सघन धान प्रणाली, डायरेक्ट सीडेड राइस (Direct Seeded Rice—DSR), जालियाँ, टमाटर को वर्षा से बचाने की व्यवस्था के विषय में महिलाओं को जानकारी प्रदान करना, और वीडर, मार्कर जैसी कृषि मशीनों के उपयोग और मिट्टी से ढँकने का प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल था। कृषि से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए

महिलाओं को अपनी वार्षिक आय बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से कृषि गतिविधियों की योजना बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। महिला कृषि प्रशिक्षकों ने उपसंघ सदस्यों की मदद से सालभर की कृषि योजना बनाई। नियोजन प्रक्रिया उनके मुख्य आजीविका विकल्प, यानी कृषि के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाने पर केन्द्रित थी। बड़े पैमाने पर अधिगम के प्रसार के लिए फ़ार्मर फ़ील्ड स्कूल मॉडल अपनाया गया। महिला कृषि प्रशिक्षकों और उपसंघ महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह महिला सदस्यों को कृषि कार्य की नई तकनीकों सीखने के लिए फ़ार्मर फ़ील्ड स्कूल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में, कृषि कार्यक्रम के माध्यम से टीम 650 स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ने में सफल रही। टीम इस वर्ष फ़ार्मर फ़ील्ड स्कूल मॉडल की मदद से लगभग 7,000 परिवारों तक उन्हें उन्नत कृषि अवधारणाओं, पद्धतियों, और तकनीकों से अवगत कराने के लिए पहुँची। उपसंघ की मासिक बैठकें होती हैं, जहाँ सदस्य प्रदर्शनों की प्रगति के साथ-साथ उन्नत तकनीकों को अपनाने वाले किसानों की प्रगति की समीक्षा करते हैं। इन बैठकों में, कृषि कार्यक्रम को टिकाऊ बनाने के लिए पेशेवरों द्वारा मदद की जाती है।

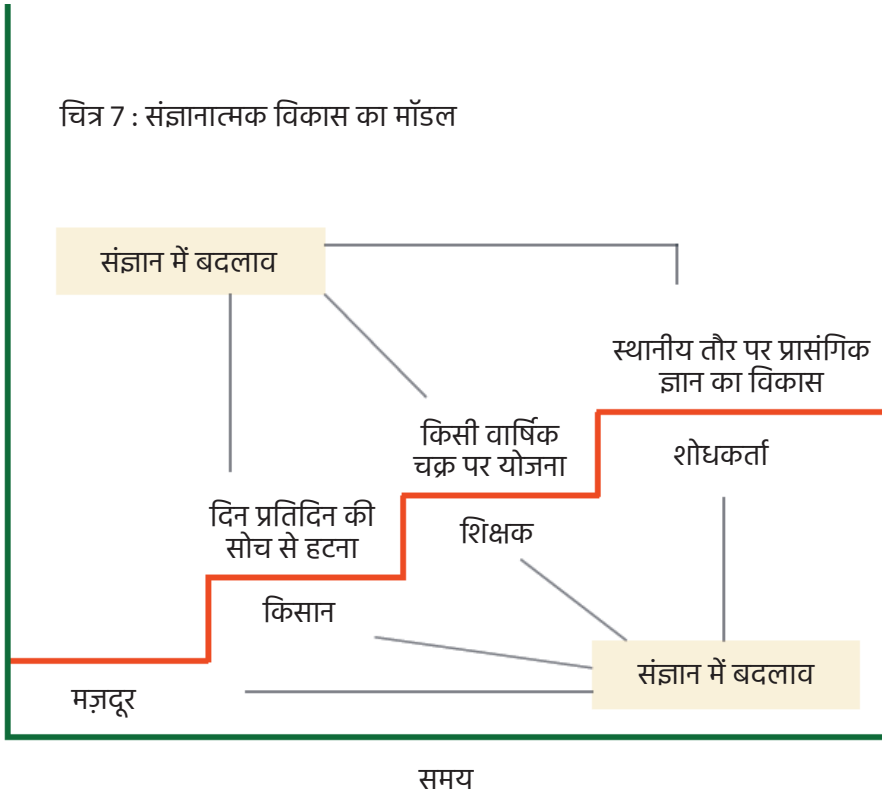
VII. मुख्य सबक

यह कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम दो कारणों से अनूठा था। पहला, वास्तविक किसानों और उनके स्वयं के खेतों में अनुसन्धान आयोजित किया गया था। दूसरा, महिलाओं को किसान शोधकर्ताओं के रूप में प्रधानता दी गई थी। परियोजना मुख्य रूप से व्यक्तियों के रूप में महिलाओं पर केन्द्रित थी, जिसका उद्देश्य उनकी अभिकरण की भावना बढ़ाना और उनकी क्षमता (मानव संसाधन क्षमता) विकसित करना था। अनुभव बताता है कि परियोजना की आवश्यकता-आधारित योजना के बजाय स्थानीय आवश्यकता-आधारित योजना अधिक प्रभावी होती है क्योंकि इसमें वास्तविकता पर आधारित डेटा शामिल किया जाता है, यह महिलाओं को किसी परियोजना के सख्त मार्गदर्शक सिद्धान्त से बंधे रहने, जैसा आमतौर पर होता है, के बजाय अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार योजना बनाने और कार्य करने के लिए अधिक स्थान और अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा, स्थानीय आवश्यकता-आधारित नियोजन स्वदेशी ज्ञान और पद्धतियों को ध्यान में रखता है, जिससे महिलाओं की अपनी समस्याएँ हल करने की क्षमता विकसित होती और बढ़ती है।

एक किसान से एक शोधकर्ता से एक शिक्षक तक की प्रगति एक क्रमिक और निरन्तर प्रक्रिया है। भावी गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए इसमें नियोजन, प्रयोगधर्मिता, समीक्षा करने, और चिन्तन करने के साथ अन्तर्दृष्टि और अनुभवों एवं लागू किए गए परिवर्तनों से सीखे गए सबक शामिल हैं। यह प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास के मॉडल का अनुसरण करती है, जैसा कि चित्र 7 में दर्शाया गया है।

समुदाय के साथ बातचीत में प्रयुक्त जुड़ाव का दृष्टिकोण, या कार्यवाही अनुसन्धान चक्र कोल्ब के अधिगम चक्र (Kolb's learning cycle) पर आधारित था जिसमें प्रयोग करने और सीखने पर ध्यान केन्द्रित था (चित्र 8)। परियोजना की गतिविधियों की रूपरेखा तदनुसार तैयार की गई, जो आरम्भिक बैठक के साथ शुरू हुई और वार्षिक समीक्षा बैठक के साथ समाप्त हुई, जहाँ नई गतिविधियाँ सुझाने के लिए अनुभवों का विश्लेषण करना और सीखे गए सबकों को संश्लेषित करना एक नियमित चक्र था। एक समीक्षा बैठक में भी, इस प्रक्रिया का पालन तत्परतापूर्वक किया गया। फ़ील्ड के संयुक्त दौरों, खेत के क्षेत्र में कामकाज करते समय प्रायोगिक कृषि भूखण्डों का अवलोकन करने, टिप्पणियों की व्याख्या करने और सीखने के लिए उनका विश्लेषण करने, तथा कार्य योजना बनाने के साथ गतिविधियों का चक्र शुरू हुआ।

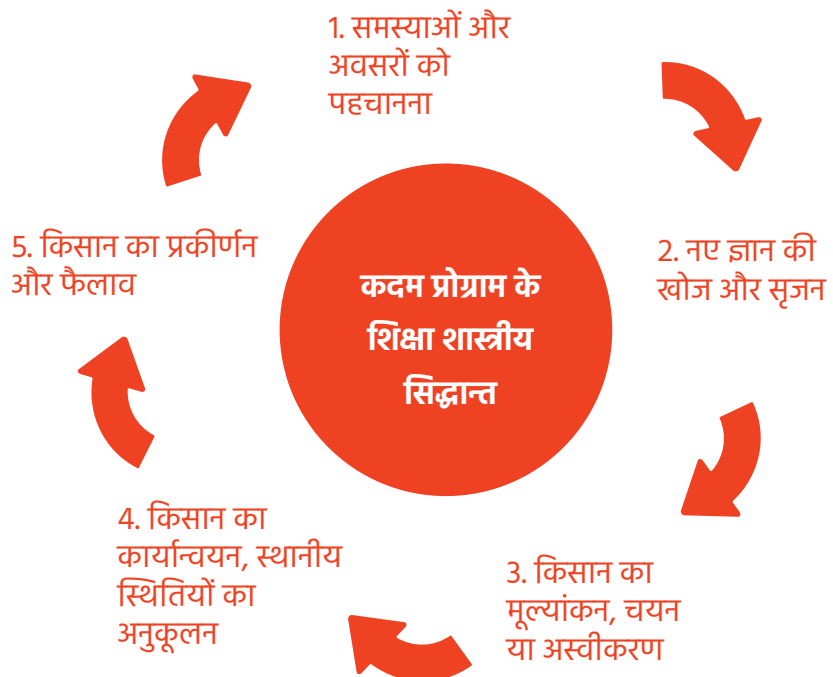
चित्र 7 : संज्ञानात्मक विकास का मॉडल



यह सुनिश्चित किया गया कि सभी प्रक्रियाएँ सहभागी हों, और अनुसन्धान में कार्यवाही अनुसन्धान रूपरेखा का पालन किया जाए।

जुड़ाव के दृष्टिकोण और इस परियोजना में अपनाई गई प्रक्रियाओं² ने प्रतिभागी की पहचान में बदलाव सुनिश्चित किया—“खेतिहर मज़दूर से एक किसान से एक शोधकर्ता” और अन्त में एक “शिक्षक”। विभिन्न सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन गतिविधियों से पता चलता है कि 85 प्रतिशत से अधिक खेती और कृषि कार्य महिलाएँ करती हैं। उनकी भूमिका और योगदान को स्वीकारा नहीं जाता है। यदि वे पारिवारिक खेत पर काम करती हैं, तो यह माना जाता है कि वे पारिवारिक कार्यों में सहायता कर रही हैं। यदि वे किसी और के खेत में काम करती हैं, तो उन्हें मज़दूर माना जाता है और उन्हें पुरुष मज़दूरों की तुलना में कम मज़दूरी चुकाई जाती है। किसी भी महिला ने खुद को किसान के रूप में नहीं पहचाना या खेती को अपने व्यवसाय के रूप में नहीं देखा। इस सम्पूर्ण परियोजना में जुड़ाव ने किसानों और अनुसन्धान किसानों के रूप में महिलाओं के लिए एक पहचान बनाने का प्रयास किया। यह शोधकर्ता किसान अब अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। अनुसन्धान गाँव के बाहर के किसान उन्हें और उनकी खेती की पद्धतियों को गौर से देखते हैं और उनसे सीखने की इच्छा रखते हैं।

चित्र 8 : कार्यवाही अनुसन्धान चक्र



आभारोक्ति: यह परियोजना जो इस केस स्टडी का विषय है, ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च (Australian Centre for International Agricultural Research—ACIAR) द्वारा सहयोग प्राप्त थी। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. पीटर कॉर्निश (Dr. Peter Cornish) इस प्रक्रिया की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने और इसे स्पष्ट करने में हमारी मदद करने में प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। इस काम में आगे प्रोफ़ेसर बिल बेलोटी और डॉ. गेविन रामसे (Prof. Bill Bellotti and Dr Gavin Ramsay) का भी सहयोग प्राप्त हुआ जिनका योगदान इस केस स्टडी में प्रयुक्त की गई वैचारिक रूपरेखा तैयार करने में मददगार रहा।

हम रितेश पांडे और वानबोरलॉंग खिमदित (Ritesh Pandey and Wanborlong Khyndeit) के प्रति उनकी अन्तर्दृष्टि और समुदाय में उनकी सुविधा सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। यह परियोजना अपनी सफलता का श्रेय PRADAN बाघमुंडी टीम के सदस्यों और इसमें शामिल अनुसन्धान टीम को भी देती है। उनके प्रति हम अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

सन्दर्भ (References)

Bellotti, B., Ramsay, G., Unkovich, M., Komarek, A., & Pain, S. (2015). Creating space for smallholder farmer innovation: Reflections from Australian researchers. https://cdn.csu.edu.au/data/assets/pdf_file/0003/1450164/Creating-space-for-smallholder-farmer-innovation-Bill-Bellotti.pdf

Cornish, P. S., et al. (2015). Improving crop production for food security and improved livelihoods on the East India Plateau. I. Rainfall-related risks with rice and opportunities for improved cropping systems. *Agricultural Systems*, 137, 166–179. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2015.01.008>

Food and Agriculture Organization (FAO). (2011) The State of Food and Agriculture 2010–2011: Women in Agriculture: Closing the gender gap for development. Rome: FAO. <http://www.fao.org/3/a-i2050e.pdf>

Kumar, A., Unkovich, M., & Bellotti, B. (2015) Smallholder farmer innovation. 1. Replacing transplanted rice monoculture with direct seeded rice based cropping systems.

Conference paper. Building Productive, Diverse and Sustainable Landscapes, 17th Australian Agronomy Conference, 20–24 September 2015, Hobart, Australia. Conference Proceedings, 2015, pp. 518–521 ref.3.

Pandey, R., Ramsay, G., & Bellotti, B. (2015) Smallholder farmer innovation. 2. Facilitating farmer agency through experimentation and learning about cropping systems. Building Productive, Diverse and Sustainable Landscapes. Proceedings of the 17th Australian Agronomy Conference, 20–24 September 2015, Hobart, Australia. www.agronomy2015.com.au

Ramsay, G., Bellotti, B., Narain, N., & Kumar, A. (2015). Learning, Research and Collaboration: Challenges and Opportunities. In Research and education for rural development and food security to build resilient rural environments: Australian and Indian Perspectives. Wagga Wagga: Charles Sturt University.
https://www.csu.edu.au/data/assets/pdf_file/0005/1450184/Learning-research-and-collaboration-challenges-and-opportunities-Gavin-Ramsay.pdf

United Nations Children's Fund (UNICEF) (1991). Strategy for improved nutrition of children and women in developing countries. Indian Journal of Pediatrics, 58, 13–24. New York: UNICEF. DOI
<https://doi.org/10.1007/BF02810402>

- i. AVRDC: Asian Vegetable Research and Development Center, based in Shanhua, Tainan, China.
- ii. ACWADAM: Advanced Center for Water Resources Development and Management, based in Pune, Maharashtra, India.
- iii. BCKV: Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, also known as Bidhan Chandra Agricultural University, located in District Nadia, Mohanpur, West Bengal, India.
- iv. L. Stoll, R. Bolam, A. McMohan, M. Wallace, & S. Thomas (2006). Professional learning communities; A review of the literature. Journal of Educational Change, 7(4), 221–258.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10833-006-0001-8>
- v. खाद्य सुरक्षा से यहाँ तात्पर्य उपभोग के लिए अनाज की उपलब्धता से है।
- vi. एक प्रश्नावली के माध्यम से प्रतिदर्श किसानों से आँकड़े एकत्रित किए गए और बाद में उन्हें एकजाई किया गया।
- vii. किसी पूर्वज्ञातक उपाधि की पाठ्यक्रम सम्बन्धी आवश्यकताओं के साथ-साथ किसी अभिकरण या विश्वविद्यालय के लिए बाहरी व्यक्ति, जिससे विद्यार्थियों ने उस वर्ष सम्पर्क किया था, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टुअर्ट वर्माक और डेमियन बाल्ज़र (Stuart Vermaak and Damien Balzer) द्वारा पोषण और कृषि (nutrition and agriculture) के बीच सम्बन्ध पर किए गए एक शोध अध्ययन की रिपोर्ट से आँकड़े और विश्लेषण प्राप्त किए गए हैं। ये दोनों विद्यार्थी युनिवर्सिटी ऑफ़ वेस्टर्न सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के छात्र हैं।
- viii. संघ : पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (WBSRLM) कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तरीय स्वसहायता समूह
- ix. उपसंघ : पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय स्वसहायता समूह

प्रोफ़ेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (PRADAN), पश्चिम बंगाल

PRADAN (प्रोफ़ेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन) का मिशन सबसे सीमान्त लोगों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं, को एक सम्माननीय आजीविका अर्जित करने और अपने स्वयं के जीवन का प्रभार लेने में सक्षम बनाता है। PRADAN की स्थापना 1983 में दो युवा पेशेवरों, दीप जोशी और विजय महाजन द्वारा की गई थी, जिन्हें इस बात का विश्वास था कि ग्रामीण भारत की हठीली, स्थानिक ग़रीबी का भी समाधान किया जा सकता है। उनका मानना था कि भली भाँति शिक्षित पेशेवर समुदायों में काम करके आवश्यक सहानुभूति और ज्ञान दोनों का वातावरण निर्मित कर सकते हैं ताकि ग़रीबों का जीवन बेहतर बनाने में उनकी मदद की जा सके। संगठन का मानना है कि सभी लोग, चाहे कितने भी ग़रीब क्यों न हों, वह बदलाव लाने में सक्षम हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। यह भली भाँति शिक्षित पेशेवरों से सहानुभूति और ज्ञान के साथ ग़रीबों का जीवन बेहतर बनाने में मदद करने के लिए ग़रीब समुदायों के साथ काम करने का आह्वान करता है। PRADAN भारत के सबसे ग़रीब क्षेत्रों में ऐसे समूह संगठित करने में अरक्षित समुदायों की मदद करने के लिए काम करता है जो एक सम्माननीय आजीविका अर्जित करने और अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में लोगों, विशेषकर महिलाओं, की मदद करें। नागरिकों के रूप में सरकारी कार्यक्रमों और अन्य अधिकारों तक पहुँचने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। सेवा या समाधान प्रदान करने के बजाय अपने स्वयं के कौशल और पहल विकसित करने में सीमान्त समुदायों के लोगों की मदद करने पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है। विकास नीतियों पर प्रभाव डालने के लिए PRADAN अन्य नागरिक समाज संगठनों और सरकार के साथ भी भागीदारी करता है।

5.2 बन्नी, गुजरात में पशुपालकों के बीच एकता और सामूहिक कार्यवाही

सहजीवन ट्रस्ट, गुजरात

सारांश

गुजरात के कच्छ में बन्नी की चरागाह भूमि को स्वतंत्रता के बाद से गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन 2008 में चीज़ें निर्णायक स्थिति में पहुँच गईं। अत्यन्त अल्प कार्बन फुटप्रिंट के साथ भोजन और अन्य संसाधन पैदा करने की सदियों पुरानी प्रणाली गम्भीर जोखिम में थी। सभी संकेत इसके अन्त की ओर इशारा कर रहे थे, जैसा कि भारतभर में कई अन्य उसी प्रकार की विकेन्द्रीकृत स्थानीय उत्पादन प्रणालियों के साथ हुआ है। जहाँ अनेक लोग इसके अन्त तक इन्तज़ार कर रहे थे, वहीं बुजुर्ग पशुपालकों के एक छोटे समूह ने परिस्थिति का सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पर्यावरण का पतन रोकने के साथ-साथ अपनी आजीविका, संस्कृति, और जीने के तरीके के लिए खतरे का सामना करने हेतु एक समूह के रूप में संगठित होने का निर्णय लिया। यह केस स्टडी उनके और अन्य पशुपालकों के कार्यों और उपलब्धियों की पड़ताल करती है जो वास्तव में प्रेरक हैं, और जो भारत में इसी तरह की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े कई लोगों के मन में आशा का संचार प्रदान करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि अपने जीने के तरीके में दृढ़ विश्वास रखने वाले कुछ दृढ़निश्चयी स्थानीय लोग कैसे उचित बाहरी समर्थन और मार्गदर्शन के साथ, अद्भुत काम कर सकते हैं।

बन्नी, गुजरात में पशुपालकों के बीच एकता और सामूहिक कार्रवाई—प्रस्तावना

पशुपालन सबसे पुराने मानवीय व्यवसायों में से एक है। यह सीमान्त भूमि पर जानवरों को पालने की कला है, यानी ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। आमतौर पर पशुपालन चरम या कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, मानव पशुपालन की बदौलत सबसे कठिन इलाकों में जीवित रहने में कामयाब रहे हैं। पशुपालन इसलिए सफल होता है क्योंकि जानवरों की कठिन, कठोर, और लचीली नस्लों में यह क्षमता होती है कि ज़मीन पर जो कुछ भी उगता है, उसे खाकर वे अपना गुज़ारा कर लेते हैं। पशुपालन प्रणालियों के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व गतिशीलता और गतिकता हैं। गतिशीलता भोजन और पानी की तलाश में लम्बी दूरी तक चलने की क्षमता है, और गतिकता उद्विकासी पर्यावरणों—आर्थिक, राजनीतिक, या पारिस्थितिक—के प्रति उचित रूप से प्रतिक्रिया करने और बदलाव के अनुकूल ढलने की क्षमता है।

भारत में पशुपालन का अध्ययन लम्बे समय से नज़रअन्दाज़ किया जाता रहा है और अभी भी ऐसी स्थिति बनी है कि शोधकर्ता और नीति निर्माता पशुपालन प्रणालियों का वास्तविक आर्थिक, पारिस्थितिक, और नृवंशविज्ञान सम्बन्धी महत्त्व समझने लगे हैं। विशेष रूप से भीषण जलवायु परिवर्तन के उभरते ख़तरे को देखते हुए इन प्रणालियों को महत्त्व दिया जाने लगा है; अनुसन्धान से पता चलता है कि पशुओं की नस्लें न केवल चरम मौसम से बच सकती हैं, बल्कि अत्यन्त संकटपूर्ण परिस्थितियों में भी उत्पादक हो सकती हैं। सभी पशुपालन प्रणालियाँ स्थानीय पारिस्थितिक, पर्यावरणीय, और स्थलाकृति सम्बन्धी परिस्थितियों के अनुरूप, और उनकी प्रतिक्रियास्वरूप विकसित हुई हैं, और स्थानीय जलवायु एवं इलाके तथा स्थलाकृति की विशेषताओं के अनुरूप सदियों से जानवरों की नस्लों को चुनिन्दा तौर पर बढ़ाया गया है। अपने-आप में, पशुपालन प्रणालियाँ कीमती पशु आनुवंशिक संसाधनों की वाहक हैं। दुनियाभर के संस्थानों और सरकारों ने हाल ही में पशुओं की नस्लों के संरक्षण के लिए संसाधनों का आवण्टन शुरू किया है।

भारत में दुनिया की कुछ सबसे समृद्ध और सबसे विविधतापूर्ण पशुपालन प्रणालियाँ हैं, जो विभिन्न इलाकों और जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं—इनमें से कुछ हैं : राजस्थान के रेगिस्तान, गुजरात के शुष्क घास के मैदान, गर्म दक्षिणी क्षेत्र, लद्दाख के ठण्डे रेगिस्तान, आदि। भारत में लगभग 34 मिलियन पशुपालक हैं, यानी करीब 30 भारतीयों में से एक पशुपालक है। भारत के अधिकांश पशुपालकों का उद्भव 15 राज्यों में हुआ है, लेकिन वे कई राज्यों में यात्रा करते हैं, और इसलिए देश के हर राज्य से सम्बन्धित हैं। भारत में पशुपालक कई मायनों में हमारे दैनिक जीवन में योगदान करते हैं, अक्सर ऐसे तरीकों से योगदान करते हैं जो हमें नज़र नहीं आते और इसलिए उपेक्षित रहते हैं। कुछ प्रासंगिक उदाहरण हैं :

- हम जो दूध पीते हैं उसका लगभग 60 प्रतिशत उन देशी नस्लों से प्राप्त होता है जो पशुपालकों द्वारा विकसित की गई हैं;
- हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन भी किसानों और चरवाहों के बीच चली आ रही सदियों पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत फलदायी बनता है (सबसे अच्छे पोषक तत्व पशुओं के गोबर और मूत्र से प्राप्त होते हैं)। इस व्यवस्था में फ़सल कटने के बाद पशुपालक के पशुओं, विशेष रूप से बकरियों, भेड़ों, और ऊंटों, को किसानों के खेतों में आने दिया जाता है जिसके बदले में उन्हें पैसा और चारा मिलता है।
- पालतू पशुओं से ऊन, चमड़ा, हड्डी, और अन्य कच्चे माल प्राप्त होते हैं जिनसे दैनिक उपयोग के उत्पाद बनाए जाते हैं।
- चरागाह के परिदृश्यों में एक अनूठी आध्यात्मिकता होती है और उनकी संस्कृति ने संगीत एवं रहस्यमय कविता को जन्म दिया है जो आज भी हमारी चेतना को बढ़ाते हैं।

परिचय

इस केस स्टडी में गुजरात के कच्छ ज़िले के बन्नी में पशुपालकों के एक समुदाय द्वारा किए गए काम, और एक स्थानीय पारिस्थितिक संगठन सहजीवन (Sahjeevan) के साथ उनके जुड़ाव का वर्णन है। बन्नी लगभग पाँच शताब्दियों तक मालधारियों (कच्छ में पशुपालकों के समुदाय को इसी नाम से जाना जाता है) का घर रहा है। कभी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चरागाह भूमि बन्नी को भारत के सभी चरागाहों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। यह 2,500 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। बन्नी में आज 7,000 से अधिक परिवार रहते हैं, और उनमें से अधिकतर मालधारी हैं। उत्तर भारत, वर्तमान बलूचिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, और मध्य एशिया सहित कई क्षेत्रों के पशुपालक सदियों से बन्नी चरागाहों में बसे हैं।

बन्नी के मालधारियों ने पारम्परिक रूप से गोजातीय पशुओं, विशेष रूप से भैंसों और गायों को पाला है। दिलचस्प बात यह है कि बन्नी के मालधारी भैंस की एक विलक्षण नस्ल पालने में सक्षम थे, जो रात में, मानवीय देखरेख के बिना अकेले चरने की क्षमता रखती है। अँधेरे में चरने के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी विशेष रूप से चुनकर इन भैंसों की वंशवृद्धि की जाती रही है। इस प्रकार, वे न केवल दिन की तेज़ धूप से बचती हैं, बल्कि कम पानी पीकर भी रह सकती हैं। इस नस्ल को बन्नी भैंस के रूप में जाना जाता है। बन्नी भैंस की एकमात्र ऐसी नस्ल भी है जो एक शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल है।



पारम्परिक रूप से बन्नी मालधारियों द्वारा खेतों पर काम करने के लिए, स्थानीय परिवहन के लिए गाड़ी खींचने वाले पशुओं के रूप में, और प्रजनन के लिए वयस्क पशु बेचे जाते रहे थे। पिछली चार या पाँच शताब्दियों से यह उनके लिए आय का एकमात्र स्रोत रहा है। इन पशुओं द्वारा उत्पादित दूध कभी नहीं बेचा गया, क्योंकि पशु व्यापार लाभदायक था और इसलिए भी कि पशुओं के साथ-साथ बच्चों को मज़बूत बनाने के लिए दूध आवश्यक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सम्बन्धी आर्थिक, राजनीतिक, और पारिस्थितिक सन्तुलन बाधित होने से पहले अपने जीवन के देहातीपन और सादगी से सन्तुष्ट कई मालधारी समुदाय बन्नी में शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे।



बदलाव की बयारें

कच्छ भौगोलिक रूप से सिंध के निकट है, और सदियों से कच्छी मालधारियों के सिंध के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और पारिवारिक सम्बन्ध रहे हैं। विभाजन ने इस व्यापार को समाप्त कर दिया, और सीमा के दोनों ओर के लोगों के बीच बाधाएँ खड़ी कर दीं। 1947 के बाद, जब सीमाएँ सदा के लिए बन्द कर दी गईं, भारतीय सीमा के भीतर किसानों के साथ व्यापार आय का एकमात्र स्रोत था। पारिस्थितिक परिदृश्य भी बदलने लगा। सरकार ने फ़सल और पानी का उपयोग लाभकारी ढंग से करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी। अदूरदर्शितापूर्ण हस्तक्षेपों ने जल धाराओं को अवरुद्ध कर दिया और उनका मार्ग परिवर्तित कर दिया जो हर साल बन्नी के चरागाहों की लवणता दूर करती थीं। बन्नी अब और खारा होने लगा; बढ़ती लवणता जल्द ही एक गम्भीर समस्या बन गई। 1965 में, बढ़ती लवणता की समस्या के समाधान के लिए सरकार एक और अदूरदर्शी समाधान लेकर आई। सरकार ने सम्पूर्ण बन्नी में विलायती बबूल (प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा—Prosopis juliflora) के रूप में जानी जाने वाली एक मज़बूत लेकिन तेज़ी से फैलने वाली जंगली प्रजातियों के बीज लगाए। यह झाड़ी, जो मैक्सिको, दक्षिण अमरीका, और कैरिबिया मूल की है, ने बन्नी में भूमि के बड़े इलाकों पर क़ब्ज़ा कर लिया है। बन्नी चरागाहों में अब देशी वनस्पति या घास मिलना मुश्किल है। फलस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में चरने वाले पशुओं के लिए उपलब्ध चारे की मात्रा घट गई है। ठीक उसी तरह बन्नी में वन्यजीवन तेज़ी से फैलने वाले विलायती बबूल की चपेट में आ गया। यह स्थानीय रूप से गांडो बवल (बावली झाड़ी) के रूप में जानी जाती है क्योंकि यह अत्यधिक तेज़ी से फैलती है।

1980 के दशक के अन्त और 1990 के दशक की शुरुआत में, किसानों ने खेती की ज़मीनों के यंत्रीकृत साधन अपनाना शुरू किया। फलस्वरूप, बन्नी के बैलों को महत्त्व दिया जाना बन्द हो गया, जो कभी खेती और गाड़ी खींचने के लिए बेशक़ीमती पशु समझे जाते थे। बैल, पारम्परिक रूप से गाड़ियाँ खींचते थे, लेकिन मोटर वाहनों के आ जाने के कारण स्थानीय परिवहन के साधन के रूप में भी महत्त्व खोने लगे, उन्हें गति, शैली, और आराम के मामले में जीपों और बसों ने आसानी से पीछे छोड़ दिया। सदी बदलने के आसपास गाय की निगरानी रखने वाले सक्रिय होने लगे, जिसका विपरीत प्रभाव पशुओं के थोड़े-से बचे-खुचे व्यापार पर भी पड़ा। लगभग उसी समय बन्नी पर मालधारी समुदायों की पकड़ भी ख़तरे में आ गई। मालधारियों को उस समय से बन्नी पर चराई के अधिकार प्राप्त थे जब कच्छ एक देशी रियासत थी; चराई कर के भुगतान के बदले यह अधिकार प्रदान किए गए थे। मालधारियों के पास आज भी 1856 के दस्तावेज़ हैं जिनमें रियासत के शासनकाल के दौरान उनके बन्नी के अधिकारों को संहिताबद्ध किया गया था। चरागाह के उपयोग और प्रबन्धन के विषय में निर्णय मालधारी समुदायों के नायकों द्वारा लिए जाते थे, और सम्पूर्ण समुदाय यह सुनिश्चित करता था कि मानदण्डों का पालन सभी लोगों द्वारा किया जाए।

1955 में बन्नी को एक संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालाँकि, उस समय कोई सर्वेक्षण या निपटान प्रक्रिया क्रियान्वित नहीं की गई। तब से चरागाह का शासन एक पेचीदा मुद्दा रहा है। राजस्व विभाग ने 1998 में बन्नी का प्रशासनिक नियंत्रण वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया। हालाँकि, वन विभाग ने बन्नी के भीतर स्थित गाँवों का सर्वेक्षण पूरा होने तक भूमि का प्रशासन करने से इंकार कर दिया। चूँकि न तो वन विभाग और न ही राजस्व विभाग ने प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लेने की दिशा में क़दम बढ़ाया, इसलिए कोई औपचारिक अधिकार नहीं होने के बावजूद, मालधारी समुदाय ने अपने प्रथागत स्थानीय शासी निकायों के माध्यम से चरागाह का प्रबन्धन और शासन जारी रखा। बन्नी का संरक्षण किया गया क्योंकि मालधारी लोग यह समझते थे कि पारिस्थितिक संसाधनों की देखभाल उनके जीवन के तरीक़े का आधार थी। इसने पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ मालधारियों की एक सुरुचिपूर्ण संस्कृति के साथ एक समन्वयात्मक सम्बन्ध विकसित किया, एक ऐसी संस्कृति जो इस भूमि पर आकर ही सबसे अच्छे ढंग से अनुभव की जा सकती है।

ऐसी अफ़वाहें थीं कि वन विभाग चरागाह पर दावा करेगा और बन्नी के बड़े इलाक़ों में आड़ लगा देगा जो चरवाहों के लिए सीमाएँ होंगी। इसने चरवाहों को भयभीत कर दिया क्योंकि चरागाहों तक पहुँच का अभाव पशुपालन प्रणाली के लिए आत्मघाती साबित होगा, जिस पर वे अस्तित्व के लिए निर्भर थे। इस तरह की आशंकाएँ बाद में सच होने वाली थीं, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, अपने स्वयं के प्रयासों की बदौलत स्थिति से निपटने के लिए मालधारी बहुत बेहतर ढंग से तैयार थे।

बन्नी में पशुपालन का अस्तित्व, जो सदियों से पनप रहा था, ख़तरे में था, और आजीविका के पारम्परिक स्रोत और पारिस्थितिक एवं प्राकृतिक संसाधनों तक लोगों की पहुँच भी ख़तरे में थी। मालधारियों की युवा पीढ़ियों ने यह मानना शुरू कर दिया कि आजीविका के रूप में पशुपालन का कोई भविष्य नहीं था और वे मज़दूरों के रूप में काम करने के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे। हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि यह ऐसा वक़्त था जब नस्लों, समुदायों, पारिस्थितिक तंत्रों और आजीविकाओं के स्तम्भों पर निर्मित बन्नी पशुपालन प्रणाली ने ख़ुद को सभी दिशाओं से आक्रमण झेलते पाया।

मालधारी और सहजीवन उत्तरदायित्व निभाते हैं

सहजीवन ने लम्बे समय तक पारिस्थितिक संरक्षण और उत्थान से सम्बन्धित ज़मीनी मुद्दों पर काम किया है। बन्नी में तनावपूर्ण परिस्थितियों और मालधारी समुदायों पर पारिस्थितिक क्षरण के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए, सहजीवन ने महसूस किया कि उसे हस्तक्षेप करने के लिए मैदान में उतरने की आवश्यकता थी। सहजीवन मुख्य रूप से कच्छ में पशुपालन प्रणालियों के संरक्षण के लिए प्रेरित था। सहजीवन ने महसूस किया कि पशुपालन का सर्वाधिक महत्त्व आनुवंशिक संसाधनों के एक अधिकोष (bank) के रूप में था। बन्नी में पशुपालन प्रणाली गम्भीर दबाव में थी और प्रणाली का संरक्षण करना, सहारा देना, पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना आवश्यक था। सहजीवन ने हमेशा स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी की है और स्थानीय लोगों को किसी अभियान में शामिल करने तथा उसके लिए उनके प्रतिबद्ध होने का महत्त्व समझा है। इसलिए, सहजीवन ने सक्रिय रूप से चरवाहों के समुदाय के साथ एक निकट सम्बन्ध विकसित करना शुरू किया और अपने कार्यक्रमों एवं हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समुदाय इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समान भागीदार होगा।

वह आर्थिक और पारिस्थितिक स्थितियाँ भी बदल गई हैं जिनके तहत बन्नी की पशुपालन प्रणाली संचालित होती है। सहजीवन ने महसूस किया कि भैंस की नस्ल के संरक्षण और पारिस्थितिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयासों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक था कि पशुपालक चरवाहे एक सम्मानजनक आजीविका अर्जित करते रहें। इसलिए सहजीवन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board—NDDB) के साथ साझेदारी में एक दूध-आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम करने का फैसला किया। पशु मेले का विचार भी सफल साबित हुआ। यह समुदाय द्वारा अपने पारम्परिक ज्ञान का उत्सव मनाने और प्रदर्शन करने तथा अपने पशुओं के लचीलेपन और मज़बूती पर प्रकाश डालने के लिए एक उत्कृष्ट मंच है।

बन्नी के मालधारियों के बुजुर्गों ने भी अपना उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया। वे अपने पशुओं से अधिक नहीं, लेकिन उनके जितने लचीले तो थे ही। उन्होंने अपने समुदाय की आजीविका को बढ़ाने के लिए केन्द्रित प्रयास करने; बन्नी मैस की आधिकारिक मान्यता के लिए काम करने; चरागाहों पर समुदाय के अधिकारों के मुद्दे को सम्बोधित करने; और बन्नी के चरागाहों के संरक्षण के लिए औपचारिक योजनाएँ विकसित करने की आवश्यकता महसूस की (जो कि एक तेज़ी से फैलने वाली विदेशी प्रजाति विलायती बबूल के प्रसार के कारण खराब हो गया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है)। उन्होंने कार्यवाही के लिए एक आह्वान किया और मालधारी समुदाय सहायता के लिए इकट्ठा हो गया।

सहजीवन ने विशेष रूप से शुरुआती वर्षों में, बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन (Banni Pashu Uchherak Maldhari Sangathan-BPUMS) की गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्पूर्ण पहल के लिए डेटा संग्रहण और प्रलेखन करने तथा पशु मेला आयोजित करने के लिए धन की आवश्यकता थी। सहजीवन ने आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के साथ भागीदारी की। मालधारी समुदायों की क्षमताओं के विकास में भी सहजीवन ने निवेश किया। आज, बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन अपने अधिकांश संसाधन अपने-आप जुटाता है।

2008 में, मालधारियों ने बन्नी की पशुओं की नस्लों, पशुपालन संस्कृति, और मानव पारिस्थितिकी का उत्सव मनाने के लिए एक पशु मेला का आयोजित करने का निर्णय लिया, और यह आयोजन परिवर्तन की शुरुआत करने का एक मंच बन गया। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि मालधारी एक साथ एक जगह पर एकत्र हुए। पशु मेला न केवल पशुओं के सर्वोत्तम नमूने प्रदर्शित करने के लिए, बल्कि मिलकर समुदायों के बारे में कहानियाँ साझा करने के लिए भी एक स्थान था। यह भी पहली बार हुआ था कि मालधारी सार्वजनिक रूप से अपने जानवरों के प्रति अपना प्यार और अपने जीवन के तरीके पर गर्व प्रकट करने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। यह दोनों सभी गाँवों और समुदायों में पाए जाने वाले सामान्य सूत्र साबित हुए।

मालधारी बुजुर्गों ने बन्नी के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए इन सूत्रों का उपयोग करने का फैसला किया। सलीम नोड, हसम हलेपोत्रा, रमज़ान हलेपोत्रा, अल्ला जुडिया जाट, और मीर मोहम्मद हिंगोरजा ने आन्दोलन का नेतृत्व किया। बुजुर्गों ने खुद को चार या पाँच के समूहों में विभाजित किया और अपनी संस्कृति, आजीविका तथा जीवन के तरीके के लिए खतरों का सामना करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बन्नी के प्रत्येक गाँव में जाकर लम्बी सभाएँ कीं। वे अधिकांश मालधारियों (उनमें से लगभग 1,200) को विश्वास दिलाने में सफल

रहे और उन्हें एक समूह में नामांकित किया जो बन्नी ब्रीडर्स एसोसिएशन (Banni Breeders' Association—BBA) के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक सदस्य ने 100 रुपये वार्षिक शुल्क का योगदान दिया और इससे समूह के कार्यक्रमों और प्रशासनिक लागतों को पूरा किया गया।



बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 और सोसाइटी एक्ट, 1860 के तहत बन्नी ब्रीडर्स एसोसिएशन 2009 में बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के रूप में पंजीकृत की गई थी और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसने काम करना शुरू किया। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने अपनी शासन संरचना को औपचारिक रूप दिया। तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए निर्वाचित 21 सदस्यीय कार्यकारी निकाय द्वारा इसका प्रबन्धन किया जाता है। कार्यकारी निकाय में 19 पंचायतों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि और दो अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल होते हैं। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने सहजीवन के साथ मिलकर बन्नी भैंस के पंजीकरण का काम किया। उन्होंने यह भी तय किया कि व्यवहारिकता का तकाज़ा यह था कि दूध-आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए क्योंकि पशु बिक्री से होने वाली आय अब उनके परिवारों के पालन-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो पहले ही अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने जल्द ही दूध-आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पारम्परिक शासन मॉडल के माध्यम से बन्नी के संरक्षण और सरकार के साथ बातचीत करके अपने औपचारिक भू-अधिकारों की बहाली करने के मुद्दे को सम्बोधित करना शुरू कर दिया।

जबकि बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन वर्तमान में एक औपचारिक निकाय है, यह प्रारम्भिक वर्षों में अधिक शिथिल रूप से संगठित था। शुरुआती दौर में, बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन को सक्रिय मार्गदर्शन के साथ-साथ काफ़ी संगठनात्मक और प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता रहती थी। सहजीवन ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया है कि बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन की गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जाएँ, उनकी निगरानी की जाए, अंकेक्षण (audit) किया जाए, और सभी आवश्यक वित्तीय और शासन नियंत्रण तथा प्रणालियाँ कार्यशील रहें।



बन्नी भैंस की नस्ल का पंजीकरण

बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने महसूस किया है कि भैंस की नस्ल का संरक्षण महत्वपूर्ण है और संरक्षण के उपाय तभी बढ़ सकेंगे जब इस नस्ल को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी जाएगी। बन्नी में पीढ़ी-दर-पीढ़ी पशुपालकों द्वारा बन्नी भैंस को पाला और विकसित किया जाता रहा है। इस नस्ल की अनूठी विशेषताएँ हैं, जैसे—शुष्कता प्रतिरोध, रोग प्रतिरोधक क्षमता, संकटपूर्ण परिस्थितियों में भी उच्च उत्पाद, शान्त व्यवहार, और रात में अपने-आप चरने की क्षमता जो इसे एक शुष्क या अर्ध-शुष्क जलवायु और कठोर इलाक़े के लिए पूरी तरह से अनुकूल बनाती है।



सहजीवन ने पशुपालक समुदायों को नस्ल के पंजीकरण का महत्व समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार जब वे आश्वस्त हो गए, तो सहजीवन ने ऐसे अन्य संगठनों को कार्य में शामिल करने का काम किया, जिनके पास पशु प्रजनन के क्षेत्र में विशेषज्ञता थी और स्थानीय भैंस की नस्ल को पंजीकृत करने के प्रयासों में मदद कर सकते थे। स्थानीय भैंसों के आणविक लक्षण वर्णन और आनुवंशिक लक्षण वर्णन के माध्यम से वैज्ञानिक सबूत एकल करने के लिए सहजीवन ने सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय (Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University—SDAU) जो बनासकांठा ज़िला, गुजरात में स्थित है, के साथ ही राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Animal Genetic Resources—NBAGR) के साथ सम्बन्ध स्थापित किया। इन साझेदारियों का विकास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और सहजीवन वैज्ञानिक संस्थानों और पशुपालक समुदायों के बीच समन्वय अभिकरण बना रहा। सहजीवन ने नस्ल के रखवालों के ज्ञान का प्रलेखन करने के साथ-साथ ज़मीनी स्तर की डेटा-संग्रहण क़वायद करने की ज़िम्मेदारी भी ली। सहजीवन, सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, और पशुपालन निदेशालय (Directorate of Animal Husbandry—DAH), गुजरात सरकार के सहयोग से बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने 2010 में इस नस्ल को पंजीकृत कराया। बन्नी भैंस के पंजीकरण के लिए समुदाय के सदस्यों ने स्वयं (बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के माध्यम से) आवेदन किया था, जबकि सहजीवन ने ज़मीनी काम करने और प्रजनकों

को जुटाने में मदद की। यह भारत में पहली बार हुआ था कि किसी समुदाय ने अपनी देहाती नस्ल के पंजीकरण के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था।

पंजीकरण के फलस्वरूप नस्ल और प्रजनकों दोनों को मान्यता प्राप्त हुई, और तब से बन्नी भैंस की कीमत दोगुनी हो गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change—MoEF&CC), भारत सरकार के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, और लोकल लाइवस्टॉक फॉर एम्पावरमेंट (Local Livestock For Empowerment—LIFE Network) ने 2009 में नस्ल उद्धारक पुरस्कार (Breed Saviour Award) एक मालधारी हाजी मूसा, और बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन को संयुक्त रूप से प्रदान किया। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के अध्यक्ष, सलेमाबाद हालेपोला को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की प्रबन्धन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया (और वे अब भी सदस्य हैं)। स्वतंत्रता के बाद बन्नी भैंस भारत में मान्यता प्राप्त होने वाली पहली भैंस की नस्ल थी और तब से राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा पशुधन की 55 नई नस्लों को पंजीकृत किया गया है (अगस्त 2019 तक)।

बन्नी भैंस के पंजीकरण ने गुजरात सरकार को हरकत में ला दिया, और उसने सामुदायिक संरक्षण तथा देहाती नस्लों की आधिकारिक मान्यता में सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया। राज्य सरकार ने प्रति पशु नस्ल 25 लाख रुपये निवेश की एक योजना भी शुरू की। यह धनराशि सामुदायिक आजीविका के विकास के साथ-साथ स्थानीय नस्लों के संरक्षण के लिए काम करने के लिए प्रजनकों का एक संघ गठित करने पर खर्च की गई।



दूध-आधारित अर्थव्यवस्था

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सहजीवन ने सबसे पहले बन्नी में दूध-आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम करना शुरू किया। 2008 में, सहजीवन के समन्वय के तहत, बन्नी में मालधारी समुदायों के बुजुर्गों ने दूध के संग्रह के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ बैठक की। 2008 की बैठक में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक

सौदा हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तब तक दूध की क्रीमतों पर वसा हेतु 15 रुपए प्रति किलो प्रीमियम भुगतान करने के लिए सहमत हुआ जब तक बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन प्रतिदिन 500 लीटर दूध के संग्रह की व्यवस्था कर सके। सहजीवन की ज़िम्मेदारी यह थी कि वह समुदाय को बल्क मिल्क चिलिंग (Bulk Milk Chilling—BMC) सुविधा केन्द्रों पर दूध जमा करने के लिए तैयार करे और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ज़िम्मेदारी दूध संग्रह के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की थी। चरवाहों को बल्क मिल्क चिलिंग सुविधा केन्द्रों को दूध बेचने के लिए समझाना मुश्किल था, क्योंकि स्थानीय दूध विक्रेताओं के साथ उनका व्यापार और ऋण पर आधारित एक दीर्घकालिक सम्बन्ध था। स्थानीय विक्रेता आमतौर पर चरवाहों को अग्रिम पैसा उधार देते थे और क़र्ज़ चुकाने तक चरवाहे अपना दूध और दुग्ध उत्पाद उन्हें बेचने के लिए बाध्य रहते थे। सहजीवन को पशुपालक समुदाय के कई सदस्यों को समझाने में सफलता मिली कि वे अपना दूध बल्क मिल्क चिलिंग सुविधा केन्द्रों को बेचना शुरू करें ताकि बल्क मिल्क चिलिंग सुविधा केन्द्र व्यवहार्य हो सकें। शुरुआती दिनों में, पावरपट्टी बल्क मिल्क चिलिंग सुविधा केन्द्रों में एकत्रित दूध की मात्रा ने लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ दिया और एक तरह की लघु-क्रान्ति की शुरुआत की क्योंकि इसने पारम्परिक दूध-आधारित अर्थव्यवस्था की गतिकी को गड़बड़ा दिया।

भिरंडियारा गाँव में एक बल्क मिल्क चिलिंग सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया। पहले दिन दूध संग्रह महज़ 265 लीटर था, लेकिन एक महीने के भीतर यह बढ़कर 500 लीटर से अधिक हो गया। एक महीने के भीतर, दूध संग्रह बढ़कर प्रतिदिन 5,000 लीटर हो गया, जो कि बल्क मिल्क चिलिंग सुविधा केन्द्र की अधिकतम क्षमता थी। बल्क मिल्क चिलिंग सुविधा केन्द्र की इस सफलता से उत्साहित, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सरहद डेयरी (Sarhad dairy) दो साल की अवधि के भीतर पाँच और बल्क मिल्क चिलिंग सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए एक साथ आए। सरहद डेयरी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड (Kutch District Co-operative Milk Producer's Union Ltd.—KDCMPUL) ने जल्द ही एक अवसर भाँपा और बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। एक दशक बाद, बन्नी देश के प्रमुख दूध उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जो प्रतिदिन 110,000 लीटर पौष्टिक दूध का उत्पादन करता है, जिसमें से अधिकांश जैविक है। इस दूध का मूल्य 4 मिलियन प्रतिदिन से अधिक और सालाना 1,500 मिलियन रुपए के करीब है।

दुग्ध डेयरी प्रायोगिक परियोजना की सफलता अन्य सन्दर्भों में भी महत्वपूर्ण थी। कच्छ में स्थानीय आबादी पशुपालन प्रणाली की पेचीदगियों और जटिलताओं से बड़े पैमाने पर अनजान थी। बन्नी के पशुपालक समुदायों को पिछड़ा, असभ्य, और भ्रष्ट माना जाता था। सहजीवन ने ज़िले और राज्य में लोगों के व्यापक समुदाय की धारणाओं को बदलने की आवश्यकता को समझा, ताकि पशुपालन से जुड़ी अर्थव्यवस्था में सभी सहयोग कर सकें। दूध डेयरी की स्थापना, बन्नी भैंस की नस्ल का पंजीकरण, पशु मेले का आयोजन, और बन्नी पशु

उछेरक मालधारी संगठन के गठन से परम्परागत मानसिकता और दृष्टिकोण बदलने में मदद मिली, और कच्छ की बड़ी आबादी बन्नी पशुपालकों के साथ काम करने की सम्भावना के प्रति अधिक उत्तरदायी बन गई।

शासन के अधिकारों के लिए संघर्ष

गुजरात में स्थिति (और विशेष रूप से कच्छ में) अलग नहीं रही है। अपने अधिकारों के औपचारिकीकरण पर सरकार के साथ बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन का विचार विमर्श एक अत्यधिक कठिन कार्य साबित हुआ, और जो अब भी खत्म नहीं हुआ है। Article 8(j)—Traditional Knowledge, Innovations and Practices of the Convention on Biological Diversity, 2002 के साथ-साथ the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 2010 के अन्तर्गत विकसित बायो-कल्चरल कम्युनिटी प्रोटोकॉल (Bio-cultural Community Protocols—BCP) में अपने सामुदायिक अधिकारों और तौर-तरीकों का प्रलेखन करते हुए बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने शुरुआत की। 2009 में वन विभाग ने बन्नी के बड़े इलाकों में बाड़ लगाने की कार्य योजना प्रस्तुत की। समुदाय की सलाह के बिना विकसित की गई इस कार्य योजना ने बन्नी के भीतर अनेक आर्द्रभूमि (wetlands) तक न केवल पशुपालकों की पहुँच में कटौती प्रस्तावित की, बल्कि एक ही कैलेंडर वर्ष में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में आने-जाने की आवश्यकताओं की तरफ़ आँखें मूँद लीं। बन्नी ब्रीडर्स एसोसिएशन ने इसके बजाय अपने सामुदायिक अधिकारों की माँग करने का फैसला लिया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि कार्य योजना के क्रियान्वयन से उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ख़तरा पैदा होगा जो उनका अस्तित्व कायम रखता था, और जिसके परिणामस्वरूप उनकी अपनी आजीविका, पशुओं की नस्लें, और संस्कृति प्रभावित होगी। बन्नी ब्रीडर्स एसोसिएशन ने यह भी महसूस किया कि वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act—FRA) बन्नी के चरागाह के उनके अधिकारों के औपचारिकीकरण में मददगार हो सकता है, और जब वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष में लगे थे तब इसने अपनी पारम्परिक शासन प्रणालियाँ पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने बन्नी के सभी 54 गाँवों में हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह अभियान, जो अब “बन्नी को बन्नी रहने दो” के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है “बन्नी को सार्वजनिक उपयोग के संसाधन के रूप में रहने दें”, पशुपालकों द्वारा चरागाहों का पारम्परिक रूप से इस्तेमाल, संरक्षण, और प्रबन्धन पुनर्स्थापित करने में सफल रहा। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने गाँवों और पंचायतों में कई बैठकें आयोजित कीं और सामूहिक रूप से सरकार की नीतियों के प्रति अपनी असममति व्यक्त करने, पशुपालकों और चरवाहों के रूप में अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने, और राज्य सरकार से जल्द-से-जल्द बन्नी में वन अधिकार अधिनियम लागू करने का आग्रह करने का निर्णय लिया। मालधारी समुदायों के

बुजुर्गों और बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के प्रतिनिधियों ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs—MTA) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि राज्य में वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू हो चुका था, लेकिन कच्छ में इस अधिनियम को लागू किया जाना बाकी था, क्योंकि गैर-अनुसूचित क्षेत्रों (जैसे—कच्छ, इसकी छोटी आदिवासी आबादी के साथ) में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नोडल अभिकरण तय किया जाना बाकी था। 2011 में, वन विभाग द्वारा कार्य योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बन्नी के विशिष्ट क्षेत्रों को घेरने के साथ-साथ वन क्षेत्रों में पशुपालक चरवाहों की पहुँच प्रतिबन्धित कर वैज्ञानिक दृष्टि से वन संसाधनों का प्रबन्धन करना था। कार्य योजना ने बन्नी के चरागाह पर पशुपालक समुदाय के परम्परागत अधिकारों और उस पर उनकी निर्भरता को ध्यान में नहीं रखा। प्रतिक्रियास्वरूप मालधारियों ने भुज में एक रैली आयोजित की और कच्छ के कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर उन्हें और राज्य स्तरीय निगरानी समिति (State Level Monitoring Committee—SLMC) को सूचित किया कि जब तक उनके अधिकार वन अधिकार अधिनियम के तहत गैर-मान्यताप्राप्त रहेंगे, वे शान्तिपूर्वक विरोध करना जारी रखेंगे। 5 जून 2012 को, बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने मीडिया को चरागाह के प्रबन्धन का अपना तरीका देखने और उसके बारे में ख़बर प्रसारित करने के लिए आमंत्रित किया तथा अपने संघर्ष के पक्ष में मीडिया के समर्थन का अनुरोध किया।

बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के कहने पर, बन्नी में ग्राम सभाओं ने प्रत्येक गाँव में वन अधिकार समितियाँ (Forest Rights Committees—FRCs) गठित करना शुरू किया, और बन्नी पर अपने अधिकारों का दावा करना शुरू किया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप गुजरात सरकार ने राज्य के सभी गैर-अनुसूचित ज़िलों के कलेक्टरों को वन अधिकार अधिनियम लागू करने का निर्देश देते हुए विस्तृत आधिकारिक पत्र जारी किया। तब कच्छ के ज़िला प्रशासन ने ग्राम सभाओं को औपचारिक रूप से प्रत्येक गाँव में वन अधिकार समितियाँ बनाने के निर्देश जारी किए। सहभागी क़वायद के आधार पर एक संसाधन-मानचित्रण योजना विकसित की गई जिसमें परम्परागत चराई प्रथाओं, जैव-भौतिक स्थितियों, पशुधन पर निर्भरता, और मौजूदा जीव एवं वनस्पति विविधता को ध्यान में रखा गया था। इन सामुदायिक दावों को उप-मण्डल स्तरीय समितियों (Sub-Divisional Level Committees—SDLCs) द्वारा अनुमोदित किया गया, जबकि ज़िला स्तरीय समिति (District Level Committee—DLC) ने उन्हें सैद्धांतिक रूप से सहमति दी। जिन 54 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया, उनमें से 48 ने बन्नी पर सार्वजनिक अधिकारों के लिए दावा प्रस्तुत करने का फ़ैसला किया। यह बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि

थी, क्योंकि इसने पशुपालकों की बन्नी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश की आवश्यकता को प्रतिबिम्बित और रेखांकित किया। यह भी पहली बार हुआ था कि एक पूरे वन पर सार्वजनिक दावे प्रस्तुत करने के लिए कोई इतना बड़ा समुदाय एकजुट होकर आगे आया था।

बन्नी मालधारियों के प्रयासों ने न केवल उनके दावों के औपचारिकीकरण के लिए द्वार खोल दिए, बल्कि ऐसे अन्य समुदायों के लिए भी द्वार खोल दिए, जो गुजरात के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों या ज़िलों में सार्वजनिक संसाधनों से दूर रहते थे, और जिन्हें अपने अधिकार स्थापित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम के सहारे की आवश्यकता थी। बन्नी को सामुदायिक अधिकारों के औपचारिकीकरण के प्रयास अब भी जारी हैं, और बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन अब भुज के ज़िला कलेक्टर और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहा है। यह यात्रा परीक्षणों और आपत्तियों द्वारा चिह्नित है, और मालधारी लोग अपनी सामूहिक ताक़त की बदौलत अब तक इन सभी से सफलतापूर्वक निपटने में सफल रहे हैं। बन्नी मालधारी समुदाय भारत का एकमात्र पशुपालक समूह है जो अपने सार्वजनिक अधिकारों के लिए सफलतापूर्वक दावा करने में सक्षम रहा है। विशेष रूप से, बन्नी सबसे बड़ा चरागाह क्षेत्र भी है, जिस पर समुदाय और सरकार के बीच भूमि अधिकारों पर बातचीत की जा रही है। भारत में सार्वजनिक संसाधनों ने शासन के अभाव या ग़लत प्रशासन के कारण लम्बे समय तक अवनति झेली है। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के माध्यम से मालधारियों ने इस स्थिति के समाधान के लिए एक प्रणाली प्रस्तावित की है, एक ऐसी प्रणाली जिसे पूरे देश में दोहराया जा सकता है। उनके अधिकारों की मान्यता न केवल भारत के पशुपालकों के लिए, बल्कि भारत में लोकतंत्र के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि बन्नी पर अधिकारों की मान्यता भारत में अन्य पशुपालक समुदायों को इसका अनुकरण और अपनी सामुदायिक भूमि एवं सार्वजनिक संसाधनों पर अपने दावे प्रस्तुत करना शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी।

RAMBLE की स्थापना

बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन और सहजीवन ने अग्रणी अनुसन्धान संस्थानों जैसे कि अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment—ATREE) और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़ (National Centre for Biological Sciences—NCBS) से हाथ मिलाया जिसका उद्देश्य था बन्नी में एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करना, जो रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन द बन्नी लैंडस्केप (Research and Monitoring in the Banni Landscape—RAMBLE) के नाम से जाना जाता है। RAMBLE की स्थापना के लिए ATREE और अन्य प्रमुख अनुसन्धान संगठनों को जोड़ने में सहजीवन ने एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। RAMBLE की स्थापना बन्नी में सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तनों का अध्ययन करने

तथा भूमि उपयोग और प्रबन्धन के बारे में कुछ कठिन सवालों के जवाब देने में मदद करने के लिए की गई थी। RAMBLE एक खुला शोध मंच है जहाँ विद्वान बन्नी चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र, इसके पशुपालक समुदायों और बन्नी चरागाह के साथ उनकी परस्पर क्रिया के विभिन्न पहलुओं पर विषयगत और अन्तर्विषयक अनुसन्धान करते हैं। अनुसन्धान से अपेक्षित है कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने वाले पारिस्थितिक, संस्थागत, सामाजिक, और आर्थिक प्रेरकों के विषय में समझ बढ़ाने में मदद मिले। RAMBLE द्वारा किए गए शोध से मालधारी समुदाय को बदलती पारिस्थितिक आवश्यकताओं का जवाब देने में मदद मिलती है और यह उनके परम्परागत ज्ञान तथा शासन प्रणालियों के प्रति विश्वास भी जगाता है। अन्ततः, इस तरह की समझ भविष्य में बन्नी के प्रबन्धन और उपयोग के विषय में चल रहे नीतिगत संवाद में योगदान करेगी, यह उम्मीद की जाती है।

यात्रा के दौरान चुनौतियाँ

दस साल लम्बी यात्रा के दौरान सबकुछ आसान नहीं था। सहजीवन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:

औपचारिक संस्थानों का निर्माण: हालाँकि बन्नी चरवाहों के पास परम्परागत शासन प्रणाली थी, लेकिन समुदाय के मानदण्डों को लागू करने के लिए कोई औपचारिक निकाय नहीं था। एक औपचारिक संस्था की अवधारणा और आवश्यकता चरवाहों के लिए अनजानी चीज़ थी, और एक साथ आने तथा एक औपचारिक निकाय बनाने के लिए उन्हें विश्वास दिलाने में कई महीनों की बातचीत और समझाने-बुझाने की आवश्यकता पड़ी।

पशुओं का टैगिंग: बन्नी भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक है। साक्षरता के स्तर निम्न हैं और लोग के मन में कई अन्धविश्वास जड़ें जमाए हुए हैं। बन्नी में पंजीकरण के लिए यह आवश्यक था कि कुछ पशुओं की समय के साथ टैगिंग (tagging) की जाए और उनकी निगरानी की जाए। चरवाहों का मानना था कि जानवरों की टैगिंग का परिणाम यह होगा कि बैंक उन पर ग्रहणाधिकार का दावा करेंगे। अधिकांश चरवाहों ने सहयोग करने से इंकार कर दिया और उन्हें सहयोग करने हेतु मनाने के लिए पुनः बहुत प्रयास करने पड़े।

वन अधिकार अधिनियम के महत्त्व को अधिग्रहण के साधन के रूप में नहीं बल्कि पारम्परिक भूमि पर पहुँच के साधन के रूप में समझाना : बन्नी के गाँव एक वन क्षेत्र में स्थित हैं। हमेशा एक आशंका बनी रहती थी कि वन विभाग को स्थानीय समुदाय को बेदखल करने की शक्ति मिल जाएगी। वन शब्द का उल्लेख मात्र समुदाय में दहशत फैलाने के लिए पर्याप्त था। एक समय पर, सहजीवन ने वन अधिकार अधिनियम के विषय से परिचय करते हुए समुदाय को एक साथ आने और इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का दावा करने का अनुरोध किया। इसने भ्रम पैदा किया, क्योंकि समुदाय को लगा कि वन अधिकार अधिनियम

के तहत अधिकारों का दावा करने का अर्थ होगा कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि भूमि का स्वामित्व वन विभाग के पास है, और इसलिए उन्होंने सहजीवन के प्रतिनिधियों को सुनने से ही इंकार कर दिया। इस भ्रम को दूर करने और समुदाय को सहयोग हेतु तैयार के लिए वन अधिकार अधिनियम पर प्रकाश डालने के लिए परिचयात्मक कार्यक्रमों और साहित्य का उपयोग किया गया।

कुछ सामान्य सबक़

नस्ल पंजीकरण का महत्त्व : किसी विशेष नस्ल के संरक्षण के प्रयासों में औपचारिक क्षेत्र को संलग्न करने के लिए देशी नस्लों का पंजीकरण आवश्यक है। जब तक कोई नस्ल पंजीकृत नहीं हो जाती, तब तक उसकी विशेषताओं, उसकी आबादी और उसकी उत्पादकता के बारे में जानकारी अनिश्चित, असत्यापित, और ग़ैर-दस्तावेज़ी रहती है। कुछ उदाहरणों में, एक ही नस्ल के अलग-अलग उपभेद होते हैं, परिणामस्वरूप उनके अलग-अलग स्थानीय नाम होते हैं। इन सबसे भ्रम पैदा होता है। किसी नस्ल के पंजीकरण से यह भी सुनिश्चित होता है कि सरकार उस पशुपालन प्रणाली के संरक्षण में निवेश की प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए उसे औपचारिक रूप प्रदान करती है जो उसका पालन-पोषण करती है, रखरखाव करती है, और उस नस्ल पर निर्भर करती है। भैंस की स्थानीय आबादी की ब्रांडिंग में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो और सरदारकृषिनागर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से प्राप्त बन्नी नस्ल का पंजीकरण महत्त्वपूर्ण था। नस्ल के पंजीकरण के बाद से, न केवल पशुपालक समुदाय की तरफ़ अधिक लोगों का ध्यान, अधिक आधिकारिक हित आकर्षित हुआ और आर्थिक निवेश में वृद्धि हुई है, बल्कि भैंसों की कीमतों में भी वृद्धि हुई, क्योंकि यह नस्ल संकटपूर्ण परिस्थितियों में भी अत्यधिक उत्पादक नस्ल के रूप में जानी जाने लगी, और यह आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है।

कच्छ ऊँट उछेरक मालधारी संगठन की स्थापना—व्यापक समुदाय में सक्रियता और शिक्षा : बन्नी में भैंस पालकों के समुदाय की सक्रियता ने कच्छ के ऊँट चरवाहों को इसी तरह की कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के सफल गठन और स्थापना के तुरन्त बाद, ज़िले के ऊँट चरवाहों के समुदाय ने एकजुट होकर अपना स्वयं का समुदाय-आधारित संगठन कच्छ ऊँट उछेरक मालधारी संगठन (Kachchh Unt Ucherak Maldhari Sangathan—KUUMS) बनाने का फैसला किया। कच्छ ऊँट उछेरक मालधारी संगठन कच्छ में ऊँट चरवाहों की स्थिति में सुधार करने के लिए काम कर रहा है। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के अनुभवों से सीख लेते हुए, कच्छ ऊँट उछेरक मालधारी संगठन ने ऊँटनी के दूध पर आधारित एक अर्थव्यवस्था और आजीविका का स्रोत विकसित करने की दिशा में काम किया। तब से, ऊँटनी के दूध की डेयरी भारत में ऊँटों के संरक्षण में एक

महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऊँटनी के दूध में अत्यधिक चिकित्सीय क्षमता पाई जाती है और अमूल ने भारत में ऊँटनी के दूध के साथ-साथ ऊँटनी के दूध से बनी चॉकलेट और अन्य उत्पादों की बिक्री भी शुरू की है।

सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व का महत्त्व : बन्नी पहल किसी भी हस्तक्षेप में उस समुदाय की भागीदारी का महत्त्व दर्शाती है जिसके लाभ के लिए उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। जो भी उपलब्धि हासिल की गई वह केवल इसलिए सम्भव हुई क्योंकि समुदाय ने सक्रिय भूमिका निभाई और वह सम्पूर्ण प्रक्रिया से जुड़ा रहा। बन्नी पहल सामुदायिक ज्ञान के महत्त्व पर भी प्रकाश डालती है; पशुओं की शुद्ध नस्लों की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए पशु मेले में प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में मालधारी समुदाय के बुजुर्गों द्वारा फ़ैसला किया गया, वे लोग पशु स्वास्थ्य, प्रजनन शक्ति, और उत्पादकता के वास्तविक विशेषज्ञ थे। प्रतियोगिताओं में जिन पशुओं को बन्नी में सबसे अच्छा घोषित किया जाता था, उन्हें ख़रीदने के लिए स्थानीय किसान हमेशा तैयार पाए जाते थे और उनकी ऊँची कीमत मिलती थी। समय के साथ, किसानों ने ध्यान दिया कि बुजुर्गों का फ़ैसला एकदम सही था, और इससे यह भावना विकसित हुई कि अधिक कीमत चुकाकर भी पुरस्कार-विजेता पशुओं को प्राप्त करना व्यावसायिक दृष्टि से उचित है।

बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन में सहजीवन के निवेश का भी यथोचित प्रतिफल प्राप्त हुआ है। समय के साथ समुदाय-आधारित संगठन ने सरकार के साथ मालधारी समुदाय के अधिकारों की पैरवी करने का बीड़ा उठाया है। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के सदस्यों ने कच्छ ज़िले के कलेक्टर के साथ-साथ गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बन्नी में प्रवेश और उस पर शासन के अधिकारों की माँग की है। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध भी विकसित किया है, और हाल ही में एक बुजुर्ग मालधारी को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा उनके काम के लिए मान्यता प्रदान की गई थी। गुजरात के पशुपालन निदेशालय द्वारा भी बन्नी भैंस के पंजीकरण के लिए बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन और सहजीवन द्वारा किए गए कार्य को अभिस्वीकृति प्रदान की गई है, और उसने गुजरात के देशी पशुओं की नस्लों की पहचान करने और फिर एक समुदाय-आधारित संगठन बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य इन नस्लों का पंजीकरण और इनके मूल निवास स्थान में इनका संरक्षण करना होगा।

बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन अपने काम के दायरे में विविधता लाया है और यह अब राजस्व विभाग तथा वन विभाग के बीच लम्बे समय से चल रहे एक विवाद को सुलझाने के लिए काम कर रहा है, जिसमें से किसी ने भी बन्नी के इस भू-संसाधन के प्रबन्धन की ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। इस कुप्रबन्धन ने अतिक्रमण को जन्म दिया है, और बन्नी पशु उछेरक

मालधारी संगठन ने अतिक्रमणों को हटाने और चरागाहों के प्रबन्धन के अधिकार हेतु दबाव डालने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal—NGT) का रुख किया है। यह आशा की जाती है कि चरागाह के विवाद को सुलझाने के बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन के प्रयासों को शीघ्र ही सफलता मिलेगी।

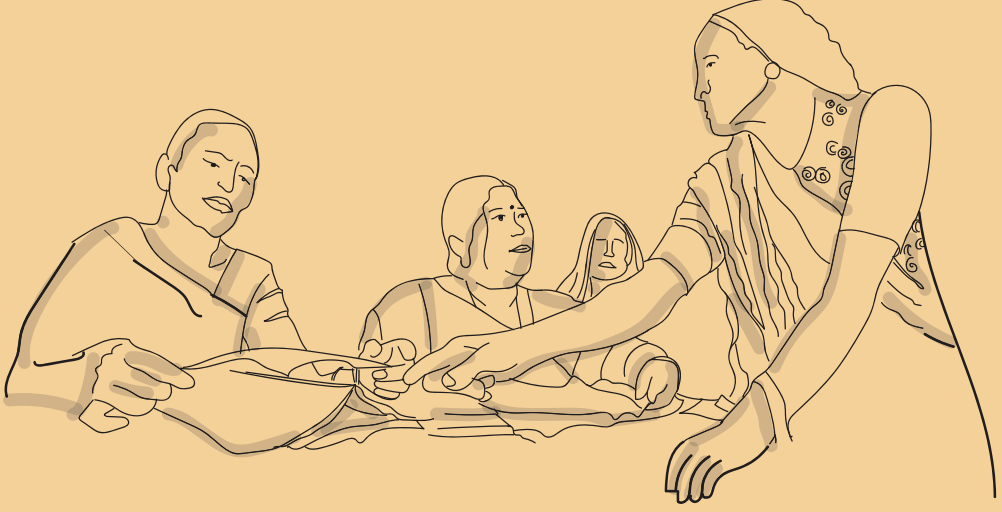
भावी मार्ग

हालाँकि बन्नी के मालधारियों ने वैश्वीकरण के खिलाफ़ लड़ाई के पहले दौर में जीत हासिल कर ली है, और इसके मद्देनज़र होने वाली उथल-पुथल का सफलतापूर्वक सामना किया है, चरागाह भूमियों और वहाँ निवास करने वाले समुदायों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और बन्नी में धर्म, जाति, तथा समुदाय से परे भाईचारे और एकता की भावना को पोषित करने एवं बनाए रखने के लिए काम जारी रखने में उल्लेखनीय दूरदर्शिता दर्शाई है, जो शुरुआत से ही उनके काम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। बन्नी मालधारियों को अहसास है कि शहरी उपभोक्ता ऐसे भोजन के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं जो हितकारी, शुद्ध, पौष्टिक, एवं स्वास्थ्यवर्धक हो, और फलस्वरूप बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन और सहजीवन ने मिलकर एक पहल शुरू की है कि कैसे बन्नी में उत्पादित दूध को जैविक दूध के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है और आला उपभोक्ता वर्गों में इसकी बिक्री की जा सकती है। वन अधिकार अधिनियम के लिए लड़ाई जारी है, और चरवाहे प्रतिदिन बन्नी पर अपने अधिकारों का दावा करने की दिशा में एक छोटा क़दम आगे बढ़ाते हैं। चरवाहा समुदाय को अपने चरागाहों के प्रबन्धन की आवश्यकता का अहसास भी है, और ग्रामीणों द्वारा तेज़ी से फैलने वाले विलायती बबूल (*Prosopis juliflora*) के उन्मूलन के लिए कई प्रायोगिक परियोजनाएँ संचालित हुई हैं। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के कारण वे वनस्पतियाँ पुनः उभरने लगी हैं, जिनके बारे में माना जाता था कि वे बन्नी चरागाहों से बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थीं। डेटा प्रदान करके और प्रयोगों में मदद करते हुए RAMBLE का अनुसन्धान स्टेशन समुदायों द्वारा संचालित प्रत्येक गतिविधि की जानकारी देना और निरीक्षण करना जारी रखता है। इसने यह दर्शाया है कि दूध-आधारित अर्थव्यवस्था की बदौलत, बन्नी के चरागाहों में पशुओं की एक इतनी बड़ी संख्या हो सकती है, जिसका भरण-पोषण यहाँ का वानस्पतिक द्रव्यमान नहीं कर सके। अनुसन्धान अब भी जारी है, और बन्नी पशु उछेरक मालधारी संगठन पर अपने सदस्यों के साथ काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है यदि RAMBLE शोधकर्ताओं की आशंका सही है।

सहजीवन ट्रस्ट, गुजरात

समुदायों द्वारा ज़मीनी और नीतिगत स्तर पर प्रदर्शित किया गया है कि सहजीवन पारम्परिक आजीविकाओं को मज़बूत करने के लिए पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और लैंगिक समानता, मानवीय मूल्यों, स्वदेशी ज्ञान तथा नवीन प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के प्रयास करता है। इसने चार विषयगत क्षेत्रों की पहचान की है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है; नामतः, पशुपालन, जल, जैव विविधता और शहरी मुद्दे; और उनके विषय में काम करने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना की है। सीमान्त समुदायों को उनकी परम्परागत पारिस्थितिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करने, उनके पारिस्थितिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक विधियों से जुड़ने, और उनकी आजीविकाओं को मज़बूत करने के लिए सहजीवन उन्हें प्रेरित करता रहा है और उन्हें सहयोग प्रदान करता रहा है। 25 वर्षों से अधिक समय से कच्छ में स्थित, संगठन ने जैव विविधता के संरक्षण, स्थानीय भू-जल वैज्ञानिक समाधानों के आधार पर परम्परागत जल प्रणालियों को पुनर्जीवित करने, पशुपालन को पुनर्जीवित करने, स्वदेशी पशुधन प्रजनन पद्धतियों को बढ़ावा देने, और वर्षा जल से सिंचित कृषि के माध्यम से लचीलेपन को मज़बूत करने के लिए स्थानीय शासन संस्थानों, समुदायों और इस सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रभावित किया है।

आज सहजीवन सम्पूर्ण गुजरात राज्य में काम करता है और उसने अपने लिए देश के अग्रणी नागरिक समाज संस्थानों में से एक होने की मान्यता अर्जित की है।



अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय
बुरागुंटे गाँव, सरजापुरा होबली, अनेकल तालुक,
बिल्लापुरा ग्राम पंचायत, बेंगलूरु - 562125